भारतीय गुणवत्ता परिषद्
QUALITY COUNCIL® OF INDIA
Creating an Ecosystem for Quality

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2024-25



CONTE

अध्यक्ष का संदेश.....06

महासचिव का संदेश 08

अध्यक्ष, एनएबीएल का संदेश 10

अध्यक्ष, एनएबीएच का संदेश 11

अध्यक्ष, एनएबीईटी का संदेश.....12

अध्यक्ष, एनएबीसीबी का संदेश.....13

अध्यक्ष, एनबीक्यूपी का संदेश.....14

क्यूसीआई कार्य-क्षेत्र परिचय.....16

क्यूसीआई–पेशकश.....17

क्यूसीआई की अखिल भारतीय उपस्थिति.....18

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निष्पादित प्रमुख कार्य.....24

भाग 01

परिचय 34

शासी परिषद् 36

शासी निकाय 38

संरचना 39

भाग 03

मानव संसाधन और प्रशासनिक गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा 171

भाग 04

वित्तीय विवरण 183



भाग 02

वित्त वर्ष 2024-25 में बोर्डों/प्रभागों/प्रकोष्ठों की गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा

1. राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) 43
2. राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्यचर्या- प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) 57
3. राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी) 74
4. राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी).....97
5. राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड (एनबीक्यूपी).....116
6. परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन प्रभाग (पीपीआईडी) 135
7. राष्ट्रीय उद्योग उत्कृष्टता प्रभाग (एनडीआईई).....145
8. परियोजना विश्लेषण और प्रलेखन प्रभाग (पीएडीडी) 154
9. रणनीति और नीति प्रभाग (एसपीडी) 164

भाग 05

संक्षिप्ताक्षर और उनका पूर्ण रूप I

अध्यक्ष का संदेश



श्री जक्षय शाह
अध्यक्ष, भारतीय गुणवत्ता परिषद्

भारतीय गुणवत्ता परिषद् के मेरे सहयोगियो और हमारे सम्मानित हितधारको,

वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गौरव और प्रयोजन-सिद्धि का अनुभव हो रहा है। यह दस्तावेज पिछले एक वर्ष में हुई उल्लेखनीय प्रगति का वृत्तांत प्रस्तुत करता है, लेकिन उससे भी बढ़कर, यह प्रबल रूपांतरण की हमारी यात्रा को दर्शाता है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने पूरी स्पष्टता के साथ 'विकसित भारत' की संकल्पना प्रस्तुत की है। उनके इस विज़न से प्रेरित होकर, भारतीय गुणवत्ता परिषद् एक उत्थानशील, समृद्ध और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र के निर्माण के अपने मिशन में अडिग रहते हुए काम कर रही है।

प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता सदैव हमारा ध्येय रही है। हमने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा है जहाँ गुणवत्ता एक विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक अधिकार हो; हम इस मिशन को भारत के हर कोने तक ले जाना चाहते हैं; और हम इस संकल्पना को अभूतपूर्व गति, पैमाने और निष्ठा के साथ प्रतिपादित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर कोई परिवर्तन लाने से पहले हमें खुद को परिवर्तित करना होता है। जनता, प्रक्रियाओं और स्थान के तीन स्तंभों पर ध्यान केन्द्रित करना ही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत रहा। हमने एक आकांक्षापूर्ण, दक्ष और नैतिकतापूर्ण कार्यस्थल के निर्माण के लिए मूलभूत सुधार की शुरुआत की। इस वर्ष नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमारे नए मुख्यालय के उद्घाटन के साथ ही 'एक क्यूसीआई' की हमारी संकल्पना साकार हो गई। अनेक एकाग्र प्रयासों के पश्चात, लंबे समय से चला आ रहा हमारा यह सपना आखिर साकार हो गया, और मैं उस टीम के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके निरंतर प्रयासों से यह संभव हो सका।

इस भौतिक एकता के साथ-साथ सांस्कृतिक और प्रक्रियागत बदलाव भी लागू किए गए। हमने अपनी बहुमूल्य परसंपत्ति यानि अपने लोगों पर ध्यान केन्द्रित किया। हमने प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिकाओं में सेवा करने के लिए उद्योग जगत से शीर्ष प्रतिभाएं आकर्षित कीं। इससे, सुधारों की पहल करने और व्यवसाय करने को आसान बनाने के लिए क्यूसीआई में नई विशेषज्ञता का समावेश हुआ। इस नई संस्कृति को स्थापित करने के लिए, हमने अपनी अभिशासन रूपरेखा का आधुनिकीकरण किया। सभी के लिए एक स्पष्ट और अनुकूलनशील रूपरेखा तैयार करने के लिए मूल सेवा एवं वित्त नियमावली में व्यापक बदलाव किए गए। सुलभता और दक्षता के उद्देश्य से हमारी प्रक्रियाओं की पुनर्रचना की गई। 'दिशा', 'मंथन' और 'यात्रा' जैसी पहलों के माध्यम से तथा आसान 'सरल' फॉर्म लागू करके, हमने गुणवत्ता की राह, विशेषत: छोटे एवं ग्रामीण संगठनों के लिए और भी सुगम एवं द्रुतगामी बना दी है।

इस कालावधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि हमने गुणवत्ता संकल्प नामक अपनी राज्य-संपर्क पहल के माध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार अंतिम छोर तक किया है। इस प्रयास के इस मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने गुजरात और विशेष रूप से नागालैंड में गुणवत्ता संकल्प आयोजित किए हैं ताकि हमारी पहुंच वास्तव में अंतिम छोर तक हो सके। हमारी सरपंच संवाद पहल भी एक अग्रणी मंच के रूप में विकसित हुई है जिसमें 30,000 से अधिक सरपंचों को जोड़ा गया है और उन्हें परिवर्तन के सच्चे वाहक के रूप में सशक्त बनाया गया है। यह लोकतांत्रिक भावना हमारी ज़ेड स्कीम के अविश्वसनीय विस्तार में भी परिलक्षित हुई है, जिसके अंतर्गत 350,000 से अधिक एमएसएमई को प्रमाणित किया है। इनमें से 90% सूक्ष्म उद्यम हैं।

एक 'प्रहरी' मात्र बने रहने के बजाए क्यूसीआई का संभवत: सर्वाधिक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक बदलाव यह था कि हम सरकार के लिए एक सक्रिय प्रवर्तक बनें। हमने नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अपने विशाल डेटा और क्षेत्र विशेषज्ञता का लाभ उठाया। हमने सरकारी संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए, छह केन्द्रीय मंत्रालयों में जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक समयबद्ध अध्ययन संपन्न किया। हमने 370 से अधिक सरकारी कार्यालयों का मूल्यांकन करते हुए, महाराष्ट्र के 100

दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने में मदद की। हमने भारतीय डाक के विशाल नेटवर्क को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में रूपांतरित करने के लिए एक परिपक्वता मॉडल विकसित किया। हमने श्री सोमनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर और उसकी सेवाओं को प्रमाणित करके उस पवित्र स्थल को अपना गुणवत्ता फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया।

विकसित भारत का अर्थ है कि हम विश्व मंच पर नेतृत्व की भूमिका में हों। हमने एशिया-प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (एपीएसी) वार्षिक कॉन्क्लेव की सफलतापूर्वक मेजबानी की जिसमें 35 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और नए वैश्विक गुणवत्ता संवाद में भारत के नेतृत्व के लिए एक मजबूत पक्ष प्रस्तुत किया। अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस गुणवत्ता समूह (आईएक्यूजी) द्वारा एनएबीसीबी को मान्यता दिया जाना, रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण में हमारे आत्मनिर्भर मिशन के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है।

यह वर्ष, हमारे सभी बोर्डों के लिए भी नई उपलब्धियों का वर्ष रहा। एनएबीएच ने अपने प्रत्यायन मानकों के छठे संस्करण का लोकार्पण किया तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यचर्या को अधिकाधिक सुलभ और भविष्य के लिए तैयार व्यवस्था बनाते हुए एक अग्रणी डिजिटल स्वास्थ्य प्रमाणन कार्यक्रम की शुरूआत की। एनएबीएल ने गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान सुझाते हुए, बायोबैंकिंग और वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण प्रत्यायन कार्यक्रम शुरू किए। एनएबीईटी ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए बैंचमार्क स्थापित करते हुए, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी, और नर्सिंग मेडिकल कॉलेजों के आकलन और रेटिंग के साथ शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में अपना कार्य आगे बढ़ाया।

हमारे लिए यह वर्ष, चिंतन और स्मरण का भी वर्ष रहा। हमने एनएबीएल के पूर्व अध्यक्ष, पद्मश्री प्रो. सुब्बम्मा अय्यप्पन को हमेशा के लिए खो दिया। उनकी विरासत विज्ञान और नवाचार में उत्कृष्टता के हमारे मिशन को सदैव प्रेरित करती रहेगी।

भविष्य पर दृष्टि रखते हुए, हमारी संकल्पना इस गतिशीलता को आगे भी बनाए रखने की है। हमारी यात्रा निरंतर जारी है। हमारा आगे का मार्ग नवाचार, सहकार एवं उत्कृष्टता द्वारा परिभाषित राष्ट्र के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और गहरा करने की असीम संभावनाओं से भरा है। यह हमारा मिशन मात्र नहीं है; यह अपने राष्ट्र के प्रति हमारी एक दृढ़ प्रतिज्ञा है।

हस्ता./-

श्री जक्षय शाह
अध्यक्ष, भारतीय गुणवत्ता परिषद्

महासचिव का संदेश



चक्रवर्ती टी. कन्नन
महासचिव, भारतीय गुणवत्ता परिषद्

प्रिय हितधारकगण और क्यूसीआई परिवार के सदस्यो,

भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है। अपनी वर्ष भर की प्रगति पर विचार करते हुए हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि दोनों ही रूपों में अर्थात् एक संगठन के रूप में और भारत की विकसित भारत यात्रा की गति को तेज करने में एक प्रमुख भागीदार के रूप में - हमने काफी उन्नति की है।

क्यूसीआई में अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष पर विचार करते हुए मुझे यह आत्मिक गौरव हो रहा है कि हमने मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है और इससे भी बढ़कर परिषद् की भावी यात्रा के लिए संकल्प-सिद्धि का भाव उत्पन्न हो रहा है। बीता हुआ यह वर्ष, मेरे लिए विलक्षण सीख का अवसर रहा है जिसने हमारे जीवंत संगठन, इसमें काम कर रहे लोगों, और विकसित भारत की दिशा में भारत की प्रगति में योगदान करने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता के बारे में मेरी समझ को और गहरा किया है।

विकसित भारत हमारे लिए कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, यह हमारा ध्रुव लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने, उनकी जरूरतों को समझने और उनके सरोकारों को सुनने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही हम उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं, जहां गुणवत्ता एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री ने कारोबार में सुगमता लाने पर बल दिया है, जो समय कम करने, प्रलेखन को सुव्यवस्थित करने, और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के हमारे मिशन के साथ पूरी तरह मेल खाता है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम ऐसे कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें लोगों के और नज़दीक लाते हैं तथा गुणवत्ता को सुलभ व किफ़ायती बनाते हैं। 'गुणवत्ता यात्रा' (ग्राहकों में पक्ष-प्रचार और दूर-दराज के क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी संपर्क-संवाद, ताकि गुणवत्ता मानकों और सर्वोत्तम परिपाटियों को संचारित और अंगीकृत किया जा सके), 'गुणवत्ता मंथन' (एक ऐसा मंच जो हितधारकों की चिंताओं को सुनने, उनसे सीखने, पुनर्रचना करने, कार्यान्वित करने और उद्योगों में गुणवत्ता के पैमाने का विस्तार करने के लिए एकजुट करता है), तथा 'समृद्धि' (गुणवत्ता अवसंरचना को मज़बूत बनाने, प्रमाणन/प्रत्यायन तक पहुंच को सुचारु बनाने और वैश्विक बाज़ार तत्परता के लिए क्षमता निर्माण हेतु एक रणनीतिक उद्योग-संपर्क) की अभिकल्पना इसी को ध्यान में रखकर की गई है। ये कार्यक्रम हमें समुदायों से सीधे जुड़ने, उनकी चुनौतियों को समझने, और गुणवत्ता मानकों के अंगीकरण को सरल बनाने में मदद करते हैं।

कारोबारी टकराव के घटाव और सरलीकरण के सरकार के आह्वान के अनुरूप क्यूसीआई, प्रत्यायन की सुगमता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उदाहरण के लिए, हमारा क्यू-मित्र प्लेटफ़ॉर्म अस्पतालों, एमएसएमई, और स्कूलों के लिए गुणवत्ता प्रमाणन को समझना और उसके लिए आवेदन करना आसान बना देगा, जिससे समय, प्रलेखन, और श्रम में कमी आएगी।

इस वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में हमारी प्रत्यायन प्रणालियों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एनएबीएच, एनएबीएल, एनएबीसीबी और एनएबीईटी के अंतर्गत, हमारी प्रत्यायन और प्रमाणन प्रक्रियाओं का अनवरत विस्तार हुआ है, जिससे और अधिक संख्या में संगठन, गुणवत्ता के उच्च मानकों को पूरा करने में सक्षम हुए हैं। यहां कुछ प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया जा रहा है :

- अब तक 24,000 से अधिक प्रत्यायन, प्रमाणन, और इम्पैनलमेंट के साथ, एनएबीएच ने डिजिटल स्वास्थ्य जैसी उभरती स्वास्थ्यचर्या प्रौद्योगिकियों के लिए नए मानक लागू किए हैं और वैश्विक स्वास्थ्यचर्या मांगों को पूरा करने के लिए साइबर सुरक्षा तथा डेटा गोपनीयता पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।

- 12,500 से अधिक प्रत्यायनों और मान्यताओं के साथ, एनएबीएल ने निर्माण परियोजनाओं में अस्थायी कार्य-स्थली

प्रयोगशालाओं के लिए नए मान्यता कार्यक्रमों का आरंभ किया है और 'स्वस्थ धरा तो खेत हरा' (एसएचसी) नामक अपनी पहल के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन किया है, जिससे जमीनी स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित हुई है।

- इस वर्ष, एनएबीसीबी ने 290 से अधिक प्रत्यायित निकायों द्वारा 1,00,000 से अधिक निरीक्षण और 2,500 से अधिक प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन संचालित किए। इसके अतिरिक्त, इसे एयरोस्पेस गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एक्यूएमएस) प्रमाणन के लिए, यूरोपीय एयरोस्पेस गुणवत्ता समूह (ईएक्यूजी) और अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस गुणवत्ता समूह (आईएक्यूजी) द्वारा मान्यता प्रदान की गई, जो भारत के एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

- एनएबीईटी के तहत 8,500 से अधिक स्कूलों का आकलन किया गया और उन्हें प्रत्यायित किया गया है जबकि पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम (पुणे) में 45,000 से अधिक छात्रों और 1,300 से ज़्यादा शिक्षकों का आकलन कार्य जारी है। एनएबीईटी ने आठ आईआईटी में शैक्षणिक कार्यक्रमों, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), और अवसंरचना का संपरीक्षण भी किया है, जिससे गुणवत्तापरक शिक्षा के राष्ट्रीय विजन में योगदान हुआ है।

- एमएसएमई के लिए ज़ेड प्रमाणन में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल 3,50,000 से ज़्यादा एमएसएमई प्रमाणित हो चुके हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यम हैं। 'लीन' योजना के तहत 8,700 से ज़्यादा एमएसएमई पंजीकृत हुए हैं, और 'समर' के तहत 30 से ज़्यादा रक्षा विनिर्माताओं को प्रमाणित किया गया है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद् ने विभिन्न क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोयले के अन्य-पक्ष नमूनाकरण, परीक्षण और विश्लेषण के माध्यम से, 4,500 से अधिक त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और 600+ एमएमटी कोयले का नमूना लिया जा चुका है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हुआ है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग (सीएफआर) पहल, अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसके अंतर्गत 15 से अधिक राज्यों में 2,570 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का मूल्यांकन किया गया और मान्यता दी गई। ऐसा करते हुए उनके वित्तीय प्रदर्शन, संसाधन जुटाने, और राजकोषीय अभिशासन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया और बेहतर शहरी अभिशासन को बढ़ावा दिया गया है। पीएमएवाई-यू के तहत, सीएलएसएस के प्रभाव आकलन में, क्यूसीआई ने 30,000 से अधिक लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया और ऐसा करते हुए प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) का मूल्यांकन किया गया। यह योजना, शहरी परिवारों की आवास जरूरतों के समाधान में मदद करती है। इसके अतिरिक्त, क्यूसीआई ने 43 संगठनों और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की व्यापक समीक्षा करके भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के लिए विज़न 2047 को आकार देने में संस्कृति मंत्रालय का सहयोग किया, जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास में योगदान संभव होगा।

क्यूसीआई में, हम यह सुनिश्चित करके कि गुणवत्ता केवल एक बैंचमार्क नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, विकसित भारत 2047 के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपनी पहुंच का विस्तार करके, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, हम उत्कृष्टता के एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जारी रखेंगे, जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यवसाय और प्रत्येक संस्थान को लाभ पहुंचे।

मैं आप सभी को, आपके निरंतर समर्थन और सहकार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ मिलकर, हम एक गुणवत्ता-प्रेरित, समृद्ध भविष्य की ओर अपनी यात्रा जारी रखेंगे।

हस्ता./-

चक्रवर्ती टी. कन्नन
महासचिव, भारतीय गुणवत्ता परिषद्



डॉ. संदीप शाह
अध्यक्ष, एनएबीएल

अध्यक्ष, एनएबीएल

एनएबीएल के माध्यम से देश की सेवा में शामिल होना सदैव सुखद होता है। हम सभी जानते हैं कि एनएबीएल, हमारे देश की प्रत्यायन अवसंरचना में और दूसरे सभी क्षेत्रों की चाहे वह स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, भोजन हो, दवाएं हों अथवा पेयजल हो, संरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नागरिकों का स्वास्थ्य और कल्याण सदैव एक राष्ट्रीय मिशन रहा है और एनएबीएल प्रत्यायन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि चिकित्सा परीक्षण के लिए सक्षम प्रयोगशालाएं उपलब्ध हों। एनएबीएल की पहल, चिकित्सा परीक्षण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल चिकित्सा प्रवेश स्तरीय परीक्षण प्रयोगशाला कार्यक्रम - [एम(ईएल)टी] के माध्यम से अपनी सेवाओं को विश्वसनीय बनाने में मदद कर रही है, जो निपुणता परीक्षण में सफल भागीदारी पर आधारित है।

समीक्षाधीन अवधि में, एनएबीएल ने सफल एपीएसी पुनर्मूल्यांकन, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला मान्यता कार्यक्रम, आदि जैसी अनेक उपलब्धियां प्राप्त कीं। एनएबीएल ने अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ 20387 के साथ बायोबैंकिंग के लिए प्रत्यायन कार्यक्रम शुरू किया है। एनएबीएल ने जिला स्तर पर जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन के माध्यम से पेयजल की संरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार का भी सहयोग किया है।

अब जब हम, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीमों के माध्यम से अपना निर्यात बढ़ाने और 'गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों' के माध्यम से उपभोक्ताओं की संरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तब, राष्ट्र में एक विश्व स्तरीय अनुरूपता आकलन अवसंरचना का विकास करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। एनएबीएल प्रत्यायन, अपनी प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के परीक्षण परिणामों में विश्वास पैदा करता है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। हमारा यह निरंतर प्रयास है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों को प्रत्यायन के दायरे में लाया जाए जिससे गुणवत्ता और संरक्षा की आश्वस्ति हो।

जमीनी स्तर पर कार्यरत प्रयोगशालाओं तक अपनी पहुंच बनाने और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों तथा सेवाओं की मांग करने के प्रति लोगों के मन में अत्यावश्यक परिवर्तन लाने के लिए मैं, एनएबीएल की सराहना करता हूँ।

गुणवत्ता अवसंरचना की एनएबीएल की विकास यात्रा में भविष्य में अन्य अनेक उपलब्धियां एनएबीएल को प्राप्त हों, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

हस्ता/-

डॉ. संदीप शाह
अध्यक्ष, एनएबीएल



श्री रिज़वान कोइता

अध्यक्ष, एनएबीएच

स्वास्थ्यचर्या क्षेत्र में निरंतर बदलाव हो रहे हैं और गुणवत्ता एवं रोगी संरक्षा पर मजबूती से ध्यान केन्द्रित करते हुए, इस बदलाव को आत्मसात करने में एनएबीएच की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-2025, मुख्य प्रत्यायन प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करने और अस्पतालों एवं स्वास्थ्यचर्या प्रदाताओं का सहयोग करने के नए तरीके तलाशने - दोनों में - अधिगम, सहकार्य और निर्णायक कदमों का वर्ष रहा है।

इस वर्ष के दौरान, एनएबीएच ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण और ऐसे व्यावहारिक अपडेट के समावेशन पर काम किया जो अलग-अलग स्तरों पर स्वास्थ्यचर्या प्रदाताओं का सहयोग करते हैं। अन्य प्रमाणन और आकलन कार्यक्रमों के विस्तार के साथ-साथ एनएबीएच प्रत्यायन मानकों के छठे संस्करण का शुभारंभ, इनमें से एक प्रमुख उपलब्धि थी। ये अपडेट हितधारकों से प्राप्त फीडबैक से निर्देशित हैं तथा हमारे अस्पतालों और स्वास्थ्यचर्या प्रणालियों की उभरती जरूरतों को प्रतिबिंबित करते हैं।

हमने नए आकलनकर्ता प्रशिक्षणों, जागरूकता सत्रों और स्वास्थ्यचर्या प्रदाताओं के साथ सीधे संपर्क-संवाद के माध्यम से क्षमता निर्माण पर निरंतर ध्यान केन्द्रित किया है। इस दिशा में गुणवत्ता मंथन, अस्पताल नेतृत्व गोलमेज जैसी पहलों का सहयोग मिला, जिससे संस्था प्रमुखों को गुणवत्ता और प्रत्यायन से जुड़ी चुनौतियों और सहकारी समाधानों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच पर लाया जा सका। हमारे संपर्क-विस्तार कार्य को आगे बढ़ाते हुए, गुणवत्ता यात्रा ने एनएबीएच के गुणवत्ता संदेश को देश भर के अस्पतालों और स्वास्थ्यचर्या संस्थानों तक पहुंचाने में मदद की, जिससे जमीनी स्तर पर संवाद-संपर्क, जागरूकता और सहयोग का अवसर मिल सका।

डिजिटल क्षेत्र में, अस्पतालों के लिए एनएबीएच डिजिटल स्वास्थ्य मानकों (डीएचएस) तथा अस्पताल सूचना प्रणाली (एचआईएस) और इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा रिकॉर्ड (ईएमआर) संबंधी मानकों को मजबूती से अपनाया जाने लगा है। अब पहले से अधिक अस्पताल प्रमाणन के लिए आवेदन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर विक्रेताओं ने अपने सिस्टम को एनएबीएच रूपरेखा के अनुरूप बना लिया है। हमने एनएबीएच प्रवेश-स्तरीय प्रमाणित अस्पतालों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रमाणन कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम से, अपेक्षाकृत छोटे अस्पतालों को अपनी डिजिटल यात्रा के सुदृढ़ीकरण के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं1 इन्हें शीघ्र से शीघ्र अपनाए जाने को उत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन शुरू किए गए और इन कार्यक्रमों को पहले से अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुल्क संरचना में संशोधन किए गए।

यह वर्ष भी नई भागीदारियों और सहकार्य का साक्षी रहा जो स्वास्थ्यचर्या में मानकों के उन्नयन के हमारे साझा लक्ष्य के अनुरूप हैं। इनमें एनएबीएच द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण गतिविधियों के आयोजन के लिए एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई), रोगी संरक्षा माइक्रोसाइट के लिए नेटहेल्थ, मधुमेह मानकों के लिए आरएसएसडीआई, और कई अन्य को साथ लेकर किए गए प्रयास शामिल हैं। ये भागीदारियां, वृहत्तर पारिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी।

एनएबीएच का कार्य, देश के विकसित भारत 2047 के विज़न से काफी निकटता से जुड़ा हुआ है, जहां स्वास्थ्यचर्या एक आधारभूत भूमिका निभाती है। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे हम व्यावहारिक, समावेशी और भविष्य के लिए तत्पर गुणवत्तापूर्ण प्रणालियों के माध्यम से अस्पतालों और स्वास्थ्यचर्या प्रदाताओं को सशक्त बनाकर, इस राष्ट्रीय लक्ष्य में सार्थक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध बने हुए हैं।

मैं, इस अवसर पर एनएबीएच टीम, हमारे आकलनकर्ताओं और अपने सभी भागीदारों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके समर्पण और प्रयास रोगी देखभाल के स्तर पर प्रभाव डाल रहे हैं, जहां इसका महत्व बहुत अधिक है। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं भविष्य में आपके साथ और अपडेट एवं उपलब्धियां साझा करने के लिए उत्सुक हूं।

सादर,

हस्ता./-

श्री रिज़वान कोइता

अध्यक्ष, एनएबीएच



श्री पी. आर. मेहता
अध्यक्ष, एनएबीईटी

2024-25 का वर्ष, एनएबीईटी के लिए समेकन का एक निर्णायक वर्ष रहा है, जिसमें साहसिक और रणनीतिक निर्णय आवश्यक हो गए थे। इन निर्णयों में, एक व्यापक पुनर्गठन पहल के भाग के रूप में अपने एक सबसे मजबूत विभाग को छोड़ने का मुश्किल किंतु अत्यावश्यक निर्णय भी शामिल है। यह निर्णायक कार्रवाई, एनएबीईटी के दीर्घकालिक विज़न और संस्थागत स्थायित्व के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता की द्योतक है।

ऐतिहासिक रूप से, एनएबीईटी ने उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में कार्य किया है, किंतु इसकी प्राथमिक पहचान शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में ही रही है। अपने फोकस को सुचारु करने और एमएसएमई लीन वर्टिकल को छोड़ने से, एनएबीईटी इन क्षेत्रों में ज्ञान, नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध एक अग्रणी संस्थान के रूप में अपनी पहचान की पुन: पुष्टि कर रहा है।

एनएबीईटी के औपचारिक शिक्षा उत्कृष्टता प्रभाग (एफईईडी) ने शैक्षिक रूपांतरण को आगे बढ़ाने में अपनी नेतृत्व क्षमता का निरंतर प्रदर्शन किया है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, एफईईडी ने प्रत्यायन, क्षमता निर्माण और गुणवत्ता सुधार पहलों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने विभिन्न सरकारी और लोक वित्तपोषित स्कूलों का बड़े पैमाने पर आकलन और मूल्यांकन किया है, जिनमें, अन्य के साथ-साथ आश्रम स्कूल, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, पीसीएमसी द्वारा संचालित स्कूल और नासिक के स्कूल शामिल हैं। इन प्रयासों से शिक्षण मानकों के उन्नयन, जवाबदेही को बढ़ावा देने और निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है।

इस वर्ष स्वास्थ्यचर्या शिक्षा में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। पहली बार, एफईईडी ने होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी, और नर्सिंग मेडिकल कॉलेजों के आकलन और रेटिंग का नेतृत्व किया। इस पहल ने चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता का नया बेंचमार्क स्थापित करते हुए, पारदर्शिता और प्रणाली-विशिष्ट मानकों की शुरूआत की।

पर्यावरण एवं अन्वेषण प्रभाग ने अपनी स्थापना के बाद से काफी विकास किया है, जहां इसने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) परामर्शदाता संगठनों के प्रत्यायन में अग्रणी भूमिका निभाई। आज, अन्वेषण एवं खनन योजना परामर्शदाताओं का प्रत्यायन शामिल करने के लिए इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है, जो स्थायित्व परिदृश्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। एनएबीईटी वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरणीय अखंडता के रक्षोपाय करने के अपने कर्तव्य के प्रति अडिग बना हुआ है।

राष्ट्रीय प्रगति के लिए अनुसंधान एवं विकास अति महत्वपूर्ण हैं तथा भारत में सरकारी सहायता और उद्योग-अकादमिक सहकार्य के माध्यम से इस क्षेत्र में मजबूत प्रगति दिख रही है। एनएबीईटी का अनुसंधान, विश्लेषण और क्षमता निर्माण प्रभाग विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं के मूल्यांकन और संवर्धन के लिए आईजीएसटीसी की 2+2 द्विपक्षीय परियोजनाओं और आई-एसटीईएम राष्ट्रीय पोर्टल सहित प्रमुख पहलों के प्रभाव का आकलन कर रहा है।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (टीसीबी) और ईक्वेस्ट प्रभाग, विभिन्न स्तरों पर कार्यबल प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण जरूरत को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कौशल अंतराल को दूर करके और सक्षमता विकास को बढ़ाकर, ये प्रभाग भारत की मानव पूंजी के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

अपनी बात पूरी करने से पहले, मैं एनएबीईटी बोर्ड के सदस्यों और सलाहकार समिति के प्रति उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं, एनएबीईटी सचिवालय को भी बोर्ड के विज़न के कार्यान्वयन में उनके समर्पण और अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं।

हम सब मिलकर, बदलाव के साथ सामंजस्य स्थापित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। एनएबीईटी एक स्पष्टतर फोकस और नवीन उद्देश्य के साथ, समाज पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालते हुए, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में एक स्थायी विरासत छोड़ने के लिए तत्पर है।

हस्ता/-

श्री पी. आर. मेहता
अध्यक्ष, एनएबीईटी



डॉ. रवि प्रकाश सिंह
अध्यक्ष, एनएबीसीबी

नमस्कार!

एनएबीसीबी, देश के गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोर्ड है, क्योंकि यह उत्पादों, प्रक्रियाओं, सेवाओं और प्रणालियों में गुणवत्ता की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और सम्मानित प्रक्रिया-संचालित आश्वासन प्रणाली उपलब्ध कराता है।

वित्त वर्ष 2024-25 में प्रगति और उद्देश्यपूर्ण भागीदारी का एक और वर्ष जैसे-जैसे पूरा हो रहा है, वैसे-वैसे मैं, राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) की गतिशील यात्रा पर विचार करते हुए, अत्यधिक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पिछले एक वर्ष में, एनएबीसीबी ने विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्दिष्ट अनुरूपता आकलन सेवाओं को बढ़ावा देते हुए, भारत की गुणवत्ता अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में अपनी महत्ता लगातार मजबूत की है।

इस वर्ष, एनएबीसीबी ने विधिमान्यकरण और सत्यापन के लिए आईएएफ की बहुपक्षीय मान्यता व्यवस्था (एमएलए) का हस्ताक्षरकर्ता बनकर और इसके साथ ही ईओएमएस तथा एफएएमआई-क्यूएस जैसे अपेक्षाकृत नए उप-क्षेत्रों के लिए एपीएसी एमआरए का दर्जा हासिल करके एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। एनएबीसीबी ने आईएसओ/आईईसी 42001:2023 प्रमाणनों के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रबंधन प्रणाली (एआईएमएस) के लिए प्रत्यायन स्कीम भी शुरू की है।

विनियामकों और मंत्रालयों - जिनमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र (टीईसी), और विद्युत मंत्रालय शामिल हैं - के साथ व्यापक सहकार्य के जरिए, एनएबीसीबी ने विनियामक अनुपालन के आधार के रूप में प्रत्यायन अनुरूपता आकलन को शामिल करने के लिए सतत प्रयास किए हैं। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग और स्थायित्वपूर्ण विमानन ईंधन प्रमाणन रूपरेखा के माध्यम से सरकार की जलवायु संबंधी कार्यसूची में सहयोग करने की हमारी भूमिका, राष्ट्रीय नीतिगत पहलों में प्रत्यायन की बढ़ती प्रासंगिकता की पुष्टि करती है।

मॉरीशस प्रत्यायन सेवा (मॉरीटास) के लिए क्षमता निर्माण परियोजनाओं, अंतरराष्ट्रीय मंचों (आईएएफ, आईएलएसी, एपीएसी) में भागीदारी और एफएसएससी, आईएससीसी, वेरा, आईएफएस, एसईआरआई और बीआरसीजीएस जैसे अंतरराष्ट्रीय स्कीम स्वामियों के साथ तकनीकी सहयोग से एनएबीसीबी की पहुंच का वैश्विक स्तर पर विस्तार हुआ है। गुणवत्ता मंथन और गुणवत्ता समृद्धि जैसी पहलें; बीएचईएल, डीएमआरसी, रिलायंस जियो, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, एलएंडटी एनर्जी, सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड और केडीडीएल लिमिटेड जैसे संगठनों के साथ संपर्क-संवाद ने हमें उद्योग हितधारकों की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें पूरा करने में मदद की है।

प्रशिक्षण और आकलनकर्ता विकास, हमारी गुणवत्ता आश्वासन रणनीति का प्रमुख आधार बना रहा। इसके अंतर्गत एयरोस्पेस क्यूएमएस, एफएएमआई-क्यूएस जैसी क्षेत्रविशिष्ट स्कीमों और विभिन्न प्रत्यायन मानकों को शामिल करते हुए, अनेक मानकों में आकलनकर्ता की सक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक दर्जन से अधिक राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए गए।

जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो, भारत जैसे-जैसे व्यापार और नवाचार में अपनी वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ बना रहा है, वैसे-वैसे एनएबीसीबी सभी क्षेत्रों तक, विशेष रूप से एमएसएमई की सहायता करने, ईएसजी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और एआई एवं साइबर सुरक्षा जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में समावेश करने के लिए गुणवत्ता और प्रत्यायित अनुरूपता आकलन की पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध बना हुआ है।

आइए, हम भारत के लिए एक विश्वसनीय, उत्थानशील और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रत्यायन रूपरेखा के निर्माण की इस यात्रा में मिलकर आगे बढ़ें।

सभी हितधारकों को शुभकामनाएं कि आने वाला वर्ष, हम सबके लिए सफल और प्रभावशाली रहे।

हस्ता/-

डॉ. रवि प्रकाश सिंह
अध्यक्ष, एनएबीसीबी



श्री विपिन सोंधी
अध्यक्ष, एनबीक्यूपी

राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड (एनबीक्यूपी), गुणवत्ता की ऐसी संस्कृति जो भारत में जीवन के हर पहलू को प्रभावित करे, विकसित करने के उद्देश्य, जुनून और अटूट प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। हम, नवाचार और सहयोग को अपनी प्रगति का आधार स्तंभ मानते हुए, काम करने, शिक्षित करने और सशक्त बनाने के अपने मिशन में दृढ़ हैं। हमारे अध्यक्ष श्री जक्षय शाह के दूरदर्शी मार्गदर्शन में और हमारे महासचिव श्री चक्रवर्ती टी. कन्नन के गतिशील नेतृत्व में, हम केवल मानकों को आगे नहीं बढ़ा रहे है बल्कि हम एक गुणवत्ता आंदोलन का सृजन कर रहे हैं जिसकी प्रतिध्वनि जमीनी स्तर के समुदायों से लेकर राष्ट्रीय संस्थानों तक सुनाई दे।

इस वर्ष, एनबीक्यूपी ने विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों के अनुरूप विविध पहलों के माध्यम से अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार किया है। हमारी प्रत्येक परियोजना, जीवन शैली के रूप में गुणवत्ता को शामिल करने, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता, संरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ करने की दिशा में बढ़ा हुआ कदम रही है।

हमने क्वालिटी समर फनकैंप के दूसरे संस्करण की शानदार सफलता देखी जो 'सेफ्टी स्टार्स: शाइनिंग ब्राइट विद क्वालिटी' विषय के अंतर्गत संरक्षा पर केन्द्रित था। इसमें सभी 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के 13,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ हमारे सहकार्य तथा शिक्षा बोर्डों और मंत्रालयों के व्यापक समर्थन से, हमने अपने सबसे युवा नागरिकों में महत्वपूर्ण जीवन कौशल विकसित किए।

गुणवत्ता भारत प्रकोष्ठ (क्यूबीसी) का शुभारंभ, गुणवत्ता के भावी अग्रदूत तैयार करने की दिशा में एक अग्रणी कदम रहा है। पांच पायलट स्कूलों और सैकड़ों प्रशिक्षित विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के साथ की गई यह पहल, शिक्षा और समाज में उत्कृष्टता के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक पीढ़ीगत बदलाव की नींव रख रही है।

इस बार गुणवत्ता माह की जगह गुणवत्ता पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान देशव्यापी प्रतियोगिताओं, जन भागीदारी और जागरूकता अभियानों के माध्यम से गुणवत्ता मूल्यों का एक सशक्त, संवादपरक उत्सव मनाया गया। इसी तरह, गुणवत्ता संकल्प गुजरात से लेकर नगालैंड तक के राज्यों में पहुंचा तथा इसने सरकार, स्वास्थ्यचर्या, उद्योग और सिविल सोसाइटी के हितधारकों को एक साथ लाकर सेक्टोरल सुधार और नवाचार को बढ़ावा दिया।

गुणवत्ता मंथन के माध्यम से, हमने अपने बोर्डों और प्रभागों के हितधारकों के साथ गहन चिंतन और सहकार्य के लिए एक व्यवस्थित मंच तैयार किया। इन वार्ताओं से रणनीतिक नियोजन को ऊर्जा मिली है और यह सुनिश्चित हुआ है कि हमारे प्रयास हमारे समुदायों और उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जुड़े रहें।

इसके साथ ही गुणवत्ता यात्रा, स्वास्थ्यचर्या और विनिर्माण में गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने की एक रणनीतिक पहल है। यह यात्रा, क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से हितधारकों को प्रत्यायन और प्रमाणन के लिए जरूरी ज्ञान से युक्त बनाती है। मार्च 2025 तक, पूरे भारत में 48 यात्राएं संचालित की गई हैं, जो सुविधा वंचित क्षेत्रों में गुणवत्ता को बढ़ावा देने की क्यूसीआई की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं। और 'मित्र' जैसी पहलों के साथ, हम छोटे स्वास्थ्यचर्या संगठनों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि वे एनएबीएच प्रमाणन प्राप्त कर सकें और सुविधा वंचित क्षेत्रों में गुणवत्ता को बेहतर बना सकें।

इस वर्ष, हमने संजीवनी पहल भी शुरू की। इस पहल का उद्देश्य, भारत की लुप्त होते जा रहे कला रूपों के समृद्ध चित्रपट को पुनर्जीवित करना है जो संस्कृति और गुणवत्ता का संगम। है इससे विकास के प्रति हमारी सर्वांगीण कार्यनीति रेखांकित होती है। इसके अलावा, प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालयों के साथ हमारी भागीदारी से अभिशासन उत्कृष्टता निरंतर बढ़ रही है। हमें ईईपीसी इंडिया क्वालिटी एंड ग्रीन अवार्ड्स को अपना सहयोग देने पर गर्व है, जो स्थायी और अनुकरणीय परिपाटियों का समर्थन करने वाले संगठनों को मान्य करते हैं।

MyGov के माध्यम से 29,000 से अधिक नागरिकों द्वारा ली गई गुणवत्ता भारत शपथ, हमारे आंदोलन: "गुणवत्ता अपनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे" की भावना को प्रतिबिंबित करती है।

हम जैसे-जैसे अगले वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, वैसे-वैसे हम इस साझा विश्वास से प्रेरित होते हैं कि गुणवत्ता कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक मन:स्थिति है। मैं टीम एनबीक्यूपी की, उनके असाधारण कार्य के लिए सराहना करता हूं, बोर्ड के हमारे सम्मानित सदस्यों के गहन और दृढ़ मार्गदर्शन की हार्दिक सराहना करता हूं, और सीईओ डॉ. ए. राज और टीम के प्रत्येक सदस्य के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिनके समर्पण से हमारा मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है।

आइए, हम सब मिलकर आगे बढ़ें, जहां गुणवत्ता एक लक्ष्य मात्र नहीं है, अपितु एक उज्ज्वल, अपेक्षाकृत मजबूत और अधिक विकसित भारत की दिशा में हमारी सामूहिक यात्रा का निश्चित आधार है।

हस्ता/-

विपिन सोंधी
अध्यक्ष, एनबीक्यूपी

क्यूसीआई
कार्य-क्षेत्र परिचय और पेशकश

क्यूसीआई
कार्य-क्षेत्र परिचय

- परिषद्, प्रमाणन/निरीक्षण/विधिमान्यकरण निकायों, परीक्षण/अंशशोधन/चिकित्सा प्रयोगशालाओं, अस्पतालों और स्वास्थ्यचर्या- प्रदाताओं तथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण/पर्यावरण क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय है।

- यह परिषद् सक्षम परीक्षण, प्रमाणन और निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से, भारत में गुणवत्ता अवसंरचना के इकोसिस्टम के सृजन की दिशा में प्रयासरत है।

- आईएएफ/आईएलएसी/एपीएसी एमआरए भागीदार देशों के बीच एनएबीसीबी/एनएबीएल प्रत्यायित संगठनों के प्रमाणन/निरीक्षण के साथ-साथ परीक्षण/अंशशोधन परिणामों की स्वीकृति देती है।

- अनुरूपता आकलन रूपरेखा के अभिकल्पन और विकास द्वारा सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता की पहुंच बना रही है।

- राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न परियोजनाओं का नेतृत्व करती है और भारत सरकार को, उसके ध्वजवाहक कार्यक्रमों के तीव्र गति से एवं बड़े पैमाने पर संचालन में सहायता प्रदान करती है।

- ई-क्वेस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से 100 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम प्रस्तुत करके और पेशेवरों को गुणवत्ता अनुशिक्षक के नेतृत्व में संचालित प्रशिक्षण प्रदान करके हर स्तर पर गुणवत्ता को बढ़ावा देती है।

- गुणवत्ता के प्रमुख पहलुओं के बारे में प्रेरणा, शिक्षा, सुगमता और आकलन की सुविधा उपलब्ध कराके हितधारकों के बीच गुणवत्ता के प्रति जागरूकता का स्तर बढ़ाती है।

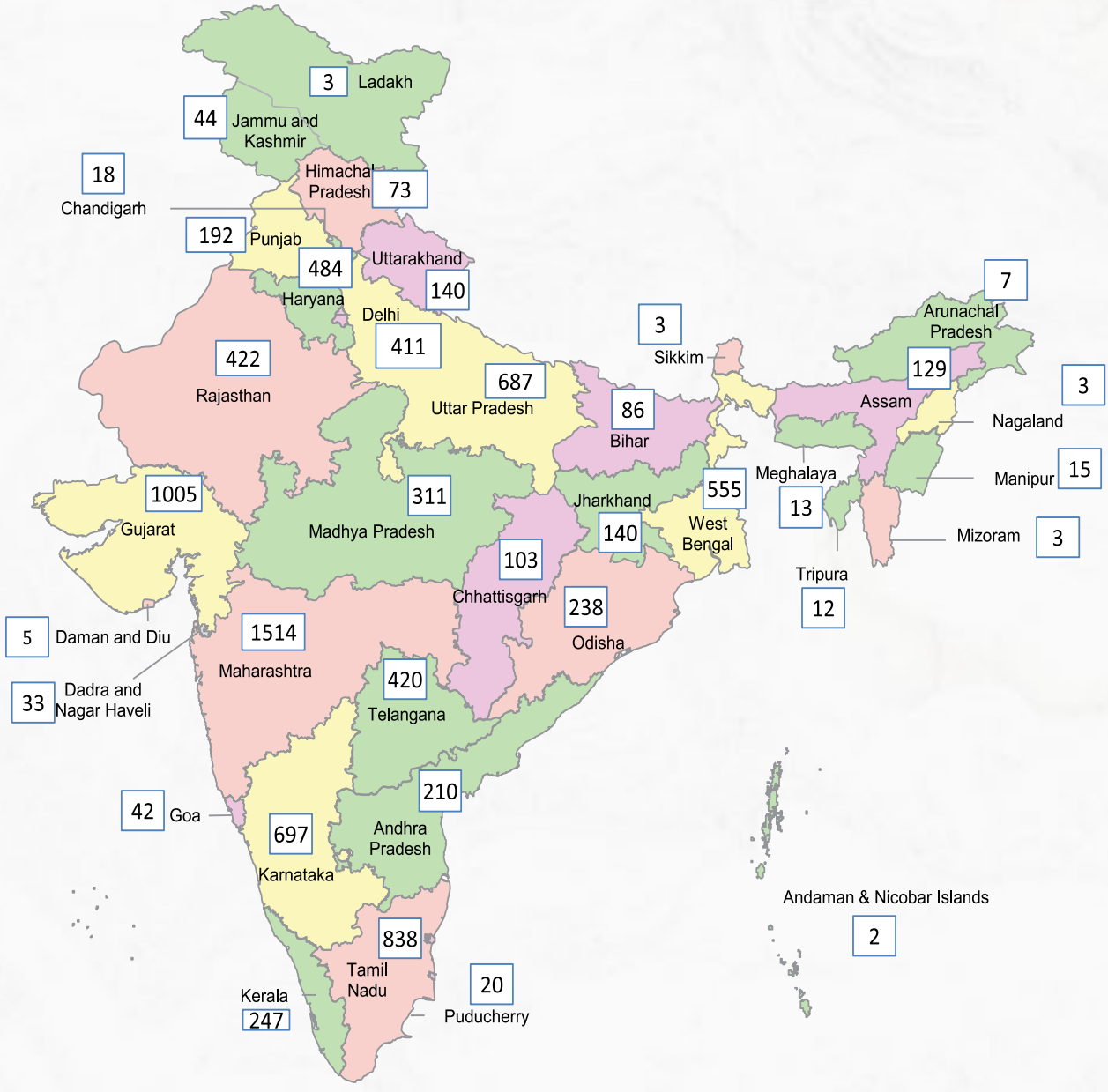
क्यूसीआई की पेशकश

स्थापित और प्रचालित करना	राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रम	एनएबीसीबी, एनएबीएल, एनएबीएच, एनएबीईटी
संचालित करना	गुणवत्ता को मापने के लिए अन्य पक्ष से आकलन	पीपीआईडी (प्रत्यायित अनुरूपता आकलन निकायों के माध्यम से)
चलाना	एक राष्ट्रव्यापी गुणवत्ता अभियान	एनबीक्यूपी
उत्प्रेरित करना	भारतीय उद्योग में स्पर्धात्मकता	एनडीआईई
विकसित करना	उभरते क्षेत्रों में गुणवत्ता के लिए क्षमता	पीएडीडी
बढ़ाना	सरकारी कार्य-क्षमता में गुणवत्ता	एसपीडी



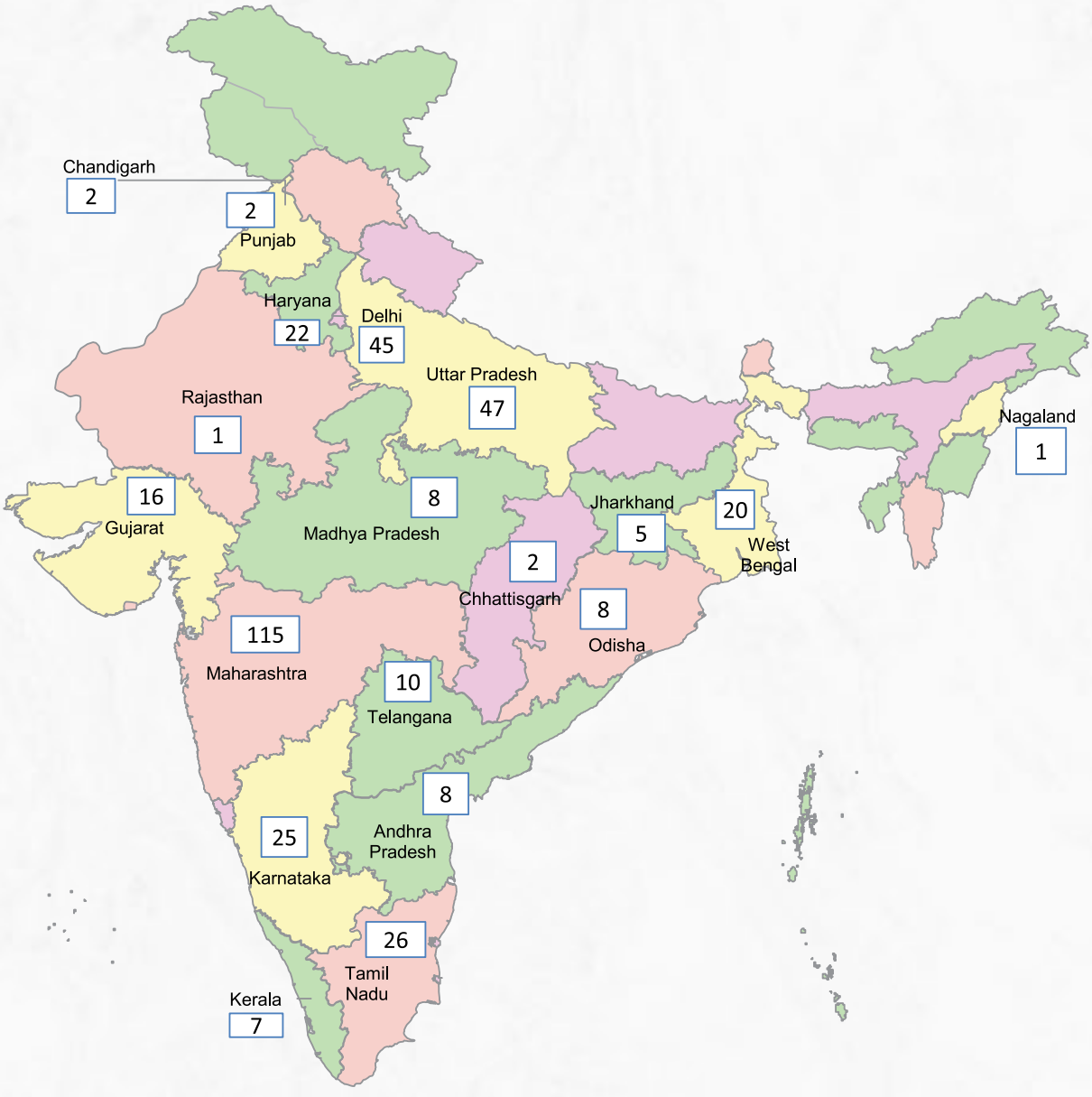
क्यूसीआई की अखिल भारतीय उपस्थिति

राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)



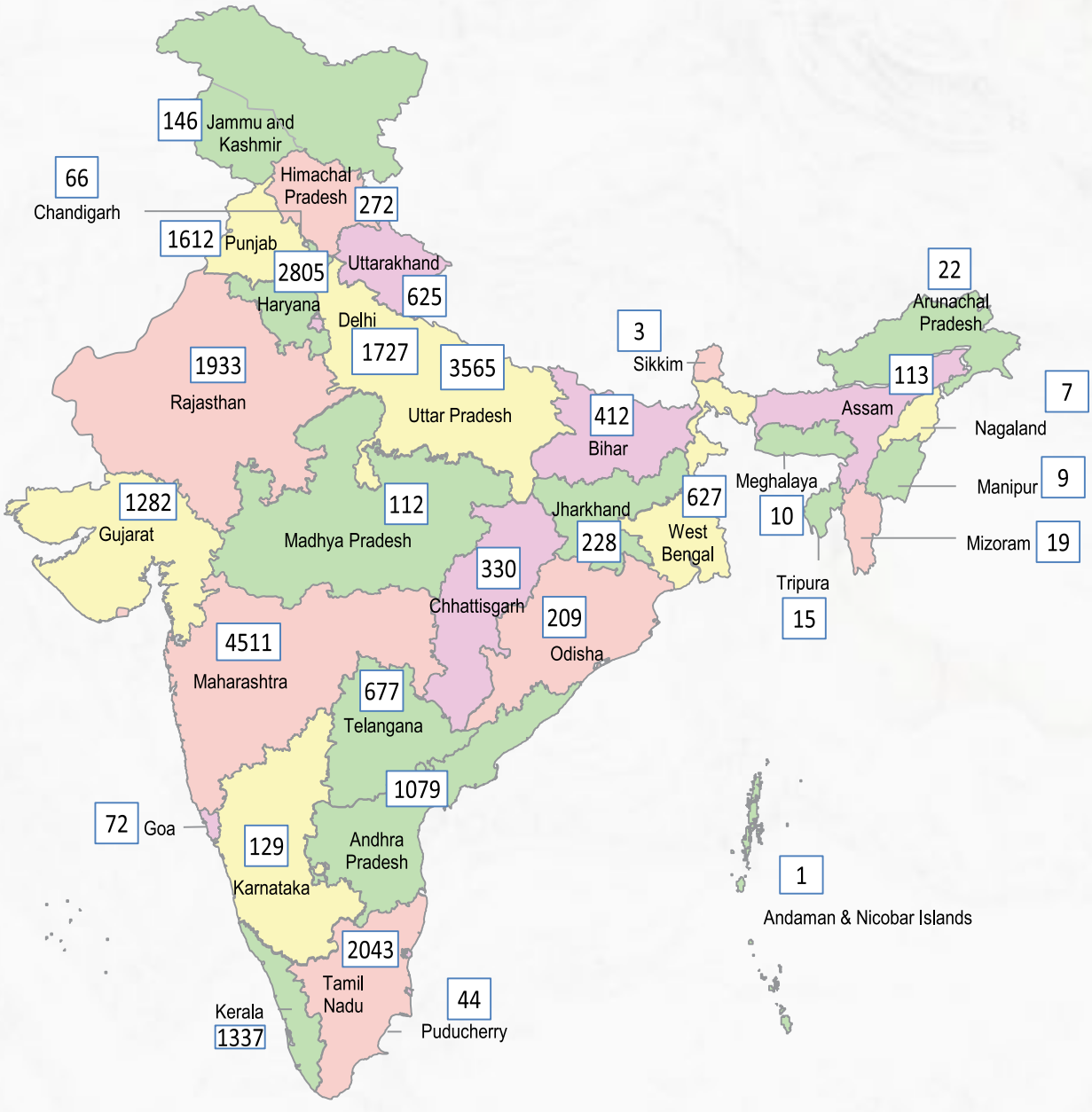
एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाएं

राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय
प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी)



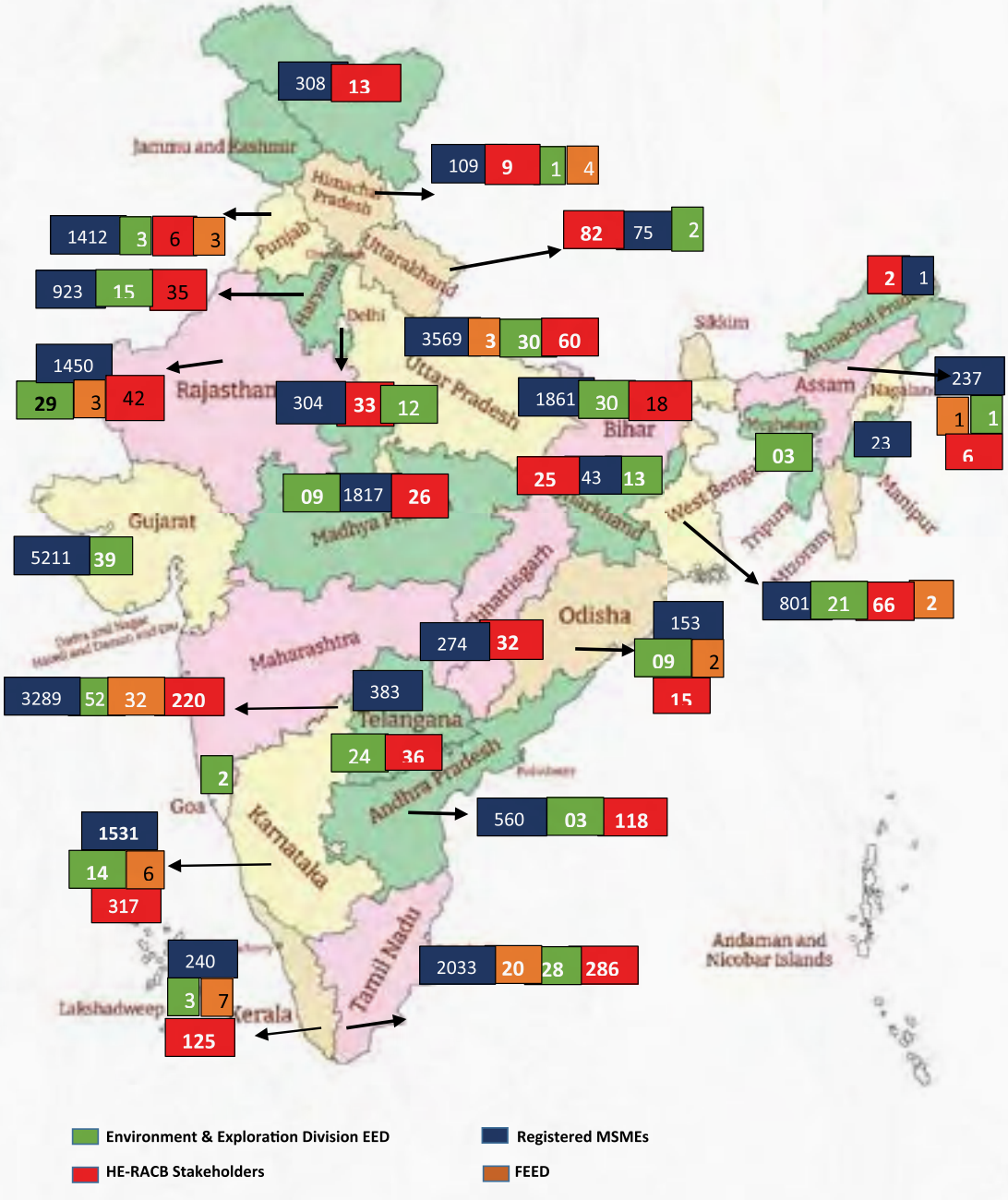
एनएबीसीबी प्रत्यायित अनुरूपता आकलन निकाय

राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्यचर्या-प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच)



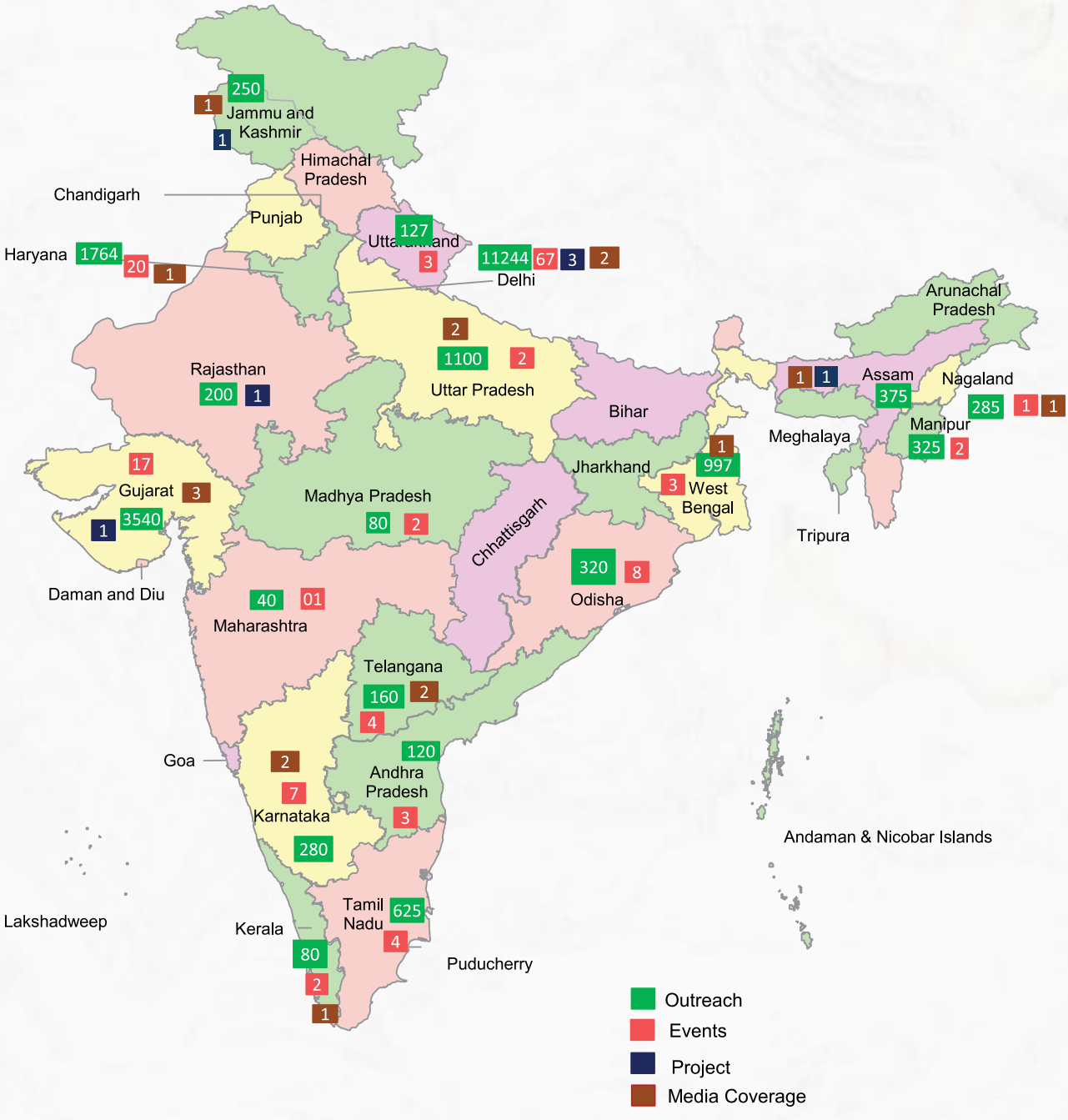
एनएबीएच प्रत्यायित/ प्रमाणित/सूचीबद्ध अस्पताल और स्वास्थ्यचर्या- प्रदाता

राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी)



एनएबीईटी प्रत्यायित स्कूल और प्रत्यायित परामर्शदाता संगठन

राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड (एनबीक्यूपी)



वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निष्पादित प्रमुख कार्य

अंतरराष्ट्रीय मान्यताएं

- एनएबीएल ने निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों के लिए एपीएसी एमआरए हस्ताक्षरकर्ता का अपना दर्जा कायम रखा:

  1. परीक्षण आईएसओ / आईईसी 17025;
  2. अंशशोधन आईएसओ / आईईसी 17025;
  3. चिकित्सा परीक्षण आईएसओ-15189;
  4. संदर्भ सामग्री उत्पादक आईएसओ 17034;
  5. निपुणता परीक्षण प्रदाता आईएसओ / आईईसी 17043

- एनएबीसीबी को विधिमान्यकरण और सत्यापन के लिए आईएएफ एमएलए (इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम इनकॉरपोरेटिड मल्टीलेटरल रिकॉगनीशन अरेंजमेंट) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है, जो प्रत्यायन सेवाएं प्रदान करने की उसकी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करता है।

  मान्यता के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं:

  - मुख्य कार्यक्षेत्र: विधिमान्यकरण और सत्यापन - आईएसओ/आईईसी 17029
  - स्तर 4 उप- कार्यक्षेत्र : आईएसओ 14065:2020 / आईएसओ14066 / आईएसओ 14064-3
  - स्तर 5 उप- कार्यक्षेत्र : आईएसओ 14064-1 / आईएसओ 14064-2

- **एनएबीसीबी को ईओएमएस और एफएएमआई-क्यूएस के लिए अंतरराष्ट्रीय समकक्षता प्राप्त है।**

  एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (एपीएसी) ने हाल ही में निम्नलिखित उप-कार्यक्षेत्रों के प्रयोजन से एनएबीसीबी के लिए अपने एमआरए हस्ताक्षरकर्ता के दर्जे की पुष्टि की है:

  - शिक्षा संगठन प्रबंधन प्रणाली (ईओएमएस);
  - विशेष फ़ीड घटकों के लिए गुणवत्ता और संरक्षा प्रणाली (एफएएमआई-क्यूएस)

उपलब्धियां और बढ़त

- सफल निपुणता परीक्षण भागीदारी के आधार पर एनएबीएल चिकित्सा (प्रवेश स्तरीय) परीक्षण प्रयोगशाला कार्यक्रम के तहत 2964 प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई।

- जल शक्ति मंत्रालय, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भारत सरकार की 489 (121 नए प्रत्यायन के साथ) जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन प्रदान किया गया। जी-एलएपी प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत कुल 855 (248 नई मान्यताओं के साथ) जल परीक्षण प्रयोगशालाएं।

- मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कार्यक्रम के तहत 433 मान्यताएं प्रदान की गईं।

- 31.03.2025 तक प्रत्यायित सीएबी की संख्या: 9142 (टी - 5755, सी -1152, एम -2146, पीटीपी -69, आरएमपी -20) है।

- डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एक्स रे उपकरण गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण एजेंसियों के विशिष्ट क्षेत्र में 119 प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन प्रदान किया गया।

- **एनएबीसीबी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रबंधन प्रणालियों के लिए पहला प्रत्यायन प्रदान किया**

  एनएबीसीबी ने अब टीयूवी इंडिया को आईएसओ/आईईसी **42001** प्रमाणन के लिए अपना पहला एआईएमएस प्रत्यायन प्रदान किया है। आईएसओ/आईईसी **42001** दुनिया का पहला एआई प्रबंधन प्रणाली मानक है, जो संगठनों के अंदर एआईएमएस की स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और निरंतर सुधार के लिए अपेक्षाएं निर्दिष्ट करता है, एआई से जुड़े जोखिमों और अवसरों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तरीका उपलब्ध कराता है और नवाचार तथा अभिशासन के बीच संतुलन स्थापित करता है।

- एनएबीएच ने **3672** स्वास्थ्यचर्या- प्रदाताओं को प्रत्यायित/ प्रमाणित किया, ईसीएचएस और सीजीएचएस पैनलबद्धता के लिए **750** अस्पतालों का निरीक्षण किया और स्वास्थ्यचर्या पेशेवरों के लिए **111** प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

- पेपरलेस इनिशिएटिव की दिशा में एक कदम के रूप में, एनएबीएच ने पूरी तरह से डिजिटल पोर्टलों पर काम करना शुरू किया और सभी आवेदकों को पोर्टल पर शामिल कर लिया गया तथा आयुष एंट्री लेवल प्रोग्राम, सीजीएचएस/ईसीएचएस एम्पैनलमेंट स्कीमों, अस्पताल और एसएचसीओ प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत एचसीओ एवं एसएचसीओ को प्रत्यायन प्रदान किया।

- **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) का निरीक्षण:**

  एनसीएच ने, देशभर में स्थित 101 होम्योपैथिक कॉलेजों और अस्पतालों के निरीक्षण का कार्य एनएबीएच को सौंपा था जिसे

एनएबीएच ने एनसीएच द्वारा नियत समय के अंदर पूरा किया। ये निरीक्षण, एनसीएच द्वारा उपलब्ध कराई गई अपेक्षाओं के अनुसार किए गए और इनकी रिपोर्टें राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को प्रस्तुत कर दी गई हैं।

- **डिजिटल स्वास्थ्य पहल:** एनएबीएच डिजिटल स्वास्थ्य पहल दक्षता, सुलभता और देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्यचर्या प्रणालियों में प्रौद्योगिकी का समावेश करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

  डिजिटल परिवर्तन को अपनाकर, स्वास्थ्यचर्या प्रदाता रोगी परिणामों में सुधार कर सकते हैं, संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर सकते हैं और स्वास्थ्यचर्या तक पहुंच में आने वाली भौगोलिक बाधाओं को दूर कर सकते हैं।

- **एनएबीएच- डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स** ई-क्वेस्ट पोर्टल पर 26 जुलाई 2024 से चल रहा है; अब तक 280 पंजीकरण और प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं।

- **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) का निरीक्षण:** एनएबीएच ने मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के निर्णय के अनुसार, एनसीएच द्वारा प्रशिक्षित निरीक्षकों का उपयोग करके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण संपन्न किया।

- **एनएबीएच रणनीतिक बैठक समन्वयन:** एनएबीएच वार्षिक रणनीतिक बैठक 28 से 30 मार्च, 2024 तक गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आयोजित की गई। यह वार्षिक रणनीतिक बैठक 2024- समन्वयन, राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्यचर्या-प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) द्वारा आयोजित की गई, जो एक तीन दिवसीय समृद्ध कार्यक्रम के रूप में सामने आई।

- **एनएबीएच-एईएलसी पहल:** एनएबीएच का उद्देश्य, स्वास्थ्यचर्या प्रणाली को पूरे भारत में जमीनी स्तर पर सुदृढ़ करना है। इसमें यह सुनिश्चित करना ही शामिल नहीं है कि जनता को उचित सेवा प्रदान की जाए, बल्कि इसके लिए कार्यबल को पर्याप्त प्रशिक्षण देना भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य विद्यमान अवसंरचना को उन्नत करना और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना है जो रोगी स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दे।

  एनएबीएच द्वारा भारत भर में 1371 आयुष स्वास्थ्य तथा आरोग्य केन्द्र/आरोग्य मंदिर प्रमाणित किए गए हैं।

  अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, कश्मीर, उत्तराखंड, असम और मिजोरम सहित पूरे भारत में **2005 से अधिक एएचडब्ल्यूसी का आकलन** किया गया है।

- **एलोपैथिक क्लीनिकों के लिए एनएबीएच मानकों का द्वितीय संस्करण:** इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, 2023 में जारी किए गए एलोपैथिक क्लीनिक मानकों के दूसरे संस्करण में डे केयर यूनिट, स्वतंत्र त्वचाविज्ञान क्लीनिक और डायलिसिस केन्द्र जैसी विशेष देखभाल सेवाएं शामिल करने के लिए मूल फ्रेमवर्क का विस्तार किया गया है।

- **एनएबीएच रोगी संरक्षा सम्मेलन 2024:** एनएबीएच ने 17 सितंबर को "एक स्वस्थ देश, विकसित भारत के लिए" विषय पर 'एनएबीएच रोगी संरक्षा सम्मेलन' आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 7 पैनल चर्चाएं शामिल थीं जिनमें देश भर के 1,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।

- **हितधारकों के साथ सहकार्य:** एनएबीएच ने मधुमेह-विशिष्ट मानक विकसित करने, ईएमआर और सीएमएस मानकों के संरेखण और देश भर में रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया (आरएसएसडीआई) के 12,000 से अधिक सदस्यों वाले नेटवर्क में एनएबीएच एलोपैथिक क्लिनिक मानक लागू करने के लिए आरएसएसडीआई के साथ मिलकर काम किया।

- **गुजरात गुणवत्ता संकल्प**

  सर्वांगीण गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता हस्तक्षेपों के माध्यम से राज्य सरकार की पहलों को बढ़ाने और सहयोग देने की यह एक महत्वपूर्ण पहल है। यह पहल, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रयास को दर्शाती है। अहमदाबाद में आयोजित गुजरात गुणवत्ता संकल्प में 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें गुजरात सरकार और उद्योग जगत के 43 वक्ता शामिल थे।

- **क्वालिटी समर फनकैंप**

  ऑनलाइन क्वालिटी समर फनकैंप (क्यूएसएफसी), विद्यार्थियों को एक मज़ेदार, संवादपरक कार्यनीति के माध्यम से गुणवत्ता से संबंधित अधिगम में आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य, गुणवत्ता के प्रति युवा मन में जिज्ञासा जगाना और गुणवत्ता की समझ को गहरा करना है। विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों के माध्यम से, दैनिक जीवन में गुणवत्ता के महत्व को परखते हुए बच्चों को अपनी रचनात्मकता, प्रतिभा और ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

  सभी 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के 13,000 से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया।

- एनबीक्यूपी, हितधारकों के एक बड़े वर्ग तक पहुंच स्थापित करने, प्रतिस्पर्धी वैश्विक वातावरण में सफलता के लिए अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण परिपाटियों की गहन समझ और व्यापक अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कार्यक्रमों और **क्यूसीआई संचालित सत्रों (क्यूपीएस)** का आयोजन करता है। **वित्त वर्ष 2024-25 में, एनबीक्यूपी ने विभिन्न उद्योग संघों के साथ ऐसे 21 क्यूपीएस में भाग लिया।**

➤ **गुणवत्ता जागरूकता कार्यशाला**, जो इस तरह डिजाइन की गई है कि यह स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होने के साथ ज्ञानवर्धक भी हो। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य, युवा शिक्षार्थियों में साफ-सफाई, पर्यावरण संरक्षण, समस्या-समाधान कौशल, उपकरण/तकनीक, गुणवत्ता के आधारिक तत्व, संरक्षा, समानुभूति जैसे प्रकरणों और अन्य मूलभूत विषयों के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना पैदा करना है। **वित्त वर्ष 2024-25 में, एनडीएमसी स्कूलों, गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों और अन्य सरकारी/निजी विद्यालयों में 57 कार्यशालाएं संचालित की गई हैं।**

➤ एनबीक्यूपी-क्यूसीआई, सरकार/विभागों की उनके विभिन्न फ्लैगशिप पुरस्कारों में सहायता करता है और इसके निष्पादन के लिए एनबीक्यूपी ने पीएमयू की स्थापना की है। एनबीक्यूपी ने ऐसे 7 पुरस्कारों में सहायता प्रदान की है।

➤ **नगालैंड गुणवत्ता संकल्प:**

सर्वांगीण गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता हस्तक्षेप के माध्यम से राज्य सरकार की पहलों को बढ़ाने और उनमें सहयोग करने की यह एक महत्वपूर्ण पहल है। यह, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित एक महत्वपूर्ण प्रयास को दर्शाती है। कोहिमा में नगालैंड गुणवत्ता संकल्प में **125 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें नगालैंड सरकार और उद्योग क्षेत्र से 23 वक्ता** शामिल थे।

➤ **गुणवत्ता भारत प्रकोष्ठ (क्यूबीसी):**

देश भर में विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा देने की यह एक अग्रणी पहल है। यह पहल, विकसित भारत 2047 की संकल्पना के अनुरूप है और इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी को उत्कृष्टता के साथ नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना है। **इस समय 5 स्कूलों (जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा) में एक पायलट परियोजना चलाई जा रही है।**

➤ समग्र शिक्षा असम, असम सरकार के मिशन निदेशक के कार्यालय में **आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली)** संपन्न।

➤ **चिकित्सा और संबद्ध स्वास्थ्यचर्या संस्थानों का आकलन और रेटिंग:**

नीति आयोग के नेतृत्व में तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल के तहत, एनएबीईटी ने चिकित्सा और संबद्ध स्वास्थ्यचर्या शिक्षा संस्थानों का सर्वप्रथम आकलन और रेटिंग संचालित की।

एनएबीईटी और छह विनियामक निकायों के बीच एक औपचारिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए:

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी)
- भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई)
- भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम)
- राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच)
- भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी)
- भारतीय भेषज परिषद (पीसीआई)

वर्ष 2024-25 की पहल के एक भाग के रूप में, एनएबीईटी ने एनसीएच के अंतर्गत 240 होम्योपैथी कॉलेजों और एनसीआईएसएम के अंतर्गत 258 आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कॉलेजों का आकलन संचालित किया। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के प्रणाली-विशिष्ट आकलन का यह पहला उदाहरण था।

संबंधित विनियामकों द्वारा इस आकलन के परिणामों को आधिकारिक तौर पर प्रकाशित कर दिया गया है और ये परिणाम उनकी वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं, जो स्वास्थ्यचर्या शिक्षा में गुणवत्ता बेंचमार्किंग, पारदर्शिता और जवाबदेही में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाते हैं।

➤ **नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थाओं का आकलन और गुणवत्ता आश्वासन:**

नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा मानकों को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दो राज्यों में गहन आकलन संचालित किए गए:

- **उत्तर प्रदेश**: उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय (यूपीएसएमएफ) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए कुल 698 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण किया गया।
- **बिहार:** बिहार नर्स पंजीकरण परिषद (बीएनआरसी) द्वारा राज्य की पहली गुणवत्ता रेटिंग पहल के भाग के रूप में दो चरणों में कुल 315 नर्सिंग कॉलेजों का आकलन किया गया।

वृहत पैमाने पर किए गए ये मूल्यांकन, भारत में नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थाओं में गुणवत्ता आश्वासन, विनियामक अनुपालन और मानकीकरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

➤ **स्कूली शिक्षा-क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार पहल**

- **पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम (पीसीएमसी) में गुणवत्ता हस्तक्षेप:** इस परियोजना का उद्देश्य 128 पीसीएमसी स्कूलों में तीन-वर्षीय हस्तक्षेप मॉडल के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में सुधार करना है। आकलित विद्यार्थियों की कुल संख्या: 47,418 (आधारिक आकलन) और 42,291 (एंडलाइन आकलन); आकलित शिक्षकों की कुल संख्या: 965

- **क्वालिटी सिटी नासिक- शिक्षा परियोजना:** क्वालिटी सिटी नासिक परियोजना के अंतर्गत 22 स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का आकलन: आकलित विद्यार्थियों की संख्या: 5544 (आधारिक आकलन) और 4578 (एंडलाइन आकलन); आकलित शिक्षकों की संख्या: 271

- **आदिवासी स्कूलों और छात्रावासों का आकलन:** पांच राज्यों: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के 300 आश्रम स्कूलों और छात्रावासों का आकलन एवं मूल्यांकन किया गया। इसका उद्देश्य, स्थापित मापदंडों के आधार पर इन स्कूलों और छात्रावासों का आकलन करना, मौजूदा अंतरालों की पहचान करना, चिंता के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करना तथा इन स्कूलों और छात्रावासों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को सिफारिशें देना था।

➤ **क्षमता निर्माण आयोग के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (सीटीआई) और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) का आकलन:** 1 अप्रेल, 2024 और 31 मार्च, 2025 के बीच, कुल 52 संस्थानों ने सफलतापूर्वक प्रत्यायन और प्रमाणन प्राप्त किये। हालांकि, प्रत्यायित और प्रमाणित संस्थानों की कुल संख्या 146 है, जो प्रत्यायन और प्रमाणन प्रक्रिया में निरंतर प्रगति दर्शाती है।

➤ **पेशेवरों का प्रशिक्षण - राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और सरकारी अधिकारी**

- लगभग 5,913 पेशेवरों को पंजीकृत और प्रशिक्षित किया गया है।

- क्यूसीआई का मार्गदर्शन अभिमुखीकरण कार्यक्रम, जन स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए आईसीएमआर के नए भर्ती तकनीकी कर्मचारियों को आवश्यक कौशलों में प्रशिक्षित करता है। चार बैच पूरे हो जाने के साथ ही भारत के विभिन्न स्थानों से भर्ती 160 कर्मचारियों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

- क्यूसीआई और क्रेडाई ने गिफ्ट सिटी में एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें 1,000 से अधिक श्रमिकों को तकनीकी कौशल और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम का क्रेडाई कोच्चि में और विस्तार किया गया। क्रेडाई पुणे मेट्रो के लिए टीसीबी ने 'सर्वश्रेष्ठ शिविर पुरस्कार' के लिए श्रमिक शिविरों का आकलन किया।

- टीसीबी-एनएबीईटी ने, नेटहेल्थ के सहयोग से, वाराणसी, लखनऊ, पटियाला और अमृतसर में डीएचएमसी सत्रों का संचालन किया, जिनमें 229 स्वास्थ्यचर्या पेशेवरों को डिजिटल स्वास्थ्य परिपक्वता, एचएमआईएस/ईएमआर के अंगीकरण और अंतर-प्रचालनीयता विषय पर प्रशिक्षण दिया गया।

- यूनिसेफ ने कोलकाता में चार दिवसीय प्रशिक्षण प्रायोजित किया, जहां टीसीबी-एनएबीईटी ने 18 राज्यों के 83 प्रतिभागियों को एनजेजेएम प्रयोगशाला प्रदर्शन और जल गुणवत्ता परीक्षण में सुधार के लिए प्रशिक्षित किया।

➤ **पर्यावरण एवं अन्वेषण प्रभाग** ने लगभग 226 पर्यावरण प्रभाव आकलन परामर्शदाता संगठनों को प्रत्यायन प्रदान किया है, साथ ही 58 परामर्शदाता संगठनों को भी प्रत्यायन प्रदान किया जो कोयला क्षेत्र (कोयला मंत्रालय) और खनिज क्षेत्र (खान मंत्रालय) के लिए अन्वेषण (भूवैज्ञानिक रिपोर्ट) और खनन योजना तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करते हैं । इससे हिमाचल प्रदेश राज्य में पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रत्यायन के साथ एनएबीईटी के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ है तथा असम, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में ईआईए की गुणवत्ता विषय पर चार जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन इस प्रभाग ने किया है।

➤ खनन और धातु विज्ञान परियोजनाओं के माध्यम से, पीपीआईडी ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य सरकारों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है।

➤ पीपीआईडी ने सामाजिक विकास क्षेत्र में भी कदम रखा और शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अन्य-पक्ष मूल्यांकन स्कीमों : ई-श्रम, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) एवं एससी/एसटी के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (एनसीएससी-एससी/एसटी), तथा विलेज सोशॅल ट्रांसफोर्मेशन फाउंडेशन (वीएसटीएफ) का प्रभाव आकलन जैसी परियोजनाएं संचालित कीं।

➤ वस्त्र मंत्रालय के साथ हथकरघा क्षेत्र में अपनी पहली भागीदारी की शुरूआत करते हुए, पीपीआईडी ने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) की एक प्रमुख पहल - कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) का अन्य -पक्ष मूल्यांकन किया।

➤ तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से, पीपीआईडी ने कई पोर्टल विकसित किए हैं जिससे हमारे ग्राहकों को बेहतर निर्णय लेने में और संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों की बेहतर सेवा डिलीवरी सक्षम बनाने में सहायता मिली है। इनमें सरकारी अनाज खरीद केन्द्रों की ग्रेडिंग के लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर सेल्फ-असेसमेंट प्लेटफॉर्म (पीसीएसएपी) और डेटा कलैक्शन एप्लीकेशन एंड असेसमेंट पोर्टल, स्टेट मॉनीटरिंग डैशबोर्ड (एसएमडी) तथा स्वच्छ सर्वेक्षण गुजरात शहरी 2024 परियोजना के लिए जोनल पोर्टल शामिल हैं।

➤ **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की "एमएसएमई सतत (ज़ेड) प्रमाणन" स्कीम:** जारी है।

- असम लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एएसआईडीसी), असम सरकार के साथ 17 मार्च, 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड सरकार के साथ 26 मार्च, 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- मोंटे कार्लो और एवन साइकल्स के साथ लुधियाना में क्रमशः 5 सितंबर, 2024 और 6 सितंबर, 2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- मध्य प्रदेश में ज़ेड स्कीम के प्रचार-प्रसार के लिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (एमपीएलयूएन) के साथ 03 अक्टूबर, 2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- पंजीकृत एमएसएमई: 149836 (सूक्ष्म: 136267, लघु: 11737, मध्यम: 1825)
- प्रमाणित एमएसएमई: 104968 (कांस्य: 102958, रजत: 731 और स्वर्ण: 1279)
- मार्गदर्शन/परामर्श सहायता के लिए प्राप्त आवेदन: 1959
- एमएसएमई जिन्होंने सिस्टम (गुणवत्ता)/परीक्षण/उत्पाद प्रमाणन के संबंध में वित्तीय सहायता प्राप्त की : 1119

➤ **समर प्रमाणन: डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय के विक्रेताओं का आकलन और रेटिंग:** जारी है।

- रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एयरो इंडिया शो 2025 में प्रदर्शित समर प्रमाणन का उद्देश्य विक्रेता गुणवत्ता और अनुपालन को बढ़ाना है। 120 से अधिक डीआरडीओ विक्रेता इसमें शामिल हुए।
- अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा आर्मामेंट्स एंड कॉम्बेट इंजीनियरिंग (एसीई) क्लस्टर के माध्यम से 18 अक्टूबर, 2024 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित विक्रेता संवाद-संपर्क अभियान में समर प्रमाणन प्रदर्शित किया गया। 250 से अधिक संगठनों ने भाग लिया।
- रेट किए गए संगठनों की संख्या: 47 (लेवल 1: 04, लेवल 2: 13, लेवल 3: 23, लेवल 4: 07)

➤ **अनुरूपता आकलन प्रणाली का विकास और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) के संरक्षण के लिए संसाधन** - साइबरस्पेस से जैसे-जैसे उद्योगों में क्रांति आ रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए इसके काफी खतरे भी सामने आ रहे हैं। प्रणालीगत क्षति को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) की सुरक्षा अत्यावश्यक है। परियोजना विश्लेषण एवं प्रलेखन प्रभाग ने महत्वपूर्ण क्षेत्र की संस्थाओं (सीएसई) की उत्थानशीलता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में 30 साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करते हुए, अपनी अनुरूपता आकलन रूपरेखा (सीएएफ) के माध्यम से इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

➤ **पारंपरिक सामुदायिक स्वास्थ्यचर्या प्रदाताओं के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम (वीसीएस-टीसीएचपी)** - वीसीएस-टीसीएचपी स्कीम ने **वित्त वर्ष 2024-25 तक 2,522 पारंपरिक सामुदायिक स्वास्थ्यचर्या प्रदाताओं (टीसीएचपी)** को प्रमाणित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे पारंपरिक स्वास्थ्यचर्या पद्धतियों की मान्यता और विधिमान्यकरण को मजबूती मिली है। **गोवा और तमिलनाडु** से पहले मिली अभिपुष्टि के आधार पर, **छत्तीसगढ़ सरकार** भी अब इस स्कीम के प्रभाव को स्वीकार कर रही है। छत्तीसगढ़ की अभिपुष्टि के बाद, **राज्य में 216 टीसीएचपी प्रमाणित किए गए,** जिससे इस पहल की पहुंच और विश्वसनीयता और भी सुदृढ़ हुई है। इस स्कीम के प्रति बढ़ता समर्थन, भारत भर में पारंपरिक स्वास्थ्यचर्या परिपाटियों के मानकीकरण और विधिमान्यकरण में इसकी सफलता को दर्शाता है।

➤ **औषधीय पादप उत्पाद के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम (वीसीएसएमपीपी)** - औषधीय पादपों की खेती में सर्वोत्तम परिपाटियों को बढ़ावा देने के एक उल्लेखनीय प्रयास के रूप में, **पूरे भारत में 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए,** जिनमें **6000 से अधिक प्रतिभागियों** ने भाग लिया। इस पहल के एक भाग के रूप में टिकाऊ खेती के लिए मानकीकृत दिशानिर्देश सुनिश्चित करते हुए, **111 प्रजातियों के लिए परिपाटी पैकेज (पीओपी) विकसित किए गए।** इस प्रयास को और मजबूती देने के लिए, **30 प्रदर्शन भूखंड स्थापित और प्रमाणित** किए गए, जो इस क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

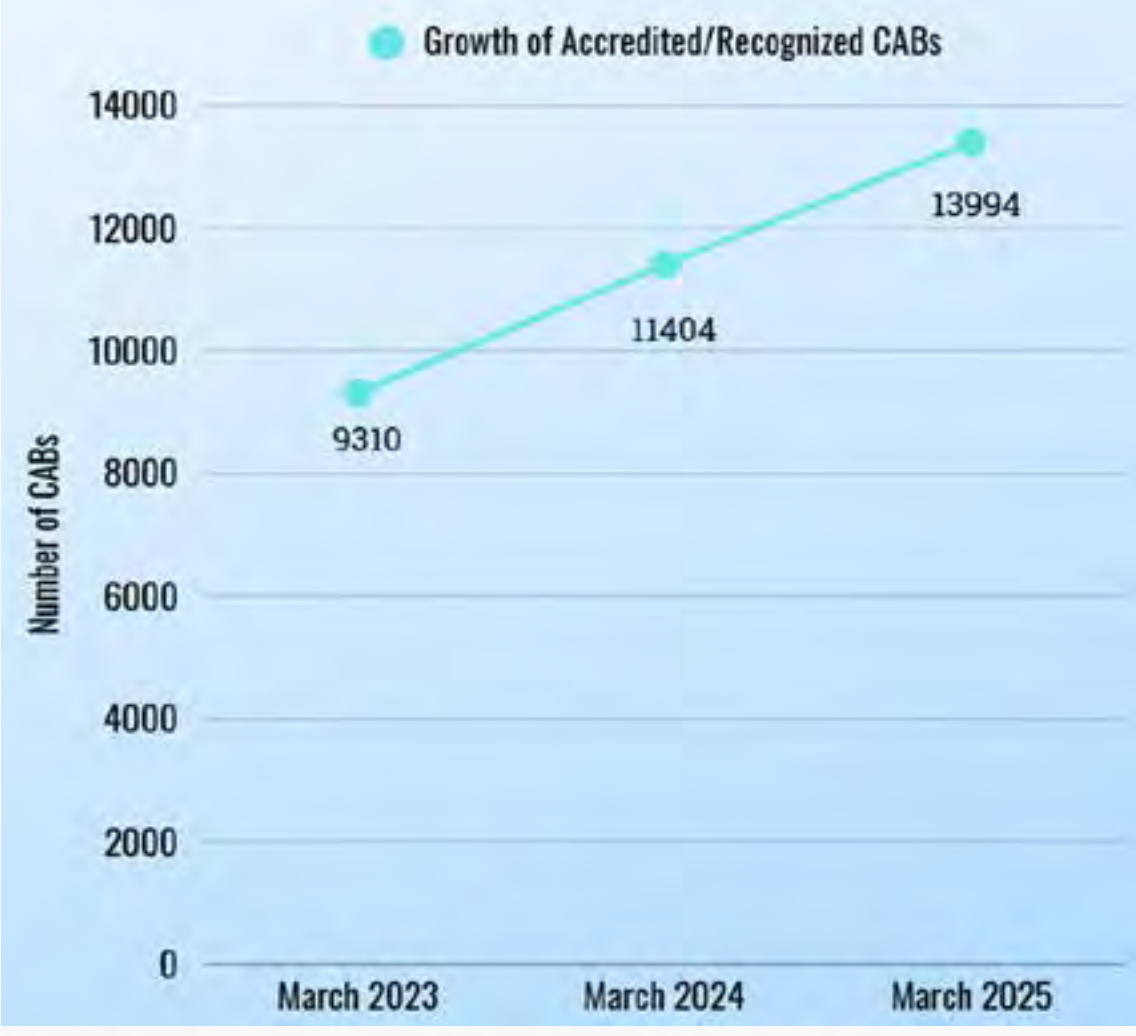
➤ **यूएएस (सीएसयूएएस) के लिए 6 प्रमाणन योजना - भारत के ड्रोन ईकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने** के एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में, इस योजना के शुभारंभ के बाद से **104 टाइप प्रमाणपत्र (टीसी)** जारी किए गए हैं, जो स्वदेशी ड्रोन प्रौद्योगिकी के विकास में सहयोग कर रहे हैं। **पीएडीडी, क्यूसीआई ने सीएसयूएएस** के माध्यम से **नागरिक विमानन मंत्रालय** और **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** के साथ सहकार्य करके, **किसान ड्रोन** में मजबूत स्वदेशी सामग्री सुनिश्चित करते हुए नमो ड्रोन दीदी योजना को आगे बढ़ाकर, और **आत्मनिर्भर भारत** को बढ़ावा देकर इस रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, **अधिकृत परीक्षण संस्थाओं (एटीई)** के लिए **पांच क्षमता-निर्माण कार्यक्रम** संचालित किए गए, जिससे उनकी समझ को डीजीसीए के विनियमों के अनुरूप बनाया जा सके।

➤ **कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (एफएमटीटीआई)** के सहकार्य से **चार प्रमुख स्थलों - बुदनी, हिसार, विश्वनाथ चरियाली और अनंतपुर - में चार दिवसीय क्षमता निर्माण-सह-संवेदीकरण कार्यक्रम** का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को **अत्याधुनिक मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस) प्रौद्योगिकी** से सशक्त बनाना था। यह पहल, भारतीय कृषि में टिकाऊ,

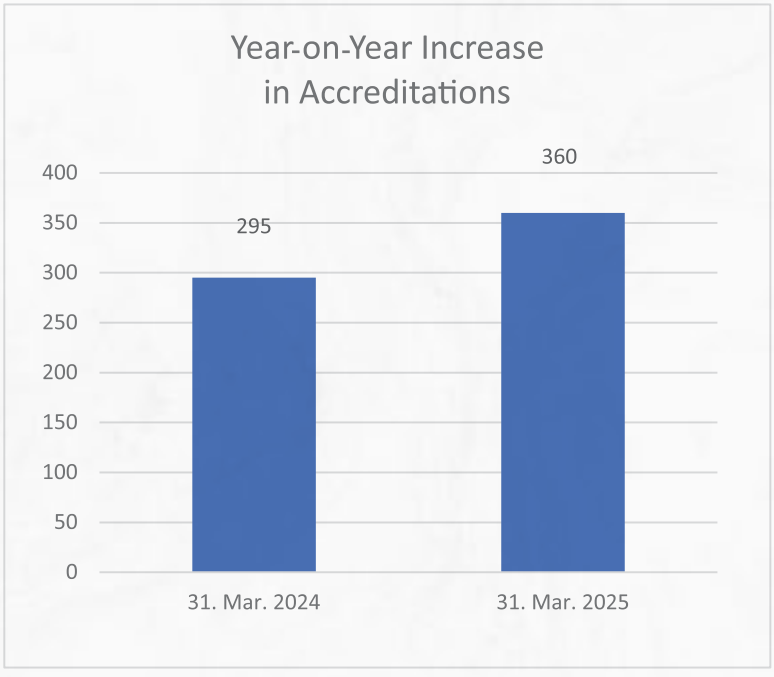
प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को बढ़ावा दे रही है, जिससे भविष्य-लक्षी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित हो रहा है।

- **आयुष मार्क स्कीम**

- **आयुष मार्क** प्रमाणन स्कीम लगातार बढ़ रही है। इस योजना के तहत **5,797 उत्पादों और 68 विनिर्माताओं** को प्रमाणित किया जा चुका है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, **आयुष मंत्रालय आयुष आहार** शुरू करने जा रहा है। यह **आयुष मार्क** के साथ एकीकृत एक ऐसी पहल है, जिसमें **क्यूसीआई को एक प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल किया गया है,** जो इस क्षेत्र में गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करता है। हितधारक सहभागिता को और सुदृढ़ करते हुए, गुणवत्ता मंथन का 21 मार्च, 2025 को सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जिसने हितधारकों को कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने, समाधानों का प्रस्ताव करने और इस स्कीम में निरंतर सुधार के लिए योगदान देने का एक मंच प्रदान किया।

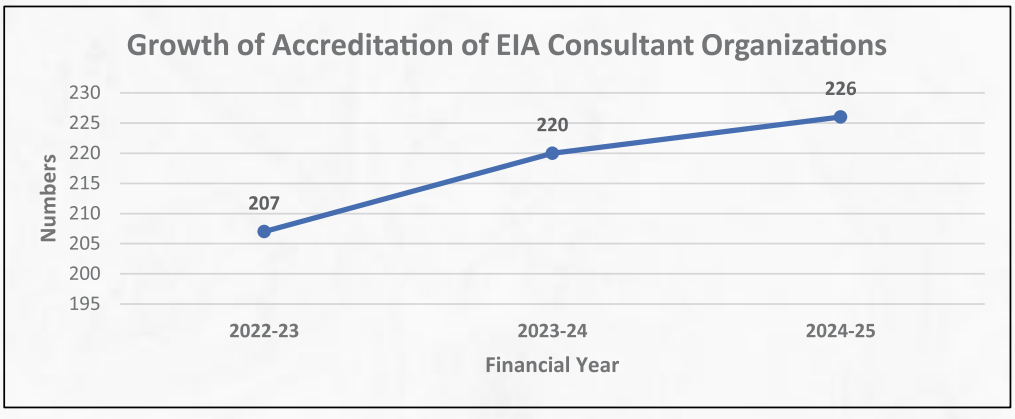


Accreditation Update

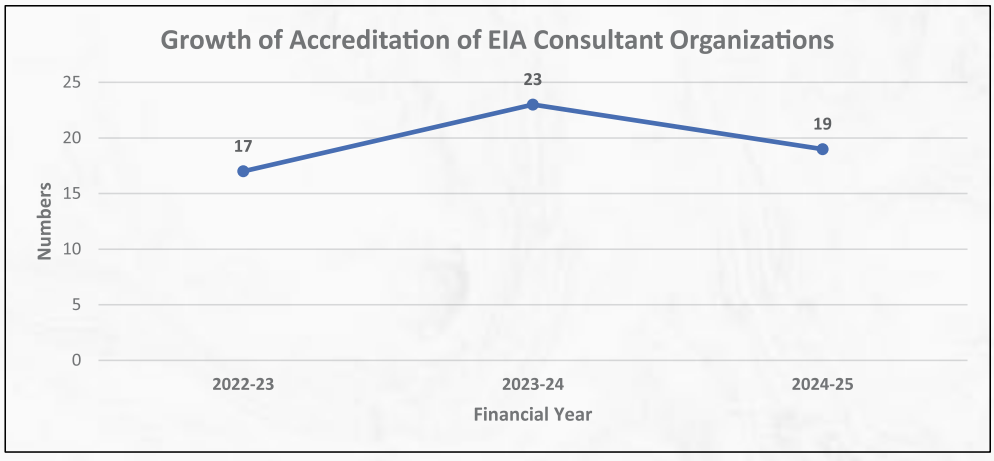




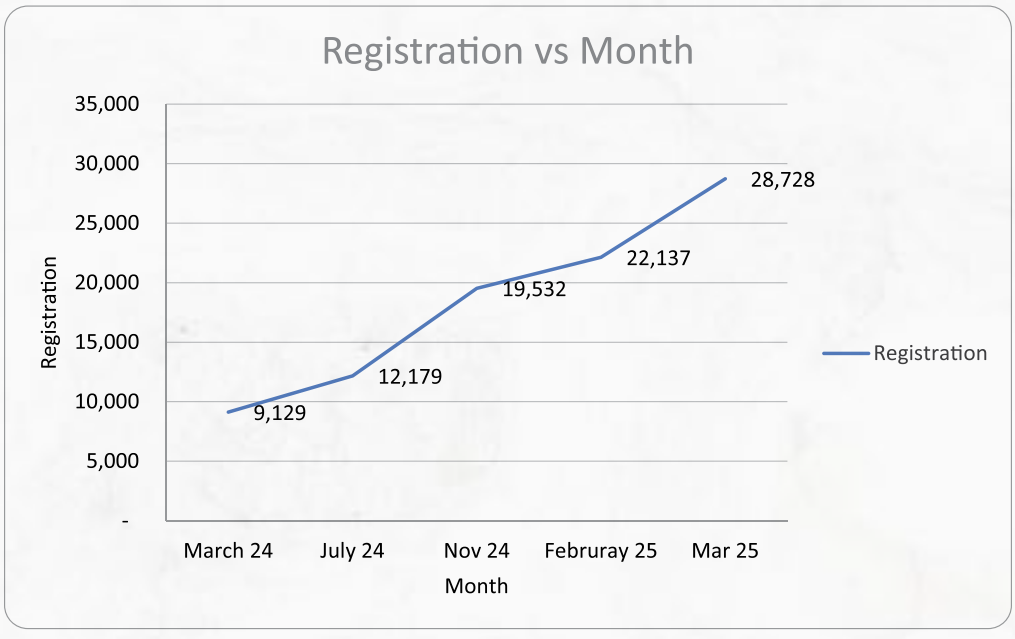
Environment and Exploration Division

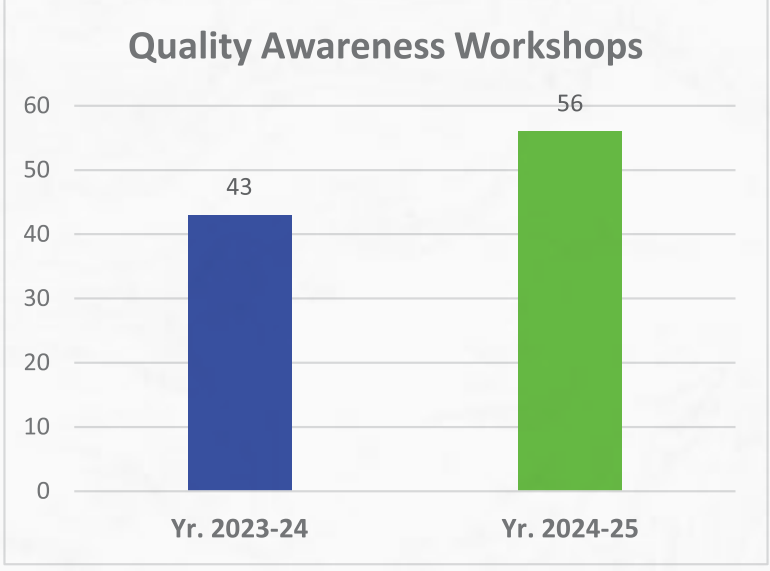


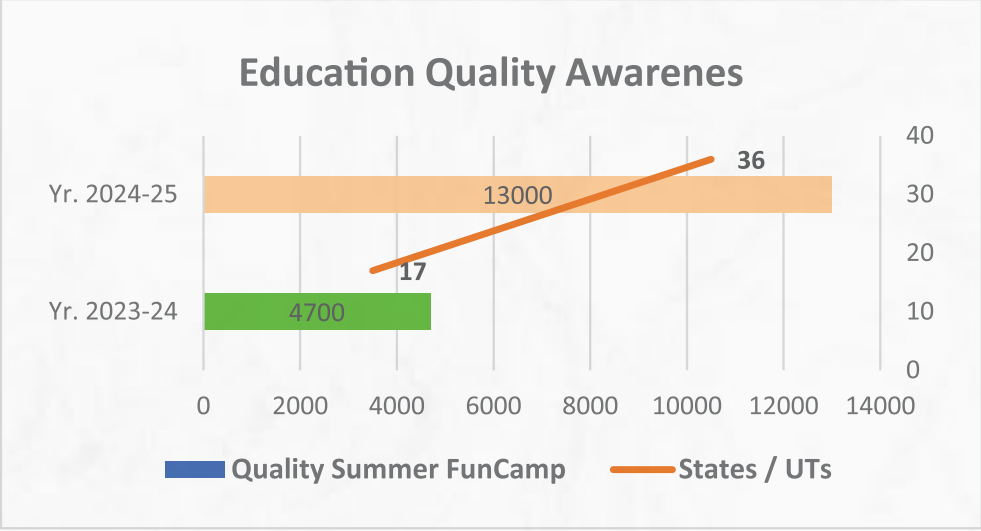
New Accredited EIA Consultant Organizations



Growth of MSME Registration (Lean)







नई स्कीमों का शुभारंभ

- बायोबैंकिंग के लिए प्रत्यायन कार्यक्रम का शुभारंभ (आईएसओ 20387)।
- रासायनिक मापिकी विषय-क्षेत्र के अंतर्गत वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण के अंशांकन हेतु प्रत्यायन कार्यक्रम का शुभारंभ।
- एनएबीसीबी दुनिया के उन गिने-चुने प्रत्यायन निकायों में से एक है जिसने पिछले साल अक्टूबर 2024 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रबंधन प्रणाली (एआईएमएस) में प्रत्यायन स्कीम शुरू की।
- **ग्राहक संबंध प्रबंधन:** हितधारकों की भागीदारी को सुचारु बनाने और सेवा डिलीवरी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, एनएबीएच ने एक ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) साधन पर काम शुरू किया है, जिसे हितधारकों के साथ संपर्क-संवाद के प्रबंधन और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अभिकल्पित किया जाएगा।
- **वेबसाइट में सुधार:** प्रयोक्ता अनुभव और सुगम्यता को बेहतर बनाने के लिए एनएबीएच की वेबसाइट में सुधार का कार्य शुरू किया गया है। विकास चरण में जाने से पहले हितधारकों का फीडबैक शामिल करने के साथ यूआई/यूएक्स चरण लगभग पूरा होने वाला है।
- **ई-मित्र:** प्रयोक्ताओं के प्रश्नों के अनुरूप वीडियो और नमूना फॉर्म खोज निकालकर सहज सहायता प्रदान करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी के साथ एकीकृत चैटबॉट का विकास किया जा रहा है।
- **हॉस्पिटल इन अ बॉक्स:** यह पहल, एनएबीएच के साथ अस्पतालों की अपनी गुणवत्ता यात्रा में सहायता करने के लिए डिजाइन की जा रही है और यह चरणबद्ध रूप में प्रक्रिया-उन्मुख दस्तावेजों का एक संग्रह बनाने पर केन्द्रित होगी। पहला चरण प्रारंभिक स्तर के अस्पतालों को लक्ष्य करेगा, अगले चरण में एनएबीएच मजबूत गुणवत्ता प्रणालियां स्थापित करने के लिए इस पहल को एनएबीएच के अन्य कार्यक्रमों में लागू करने की योजना बनाएगा।
- **गुणवत्ता यात्रा:** एनएबीएच-क्यूसीआई गुणवत्ता यात्रा का संचालन कर रहा है। यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य अस्पतालों और स्वास्थ्यचर्या प्रदाताओं के साथ सीधे जुड़ना है। अब तक एनएबीएच ने रेवाड़ी, अहमदाबाद, राजकोट, कोच्चि, कोलकाता, इंफाल, हैदराबाद, बंगलुरु, मैसूरू, भावनगर जैसे शहरों को शामिल कर लिया है।
- **गुणवत्ता मंथन:** पहला एनएबीएच गुणवत्ता मंथन, 18 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में प्रत्यायित अस्पतालों के लिए आयोजित किया गया। इस मंथन का उद्देश्य, स्वास्थ्यचर्या क्षेत्र में गुणवत्ता अग्रदूतों के योगदान को मान्यता देना और उनका सम्मान करना है, ताकि स्वास्थ्यचर्या की गुणवत्ता बढ़ाने में सीईओ को शामिल किया जा सके और उन्हें सशक्त बनाया जा सके।
- **ब्रांड निर्माण और संचार रणनीति:** एनएबीएच संसक्त ब्रांड पहचान और संचार रणनीति तैयार करने के लिए और ब्रांड निर्माण के लिए काम कर रहा है ताकि दृश्यता और हितधारकों की भागीदारी बढ़ाई जा सके।
- **एनएबीएच कार्यक्रम के नए और संशोधित मानकों का विमोचन**
  - अस्पतालों के लिए एनएबीएच प्रत्यायन मानकों का छठा संस्करण (12 भारतीय भाषाओं में)

- स्वास्थ्यचर्या में जलवायु कार्रवाई और स्थायित्व के लिए एनएबीएच निर्देश पुस्तिका
- अस्पतालों की एनएबीएच जांचसूची जो मनोभ्रंश रोग ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अनुकूल हैं
- आयुष अस्पतालों के लिए एनएबीएच प्रत्यायन मानक - प्रथम संस्करण
- आयुष उपचार एवं आरोग्य केन्द्रों (एटीडब्ल्यूसी) के लिए एनएबीएच प्रत्यायन मानक
- मेडिकल वेल्यू ट्रेवल फेसिलिटेटर्स के लिए एनएबीएच एंपैनलमेंट मानक - द्वितीय संस्करण
- एनएबीएच समाचार पत्रक
- एचआईएस/ईएमआर प्रणालियों के लिए एनएबीएच डिजिटल स्वास्थ्य मानक - प्रथम संस्करण

➤ वित्त वर्ष 2024-25 में, पीपीआईडी ने 124 परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जिनमें से 50 परियोजनाएं नई-नई शुरू की गई थीं। नई शुरू की गई इन परियोजनाओं ने पीपीआईडी द्वारा डिलीवर की जाने वाली परियोजनाओं की विविधता अर्थात् - अन्य-पक्ष निरीक्षण/ मूल्यांकन/आकलन/गुणवत्ता आश्वासन (34), क्षमता निर्माण एवं प्रभाव आकलन (10) आदि प्रदर्शित की।

➤ **गुणवत्ता यात्रा** शुरू की, यह ऐसी पहल है जो स्वास्थ्यचर्या की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ शुरू की गई थी और अब यह विनिर्माण गुणवत्ता भी बढ़ा रही है। यह, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में छोटे और बड़े स्वास्थ्यचर्या संगठनों (एचसीओ), विनिर्माण संघों और इकाइयों में एनएबीएच, एनएबीसीबी और एनडीआईई मानकों को बढ़ावा देती है। **इस अवधि में 48 यात्राएं संचालित की गई।**

➤ क्यूसीआई द्वारा हितधारकों से फीडबैक एकत्र करने तथा सहकार्य और कार्यान्वयन योग्य समाधानों के माध्यम से गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **गुणवत्ता मंथन नामक** रणनीतिक पहल शुरू की गई। यह, हितधारकों को अपने विचारों के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने के लिए एक विशेष मंच उपलब्ध कराता है। क्यूसीआई इस सामूहिक ज्ञान का उपयोग रणनीतिक योजना को बेहतर बनाने, गुणवत्ता पहलों को आगे बढ़ाने और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए करता है। **एनएबीसीबी, एनएबीएच, एनडीआईई और पीएडीडी के लिए ये मंथन संचालित किए गए हैं।**

भाग 1

परिचय

भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) की स्थापना, 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी स्वायत्त सोसायटी के रूप में की गई है ताकि देश में एक प्रत्यायन संरचना स्थापित की जा सके और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान चलाकर भारत में गुणवत्ता आंदोलन का प्रसार किया जा सके। क्यूसीआई, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के रूप में काम करती है, जो सरकार द्वारा समर्थित है लेकिन अपने कामकाज में स्वतंत्र है।

क. विज़न :

गुणवत्ता के लिए इकोसिस्टम का सृजन करना।

ख. मिशन स्टेटमेंट

भारतीय गुणवत्ता परिषद् का मिशन, मुख्य रूप से राष्ट्र और उसके नागरिकों के हितों के संवर्धन और संरक्षण के लिए गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों के अनुपालन पर बल देने के लिए, सभी हितधारकों को साथ लेकर, भारत में राष्ट्रव्यापी गुणवत्ता आंदोलन का नेतृत्व करना है।

ग. मुख्य उद्देश्य:

शिक्षा, स्वास्थ्यचर्या, पर्यावरण संरक्षण, अभिशासन, सामाजिक क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र और संगठित गतिविधियों के ऐसे अन्य क्षेत्रों सहित गतिविधियों के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणवत्ता-मानकों के प्रचार, अंगीकरण और अनुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर भारतीय गुणवत्ता परिषद् के मिशन को प्राप्त करना है जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव, भारत के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और कुशल-क्षेम में सुधार लाने पर पड़ता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में, गुणवत्ता के सामान्य अनुप्रयोग को सीमित किए बिना, अन्य बातों के साथ-साथ आमतौर पर ये कार्य-क्षेत्र शामिल होंगे:

(क) नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने, गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता की मांग करने में उन्हें सशक्त बनाने और गुणवत्ता मानकों एवं साधनों को अपनाने तथा उनका अनुपालन करने के लिए माल विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करके नागरिकों की कुशल-क्षेम के संवर्धन और संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से देश में राष्ट्रव्यापी गुणवत्ता आंदोलन का नेतृत्व करना।

(ख) निरंतर गुणवत्ता सुधार के कार्यान्वयन और संस्थापन के लिए सरकारों, संस्थाओं और उद्यमों के स्तर पर तदनुसार क्षमताओं का विकास करना।

(ग) उत्पादों, कर्मियों, प्रबंधन प्रणालियों का प्रमाणन करने वाले अनुरूपता आकलन निकायों के लिए प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रमों को विकसित करना, स्थापित करना और प्रचालित करना; उत्तम प्रयोगशाला परिपाटियों के ओईसीडी सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए परीक्षण, अंशशोधन और चिकित्सा प्रयोगशालाओं, निपुणता परीक्षण प्रदाताओं, संदर्भ सामग्री उत्पादकों और परीक्षण केन्द्रों के लिए निरीक्षण संचालित करना और संगठित गतिविधियों के ऐसे अन्य क्षेत्रों में कार्य करना जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव, भारत के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और कुशल-क्षेम में सुधार पर पड़ता हो।

(घ) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों और दिशानिर्देशों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्यचर्या, पर्यावरण संरक्षण, अभिशासन, सामाजिक क्षेत्रों, अवसंरचना क्षेत्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसे विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रमों का यथापेक्षित विकास, संस्थापन और प्रचालन करना, और जहां ऐसे मानक उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्रत्यायन कार्यक्रमों की सहायता के लिए प्रत्यायन मानक विकसित करना।

(ङ) टीबीटी/एसपीएस बाधाओं से पार पाने के लिए विनियमन, अनुरूपता आकलन और प्रत्यायन के क्षेत्रों में क्षमताओं का निर्माण करना;

अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (आईएलएसी), अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन मंच (आईएएफ),

एशिया प्रशांत प्रयोगशाला प्रत्यायन (एपीएलएसी), प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (पीएसी), इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थकेयर (आईएसक्यूए), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंचों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना और बनाए रखना तथा शीर्ष सत्रों, समिति की बैठक आदि में भाग लेकर नवीनतम विकास कार्यों के साथ तालमेल बनाए रखना ताकि डेटा की बहु-पार्श्व प्रत्यायन व्यवस्था/ पारस्परिक स्वीकृति को बढ़ावा मिल सके, और

अन्य देशों में क्यूसीआई/संघटक बोर्डों और प्रत्यायन निकायों के बीच द्विपक्षीय/बहु-पक्षीय मान्यता व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली सभी गतिविधियों को शुरू करना।

(च) सरकार, नियामकों, संगठनों और समाज में उपयोग के लिए अन्य पक्ष आकलन मॉडल के विकास और अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(छ) गुणवत्ता प्रबंधन मानकों और गुणवत्ता साधनों को अपनाने और उनके पालन के माध्यम से भारत के उद्यमों, विशेष रूप से एमएसएमई की गुणवत्ता स्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना।

(ज) सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय परिपाटियों के भंडार के रूप में गुणवत्ता सुधार और बेंचमार्किंग केन्द्र की स्थापना को बढ़ावा देना और सभी क्षेत्रों में उद्योगों के बीच उन परिपाटियों का प्रसार करना ।

(झ) गुणवत्ता के क्षेत्र में औद्योगिक/अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना तथा प्रासंगिक प्रकाशन और व्यापार पत्रिकाओं में इसके परिणाम का प्रसार करना;

पुस्तकों, साहित्य और पत्रिकाओं का प्रकाशन करना और क्यूसीआई के उद्देश्यों से संबंधित जानकारी का प्रसार करना; और

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करना/उनमें सहभागिता करना।

(ञ) भारत के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और कुशल-क्षेम में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खाद्य क्षेत्र, तेल और गैस, वानिकी, कृषि/पशुपालन, गोदाम, फार्मेसी आदि जैसे अथवा समय-समय पर सामने आने वाली जरूरत के अनुसार, अन्य उभरते क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गुणवत्ता प्रत्यायन तंत्र के विकास सहित क्षमताओं का निर्माण करना।

(ट) अनसुलझी शिकायतों से निपटने के लिए अपील तंत्र सहित मानकों और गुणवत्ता संबंधी राष्ट्रीय सूचना एवं पूछताछ सेवा के प्रभावी कामकाज को सुगम बनाना।

(ठ) अनसुलझी शिकायतों से निपटने के लिए एक अपील तंत्र विकसित करना और उसका प्रचालन करना।

शासी परिषद्

परिषद् के नियमों और विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार, परिषद् के सदस्य निम्नानुसार हैं:

अध्यक्ष | भारतीय गुणवत्ता परिषद्, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, दूसरा तल, 2 - बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

सचिव | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सचिव | वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सचिव | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016

सचिव | उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

अध्यक्ष डीसीसी एवं सचिव (टी) | दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सचिव | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011

अध्यक्ष एवं सीईओ | रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001

महानिदेशक | गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए), डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011

महानिदेशक | भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, भारत

महानिदेशक | वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर), अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110 001

महानिदेशक | मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, तृतीय तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003

निदेशक | राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), डॉ. के. एस. कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली - 110012

अध्यक्ष | भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), 23, लोदी इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110 003

अध्यक्ष | एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), 5, सरदार पटेल मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110 021

अध्यक्ष | फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली 110 001

अध्यक्ष | फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो), निर्यात भवन, राव तुलाराम मार्ग, आर्मी हॉस्पिटल के सामने, नई दिल्ली-110057

अध्यक्ष | इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए), आईआईए भवन, विभूति खंड, फेज 2, गोमतीनगर, लखनऊ – 226010

अध्यक्ष | इंडियन मर्चेंट चैंबर्स (आईएमसी), आईएमसी बिल्डिंग, आईएमसी मार्ग, चर्चगेट स्टेशन के सामने, चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र 400020

महासचिव | भारतीय गुणवत्ता परिषद्, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, दूसरा तल, 2 - बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002

अध्यक्ष, एनएबीसीबी	इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, प्रथम तल, 2 - बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
अध्यक्ष, एनबीक्यूपी	आशी भवन, 19 राऊज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110002
अध्यक्ष, एनएबीएच	आईटीपीआई बिल्डिंग, 4-ए, रिंग रोड, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
अध्यक्ष, एनएबीईटी	आईटीपीआई बिल्डिंग, 4-ए, रिंग रोड, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
अध्यक्ष, एनएबीएल	एनएबीएल हाउस, प्लॉट नंबर 45, सेक्टर 44, गुरुग्राम - 122003, हरियाणा
अध्यक्ष	वित्त समिति, बी- ब्लॉक, सेक्टर 58, नोएडा- 201307
प्रतिनिधि	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई), 'नवीन हाउस, सरदार पटेल सेवा समाज हॉल के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380006 (गुजरात)'
महासचिव	कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीईएएमए), एफ-4/23, चौथी मंजिल, वेब फर्स्ट सिल्वर टावर, सेक्टर 18, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301
अध्यक्ष	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् (ईईपीसी), 'वंदना', चौथी मंजिल, 11, टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001
एमडी, डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	नामिती, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ईएलसीआईएनए), एल्सिना हाउस, 422, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-3, नई दिल्ली, -110020
उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001
सदस्य	प्रबंधन समिति, स्पोर्ट्सकॉम इंडस्ट्री कन्फेडरेशन, 24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), 301, तीसरी मंजिल, वेस्ट विंग, वर्ल्ड मार्क 1, एसेट 11, एयरोसिटी, नई दिल्ली – 110037
राष्ट्रीय अध्यक्ष	भारतीय औषध विनिर्माता संघ (आईडीएमए), 102, पूनम चैंबर्स, 'ए' विंग, पहली मंजिल, डॉ. ए.बी. रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018
प्रतिनिधि	कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई), 5वीं मंजिल, पीएचडी हाउस, 4/2 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110 016
मुख्य कार्यपालक	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई), 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली, 110016 (भारत)
ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (इंडिया)	सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ), डीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एफडीए भवन, आईटीओ, कोटला रोड, नई दिल्ली -110002
महासचिव	कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीजीएसआई), ब्लॉक जे, आजाद मैदान, कामा अस्पताल के सामने, महापालिका मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400001, महाराष्ट्र

शासी निकाय

शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य हैं:

अध्यक्ष | भारतीय गुणवत्ता परिषद्, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 2 - बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002

सचिव | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सचिव | वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सचिव | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016

अध्यक्ष एवं सीईओ | रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001

महानिदेशक | वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर), अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110 001

अध्यक्ष | भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), 23, लोदी इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110 003

अध्यक्ष | फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग नई दिल्ली - 110 001

अध्यक्ष | एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), 5, सरदार पटेल मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली -110 021

महानिदेशक | मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, तीसरी मंजिल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003

अध्यक्ष | भारतीय उद्योग संघ (आईआईए), आईआईए भवन, विभूति खंड, फेज 2, गोमतीनगर, लखनऊ – 226010

सदस्य | प्रबंधन समिति, स्पोर्ट्सकॉम इंडस्ट्री कन्फेडरेशन, 24-25 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

अध्यक्ष, एनएबीसीबी | इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, पहली मंजिल, 2 - बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002

अध्यक्ष, एनबीक्यूपी | आशी भवन, 19 राऊज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110002

अध्यक्ष, एनएबीएच | आईटीपीआई बिल्डिंग, 4-ए, रिंग रोड, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली – 110002

अध्यक्ष, एनएबीईटी | आईटीपीआई बिल्डिंग, 4-ए, रिंग रोड, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली- 110002

अध्यक्ष, एनएबीएल | एनएबीएल हाउस, प्लॉट नंबर 45, सेक्टर 44, गुरुग्राम - 122003, हरियाणा

अध्यक्ष | वित्त समिति, बी- ब्लॉक, सेक्टर 58, नोएडा- 201307

प्रतिनिधि | कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई), 5वीं मंजिल, 4/2 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110 016

प्रतिनिधि | पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई), नवीन हाउस, सरदार पटेल सेवा समाज हॉल के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380006

महासचिव | भारतीय गुणवत्ता परिषद्, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 2 - बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110002

संरचना

अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति और मान्यता प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय गुणवत्ता परिषद्, शासी परिषद् द्वारा निर्धारित रणनीति, नीति और प्रचालन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए शासी निकाय और अन्य कार्यकारी निकायों (बोर्ड/ समितियों) के माध्यम से कार्य करती है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद् के विभिन्न निकाय निम्नानुसार हैं (जैसा कि अभिशासन संरचना में उल्लेख किया गया है)

(i) शासी परिषद् (जीसी)

(ii) शासी निकाय (जीबी)

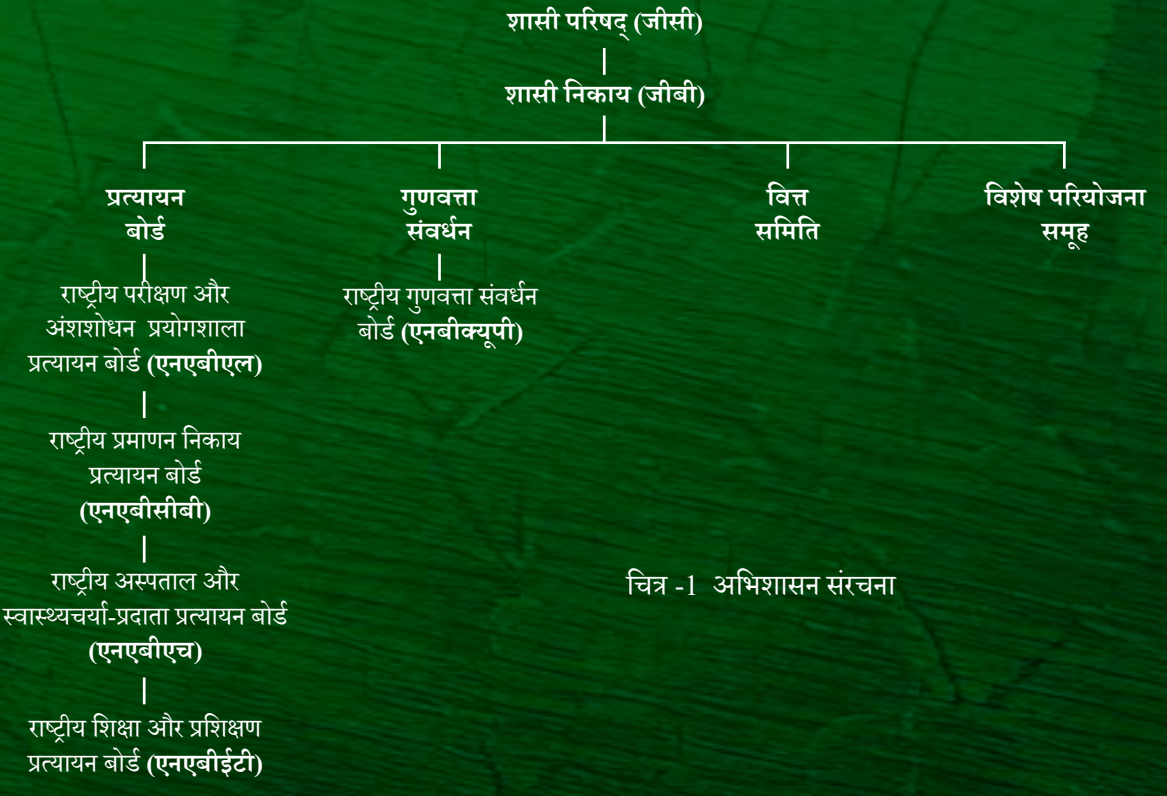
(iii) वित्त समिति (एफसी)

(iv) प्रत्यायन बोर्ड (एबी) और गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड

इसके अलावा, संगठन में एक पूर्ण विकसित सचिवालय है जो समय-समय पर शासी निकाय द्वारा प्राधिकृत प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी कार्यों का प्रबंधन करता है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद् की अभिशासन संरचना और प्रशासनिक संरचना चित्र-1 और चित्र-2 के अनुसार है।

अभिशासन संरचना



चित्र -1 अभिशासन संरचना



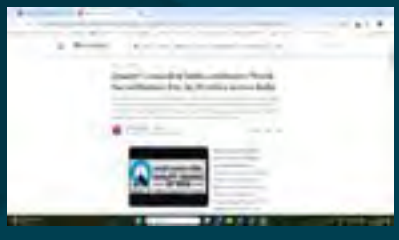
चित्र-2 प्रशासनिक संरचना

हमारी सोशल मीडिया उपस्थिति



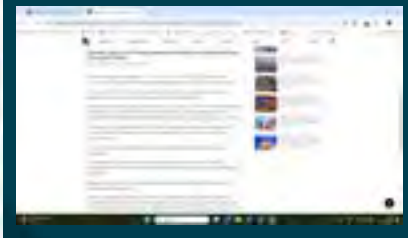


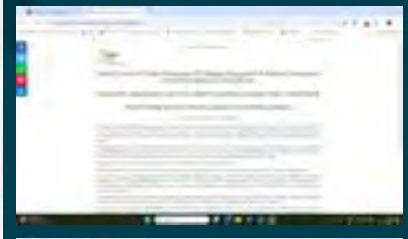






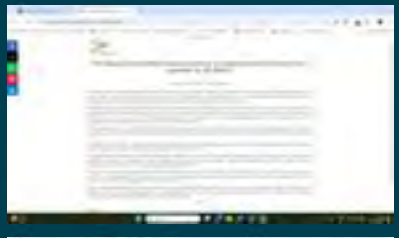




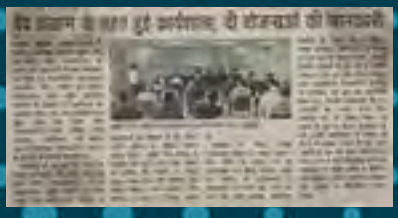






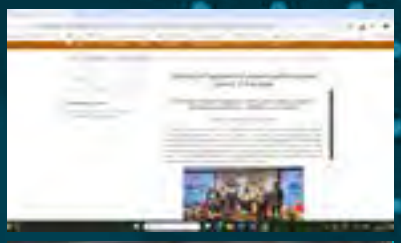





















राज एक्सप्रेस

रैंप प्रोग्राम में भाग लेकर उद्योगों को लाभ लेने प्रोत्साहित करें एसोसिएशन






जिले के उद्योगों को जेड सर्टिफाइड बनाने के लिए हुई कार्यशाला






एमएसएमई विभाग की कार्यशाला सम्पन्न


राष्ट्रीय हिन्दी मेल

रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस को लेकर कार्यशाला आयोजित





रैम्प योजना के तहत सागर में कार्यशाला का आयोजन





भाग
2

वित्त वर्ष 2024-25 में बोर्डों/ प्रभागों/प्रकोष्ठों की गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा



NABL

1 राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)

राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल), दुनिया का अग्रणी प्रत्यायन निकाय बनने और अपनी सेवाओं में हितधारकों का विश्वास बढ़ाने की अपनी परिकल्पना को साकार करने की दिशा में काम करता आ रहा है। एनएबीएल ने प्रत्यायित सीएबी की संख्या बढ़ाते समय अपनी सेवाओं की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया है। एनएबीएल के मिशन के अनुरूप, प्रत्यायन प्रणाली को मजबूत करने के लिए सक्षम आकलनकर्ताओं को सूचीबद्ध करने, हितधारकों में जागरूकता पैदा करने, प्रत्यायन गतिविधियों में सहयोग करने वाले नए कार्यक्रम शुरू करने और संगठनात्मक उत्कृष्टता की प्राप्ति की दिशा में काम करने जैसी गतिविधियां शुरू की गई हैं।

एनएबीएल, निम्नलिखित के लिए स्वैच्छिक प्रत्यायन सेवाएं प्रदान करता है:

- आईएसओ/आईईसी 17025: 2017 के अनुसार परीक्षण प्रयोगशालाओं को
- आईएसओ/आईईसी 17025: 2017 के अनुसार अंशशोधन प्रयोगशालाओं को
- आईएसओ 15189: 2012/2022 के अनुसार चिकित्सा प्रयोगशालाओं को
- आईएसओ / आईईसी 17043: 2010/2023 के अनुसार निपुणता परीक्षण प्रदाताओं को
- आईएसओ 17034: 2016 के अनुसार संदर्भ सामग्री उत्पादकों को

एनएबीएल आईएसओ/आईईसी 17011:2017 "अनुरूपता आकलन निकायों को प्रत्यायन प्रदान करने वाले प्रत्यायन निकायों के लिए अनुरूपता आकलन अपेक्षाओं" का अनुपालन कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मान्यताएं

एनएबीएल, अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (आईएलएसी) के साथ-साथ एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (एपीएसी) पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (एमआरए), जो समकक्ष आकलन पर आधारित है, का एक पूर्ण सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता (सन् 2000 से) है। इस तरह की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं उन देशों के बीच परीक्षण/अंशशोधन परिणामों की स्वीकृति को सुगम बनाती हैं जिनका प्रतिनिधित्व एमआरए भागीदारों द्वारा किया जाता है।

उद्देश्य

क) देश के लिए उपयुक्त और बदलती जरूरतों के अनुकूल संगत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रयोगशालाओं, निपुणता परीक्षण प्रदाताओं एवं संदर्भ सामग्री उत्पादकों के लिए प्रत्यायन प्रणाली को बढ़ावा देना, लागू करना और बनाए रखना।

ख) प्रत्यायित और आवेदक अनुरूपता आकलन निकायों को समय पर प्रत्यायन सेवाएं प्रदान करना।

ग) संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, अनुरूपता आकलन निकाय-उद्योग-प्रत्यायन निकाय बैठकों सहित विभिन्न माध्यमों से अनुरूपता आकलन निकाय के प्रत्यायन के सभी पहलुओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

घ) परीक्षण, अंशशोधन, चिकित्सा परीक्षण, निपुणता परीक्षण प्रदाताओं एवं संदर्भ सामग्री उत्पादकों के भिन्न-भिन्न विषयक्षेत्रों में आकलनकर्ताओं और विशेषज्ञों का डेटाबेस तैयार करना और उसे बनाए रखना तथा आकलनकर्ताओं की नियमित निगरानी करना।

ङ) प्रयोगशाला/ संदर्भ सामग्री उत्पादकों/ निपुणता परीक्षण प्रदाताओं के प्रत्यायन और संबंधित गतिविधियों में सहयोग के लिए और उनके सुधार के लिए समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना, जैसे कि आकलनकर्ताओं, प्रत्यायन अधिकारियों का प्रशिक्षण।

च) प्रत्यायन के संबंध में एनएबीएल के निर्णयों के विरुद्ध शिकायतों और अपीलों से निपटने के लिए तंत्र का विकास और प्रचालन करना।

छ) अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (आईएलएसी), एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (एपीएसी) जैसे अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय निकायों के साथ विभिन्न बैठकों में और ऐसे निकायों की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से संपर्क स्थापित करना और उसे बनाए रखना।

ज) एनएबीएल प्रत्यायित अनुरूपता आकलन निकायों के परीक्षण परिणामों की अपेक्षाकृत व्यापक स्वीकृति के उद्देश्य से एनएबीएल और दूसरे देशों के प्रत्यायन निकायों के बीच द्विपक्षीय/बहुपक्षीय (पारस्परिक) मान्यता व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली सभी गतिविधियां शुरू करना।

1.1 परीक्षण

- आईएसओ/आईईसी 17025: 2017 के अनुसार 1079 परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन प्रदान किया गया (एनएबीएल द्वारा कुल 5755 परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रत्यायित किया गया)।
- प्रत्यायन के संबंध में निर्णयों की संस्तुति करने के लिए प्रत्यायन समितियों की 314 बैठकें हुईं।
- एफएसएसएआई, ईआईसी, एपीईडीए आदि जैसे विनियामकों को शामिल करते हुए एकीकृत आकलन के लिए प्रत्यायन समितियों की 40 बैठकें हुईं।
- निर्यात बाजार के लिए एकीकृत आकलन स्कीम (ईआईसी, आईओपीईपीसी और एपीईडीए) से 207 प्रयोगशालाओं; घरेलू बाजार के लिए एफएसएसएआई तथा कमोडिटी बोर्डों को लाभ मिला।

- जल शक्ति मंत्रालय, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भारत सरकार की 489 (121 नए प्रत्यायन के साथ) जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन प्रदान किया गया। जी-एलएपी प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत कुल 855 (248 नई मान्यताओं के साथ) जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई।
- एईआरबी की मान्यता योजना के तहत नैदानिक रेडियोलॉजी के लिए गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण में कुल 18 प्रयोगशालाओं को नए प्रत्यायन प्रदान किए गए और इस प्रकार कुल 119 प्रत्यायन प्रदान किए गए।
- मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कार्यक्रम में 433 की संख्या में मान्यताएं प्रदान की गईं।

1.2 अंशशोधन

- आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार 171 अंशशोधन प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन प्रदान किया गया (एनएबीएल द्वारा कुल 1152 अंशशोधन प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन प्रदान किया गया)।
- 5 प्रयोगशालाओं को चिकित्सा उपकरण अंशशोधन के तहत प्रत्यायन प्रदान किए गए। चिकित्सा उपकरण अंशशोधन में प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 69 है।
- प्रत्यायन के संबंध में निर्णयों की संस्तुति करने के लिए प्रत्यायन समितियों की 98 बैठकें आयोजित की गईं।

1.3 चिकित्सा

- आईएसओ 15189 के अनुसार 440 चिकित्सा प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन प्रदान किया गया (एनएबीएल द्वारा कुल 2146 चिकित्सा प्रयोगशालाएं प्रत्यायित हैं)
- प्रत्यायन के संबंध में निर्णय की संस्तुति करने के लिए प्रत्यायन समितियों की 147 बैठकें आयोजित की गईं।

1.4 निपुणता परीक्षण प्रदाता (पीटीपी)

- एनएबीएल ने परीक्षण, अंशशोधन और चिकित्सा विषय-क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में 69 निपुणता परीक्षण प्रदाताओं (पीटीपी) को प्रत्यायित किया है। चालू वर्ष में 10 नए निपुणता परीक्षण प्रदाताओं को प्रत्यायन प्रदान किए गए।
- निपुणता परीक्षण प्रदाताओं के प्रत्यायन के संबंध में निर्णय की संस्तुति करने के लिए प्रत्यायन समितियों की 10 बैठकें आयोजित की गईं।

1.5 संदर्भ सामग्री उत्पादक (आरएमपी)

- एनएबीएल ने अब तक 20 संदर्भ सामग्री उत्पादकों को प्रत्यायन प्रदान किए हैं। इनमें से 5 को चालू वर्ष में प्रत्यायन प्रदान किए गए। पहली बार, कीटनाशकों के लिए प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) का उत्पादन करने वाले आरएमपी को एनएबीएल प्रत्यायन के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह 'मेक इन इंडिया' के तहत आरएमपी द्वारा एक उल्लेखनीय पहल है क्योंकि इससे प्रयोगशालाओं द्वारा भारत के बाहर से सीआरएम की खरीद पर किए जाने वाले व्यय में भारी कमी आएगी।
- संदर्भ सामग्री उत्पादकों के प्रत्यायन के संबंध में निर्णय की संस्तुति करने के लिए प्रत्यायन समितियों की 8 बैठकें आयोजित की गईं।

कॉन्क्लेव: मैसूरू में 30-31 अगस्त, 2024 को आठवां आरएमपी/पीटीपी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया

मैसूरू में 30 और 31 अगस्त, 2024 को आठवां निपुणता परीक्षण प्रदाता/संदर्भ सामग्री उत्पादक (पीटीपी/आरएमपी) कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव में निपुणता परीक्षण प्रदाताओं (पीटीपी), संदर्भ सामग्री उत्पादकों (आरएमपी), परीक्षण प्रयोगशालाओं, अंशशोधन प्रयोगशालाओं, चिकित्सा परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा सरकारी और विनियामक निकायों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कॉन्क्लेव ने प्रतिभागियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सामने आ रही चुनौतियों एवं अवसरों के बारे में विचार विमर्श करने तथा अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। कॉन्क्लेव में प्रत्यायित निपुणता परीक्षण प्रदाताओं और संदर्भ सामग्री उत्पादकों ने अपनी निपुणता परीक्षण स्कीमों और संदर्भ सामग्री उत्पादन योजना के संबंध में प्रस्तुतियां दीं। प्रथम पुरस्कार, पीटी प्रदाता (पीटीपी) ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड, जीरकपुर ने जीता। दूसरा पुरस्कार भी एक अन्य पीटी प्रदाता लैंडमार्क मटिरियल टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी प्रा. लि., जयपुर ने जीता। तीसरा पुरस्कार संदर्भ सामग्री उत्पादक (आरएमपी) एचपीसीएल आरएमपी, विशाखापट्टणम ने जीता। एक पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें पीटीपी द्वारा संचालित पीटी स्कीमें प्रदर्शित की गईं। पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता बीपीसीएल निपुणता परीक्षण मुंबई, एनएमएल जमशेदपुर और निर्यात निरीक्षण एजेंसी - कोच्चि रहे। यह कॉन्क्लेव, निपुणता परीक्षण करने और संदर्भ सामग्री के उत्पादन के लिए नेटवर्किंग, सहकार्य एवं नए अवसर तलाशने के लिए एक बहुमूल्य कार्यक्रम था।

1.6 एनएबीएल एम (ईएल) टी लैब्स प्रोग्राम

- एनएबीएल, बुनियादी परीक्षण करने वाली चिकित्सा परीक्षण प्रयोगशालाओं को गुणवत्ता परिपाटियों में सुधार करने के प्रति जागरूक करने और अधिकांश नागरिकों, विशेष रूप से गांवों, छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यचर्या तक पहुंच प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक कार्यक्रम अर्थात 'एनएबीएल चिकित्सा (प्रवेश स्तरीय) परीक्षण एम (ईएल) टी प्रयोगशाला कार्यक्रम' संचालित करता है। यह स्कीम, एक स्वतंत्र गुणवत्ता आश्वासन स्कीम है, जो एपीएसी और आईएलएसी एमआरए के तहत शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 में 377

प्रयोगशालाओं ने एम (ईएल) टी लैब्स कार्यक्रम का लाभ उठाया।

1.7 गुणवत्ता

- एनएबीएल ने आईएसओ/आईईसी 17011: 2017 के अनुसार, अपना एपीएसी एमआरए हस्ताक्षरकर्ता का दर्जा बनाए रखा है।
- एनएबीएल ने 08 सदस्यीय दल जिसमें 06 बाहरी प्रशिक्षित संपरीक्षक शामिल थे, द्वारा 19 से 25 जून, 2024 तक अपनी आंतरिक संपरीक्षा कराई।
- एनएबीएल ने जोखिम समिति और निष्पक्षता समिति की 03 बैठकें आयोजित की।
- एनएबीएल ने 10 दस्तावेज संशोधित/ जारी किए हैं।

1.8 एनएबीएल जागरूकता/ प्रशिक्षण कार्यक्रम

गुणवत्ता पाठशाला - आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार एनएबीएल आकलनकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम			
क्रम संख्या	स्थान	तारीख	प्रशिक्षित आकलन-कर्ताओं की संख्या
1	चेन्नै	अप्रेल 27 – मई 1, 2024	24
2	बेंगलुरु	मई 13 – 17, 2024	24
3	कोलकाता	मई 14 – 18, 2024	21
4	मुंबई	मई 26 – 30, 2024	19
5	दिल्ली	मई 27 – 31, 2024	21
6	हैदराबाद	मई 27 – 31, 2024	22
7	चेन्नै	मई 27 – 31, 2024	21
8	पुणे	मई 28 – जून 1, 2024	22
9	कोलकाता	जून 11 – 15, 2024	22
10	बेंगलुरु	जून 11 – 15, 2024	22
11	मुंबई	जून 11 – 15, 2024	22
12	चेन्नै	जून 11 – 15, 2024	19
13	दिल्ली	जून 12 – 16, 2024	21
14	दिल्ली	जून 19 – 23, 2024	15
15	दिल्ली	जून 24 – 28, 2024	20
16	पुणे	जून 24 – 28, 2024	16
17	हैदराबाद	जून 24 – 28, 2024	19
18	अहमदाबाद	जून 25 – 29, 2024	21
19	दिल्ली	अगस्त 5 – 9, 2024	19
20	हैदराबाद	सितम्बर 9 – 13, 2024	19
21	बेंगलुरु	अगस्त 25 – 29, 2024	18

22	गुरुग्राम	अक्तूबर 14 – 18, 2024	20
23	बेंगलुरु	नवम्बर 18 – 22, 2024	21
24	मुंबई	दिसम्बर 9 – 13, 2024	23
25	मदुरै	जनवरी 20 – 24, 2025	14
26	गुरुग्राम	फरवरी 17 – 21, 2025	21
गुणवत्ता पाठशाला - आईएसओ 15189:2022 के अनुसार एनएबीएल आकलनकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम			
27	दिल्ली	नवम्बर 18 – 22, 2024	28
28	चेन्नै	नवम्बर 27 – दिसम्बर 1, 2024	22
29	पुणे	फरवरी 4 – 8, 2025	23
30	कोलकाता	फरवरी 11 – 15, 2025	25

गुणवत्ता यात्रा - एनएबीएल प्रत्यायन/मान्यता कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम

क्रम संख्या	राज्य	शहर	कार्यक्रमों की संख्या
1	राजस्थान	जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, कोटा	10
2	उत्तर प्रदेश	वाराणसी, नोएडा, मेरठ	3
3	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, जलपाईगुड़ी, दुर्गापुर, मालदा, सिलीगुड़ी, बर्धमान, पूर्व मिदनापुर, हुगली, बैरकपुर, पूर्व बर्धमान, कूचबिहार, तमलुक, पश्चिम मेदिनीपुर, बहरमपुर, बांकुड़ा, उत्तर 24 परगना, बीरभूम, उत्तरपाड़ा, पुरुलिया, दक्षिण 24 परगना, मालदा, हावड़ा	36
4	दिल्ली	नई दिल्ली	3
5	गुजरात	वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, वेरावल, सूरत, गांधीनगर, नवसारी, जूनागढ़, मेहसाणा, वापी, दहेज, सरदार कृषिनगर, पोरबंदर, मोरबी, करमसद, अंजार, भुज, जामनगर, अमरेली, अंकलेश्वर, भरूच, भावनगर, वडनगर	46
6	मध्य प्रदेश	इंदौर, भोपाल, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), ग्वालियर, दतिया, सतना, जबलपुर	13
7	कर्नाटक	मैसूरु, मंगलुरु, हुबली, बेंगलुरु, चिकमंगलुरु +1, रायचूर, मूडबीदरी, बेलगावी, चिकबल्लापुर	21

8	तेलंगाना	हैदराबाद	7
9	तमिलनाडु	मदुरै, थूथुकुडी, चेन्नै, पुदुक्कोट्टै, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, होसुर, गुम्मिडीपूंडी, वेल्लोर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, डिंडीगुल, तिरुपुर, विरुधुनगर, कोयंबटूर, तिरुनेलवेली, कृष्णागिरी, मदुरै, सलेम	26
10	केरल	कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि	4
11	असम	गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सोनितपुर	5
12	पुदुचेरी	पुदुचेरी	2
13	पंजाब	भटिंडा, लुधियाना, जालंधर	3
14	महाराष्ट्र	नागपुर, मुंबई, औरंगाबाद, कोपरगांव, नासिक, पुणे, कोल्हापुर, अमरावती	22
15	मणिपुर	इंफाल	2
16	छत्तीसगढ़	रायपुर	1
17	ओडिशा	मयूरभंज, कटक, भुवनेश्वर, क्योंझर, राउरकेला, पुरी, अंगुल, बेहरामपुर, पारादीप, राउरकेला	15
18	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1
19	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टणम, श्री सिटी, काकीनाडा	3
20	मेघालय	शिलांग	1
21	बिहार	पटना, महुआ	2
22	लक्षद्वीप	कावारत्ती द्वीप	1
23	गोवा	पणजी	1
24	झारखंड	जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो	6
25	हरियाणा	बहादुरगढ़	1

अन्य कार्यक्रम (राष्ट्रीय)

- एनएबीएल ने एनएबीसीबी के साथ मिलकर 10 जून, 2024 को नई दिल्ली में विश्व प्रत्यायन दिवस 2024 मनाया। एनएबीएल द्वारा "प्रत्यायन: एम्पावरिंग टुमॉरो एंड शेपिंग द फ्यूचर" विषय पर यह कार्यक्रम पूरे भारत के 20 अन्य शहरों में 10 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया गया, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया गया कि प्रत्यायन किस तरह हमारी बदलती दुनिया में जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकार देने में सहायता कर सकता है।
- रासायनिक मापिकी विषय-क्षेत्र के अंतर्गत वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरणों के अंशाकन हेतु प्रत्यायन कार्यक्रम का शुभारंभ।
- बायोबैंकिंग के लिए प्रत्यायन कार्यक्रम का शुभारंभ (आईएसओ 20387)।

राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अंतरराष्ट्रीय भागीदारी

क्रम संख्या	गतिविधि का नाम	तारीख
	एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (एपीएसी)	
1	अनंतिम मूल्यांकनकर्ता के रूप में केएएन-इंडोनेशिया का एपीएसी मूल्यांकन	मई 25 - जून 1, 2024
2	दुबई में एपीएसी कार्यकारी समिति और एमआरएएमसी बैठक और 2024 एपीएसी वार्षिक बैठकें	जुलाई 14 - 18, 2024
3	एडीएपीटी डिजिटलीकरण डब्ल्यूजी ऑनलाइन बैठकें:	मई 22, 2024, जुलाई 26, 2024, सितम्बर 18, 2024, अक्तूबर 24, 2024, दिसम्बर 25, 2024, जनवरी 30, 2025, मार्च 25, 2025
4	प्रत्यायन में डिजिटलीकरण रूपांतरण विषय पर आईएएसी एपीएसी संयुक्त ऑनलाइन वेबिनार	जुलाई 31, 2024
5	डिजिटल आकलन के साधन एवं तकनीक विषय पर ऑनलाइन एडीएपीटी कार्यशाला: अनुभव का आदान-प्रदान (आकलन के बाद)	अगस्त 7, 2024
6	एपीएसी टीम लीडर के रूप में यूनाइटिड एक्रेडिटेशन फाउंडेशन (यूएएफ), यूएसए का एपीएसी मूल्यांकन	अगस्त 5 - 10, 2024
7	एडीएपीटी डिजिटलीकरण नेटवर्क बैठक	अप्रेल 17, 2024, मई 21, 2024, अगस्त 28, 2024, नवम्बर 16, 2024, फरवरी 5, 2025, मार्च 19, 2025
8	एडीएपीटी परियोजना संचालन समिति की ऑनलाइन बैठक	मई 22, 2024, जुलाई 13, 2024, सितम्बर 12, 2024, फरवरी 5, 2025
9	ए2एलए, यूएसए में एपीएसी आईएसओ 20387 बायोबैंकिंग प्रशिक्षण में भाग लिया	सितम्बर 10 - 12, 2024
10	ईयूआरएसीएचईएम द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला – गुणावत्तापरक संदर्भ सामग्री का उत्पादन	सितम्बर 19, 2024
11	बर्लिन, जर्मनी में एपीएसी एमआरएएमसी बैठक	सितम्बर 29, 2024
12	बर्लिन, जर्मनी में एपीएसी कार्यकारी समिति की बैठक	सितम्बर 30, 2024
13	एपीएसी टीम लीडर और मूल्यांकनकर्ता के रूप में एएसी "एनेलिटिका", फेडरेशन ऑफ रसिया का एपीएसी मूल्यांकन	अक्तूबर 19 - 26, 2024

14	**एपीएसी के निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया।** 1. आकलन गतिविधियों के संबंध में ऑनलाइन एडीएपीटी अनुभव आदान-प्रदान कार्यशाला 2. नई दिल्ली में चिकित्सा परीक्षण (आईएसओ 15189) प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन के संबंध में एपीएसी प्रशिक्षण कार्यक्रम और एपीएसी मूल्यांकनकर्ता कार्यशाला (चिकित्सा परीक्षण मूल्यांकनकर्ता) का आयोजन किया 3. आकलन पश्चचात गतिविधियों के विषय पर ऑनलाइन एडीएपीटी अनुभव आदान-प्रदान कार्यशाला 4. ऑनलाइन प्रशिक्षण का डिजिटलीकरण विषय पर ऑनलाइन एडीएपीटी कार्यशाला 5. सीएबी की सहायता हेतु परिवर्तन प्रबंधन विषय पर ऑनलाइन कार्यशाला	1. मई 10, 2024 2. जून 24 - 28, 2024 3. अगस्त 7, 2024 4. सितम्बर 10, 2024 5. अक्तूबर 16, 2024
15	शंघाई मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए एपीएसी मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण कार्य समूह की बैठकें	नवम्बर 8, 2024, दिसम्बर 13, 2024, जनवरी 9, 2025, जनवरी 31, 2025
16	एनपीएल, भारत में एपीएसी ईसी प्रतिनिधियों के रूप में एपीएमपी - एपीएसी पीटीडब्ल्यूजी बैठक	नवम्बर 24, 2024
17	मस्कट, ओमान में एपीएसी - आरएमपी का प्रत्यायन (आईएसओ 17034) और प्रासंगिक आईएसओ 3340x श्रृंखला	दिसम्बर 2 - 6, 2024
18	ऑनलाइन-यूरो लैब – 23आईएनडी13 स्क्रीन फूड प्रोजेक्ट -(हितधारक कार्यशाला)- सेफ्टी ऑफ सस्टेनेबिल फूड पैकेजिंग स्टेट-ऑफ-द आर्ट और संदूषक आकलन की आवश्यकताएं	फरवरी 12, 2025
19	बहरीन में एपीएसी मूल्यांकनकर्ता टीम के रूप में आईएएस, यूएसए (कार्यक्षेत्र का विस्तार) का एपीएसी समकक्ष मूल्यांकन	जनवरी 29 – 30, 2025
20	प्रशिक्षक संगठनों के विनिर्देशन तैयार करना विषय पर ऑनलाइन एडीएपीटी पीएससी उप-कार्य समूह	फरवरी 18, 2025
21	शंघाई, चीन में एपीएसी नामित समकक्ष मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम	फरवरी 24 – 25, 2025
22	शंघाई, चीन में एपीएसी प्रमुख मूल्यांकनकर्ता कार्यशाला	फरवरी 26 – 27, 2025
23	शंघाई, चीन में एपीएसी एमआरएएमसी और एपीएसी की कार्यकारी समिति की बैठकें	फरवरी 28 – मार्च 1, 2025
	अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (आईएलएसी)	
24	30 अधिकारियों ने ऑनलाइन आईएएफ/आईएलएसी मध्यावधि (आईएलएसी प्रत्यायन समिति - एआईसी) बैठक में भाग लिया	अप्रेल 10, 2024
25	27 अधिकारियों ने ऑनलाइन आईएएफ/आईएलएसी मध्यावधि (आईएलएसी संयुक्त विकास सहायता समिति-जेडीएससी) बैठक में भाग लिया	अप्रेल 16, 2024
26	28 अधिकारियों ने ऑनलाइन आईएएफ/आईएलएसी मध्यावधि (आईएलएसी व्यवस्था समिति-एआरसी) बैठक में भाग लिया	अप्रेल 18, 2024
27	21 अधिकारियों ने ऑनलाइन आईएएफ/आईएलएसी मध्यावधि (आईएलएसी निरीक्षण समिति- आईसी) बैठक में भाग लिया	अप्रेल 19, 2024

28	आईएलएसी वार्षिक बैठक 2024, बर्लिन, जर्मनी	अक्तूबर 1 – 10, 2024
29	आईएलएसी एआईसी कार्य समूह मेट्रोलॉजी (न्यूज़लेटर #3)	नवम्बर 26, 2024
30	आईटीयू के साथ आईएलएसी संपर्क बैठक	दिसम्बर 20, 2024, जनवरी 9, 2025
अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)		
31	आईएसओ/टीसी 334 संदर्भ सामग्री पूर्ण बैठक	अप्रेल 19, 2024
32	बर्लिन, जर्मनी में आईएसओ टीसी 212 कार्य समूह 1 " चिकित्सा प्रयोगशाला में गुणवत्ता और सक्षमता" बैठक में भाग लिया।	मई 6 – 8, 2024
33	आईएसओ टीसी 212 कार्य समूह 2 "संदर्भ प्रणालियां"	मई 14 – 15, 2024
34	आईएसओ/टीसी 334 संदर्भ सामग्री	जून 4 – 5, 2024 और जून 7, 2024
35	अमरांते, पुर्तगाल में आईएसओ/टीसी 69, इसकी उपसमितियों और कार्य समूहों की 46वीं पूर्ण बैठक में भागीदारी	जून 17 – 21, 2024
36	आईएसओ/टीसी 334/कार्य समूह 10 "आरएम नियम और परिभाषाएं"	अगस्त 12 – 14, 2024
37	आईएसओ/टीसी 212/ कार्य समूह 1 “चिकित्सा प्रयोगशाला में गुणवत्ता और सक्षमता”	अक्तूबर 7 – 9, 2024
38	आईएसओ/टीसी 334/ कार्य समूह 13 “गुणवत्तापरक संदर्भ सामग्री”	अक्तूबर 11, 2024
39	आईएसओ/टीसी 212/ कार्य समूह 2 “संदर्भ प्रणालियां”	अक्तूबर 18, 2024
40	आईएसओ/टीसी 212 “चिकित्सा प्रयोगशालाएं और इनविट्रो डायग्नोस्टिक प्रणाली”	अक्तूबर 25, 2024
41	आईएसओ/टीसी69/एससी6/ कार्य समूह 1 “मापन विधियों की सटीकता और परिणाम”	नवम्बर 5 – 8, 2024
42	आईएसओ/टीसी 334/ कार्य समूह 19 “धातुओं के लिए शुद्धता आरएम”	दिसम्बर 19, 2024
43	आईएसओ/टीसी 69 एससी6 कार्य समूह 7 - मापन अनिश्चितता मूल्यांकन में सहायता के लिए सांख्यिकीय विधियाँ	मार्च 6, 2025



एनएबीएल और पीएचडीसीसीआई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए



एनएबीएल और पीएचडीसीसीआई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए





एनएबीएल और ईईपीसी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए



एनएबीएल और कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए

निपुणता परीक्षण प्रदाताओं (पीटीपी) और संदर्भ सामग्री उत्पादकों (आरएमपी) के लिए 8वां कॉन्क्लेव

एनएबीएल का निपुणता परीक्षण प्रदाताओं (पीटीपी) और संदर्भ सामग्री उत्पादकों (आरएमपी) के लिए 8वां कॉन्क्लेव 30 और 31 अगस्त, 2024 को मैसूर में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इसमें लगभग 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें निपुणता परीक्षण प्रदाता (पीटीपी), संदर्भ सामग्री उत्पादक (आरएमपी), परीक्षण प्रयोगशालाओं, अंशशोधन प्रयोगशालाओं, चिकित्सा परीक्षण प्रयोगशालाओं और सरकारी एवं नियामक निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

इस सत्र का उद्घाटन एनएबीएल के अध्यक्ष पद्मश्री प्रो. सुब्बन्ना अय्यप्पन ने किया। उन्होंने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) के निदेशक प्रो. वेणुगोपाल अचंता और एनएबीएल के सीईओ श्री एन. वेंकटेश्वरन के साथ दीप प्रज्ज्वलित किया।

इस कॉन्क्लेव के मुख्य आकर्षण थे:

- प्रत्यायित पीटीपी और आरएमपी ने अपनी निपुणता परीक्षण स्कीमों और संदर्भ सामग्री उत्पादों का प्रदर्शन किया।
- इस कॉन्क्लेव ने प्रतिभागियों को अपने-अपने क्षेत्रों में तकनीकी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने और विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान किया।
- एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पीटीपी द्वारा संचालित पीटी स्कीम, पोस्टरों के माध्यम से प्रदर्शित की गई।
- यह कॉन्क्लेव नेटवर्किंग, सहकार्य तथा निपुणता परीक्षण के संचालन और संदर्भ सामग्री के उत्पादन के नए अवसर तलाशने के लिए एक बहुमूल्य आयोजन था।



विश्व प्रत्यायन दिवस 2024

एनएबीएल ने एनएबीसीबी के साथ मिलकर 10 जून, 2024 को नई दिल्ली में विश्व प्रत्यायन दिवस 2024 मनाया। एनएबीएल द्वारा "प्रत्यायन: एम्पारिंग टुमॉरो एंड शेपिंग द फ्यूचर" विषय पर यह कार्यक्रम पूरे भारत के 20 अन्य शहरों में 10 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया गया, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया गया कि प्रत्यायन किस तरह हमारी बदलती दुनिया में जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकार देने में सहायता कर सकता है।







विश्व प्रत्यायन दिवस 2024



गुणवत्ता मंथन – प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के हितधारकों को शामिल करते हुए एक दिवसीय चर्चा

एनएबीएल ने निम्नलिखित शहरों में प्रत्यायित परीक्षण, अंशशोधन और चिकित्सा प्रयोगशालाओं के हितधारकों को शामिल करते हुए, प्रत्यायन यात्रा के संबंध में उनका फीडबैक एकत्र करने के लिए गुणवत्ता मंथन - एक दिवसीय चर्चा का संचालन किया:

क) नई दिल्ली, दिल्ली, 4 फरवरी, 2025 को

ख) नागपुर, महाराष्ट्र, 16 फरवरी, 2025 को

ग) अहमदाबाद, गुजरात, 6-7 मार्च, 2025 को

घ) चेन्नै, तमिलनाडु, 20 मार्च, 2025 को

ङ) कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 28.03.2025 को







कार्यक्रम - नव प्रत्यायित प्रयोगशालाओं का सम्मान समारोह

एनएबीएल द्वारा नई दिल्ली में नव प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

क) नव प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए 30 मई, 2024 को प्रथम सम्मान समारोह।

ख) नव प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए 1 जुलाई, 2024 को दूसरा सम्मान समारोह।

ग) नव प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए 1 अगस्त, 2024 को तीसरा सम्मान समारोह।

घ) नव प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए 4 सितंबर, 2024 और 26 सितंबर, 2024 को चौथा एवं पांचवां सम्मान समारोह।

ङ) नव प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए 4 नवंबर, 2024 को छठा सम्मान समारोह।

च) नव प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए 9 दिसंबर, 2024 को सातवां सम्मान समारोह।

छ) नव प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए 7 जनवरी, 2025 को आठवां सम्मान समारोह।

ज) नव प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए 4 फरवरी, 2025 को नौवां सम्मान समारोह।

झ) नव प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए 19 मार्च, 2025 को 10वां सम्मान समारोह।







एनएबीएल द्वारा नई दिल्ली में एपीएसी प्रशिक्षण की मेजबानी की गई।

चिकित्सा परीक्षण (आईएसओ 15189) विषय पर एपीएसी प्रशिक्षण 24 से 26 जून, 2024 तक एपीएसी द्वारा आयोजित किया गया और एनएबीएल, इंडिया द्वारा उसकी मेजबानी की गई।

एपीएसी के प्रत्यायन प्रबंधकों और एपीएसी सदस्यों के आकलन कर्मियों तथा एपीएसी मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आमने-सामने, संवादपरक, ज्ञान साझाकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का एपीएसी की ओर से 24 से 26 जून, 2024 तक सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और एनएबीएल द्वारा होटल ली-मेरिडियन, नई दिल्ली में इसकी मेजबानी की गई।

ये प्रतिभागी 16 प्रत्यायन निकायों, अर्थात् दुनिया भर की सभी अर्थव्यवस्थाओं से आए थे।

इसमें आईएसओ 15189 चिकित्सा प्रयोगशालाओं के नए संस्करण - चिकित्सा परीक्षण केन्द्रों को प्रत्यायन प्रदान करने के लिए गुणवत्ता और सक्षमता अपेक्षाओं के प्रयोग को कवर किया गया और आईएसओ 15189 के प्रत्येक खंड में हुए परिवर्तनों के साथ पॉइंट-ऑफ-केयर टेस्टिंग (पीओसीटी) का संदर्भ इसमें शामिल था।



गुणवत्ता पाठशाला - एनएबीएल द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

निपुणता परीक्षण प्रदाता (पीटीपी) और संदर्भ सामग्री उत्पादक (आरएमपी) प्रशिक्षण कार्यक्रम:

क) आईएसओ 17034: 2016 "संदर्भ सामग्री उत्पादकों की सक्षमता के लिए सामान्य अपेक्षाएं" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, तारीख: 14 - 15 मई, 2024, स्थान: दिल्ली

ख) निपुणता परीक्षण प्रदाता के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम, तारीख - 22 मई, 2024, स्थान - भरूच

ग) आईएसओ गाइड 35 - संदर्भ सामग्री की समरूपता और स्थिरता का निरूपण और आकलन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, तारीख - 16 मई - 17 मई, 2024, स्थान - दिल्ली

घ) आईएसओ/आईईसी 17043:2023 और आईएसओ 13528:2022 विषय पर निपुणता परीक्षण प्रदाताओं (पीटीपी) का प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 से 6 दिसंबर, 2024 तक बेंगलुरु में आयोजित किया गया।

ङ) आईएसओ 17034:2016 के अनुसार संदर्भ सामग्री उत्पादक

विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 26-27 नवंबर, 2024 को और आईएसओ गाइड 35:2017 विषय पर 28-29 नवंबर, 2024 को पुणे में।

च) आईएसओ 17034 और आईएसओ गाइड 35 विषय पर 4-7 फरवरी, 2025 के दौरान चेन्नै, तमिलनाडु में।

छ) आईएसओ/आईईसी 17043:2023 और आईएसओ 13528:2022 विषय पर 4-7 मार्च, 2025 के दौरान नई दिल्ली में।











आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार एनएबीएल आकलनकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम 17-21 फरवरी, 2025 के दौरान गुरुग्राम, हरियाणा में संचालित किया गया।



गुणवत्ता यात्रा - एनएबीएल द्वारा संचालित जागरूकता कार्यक्रम

एनएबीएल ने एनएबीएल प्रत्यायन और इसके लाभ विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया। यह एनएबीएल आईएसओ 15189:2022 मानक के संबंध में एक सूचनात्मक सत्र था। यह कार्यक्रम निम्नलिखित विवरण के अनुसार संचालित किया गया:

क) 26 जुलाई, 2024 को एम्स भटिंडा, पंजाब में।

ख) 10 अगस्त, 2024 को एम्स, गुवाहाटी, असम में।

ग) 27 अगस्त, 2024 को एम्स, रायपुर, छत्तीसगढ़ में।

घ) 6 दिसंबर, 2024 को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुदुचेरी में।

ङ) 18 दिसंबर, 2024 को एम्स, राजकोट, गुजरात में।

च) 24 जनवरी, 2025 को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल, पटना, बिहार में।

छ) 21 फरवरी, 2025 को ईएसआईसी हॉस्पीटल, बापूनगर, अहमदाबाद, गुजरात में।













एनएबीएल ने एनएबीएल प्रत्यायन के महत्व और इसके लाभों के संबंध में निम्नलिखित जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए हैं:

क) आईसीएआर सीआईएफटी, वेरावल सोमनाथ, गुजरात में 19 जुलाई, 2024 को

ख) वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, वापी, गुजरात में 12 अगस्त, 2024 को

ग) विरुधुनगर, तमिलनाडु में 30 जनवरी, 2025 को

घ) केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बेलगावी (कुंडा नगर), कर्नाटक में 13 फरवरी, 2025 को

ङ) हैदराबाद, तेलंगाना में 21 फरवरी, 2025 को एनएबीएल ने एनएबीएल प्रत्यायन के महत्व और इसके लाभ, एम(ईएल)टी मान्यता स्कीम और मृदा परीक्षण मान्यता स्कीम के संबंध में निम्नलिखित जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए हैं:

च) रथीन्द्र कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), विश्वभारती, बीरभूम, कोलकाता में 20.12.2024 को

छ) आईएमएस और एसयूएम हॉस्पीटल, भुवनेश्वर, ओडिशा में 20.12.2024 को।

















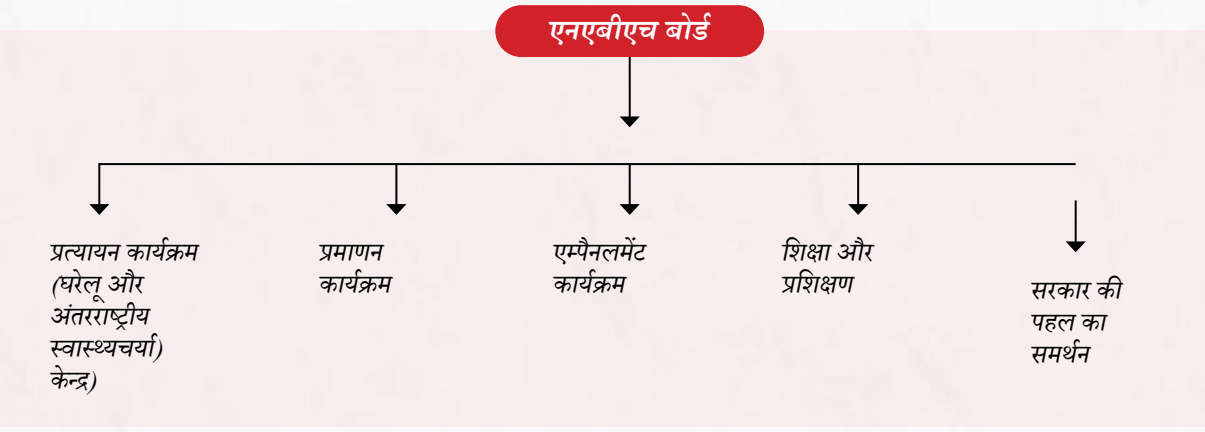
2 राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्यचर्या-प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच)

राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्यचर्या-प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) ने 2006 में अपनी स्थापना के बाद से, स्वास्थ्यचर्या सेवाओं के प्रबंधन और रोगियों को सेवा-संदाय के प्रति स्वास्थ्यचर्या प्रदाताओं द्वारा अपनाई गई कार्यनीति में उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बोर्ड, भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) के घटक बोर्डों में से एक है और स्वास्थ्यचर्या संगठनों के लिए प्रत्यायन, प्रमाणन और पैनलबद्धता कार्यक्रमों का कामकाज देख रहा है। एनएबीएच की स्थापना, स्वास्थ्य प्रणालियों की अभिवृद्धि और निरंतर गुणवत्ता सुधार एवं रोगी संरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। यद्यपि, बोर्ड को उद्योग क्षेत्र, उपभोक्ताओं, सरकार सहित सभी हितधारकों का सहयोग मिलता है, फिर भी अपने संचालन में इसे पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है। एनएबीएच मानकों में, बदलते स्वास्थ्यचर्या वातावरण में स्वास्थ्यचर्या केन्द्रों द्वारा रोगी संरक्षा और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की डिलीवरी पर ध्यान दिया गया है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, यह बोर्ड जन साधारण को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित रखता है।

एनएबीएच अस्पतालों को उनके स्वामित्व, आकार और स्वतंत्रता के स्तर पर ध्यान दिए बिना उद्देश्यपूर्ण, गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से प्रत्यायन/ प्रमाणन प्रदान करता है।

अस्पताल प्रत्यायन कार्यक्रम के लिए एनएबीएच मानक, आईएसक्यूएू द्वारा प्रत्यायित किए गए हैं। एक संगठन के रूप में भी एनएबीएच को आईएसक्यूएू द्वारा प्रत्यायित किया गया है। ये प्रत्यायन यह अभिप्रमाणित करते हैं कि अस्पताल प्रत्यायन कार्यक्रम के लिए एनएबीएच मानक और एक संगठन के रूप में स्वयं एनएबीएच आईएसक्यूएू द्वारा निर्धारित वैश्विक बेंचमार्कों के अनुरूप हैं।

2.1 एनएबीएच की गतिविधियां



एनएबीएच प्रत्यायन कार्यक्रम: एनएबीएच अस्पतालों, ब्लड बैंकों और ट्रांसफ्यूजन सेवाओं, लघु स्वास्थ्यचर्या संगठनों, दंत चिकित्सा केन्द्रों, आयुष अस्पतालों, मेडिकल इमेजिंग सेवाओं (एमआईएस), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), एलोपैथिक क्लीनिकों, मौखिक प्रतिस्थापन चिकित्सा (ओएसटी) केन्द्रों, नैदानिक परीक्षण (आचार समितियों), नेत्र देखभाल संगठन (ईसीओ) और पंचकर्म क्लीनिकों, नशा-रोगी एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए), डिजिटल स्वास्थ्य और देखभाल गृहों को प्रत्यायन प्रदान करता है।

एनएबीएच प्रमाणन कार्यक्रम: एनएबीएच चिकित्सा प्रयोगशालाओं, नर्सिंग उत्कृष्टता के लिए प्रमाणन, अस्पतालों के लिए प्रवेश स्तरीय प्रमाणन, छोटे स्वास्थ्यचर्या संगठनों, अस्पताल में आपातकालीन विभाग के लिए प्रवेश स्तरीय प्रमाणन, आयुष केन्द्रों के लिए प्रवेश स्तरीय प्रमाणन, आयुष अस्पतालों के लिए प्रवेश स्तरीय प्रमाणन, डेन्टल क्लीनिक्स के लिए प्रवेश स्तरीय प्रमाणन, एचआईएस/ ईएमआर प्रणालियों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम और स्ट्रोक प्रमाणन प्रदान करता है।

एनएबीएच एम्पैनलमेंट कार्यक्रम: एनएबीएच क) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), ख) पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) और ग) मेडिकल वैल्यू ट्रैवल फैसिलिटेटर (एमवीटीएफ) के लिए एम्पैनलमेंट कार्यक्रम चलाता है।

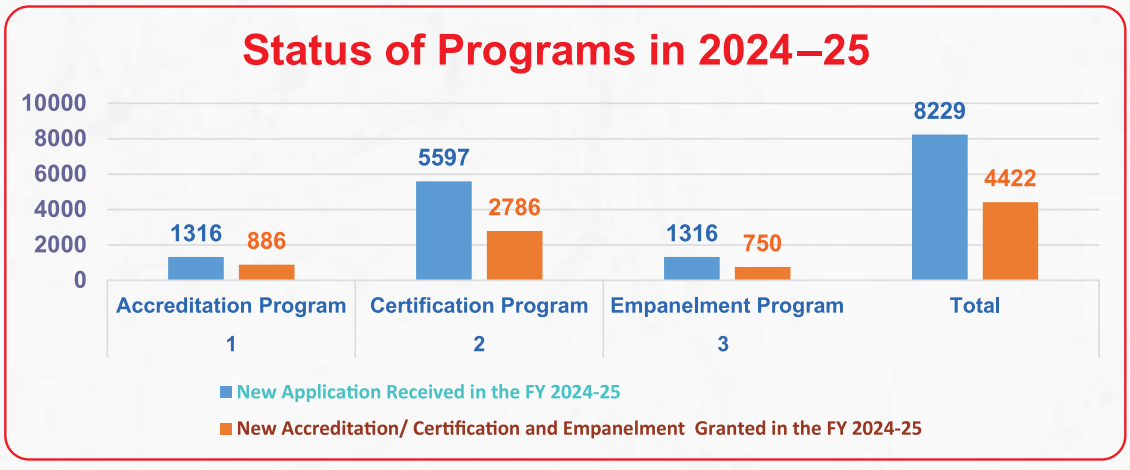
एनएबीएच इंटरनेशनल: एनएबीएच, अस्पताल प्रत्यायन कार्यक्रम, लघु स्वास्थ्यचर्या संगठन (एसएचसीओ) प्रत्यायन कार्यक्रम, नेत्र चिकित्सा संगठन (ईसीओ) प्रत्यायन कार्यक्रम और आयुष प्रत्यायन कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रत्यायन सेवाएं प्रदान करता है।

प्रशिक्षण और शिक्षा: एनएबीएच आकलनकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कार्यान्वयन कार्यक्रम (पीओआई), शिक्षा इंटरैक्टिव कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करता है।

2.1.1. अप्रेल, 2024 से मार्च, 2025 की अवधि के दौरान प्राप्त नए आवेदनों और प्रदान किए गए नए प्रत्यायन/प्रमाणन की स्थिति नीचे दी गई है:

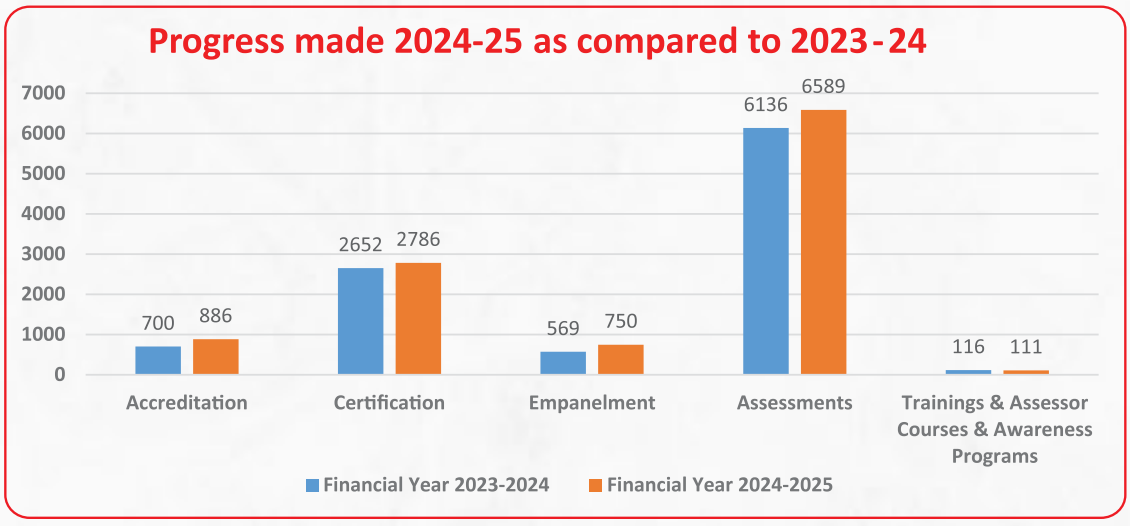
क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	नए आवेदन	नए प्रत्यायन/प्रमाणन
	प्रत्यायन कार्यक्रम		
1	अस्पताल प्रत्यायन कार्यक्रम	280	181
2	लघु स्वास्थ्यचर्या संगठन (एसएचसीओ) प्रत्यायन कार्यक्रम	295	223
3	ब्लड बैंक प्रत्यायन कार्यक्रम	18	8
4	मेडिकल इमेजिंग सेवा प्रत्यायन कार्यक्रम	133	68
5	एलोपैथिक क्लीनिक प्रत्यायन कार्यक्रम	59	38
6	दंत चिकित्सा प्रत्यायन कार्यक्रम	160	90
7	आयुष प्रत्यायन कार्यक्रम	106	97
8	पंचकर्म क्लीनिक प्रत्यायन कार्यक्रम	24	27
9	नैदानिक परीक्षण (आचार समिति) प्रत्यायन कार्यक्रम	3	3
10	नेत्र चिकित्सा संगठन	106	49
11	डिजिटल स्वास्थ्य प्रत्यायन कार्यक्रम	127	100
12	देखभाल गृह प्रत्यायन कार्यक्रम	5	2
	जोड़	1316	886
	प्रमाणन कार्यक्रम		
1	प्रवेश स्तरीय अस्पताल	869	357
2	प्रवेश स्तरीय लघु स्वास्थ्यचर्या संगठन	3093	1364
3	नर्सिंग उत्कृष्टता कार्यक्रम	59	40
4	चिकित्सा प्रयोगशाला कार्यक्रम	10	10
5	अस्पताल में आपातकालीन विभाग	22	21
6	प्रवेश स्तरीय आयुष अस्पताल	60	60
7	प्रवेश स्तरीय आयुष केन्द्र	14	24
8	एनएएम के अंतर्गत आयुष हेल्थ एंड वैलनैस सेंटर	1446	900
9	स्ट्रोक सेंटर प्रमाणन कार्यक्रम	17	10
10	एचआईएस/ ईएमआर प्रणाली	7	0
	जोड़	5597	2786
	एम्पैनलमेंट		
1	पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) एम्पैनलमेंट कार्यक्रम	652	359

2	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) एम्पैनलमेंट कार्यक्रम	660	389
3	मेडिकल वैल्यू ट्रैवल फैसिलिटी (एमवीटीएफ) एम्पैनलमेंट कार्यक्रम	4	2
	जोड़	1316	750



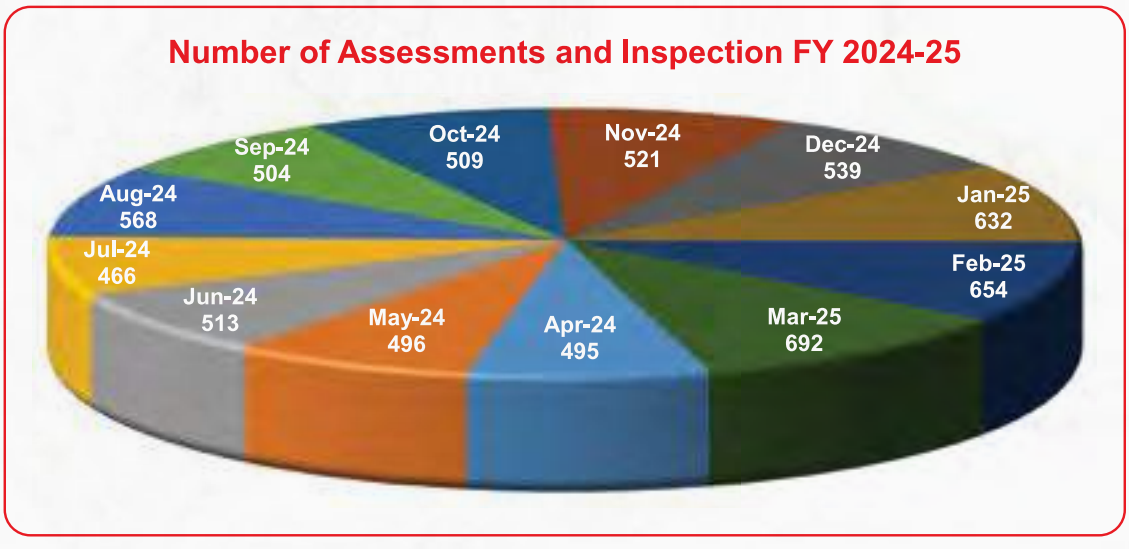
2.1.2. 2023-24 की तुलना में 2024-25 में हुई प्रगति

गतिविधियां	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
प्रत्यायन	700	886
प्रमाणन	2652	2786
एम्पैनलमेंट	569	750
आकलन	6136	6589
प्रशिक्षण और आकलनकर्ता पाठ्यक्रम	116	111



2.1.3. वित्त वर्ष 2024-25 में आकलनों एवं निरीक्षणों की संख्या

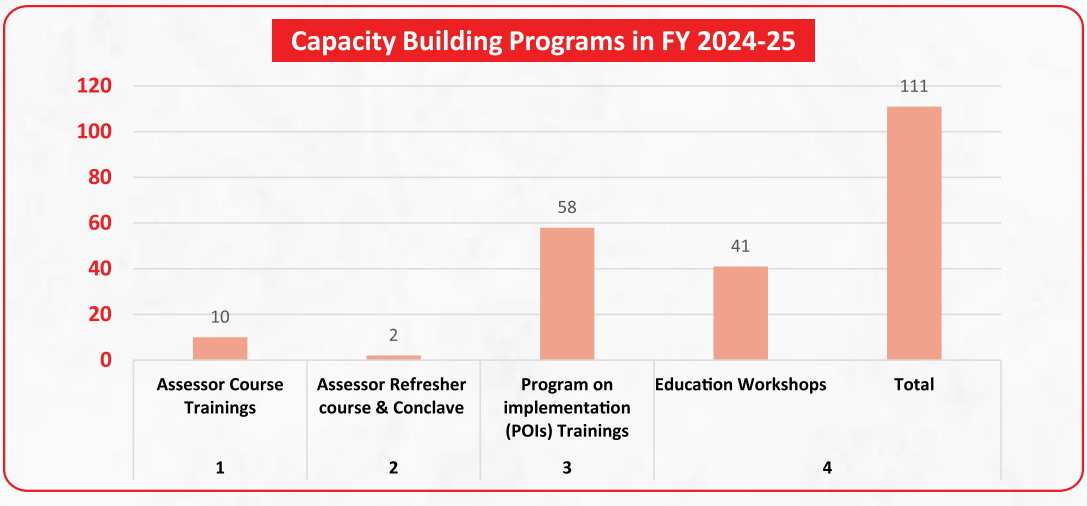
मास एवं वर्ष	आकलनों की संख्या
अप्रेल 2024	495
मई 2024	496
जून 2024	513
जुलाई 2024	466
अगस्त 2024	568
सितंबर 2024	504
अक्टूबर 2024	509
नवंबर 2024	521
दिसंबर 2024	539
जनवरी 2025	632
फरवरी 2025	654
मार्च 2025	692
जोड़	6589



2.1.4. एनएबीएच के साथ गुणवत्ता संपर्क अधिगम के अंतर्गत एनएबीएच आकलनकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, शिक्षा प्रशिक्षणों और कार्यशालाओं की स्थिति

क्रम संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	कुल संख्या
	आकलनकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	
1.	अस्पताल प्रत्यायन आकलनकर्ता पाठ्यक्रम	2
2.	मेडिकल इमेजिंग सेंटर आकलनकर्ता पाठ्यक्रम	1

3.	आयुष आकलनकर्ता पाठ्यक्रम	1
4.	आईआरसीए आकलनकर्ता पाठ्यक्रम	1
5.	प्रवेश स्तरीय अस्पताल एवं एसएचसीओ प्रमाणन आकलनकर्ता पाठ्यक्रम	4
6.	डिजिटल स्वास्थ्य मानक आकलनकर्ता पाठ्यक्रम	1
	कुल आकलनकर्ता पाठ्यक्रम	10
प्रधान आकलनकर्ता क्षेत्रीय कॉन्क्लेव		
1.	आकलनकर्ता पुनश्चर्या पाठ्यक्रम एवं कॉन्क्लेव	2
कार्यान्वयन कार्यक्रम (पीओआई)		
1.	अस्पताल प्रत्यायन मानकों का छठा संस्करण	22
2.	अस्पताल प्रत्यायन मानकों का 5वां संस्करण	14
3.	आयुष प्रत्यायन मानकों का द्वितीय संस्करण	2
4.	दंत चिकित्सा प्रत्यायन मानकों का तृतीय संस्करण	2
5.	एचआईएस/ईएमआर प्रमाणन मानकों का प्रथम संस्करण	3
6.	मेडिकल वैल्यू ट्रैवल फैसिलिटेटर (एमवीटीएफ) पीओआई	2
7.	डिजिटल स्वास्थ्य प्रत्यायन मानकों का प्रथम संस्करण	13
	कुल पीओआई पाठ्यक्रम	58
शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यशालाएं		
1	नैदानिक संपरीक्षा	13
2.	निरंतर गुणवत्ता सुधार	8
3.	रोगी संरक्षा के लिए प्रलेखन अपेक्षाएं	10
4.	उत्तम नैदानिक परीक्षण परिपाटियां (जीसीपी)	10
	कुल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यशालाएं	41



एनएबीएच प्रशिक्षणों की झलक



प्रवेश स्तरीय अस्पताल आकलनकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम विषय पर 24-26 अप्रेल, 2024 को नई दिल्ली में संचालित एनएबीएच आकलनकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम



29 अप्रेल से 3 मई, 2024 तक नई दिल्ली में संचालित एनएबीएच का 48वां अस्पताल आकलनकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम



आयुष प्रत्यायन कार्यक्रम के लिए 8वें एनएबीएच आकलनकर्ता पाठ्यक्रम विषय पर 15 से 19 जुलाई, 2024 तक नई दिल्ली में संचालित एनएबीएच आकलनकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम।



तीन दिवसीय निर्णायक आकलनकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल प्रत्यायन कार्यक्रम आकलनकर्ताओं के साथ-साथ भारत के शीर्ष स्वास्थ्यचर्या सीआईओ और सीटीओ शामिल थे। इनका प्रतिनिधित्व सीएचआईएमई के सदस्यों ने किया। यह अस्पतालों के लिए एनएबीएच के डिजिटल स्वास्थ्य मानकों के प्रथम संस्करण के संबंध में तीसरा आकलनकर्ता प्रशिक्षण था, जो स्वास्थ्यचर्या संस्थाओं को अत्याधुनिक डिजिटल परिपाटियों के अनुरूप बनाने की एक परिवर्तनकारी पहल है।

2.2 विभिन्न मंचों में एनएबीएच की नई भागीदारी:

2.2.1 एनएबीएच की भागीदारी: एनएबीएच टीम ने नई दिल्ली में आयोजित 10वें नेटहेल्थ वार्षिक आरोग्य भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया।



2.2.2 एनएबीएच टीम ने 5 से 7 अप्रेल, 2024 तक सीएएचओकॉन में 'स्वास्थ्यचर्या की गुणवत्ता पर प्रत्यायन का प्रभाव' विषय पर एक सशक्त सत्र का समन्वय किया।



2.2.3 एनएबीएच टीम ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा 10 और 11 अप्रेल, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 में भाग लिया।



2.2.4 एनएबीएच टीम ने 3 मई, 2024 को पुणे में आयोजित एनआरसीईएस प्रयोक्ता समर मीट में भाग लिया। यह ईएचआर मानकों के अंगीकरण, व्यावहारिक चुनौतियों, समाधानों, सर्वोत्तम परिपाटियों और भावी कार्यनीतियों के बारे में सूचना के आदान-प्रदान का एक अवसर था।

डॉ. कुमुदिता तलवार और डॉ. प्रियंका चौहान ने डिजिटल स्वास्थ्य मानकों में एनएबीएच की पहल पर प्रस्तुति दी, जिससे देश भर में अंतर-प्रचालनीय स्वास्थ्यचर्या प्रणाली की स्थापना की दिशा में सहकार्य को बढ़ावा मिला।





2.2.5 एनएबीएच-स्माइल ट्रेन इंडिया प्रोजेक्ट की बैठक 29 अप्रेल, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। स्माइल ट्रेन की निदेशक डॉ. एलिजाबेथ इगागा ने सदस्यों के समक्ष स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट और रोगी संरक्षा के पहलुओं पर अपना संबोधन दिया। एनएबीएच के सीईओ ने एनएबीएच की गतिविधियों और पहलों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद एनएबीएच टीम ने स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट की स्थिति रिपोर्ट पेश की।



2.2.6 एनएबीएच ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के एक भाग के रूप में, एनएबीएच आयुष प्रवेश-स्तरीय प्रमाणन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के 85 से अधिक जिला आयुष अधिकारियों (डीएओ) को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है।



2.2.7 आयुष एमवीटी शिखर सम्मेलन 30 सितंबर, 2024 को होटल सोफिटेल, बीकेसी, मुंबई में आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर्स महासंघ (फिक्की) के सहयोग से किया गया।



2.2.8 एनएबीएच ने जयपुर, कोचीन, भुवनेश्वर और भोपाल में आयोजित सिस्टम इंटीग्रेटर्स इन डिजिटल हेल्थ (एसआईडीएच) कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।



2.2.9 एनएबीएच टीम ने गांधीनगर, गुजरात में 49वें वार्षिक ट्रांसकॉन सम्मेलन में भाग लिया। इसकी मेजबानी इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी (आईएसबीटीआई) ने की थी।





2.2.10 दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में आयोजित नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स की 15वीं बैठक में एनएबीएच की भागीदारी।



2.2.11 एनएबीएच ने फिक्की हील 2024 सम्मेलन में भाग लिया; एनएबीएच की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल देते हुए, भारत में अस्पताल और प्रयोगशाला प्रत्यायन के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया गया।





2.2.12 एनएबीएच को धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के ऐतिहासिक समारोह में भाग लेने का सौभाग्य मिला, जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में स्वास्थ्यचर्या को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया।



2.2.13 एनएबीएच ने राष्ट्रीय समन्वय केन्द्र (एनसीसी) द्वारा 23 सितंबर, 2024 को भारतीय भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद में भारतीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम (पीवीपीआई) के लिए आयोजित चौथे राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह के हितधारकों की बैठक-सह-समापन समारोह में भाग लिया।



2.2.14 एनएबीएच ने 3 से 5 अक्टूबर, 2024 तक शिल्पकला वेदिका, हाईटेक सिटी, हैदराबाद में आयोजित जी-स्पार्क 2024 (ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस ऑन इन्फेक्शन प्रीवेंशन एंड कंट्रोल एंड एंटीमाइक्रोबियल स्टीवार्डशिप) में भाग लिया।



2.2.15 एनएबीएच-क्यूसीआई ने 1 फरवरी, 2025 को यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स, कौशाम्बी में गुणवत्ता गुरुकुल के प्रशिक्षुओं (बैच 7) के लिए क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन किया। इसका उद्देश्य इन छात्रों को यह जानने का एक विशेष अवसर प्रदान करना है कि एनएबीएच, अस्पताल प्रचालन के सभी पहलुओं में गुणवत्तापूर्ण देखभाल और रोगी संरक्षा सुनिश्चित करते हुए, स्वास्थ्यचर्या मानकों को उन्नत करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



2.2.16 एनएबीएच ने एनएबीएच-प्रत्यायित अस्पतालों के उद्देश्य से 31 जनवरी, 2025 को फोर्टिस मोहाली में फार्माकोविजिलेंस पर एक कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस सत्र के दौरान, एनएबीएच में उप निदेशक सुश्री वर्षा श्रीवास्तव ने भारत में एनएबीएच प्रत्यायित अस्पतालों के लिए एडीआर (दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव) रिपोर्टिंग के महत्व पर श्रोताओं को संबोधित किया।



2.2.17 एनएबीएच ने केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयूएम) और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 11 - 12 फरवरी, 2025 को आयोजित यूनानी दिवस 2025 और 'एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार – एक नई दिशा' अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।



2.2.18 एनएबीएच ने 13 फरवरी, 2025 को जामिया हमदर्द में यूनानी दिवस समारोह 2025 और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। सीईओ, एनएबीएच ने सर्वांगीण स्वास्थ्यचर्या में यूनानी चिकित्सा के महत्व पर प्रकाश डाला और मजीदिया अस्पताल को एनएबीएच प्रवेश-स्तरीय प्रमाणन प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया तथा गुणवत्ता और रोगी संरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की।



2.2.19 एनएबीएच ने 21 - 22 फरवरी, 2025 को भारत मंडपम में अपोलो हॉस्पिटल्स द्वारा आयोजित 12वें अंतरराष्ट्रीय रोगी संरक्षा सम्मेलन (आईपीएससी) 2025 में भाग लिया। इस सम्मेलन ने स्वास्थ्यचर्या के क्षेत्र में वैश्विक स्तर के अग्रणी व्यक्तियों को रोगी संरक्षा, गुणवत्ता सुधार और स्वास्थ्यचर्या के भविष्य पर चर्चा करने का एक मंच दिया।



2.2.20 एनएबीएच ने 31 जनवरी, 2025 को कोच्चि में और 7 मार्च, 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित एनएचए सिस्टम इंटीग्रेटर्स इन डिजिटल हेल्थ (एसआईडीएच) कार्यशाला में सक्रियता से भाग लिया।







2.2.21 एनएबीएच रोगी संरक्षा सम्मेलन 2024 (एनपीएससी 2024):

संदेश और इस वर्ष के विषय को अपनाते हुए, एनएबीएच ने 17 सितंबर, 2024 को "एक स्वस्थ देश, विकसित भारत के लिए" विषय पर एक दिवसीय "एनएबीएच रोगी संरक्षा सम्मेलन 2024" का आयोजन किया। यह सम्मेलन, रोगी संरक्षा के सभी पहलुओं को जानने और गहराई से समझने के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में वैश्विक अग्रणी विचारकों, उद्योग विशेषज्ञों और स्वास्थ्यचर्या पेशेवरों ने रोगी संरक्षा के बारे में अपने अनुभवों और अभिनव कार्यनीतियों का आदान-प्रदान किया। यह एक शानदार और उत्साहवर्धक सम्मेलन था जो स्वास्थ्यचर्या के रोगी संरक्षा के नए युग में प्रवेश का प्रतीक है, क्योंकि एनएबीएच ने अस्पतालों, राष्ट्रीय संगठनों, आयुष, डिजिटल स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा जैसे स्वास्थ्यचर्या के सभी पहलुओं के विशेषज्ञ, प्रतिनिधि और हितधारक शामिल किए थे। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य यह चर्चा करना था कि रोगियों की देखभाल के लिए अपनी पहल पर शुरू की गई परिपाटियों, स्वास्थ्यचर्या प्रणालियों और निर्णय लेने में रोगियों को समझने और उन्हें शामिल करने की सुव्यवस्थित प्रणालियों से रोगी संरक्षा में कैसे सुधार हो सकता है। इस सम्मेलन में 7 संवादपरक पैनल चर्चाएं हुईं। देश भर से 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे यह सम्मेलन, भारत के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक सम्मेलन बन गया।















गुणवत्ता प्रतिज्ञा

1000 से अधिक रोगी संरक्षा समर्थकों ने गुणवत्ता भारत प्रतिज्ञा ली। भारतीय गुणवत्ता परिषद् द्वारा शुरू की गई गुणवत्ता भारत प्रतिज्ञा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा देने की एक प्रतिबद्धता है। इस प्रतिज्ञा का उद्देश्य व्यक्तियों और संगठनों को गुणवत्तापूर्ण परिपाटियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके उत्पादकता बढ़ाना, स्थायित्वपूर्ण विकास को बढ़ावा देना और समग्र जीवन स्तर को सुधारना है। प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति यह मानते हुए निरंतर सुधार, नवाचार और सहकार्य के लिए प्रतिबद्ध होते हैं कि गुणवत्ता एक ऐसी सामूहिक जिम्मेदारी है जो सभी उद्योगों में व्याप्त है।

यह पहल, केवल भारतीय उद्यमों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का प्रयास ही नहीं करती है, अपितु भारत को गुणवत्ता उत्कृष्टता में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करती है, जिससे राष्ट्रीय विकास और वैश्विक स्पर्धात्मकता में योगदान मिलता है।





श्री जे पी नड्डा (केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री) ने विश्व रोगी संरक्षा दिवस पर एनएबीएच रोगी संरक्षा सम्मेलन में प्रतिभागियों को वर्चुअली संबोधित किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों से स्वास्थ्यचर्या डेटा के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने का आग्रह किया, जिससे रोगी डेटा की सुरक्षा और सुलभता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने दूरदराज के क्षेत्रों में, जहां विशेषीकृत चिकित्सा विशेषज्ञों तक पहुंच सीमित है, टेलीमेडिसिन ई-स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जब रोगी डेटा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया जाता है, तो कई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, जिनमें डेटा की सुरक्षा, अंतर-प्रचालनीयता और सूचना की सटीकता शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार नवाचारों को बढ़ावा देने और डिजिटल स्वास्थ्यचर्या के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि क्यूसीआई-एनएबीएच की प्रत्यायन प्रणाली ने देश में स्वास्थ्यचर्या सेवाओं के मानकों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एनएबीएच मानक देश के छोटे से छोटे अस्पतालों तक पहुंचें ताकि हर नागरिक उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यचर्या सेवाएं प्राप्त कर सके।

श्री जे पी नड्डा जी-

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7241758170128285696





एनएबीएच क्वालिटी कनेक्ट अनुदान 2024: एनएबीएच क्वालिटी कनेक्ट अनुदान 2024 कार्यक्रम, उन स्वास्थ्यचर्या गुणवत्ता पेशेवरों के लिए है जो स्वास्थ्यचर्या गुणवत्ता और रोगी संरक्षा के क्षेत्र में नवाचारी सोच और बदलाव के साथ नई पहल का सूत्रपात करना चाहते हैं। यह कार्यक्रम इन पेशेवरों को उनके रणनीतिक, प्रचालनात्मक, वैचारिक नेतृत्वकारी और अभिनव कौशलों को अगले स्तर तक ले जाने में सहयोग देने के लिए अभिकल्पित और सृजित किया गया है। कार्यक्रम के लिए चुने गए पेशेवरों को 25,000/- से लेकर 50,000/- रुपए तक के अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया था। इसके आधार पर, 15 जुलाई, 2024 से 15 अगस्त, 2024 तक प्रस्तुतियां आमंत्रित करते हुए एनएबीएच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनएबीएच वेबसाइट के माध्यम से एक विज्ञापन दिया गया था। एनएबीएच को पूरे भारत के विभिन्न स्वास्थ्यचर्या पेशेवरों से जबरदस्त प्रतिक्रिया और जवाब मिले। प्रस्तावों की सिफारिश करते समय व्यवहार्यता, लेख की गुणवत्ता, प्रकाशन की संभावित क्षमता और गुणवत्ता/रोगी संरक्षा की विश्वसनीयता पर विचार किया गया। एनएबीएच द्वारा अनुदान के लिए पांच अभिनव प्रस्तावों का चयन किया गया। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि के संबंध में अपना निर्णय देने के लिए स्वास्थ्यचर्या गुणवत्ता और रोगी संरक्षा क्षेत्र के तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञों एवं अग्रणी व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया गया था। विजेताओं को 17 सितंबर, 2024 को एनएबीएच रोगी संरक्षा सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र में ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और चेक प्रदान किए गए। स्वास्थ्यचर्या और रोगी संरक्षा में गुणवत्ता आश्वासन की केन्द्रित कार्यनीति के लिए स्थापित भारत का राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय - एनएबीएच इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिकतम 5 उम्मीदवारों को शोध के लिए सहायता देगा और उक्त पद्धति से चयनित प्रस्तावों को हर साल 17 सितम्बर (विश्व रोगी संरक्षा दिवस) को इसी प्रक्रिया के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा।











2.2.22 नए एवं संशोधित एनएबीएच मानकों का विमोचन:



अस्पतालों के लिए एनएबीएच प्रत्यायन मानक - छठा संस्करण (स्थानीय भाषाओं सहित)



आयुष उपचार और वैलनैस सेंटर के लिए एनएबीएच प्रत्यायन मानक- प्रथम संस्करण



स्वास्थ्यचर्या में जलवायु कार्रवाई और स्थायित्व के लिए एनएबीएच गाइडबुक - प्रथम संस्करण



मेडिकल वेल्यू ट्रेवल फेसिलिटेटर के लिए एनएबीएच एम्पैनलमेंट मानक - द्वितीय संस्करण



मनोभ्रंश रोग ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अनुकूल अस्पतालों की एनएबीएच चेकलिस्ट -प्रथम संस्करण



एनएबीएच न्यूज़लेटर



आयुष अस्पतालों के लिए एनएबीएच प्रत्यायन मानक- प्रथम संस्करण



एनएबीएच एफओजीएसआई सहकार्य के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा का सुदृढ़ीकरण



एचआईएस/ईएमआर प्रणालियों के लिए एनएबीएच डिजिटल स्वास्थ्य मानक - प्रथम संस्करण

2.3 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह की कुछ झलकियां: स्वास्थ्यचर्या की उन्नति के लिए विभिन्न संगठनों के साथ एनएबीएच की भागीदारी

2.3.1 एनएबीएच ने भारत की सबसे बड़ी डायबिटीज एसोसिएशन - रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडीज ऑफ डायबिटीज इन इंडिया (आरएसएसडीआई) के साथ सहकार्य किया है। इस एसोसिएशन के 12,000 से अधिक सदस्य हैं। इस समझौता ज्ञापन पर श्री रिज़वान कोइता (अध्यक्ष, एनएबीएच) और डॉ. अतुल मोहन कोचर (सीईओ, एनएबीएच) ने हस्ताक्षर किए।

इस भागीदारी के अंतर्गत, आरएसएसडीआई और एनएबीएच-क्यूसीआई, तीन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग करेंगे:

- आरएसएसडीआई के देखभाल संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप एनएबीएच द्वारा मधुमेह-विशिष्ट मानकों का विकास।
- इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स (ईएमआर) और क्लीनिक प्रबंधन प्रणालियों (सीएमएस) के लिए एनएबीएच द्वारा मधुमेह-विशिष्ट मानकों का विकास।
- आरएसएसडीआई सदस्य नेटवर्क में एनएबीएच एलोपैथिक क्लीनिक मानकों का क्रियान्वयन।





2.3.2 एनएबीएच ने एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) के साथ सहकार्य किया। यह सहकार्य टियर-III शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश-स्तरीय प्रमाणन कार्यक्रम और आयुष प्रवेश-स्तरीय प्रमाणन कार्यक्रम के लिए गुजरात राज्य में अस्पतालों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण गतिविधियों के आयोजन के लिए है।

2.3.3 एनएबीएच का गुजरात सरकार के साथ सहकार्य - एनएबीएच ने पूरे राज्य में स्वास्थ्यचर्या सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक रूपरेखा का वर्णन करते हुए प्रस्ताव, गुजरात सरकार को सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दिए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय, गुजरात सरकार द्वारा 3 प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं और इनके लिए कार्य आदेश प्राप्त हो गया है।

2.4 एनएबीएच की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति:

2.4.1 आईएसक्यूयूए सम्मेलन 2024: एनएबीएच टीम ने 23 से 27 सितंबर, 2024 तक इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित आईएसक्यूयूए 2024 सम्मेलन में स्थायित्वपूर्ण देखभाल, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों और रोगी संरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।















12वें अंतरराष्ट्रीय रोगी संरक्षा सम्मेलन (आईपीएससी) 2025 में, एनएबीएच की उप निदेशक, डॉ. कुमुदिता तलवार ने स्वास्थ्यचर्या मानकों के विकास के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने, वैश्विक मानकों के साथ तालमेल सुनिश्चित करते हुए देखभाल की निरंतरता, स्थायित्व के लिए हरित चेकलिस्ट और अद्यतन मेडिकल वेल्यू ट्रेवल (एमवीटी) मानकों पर बल दिया। केवल कुछ ही देशों के अपने प्रत्यायन मानक हैं; भारत वैश्विक स्वास्थ्यचर्या गुणवत्ता और प्रत्यायन में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते हुए अग्रणी बना हुआ है।



2.4.2 एनएबीएच ने 12वें अंतरराष्ट्रीय रोगी संरक्षा सम्मेलन (आईपीएससी) 2025 में भाग लिया। यह सम्मेलन अपोलो हॉस्पिटल्स द्वारा 21 से 22 फरवरी, 2025 को भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन ने स्वास्थ्यचर्या के क्षेत्र में वैश्विक स्तर के अग्रणी व्यक्तियों को रोगी संरक्षा, गुणवत्ता सुधार और स्वास्थ्यचर्या के भविष्य पर चर्चा करने का एक मंच दिया।

श्री अविनाश पांडे, ग्रुप लीड - डिजिटल स्वास्थ्य, एनएबीएच ने 'एनएबीएच नेक्स्टजेन: पथ प्रदर्शक डिजिटल स्वास्थ्य मानक' का परिचय दिया, जो स्वास्थ्यचर्या प्रत्यायन में एक नए युग का सूत्रपात है। यह मान्य करते हुए कि अस्पताल के कार्यप्रवाह के साथ डिजिटल हस्तक्षेपों का एकीकरण अब अत्यावश्यक है, एनएबीएच ने निर्बाध और दक्ष प्रत्यायन रूपरेखा का सृजन करते हुए, अपने गुणवत्ता मानकों को डिजिटल स्वास्थ्य बैंचमार्क के साथ मानचित्रित कर लिया है।

इस पहल के साथ, भारत संभवतः विश्व स्तर पर पहला देश बन गया है जिसने स्वास्थ्यचर्या डिलीवरी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अस्पताल गुणवत्ता मानकों का तालमेल डिजिटल स्वास्थ्य मानकों, एचआईएस और ईएमआर मानकों के साथ बैठाते हुए एकीकृत कार्यनीति अपनाई है।

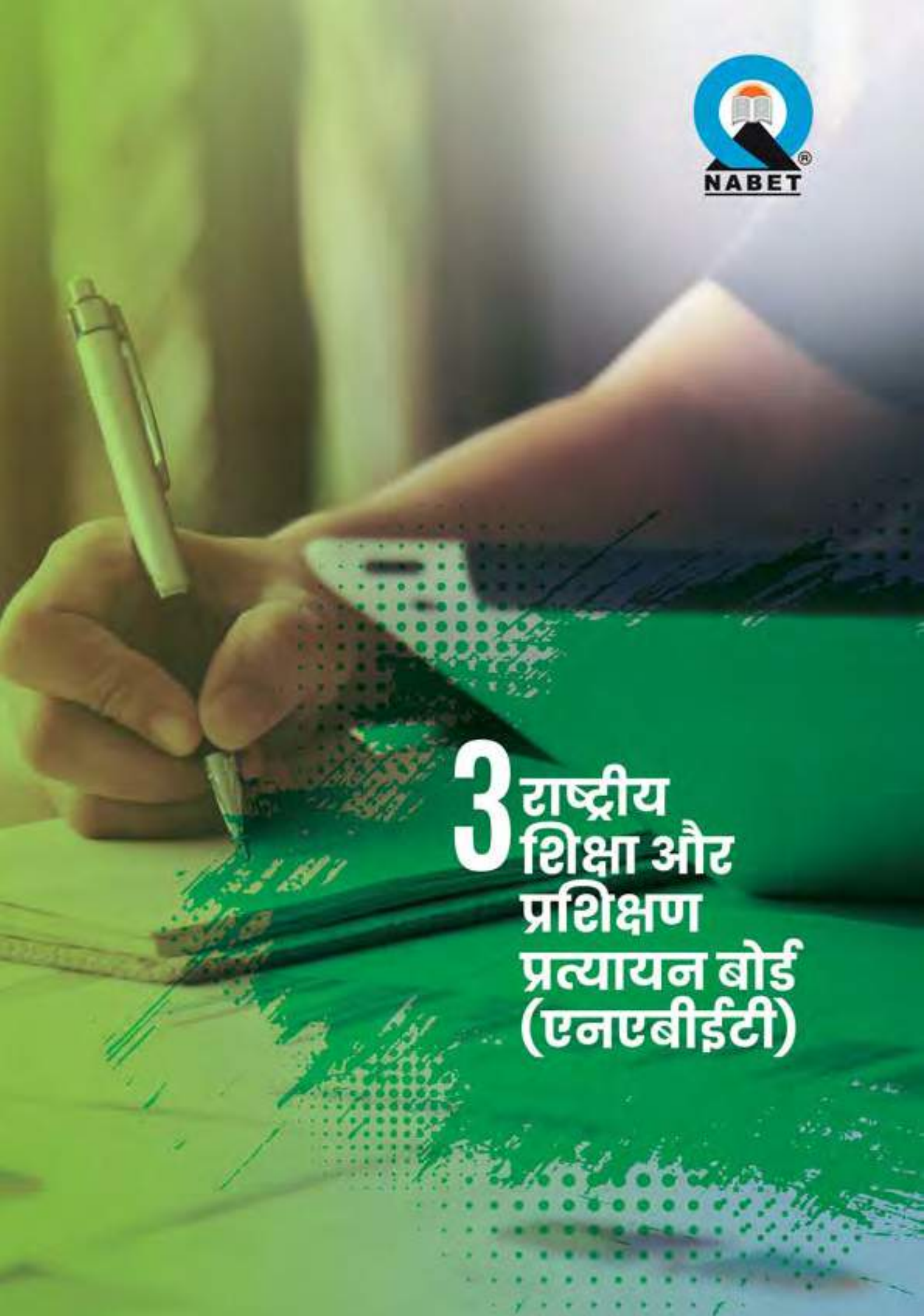


श्री उजैर रहमानी और श्री प्रतीक गौतम द्वारा लिखित, डॉ. प्रियंका चौहान और डॉ. अतुल मोहन कोचर द्वारा सह-लिखित 'गुणवत्ता और रोगी संरक्षा का रूपांतरण: एनएबीएच संदर्श के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्यचर्या का गुणात्मक अन्वेषण', इस शोध पत्र को 12वें अंतरराष्ट्रीय रोगी संरक्षा सम्मेलन (आईपीएससी) में प्रस्तुत किए जाने के लिए चुना गया है।



2.4.3 एनएबीएच ने 19 मार्च, 2025 को थाईलैंड में आयोजित 25वें एचए फोरम - एक अंतरराष्ट्रीय हाइब्रिड सम्मेलन में भाग लिया। एनएबीएच में निदेशक डॉ. पूनम बजाज ने 'भारत में जलवायु उत्थानशील और अनुकूली स्वास्थ्यचर्या पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में एनएबीएच मानकों की क्षमता' विषय पर एक सत्र को संबोधित किया।





3 राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी)

राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी), भारतीय गुणवत्ता परिषद् का एक प्रमुख बोर्ड है। यह बोर्ड शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य, मजबूत प्रत्यायन और आकलन फ्रेमवर्क स्थापित करके अपने अधिदेश के अनुरूप एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो संस्थागत गुणवत्ता में सुधार करे, सक्षमता-आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करे, और राष्ट्रीय कौशल परिदृश्य को उन्नत करें।

3.1 औपचारिक शिक्षा उत्कृष्टता प्रभाग (एफईईडी)

3.1.1 परियोजनाएं:

3.1.1.1 क्षमता निर्माण आयोग के अंतर्गत सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों का आकलन और प्रत्यायन: 1 अप्रेल, 2024 और 31 मार्च, 2025 के बीच, कुल 52 संस्थानों ने सफलतापूर्वक प्रत्यायन और प्रमाणन प्राप्त किया। यद्यपि, प्रत्यायित और प्रमाणित संस्थानों की कुल संख्या 146 है, जो प्रत्यायन और प्रमाणन प्रक्रिया में निरंतर प्रगति दर्शाती है।



हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (एचपीआईपीए) का 11-12 सितंबर, 2024 को संपन्न ऑनसाइट आकलन

3.1.1.2 क्वालिटी सिटी नासिक (शिक्षा परियोजना): एनएबीईटी ने 2023 और 2024 में तीन शिक्षा समितियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल में नासिक के 22 स्कूलों में तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा के 5,000 से अधिक विद्यार्थियों का आकलन शामिल है। 4408 विद्यार्थियों का आकलन और शिक्षकों के 250 क्लासरूम प्रेक्षण पूरे कर लिए गए हैं और परिणामों का संकलन किया जा रहा है।





अगस्त, 2024 माह में विद्यार्थियों का आकलन

3.1.1.3 250 से अधिक आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी महाविद्यालयों का आकलन और रेटिंग: जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 तक 258 आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी महाविद्यालयों का आकलन और रेटिंग कार्य सफलतापूर्वक किया गया।



मई 2024 में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी आकलनकर्ताओं के लिए आकलनकर्ता प्रशिक्षण



अगस्त 2024 में डी.वाई. पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय की सिमुलेशन प्रयोगशाला में आकलन



अगस्त 2024 में एसडीएम आयुर्वेद महाविद्यालय में कौशल प्रयोगशाला का आकलन

3.1.1.4 240 होम्योपैथी महाविद्यालयों का आकलन और रेटिंग: अप्रेल, 2024 से जुलाई, 2024 तक 240 होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों का आकलन और रेटिंग कार्य सफलतापूर्वक किया गया।



मई 2024 में बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों का आकलन



मई 2024 में बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में संकाय सदस्यों के साथ संपर्क-संवाद



जुलाई 2024 में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों के साथ संपर्क-संवाद

3.1.1.5 स्कूली शिक्षा का रूपांतरण:

पीसीएमसी और क्यूसीआई के बीच सहकार्य: क्यूसीआई महासचिव श्री चक्रवर्ती टी. कन्नन ने कक्षा 1 से 10 तक के 45,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाली एक रूपांतरकारी शिक्षा पहल के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम (पीसीएमसी) के स्कूलों का दौरा किया। अपनी इस यात्रा के दौरान, महासचिव ने कार्यक्रम की प्रगति और चुनौतियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और आकलनकर्ताओं से बातचीत की। इस विचार-विमर्श से हस्तक्षेप रणनीतियों को परिष्कृत करने और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को इष्टतम बनाने की क्यूसीआई की प्रतिबद्धता और सुदृढ़ हुई। उनकी यह यात्रा, क्यूसीआई के शैक्षिक मानकों को उन्नत करने और देश भर में प्रभावी मॉडलों को बढ़ावा देने के मिशन में एक मील का पत्थर सिद्ध हुई।

इस परियोजना का प्रयास है कि 128 पीसीएमसी स्कूलों में तीन-वर्षीय हस्तक्षेप मॉडल के जरिए विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में सुधार लाया जाए। अब तक, 42,000 से अधिक विद्यार्थियों का आकलन और 950 शिक्षकों का प्रेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और इस समय परिणाम संकलित किए जा रहे हैं।



जुलाई 2024 में पीसीएमसी स्कूलों के दौरे पर एक स्कूल द्वारा क्यूसीआई के महासचिव का स्वागत



जुलाई 2024 में क्यूसीआई आकलनकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए क्यूसीआई के महासचिव



जुलाई 2024 में क्यूसीआई के महासचिव और स्कूल के प्रधानाचार्य के बीच बातचीत

3.1.1.6 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत 300 जनजातीय आश्रम विद्यालयों और छात्रावासों का आकलन और मूल्यांकन: इस परियोजना के एक भाग के रूप में, पांच राज्यों में 300 जनजातीय विद्यालयों और छात्रावासों का छह प्रमुख मापदंडों के आधार पर आकलन किया गया। अंतरालों की पहचान की गई और प्रत्येक विद्यालय और छात्रावास की गुणवत्ता में सुधार के लिए रणनीतियों की संस्तुति की गई।



मई 2024 में आश्रम विद्यालयों और छात्रावासों का आकलन



मई 2024 में आश्रम विद्यालयों और छात्रावासों का आकलन

3.1.1.7 उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी (यूपीएसएमएफ) के अंतर्गत संबद्धता अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों का आकलन: एनएबीईटी, क्यूसीआई को नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों के निरीक्षण का कार्य सौंपा गया था। इस परियोजना के कार्यक्षेत्र में 698 संस्थानों का निरीक्षण शामिल था, जिसमें भारतीय नर्सिंग परिषद और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार शिक्षण ब्लॉक, छात्रावास ब्लॉक और अस्पताल शामिल थे।

संबंधित संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में विचार हेतु वर्ष 2024-25 की विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत कर दी गई है।



अगस्त 2024 में यूपीएसएमएफ के अंतर्गत नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण



सितम्बर 2024 में यूपीएसएमएफ के अंतर्गत नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण

3.1.1.8 बिहार नर्स पंजीकरण परिषद (बीएनआरसी): इस परियोजना के प्रथम चरण जिसमें 231 नर्सिंग संस्थानों का आकलन किया गया था, के सफल समापन के बाद, एनएबीईटी-क्यूसीआई को द्वितीय चरण के तहत 84 अन्य नर्सिंग संस्थानों के आकलन के लिए एक अतिरिक्त कार्य आदेश दिया गया।

जमीनी निष्कर्षों पर आधारित एक मसौदा आकलन रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत कर दी गई है। अंतिम रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है और इसे अप्रेल 2025 में प्रस्तुत किया जाना तय है।



दिसम्बर, 2024 माह में बिहार आकलन

3.1.2 अन्य गतिविधियां:

3.1.2.1 आकलनकर्ताओं की बैठक: एनएबीईटी ने प्रत्यायन प्रक्रिया का मानकीकरण करने के लिए 31 जनवरी, 2025 को दिल्ली में आकलनकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में मानकों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर ध्यान दिया गया।



31 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित आकलनकर्ताओं की बैठक



31 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित आकलनकर्ताओं की बैठक



31 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित आकलनकर्ताओं की बैठक

3.1.2.2 संपर्क विस्तार गतिविधियां: क्यूसीआई में वरिष्ठ सलाहकार सुश्री मधु अहलूवालिया ने एनएबीईटी-क्यूसीआई की पहलों पर प्रकाश डालते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत समतापूर्ण, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अपने विचार साझा किए। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और 60 से अधिक स्कूल हितधारकों के समक्ष रूपांतरकारी शिक्षा और विकसित भारत के विज़न के बारे में संबोधन दिया।



फरवरी, 2025 में संपन्न कार्यक्रम की झलक



फरवरी, 2025 में संपन्न कार्यक्रम की झलक

3.2 पर्यावरण एवं अन्वेषण प्रभाग (ईईडी)

3.2.1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 15 अप्रेल, 2024 को सांविधिक स्वीकृतियों के संबंध में "पर्यावरण अनुकूल शमन उपायों और चुनौतियों सहित एफसी, ईसी और ईआईए-ईएमपी प्रस्तावों की तैयारी" विषय पर आयोजित **एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला।** प्रतिभागियों की कुल संख्या लगभग 800 (300 भौतिक रूप में और 500 ऑनलाइन मोड में) थी। ये प्रतिभागी मुख्य रूप से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्यूसीआई-एनएबीईटी, डीपीआर परामर्शदाता, रियायतग्राही, एई और आईई संगठनों से थे। इसमें क्यूसीआई-एनएबीईटी में वरिष्ठ निदेशक **श्री ए. के. झा** ने भाग लिया।



पर्यावरण अनुकूल शमन उपायों और चुनौतियों सहित एफसी, ईसी और ईआईए-ईएमपी प्रस्तावों की तैयारी विषय पर कार्यशाला।

3.2.2 कार्मेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स फॉर वुमेन, नुवेम-गोवा के जीवविज्ञान विभाग ने 6 अप्रेल, 2024 को पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) की गुणवत्ता बढ़ाने में क्यूसीआई-एनएबीईटी की भूमिका पर एक ऑनलाइन अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया। डॉ. यति कछावा (उप निदेशक) ने व्याख्यान दिया, जिसमें लगभग 40 विद्यार्थियों /प्रतिभागियों ने भाग लिया।



ईआईए की गुणवत्ता बढ़ाने में क्यूसीआई-एनएबीईटी की भूमिका पर ऑनलाइन अतिथि व्याख्यान

3.2.3 पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं के लिए 28 मई, 2024 को गुवाहाटी, असम में 'पर्यावरणीय प्रभाव आकलन परामर्शदाता संगठनों के लिए प्रत्यायन स्कीम' विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुल 25 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।



'पर्यावरणीय प्रभाव आकलन परामर्शदाता संगठनों के लिए प्रत्यायन स्कीम' विषय पर जागरूकता कार्यशाला

3.2.4 सीएमपीडीआईएल, रांची (झारखंड) में 19-21 जून, 2024 तक एक क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भिन्न-भिन्न तकनीकी/ ईआईए-संबंधी सत्र शामिल थे। प्रतिभागियों की कुल संख्या लगभग 50 थी।



सीएमपीडीआईएल, रांची में क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

3.2.5 प्रभाग द्वारा 5 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में "भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा उत्थानशीलता" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 130 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

3.2.6 राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार: 20 अगस्त, 2024 को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र में 2023 के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार (एनजीए) प्रदान किए। इस समारोह में कुल 21 भूवैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, प्रतिष्ठित भूवैज्ञानिक, शोधार्थी, नीति निर्माता और उद्योग जगत के महारथी शामिल थे। क्यूसीआई-एनएबीईटी की ओर से वरिष्ठ निदेशक श्री ए.के. झा और संयुक्त निदेशक श्री जगमिंदर कटारिया भी उपस्थित थे।

3.2.7 पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) द्वारा 19 जुलाई, 2024 को चौथा अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। 'डेंटेड कॉर्न एथेनॉल: एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड डीकार्बोनाइजेशन' विषयक इस सम्मेलन में दुनिया की सतत विकास की यात्रा के साथ-साथ परस्पर जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डाला गया। इसमें लगभग 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया।





चौथा अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2024, ताज पैलेस, नई दिल्ली

3.2.8 विश्व ओजोन दिवस 2024 का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 13 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। वर्ष 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सदस्य बनने के बाद से ही भारत सरकार हर वर्ष राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विश्व ओजोन दिवस मनाती रही है। इस वर्ष लगभग 350 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। इस वर्ष का विषय "मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन" था।



भारत मंडपम में विश्व ओजोन दिवस 2024 का आयोजन

3.2.9 प्रत्यायित परामर्शदाता संगठन (एसीओ) की बैठक 11 सितंबर, 2024 (बुधवार) को होटल रेडिसन ब्लू प्लाजा, नई दिल्ली में आयोजित की गई। एसीओ बैठक की कार्यसूची में व्यापक ईआईए स्कीम के दिशानिर्देशों में नए संशोधनों, पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया के मूल्यांकन तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रत्यायित परामर्शदाताओं से अपेक्षाओं पर चर्चा शामिल थी। इसने परामर्शदाताओं को प्रत्यायन के संबंध में अपने दृष्टिकोण साझा करने और विकास के नए अवसर तलाशने के लिए एक मंच भी प्रदान किया। एनएबीईटी का प्रतिनिधित्व सीईओ डॉ. वरिंदर सिंह कंवर ने किया। उन्होंने स्वागत भाषण दिया और समापन सत्र में समापन टिप्पणी की। क्यूसीआई महासचिव श्री चक्रवर्ती टी. कन्नन ने उद्घाटन सत्र के दौरान संबोधन दिया। एनएबीईटी, क्यूसीआई में वरिष्ठ निदेशक श्री ए. के. झा ने व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन स्कीम के दिशानिर्देशों में संशोधनों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में निदेशक डॉ. श्रुति राय ने पर्यावरण संरक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन और अनुपालन निगरानी पर सत्र का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में कुल 230 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।



प्रत्यायित परामर्शदाता संगठन (एसीओ) की बैठक

3.2.10 क्यूसीआई-एनएबीईटी के पर्यावरण प्रभाग ने 25-27 सितंबर, 2024 तक होटल प्राइड, पुणे, महाराष्ट्र में प्रत्यायित परामर्शदाता संगठनों के लिए तीन दिवसीय "क्षमता निर्माण कार्यशाला" का आयोजन किया। इस अवसर पर श्री दीपक गोविंदराव म्हैसेकर (सेवानिवृत्त आईएएस), अध्यक्ष एसईआईएए मुख्य अतिथि और डॉ. दीपाली निंबालकर, वीएसआई, पुणे विशिष्ट अतिथि थीं। इस कार्यशाला की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुई और एनएबीईटी में वरिष्ठ निदेशक श्री ए. के. झा ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए स्वागत भाषण दिया। इसके बाद विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि ने अपने-अपने संबोधन दिए। इस कार्यशाला में प्रत्यायित परामर्शदाता संगठनों के 70 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। श्री ए. के. झा के साथ-साथ डॉ. यति कछावा, उप निदेशक और सुश्री कृतिका शर्मा, प्रत्यायन अधिकारी ने एनएबीईटी का प्रतिनिधित्व किया गया।



पुणे में प्रत्यायित परामर्शदाता संगठनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला



पुणे में प्रत्यायित परामर्शदाता संगठनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला

3.2.11 क्यूसीआई-एनएबीईटी ने 17-19 दिसंबर, 2024 तक पार्क इन बाई रेडिसन, सूरत, गुजरात में एक तीन दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य उच्च-गुणवत्तापूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट तैयार करने के लिए ईआईए परामर्शदाताओं की क्षमता बढ़ाना था। इस कार्यशाला में पर्यावरणीय क्षति आकलन एवं बहाली लागत/ क्षतिपूर्ति की गणना; विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) और ईएसजी परिपाटियां; ईआईए रिपोर्ट तैयार करने में जीआईएस का प्रयोग; सामाजिक-आर्थिक और आधारभूत अध्ययन; पारिस्थितिकी; जैव विविधता जोखिम और खतरों का आकलन; प्रभाव पहचान के लिए डेटा का परिमाणीकरण और व्याख्या; व्यावहारिक समूह गतिविधियां और प्रकरण अध्ययन; तथा परिवेश 2.0 में अंतर्दृष्टि सहित महत्वपूर्ण प्रकरण शामिल किए गए थे। ईआईए समन्वयकों, कार्यशील क्षेत्र विशेषज्ञों और सहयोगियों सहित 45 से अधिक पेशेवरों की भागीदारी के साथ इस कार्यशाला में 8-10 अनुभवी संकाय सदस्यों ने भाग लिया, जिन्होंने ईआईए की तैयारी में अपनी विशेषज्ञता और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि साझा की। इस कार्यशाला ने पर्यावरणीय आकलनों के क्षेत्र में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए समृद्ध चर्चाओं, व्यावहारिक गतिविधियों और अधिगम के अवसरों को बढ़ावा दिया। क्यूसीआई- एनएबीईटी का प्रतिनिधित्व डॉ. ए. के. झा (वरिष्ठ निदेशक), डॉ. यति कछावा (उप निदेशक) और श्री विपिन पंत (प्रत्यायन अधिकारी) ने किया।





सूरत में उच्च-गुणवत्तापूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट तैयार करने हेतु ईआईए परामर्शदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला

3.2.12 बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीएंडआई) ने 10 फरवरी, 2025 को सिल्वर ओक हॉल, इंडिया हैबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली में लगभग 70 प्रतिभागियों के साथ अपना वार्षिक 'मिनरल्स माइनिंग एंड मेटल्स कॉन्क्लेव' आयोजित किया। इस कार्यक्रम में श्री संदीप पौंड्रिक, आईएएस, सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार; श्री नागेंद्र सिन्हा, धातु राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष एवं इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव; श्री राणा सोम, खनिज एवं खनन राष्ट्रीय समिति, बीसीसीएंडआई के मार्गदर्शक और एनएमडीसी एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पूर्व सीएमडी; तथा क्यूसीआई-एनएबीईटी से श्री जगमिंदर कटारिया, संयुक्त निदेशक और डॉ. यति कछावा, उप निदेशक सहित गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। उन्होंने खनिज, खनन एवं धातु क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों, स्थायित्व और प्रगति पर चर्चा की।



आईएचसी, नई दिल्ली में वार्षिक मिनरल्स माइनिंग एंड मेटल्स कॉन्क्लेव

3.2.13 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 15 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में "जीआईएस - आधारित एलएपी निर्माण, जीएचडी के लिए जीआईएस मानचित्रण और वन एवं पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित मुद्दे" विषय पर एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। लगभग 75 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य उच्च गुणवत्तापूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर बल देते हुए, एनएचएआई की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण योजना (एलएपी) की दक्षता बढ़ाना था। क्यूसीआई-एनएबीईटी के सीईओ प्रो. (डॉ.) वरिंदर एस. कंवर ने तकनीकी सत्र के दौरान सड़क अवसंरचना क्षेत्र के लिए गुणवत्तापूर्ण परामर्शदाताओं के चयन पर बहुमूल्य जानकारी साझा की और एक प्रभावी डीपीआर परामर्शदाता की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया।



"जीआईएस-आधारित एलएपी निर्माण, जीएचडी के लिए जीआईएस मानचित्रण और वन एवं पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित मुद्दे" विषय पर कार्यशाला

3.2.14 भारत जलवायु सप्ताह 2025: जलवायु कार्रवाई के लिए विश्व को एकजुट करने का कार्य 3 से 7 फरवरी, 2025 तक किया गया, जिसमें जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक हितधारकों को एक साथ लाया गया। भारत ईपीआर गठबंधन का शुभारंभ, इस कार्यक्रम की एक प्रमुख घटना थी। इसका उद्देश्य निवल-शून्य समाधानों में अग्रता लेना और डीकार्बोनाइजेशन एवं उत्थानशीलता के लिए सहभागिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसमें सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ताओं, नीति निर्माताओं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों ने भाग लिया। क्यूसीआई-एनएबीईटी का प्रतिनिधित्व करते हुए उप निदेशक डॉ. यति कछावा उक्त चर्चा में उपस्थित रहे। इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण सत्र 6 फरवरी, 2025 को ली मेरिडियन, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जो स्थायित्वपूर्ण समाधानों और जलवायु उत्थानशीलता के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।



ली-मेरिडियन, नई दिल्ली में भारत जलवायु सप्ताह 2025

3.2.15 विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च, 2025 तक आयोजित किया गया। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन "पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डिवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस" विषय पर केन्द्रित था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गयाना के माननीय प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर मार्क फिलिप और ब्राजील की माननीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सुश्री मरीना सिल्वा ने किया। इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और विषय विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। इस शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें क्यूसीआई-एनएबीईटी का प्रतिनिधित्व सहायक निदेशक श्री विपिन चंद्र पंत ने किया। सम्मेलन में सतत विकास और जलवायु कार्रवाई पर सहयोग और चर्चा को बढ़ावा दिया गया।



आईएचसी, नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025

3.2.16 पर्यावरण प्रभाग चार प्रत्यायन स्कीमें प्रचालित कर रहा है।

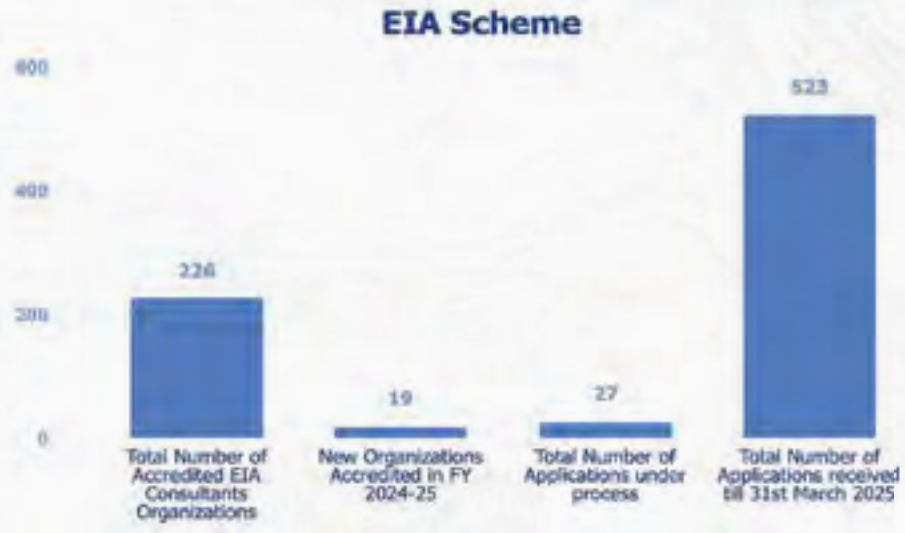
क. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) परामर्शदाता संगठन।

ख. जल शक्ति मिशन के अंतर्गत भूजल परामर्शदाता संगठन।

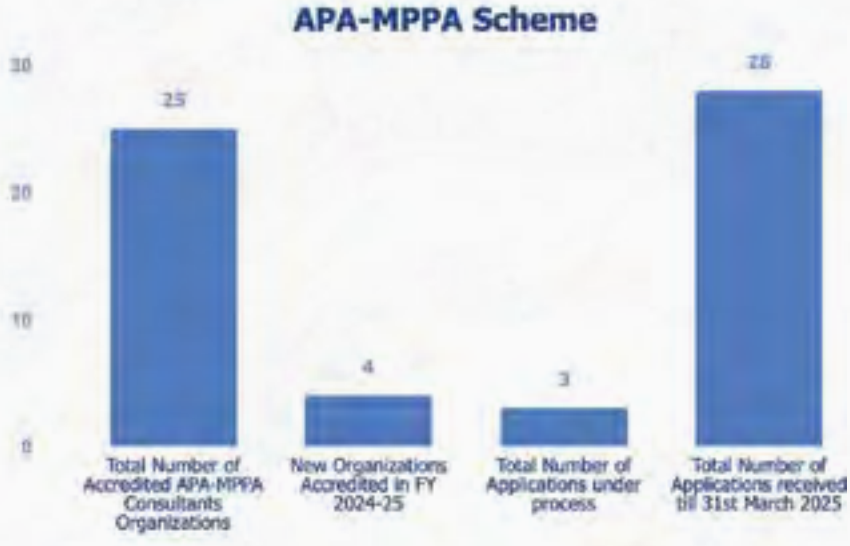
ग. कोयला मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वेक्षण/खनन योजना तैयार करने वाली एजेंसियां (एपीए/एमपीपीए)।

घ. खान मंत्रालय के अंतर्गत खनिज क्षेत्र में अन्वेषण एजेंसियों (एईए) के लिए प्रत्यायन स्कीम।

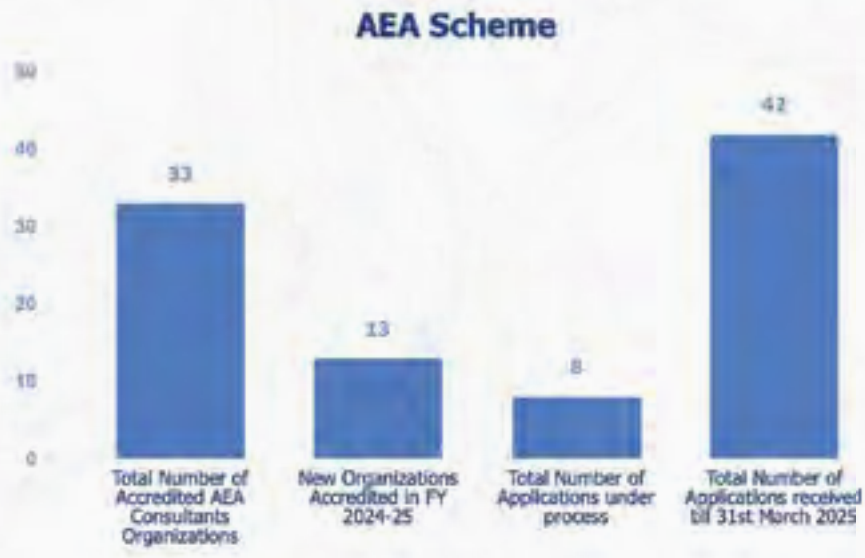
ईआईए परामर्शदाता संगठनों के लिए प्रत्यायन स्कीम



कोयला क्षेत्र में अन्वेषण और खनन योजनाएं तैयार करने वाली एजेंसियों के लिए प्रत्यायन स्कीम



खनिज क्षेत्र में अन्वेषण एजेंसियों (एईए) के लिए प्रत्यायन स्कीम



भूजल परामर्शदाता संगठनों के लिए प्रत्यायन स्कीम



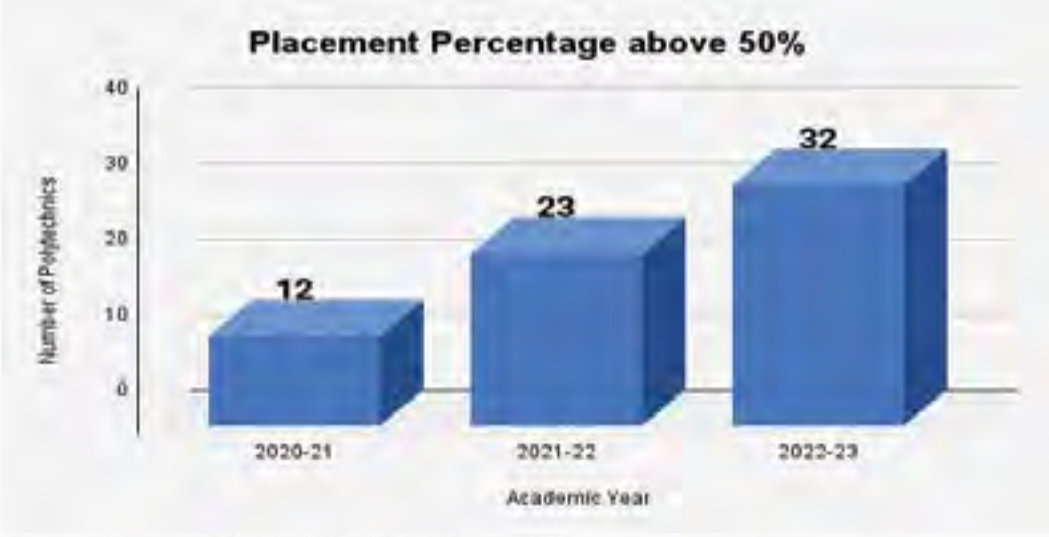
3.3 एमएसएमई लीन और कौशल प्रशिक्षण एवं सेवा (एसटीएस) प्रभाग

3.3.1 कौशल प्रशिक्षण एवं सेवा प्रभाग

एनएबीईटी-क्यूसीआई ने जून 2024 में पॉलिटेक्निकों की रैंकिंग का तीसरा चक्र पूरा कर लिया। रैंकिंग प्रक्रिया के तीसरे चक्र में कुल 132 सरकारी और निजी पॉलिटेक्निकों ने भाग लिया। इस चक्र की रिपोर्ट 30 जुलाई, 2024 को ओडिशा सरकार के कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के माननीय राज्य मंत्री श्री संपद चंद्र स्वाईं द्वारा जारी की गई। ओडिशा सरकार की इस अनूठी परियोजना का उद्देश्य, पॉलिटेक्निकों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाना और विद्यार्थियों के शिक्षण एवं अधिगम परिणामों को बेहतर बनाना था। इस क्षेत्र में क्यूसीआई के गुणवत्तापूर्ण हस्तक्षेपों के फलस्वरूप उल्लेखनीय सुधार हुए, जिससे पिछले तीन चक्रों में मूल्यांकन मापदंडों (सात व्यापक

मापदंड और चौरासी उप-मापदंड) के आधार पर लगभग सभी प्रतिभागी पॉलिटेक्निकों के प्रदर्शन में क्रमिक वृद्धि हुई। इस प्रगति के कारण पॉलिटेक्निकों के एनबीए प्रत्यायन और एआरआईआईएफ रैंकिंग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता में इससे लगभग 30% की वृद्धि हुई है (इसका विवरण नीचे दिए गए चार्ट में प्रस्तुत है)।

आकलन वर्ष 2022-23, आकलन वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2020-21 की तुलना में सभी पॉलिटेक्निकों के नियोजन प्रतिशत में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है।





तीसरे चक्र की रिपोर्ट का विमोचन ओडिशा सरकार के एससीटीई और वीटी विभाग के माननीय राज्य मंत्री श्री संपद चंद्र स्वाईं द्वारा किया गया।

3.3.2 एमएसएमई लीन प्रभाग

भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) - राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी) को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन स्कीम के अंतर्गत एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 क्यूसीआई- एनएबीईटी में एमएसएमई लीन वर्टीकल के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। इसमें कार्यान्वयन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति दर्ज हुई है।

प्रमुख उपलब्धियां

क) विस्तार और उद्योग सहकार्य: वित्त वर्ष 2024-25 में, क्यूसीआई- एनएबीईटी ने निम्नलिखित के माध्यम से अपने संपर्क-विस्तार में महत्वपूर्ण वृद्धि की है:

- 26,613 एमएसएमई को लीन प्लेटफॉर्म पर शामिल करके।
- लघु उद्योग भारती और भारतीय उद्योग संघ जैसे प्रमुख उद्योग संघों के साथ सहयोग करके।
- मेसर्स फोर्ब्स मार्शल, मेसर्स एवन साइकिल्स, मेसर्स मोंटे कार्लो और मेसर्स जे.के. टायर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठित मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) से जुड़कर।

ख) स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई की प्रगति

भिन्न-भिन्न चरणों में एमएसएमई की ऑन-बोर्डिंग और प्रगति का सारांश नीचे दिया गया है:

चरण	संख्या
एमएसएमई पंजीकरण	26,613
मूल प्रमाणन	8,639
मध्यवर्ती पंजीकृत एमएसएमई	526
उद्यमों के गठित समूह (जीओई)	59

ग) **सहायता और संपर्क-विस्तार गतिविधियां:** लीन स्कीम के संबंध में क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गईं:

गतिविधि	संख्या
संचालित जागरूकता कार्यक्रम	300
लीन विनिर्माण परामर्शदाता (एलएमसी) – 5 दिवसीय प्रशिक्षण	10
संचालित आकलनकर्ता कार्यक्रम	1
पैनलबद्ध एलएमसी संगठन	22
पैनलबद्ध परामर्शदाता	204



3.4 उच्चतर शिक्षा - अनुसंधान विश्लेषण और क्षमता निर्माण प्रभाग (एचई-आरएसीबी)

उच्चतर शिक्षा-आरएसीबी प्रभाग शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण हस्तक्षेप के नए अवसर तलाश रहा है तथा यह उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान, जो वर्तमान वैश्विक परिवर्तनकारी युग में अत्यधिक रुचि के क्षेत्र हैं, में गुणवत्ता सूचकांकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

3.4.1 उच्चतर शिक्षण संस्थाओं (एचईआई) की संपरीक्षा

उच्चतर शिक्षा-आरएसीबी प्रभाग को हरियाणा के 24 निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक संपरीक्षा करने का कार्य आदेश प्राप्त हुआ है। गुरुग्राम स्थित स्टारेक्स विश्वविद्यालय की संपरीक्षा पूरी कर ली गई है और इसकी रिपोर्ट हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा निदेशालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

इस प्रभाग ने विशेषज्ञों के परामर्श से उच्चतर शिक्षण संस्थाओं (एचईआई) में शैक्षणिक और प्रशासनिक संपरीक्षा (एएए); एक प्रमाणन कार्यक्रम (राष्ट्रीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गुणवत्ता प्रमाणपत्र); और उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग (आरएचएआई) के लिए अवधारणा नोट्स, रूपरेखाएं और मानक प्रचालन पद्धतियां (एसओपी) विकसित की हैं। 24 फरवरी, 2025 को विशेषज्ञ समिति के साथ हुई पिछली बैठक में, उच्चतर शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक और प्रशासनिक संपरीक्षा के लिए रूपरेखा और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं; प्रमाणन कार्यक्रम (एनएचईक्यूसी) के लिए रूपरेखा; और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की रैंकिंग के लिए अवधारणा नोट, रूपरेखा और मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप दिया गया। समिति ने प्रस्तावित एनएएसी अपडेट के अनुसार विकसित की जा रही बाइनरी प्रत्यायन रूपरेखा पर भी चर्चा की। विकसित रूपरेखा के आधार पर, अदाणी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद की शैक्षणिक और प्रशासनिक संपरीक्षा 10-11 मार्च, 2025 को की गई है।



उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, एनएचईक्यूसी और आरएचएआई की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संपरीक्षा के लिए रूपरेखा, मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अवधारणा नोट पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए एनएबीईटी-क्यूसीआई कार्यालय में संपन्न उप-सलाहकार समिति की बैठकें।

3.4.2 अनुप्रयुक्त एवं औद्योगिक अनुसंधान:

3.4.2.1 भारत-जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईजीएसटीसी) के साथ सहकार्य

एनएबीईटी के एचई-आरएसीबी प्रभाग ने आईजीएसटीसी की 2+2 द्विपक्षीय परियोजनाओं के लिए उद्योगों की अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं का मूल्यांकन किया, जिसमें 16 भारतीय उद्योग भागीदार शामिल थे। ये भागीदार भारत और जर्मनी, दोनों के एक शैक्षणिक संस्थान और एक उद्योग द्वारा गठित संघ का हिस्सा हैं, जो स्थापित रूपरेखा के अनुसार आईजीएसटीसी के 2+2 द्विपक्षीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आईजीएसटीसी ने विशेषत: "स्थायित्व के लिए एआई" के विषय क्षेत्र में 2+2 भागीदारी विधि से औद्योगिक प्रासंगिकता वाली संयुक्त अनुसंधान एवं विकास एवं नवाचार परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। तत्पश्चात चुने गए उद्योग, प्रस्तावित परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं, तकनीकी जानकारी और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, संघ में उनकी भूमिकाओं के आकलन हेतु प्रभाग को भेजे गए।



आईजीएसटीसी के 2+2 द्विपक्षीय प्रस्तावों पर 25 नवंबर, 2024 को सुहोरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा में विशेषज्ञों की बातचीत



आईजीएसटीसी के 2+2 द्विपक्षीय प्रस्तावों पर 28 नवंबर, 2024 को ग्रोलॉक प्राइवेट लिमिटेड, पुणे में विशेषज्ञों की बातचीत

3.4.3 वैज्ञानिक परियोजनाएं:

3.4.3.1 आई-एसटीईएम नेशनल पोर्टल का प्रभाव आकलन

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने आई-एसटीईएम नेशनल पोर्टल का प्रभाव आकलन अध्ययन करने के लिए इस प्रभाग को काम सौंपा है। बेंगलुरु स्थित आई-एसटीईएम कार्यालय से आई-एसटीईएम पोर्टल की प्रतिभागी संस्थाओं और लाभार्थी प्रयोक्ताओं की सूची प्राप्त की गई है। डेटा, जो बहुत बड़ा था, का गहन विश्लेषण किया गया तथा समय की पाबंदी और वित्तीय सीमाओं के आधार पर, प्रभाव आकलन के लिए नमूने के तौर पर 10% डेटा साइज लिया गया है। इसमें 315 संस्थान और 939 प्रयोक्ता शामिल हैं जिनका चयन आई-एसटीईएम के अधिकारियों और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के साथ विचार विमर्श करने के बाद किया गया है। इसके अलावा, चयनित नमूनों के बड़े आकार और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, 10% संपर्क-संवाद भौतिक रूप से किया जा रहा है और शेष 90% संपर्क-संवाद वर्चुअल विधि से किया जा रहा है। अब तक लगभग 40% भौतिक आकलन और 10% वर्चुअल आकलन कर लिया गया है।



आई-एसटीईएम नेशनल पोर्टल के प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए 8 मार्च, 2025 को आईआईटी मंडी में विशेषज्ञों के साथ संवाद-संपर्क



आई-एसटीईएम नेशनल पोर्टल के प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए 3 मार्च, 2025 को जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली में विशेषज्ञों के साथ संवाद-संपर्क



आई-एसटीईएम नेशनल पोर्टल के प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए 4 मार्च, 2025 को एनआईटी कालीकट में विशेषज्ञों के साथ संवाद-संपर्क

3.5 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रभाग (टीसीबी प्रभाग)

3.5.1 गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रभाग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यशालाओं और क्षमता निर्माण गतिविधियों का समन्वय करता है। यह प्रभाग अनुरूपता आकलन, खाद्य, सामान्य प्रबंधन प्रणाली, चिकित्सा और स्वास्थ्यचर्या, विनिर्माण, पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुदेशक के नेतृत्व में, वर्चुअल, ऑनसाइट प्रशिक्षण और ई-लर्निंग सत्र संचालित करता है।

3.5.2 गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा

3.5.2.1 अनुदेशक के नेतृत्व में प्रशिक्षण (वर्चुअल और ऑनसाइट)

क) वित्त वर्ष 2024-25 में, टीसीबी द्वारा कुल 148 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 5913 पेशेवर उपस्थित थे। आईएसओ/आईईसी 17020, आईएसओ/आईईसी 17021, आईएसओ/आईईसी 17025, आईएसओ 13485, आईएसओ 15189 और आईएसओ/आईईसी 17065 सहित विभिन्न प्रत्यायन और प्रमाणन मानकों के संबंध में वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। सिक्स सिग्मा यलो बेल्ट प्रमाणन, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और डिजिटल मार्केटिंग के मूल सिद्धांतों जैसे सामान्य प्रबंधन के क्षेत्र में भी अनेक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष कुछ नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें भारतीय नियामक रूपरेखा में पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी), रासायनिक विश्लेषण के लिए कार्यविधि विधिमान्यकरण और सत्यापन

(कीटनाशक अवशिष्ट, संदूषक और पोषणात्मक विश्लेषण सहित) तथा एकीकृत प्रबंधन प्रणालियों (आईएसओ 9001, आईएसओ 45001 और 14001) का कार्यान्वयन शामिल है।

ख) टीसीबी ने सरकारी और निजी, दोनों संगठनों से संबद्ध अधिकारियों के लिए कई विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं, जिनमें एम्स (पूरे भारत में), आईसीएमआर, यूनिसेफ, एडीएलक्यू, बिपार्ड, बीकेटी टायर्स, भुज, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, सूरत, एक्सिस इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट, आई-कैट, नेटहेल्थ, एनसीडीसी, सीआईपीईटी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, एडीआई कंसल्टेंट, उद्योग और वाणिज्य विभाग, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख तथा भारतीय नौसेना प्रशिक्षण पोत निर्माण केन्द्र, विशाखापत्तनम शामिल हैं।













3.5.3 क्षमता निर्माण हस्तक्षेप (राष्ट्रीय)

(क) क्यूसीआई और क्रेडाई महिला शाखा के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, सैवी और शिवालिक समूहों के निर्माण कामगारों के लिए गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में एक प्रायोगिक प्रशिक्षण सत्र संचालित किया गया। तीन दिनों में, 1,000 से अधिक कामगारों ने सामाजिक कल्याण योजनाओं और तकनीकी कौशल पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमें से 350 कामगारों ने चिनाई, सरिया मुड़ाई और शटरिंग कारपेंटरी विषयक सत्रों में भाग लिया, जबकि 750 कामगारों ने सामाजिक कल्याण योजनाओं, डिजिटल कौशल और वित्तीय साक्षरता विषय पर कल्याणकारी सत्रों में भाग लिया। विशेष सत्रों में

महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसमें 225 कामगारों ने सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया। इसके अतिरिक्त, क्रेडाई कोच्चि ने छह डेवलपर्स के 300 से अधिक कामगारों के लिए इसी तरह का प्रशिक्षण पूरा किया। इस बीच, एक सहयोगी भागीदार के रूप में, क्रेडाई पुणे मेट्रो ने 'सर्वश्रेष्ठ केन्द्र पुरस्कार' के लिए श्रमिक शिविरों के ऑन-साइट आकलन में भाग लिया और 31 अगस्त, 2024 को पुणे में पुरस्कार समारोह में भी भाग लिया।











(ख) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के राज्यीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के लिए लखनऊ में तथा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूकेपीसीबी) के अधिकारियों के लिए देहरादून में पीटीबी जर्मनी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण संचालित किया गया। यह प्रशिक्षण 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)' में सहायता के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण अवसंरचना और प्रयोगशाला प्रत्यायन पर केन्द्रित था। यूकेपीसीबी के रुड़की, हल्द्वानी, काशीपुर और देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ मुख्यालय के अधिकारियों सहित प्रतिभागियों को प्रमुख मापिकी और गुणवत्ता अपेक्षाओं से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों से परिचित कराया गया। इस कार्यक्रम से प्रयोगशाला प्रचालनों, माप सटीकता और प्रत्यायन प्रक्रियाओं के बारे में उनके कौशल में वृद्धि हुई।







(ग) यूनिसेफ ने एसपीएम निवास, कोलकाता में एक व्यापक चार दिवसीय आवासीय 'कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण' प्रायोजित किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) रूपरेखा के अंतर्गत प्रयोगशालाओं के कार्यनिष्पादन का आकलन करना और उसे बेहतर बनाना था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, प्रयोगशाला प्रचालन में विद्यमान अंतरालों की पहचान करना और इन खामियों को दूर करने के लिए लक्षित प्रशिक्षण प्रदान करना था। टीसीबी ने बेहतर जल गुणवत्ता परीक्षण और एनजेजेएम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रयोगशाला पद्धतियों में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार की और उसका संचालन किया, जिसमें प्रतिभागियों को व्यावहारिक सत्रों, चर्चाओं और व्यावहारिक अभ्यासों में शामिल किया गया। कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण में भारत के 18 राज्यों के 83 व्यक्तियों ने भाग लिया।











(घ) क्यूसीआई द्वारा आयोजित मार्गदर्शन अभिमुखीकरण कार्यक्रम, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के नए भर्ती कर्मचारियों को आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के उद्देश्य से की गई एक प्रमुख पहल है। एक माह का यह कार्यक्रम प्रशासन, वित्त, वैज्ञानिक नेतृत्वशीलता, गुणवत्ता और परियोजना प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पहल, उत्कृष्टता एवं सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को कायम रखते हुए प्रतिभागियों को अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने, नवाचार को बढ़ावा देने और आईसीएमआर की परिवर्तनकारी पहलों में योगदान करने के लिए आवश्यक साधनों और अंतर्दृष्टि से सशक्त बनाकर, भारत में जन स्वास्थ्य अनुसंधान के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब तक, मानव रचना यूनीवर्सिटी, फरीदाबाद (2 बैच), एनपीसी, चेन्नै (1 बैच) और आईआईटी हैदराबाद (1 बैच) सहित अनेक स्थलों पर संचालित प्रशिक्षण सत्रों के साथ इस कार्यक्रम के चार बैच पूरे कर लिए गए हैं, जिनमें लगभग 160 नए भर्ती कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। मार्गदर्शन अभिमुखीकरण कार्यक्रम, भारत के जन स्वास्थ्य अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करता रहेगा।























(ङ) टीसीबी-एनएबीईटी, क्यूसीआई ने नेटहेल्थ के सहकार्य से डिजिटल हेल्थ मास्टर क्लास (डीएचएमसी) प्रशिक्षण सत्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्यचर्या पेशेवरों को डिजिटल स्वास्थ्य परिपक्वता, एचएमआईएस/ईएमआर के अंगीकरण और अंतर-प्रचालनीयता के बारे में आवश्यक ज्ञान से युक्त बनाना था। ये सत्र, स्वास्थ्यचर्या पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, अनुपालन और निर्बाध प्रौद्योगिकी एकीकरण को बढ़ावा देकर, भारत के डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन में तेजी लाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। अब तक, हमने चार शहरों अर्थात वाराणसी, लखनऊ, पटियाला और अमृतसर में डीएचएमसी प्रशिक्षण संचालित किया है, जहां पर कुल मिलाकर 229 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

(च) बिपार्ड के संस्थानों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक अंतराल विश्लेषण रिपोर्ट और एक विस्तृत कार्य योजना बिपार्ड पटना और गया के साथ साझा की गई। अंतराल विश्लेषण में क्यूएमएस मानकों के लिए वर्तमान प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करके ऐसे प्रमुख क्षेत्रों का सटीक निर्धारण किया गया जहां सुधार आवश्यक हैं। निष्कर्षों के आधार पर, प्रशिक्षण, प्रलेखन, प्रक्रिया अनुकूलन और सर्वोत्तम परिपाटियों के पालन सहित कार्यान्वयन के लिए कदम- दर-कदम उपाय दर्शाते हुए एक कार्य योजना तैयार की गई।







(छ) टीसीबी/क्यूसीआई अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा आईएसओ 15189:2022 की अपेक्षाओं के अनुसार एम्स बठिंडा में चार विभागों: जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, विकृति विज्ञान और रेडियोडायग्नोसिस प्रयोगशालाओं का अंतराल विश्लेषण किया गया। आकलन रिपोर्ट संबंधित विभागों के साथ साझा की गई और अनुशंसित कार्यों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक अनुवर्ती दौरा किया गया। अंतिम दौरे में प्रयोगशाला निरीक्षण, कार्मिकों के साथ चर्चा, प्रचालन समीक्षा, प्रलेखन सत्यापन (एसओपी, रिकॉर्ड, रिपोर्टिंग) और अनुपालन जांच शामिल थी। इस दौरे की अभ्युक्तियों से आगे और सुधारों का मार्ग प्रशस्त होगा।













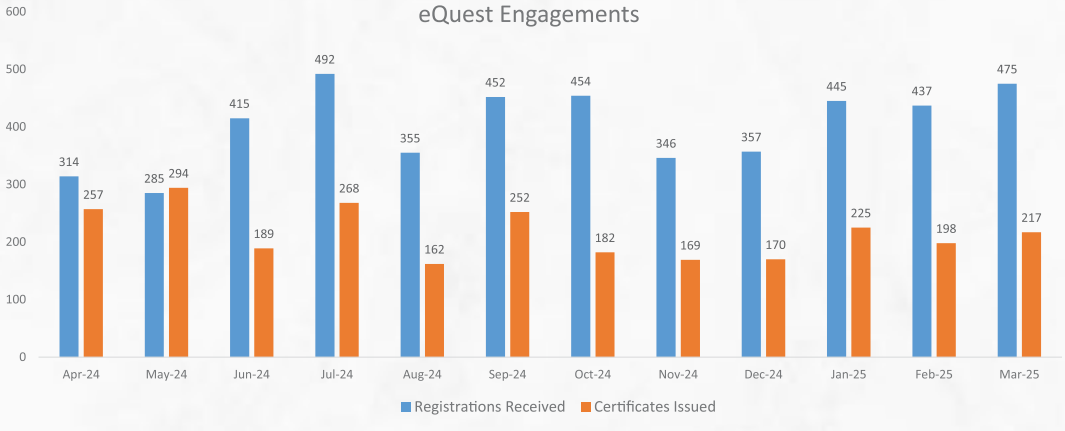
3.5.4 टीसीबी द्वारा अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां

(क) गुणवत्ता प्रबंधन और अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए एंटी-डोपिंग लैब कतर (एडीएलक्यू) के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण संचालित किया गया। सितंबर में आयोजित सत्र गुणवत्ता, परीक्षण और जोखिम प्रबंधन पर केन्द्रित रहे, जबकि दिसंबर का प्रशिक्षण आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन और मापन की अनिश्चितता पर केन्द्रित रहा। इन कार्यक्रमों से अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला मानकों को बनाए रखने में एडीएलक्यू की क्षमताएं सुदृढ़ हुईं।

3.5.5 विषय: ई-लर्निंग/ऑनलाइन लर्निंग:

क) ईक्वेस्ट: वित्त वर्ष 2024-25 में परिणाम:

ईक्वेस्ट, भारतीय गुणवत्ता परिषद् के शिक्षा बोर्ड - एनएबीईटी का ई-लर्निंग पोर्टल है। इस पोर्टल पर गुणवत्ता, स्वास्थ्यचर्या, शिक्षा, पर्यावरण, एमएसएमई आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 100 ई-लर्निंग पाठ्यक्रम प्रदर्शित किए गए हैं। इस लर्निंग पाठ्यक्रम को कौशल एवं प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्त पंजीकरण और जारी किए गए प्रमाणपत्र इस प्रकार हैं:



ख) भावी प्रेक्षण:

उपलब्ध पाठ्यक्रमों की सूची में वृद्धि करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों का विकास।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलों को सुकर बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और अंतरराष्ट्रीय संगठनों, एमएसएमई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।

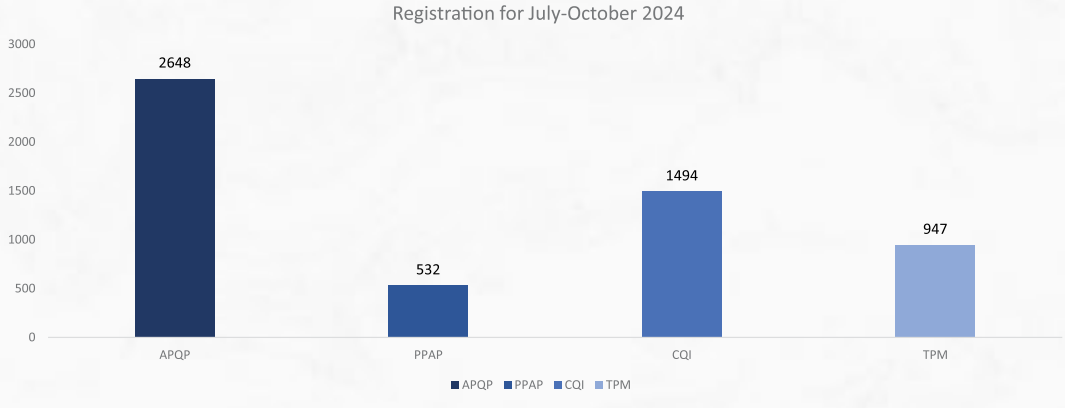
3.5.6 'स्वयं' (एसडब्ल्यूएवाईएएम) पोर्टल पर उपलब्ध क्यूसीआई पाठ्यक्रम: -

'स्वयं', भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों अर्थात पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता को हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 'स्वयं' के साथ ईक्वेस्ट-क्यूसीआई की भागीदारी का मुख्य उद्देश्य, भारतीय प्रबंधन संस्थान बंगलोर (आईआईएमबी) के सहकार्य से और उसके पुनरीक्षण के साथ गुणवत्ता के क्षेत्र में ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों का विकास और उनका संवर्धन करना है।

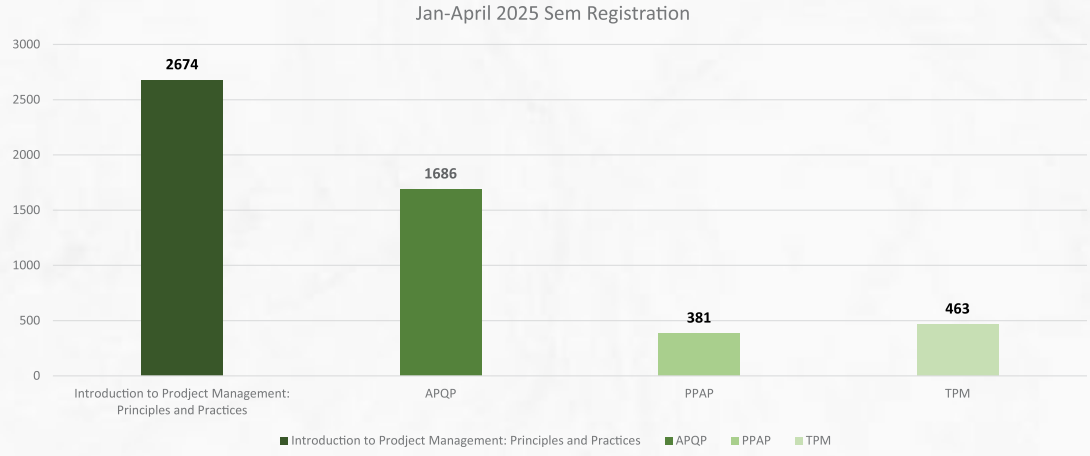
क) जनवरी-अप्रेल सेमेस्टर 2024 के लिए प्राप्त पाठ्यक्रम-वार पंजीकरण:



ख) जुलाई-अक्टूबर सेमेस्टर 2024 के लिए प्राप्त पाठ्यक्रम-वार पंजीकरण:



ग) जनवरी-मार्च सेमेस्टर 2025 के लिए प्राप्त पाठ्यक्रम-वार पंजीकरण:



भावी प्रेक्षण – संपर्क-विस्तार हासिल करने के लिए उपर्युक्त पाठ्यक्रमों का निरंतर प्रचार-प्रसार।

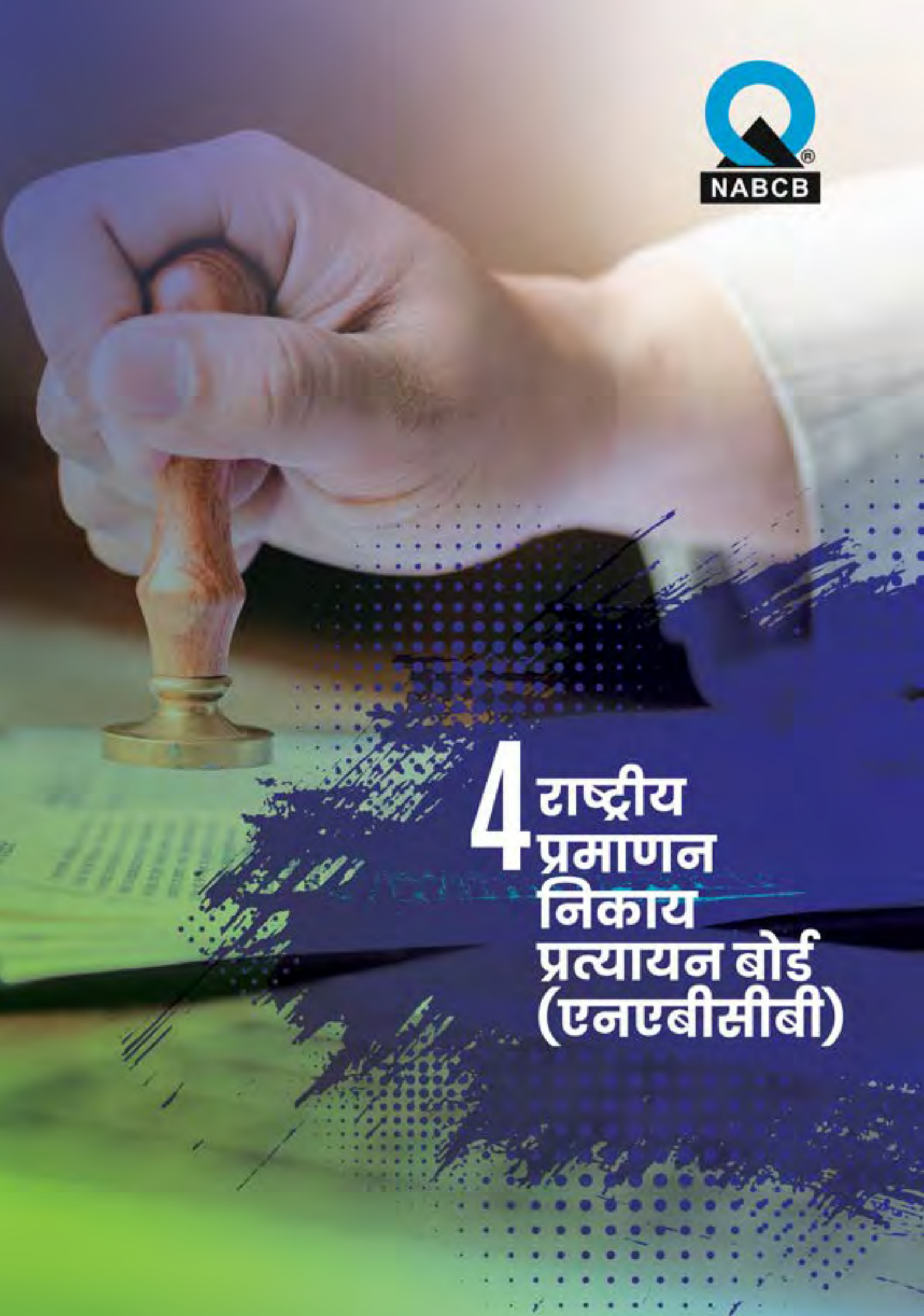
3.5.7 आई-गॉट:

कर्मयोगी भारत, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) का एक अभिन्न अंग है, जिसे मिशन कर्मयोगी के नाम से भी जाना जाता है। यह पहल भारत में सिविल सेवा क्षमता निर्माण का परिदृश्य बदलने के लिए अभिकल्पित की गई है। इसका उद्देश्य एक सक्षम सिविल सेवा का सृजन करना है जिसकी जड़ें भारतीय लोकाचार में निहित हों और जो देश की प्राथमिकताओं की साझा समझ रखती हो। आई-गॉट कर्मयोगी, बड़े पैमाने पर व्यापक अधिगम और करियर प्रबंधन का मंच है, जो सरकारी अधिकारियों की ज्ञान संबंधी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करता है।

अप्रेल, 2024-मार्च, 2025 के लिए प्राप्त पाठ्यक्रम-वार पंजीकरण:



भावी प्रेक्षण – संपर्क-विस्तार हासिल करने के लिए उपर्युक्त पाठ्यक्रमों का निरंतर प्रचार-प्रसार।

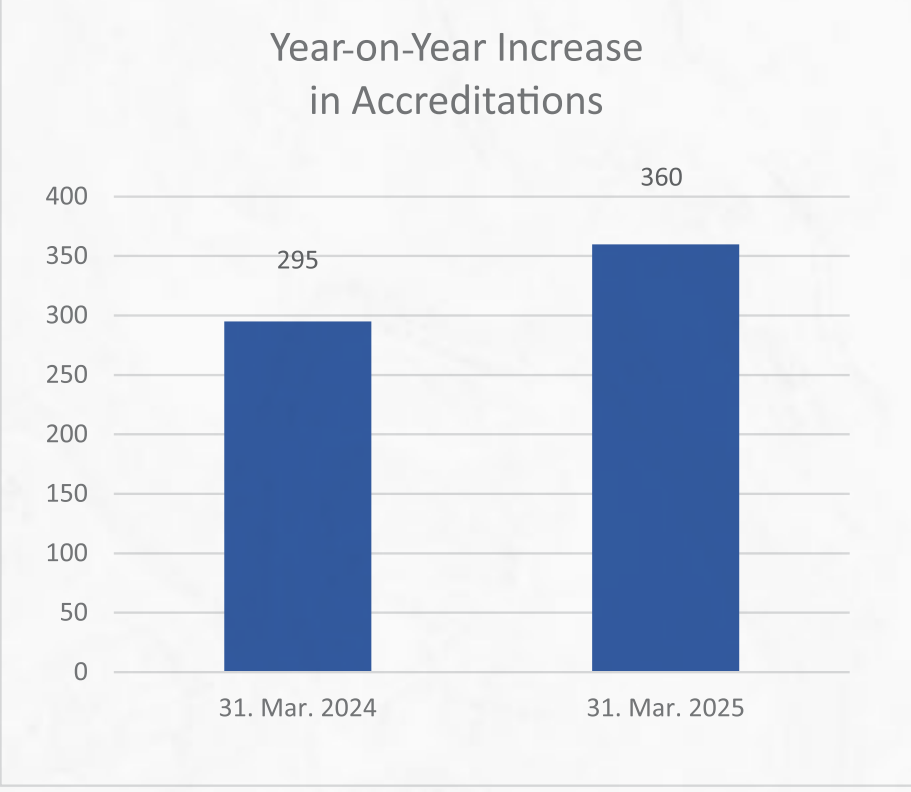


4 राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी)

राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी), क्यूसीआई का एक घटक बोर्ड है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी और यह बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय मानकों (आईएसओ/आईईसी) के अनुसार प्रमाणन, निरीक्षण और विधिमान्यकरण तथा सत्यापन निकायों को प्रत्यायन प्रदान करता है।

एनएबीसीबी अंतरराष्ट्रीय निकायों जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम (आईएएफ), अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (आईएलएसी) और एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (एपीएसी) का सदस्य है। इसके साथ ही, प्रबंधन प्रणालियों (आईएसओ/आईईसी 17021-1), उत्पाद (आईएसओ/आईईसी 17065), और व्यक्तियों (आईएसओ/आईईसी 17024) के प्रमाणनों के लिए उनकी बहुपक्षीय पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (एमएलए/एमआरए); निरीक्षण (आईएसओ/आईईसी 17020) और विधिमान्यकरण एवं सत्यापन (आईएसओ/आईईसी 17029) जो प्रत्यायित प्रमाणपत्रों और रिपोर्टों के लिए अंतरराष्ट्रीय समतुल्यता और स्वीकृति प्रदान करते हैं, का हस्ताक्षरकर्ता है। एनएबीसीबी को कई अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र विशिष्ट प्रमाणन स्कीम स्वामियों जैसे कि- ग्लोबल गैप, इंटरनेशनल फीचर्ड स्टैंडर्ड्स (आईएफएस), ग्लोबल सीफूड एलायंस-बेस्ट एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेज (जीएसए-बीएपी), ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम (बीआरसीजीएस), वन प्रमाणन अनुसमर्थन कार्यक्रम (पीईएफसी), एफएसएससी 22000 फाउंडेशन, एफएएमआई-क्यूएस, अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन-कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (आईसीएओ-कोर्सिया), वीईआरआरए, सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग इंटरनेशनल (एसईआरआई), और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन (आईएसए) सिक्योर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से भी मान्यता प्राप्त है।

विश्व व्यापार संगठन के टीबीटी और एसपीएस, दोनों करारों के अंतर्गत प्रत्यायन पर निर्भरता के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए अनुरूपता आकलन ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली है। विनियमों के अनुपालन को सत्यापित करने के उद्देश्य से अनुरूपता आकलन निकायों को मान्यता देने में दुनिया भर के विनियामक निकाय राष्ट्रीय प्रत्यायन पर भरोसा कर रहे हैं। प्रत्यायन से, जी2जी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के अलावा विनियामक और स्वैच्छिक - दोनों क्षेत्रों में व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं को कम करने में मदद मिलती है।



31 मार्च, 2025 तक प्रत्यायन की स्थिति

प्रत्यायन कार्यक्रम	प्रत्यायन	आवेदन
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस)	56	8
पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)	29	4
निरीक्षण निकाय (आईबी)	134	27
खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस)	29	6
व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस)	24	5
उत्पाद प्रमाणन (पीसीबी)	41	8
सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस)	11	5
ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस)	9	2
सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रबंधन प्रणाली (आईटीएसएमएस)	4	0
कार्मिक प्रमाणन (पीआरसीबी)	9	2
सड़क यातायात संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आरटीएसएमएस)	0	0
विश्वसनीय डिजिटल रिपॉजिटरी प्रबंधन प्रणाली (टीडीआरएमएस)	1	0
ग्रीनहाउस गैस विधिमान्यकरण और सत्यापन निकाय (जीएचजी)	7	10
व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस)	3	0
रिश्वत-रोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस)	0	1
परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (एएमएस)	0	1
फेसिलिटी प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस)	0	0
एयरोस्पेस गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एक्यूएमएस)	2	3
कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रबंधन प्रणाली (एआईएमएस)	1	2

4.1 अंतरराष्ट्रीय समतुल्यताएं

4.1.1 एनएबीसीबी विधिमान्यकरण और सत्यापन के लिए आईएएफ एमएलए का हस्ताक्षरकर्ता बना

एनएबीसीबी को आईएएफ एमआरए (अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन मंच इनकॉरपोरेटिड बहुपक्षीय मान्यता व्यवस्था) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रत्यायन सेवाएं प्रदान करने के लिए उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। मान्यता के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं:

- मुख्य कार्यक्षेत्र: विधिमान्यकरण और सत्यापन - आईएसओ/आईईसी 17029
- स्तर 4 उप-कार्यक्षेत्र: आईएसओ 14065:2020 / आईएसओ14066 / आईएसओ 14064-3
- स्तर 5 उप-कार्यक्षेत्र: आईएसओ 14064-1 / आईएसओ 14064-2

यह मान्यता, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विधिमान्यकरण और सत्यापन अनुरूपता आकलन गतिविधियों को प्रत्यायन प्रदान करने में एनएबीसीबी की दक्षता और विश्वसनीयता को रेखांकित करती है। यह, उच्चतम गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय स्थायित्व प्रयासों में योगदान देने के प्रति एनएबीसीबी के समर्पण को दर्शाता है।

4.1.2 एपीएसी ने एनएबीसीबी के लिए एमआरए दर्जे की पुनः पुष्टि की

एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (एपीएसी) ने हाल ही में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र और उप-कार्यक्षेत्रों हेतु एनएबीसीबी के लिए इसके एमआरए हस्ताक्षरकर्ता के दर्जे की पुनः पुष्टि की है:

- प्रमाणन - प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ/आईईसी 17021-1) – बीसीएमएस, ईएमएस, ईएनएमएस,

एफएसएमएस, एफएसएससी 22000, आईएसएमएस, आईटीएसएमएस, एमडीक्यूएमएस, ओएचएसएमएस और क्यूएमएस;

- प्रमाणन - व्यक्ति (आईएसओ/आईईसी 17024);
- प्रमाणन - उत्पाद, प्रकिया और सेवाएं (आईएसओ/ आईईसी 17065) जिसमें वैश्विक जी.ए.पी. भी शामिल है;
- निरीक्षण (आईएसओ/आईईसी 17020);
- ग्रीनहाउस गैसों का विधिमान्यकरण और सत्यापन (आईएसओ 14065:2013), जिसमें आईसीएओ - सीओआरएसआईए शामिल है;
- विधिमान्यकरण और सत्यापन (आईएसओ/आईईसी 17029), जिसमें पर्यावरण संबंधी सूचना (आईएसओ 14065:2020) शामिल है;

एमआरए हस्ताक्षरकर्ता के दर्जे की पुनः पुष्टि, मार्च/ अप्रैल 2024 के दौरान 9 सदस्यीय एपीएसी समकक्ष मूल्यांकन टीम द्वारा एक कठोर समकक्ष पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के पश्चात की गई। इस टीम में 9 अलग-अलग प्रत्यायन निकायों/देशों के मूल्यांकनकर्ता शामिल थे।

4.1.3 एयरोस्पेस गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्कीम के लिए एनएबीसीबी का मूल्यांकन

एयरोस्पेस गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्कीम के लिए यूनाइटेड किंगडम रीजनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर (यूके-आरएमएस) द्वारा 3-4 जुलाई, 2024 को एनएबीसीबी का सफल वार्षिक निरीक्षण दौरा किया गया। यह मूल्यांकन उत्तरी यूरोप के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री मार्को पेलेग्रिनी और बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स के आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता विशेषज्ञ श्री माइक ओल्डहैम द्वारा किया गया। भारतीय एयरोस्पेस गुणवत्ता समूह (आईएनएक्यूजी) के 2 अधिकारियों ने भी इस दौरे की निगरानी की। इस निरीक्षण मूल्यांकन में 3 प्रमुख विशेषताओं, 4 ओएफआई और 1 मामूली एनसी की रिपोर्ट की गई, जिनका एनएबीसीबी द्वारा उचित समाधान किया गया और 7 अगस्त, 2024 को यूके-आरएमएस टीम द्वारा उसे स्वीकार किया गया।

एनएबीसीबी ने एएस 9100 मानक श्रृंखला के लिए प्रमाणन प्रदान करने के उद्देश्य से एक्यूएमएस स्कीम में पहले ही दो प्रमाणन निकायों को प्रत्यायन प्रदान कर दिया है तथा दो अन्य आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है।





4.1.4 एनएबीसीबी ने ईओएमएस और एफएएमआई-क्यूएस के लिए अंतरराष्ट्रीय समकक्षता प्राप्त की

एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (एपीएसी) ने निम्नलिखित उप-क्षेत्रों में एनएबीसीबी के लिए अपने एमआरए हस्ताक्षरकर्ता के दर्जे की हाल ही में पुष्टि कर दी है:

- शिक्षा संगठन प्रबंधन प्रणाली (ईओएमएस);
- विशिष्ट फीड सामग्री के लिए गुणवत्ता और संरक्षा प्रणाली (एफएएमआई-क्यूएस)

एपीएसी द्वारा यह मान्यता एनएबीसीबी के इस प्रदर्शन पर आधारित है कि वह, बोर्ड पर लागू अंतरराष्ट्रीय मानक, आईएसओ/ आईईसी 17011 की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है तथा ईओएमएस मानक और एफएएमआई-क्यूएस स्कीम के लिए प्रमाणन निकायों को प्रत्यायित करने की क्षमता रखता है।

यह, उद्योग/बाजार की जरूरतों के अनुसार प्रत्यायन सेवाएं प्रदान करने की एनएबीसीबी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

4.2 आकलनकर्ताओं के कॉन्क्लेव और प्रशिक्षणों के संबंध में अद्यतन सूचना

4.2.1 एनएबीसीबी आकलनकर्ता कॉन्क्लेव 2024

एनएबीसीबी ने 16 - 17 दिसंबर, 2024 को मानेसर, गुरुग्राम में हाइब्रिड मोड में वार्षिक आकलनकर्ता कॉन्क्लेव का आयोजन किया। पहले दिन, जो विशिष्ट रूप से प्रमाणन निकायों की स्कीमों के आकलनकर्ताओं के लिए नियत था, एनएबीसीबी द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी नई प्रत्यायन स्कीमों, एफएसएससी 22000, बीआरसीजीएस, ग्लोबल जी.ए.पी., आईएफएस, एफएएमआई-क्यूएस जैसी स्कीमों की अपेक्षाओं के संबंध में अद्यतन सूचना, आईएसओ/आईईसी 27001-1:2024 के संबंध में अवस्थांतर नीति, एयरोस्पेस गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों में नवीनतम प्रगति, विकासशील स्कीमों के संबंध में अद्यतन सूचना, नव प्रकाशित आईएसओ मानकों सहित आईएसओ कैस्को (सीएएससीओ) मानकों में किए जा रहे संशोधनों, आईएएफ अनिवार्य दस्तावेज और कई अन्य प्रासंगिक विषयों/मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

एनएबीसीबी के सीईओ, श्री राजेश माहेश्वरी ने स्वागत संबोधन के साथ इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और एनएबीसीबी, एपीएसी, आईएसओ, आईएएफ तथा आईएलएसी के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान की। उन्होंने एनएबीसीबी को अपना सशक्त समर्थन और सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी आकलनकर्ताओं की सराहना की।

जिन अन्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें दस्तावेज समीक्षा, प्रमुख गैर-अनुरूपताएं, आकलन तकनीक और जोखिम-आधारित आकलन विधियां, आकलन रिपोर्टें, आचार संहिता तथा आकलनकर्ताओं के सामंजस्य हेतु आकलन अनुभव का आदान-प्रदान जैसे विषय शामिल थे।

दूसरे दिन के कॉन्क्लेव का आयोजन, निरीक्षण और विधिमान्यकरण/सत्यापन निकायों के लिए एनएबीसीबी आकलनकर्ताओं में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया। आकलनकर्ताओं को एनएबीसीबी प्रत्यायित निरीक्षण निकायों का प्रावधान करने वाले सरकारी, नियामकों, उद्योग और अन्य निकायों के बारे में अद्यतन जानकारी दी गई।

इस विचार-विमर्श में आईबी प्रत्यायन की प्रमुख अपेक्षाएं, आईबी के आकलन से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

आईसीएओ कॉर्सिया स्कीम के सिंहावलोकन, नई स्कीमों - आईएससीसी, बीआरएसआर कोड आश्वासन, आईएसओ 14066:2023 के लिए अवस्थांतर नीति पर चर्चा के लिए भी एक सत्र आयोजित किया गया।

इस कॉन्क्लेव में भौतिक और वर्चुअल, दोनों रूपों में 100 से अधिक आकलनकर्ताओं ने भाग लिया।





4.2.2 आईएसओ/आईईसी 17065:2012 विषय पर एनएबीसीबी आकलनकर्ताओं का प्रशिक्षण

एनएबीसीबी आकलनकर्ताओं के पूल का विस्तार करने और विद्यमान आकलनकर्ताओं को भिन्न-भिन्न मानकों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए, एनएबीसीबी ने 19 से 21 दिसंबर, 2024 तक नई दिल्ली में आईएसओ/आईईसी 17065:2012 विषय पर 3-दिवसीय आकलनकर्ता प्रशिक्षण का संचालन किया। इस प्रशिक्षण में 25 संभावित आकलनकर्ताओं ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण एनएबीसीबी की अत्यंत अनुभवी और प्रख्यात संकाय सदस्य सुश्री राजलक्ष्मी सुब्रमण्यम और श्री अनुपम गुप्ता द्वारा दिया गया। इसके बाद प्रतिभागियों की परीक्षा ली गई/मूल्यांकन किया गया।

4.2.3 आईएसओ/आईईसी 17020:2012 विषय पर एनएबीसीबी प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनएबीसीबी आकलनकर्ताओं का डेटाबेस बढ़ाने तथा विद्यमान आकलनकर्ताओं और नए संभावित आकलनकर्ताओं को भिन्न-भिन्न मानकों के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए, एनएबीसीबी ने 6-8 जनवरी, 2025 तक नई दिल्ली में आईएसओ/आईईसी 17020:2012 विषय पर तीन दिवसीय आकलनकर्ता प्रशिक्षण संचालित किया। इस प्रशिक्षण में 26 संभावित आकलनकर्ताओं ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण, एनएबीसीबी की अत्यंत अनुभवी और प्रख्यात प्रशिक्षक, सुश्री राजलक्ष्मी सुब्रमण्यम और श्री आर.डी. खत्री द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के बाद सभी प्रतिभागियों की परीक्षा ली गई।



4.2.4 एनएबीसीबी की बीएसआई और यूकेएएस के साथ भागीदारी

एनएबीसीबी ने बीएसआई और यूकेएएस के साथ भागीदारी में 4-5 मार्च, 2025 को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एक्यूएमएस) विषय पर एक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह कार्यक्रम एएस 9104-001:2013 और एयरोस्पेस गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन में सर्वोत्तम परिपाटियों पर केन्द्रित था, जिसमें सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। यह प्रशिक्षण ऐसे पेशेवरों के लिए डिजाइन किया था जो क्यूएमएस अपेक्षाओं से परिचित हैं और एयरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र के मानकों की बेहतर जानकारी चाहते हैं।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यूके/ईयू की सर्वोत्तम परिपाटियों का आदान-प्रदान करके विमानन क्षेत्र में क्यूएमएस मानकों के विकास और कार्यान्वयन में एनएबीसीबी, क्यूसीआई, भारतीय उद्योगों, प्रशिक्षण संस्थाओं और प्रमुख हितधारकों की सहायता करना था। इस प्रशिक्षण में प्रमुख प्रकरणों में मानकों का सिंहावलोकन, आकलन की योजना बनाने की सर्वोत्तम परिपाटियां, सामान्य आकलन चुनौतियां तथा एएस 9104-1:2022 और आईए 9104/1 के बारे में प्रमुख अपडेट शामिल थे।



4.2.5 एनएबीसीबी ने आईएसओ/आईईसी 17024:2012 विषय पर आकलनकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया

एनएबीसीबी आकलनकर्ताओं का डेटाबेस बढ़ाने तथा विद्यमान आकलनकर्ताओं और नए संभावित आकलनकर्ताओं को भिन्न-भिन्न मानकों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए, एनएबीसीबी ने 20-22 फरवरी, 2025 तक नई दिल्ली में आईएसओ/ आईईसी 17024:2012 विषय पर तीन दिवसीय आकलनकर्ता प्रशिक्षण संचालित किया। इस प्रशिक्षण में 21 संभावित आकलनकर्ताओं ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण, एनएबीसीबी के अत्यंत अनुभवी और प्रख्यात प्रशिक्षक श्री एस कृष्णमूर्ति और श्री ए. सुधींद्र द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के बाद सभी प्रतिभागियों की परीक्षा ली गई।



4.2.6 स्थायित्वपूर्ण विमानन ईंधन (एसएएफ) विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनएबीसीबी ने 23-24 जनवरी, 2025 को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) और यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) द्वारा स्थायित्वपूर्ण विमानन ईंधन विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

दो दिवसीय पारस्परिक संवाद, सभी प्रतिभागियों के लिए बहुमूल्य अधिगम अनुभव रहा। इस कार्यशाला में फीडस्टॉक्स टेक्नोलॉजी पाथवेज, संभावित एसएएफ उत्पादन क्षमता के सृजन, फीडस्टॉक संग्रह के लिए अवसंरचना का सृजन, एसएएफ उत्पादन एवं एसएएफ सम्मिश्रण तथा एसएएफ स्थायित्वपूर्णता प्रमाणन, एसएएफ के उत्पादन और बिक्री पर आगामी कॉर्सिया क्रेडिट की पात्रता और उनके व्यापार तंत्र के साथ-साथ विमानपत्तन सुविधाओं तक इसकी आपूर्ति सहित एसएएफ के अनेक पहलुओं पर चर्चा की गई।



4.2.7 एनएबीसीबी ने आईएसओ/आईईसी 17021-1:2015 विषय पर आकलनकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

एनएबीसीबी आकलनकर्ताओं का डेटाबेस बढ़ाने तथा विद्यमान आकलनकर्ताओं और नए संभावित आकलनकर्ताओं को भिन्न-भिन्न मानकों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए, एनएबीसीबी ने 24-26 मार्च, 2025 तक नई दिल्ली में आईएसओ/ आईईसी 17021-1:2015 विषय पर तीन दिवसीय आकलनकर्ता प्रशिक्षण संचालित किया। इस प्रशिक्षण में 29 संभावित आकलनकर्ताओं ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण, एनएबीसीबी की अत्यंत अनुभवी और प्रख्यात प्रशिक्षक

सुश्री राजलक्ष्मी सुब्रमण्यम और श्री अनुपम गुप्ता द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के बाद सभी प्रतिभागियों की परीक्षा ली गई।



अंतरराष्ट्रीय क्षमता निर्माण गतिविधियां

4.3 अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां

4.3.1 एनएबीसीबी ने बीआरसीजीएस विषय पर प्रशिक्षण के आयोजन में एपीएसी को सहयोग प्रदान किया

एनएबीसीबी ने 3 - 5 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में आईएसओ/आईईसी 17065 के संबंध में बीआरसीजीएस खाद्य मानक विषय पर प्रत्यायन निकायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में एशिया-प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (एपीएसी) की सहायता की। इस प्रशिक्षण में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 19 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बीआरसीजीएस से सुश्री ऋतु बजाज और श्री आशीष गौड़ इस प्रशिक्षण के संकाय सदस्य थे। एनएबीसीबी के 06 अधिकारी भी इस प्रशिक्षण में शामिल हुए।



4.3.2 मॉरीशस प्रत्यायन निकाय (मॉरीटास) के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियां

एनएबीसीबी को औद्योगिक विकास, लघु एवं मध्यम उद्यम और सहकारिता मंत्रालय, मॉरीशस सरकार द्वारा सूचना संरक्षा प्रबंधन प्रणालियों, उत्पाद प्रमाणन और खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए मॉरीशस प्रत्यायन निकाय (मॉरीटास) की क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए परियोजनाएं सौंपी गईं।

इस परियोजना के एक भाग के रूप में, एनएबीसीबी ने क्रमशः 29 जुलाई से 2 अगस्त, 2024, 5 से 9 अगस्त, 2024 और 18 से 20 नवंबर, 2024 के दौरान सूचना संरक्षा प्रबंधन प्रणालियों (आईएसएमएस), उत्पाद प्रमाणन (पीसीबी) और खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणालियों (एफएसएमएस) के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और प्रत्येक कार्यक्रम में लगभग 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों द्वारा इन प्रशिक्षणों की अत्यधिक सराहना की गई।

एनएबीसीबी ने उत्पाद प्रमाणन प्रत्यायन स्कीम के लिए मॉरीटास की विद्यमान प्रणाली का अंतराल विश्लेषण भी किया और मॉरीटास को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।





4.4 अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी

4.4.1 आईएएफ/आईएलएसी/पीएसी/एपीएलएसी बैठकों में भागीदारी

i. 27-28 जून, 2024 के दौरान नई दिल्ली में आईएसओ 15189 विषय पर एपीएसी समकक्ष मूल्यांकक कार्यशाला

ii. 5 जुलाई, 2024 को एबी सहयोग पर चर्चा के लिए लघु समूह टीएफजी दस्तावेज की वर्चुअल बैठक

iii. 14-18 जुलाई, 2024 के दौरान दुबई में एपीएसी की वार्षिक बैठकें

iv. मार्च-अप्रैल 2024 के दौरान रूप से आईएएफ/आईएलएसी की संयुक्त मध्यावधि वर्चुअल बैठक

v. 28-30 मई, 2024 के दौरान जिनेवा में आईएसओ/कैस्को कार्य समूह 30 की चौथी बैठक

vi. 30 सितंबर, 2024 को बर्लिन में बीआरसीजीएस की वार्षिक बैठक

vii. 1 अक्टूबर, 2024 को बर्लिन में आईएफएस की वार्षिक बैठक

viii. 2 अक्टूबर, 2024 को बर्लिन में ग्लोबल जी.ए.पी. की वार्षिक बैठक

ix. 1-10 अक्टूबर, 2024 के दौरान बर्लिन में आईएएफ और आईएलएसी की संयुक्त वार्षिक बैठक

x. 23-28 सितंबर, 2024 के दौरान मास्को में रूसएक्रेडिटेशन का समकक्ष मूल्यांकन

xi. 18 फरवरी, 2025 को हलाल प्रमाणन के लिए एमआरए पर चर्चा हेतु संयुक्त अरब अमीरात सरकार के उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ द्विपक्षीय बैठक

xii. 26 फरवरी - 1 मार्च, 2025 के दौरान एपीएसी प्रमुख मूल्यांकनकर्ता कार्यशाला, आईएएफ सर्टसर्च के संबंध में सीएनएएस के साथ बैठक और एपीएसी कार्यकारिणी समिति की बैठक।

4.4.2 अन्य बैठकें/प्रशिक्षण

एनएबीसीबी अधिकारियों ने निम्नलिखित बैठकों/कार्यक्रमों में भाग लिया/उपस्थित रहे:

i. 14 मई, 2024 को यूनाइटेड किंगडम रीजनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बोर्ड की वर्चुअल बैठक जिसमें एनएबीसीबी ने एक्यूएमएस प्रत्यायन कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की।

ii. इंडियन रीजनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बोर्ड की 17 मई, 2024 को वर्चुअल बैठक। एनएबीसीबी ने आईएनएक्यूजी को एक्यूएमएस प्रत्यायन की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की।

iii. 1 अगस्त, 2024 को एबी सहयोग पर चर्चा के लिए टीएफजी दस्तावेज की वर्चुअल बैठक।

iv. 7 अगस्त, 2024 को डिजिटल आकलन उपकरण एवं तकनीक विषय पर एडीएपीटी कार्यशाला: आकलन पश्चात अनुभव का वर्चुअल आदान-प्रदान।

v. आईएएफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्चुअल बैठक।

vi. 26 अगस्त, 2024 को प्रत्यायन निकायों के लिए पीईएफसी सीओसी ईयूडीआर प्रशिक्षण।

vii. 20-24 अक्टूबर, 2024 के दौरान एपीएक्यूजी एवं आईएक्यूजी की वार्षिक बैठक।

viii. 29-31 अक्टूबर, 2024 के दौरान आईएसओ कैस्को कार्य समूह 65 की बैठक।

ix. 20-22 नवंबर, 2024 के दौरान आईएसओ कैस्को कार्य समूह 65 की बैठक।

x. 25-30 नवंबर, 2024 को जिनेवा में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का 47वां सत्र।

अंतरराष्ट्रीय बैठकों में भागीदारी

4.5 अंतरराष्ट्रीय बैठकें

4.5.1 मेसोपार्टनर के साथ एनएबीसीबी की बैठक

एनएबीसीबी ने वैश्विक गुणवत्ता अवसंरचना सूचकांक (जीक्यूआईआई) में भारत की रैंकिंग में सुधार की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए 12 जुलाई, 2024 को मेसोपार्टनर के एक भागीदार डॉ. उलरिच हरमीज-लाइडके के साथ बैठक की। मेसोपार्टनर एक ज्ञान आधारित फर्म है जो आर्थिक विकास, स्पर्धात्मकता और नवाचार में विशेषज्ञता रखती है।

जीक्यूआईआई किसी देश की गुणवत्ता अवसंरचना की गुणवत्ता और प्रदर्शन की माप करता है, जिसमें मानक, मापिकी, प्रत्यायन और अनुरूपता आकलन शामिल हैं। इस सूचकांक में भारत की वर्तमान रैंकिंग चर्चा का केन्द्र रही, जिसका उद्देश्य भारत की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई योग्य उपायों की पहचान करना था। इस समय, भारतीय प्रत्यायन प्रणाली दुनिया में 5वें स्थान पर है।

इस बैठक में, डॉ. हरमीज लाइडके ने कुछ मापदंडों के बारे में बताया जिन पर जीक्यूआईआई रैंकिंग आधारित होती है। एनएबीसीबी और मेसोपार्टनर के बीच सहकार्य से भारत की गुणवत्ता अवसंरचना को अंतरराष्ट्रीय बैंचमार्क के अनुरूप बनाकर, अपनी वैश्विक स्पर्धात्मकता बढ़ाने के अपने रणनीतिक प्रयासों में योगदान मिलने की उम्मीद है।

4.5.2 एनएबीसीबी की डीजीसीए और आईएससीसी जीएमबीएच के साथ बैठक

डीजीसीए ने एनएबीसीबी के साथ मिलकर आईएससीसी जीएमबीएच, जिसे आईसीएओ आधिकारिक तौर पर एक प्रमाणन स्कीम के रूप में मान्यता देता है, के साथ चर्चा शुरू की, ताकि भारत में एसएएफ का प्रमाणन शुरू करने के इरादे से सीओआरएसआईए-योग्य ईंधनों के लिए स्थायित्व मापदंडों का अनुपालन दर्शाया जा सके। यह बैठक 5 जुलाई, 2024 को हुई थी।

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (सीओआरएसआईए) के तहत एयरलाइनों को 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए जेट ईंधन में स्थायित्वपूर्ण विमानन ईंधन (एसएएफ) मिलाना होगा। यह सीओआरएसआईए के अनिवार्य चरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कुछ अपवादों के साथ सभी अंतरराष्ट्रीय प्रचालकों पर लागू होगा। इसका लक्ष्य, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके 2020 के स्तर पर लाना है। भारत सरकार ने भी 2027 तक पारंपरिक जेट ईंधन में 1% एसएएफ मिलाने का एक सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) ने 2027 के आरंभ से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए जेट ईंधन में 1% स्थायित्वपूर्ण विमानन ईंधन (एसएएफ) मिलाने का लक्ष्य तय किया है। यह लक्ष्य, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (सीओआरएसआईए) के अनुरूप है।

4.5.3 ग्लोबल सीफूड अलायंस (जीएसए) के साथ एनएबीसीबी की बैठक

25 जुलाई, 2024 को एनएबीसीबी और ग्लोबल सीफूड अलायंस (जीएसए) के बीच एक वर्चुअल वार्षिक बैठक आयोजित की गई।

जीएसए, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार मत्स्यपालन परिपाटियों को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर के प्रतिबद्ध हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है। सर्वोत्तम मत्स्यपालन परिपाटी (बीएपी) प्रमाणन मानकों के विकास के माध्यम से, जीएसए मत्स्यपालन - समुद्री भोजन के लिए अग्रणी मानक-निर्धारक संगठन बन गया है।

इस बैठक में जीएसए कार्यक्रमों के बारे में तकनीकी अपडेट के साथ-साथ एनएबीसीबी और जीएसए के बीच सहकार्य और तकनीकी प्रगति के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई। एनएबीसीबी ने पहले ही जीएसए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

4.5.4 एफएसएससी फाउंडेशन टीम के साथ बैठक

एनएबीसीबी ने 3 मई, 2024 को एफएसएससी फाउंडेशन टीम के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस टीम में श्री एल्डिन हिलब्रांड्स- सीईओ, श्री कॉलिन मॉर्गन- मार्केट डेवलपमेंट डायरेक्टर; एफएसएससी फाउंडेशन में टेक्निकल मैनेजर सोशॅल सस्टेनेबिलिटी श्री एंते बेटिनिक और भारत प्रतिनिधि सुश्री स्मिता मूर्ति शामिल थे। इस बैठक का उद्देश्य एफएसएससी 24000 स्कीम और आगे की रणनीति पर चर्चा करना था। इसमें एफएसएससी 24000 स्कीम के लिए एनएबीसीबी के आकलनकर्ताओं एवं अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम और एफएसएससी 24000 के संबंध में एनएबीसीबी प्रत्यायित/आवेदक अनुरूपता आकलन निकायों के लिए एक विस्तृत जागरूकता सत्र के आयोजन पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में एनएबीसीबी के सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

4.5.5 आईएसएसीए के क्रेडेंशियलिंग प्रोग्राम और सीएमएमआई आकलन रूपरेखा पर वेबिनार

एनएबीसीबी ने आईएसएसीए के साथ मिलकर 8 जुलाई, 2024 को आईएसएसीए के क्रेडेंशियलिंग प्रोग्राम और सीएमएमआई आकलन रूपरेखा विषय पर एक प्रचुर सूचनाप्रद वेबिनार का संचालन किया।

आईएसएसीए ने, जो दुनिया भर के 170,000 से अधिक पेशेवरों की सदस्यता के साथ आईटी प्रमाणन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है, भारत के साइबर सुरक्षा लक्ष्यों में सहायता देने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। सीआईएसए, सीआईएसएम और सर्टिफाइड इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (सीईटी) प्रमाणन सहित आईटी प्रमाणन में उनकी व्यापक विशेषज्ञता, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के हमारे मिशन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है।

वेबिनार में आईएसएसीए के क्रेडेंशियलिंग प्रोग्राम (सीआईएसए, सीआईएसएम, सीजीईआईटी, सीडीपीएसई, सीआरआईएससी) और सीएमएमआई आकलन रूपरेखा के संबंध में विस्तृत प्रस्तुति शामिल थी। इस वेबिनार में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

4.5.6 ईसीसीपी और यूरोप्राइवेसी/इंटरप्राइवेसी प्रमाणन स्कीमों पर वेबिनार

एनएबीसीबी ने यूरोप्राइवेसी के सहयोग से ईसीसीपी और यूरोप्राइवेसी/इंटरप्राइवेसी प्रमाणन स्कीमों पर एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें दुनिया भर के 140 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रभावशाली भागीदारी की।

इस सत्र की शुरुआत, एनएबीसीबी के सीईओ श्री राजेश माहेश्वरी द्वारा नियामक परिदृश्य और डेटा गोपनीयता/संरक्षण के लिए प्रत्यायन प्रमाणन की जरूरत के संबंध में वर्तमान परिज्ञान के साथ हुई। ईसीसीपी में यूरोप्राइवेसी इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स के अध्यक्ष डॉ. सेबेस्टियन जेड. ने आज की परस्पर संबद्ध दुनिया में डेटा गोपनीयता की सुरक्षा के लिए ईसीसीपी, यूरोप्राइवेसी और इंटरप्राइवेसी फ्रेमवर्क, अत्यावश्यक साधनों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने यह भी बताया कि प्रमाणन निकाय, गोपनीयता अनुपालन और डेटा संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इन स्कीमों के तहत

किस तरह प्रमाणन प्रदान कर सकते हैं। यह उपस्थिति वैश्विक पैमाने पर गोपनीयता प्रमाणन मानकों को आगे बढ़ाने की तात्कालिकता और प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

इस वेबिनार में लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

4.5.7 गेट इट फेयर (जीआईएफ) ईएसजी रेटिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्कीम पर वेबिनार

एनएबीसीबी ने गेट इट फेयर के सहकार्य से 22 नवंबर, 2024 को गेट इट फेयर (जीआईएफ) - ईएसजी रेटिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्कीम विषय पर एक प्रचुर सूचनाप्रद वेबिनार का संचालन किया।

जीआईएफ ईएसजी रेटिंग स्कीम, संगठन (और उसके हितधारकों) की सामाजिक जिम्मेदारी तथा उसके प्रचालन और आपूर्ति श्रृंखला में ईएसजी जोखिमों के बारे में विश्वसनीय और सत्यापित जानकारी की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

इस वेबिनार में गेट इट फेयर (जीआईएफ) ईएसजी रेटिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्कीम, सटीक, विश्वसनीय और प्रामाणिक स्थायित्व सूचना के रुझान और मांग, ईएसजी रेटिंग और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, प्रत्यायन की भूमिका तथा विधिमान्यकरण और सत्यापन निकायों के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस वेबिनार में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

4.5.8 सीमेंस, जर्मनी के साथ बैठक

एनएबीसीबी ने जर्मनी की दिग्गज कंपनी सीमेंस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। यह कंपनी अनेक उद्योग क्षेत्रों में काम करती है और भारत में महत्वपूर्ण उपस्थिति रखती है।

सूचना के आदान-प्रदान और अनुरूपता आकलन में उभरते क्षेत्रों और परिपाटियों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट और अन्य संबंधित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए यह बैठक 4 दिसंबर, 2024 को की गई थी। सीमेंस की टीम ने एनएबीसीबी को एआई के बारे में आगामी ईसी विनियमन के कार्यान्वयन के संबंध में भी जानकारी दी और उद्योग के दृष्टिकोण से आपसी हित के क्षेत्रों में मदद करने की पेशकश की। एनएबीसीबी ने सीमेंस टीम को भारत में गुणवत्ता अवसंरचना, विशेषत: प्रत्यायन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी जानकारी दी, जिसे पिछले दो जीक्यूआईआई वैश्विक रैंकिंग के अनुसार विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर रखा गया है।

4.5.9 वैश्विक गुणवत्ता अवसंरचना सूचकांक (जीक्यूआईआई) के बारे में बैठक

एनएबीसीबी ने 14 फरवरी, 2025 को वैश्विक गुणवत्ता अवसंरचना सूचकांक (जीक्यूआईआई) के बारे में एक बैठक की। इस बैठक में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला (एनपीएल), राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह बैठक जीक्यूआईआई 2025 रैंकिंग की कार्यविधि पर चर्चा करने और इस वर्ष की रैंकिंग के लिए इनपुट/तैयारी प्रस्तुत करने के लिए बुलाई की गई थी।

4.5.10 यूके आरएमएस बोर्ड बैठक

एनएबीसीबी ने 25 फरवरी, 2025 को संपन्न यूके-आरएमएस (यूनाइटेड किंगडम रीजनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर फॉर एयरोस्पेस क्यूएमएस स्कीम) की तिमाही बैठक में वर्चुअल रूप से भाग लिया। इस बैठक में एनएबीसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बोर्ड के सीईओ ने भी भाग लिया। इस बैठक में विभिन्न हितधारकों अर्थात यूकेएएस और एनएबीसीबी जैसे प्रमाणन निकायों, प्रत्यायन निकायों और यूनाइटेड किंगडम के रक्षा क्षेत्र के नियामक निकाय ने विचार-विमर्श किया।

4.6 सरकार/नियामकों/उद्योग/उपभोक्ताओं को सहायता

4.6.1 टीईसी ने एनएबीसीबी प्रत्यायन पर भरोसा करने का निर्णय लिया

क्यूसीआई/एनएबीसीबी और भारत में दूरसंचार उत्पादों और उनके विनिर्माताओं के अनुमोदन के लिए विनियामक - दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र (टीईसी) ने उत्पाद प्रमाणन निकायों (पीसीबी) को आईएसओ/आईईसी 17065 के अनुसार प्रत्यायन प्रदान करने के उद्देश्य से "भारत अनुरूपता आकलन स्कीम (आई-सीएएस) - दूरसंचार उत्पाद" विकसित करने के लिए सहयोग करने तथा दूरसंचार उत्पादों और संबंधित आईसीटी उपकरणों के विनिर्माताओं के एनएबीसीबी प्रत्यायित प्रमाणन और उनके किस्म अनुमोदन पर भरोसा करने पर सहमत हुए।

क्यूसीआई/एनएबीसीबी और टीईसी के बीच एक प्रारंभिक बैठक हुई, जो एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि एक और विनियामक ने एनएबीसीबी प्रत्यायन पर भरोसा करने का निर्णय लिया है। एनएबीसीबी के सीईओ श्री राजेश माहेश्वरी और टीईसी के उप महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार ने अपनी-अपनी टीमों और विशेषज्ञों के साथ इस स्कीम के विकास और इसकी विशिष्ट अपेक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

यह सहकार, भारत में दूरसंचार एवं संबंधित आईसीटी उत्पादों के लिए एक मजबूत, प्रत्यायित अनुरूपता आकलन पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने की दिशा में क्यूसीआई/एनएबीसीबी द्वारा किए गए ठोस प्रयास को दर्शाता है, जो एक ऐसे भविष्य का वादा करता है जहां भारत के प्रमाणित उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बैंचमार्क पर खरे उतरेंगे और वैश्विक बाजारों में व्यापार और स्पर्धात्मकता को बढ़ावा देंगे।

4.6.2 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ बैठक

सेबी ने 10 मई, 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562 और 11 जुलाई, 2023 के मुख्य परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 के तहत सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा ईएसजी प्रकटीकरण के आश्वासन का सत्यापन शुरू करने का निर्णय लिया था। इस संदर्भ में, एनएबीसीबी ने आश्वासन प्रदाताओं के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन के निर्धारण के संबंध में सेबी के साथ चर्चा शुरू की, जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व (बीआर) और स्थायित्वपूर्ण रिपोर्टिंग (एसआर) मूल आश्वासन का सत्यापन करेंगे। सेबी ने बीआरएसआर मूल आश्वासन संबंधी अपने उद्योग मानकों में राष्ट्रीय प्रत्यायन पर विचार करने के लिए सहमति दी है।

4.6.3 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के साथ बैठक

भेल (बीएचईएल) की विभिन्न विनिर्माण सुविधाओं और संपूर्ण आपूर्ति मूल्य श्रृंखला में शामिल विक्रेताओं के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन निर्धारित करने के उद्देश्य से 24 दिसंबर, 2024 को भेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ बैठक की गई। इसके बाद, भेल की आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ-साथ उसकी आवश्यकताओं के लिए, विशेषत: निरीक्षण और प्रबंधन प्रणालियों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन निर्धारित करने पर भेल के गुणवत्ता आश्वासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चर्चा की गई। एनएबीसीबी और भेल, अपनी आपूर्ति श्रृंखला में उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन के अन्य क्षेत्रों का और अधिक लाभ उठाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए।

एनएबीसीबी में संयुक्त निदेशक श्री अजय शर्मा और श्री आनंद दीप गुप्ता ने भेल के कॉर्पोरेट गुणवत्ता आश्वासन और कॉर्पोरेट एचएसई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगे विचार-विमर्श करने के लिए 13 फरवरी, 2025 को भेल के साथ अनुवर्ती बैठक भी की।

4.6.4 विद्युत मंत्रालय और महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ बैठक

सीईओ, एनएबीसीबी श्री राजेश माहेश्वरी ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन के निर्धारण के संबंध में 20 जनवरी, 2025 को विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव एवं महानिदेशक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो श्री श्रीकांत नागुलापल्ली से मुलाकात की। विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले विभिन्न विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संयुक्त उद्यमों के लिए निरीक्षण, प्रमाणन और विधिमान्यकरण एवं सत्यापन करने हेतु एनएबीसीबी प्रत्यायित अनुरूपता आकलन निकायों (सीएबी) के उपयोग पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

4.6.5 मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के साथ बैठक

एनएबीसीबी ने एनएबीसीबी प्रत्यायन और प्रत्यायित अनुरूपता आकलन को बढ़ावा देने के लिए अपनी "इंडस्ट्री कनेक्ट" पहल के तहत, 18 फरवरी, 2025 को मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स 250 साल पुराना संगठन है और भारत की एक प्रमुख जहाज निर्माण कंपनी है, जो नौसेना और तटरक्षक बल के लिए आधुनिक युद्धपोतों, बॉम्बे हाई के लिए अपतटीय संरचनाओं और विभिन्न वाणिज्यिक एवं उपयोगी जलयानों का निर्माण करती है। पिछले कुछ वर्षों में, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने नौवहन उद्योग में गुणवत्तापूर्ण कार्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए ख्याति अर्जित की है।

सीईओ, एनएबीसीबी श्री राजेश माहेश्वरी और एचओडी/जीएम श्री सी एम लाटकर ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और एनएबीसीबी के संयुक्त निदेशक श्री अजय शर्मा के साथ चर्चा का नेतृत्व किया। इस बात पर बल दिया गया कि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड अपनी विविध अनुरूपता आकलन जरूरतों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन का उपयोग करे और उसका निर्धारण करे। इन जरूरतों में आपूर्ति श्रृंखला में अन्य-पक्ष निरीक्षण और उत्पाद प्रमाणन, व्यक्तियों का प्रमाणन, सत्यापन गतिविधियां आदि शामिल हैं। उन्हें यह भी बताया गया कि एनएबीसीबी की अंतरराष्ट्रीय मान्यता से क्या-क्या लाभ मिलेंगे। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के पास पहले से ही एनएबीसीबी-प्रत्यायित प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन हैं और वह अन्य-पक्ष निरीक्षणों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन निर्धारित कर रहा है।

इस बैठक के आयोजन में मुंबई स्थित इंटरनेशनल

सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो एनएबीसीबी प्रत्यायित निकाय है, ने सहायता की। इसके कंट्री मैनेजर श्री सुमीत कटारिया और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।



4.6.6 रिलायंस जियो के साथ बैठक

एनएबीसीबी ने एनएबीसीबी प्रत्यायन और प्रत्यायित अनुरूपता आकलन को बढ़ावा देने के लिए अपनी "इंडस्ट्री कनेक्ट" पहल के एक भाग के रूप में 21 फरवरी, 2025 को रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। रिलायंस जियो भारत में सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एकल-देश ऑपरेटर है। जियो ने पूरे भारत में एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत की है और 2016 में अपनी सेवाओं के शुभारंभ के पश्चात एक साल में भारत को मोबाइल ब्रॉडबैंड डेटा खपत में वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पर पहुंचा दिया है।

सीईओ, एनएबीसीबी श्री राजेश माहेश्वरी और संयुक्त निदेशक श्री अजय शर्मा ने नवी मुंबई में रिलायंस कॉरपोरेट पार्क में श्री ध्रुव कुमार तायल, अध्यक्ष, नेटवर्क इंफ्रा; श्री सुधीर अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष; श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव और आरजेआईएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। एनएबीसीबी प्रत्यायन और उद्योग क्षेत्रों में इसकी वैश्विक पहुंच के संबंध में एक संक्षिप्त विवरण आरजेआईएल के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा आपूर्ति श्रृंखला सहित इसकी विविध अनुरूपता आकलन जरूरतों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन का उपयोग करने अथवा निर्धारित करने पर बल दिया गया। आरजेआईएल के अधिकारियों ने एनएबीसीबी प्रत्यायन में, विशेषत: प्रत्यायित अन्य-पक्ष निरीक्षणों, आपूर्ति श्रृंखला में उत्पाद प्रमाणनों, अपनी अवसंरचना की स्थापना और अनुरक्षण के लिए आवश्यक विभिन्न कौशलों के लिए व्यक्तियों के प्रमाणन, प्रत्यायित सत्यापन गतिविधियों आदि तथा एनएबीसीबी की अंतरराष्ट्रीय मान्यता से उसे मिलने वाले लाभों में गहरी रुचि दिखाई। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आरजेआईएल के पास एक प्रबंधन प्रणाली में पहले से ही एनएबीसीबी प्रत्यायित प्रमाणन है तथा कंपनी एनएबीसीबी प्रत्यायन के तहत और अधिक प्रमाणन प्राप्त करना चाहती है। इसने विभिन्न अन्य-पक्ष अनुरूपता आकलनों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन निर्धारित करने में भी रुचि दिखाई है।

इस बैठक के आयोजन में मुंबई स्थित ब्यूरो वेरिटास ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो एनएबीसीबी प्रत्यायित निकाय है, ने सहायता की और इसके महाप्रबंधक श्री श्याम देशमुख और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।



4.6.7 दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) के साथ बैठक

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में एनएबीसीबी प्रत्यायन और प्रत्यायित अनुरूपता आकलन, विशेषत: उत्पाद प्रमाणन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एनएबीसीबी का दौरा किया। भारत सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा 1995 में संयुक्त रूप से स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, दिल्ली मेट्रो भारत में सबसे बड़ी और व्यस्ततम तीव्र परिवहन प्रणाली है, जो देश के राजधानी क्षेत्र को उप नगरों से जोड़ती है। दिल्ली मेट्रो, भारत में सार्वजनिक शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करने में सहायक रही है। दिल्ली मेट्रो ने रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए कार्बन क्रेडिट का दावा करने वाली दुनिया की पहली रेलवे परियोजना बनकर पर्यावरण के मोर्चे पर भी जबरदस्त योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी डीएमआरसी को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने के लिए कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली मेट्रो रेल और रेल-आधारित प्रणाली के रूप में प्रमाणित किया गया है, क्योंकि इसने शहर में प्रदूषण के स्तर को हर साल 6.3 लाख टन तक कम करने में मदद की है और इस तरह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद की है।

डीएमआरसी के अधिकारी श्री अरुण कुमार, सलाहकार (एस एंड टी), श्री शोभन चौधरी, सलाहकार (आर एंड डी), श्री नवीन तलवार, कार्यकारी निदेशक (आर एंड डी)

और अन्य अधिकारियों ने एनएबीसीबी में सीईओ श्री राजेश माहेश्वरी, संयुक्त निदेशक श्री अजय शर्मा और श्री आनंद दीप गुप्ता से मुलाकात की। डीएमआरसी अधिकारियों के समक्ष एनएबीसीबी प्रत्यायन और विशेष रूप से मेट्रो/रेलवे क्षेत्र में प्रत्यायित अनुरूपता आकलन से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। इस बात पर बल दिया गया कि डीएमआरसी अपनी आपूर्ति श्रृंखला सहित विविध अनुरूपता आकलन जरूरतों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन का उपयोग करे अथवा उसे निर्धारित करे। डीएमआरसी अधिकारियों ने एनएबीसीबी प्रत्यायन में, विशेषत: रेलवे संरक्षा मानकों और विनियमों के लिए स्वतंत्र संरक्षा आकलन (आईएसए) हेतु प्रत्यायित उत्पाद प्रमाणन में गहरी रुचि दिखाई। डीएमआरसी के समक्ष आपूर्ति श्रृंखला में उत्पाद प्रमाणन और विभिन्न विशिष्ट कौशलों के लिए व्यक्तियों के प्रमाणन पर भी बल दिया गया। डीएमआरसी ने अपनी विभिन्न अन्य-पक्ष अनुरूपता मूल्यांकन जरूरतों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन निर्धारित करने में रुचि दिखाई है और डीएमआरसी आगे भी एनएबीसीबी के साथ अनुवर्ती बैठकें करेगा।



4.6.8 एलएंडटी एनर्जी - हाइड्रोकार्बन (एडवेंट) के साथ बैठक

एनएबीसीबी ने एनएबीसीबी प्रत्यायन और प्रत्यायित अनुरूपता आकलन को बढ़ावा देने के लिए अपनी "इंडस्ट्री कनेक्ट" पहल के तहत हाल ही में एलएंडटी एनर्जी - हाइड्रोकार्बन (एडवेंट) के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। एलएंडटी का हाइड्रोकार्बन व्यवसाय परियोजनाएं प्रतिपादित करता है जिनमें इंजीनियरी, प्रापण, फेब्रीकेशन, निर्माण, संस्थापना, परियोजना प्रबंधन और परिसंपत्ति सेवाकाल प्रबंधन सेवाओं जैसे सभी प्रकार्य शामिल हैं। एडवेंट (उन्नत मूल्यपरक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी) एलएंडटी का एक व्यवसाय विभाग है, जो हाइड्रोकार्बन और विशिष्ट रसायन उद्योग को एकीकृत मॉड्यूलर समाधान, ईपीसी परियोजना समाधान और अत्याधुनिक हाइड्रोकार्बन प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराता है।

एनएबीसीबी के सीईओ श्री राजेश माहेश्वरी और संयुक्त निदेशक श्री अजय शर्मा ने मुंबई में एलएंडटी एडवेंट के क्यूए/क्यूसी प्रमुख श्री आलोक खरे; गुणवत्ता, अपतटीय पवन व्यवसाय प्रमुख श्री गुरुदास माद्ये; एलएंडटी, डीजीएम क्यूए/क्यूसी श्री प्रमोद पाटिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। एलएंडटी के समक्ष एनएबीसीबी प्रत्यायन और उद्योग क्षेत्रों में इसकी वैश्विक पहुंच का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया और एल एंड टी की आपूर्ति श्रृंखला सहित विविध अनुरूपता आकलन जरूरतों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन का उपयोग करने अथवा निर्धारण करने पर बल दिया गया। एलएंडटी के अधिकारियों ने एनएबीसीबी प्रत्यायन में, विशेष रूप से प्रत्यायित अन्य-पक्ष निरीक्षणों, अपनी आपूर्ति श्रृंखला में उत्पाद प्रमाणनों, उसके लिए जरूरी विभिन्न विशिष्ट कौशलों के लिए व्यक्तियों के प्रमाणन आदि में गहरी रुचि दिखाई। एलएंडटी ने अपनी विभिन्न अन्य-पक्ष अनुरूपता आकलन जरूरतों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन के निर्धारण में भी रुचि दिखाई है।

इस बैठक के आयोजन में एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो एनएबीसीबी प्रत्यायित निकाय है, ने सहायता की। इस बैठक में एसजीएस से एक्जिम और एचएस एंड क्यू, उद्योग एवं पर्यावरण प्रमुख श्री विश्वास नखवा भी उपस्थित थे।

4.6.9 सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड (एसएफएल) के साथ बैठक

एनएबीसीबी ने एनएबीसीबी प्रत्यायन और प्रत्यायित अनुरूपता आकलन को बढ़ावा देने के लिए अपनी "इंडस्ट्री कनेक्ट" पहल के तहत हाल ही में सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड (एसएफएल) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड मोटर वाहनों, अवसंरचना, पवन ऊर्जा और विमानन क्षेत्रों के लिए उच्च शुद्धता वाले पुर्जों का एक भारतीय विनिर्माता है। एसएफएल की स्थापना 1962 में टीवीएस समूह की एक सहायक कंपनी के रूप में कासजैक्स इंजीनियरिंग एंसिलरीज के नाम से की गई थी। यह कंपनी फास्टनर्स, ड्राइवट्रेन पार्ट्स, मोल्डेड मेटल गुड्स, रेडिएटर टॉप्स और वाटर पंप सहित अनेक उत्पादों का विनिर्माण करती है। चेन्नै, तमिलनाडु में अपने मुख्यालय के साथ एसएफएल पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु में कई संयंत्रों का प्रचालन करती है। कंपनी ने चीन में सुंदरम फास्टनर्स (झेजियांग) लिमिटेड और यूनाइटेड किंगडम में क्रैमलिंग्टन प्रिसिजन फोर्ज लिमिटेड जैसी सहायक कंपनियों के साथ वैश्विक स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है।

एनएबीसीबी के सीईओ श्री राजेश माहेश्वरी और संयुक्त निदेशक श्री अजय शर्मा ने एसएफएल के कार्यकारी निदेशक श्री एस.वी. महेश से मुलाकात की। एनएबीसीबी प्रत्यायन और उद्योग क्षेत्रों में इसकी वैश्विक पहुंच का एक संक्षिप्त विवरण सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड (एसएफएल) के समक्ष प्रस्तुत किया गया और आपूर्ति श्रृंखला सहित इसकी विविध अनुरूपता आकलन जरूरतों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन का उपयोग करने अथवा निर्धारण करने पर बल दिया गया। सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड (एसएफएल) के अधिकारियों ने एनएबीसीबी प्रत्यायन में, विशेषत: प्रत्यायित अन्य-पक्ष निरीक्षणों, अपनी आपूर्ति श्रृंखला में उत्पाद प्रमाणन, उसके लिए जरूरी विभिन्न विशिष्ट कौशलों के लिए व्यक्तियों के प्रमाणन आदि में गहन रुचि दिखाई। एसएफएल ने अपनी विभिन्न अन्य-पक्ष अनुरूपता आकलन जरूरतों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन निर्धारित करने में रुचि दिखाई है।

4.6.10 ईजेन समूह की एक यूनिट, केडीडीएल लिमिटेड के साथ बैठक

एनएबीसीबी ने एनएबीसीबी प्रत्यायन और प्रत्यायित अनुरूपता आकलन को बढ़ावा देने के लिए अपनी "इंडस्ट्री कनेक्ट" पहल के तहत हाल ही में 24 मार्च, 2025 को केडीडीएल लिमिटेड (यूनिट ईजेन) के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

सीईओ, एनएबीसीबी श्री राजेश माहेश्वरी और संयुक्त निदेशक श्री अजय शर्मा ने केडीडीएल लिमिटेड के श्री एमएस रामानंदन (प्लांट हेड); श्री कृष्णामूर्ति भट (प्रबंधन प्रतिनिधि) और श्री भूपति (मार्केटिंग हेड) से मुलाकात की। एनएबीसीबी प्रत्यायन और उद्योग क्षेत्रों में इसकी वैश्विक पहुंच का एक संक्षिप्त विवरण केडीडीएल लिमिटेड (यूनिट ईजेन) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। केडीडीएल लिमिटेड के अधिकारियों ने एनएबीसीबी प्रत्यायन में, विशेषत: प्रत्यायित अन्य-पक्ष निरीक्षणों, अपनी आपूर्ति श्रृंखला में उत्पाद प्रमाणन, उसके लिए जरूरी विभिन्न विशिष्ट कौशलों के लिए व्यक्तियों के प्रमाणन आदि में गहन रुचि दिखाई। केडीडीएल लिमिटेड ने अपनी विभिन्न अन्य-पक्ष अनुरूपता आकलन जरूरतों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन निर्धारित करने में भी रुचि दिखाई है।

4.6.11 इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2025 (आईडीएस)

सीईओ, एनएबीसीबी श्री राजेश माहेश्वरी को 15 जनवरी, 2025 को "इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट – रोड टु नेट जीरो 2025 (आईडीएस)" के दूसरे संस्करण में "वक्ता" के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने "कार्बन अभिग्रहण और भंडारण तकनीकों को सुगम बनाने के लिए प्रत्यायन" विषय पर एक तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें उन्होंने एनएबीसीबी प्रत्यायन की भूमिका का वर्णन किया और बताया कि प्रत्यायित सेवाओं का उपयोग करने से उद्योग को कैसे लाभ होता है।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किया। इसमें सरकार, उद्योग, परामर्शदाताओं और सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। पैनल चर्चा और प्रस्तुतीकरणों में डीकार्बनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय जलवायु, ई-मोबिलिटी, ईएसजी, अल्प कार्बन उत्पादन, बैटरी चार्जिंग और ऊर्जा भंडारण प्रणाली तथा कार्बन अभिग्रहण उपयोग एवं भंडारण प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों और विनियमों सहित विविध प्रकरण शामिल किए गए।

यह कार्यक्रम भारतीय वायु प्रदूषण नियंत्रण संघ (आईएएपीसी), दिल्ली और पीएचडीसीसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

यह शिखर सम्मेलन डीकार्बनाइजेशन से संबंधित अनेक विषयों पर केन्द्रित रहा जिनमें जलवायु परिवर्तन एवं प्रशमन, स्थायित्व प्रबंधन, नीतिगत मुद्दों, नेट-ज़ीरो के लिए संवहनीय मार्ग और अभिनव जलवायु समाधानों के लिए संभावनाशील प्रौद्योगिकियां जैसे विषय शामिल थे।

इस कार्यक्रम में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनेक नेतृत्वकर्ताओं ने भाग लिया, जो भारत में जलवायु कार्रवाई में आगे आगे रहे हैं। इसका उद्देश्य रणनीतिक व्यावसायिक संबंधों का निर्माण करना, नई गहन जानकारी प्राप्त करना तथा नेटवर्किंग कार्यक्रमों और रणनीतिक आदान-प्रदान सत्रों के माध्यम से जलवायु के संबंध में वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं के साथ सहकार करना है।



4.6.12 एमआरएआई द्वारा इंटरनेशनल मेटीरियल रीसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस

सीईओ, एनएबीसीबी श्री राजेश माहेश्वरी को 28 जनवरी, 2025 को एमआरएआई द्वारा इंटरनेशनल मेटीरियल रीसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस 2025 में एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। वह "कार्बन बाजारों का प्रशस्तीकरण और चक्रीय अर्थव्यवस्था में रीसाइक्लिंग की भूमिका" सत्र में शामिल हुए। उन्होंने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने में कार्बन अभिग्रहण और भंडारण (सीसीएस) की भूमिका, उत्सर्जन में प्रामाणिक कमी सुनिश्चित करने में प्रत्यायन के महत्व, और कार्बन अभिग्रहण एवं उपयोग (सीसीयू) में प्रत्यायित विधिमान्यकरण और सत्यापन निकायों की भूमिका के बारे में बात की।

इस सम्मेलन ने विभिन्न मंत्रालयों, हितधारकों और रीसाइक्लर्स को एक ही छत के नीचे नेटवर्किंग का और अपने व्यावसायिक हितों, उत्पादों, प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, नवाचारों और संदर्शों को प्रदर्शित करने का अवसर दिया।



4.7 प्रचार गतिविधियां

4.7.1 एनएबीसीबी ने विश्व प्रत्यायन दिवस 2024 मनाया

विश्व प्रत्यायन दिवस (डब्ल्यूएडी), अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (आईएलएसी) और अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन मंच (आईएएफ) द्वारा स्थापित एक वैश्विक पहल है। यह दिवस संबंधित हितधारकों में प्रत्यायन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 9 जून को मनाया जाता है।

विश्व प्रत्यायन दिवस (डब्ल्यूएडी) 2024 मनाने के लिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) के दो घटक बोर्डों अर्थात राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) और राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) ने देश के भिन्न-भिन्न भागों में कार्यक्रम आयोजित किए। "एक्रेडिटेशन: एम्पावरिंग टुमॉरो एंड शेपिंग द फ्यूचर'" विषय पर मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में और 19 समानांतर कार्यक्रम मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद तथा लखनऊ आदि अन्य शहरों में आयोजित किए गए।

उद्घाटन सत्र में डीपीआईआईटी सचिव श्री राजेश कुमार सिंह; एम्स, नई दिल्ली के निदेशक श्री एम. श्रीनिवास; क्यूसीआई अध्यक्ष श्री जक्षय शाह और क्यूसीआई महासचिव श्री चक्रवर्ती टी. कन्नन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सीईओ, एनएबीसीबी श्री राजेश माहेश्वरी ने अपने स्वागत भाषण में इस बात पर बल दिया कि एक मजबूत प्रत्यायन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि कोई संगठन गुणवत्ता और मानकों का उच्च स्तर हासिल करे। उन्होंने आगे कहा कि क्यूसीआई के बोर्ड - एनएबीसीबी और एनएबीएल - प्रत्यायन के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विश्व प्रत्यायन दिवस 2024 के अवसर पर आईएएफ-आईएलएसी अध्यक्ष का संयुक्त संदेश, श्री पंकज जौहरी, निदेशक, एनएबीएल द्वारा पढ़ा गया। संदेश में यह कहा गया कि प्रत्यायन भरोसे और विश्वसनीयता की रूपरेखा प्रदान करके, संगठनों को आत्मविश्वास के साथ नई तकनीकें अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। चाहे यह विनिर्माण क्षेत्र हो, स्वास्थ्यचर्या क्षेत्र हो अथवा कृषि क्षेत्र हो, प्रत्यायित अनुरूपता आकलन यह सुनिश्चित करता है कि नए उत्पाद और प्रक्रियाएं कठोर अपेक्षाओं को पूरा करें, जिससे उन्हें अपनाने और विद्यमान प्रणालियों में एकीकृत करने में सुविधा होती है। परीक्षण और निरीक्षण, उत्पाद संरक्षा और विनियामक अनुपालन में भरोसा पैदा करते हैं। डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा स्कीमें व्यवसायों को व्यापक डेटा संरक्षण प्रक्रियाएं लागू करने, तेजी से जटिल हो रहे साइबर हमलों से बचाव और उपभोक्ता गोपनीयता की रक्षा करने में मदद करती हैं।

मुख्य अतिथि, श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव, डीपीआईआईटी ने मानक परिपाटियों से आगे बढ़ने और ऐसी प्रक्रियाएं विकसित करने की जरूरत पर बल दिया जो हमें एक विशिष्ट पहचान दें। उन्होंने कहा कि प्रत्यायन निकाय और संपूर्ण गुणवत्ता प्रणाली को सुदृढ़ करना एक आवश्यकता मात्र नहीं है, बल्कि उत्कृष्टता की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

क्यूसीआई महासचिव श्री चक्रवर्ती टी. कन्नन ने इस कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में क्यूसीआई की भविष्योन्मुखी संकल्पना के बारे में बात की। उन्होंने क्यूसीआई के मार्गदर्शन में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों

और आगामी वर्षों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करने पर बल दिया। उन्होंने यह रेखांकित किया कि गुणवत्ता एक सतत यात्रा है। उन्होंने भविष्य को आकार देने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका भी रेखांकित की और सुझाव दिया कि एआई गुणवत्ता मानकों और प्रत्यायन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।

अपने बीज वक्तव्य में, एम्स, नई दिल्ली के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास ने आईटी, साइबर सुरक्षा और एआई सहित सभी क्षेत्रों में उच्च मानक बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। डॉ. श्रीनिवास ने बताया कि कई प्रयोगशाला कार्य अब एआई द्वारा किए जाते हैं, जिससे जांच, संतुलन और सुरक्षा प्रक्रियाएं बेहतर होती हैं।

तकनीकी सत्र में, बीआईएस, आईसीएमआर, कार्बन चेक, आईएआरआई, टीयूवी एसयूडी दक्षिण एशिया, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और आईआरक्लास के पैनलिस्ट ने मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, जो सूत्र की भांति औद्योगिक परिपाटियों के हर पहलू में उत्कृष्टता बुनते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इन मानकों के अनुपालन से निरंतरता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रत्यायन का महत्व रेखांकित किया, इसे विश्वास की मुहर बताया जिससे इन उच्च मानकों को बनाए रखने की किसी संगठन की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है और हितधारकों एवं उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ता है।





4.8 अनुरूपता आकलन निकायों (सीएबी) के साथ एनएबीसीबी का संपर्क-संवाद

4.8.1 निरीक्षण निकायों के साथ वार्षिक बैठक 2024

निरीक्षण एवं विधिमान्यकरण/सत्यापन निकायों (आईबी और वीवीबी) के साथ एनएबीसीबी की वार्षिक संपर्क-संवाद बैठक दिनांक 13 मई, 2024 को आयोजित की गई। यह बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। इस बैठक में एनएबीसीबी के अध्यक्ष डॉ. आर.पी. सिंह भी उपस्थित रहे और उन्होंने इस विषय पर अपनी अंतर्दृष्टि का परिचय देते हुए प्रतिभागियों को संबोधित भी किया। बैठक में 82 प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 40 प्रतिभागियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। बैठक में पीएनजीआरबी, बीआईएस, एफएसएसएआई, बीईई, डीजीक्यूए, डीजीसीए और वीईआरआरए जैसे विनियामक और स्कीम स्वामी संगठन भी उपस्थिति रहे, जिन्होंने प्रत्यायित निरीक्षण निकायों के उपयोग के संबंध में अपनी अपेक्षाएं/अनुभव साझा किए। इसमें निरीक्षण निकायों और वीवीबी द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा की गई। यह चर्चा प्रत्यायित अन्य-पक्ष निरीक्षणों, प्रत्यायित निकायों के अनुभवों और स्थायित्वपूर्ण विमानन ईंधन कार्यक्रम की स्थिति पर केन्द्रित थीं। एनएबीसीबी सचिवालय ने आईएलएसी, एपीएसी और आईएएफ संकल्पों, अवस्थांतर नीतियों और संशोधित प्रत्यायन मापदंडों के संबंध में अद्यतन जानकारी साझा की।



4.8.2 प्रमाणन निकायों के साथ वार्षिक बैठक 2024

एनएबीसीबी ने प्रमाणन निकायों (सीबी) की वार्षिक संपर्क-संवाद बैठक 14 मई, 2024 को आयोजित की। यह बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। बैठक में 58 प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 35 प्रतिभागियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। कार्यसूची के अनुसार, आईएएफ/एपीएसी के संबंध में अद्यतन जानकारी, नए आईएसओ सीएएससीओ (कैस्को) मानक एवं संशोधन

की स्थिति, आईएएफ एमएलए के अंतर्गत सम्मिलित नई स्कीमों, विभिन्न आईएएफ अनिवार्य दस्तावेज, अवस्थांतर नीति जैसे विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिए गए तथा प्रमाणन निकायों के प्रश्नों पर स्पष्टीकरण दिए गए। प्रमाणन निकायों ने भी एनएबीसीबी के साथ अपने अनुभव साझा किए। बैठक में सीईए, सीडीएससीओ, एफएसएससी फाउंडेशन और बीआरसीजीएस जैसे विनियामक एवं स्कीम स्वामी संगठन भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस बैठक में प्रमाणन निकायों के साथ संवाद-संपर्क किया।



4.8.3 एनएबीसीबी गुणवत्ता मंथन

राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) का गुणवत्ता मंथन 17 फरवरी, 2025 को सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इसमें अनुरूपता आकलन निकायों (सीएबी) के 35 से अधिक उद्योग जगत प्रमुखों ने भाग लिया तथा राष्ट्रीय और हितधारकों के दृष्टिकोण से यथा-अपेक्षित एनएबीसीबी प्रत्यायन और प्रत्यायित अनुरूपता आकलन के लिए भावी जरूरतों पर गहन विचार-विमर्श किया। इस कार्यक्रम का आयोजन एनएबीसीबी और एनबीक्यूपी द्वारा किया गया था।

विचार-विमर्श का नेतृत्व क्यूसीआई महासचिव श्री चक्रवर्ती टी. कन्नन; एनएबीसीबी अध्यक्ष डॉ. रवि पी. सिंह; श्रीमती हेमगौरी भंडारी, मुख्य सलाहकार, क्यूसीआई; और श्री राजेश माहेश्वरी, सीईओ, एनएबीसीबी ने किया। उन्होंने सक्रिय रूप से विचार-मंथन सत्र का नेतृत्व किया, प्रश्नों के उत्तर दिए, हितधारकों से फीडबैक प्राप्त किया और प्रत्यायन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की।

बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और गुणवत्ता के प्रति साझा प्रतिबद्धता के साथ, यह मंथन भारत के उद्योग क्षेत्रों में प्रत्यायित अन्य-पक्ष अनुरूपता आकलन के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षाकृत मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र का मार्ग प्रशस्त करता है।



4.8.4 प्रमाणन निकायों के साथ वार्षिक बैठक 2025

एनएबीसीबी ने प्रमाणन निकायों (सीबी) की वार्षिक संपर्क-संवाद बैठक 24 फरवरी, 2025 को आयोजित की। यह बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। इस बैठक में 51 प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 35 प्रतिभागियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। बैठक की कार्यसूची के अनुसार, आईएएफ/एपीएसी के संबंध में अपडेट; विमानन, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र की आईसीओपी स्कीम, आई-सीएएस हलाल स्कीम, अवस्थांतर नीति, स्थायित्वपूर्ण विमानन ईंधन संबंधी प्रमाणन स्कीम, अंतरराष्ट्रीय विशिष्ट मानक (आईएफएस) स्कीम, क्यूसीआई-पीएडीडी: अनुरूपता आकलन स्कीम, औद्योगिक ऑटोमेशन में साइबर सुरक्षा के लिए आईएसए सिक्योर स्कीम, रेलवे के लिए स्वतंत्र संरक्षा आकलन (आईएसए) आदि जैसे विभिन्न प्रकरणों पर प्रस्तुतीकरण दिए गए तथा प्रमाणन निकायों के प्रश्नों के स्पष्टीकरण दिए गए। प्रमाणन निकायों ने भी एनएबीसीबी के साथ अपने अनुभव साझा किए। बैठक में सीडीएससीओ जैसे नियामक और आईएससीसी, आईएफएस और आईएनएक्यूजी जैसे स्कीम स्वामी संगठन भी उपस्थित थे, जिन्होंने प्रमाणन निकायों के साथ संपर्क-संवाद किया।



4.8.5 निरीक्षण निकायों के साथ वार्षिक बैठक 2025

एनएबीसीबी ने निरीक्षण एवं विधिमान्यकरण/सत्यापन निकायों (आईबी और वीवीबी) की वार्षिक संपर्क-संवाद बैठक 25 फरवरी, 2025 को आयोजित की। यह बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। एनएबीसीबी के अध्यक्ष डॉ. आर.पी. सिंह बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए और प्रतिभागियों को इस विषय पर अपनी अंतर्दृष्टि से परिचित कराया। बैठक में 86 प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 30 प्रतिभागियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। बैठक में पीएनजीआरबी, गोल्ड स्टैंडर्ड एवं वीईआरआरए जैसे नियामक और स्कीम स्वामी संगठन भी उपस्थित थे, जिन्होंने प्रत्यायित निरीक्षण निकायों के उपयोग के संबंध में अपनी अपेक्षाओं/अनुभवों के बारे में बताया। आईबी और वीवीबी द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा की गई। यह चर्चा प्रत्यायित अन्य-पक्ष निरीक्षण, गोल्ड स्टैंडर्ड, वीईआरआरए (वेरा) प्रमाणन स्कीम, स्थायित्वपूर्ण विमानन ईंधन कार्यक्रम आदि पर केन्द्रित रही। एनएबीसीबी सचिवालय ने आईएलएसी, एपीएसी और आईएएफ संकल्पों, अवस्थांतर नीतियों तथा आईएसओ/आईईसी 17020 में परिवर्तन के संबंध में अद्यतन जानकारी साझा की।



4.9 उपभोक्ता/उद्योग जागरूकता कार्यक्रम

4.9.1 एक्यूएमएस प्रत्यायन विषय पर जागरूकता सत्र

द इंडियन एयरोस्पेस क्वालिटी ग्रुप (आईएनएक्यूजी), जो एपीएक्यूजी/आईएक्यूजी का कंट्री क्वालिटी ग्रुप है, ने एनएबीसीबी के साथ मिलकर 25 अप्रैल, 2024 को "आईएनएक्यूजी और भारतीय एयरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला सुधार पहलों में इसकी भूमिका" विषय पर जागरूकता वेबिनार सत्र की मेजबानी की। इस जागरूकता सत्र में आईएनएक्यूजी की स्थापना और इसकी भूमिका तथा एनएबीसीबी द्वारा विकसित भारत-आईसीओपी स्कीम जैसे प्रकरणों पर चर्चा की गई। इस सत्र में लगभग 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

4.9.2 निरीक्षण निकायों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन तथा उद्योग एवं सरकारी निकायों को इसके लाभ विषय पर वेबिनार

एनएबीसीबी ने 18 जून, 28 अगस्त, 2024; 13 नवंबर, 2024; 15 जनवरी, 2025; 19 फरवरी, 2025 और 19 मार्च, 2025 को निरीक्षण निकाय प्रत्यायन स्कीम विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सरकारी संगठनों, विनियामकों और उद्योग जगत में एनएबीसीबी प्रत्यायित निरीक्षण निकाय के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा निरीक्षण निकाय प्रत्यायन स्कीम को बढ़ावा देना था। एनएबीसीबी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और लगभग 740 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, घाना, मोरक्को, हांगकांग, भूटान, कजाखिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, केन्या, रूस, फिलीपींस, जॉर्डन, ताइवान, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात आदि जैसे देशों से प्रतिभागी शामिल थे। इस वेबिनार में एनएबीसीबी प्रत्यायन और उसके लाभों, एनएबीसीबी प्रत्यायन प्रक्रिया और आईएसओ/आईईसी 17020:2012 मानक की प्रमुख अपेक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एनएबीसीबी के संयुक्त निदेशक श्री अजय शर्मा, श्री आनंद दीप गुप्ता और उप निदेशक सुश्री वर्षा मिश्रा इस वेबिनार के वक्ता थे।

4.9.3 आईएसओ/आईईसी 17029:2019 के सिंहावलोकन के साथ, विधिमान्यकरण और सत्यापन निकायों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन विषय पर वेबिनार

एनएबीसीबी ने 23 अगस्त, 2024 और 30 दिसंबर, 2024 को वेबिनार आयोजित किए। इनका उद्देश्य सरकारी संगठनों, नियामकों, उद्योग जगत में एनएबीसीबी प्रत्यायित विधिमान्यकरण और सत्यापन निकायों के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा विधिमान्यकरण और सत्यापन निकाय प्रत्यायन स्कीम को बढ़ावा देना था। एनएबीसीबी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और लगभग 300 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, जिनमें भूटान, घाना, कजाखिस्तान, मंगोलिया, पेरू, श्रीलंका, ट्यूनीशिया, म्यांमार, केन्या, यूएई और जॉर्डन आदि देशों के प्रतिभागी शामिल थे। इस वेबिनार में एनएबीसीबी प्रत्यायन और इसके लाभों, एनएबीसीबी प्रत्यायन प्रक्रिया और आईएसओ/आईईसी 17029 मानक की प्रमुख अपेक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एनएबीसीबी के संयुक्त निदेशक श्री अजय शर्मा और श्री आनंद दीप गुप्ता इस वेबिनार के वक्ता थे।

4.9.4 आईएसओ/आईईसी 17065:2012 के सिंहावलोकन के साथ 'उत्पाद प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन' विषय पर वेबिनार

एनएबीसीबी ने 19 नवंबर, 2024 और 26 फरवरी, 2025 को आईएसओ/आईईसी 17065:2012 मानक के संबंध में एक सिंहावलोकन के साथ 'उत्पाद प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन' विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया। इस वेबिनार में विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय उत्पाद प्रमाणन स्कीमों की जानकारी प्रदान की गई। इस वेबिनार में आईएसओ 17065:2012 मानक की अपेक्षाओं और विभिन्न विद्यमान उत्पाद प्रमाणन स्कीमों के बारे में गहन जानकारी प्रदान की गई। इस वेबिनार में लगभग 220 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें भूटान, घाना, पाकिस्तान, ओमान, केन्या, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, ट्यूनीशिया, जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश आदि देशों के प्रतिभागी भी शामिल थे। एनएबीसीबी के संयुक्त निदेशक श्री आनंद दीप गुप्ता और उप निदेशक सुश्री वर्षा मिश्रा इस वेबिनार के वक्ता थे।

4.9.5 खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली विषय पर वेबिनार

एनएबीसीबी ने खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणालियों (एफएसएमएस) पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 28 मार्च, 2025 को प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया। इस सत्र में एनएबीसीबी प्रत्यायन प्रक्रिया, उसके मापदंड और खाद्य सुरक्षा एवं विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने में इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए, आईएसओ/आईईसी 17021-1:2015 और आईएसओ 22003-1:2022 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसमें 120 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें बांग्लादेश, भूटान, घाना, श्रीलंका, यूएई आदि के प्रतिभागी भी शामिल थे। इस सत्र में प्रमाणन प्रक्रियाओं और उद्योग जगत की सर्वोत्तम परिपाटियों पर सार्थक चर्चा हुई। एनएबीसीबी के संयुक्त निदेशक श्री आनंद दीप गुप्ता और उप निदेशक सुश्री वर्षा मिश्रा इस वेबिनार के वक्ता थे।

4.9.6 आईटी क्षेत्र में विनियमन, प्रत्यायन और प्रमाणन विषय पर वेबिनार

एनएबीसीबी ने 23 दिसंबर, 2024 को आईटी क्षेत्र में विनियमन, प्रत्यायन और प्रमाणन विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया। इस वेबिनार में वैश्विक आईटी परिदृश्य में सर्वोत्तम परिपाटियों और अनुपालनों, एनएबीसीबी प्रत्यायन मापदंडों की अपेक्षाओं, सूचना सुरक्षा प्रक्रिया और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रबंधन प्रणाली स्कीमों और इनके लाभ तथा भारत में आईटी/साइबर कानून पारिस्थितिकी तंत्र और आगे की राह के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई। श्री श्रीनिवास काज़ा, एनएबीसीबी विशेषज्ञ और श्री अजय शर्मा, संयुक्त निदेशक (एनएबीसीबी) इस वेबिनार के वक्ता थे। वेबिनार में लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

4.9.7 आईएसओ/आईईसी 17024:2012 के सिंहावलोकन के साथ कार्मिक प्रमाणन निकायों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन विषय पर वेबिनार

एनएबीसीबी ने प्रत्यायन मानकों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ाने के उद्देश्य से 31 जनवरी, 2025 को एक वेबिनार का आयोजन किया। एनएबीसीबी ने हाल ही में "कार्मिक प्रमाणन निकायों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन: आईएसओ/आईईसी 17024 का सिंहावलोकन और विभिन्न क्षेत्रों में इसका महत्व" विषय पर एक सूचनाप्रद वेबिनार का आयोजन किया था। इस सत्र में आईएसओ/आईईसी 17024 मानक का व्यापक बोध कराया गया, जिसमें प्रत्यायन प्रक्रिया, प्रमुख खंड, प्रमाणन स्कीमें, मूलभूत अपेक्षाएं तथा प्रमाणन निकायों, उद्योगों और विनियामक प्राधिकरणों को इससे मिलने वाले लाभ जैसे विषय शामिल थे। एनएबीसीबी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और लगभग 150 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, जिनमें ओमान, यूएई, भूटान, केन्या, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जापान, ईरान आदि देशों के प्रतिभागी शामिल थे। एनएबीसीबी के संयुक्त निदेशक श्री अजय शर्मा और उप निदेशक सुश्री वर्षा मिश्रा इस वेबिनार के वक्ता थे।


NBQP
5 राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड (एनबीक्यूपी)

राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड (एनबीक्यूपी), भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) का एक घटक बोर्ड है, जिसे सभी क्षेत्रों और समाज के भीतर गुणवत्ता को एक प्रमुख जीवन मूल्य के रूप में स्थापित करने का मिशन सौंपा गया है। "राष्ट्रीय कल्याण के लिए गुणवत्ता" के सर्वव्यापी विज़न से मार्गदर्शित, एनबीक्यूपी उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्यचर्या, और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) – जिन्हें व्यापक रूप से भारत के समावेशी विकास और प्रगति के स्तंभों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों, साधनों और संरचनाओं के अंगीकरण और उनके उन्नयन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ।

मूलतः,एनबीक्यूपी का उद्देश्य निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना, उत्पादकता और स्पर्धात्मकता को बढ़ाना, तथा गुणवत्ता के दृष्टिकोण से अभिशासन प्रणालियों को सशक्त बनाना है। इसके हस्तक्षेप न केवल संस्थाओं को उनकी अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद प्रदान करते हैं, बल्कि नागरिकों और सेवा प्रदाताओं दोनों में समान रूप से उत्कृष्टता और उत्तरदायित्व की मानसिकता भी विकसित करते हैं।

एनबीक्यूपी की कार्यनीति का एक विशिष्ट तत्व, नागरिक सशक्तीकरण पर इसके द्वारा बल दिया जाना है। लक्षित जागरूकता कार्यक्रमों, अभियानों, और क्षमता निर्माण पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से, यह बोर्ड व्यक्तियों को सूचना-संपन्न और गुणवत्ता के प्रति जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मांग-प्रेरित रणनीति एक प्रेरक प्रभाव पैदा करती है – जहां उपभोक्ता की अपेक्षाएं उत्पादकों, सेवा प्रदाताओं और संस्थाओं को अपने मानकों को उन्नत करने के लिए उत्प्रेरित करती हैं - जिससे गुणवत्ता एक विनियामक दायित्व के बजाय एक साझा राष्ट्रीय आकांक्षा बन जाती है।

इस मिशन को पूरा करने के लिए, एनबीक्यूपी देश भर में शैक्षिक पहलों और संपर्क-विस्तार, सहभागिता की एक विस्तृत श्रृंखला संचालित करता है। गुणवत्ता संकल्प, गुणवत्ता यात्रा, गुणवत्ता मंथन, और गुणवत्ता समृद्धि जैसे प्रमुख कार्यक्रम गतिशील मंचों के रूप में कार्य करते हैं जो गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन के लिए विचार-विमर्श और सह-निर्माण के पथ-प्रशस्त करने हेतु नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, युवाओं और सिविल सोसाइटी को एकजुट करते हैं। गुणवत्ता समर फनकैंप और गुणवत्ता पखवाड़ा जैसे युवा-केंद्रित अभियान, आरम्भ से ही युवाओं में गुणवत्ता मूल्यों को स्थापित करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अगली पीढ़ी उच्च मानकों को बनाए रखने और उनकी मांग करने में सक्षम हो। इन पहलों के अलावा, एनबीक्यूपी क्यूसीआई के बोर्डों और प्रभागों को उनके प्रमुख कार्यक्रमों के आयोजन में भी सहायता करता है, और विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए रणनीतिक तथा प्रचालन संबंधी सहायता प्रदान करता है।

एनबीक्यूपी आईएसओ मानकों, कार्य निष्पादन उत्कृष्टता संरचनाओं और अनुकूलित गुणवत्ता हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ सहकार्य में एक रणनीतिक सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। प्रक्रिया सुधार और क्षमता आकलन से लेकर सक्रिय मार्गदर्शन प्रदान करने तक, एनबीक्यूपी संस्थागत दक्षता और सेवा संदाय तंत्रों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा, यह बोर्ड सक्रिय रूप से उन पुरस्कार तंत्रों और मान्यता संरचनाओं का सक्रिय समर्थन करता है जो गुणवत्ता कार्यान्वयन में अनुकरणीय प्रयासों को सम्मानित करते हैं। ये पुरस्कार संगठनों को सर्वोत्तम परिपाटियों को अंगीकार करने, वैश्विक स्तर के मानदंड का अनुसरण करने, और आकांक्षा एवं उत्कृष्टता की संस्कृति का निर्माण करने के लिए प्रेरित करते हैं।

संक्षेप में, एनबीक्यूपी भारत के गुणवत्ता आंदोलन के लिए न केवल एक सुविधा-प्रदाता है, बल्कि शक्तिवर्धक भी है जो जागरूकता बढ़ाने, अंगीकरण को प्रेरित करने, नवाचार को सुगम बनाने, और अंततः विकसित भारत @2047 की ओर राष्ट्र की यात्रा में योगदान देने का काम करता है। अपने एकीकृत प्रयासों के माध्यम से, एनबीक्यूपी अभिशासन, उद्योग और समाज के लिए गुणवत्ता के अर्थ को पुनर्परिभाषित करना जारी रखे हुए है - जिससे गुणवत्ता, राष्ट्रीय कुशल क्षेम की आधारशिला बने।

5.1 ऑनलाइन क्वालिटी समर फनकैंप

भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) के वार्षिक ऑनलाइन क्वालिटी समर फनकैंप का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ – इस पहल का उद्देश्य, अगली पीढ़ी के निर्णयकर्ताओं के बीच गुणवत्ता के सिद्धांतों को पुष्ट करना है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य, बच्चों को छोटी उम्र से ही गुणवत्ता के महत्व से अवगत कराना और उनमें गुणवत्ता के मूल्यों को जगाना है, जिसमें आहार, स्वास्थ्यचर्या, शिक्षा, पर्यावास, पर्यावरण संबंधी देखभाल, खिलौने, और स्थायित्व जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। इन अवधारणाओं पर शुरुआत से ही बल देने के पीछे क्यूसीआई का उद्देश्य भारत के युवाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और गुणवत्ता-उन्मुख मानसिकता विकसित करना है।

फनकैंप की प्रतियोगिताएं किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थीं, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि गुणवत्ता अपनाने की कोई उम्र नहीं होती। इस वर्ष की थीम "सुरक्षा सितारे: गुणवत्ता की आभा से प्रदीप्त" ने प्रतिभागियों को विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और गुणवत्ता के महत्व पर आत्मचिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

ऑनलाइन क्वालिटी समर फनकैंप में विविध प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनकी अभिकल्पना विद्यार्थियों को मनोरंजक और शैक्षणिक तरीके से आकर्षित करने की दृष्टि से की गई थी। इन प्रतियोगिताओं में शामिल हैं:

- निबंध/लेख प्रतियोगिता
- चित्रकला प्रतियोगिता
- गुणवत्ता क्विज़ प्रतियोगिता
- शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता

6 सितंबर, 2024 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान इस रोमांचक यात्रा का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में विद्यार्थियों, अभिभावकों, तथा सम्मानित अतिथियों ने प्रतिभाग किया और युवा विजेताओं का उत्साह बढ़ाया। विजेताओं के नामों की घोषणा एक विशेष वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से की गई। इस दौरान, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार, आईएएस, और डॉ. ललित गभाने (डीजी, एनएससी); श्री चक्रवर्ती टी. कन्नन (एसजी,क्यूसीआई); श्री विपिन सोंधी (अध्यक्ष, एनबीक्यूपी); सुश्री हेमगौरी भंडारी (मुख्य सलाहकार, क्यूसीआई), और डॉ. ए. राज (सीईओ, एनबीक्यूपी) उपस्थित रहे। समारोह के दौरान मुख्य वक्ताओं में - डॉ. ओम प्रकाश, मिशन निदेशक, समग्र शिक्षा, असम; श्री रूपेश माथुर, संयुक्त सचिव, विवेकानंद केंद्र विद्यालय, आंध्र प्रदेश; डॉ. अरुण कुमार, प्रभारी, जिला शिक्षा, गुणवत्ता प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, राजस्थान सरकार; श्रीमती मीना मन्हास, हिंदी अध्यापिका (विद्यालय प्रभारी), राजकीय माध्यमिक विद्यालय, होशियारपुर, पंजाब शामिल रहीं। कार्यक्रम के दौरान विशिष्टजनों की सामूहिक उपस्थिति ने इस आयोजन के महत्व और गुणवत्ता के प्रति जागरूक भावी पीढ़ी के पोषण के लिए क्यूसीआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

ऑनलाइन क्वालिटी समर फ़नकैंप 2024 बच्चों के लिए एक उल्लेखनीय मंच साबित हुआ। इस मंच के माध्यम से बच्चों ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और गुणवत्ता की समझ को मज़ेदार और आकर्षक रूप से प्रदर्शित किया। इसने हमें याद दिलाया कि गुणवत्ता के बीज, जब जल्दी बोए जाते हैं, तो वे जीवनपर्यन्त कायम रहने वाले मूल्यों को विकसित करते हैं और समाज में सार्थक योगदान देते हैं।

राज्य:

13000+ प्रविष्टियां

राज्यवार शीर्ष 3 प्रविष्टियां : हरियाणा (2915), दिल्ली (1750) और पंजाब (1166) - विशेष उल्लेख: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (3)

राज्यवार शीर्ष 3 विजेता: पश्चिम बंगाल (27), हरियाणा (25), चंडीगढ़ (16), दिल्ली (14) और अरुणाचल प्रदेश (12)

कुल 153 विजेता: बालिकाएं (98) और बालक (55)

[विजेताओं में 64% बालिकाएं और 36% बालक शामिल हैं]

इस संस्करण में, शिक्षा मंत्रालय ने दूसरे ऑनलाइन क्वालिटी समर फ़नकैंप को बढ़ावा देने के लिए, अपने संबंधित विभागों को एक परिपत्र जारी करके हमारा समर्थन किया। इसके अलावा, असम, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नगालैंड और मिज़ोरम सहित कई राज्यों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में परिपत्र जारी करके अपना समर्थन प्रदान किया।



एनबीक्यूपी ने क्वालिटी समर फनकैंप के दूसरे संस्करण के लिए ऑनलाइन पुरस्कार समारोह आयोजित किया। 6 सितंबर, 2024 को आयोजित इस वर्चुअल पुरस्कार समारोह में, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार की गरिमामय उपस्थिति रही और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के महानिदेशक डॉ. ललित आर. गभाने ने मुख्य वक्ता के रूप में अपना संबोधन दिया।

5.2 गुणवत्ता जागरूकता कार्यशाला

गुणवत्ता जागरूकता कार्यशाला को इस तरह से अभिकल्पित किया गया है कि वह विद्यार्थियों के लिए आकर्षक और सूचनापरक दोनों हो। इस कार्यशाला का उद्देश्य, युवा शिक्षार्थियों के मन में साफ-सफाई, पर्यावरण संरक्षण, समस्या-समाधान कौशल, साधन/तकनीक, गुणवत्ता से संबंधित मूल बातें, संरक्षा, समानुभूति, और अन्य आवश्यक विषयों के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना जागृत करना है। अब तक, एनडीएमसी स्कूलों, गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों और अन्य सरकारी/निजी स्कूलों में 57 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।



एनबीक्यूपी ने चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट (सीबीटी) के सहकार से गुणवत्ता जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया। ये कार्यशालाएं जून माह में प्रत्येक शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित की गईं।



एनबीक्यूपी ने अप्रैल-मई, 2024 के दौरान, एनडीएमसी स्कूलों, गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, और दिल्ली एनसीआर के अन्य सरकारी स्कूलों में विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया।



5.3 क्वालिटी सेतु

क्वालिटी सेतु, एनबीक्यूपी की एक प्रमुख पहल है, जिसका लक्ष्य भारत में गुणवत्ता से संबंधित सभी प्रश्नों एवं सरोकारों के लिए एक व्यापक और अद्यतन प्लेटफॉर्म बनना है।

क्यूसीआई के बोर्डों एवं प्रभागों और उनके प्रयोक्ताओं के बीच निर्बाध संपर्क-संवाद सुनिश्चित करने के लिए, एनबीक्यूपी ने गुणवत्ता सेतु नामक एक केंद्रीकृत सूचना और पूछताछ प्रणाली की शुरुआत की है। यह प्लेटफॉर्म, क्यूसीआई की सभी पहलों से संबंधित सूचनाओं तक पहुंचने और उनको ट्रैक करने के लिए वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करके प्रयोक्ता अनुभव को समृद्ध बनाता है।

दिनांक 16 अगस्त, 2024 के कार्यालय आदेश संख्या, क्यूसीआई/आदेश/2024/476 के अनुसार, क्वालिटी सेतु ऐप और वेबसाइट को आईटी सेल को हस्तांतरित कर दिया गया है, और ज्ञान हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

5.4 गुजरात गुणवत्ता संकल्प

गुजरात गुणवत्ता संकल्प एक उल्लेखनीय सफलता रही। इसमें गुजरात सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) के विभिन्न बोर्डों और प्रभागों के 43 उत्कृष्ट वक्ताओं और संचालकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए।

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात गुणवत्ता संकल्प का उद्घाटन किया और गुणवत्ता को विकास की आधारशिला बनाने की राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि गुजरात 5जी मॉडल के तहत अपनी प्रगति को तीव्रता दे रहा है और इसमें 'गुणवत्ता' के रूप में एक नए आयाम को जोड़ने का प्रस्ताव उन्होंने किया। माननीय मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि गुणवत्ता को विकसित गुजरात और विकसित भारत का प्रमुख प्रेरक तत्व बनाने में शत प्रतिशत सफलता मिलेगी।

विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्यचर्या, एमएसएमई एवं ई-कॉमर्स, पर्यटन एवं संस्कृति, और जीवन की समग्र गुणवत्ता को शामिल करते हुए, इस कार्यक्रम में नागरिक सशक्तीकरण, स्वास्थ्यचर्या में प्रगति, आर्थिक विकास, और ई-कॉमर्स में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। प्रमुख संगठनों के 600 से अधिक प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ, इस कार्यक्रम को इसकी सुव्यवस्थित संरचना, प्रासंगिक विषय-वस्तु और कुशलतापूर्वक तैयार की गई समय-सारणी लिए व्यापक प्रशंसा मिली।











11 जुलाई, 2024 को अहमदाबाद में, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा गुजरात गुणवत्ता संकल्प का उद्घाटन किया गया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव श्री एस. जे. हैदर (आईएएस); गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार, श्री एस.एस.राठौड़; क्यूसीआई अध्यक्ष श्री जक्षय शाह; क्यूसीआई महासचिव, श्री चक्रवर्ती टी. कन्नन; और क्यूसीआई की मुख्य सलाहकार, श्रीमती हेमगौरी भंडारी की गरिमामय उपस्थिति रही।

5.5 नगालैंड गुणवत्ता संकल्प

नगालैंड गुणवत्ता संकल्प एक शानदार ढंग से सफल हुआ। इसमें नगालैंड सरकार और क्यूसीआई के बोर्डों एवं प्रभागों के 23 वक्ताओं एवं संचालकों ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं।

गुणवत्ता संकल्प नगालैंड के इस कार्यक्रम में, पर्यटन एवं उच्चतर शिक्षा मंत्री श्री तेम्जेन इम्ना अलोंग; मुख्य सचिव, डॉ. जे. आलम (आईएएस); मुख्यमंत्री के सचिव श्री केसोन्यू योमे (आईएएस); और क्यूसीआई के अध्यक्ष श्री जक्षय शाह की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर माननीय मंत्री ने अपने मुख्य संबोधन में इस बात पर बल दिया कि, "नगालैंड के लोग राष्ट्र के लिए गुणवत्ता के प्रतीक बन सकते हैं। उत्कृष्टता और गुणवत्ता का अनुसरण हमारी प्रगति का मूल है।" इस कार्यक्रम ने स्वास्थ्यचर्या, शिक्षा एवं कौशल विकास, एमएसएमई, पर्यटन एवं संस्कृति, परिवहन और लोक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में गुणवत्ता संवर्धन पर, एएचओडी/एचओडी से चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया, जिससे गुणवत्ता-नीत विकास के माध्यम से विकसित भारत 2047 के विज़न के प्रति नगालैंड की प्रतिबद्धता को बल मिला।

कार्यक्रम में नगालैंड सरकार के विभिन्न विभागों सहित प्रतिष्ठित संगठनों के 125 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रतिभागियों ने गंभीर चर्चाएं कीं और अपने बहुमूल्य दृष्टिकोण साझा किए। उनकी प्रारंभिक प्रतिपुष्टि सकारात्मक रही और उन्होंने भारतीय गुणवत्ता परिषद् द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की खूब प्रशंसा की।

इस दौरान विविध कार्यक्षेत्रों से आने वाले वक्ताओं एवं संचालकों ने अपने ज्ञान और अनुभव को साझा किया और एक सहकार्यात्मक वातावरण का निर्माण किया, जहां नवीन विचारों और सर्वोत्तम परिपाटियों का आदान-प्रदान हुआ। इस सहकार्यात्मक भावना ने नगालैंड की अनूठी चुनौतियों के समाधान और अवसरों की तलाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो अंततः इस क्षेत्र के विकास और वृद्धि में योगदान करेंगे।

समग्र रूप से, नगालैंड गुणवत्ता संकल्प ने न केवल विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि इस क्षेत्र में उत्कृष्टता और निरंतर सुधार लाने के लिए हितधारकों की प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ किया।



नगालैंड गुणवत्ता संकल्प, 27 फरवरी, 2025 कोहिमा, नगालैंड



कार्यक्रम का उद्घाटन श्री तेम्जेन इम्ना अलोंग, पर्यटन एवं उच्चतर शिक्षा मंत्री, नगालैंड सरकार द्वारा किया गया।



श्री जक्षय शाह, अध्यक्ष, क्यूसीआई



श्री केसोन्यू योमे (आईएएस), आयुक्त एवं माननीय मुख्यमंत्री के सचिव



डॉ. जे. आलम (आईएएस), मुख्य सचिव, नगालैंड सरकार



श्री चक्रवर्ती टी. कन्नन, महासचिव, क्यूसीआई



श्रीमती हेमगौरी भंडारी, मुख्य सलाहकार, क्यूसीआई



5.6 पिछले गुणवत्ता संकल्प पर अनुवर्ती कार्रवाई

गुणवत्ता संकल्प पहल के पश्चात, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ जुड़ने के हमारे प्रयासों के क्रम में, राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड (एनबीक्यूपी) ने असम गुणवत्ता संकल्प के पश्चात, असम के मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत की गई सिफारिशों के संबंध में असम सरकार के साथ संवाद स्थापित किया। एनबीक्यूपी की टीम ने असम में व्यक्तिगत रूप से बैठकें आयोजित कीं और तत्पश्चात असम सरकार के संबंधित अधिकारियों और क्यूसीआई के संबंधित बोर्डों/प्रभागों की वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सदस्यों के बीच कई बार ऑनलाइन बैठकें आयोजित करने में मदद कीं। ये चर्चाएं निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित रहीं:

1. विनिर्माण एवं सेवाएं

2. शिक्षा एवं कौशल विकास, और 3. पर्यटन

5.7 क्वालिटी भारत प्रतिज्ञा

क्वालिटी भारत प्रतिज्ञा का लक्ष्य, गुणवत्ता परिपाटियों को अंगीकार करना और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है। यह प्रतिबद्धता हिंदी वाक्यांश "गुणवत्ता अपनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे" में निहित है, जिसका अर्थ है "हम गुणवत्ता को अंगीकार करेंगे, और हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे।" यह प्रतिज्ञा निम्नलिखित प्रमुख आशयों पर बल देती है:

- गुणवत्ता के प्रति समर्पण
- राष्ट्रीय विकास को प्रेरित करना
- जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई करना
- सामूहिक जिम्मेदारी

क्वालिटी भारत प्रतिज्ञा, क्यूसीआई की वेबसाइट पर 29 अगस्त, 2024 को आधिकारिक रूप से आरंभ की गई थी। इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए, "MyGov" के साथ एक सफल साझेदारी स्थापित की गई थी, जिससे अब तक, MyGov पृष्ठ पर 29,000 से अधिक नागरिकों ने क्वालिटी भारत प्रतिज्ञा ग्रहण की है।



5.8 राज्य संपर्क

एनबीक्यूपी सक्रियता से साझेदारियों को पुष्ट करता आ रहा है और इसके लिए दिल्ली स्थित राज्य सरकारों के नोडल कार्यालयों, जिनमें रेजिडेंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर शामिल हैं, के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ जुड़कर पूरे भारत में अवसरों की तलाश करता रहा है।

एनबीक्यूपी ने मिज़ोरम, सिक्किम, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और नगालैंड के स्थानिक आयुक्तों के साथ सार्थक संबंध स्थापित किए हैं, जिससे इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ रणनीतिक सहयोग और प्रगति का आधार तैयार हुआ है। इसके अलावा, इस बोर्ड ने पूरे देश में उन्नत गुणवत्ता संबंधी पहलों को आगे बढ़ाने और विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ आपसी सहयोग के अवसर तलाशने के लिए संवाद शुरू किए हैं।



मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन के साथ बैठक







5.9 संजीवनी

'संजीवनी' मृतप्राय कला रूपों को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार की गई एक पहल है। इसके तहत, एक सुविकसित अवधारणा और प्रस्तावना के साथ, एक समर्पित आंतरिक समिति गठित की गई है, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, राष्ट्रीय संग्रहालय, अखिल भारतीय शिल्पकार और कलाकार संघ, वस्त्र क्षेत्र कौशल परिषद्, बुनकर सेवा केंद्र, और अन्य जैसे प्रतिष्ठित संगठनों से सदस्यों को शामिल किया गया है। एनबीक्यूपी के सीईओ और समिति के सदस्यों के साथ आयोजित की गईं आरंभिक बैठकें काफी सफल रहीं, जिनमें विचारार्थ विषय का मसौदा तैयार करने और आधिकारिक रूप से सदस्यों को समिति में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

'संजीवनी' उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। इस समिति में प्रतिष्ठित संगठनों के सदस्यों को सफलतापूर्वक शामिल कर लिया गया है और समिति ने, अपनी उद्घाटन बैठक के साथ-साथ कई दौर की चर्चाएं भी आयोजित की हैं। इन बैठकों में मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के कला रूपों के लिए मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए हैं। "नौटंकी" को पायलट अध्ययन के लिए चुना गया है, और इस कला रूप के मूल्यांकन के लिए,, क्षेत्र अनुसंधान एवं भ्रमण सक्रिय रूप से चल रहे हैं। ये प्रयास, सहकार्य और नवाचार के माध्यम से भारत के मृतप्राय कलारूपों को पुनर्जीवित करने के संजीवनी के लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रगति को दर्शाते हैं।





संजीवनी – गुणवत्तापूर्ण भारत मिशन के तहत एक पहल: सदस्यों के साथ अधिकार प्राप्त समिति की पहली बैठक

5.10 गुणवत्ता पखवाड़ा

'गुणवत्ता से सशक्त भारत, विकसित भारत' थीम के साथ, राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड (एनबीक्यूपी) को प्रत्येक वर्ष 14 से 28 नवंबर तक गुणवत्ता पखवाड़ा मनाने की घोषणा करते हुए गर्व का अनुभव होता है। दो-सप्ताह तक चलने वाली यह पहल, जीवन के विभिन्न आयामों, व्यक्तिगत कार्यव्यवहार से लेकर संगठनात्मक मानकों तक में गुणवत्ता के महत्व की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित की गई है। गुणवत्ता की संस्कृति को प्रोत्साहित करके, हमारा लक्ष्य एक मजबूत और अधिक दक्ष राष्ट्र का निर्माण करना है, जो उद्योगों और विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता के उच्चतम मापदंडों को बनाए रखे।

इस पहल के एक हिस्से के रूप में, हमने व्यक्तियों और संगठनों को अपने साथ जोड़ने के लिए, रोमांचक प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला शुरू की है। इसके तहत निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं :

- क्रिएटिव बैनर मेकिंग प्रतियोगिता
- गुणवत्ता सुधार पहलों का प्रदर्शन
- गुणवत्ता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
- संगठनों के भीतर गुणवत्ता संस्कृति की सराहना

नवंबर 2024 में, 15 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए, बोर्ड ने एक वेब पोर्टल आरंभ किया। इसके माध्यम से हमें 1,201 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जो पिछले वर्ष से अधिक थीं। गुणवत्ता पखवाड़ा के विजेताओं की घोषणा की जा चुकी है।



5.11 क्वालिटी टाइम्स

क्वालिटी टाइम्स, 5 से 7 मिनट का एक त्रैमासिक वीडियो कैप्सूल है, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता के संदेश को लेकर जनसामान्य और संबंधित हितधारकों तक पहुंचना है। इसमें मुख्यतः, हम क्वालिटी न्यूज़मेकर और स्पॉटलाइट के तहत, गुणवत्ता पर आधारित छोटी-छोटी जानकारी को विस्तार से कवर करते हैं। अब तक इसके 5 संस्करण जारी किए जा चुके हैं, और पांचवें संस्करण में हमने पाबी डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक श्रीमती पाबीबेन रबारी को कवर किया है, जिसका शुभारंभ 11 जुलाई को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित, गुजरात गुणवत्ता संकल्प के दौरान किया गया था।

टीम ने विभिन्न बोर्डों और प्रभागों के लिए डिज़ाइन से संबंधित कार्यों को पूरा किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि समस्त दृश्य सामग्री हमारे गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो।

इस टीम ने, क्यूसीआई और उसके बोर्डों एवं प्रभागों की सोशल मीडिया उपस्थिति को भी प्रबंधित किया और विविध दर्शकों के साथ प्रभावी तरीके से जुड़कर, गुणवत्ता के संदेश को प्रचारित किया।



क्वालिटी टाइम्स प्रसंग 6 के लिए, न्यूज़मेकर शूट: मनु भाकर (ओलंपिक पदक विजेता) और श्री कलिकेश नारायण सिंह देव (अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ) के साथ

5.12 क्वालिटी भारत प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड (एनबीक्यूपी) ने क्वालिटी भारत प्रकोष्ठ (क्यूबीसी) की शुरुआत की है। यह एक अग्रगामी पहल है जिसे विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच गुणवत्ता की संस्कृति विकसित करने, उन्हें गुणवत्तापूर्ण साधनों/तकनीकों से सशक्त बनाने, सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने, और समानुभूति का पोषण करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। क्यूबीसी का प्रयास देश भर में प्रशिक्षणों, पूर्व और पश्चात के सुव्यवस्थित आकलनों के माध्यम से प्रमुख गुणवत्ता सिद्धांतों की समझ बढ़ाने और क्षमता निर्माण करने का है। यह पहल विकसित भारत 2047 के विज़न का समर्थन करती है, उत्कृष्टता के साथ नेतृत्व करने के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाती है।

मॉड्यूल की संकल्पना तैयार करने और कार्यक्रम कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी की सहायता ली गई।

अपने पायलट फेज में, क्यूसीबी को उत्तर और पश्चिम क्षेत्र के पांच स्कूलों में लागू किया जा रहा है: जिनमें डीएवी पब्लिक स्कूल (साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश), हिंदू कन्या विद्यालय (सोनीपत, हरियाणा), आदिनाथ पब्लिक स्कूल (अलवर, राजस्थान), द मान स्कूल (पश्चिम दिल्ली), और एयर फ़ोर्स स्कूल (जम्मू) शामिल हैं।

कुल 480 विद्यार्थियों और शिक्षकों को भावी गुणवत्ता अग्रदूतों के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो निरंतर सुधार को बढ़ावा देने के लिए, अपने साथियों के बीच गुणवत्ता सिद्धांतों तथा गुणवत्ता संबंधी साधनों और तकनीकों का सक्रिय रूप से प्रचार- प्रसार करेंगे।

2 अप्रैल, 2025 को एयर फ़ोर्स स्कूल, जम्मू में एक शानदार समापन समारोह के साथ क्वालिटी भारत प्रकोष्ठ (क्यूबीसी) का प्रथम चरण संपन्न हुआ जो विद्यार्थियों की गुणवत्ता-प्रेरित मानसिकता की ओर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

इस समारोह में, श्री विपिन सोंधी (अध्यक्ष, एनबीक्यूपी-क्यूसीआई), डॉ. ए. राज (सीईओ, एनबीक्यूपी-क्यूसीआई), एयर कमोडोर सागर सिंह रावत वीएम (चेयरमैन), श्रीमती शुचि गुप्ता (प्रधानाचार्य) और श्री रमन अरोड़ा (प्रधानाध्यापक) सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

समारोह के दौरान, श्री सोंधी ने एक सम्मोहक कहानी साझा की, और बताया कि कैसे गुणवत्ता केवल एक अवधारणा नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। विद्यार्थियों ने भी उनकी बात की पुष्टि की, और बताया कि कैसे क्यूसीबी ने, गुणवत्ता के बारे में उनके दृष्टिकोण को "सिर्फ़ उत्पाद" तक से परिवर्तित करके अब "दिन-प्रतिदिन के कार्यों" में शामिल कर दिया है। घर पर 5S लागू करने से लेकर, परीक्षा के तनाव को प्रबंधित करने के लिए पीडीसीए का इस्तेमाल करने तक—उनकी कहानियां प्रेरणादायक और वास्तविक थीं। इस दौरान डॉ. राज ने हमारे दैनिक जीवन में भी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के महत्व को समझाया।



डीएवी पब्लिक स्कूल, साहिबाबाद में प्रथम 'क्वालिटी भारत प्रकोष्ठ' का शुभारंभ

22 जनवरी, 2025, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश



दिल्ली के मान स्कूल में 'क्वालिटी भारत प्रकोष्ठ' का शुभारंभ

3 फरवरी, 2025, नई दिल्ली



आदिनाथ पब्लिक स्कूल में तीसरे 'क्वालिटी भारत प्रकोष्ठ' का शुभारंभ

10 फ़रवरी, 2025, अलवर, राजस्थान



हिंदू कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चौथे 'क्वालिटी भारत प्रकोष्ठ' का शुभारंभ

19 फरवरी, 2025, सोनीपत, हरियाणा



वायु सेना विद्यालय, जम्मू में पांचवें 'क्वालिटी भारत प्रकोष्ठ' का शुभारंभ

17 मार्च, 2025, जम्मू और कश्मीर

5.13 गुणवत्ता मंथन

गुणवत्ता मंथन क्यूसीआई द्वारा शुरू की गई एक रणनीतिक पहल है, जिसका लक्ष्य हितधारकों से फीडबैक प्राप्त करना और सहकार्य एवं कार्रवाई योग्य समाधानों के माध्यम से गुणवत्ता की संस्कृति को पुष्ट करना है। हितधारकों की विशेषज्ञता और ग्राहक समर्थन का लाभ उठाकर, यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर सुधार लाने का प्रयास करती है।

हितधारकों को अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने और सर्वोत्तम परिपाटियों को अंगीकार करने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करते हुए क्यूसीआई, इस सामूहिक ज्ञान का उपयोग, रणनीतिक नियोजन को बेहतर बनाने, गुणवत्तापूर्ण पहलों को आगे बढ़ाने और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए करती है। इन समन्वित प्रयासों के माध्यम से, गुणवत्ता मंथन का लक्ष्य, उद्योग मानकों में सुधार करना, गुणवत्ता परिपाटियों को मजबूत करना, और समग्र परिणामों में सुधार करना है।

एनडीआईई के लिए पहला मंथन 13 फरवरी, 2025 को आयोजित किया गया था। 31 मार्च, 2025 तक, हमने पीएडी प्रभाग (नई दिल्ली), एनएबीसीबी (नई दिल्ली), एनएबीएच (नई दिल्ली) और एनडीआईई (चेन्नै) के लिए चार गुणवत्ता मंथन आयोजित किए हैं। इसी प्रकार, आगामी वित्तीय वर्ष में भी और अधिक हितधारकों को शामिल करने तथा गहन सहकार्य को बढ़ावा देने की हमारी योजना है।







5.14 गुणवत्ता समृद्धि

गुणवत्ता समृद्धि उद्योग संपर्क-संवाद से संबंधित एक पहल है, जिसे क्यूसीआई की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर व्यावसायिक उत्कृष्टता एवं वैश्विक स्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए अभिकल्पित किया गया है। समृद्धि का प्राथमिक लक्ष्य भारतीय गुणवत्ता मानकों को पुष्ट करना, प्रमाणन का बोझ कम करना, और निर्यात के अवसरों का सृजन करना है, जिससे एक मज़बूत और वैश्विक प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिले। प्रमाणन में सहायता, गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रमों, और उद्योग सहकार्य जैसे लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से समृद्धि, एमएसएमई और बड़े उद्यमों के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करती है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करती है।

चयनित क्षेत्र

- इलेक्ट्रॉनिक्स
- व्हाइट गुड्स
- फार्मास्यूटिकल्स

4 उद्योगों के साथ संपर्क-संवाद स्थापित किया गया

1. हायर: हायर और क्यूसीआई के उच्च अधिकारियों के बीच 20 फरवरी, 2025 को बैठक आयोजित की गई।

क) प्रारंभिक बैठक में हुई चर्चा में निम्नलिखित बिंदु शामिल थे:

- **एनएबीएल:** यह चर्चा, एनएबीएल की सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति, हायर की आपूर्ति- श्रृंखला से

जुड़े वेंडरों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के महत्व, और गुणवत्ता पहलों में वेंडरों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की रणनीतियों पर केंद्रित थी।

- एनडीआईई: चर्चा के मुख्य बिंदु में, ज़ेड (ज़ीरो डिफ़ेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट) और एमसीएलएस (एमएसएमई स्पर्धात्मकता लीन स्कीम) प्रमाणन से परिचित कराना, हायर और उसकी आपूर्ति-श्रृंखला के बीच संभावित सामंजस्य की खोज करना, और हायर के वेंडर पारिस्थितिकी तंत्र में गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने के तरीकों की पहचान करना शामिल था।

- एनएबीसीबी: यह चर्चा, हायर की प्रमाणन संबंधी अपेक्षाओं, मानकों के अनुपालन में उद्योग के समक्ष आने वाली चुनौतियों, और एक सुचारु एवं लागत-प्रभावी मानकीकरण प्रक्रिया की आवश्यकता पर केंद्रित थी। एनएबीसीबी ने, हायर के पारिस्थितिकी तंत्र के मानचित्रण और वेंडरों को प्रासंगिक प्रमाणन प्राप्त करने से संबंधित मार्गदर्शन के लिए एक पायलट परियोजना का प्रस्ताव रखा।

ख) 16 अप्रैल, 2025 को हायर प्लांट, नोएडा में एक अनुवर्ती बैठक और कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

ग) हायर के साथ आगे सहकार्य और जुड़ाव, चर्चा के आधार पर व्यवस्थित किया जाना है।

5.15 गुणवत्ता यात्रा

गुणवत्ता यात्रा एक पहल है, जो स्वास्थ्यचर्या की गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित थी और अब विनिर्माण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। यह लघु और वृहत् स्वास्थ्य सेवा संगठनों (एचसीओ), विनिर्माण संघों और इकाइयों के बीच, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में, एनएबीएच, एनएबीसीबी और एनडीआईई के मानकों को बढ़ावा देती है। इस यात्रा का उद्देश्य, लक्षित क्षमता निर्माण कार्यशालाओं और सशक्त समर्थन प्रणालियों के माध्यम से, पेशेवरों को इन महत्वपूर्ण मानकों को प्राप्त करने के लिए जरूरी ज्ञान और साधनों से लैस करना है। स्वास्थ्यचर्या और विनिर्माण परिपाटियों को उन्नत करके और सुगम्यता को बढ़ावा देकर, यह यात्रा अल्प-सेवित क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करने में क्यूसीआई की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, हमने एनएबीएच, एनएबीएल, और एनडीआईई प्रत्यायन और प्रमाणन से संबंधित प्रक्रिया और लाभों के बारे में संबंधित हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए पूरे भारत में 48 गुणवत्ता यात्राएं पूरी कर ली हैं।

प्रक्षेत्रवार और बोर्डवार सिंहावलोकन – संपन्न गुणवत्ता यात्रा

- उत्तर: 10 यात्राएं संपन्न
- पूर्व: 06 यात्राएं संपन्न
- दक्षिण: 18 यात्राएं संपन्न
- पश्चिम: 14 यात्राएं संपन्न

यात्रा में शामिल किए गए संघों की संख्या: 30+

- आईएमए - गुजरात (अहमदाबाद और भावनगर), केरल (कोच्चि), हरियाणा (रेवाड़ी), तेलंगाना (हैदराबाद), और तमिलनाडु (कोयम्बतूर)
- एएचपीआई
- आईडीए - तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल
- एफटीसीसीआई
- डब्ल्यूएसीआईए (वासिया)
- एनआई - एमएसएमई
- आईएएमएसएमई ऑफ इंडिया
- अन्य



गुणवत्ता यात्रा - कोच्चि, दक्षिण भाग



भावनगर, पश्चिम भाग



रेवाड़ी, उत्तर भाग



इम्फाल, पूर्व भाग

5.16 ईईपीसी इंडिया क्वालिटी अवार्ड - चौथा संस्करण

ईईपीसी इंडिया क्वालिटी अवार्ड ने इंजीनियरिंग उद्योग में गुणवत्ता परिपाटियों की उत्कृष्टता को मान्यता देने और उन्हें पुरस्कृत करने की अपनी यात्रा जारी रखी है। इसके लिए एनबीक्यूपी/क्यूसीआई द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की गई। इस पुरस्कार प्रक्रिया में चार प्रमुख चरण शामिल थे – दस्तावेज आकलन, प्रस्तुति, ऑनसाइट आकलन, और ईईपीसी इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष सारांश प्रस्तुति।

इस कठोर मूल्यांकन से निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगियों का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सका:

1. केंद्रीय संयुक्त उद्यम/सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लिए ईईपीसी इंडिया गुणवत्ता पुरस्कार
2. बड़े उद्यमों के लिए ईईपीसी इंडिया गुणवत्ता पुरस्कार
3. मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए ईईपीसी इंडिया गुणवत्ता पुरस्कार
4. एसएमई इकाइयों के लिए ईईपीसी इंडिया गुणवत्ता पुरस्कार

पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा के साथ यह चक्र पूरा हुआ। विजेताओं को 15 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 54वें राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार एवं गुणवत्ता पुरस्कार समारोह के दौरान सम्मानित किया गया।

ये पुरस्कार, माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद; वाणिज्य विभाग, भारत सरकार में संयुक्त सचिव, श्री विमल आनंद; ईईपीसी इंडिया के कार्यकारी निदेशक एवं सचिव श्री अधीप मित्रा; ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन श्री पंकज चड्ढा; क्षेत्रीय चेयरमैन (उत्तर क्षेत्र) श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल द्वारा प्रदान किए गए।





5.17 ईईपीसी इंडिया ग्रीन अवार्ड – प्रथम संस्करण

ईईपीसी इंडिया ग्रीन अवार्ड, इंजीनियरिंग उद्योग में स्थायित्वपूर्ण परिपाटियों को मान्यता देने और उन्हें पुरस्कृत करने की एक प्रमुख पहल है, इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान की गई। इस पुरस्कार प्रक्रिया में तीन प्रमुख चरण शामिल थे: दस्तावेज़ आकलन, ऑनसाइट आकलन, और ईईपीसी इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष सारांश प्रस्तुति।

इस कठोर मूल्यांकन से निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगियों का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सका:

1. केंद्रीय संयुक्त उद्यम/सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ईईपीसी इंडिया ग्रीन अवार्ड
2. बड़े उद्यमों के लिए ईईपीसी इंडिया ग्रीन अवार्ड
3. मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए ईईपीसी इंडिया ग्रीन अवार्ड
4. एसएमई इकाइयों के लिए ईईपीसी इंडिया ग्रीन अवार्ड

पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा के साथ यह चक्र पूरा हुआ। विजेताओं को 27 नवंबर, 2024 को चेन्नै में आयोजित बारहवें आईईएसएस उद्घाटन एवं हरित पुरस्कार समारोह के दौरान सम्मानित किया गया।

ये पुरस्कार डॉ. अतुल आनंद (आईएएस), प्रमुख सचिव, एमएसएमई विभाग, तमिलनाडु सरकार; श्री विमल आनंद, (आईआरएस), संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार; श्री आकाश शाह, वाइस चेयरमैन (ईईपीसी इंडिया);

श्री पंकज चड्ढा, चेयरमैन (ईईपीसी इंडिया); श्री अधीप मित्रा, कार्यकारी निदेशक (ईईपीसी इंडिया) द्वारा प्रदान किए गए।



5.18 निधि - आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस

क्यूसीआई ने पर्यटन मंत्रालय के लिए 'निधि' पोर्टल विकसित किया, जो भारत में पर्यटन व्यवसायों को सशक्त बनाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में की गई एक पहल है। यह एक डेटाबेस है जो पर्यटन उद्योग के लिए अवसरों का द्वार खोलने वाला उपक्रम बन सकता है। निधि पोर्टल पर पंजीकृत पर्यटन इकाई को विभिन्न सेवाओं एवं लाभों का इलेक्ट्रॉनिक संदाय सुनिश्चित होता है। यह पोर्टल व्यापार को सुगम बनाने के लिए उद्योग से जुड़े सभी संगठनों को नई संकल्पनाएं गढ़ने, सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा करने और सरकार से जुड़ने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।

क्यूसीआई का राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड, मंत्रालय को पोर्टल के प्रबंधन, आईटी प्रचालनों में मदद करने और हितधारकों के प्रश्नों के समाधान के लिए हेल्पडेस्क के संचालन में सहायता कर रहा है। यह व्यापक प्रणाली, पंजीकरण से लेकर ऑनसाइट/रिमोट आकलनों को प्रदर्शित करने तक की सभी प्रक्रियाओं को मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके डिजिटल बनाती है और हितधारकों के साथ एपीआई एकीकरण की पेशकश करती है। यह प्रणाली अब पूरी तरह से प्रचालन में है और अब इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म (https://nidhi.tourism.gov.in/) के माध्यम से सभी गुणवत्ता प्रमाणन जारी किए जाते हैं।

5.19 सरकारी विभागों में आईएसओ मानक कार्यान्वयन

क्यूसीआई/एनबीक्यूपी पूरे देश में मंत्रालयों और सरकारी विभागों (केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर) को सहायता प्रदान कर आईएसओ मानकों को अंगीकार करने और प्रमाणन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों में सुधार सुनिश्चित हो रहा है। एनबीक्यूपी के प्रयास, सार्वजनिक संस्थानों में अभिशासन, जवाबदेही और प्रचालन दक्षता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं।

कार्यान्वयन गतिविधियां हमारे पैनलबद्ध तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से चरणबद्ध रूप में संचालित की गई थीं। इन चरणों में शामिल हैं:

चरण 1: जागरूकता प्रशिक्षण

चरण 2: अंतराल विश्लेषण

चरण 3: प्रलेखन

चरण 4: आंतरिक संपरीक्षक प्रशिक्षण

चरण 5: आंतरिक संपरीक्षा और प्रबंधन समीक्षा

क) समग्र शिक्षा असम, असम सरकार के मिशन निदेशक कार्यालय में, आईएसओ 9001:2015 कार्यान्वयन गतिविधियां संपन्न हुईं

एनबीक्यूपी ने मिशन निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा असम को आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली मानकों की अपेक्षाओं के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान किया और प्रमाणन संपरीक्षा आयोजित करने के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायित प्रमाणन निकाय को शामिल करने में सहायता प्रदान की। समग्र शिक्षा असम का मिशन निदेशक कार्यालय प्रमाणन प्राप्त करने में सफल रहा। यह उपलब्धि शिक्षा प्रबंधन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के समर्पण को दर्शाती है। प्रतिष्ठित प्रमाणन समारोह में असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिभाग किया, उन्होंने संस्था की ओर से प्रमाणपत्र प्राप्त किया। यह मान्यता न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति असम की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, बल्कि भारत के अन्य राज्यों के लिए अपनी शैक्षिक संरचना को मजबूत करने के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है।







ख) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद में आईएसओ 9001:2015 कार्यान्वयन गतिविधियां प्रगति पर हैं

एनबीक्यूपी ने राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद को आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों की अपेक्षाओं के कार्यान्वयन में अपना सहयोग प्रदान किया। कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां प्रगति पर हैं।







5.20 'मित्र' पहल

एनएबीएच मानकों को अंगीकार करने के लिए प्रोत्साहित करके और विशेषकर टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लघु स्वास्थ्यचर्या संगठनों (एसएचसीओ) द्वारा, एनएबीएच प्रवेश स्तरीय प्रमाणन (या प्रत्यायन) प्राप्त किए जाने में सहयोग प्रदान करके स्वास्थ्यचर्या प्रणाली में क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, एनबीक्यूपी ने "मित्र" पहल (भौतिक मोड) इस पहल की घोषणा राष्ट्रीय रोगी संरक्षा सम्मेलन में क्यू सी आई के अध्यक्ष द्वारा के गई थी।, के तहत गुजरात राज्य में एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) के साथ एक पायलट परियोजना शुरू की है। इसके तहत, आस-पास के क्षेत्रों के गैरप्रमाणित/गैरप्रत्यायित एसएचसीओ के लिए वडोदरा और सूरत में दो कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।



मित्र पहल के तहत गुणवत्ता यात्रा:

गुणवत्ता यात्रा में सहयोग करने पर चर्चा के लिए अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक

24 अक्टूबर, 2024 अहमदाबाद, गुजरात



मित्र पहल के तहत गुणवत्ता यात्रा:

एएचपीआई गुजरात के अध्यक्ष, डॉ. नीरज लाल और उनकी टीम के साथ बैठक

अहमदाबाद, गुजरात, 24 अक्टूबर, 2024





मित्र पहल के तहत गुणवत्ता यात्रा:

गुणवत्ता यात्रा में सहयोग करने पर चर्चा के लिए, आईएमए - गुजरात राज्य शाखा के अधिकारियों के साथ बैठक

अहमदाबाद, गुजरात, 20 नवंबर, 2024

5.21 कार्यक्रम

क्यूसीआई सक्रिय रूप से कार्यक्रमों और क्यूसीआई - संचालित सत्रों (क्यूपीएस) का आयोजन करती है, ताकि हितधारकों के एक व्यापक समूह को जोड़ा जा सके, जिससे प्रतिस्पर्धी वैश्विक वातावरण में उत्थानशीलता के लिए आवश्यक गुणवत्ता परिपाटियों की गहरी समझ विकसित हो और उसे व्यापक रूप से अंगीकार किए जाने को प्रोत्साहन मिले। वित्त वर्ष 2024-25 में, एनबीक्यूपी ने 28 उल्लेखनीय कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिनमें गुणवत्ता संकल्प, गुणवत्ता गुरुकुल दीक्षांत समारोह और वार्षिक दिवस, और एनएबीएच रोगी संरक्षा 2025 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनबीक्यूपी ने भारत भर के विभिन्न उद्योग संघों और निकायों के साथ मिलकर 21 क्यूसीआई -संचालित सत्रों का समन्वय किया। इन सत्रों ने स्वास्थ्य, एमएसएमई, खाद्य, कृषि, ड्रोन और वस्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्यूसीआई के बोर्डों और प्रभागों की स्कीमों एवं गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया।



एनबीक्यूपी ने 21 मार्च, 2024 को अंबेडकर भवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित 74वीं क्यूसीआई शासी निकाय बैठक के आयोजन में सहायता की



क्यूसीआई के अध्यक्ष श्री जक्षय शाह, हिंदी भवन, नई दिल्ली में द्वितीय बैच के दीक्षांत समारोह के दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए



12 अप्रैल, 2024 से आरंभ हुआ गुणवत्ता गुरुकुल का तीसरा बैच



विभिन्न उद्योगों में प्रयोगशाला प्रचालनों से संबंधित गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनएबीएल का पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) से सहकार



दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्य अतिथि श्री अनुराग जैन, सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ तीसरे बैच के विद्यार्थी



राष्ट्र के भिन्न-भिन्न हिस्सों से चयनित किए गए, गुणवत्ता गुरुकुल के विद्यार्थियों का चौथा बैच



गुणवत्ता गुरुकुल के चौथे बैच के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए, विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार, मुख्य अतिथि श्री हेमांग प्रियवदन जानी



गुणवत्ता गुरुकुल के छठे बैच के अभिमुखीकरण कार्यक्रम के आयोजन में एनबीक्यूपी ने सहायता की



अभिमुखीकरण कार्यक्रम के दौरान, गुणवत्ता गुरुकुल के सबसे बड़े, पांचवें बैच के विद्यार्थीगण



वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए क्यूसीआई के अध्यक्ष, श्री जक्षय शाह। उन्होंने पिछले वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए गुणवत्ता गुरुकुल टीम को हार्दिक बधाई दी।



एनबीक्यूपी द्वारा समर्थित एनएबीएच के रोगी संरक्षा दिवस, जो सुरक्षित स्वास्थ्य अवसंरचना पर जोर देता है और बारह नए मानक पेश करता है, के अवसर पर स्वास्थ्यचर्या पेशेवरों को सम्मानित करते हुए



एनबीक्यूपी ने 30 नवंबर, 2024 को दिल्ली-एनसीआर के आकलनकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में एनएबीएच की सहायता की।



दीक्षांत समारोह के दौरान, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव एवं मुख्य अतिथि, श्री के. श्रीनिवास का अभिनंदन



क्यूसीआई के अध्यक्ष श्री जक्षय शाह और क्यूसीआई के महासचिव श्री चक्रवर्ती टी कन्नन, नई दिल्ली के प्रतिष्ठित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित नए कार्यालय -Iक्यूसीआई में पूजा करते हुए।



एनबीक्यूपी ने डीआईएसएचए के तहत दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने में एनडीआईई की सहायता की, यह ज़ेड आकलन मॉडलों को सरल और मजबूत बनाने की एक पहल है।



गुणवत्ता गुरुकुल की मानव संसाधन और प्रचालन प्रमुख सुश्री अर्पिता सेन ने क्यूसीआई-संचालित चित्ताकर्षक सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें गुणवत्ता गुरुकुल की यात्रा, प्रक्रिया और लाभों पर प्रकाश डाला गया।



अपने दीक्षांत समारोह के दौरान गुणवत्ता गुरुकुल का छठा और सातवाँ बैच



चौथे गुड एयर समिट 2024 के दौरान पीएडीडी-क्यूसीआई के श्री सी.एस. शर्मा का अभिनंदन।



एनबीक्यूपी ने नई दिल्ली में क्यूसीआई के शासी निकाय की 78वीं बैठक के आयोजन में सहायता की



एनएबीसीबी के सीईओ श्री राजेश माहेश्वरी ने "डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से प्रगति को गति प्रदान करना" विषय पर केंद्रित क्यूसीआई संचालित सत्र के दौरान, मुख्य वक्ता के रूप में संबोधन दिया।



"स्वास्थ्यचर्या को कुशल, प्रभावी, किफायती और न्यायसंगत बनाना" विषय पर संबोधित करते हुए, एनएबीएच-क्यूसीआई के सीईओ डॉ. अतुल मोहन कोचर



एनएबीईटी, क्यूसीआई में एमएसएमई लीन प्रभाग की निदेशक एवं प्रमुख डॉ.आराधना चोपड़ा ने "एमसीएलएस (लीन) स्कीम का परिवर्तनकारी प्रभाव" विषयक क्यूसीआई-संचालित सत्र का नेतृत्व किया।



एनएबीसीबी के संयुक्त निदेशक श्री अजय शर्मा ने क्यूसीआई द्वारा संचालित सत्र में अग्नि और जीवन सुरक्षा क्षेत्र में क्यूसीआई की महत्वपूर्ण भूमिका पर बहुमूल्य जानकारी साझा की।



क्यूसीआई ने कौशल विकास पहलों जो जीआईएफटी आईएफएससी के प्रतिभा पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती हैं, पर सहकार्य के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



पीपीआईडी प्रमुख, श्री सुब्रतो घोष "प्रतिभा का सशक्तीकरण और वैश्विक उत्कृष्टता का अंगीकरण: वैश्विक सफलता के लिए कौशलों में परिवर्तन" विषय पर क्यूसीआई द्वारा संचालित सत्र में गणमान्य अतिथियों के मध्य विराजमान



एनबीक्यूपी ने आईएसबीटीआई के 49वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए एनएबीएच की सहायता की।



एनएबीएच-क्यूसीआई के सीईओ डॉ. अतुल मोहन कोचर और एनएबीएल-क्यूसीआई के निदेशक श्री पंकज जौहरी ने भारत में गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।



एनबीक्यूपी-क्यूसीआई में सलाहकार, श्री सी. वेणुगोपाल ने प्राकृतिक रंगाई और हथकरघा उत्पादों से संबंधित क्यूसीआई संचालित सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में विशेष व्याख्यान दिया।



एनएबीएच का प्रतिनिधित्व करते हुए, उप निदेशक डॉ. कुमुदिता तलवार ने क्यूसीआई-संचालित सत्र के दौरान दंत चिकित्सालयों के लिए प्रवेश-स्तरीय प्रमाणन कार्यक्रम की शुरुआत की।



"प्रत्यायन और प्रमाणन के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में एनएबीएल का योगदान" विषय पर क्यूसीआई संचालित सत्र में व्याख्यान देती हुई डॉ.भूमि राज्यगुरु



एनएबीएल-क्यूसीआई की डॉ. भूमि, और ज़ेड आकलनकर्ता श्री समीप ने क्यूसीआई-संचालित सत्र के दौरान, एमएसएमई को एनएबीएल, ज़ेड और लीन कार्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्ता उत्कृष्टता के अंगीकरण के लिए प्रोत्साहित किया।



एनएबीएच- क्यूसीआई की प्रत्यायन अधिकारी डॉ. मामोनी मैती ने, भारत भर में स्वास्थ्यचर्या की गुणवत्ता और रोगी संरक्षा को बढ़ावा देने में एनएबीएच की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।



पहले एएचपीआईकॉन एनई II के आयोजकों द्वारा एनएबीए-क्यूसीआई में प्रत्यायन अधिकारी, डॉ. मामोनी मैती का अभिनंदन।



पीएडीडी-क्यूसीआई के निदेशक एवं प्रमुख डॉ. मनीष पांडे ने बीएए इंडिया द्वारा आयोजित इंडिया सोर्सिंग कॉन्क्लेव 2025 में "अनुरूपता आकलन संरचनाओं के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को सशक्त बनाना" विषय पर क्यूसीआई-संचालित सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें सभी कर्ताओं के लिए ईएसजी अनुपालन पर ध्यान केन्द्रित किया गया।



पीएचडीसीसीआई ने, नवाचार को बढ़ावा देने और भारत के गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भागीदार होने के लिए क्यूसीआई को सम्मानित किया।





मेडिकल फेयर इंडिया 2025 में, क्यूसीआई- संचालित सत्र को संबोधित करते हुए, एनएबीएल के निदेशक श्री पंकज जौहरी, और पीएडीडी-क्यूसीआई के निदेशक एवं प्रमुख डॉ. मनीष पांडे।



PPID
Project Planning &
Implementation Division

6 परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन प्रभाग (पीपीआईडी)

6.1 सीआईएल, फरीदाबाद

केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला (सीआईएल), वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

- क्यूसीआई को केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला (सीआईएल), फरीदाबाद के सभी चार प्रभागों (रसायन विज्ञान प्रभाग, जैव परख प्रभाग, चिकित्सा विष विज्ञान प्रभाग और पैकेजिंग एवं प्रसंस्करण प्रभाग) का अन्य-पक्ष आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह आकलन, उपलब्ध अवसंरचना, अपेक्षित अवसंरचना, सीआईएल द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में किया जाना था, तथा सीआईएल को वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सर्वश्रेष्ठ में से एक संगठन के रूप में स्थापित करने के लिए सुझाव भी दिए जाने थे। इसके साथ ही, कीटनाशकों/कीटाणुनाशकों में मिलावट को रोकने/नियंत्रित करने के तरीके भी बताए जाने थे।

- क्यूसीआई द्वारा किए गए मूल्यांकन में अवसंरचना, प्रौद्योगिकीय क्षमताओं और मानव संसाधन क्षमता से संबंधित महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया है, ताकि सीआईएल, वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रचालन कर सके। सीआईएल को कीटाणुनाशकों के परीक्षण और अनुसंधान के लिए एक विश्वस्तरीय केंद्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए, क्यूसीआई द्वारा एक चरणबद्ध विकास रणनीति की सिफारिश की गई थी:
  - चरण I (0-2 वर्ष): अवसंरचना और कार्यबल का तत्काल विस्तार
  - चरण II (3-5 वर्ष): उन्नत प्रौद्योगिकियों और क्षमता निर्माण पहलों का एकीकरण
  - चरण III (5 वर्ष से आगे): अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन और मान्यता प्राप्त करने के लिए रणनीतिक नीतियों का कार्यान्वयन



क्यूसीआई टीम, सीआईएल टीम के साथ अगस्त 2024 में केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला, फरीदाबाद परियोजना के तहत सीआईएल फरीदाबाद में अवसंरचना, प्रौद्योगिकीय क्षमताओं और मानव संसाधन की स्थिति को समझने के लिए चर्चा कर रही है।

6.2 राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्कीम I और II का अन्य-पक्ष मूल्यांकन

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू)

- क्यूसीआई को वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के लिए एनएचबी स्कीम - I और II के अन्य-पक्ष मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए चरण-II के रूप में समवर्ती मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:
  - बागवानी से संबंधित फसलों के उत्पादन और कटाई-पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास।
  - बागवानी उत्पादों के भंडारण के लिए शीतगृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम।
- भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) ने एनएचबी स्कीम के तहत, चरण I में लगभग 432 इकाइयों और चरण II में 108 इकाइयों का आकलन किया। क्यूसीआई के प्रेक्षणों के आधार पर, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने स्कीम के प्रभाव और पहुंच को बढ़ाने के लिए कई प्रमुख पहलें शुरू की हैं:
  - व्यापक सूचना प्रसार
  - आदर्श डीपीआर और प्रशिक्षण संसाधन
  - संस्थागत सहकार्य को सुदृढ़ करना
  - स्वच्छ पौधारोपण कार्यक्रम
  - प्रमाणन को बढ़ावा देना



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्कीम- I और II की अन्य-पक्ष मूल्यांकन परियोजना के अंतर्गत, सितंबर 2024 में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में अंगूर के खेत के मूल्यांकन के दौरान क्यूसीआई टीम

6.3 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमकेएसवाई के तहत, कृषि प्रसंस्करण संकुलों के लिए अवसंरचना का निर्माण स्कीम (एपीसी स्कीम) का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की कृषि प्रसंस्करण संकुल (एपीसी) स्कीम का लक्ष्य उद्यमियों को, आधुनिक अवसंरचना के साथ संकुल कार्यनीति पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। एपीसी स्कीम का मूल्यांकन निम्नलिखित आउटपुट/परिणाम संकेतकों के अनुसार पूरा किया जा चुका है -
  - स्कीम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य
  - मात्रा और मूल्यों के संदर्भ में बरबादी में कमी
  - अंतराल आकलन और निर्मित की जा रही अवसंरचना का क्षमता उपयोग
  - सेवा और आय के संदर्भ में किसानों (लघु, सीमांत और वृहत) पर पड़ने वाला प्रभाव
  - रोजगार सृजन, आदि।
- मूल्यांकन पूरा हो चुका है, तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की कृषि प्रसंस्करण उद्योग परिषद् (एपीसी) को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है।



अगस्त 2024 में हरियाणा के हिसार स्थित श्री श्याम स्नैक्स एपीसी के मूल्यांकन के दौरान, क्यूसीआई टीम कृषि प्रसंस्करण संकुलों(एपीसी स्कीम) के लिए अवसंरचना के निर्माण की स्कीम के प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन करते हुए

6.4 सरकारी अनाज प्रापण केंद्रों का वर्गीकरण करना: प्लेटफ़ॉर्म विकास

भारतीय खाद्य निगम और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

- 5 जुलाई, 2023 को केंद्र और संघ राज्यक्षेत्रों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान लिए गए संकल्प के अनुरूप, 44,000 से अधिक अनाज प्रापण केंद्रों (पीसी) के लिए एक ग्रेडिंग तंत्र शुरू किया गया। भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) द्वारा विकसित इस परिपक्वता मॉडल का लक्ष्य, अनाज प्रापण प्रचालनों में जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और समग्र गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार करना है।
- इस सुधार को आगे बढ़ाने के लिए, क्यूसीआई ने प्रोक्योरमेंट सेंटर सेल्फ असेसमेंट प्लेटफ़ॉर्म (पीसीएसएपी) नामक आईसीटी-आधारित एक अभिनव पहल को अभिकल्पित और कार्यान्वित किया, जो प्रापण केंद्रों को स्व-आकलन करने और अपनी परिपक्वता का स्तर निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। क्यूसीआई ने राज्यों में सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक क्षमता निर्माण प्रयास भी किए।
- खरीफ विपणन सत्र 2024-25 में, 42,217 से अधिक प्रापण केंद्र (94%) पीसीएसएपी पर पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 37,455 से अधिक केंद्रों (89%) ने अपना स्व-आकलन पूरा कर लिया है। इस व्यवस्था को व्यापक पैमाने पर अपनाए जाने से अनाज प्रापण प्रचालनों में पारदर्शिता और जवाबदेही उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, जिससे देश भर के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे लाभ हुआ है।
- राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर, तत्समय, डेटा-संचालित डैशबोर्ड अब नीति निर्माताओं को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वे अधिक सूचना संपन्न बनकर वित्तीय और नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

6.5 ओएससीएससी के लिए खरीफ विपणन सत्र 2024-25 में धान मिलों और प्रापण केंद्रों का सत्यापन

ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (ओएससीएससी)

- इस परियोजना का लक्ष्य धान के मिलों का सत्यापन और प्रापण केंद्रों का मौका मुआयना करके, ओडिशा में सूचीबद्ध 1,337 मिलों और प्रापण केंद्रों में, ओएससीएससी तथा केएमएस प्रचालन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
- मार्च 2025 तक, क्यूसीआई ने 1,400 से अधिक अनाज प्रापण केंद्रों का आकलन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे प्रापण प्रचालनों में पारदर्शिता और दक्षता के प्रति किसानों के मन में विश्वास बढ़ा है।
- आगामी महीने में, क्यूसीआई मिलों की ग्रेडिंग और स्टॉक सत्यापन का कार्य शुरू करेगी, ताकि प्रापण और भंडारण मानकों के साथ जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- इस पहल का लक्ष्य ओडिशा की अनाज प्रापण और भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना, प्रापण केंद्रों

एवं मिलों की दक्षता बढ़ाते हुए, सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली में विश्वास को बल देना है।



दिसंबर 2024 में, ओडिशा के पुरी स्थित पायल राइस मिल में, ओएससीएससी के लिए खरीफ विपणन सत्र 2024-25 में धान मिलों और प्रापण केंद्रों के सत्यापन संबंधी परियोजना के अंतर्गत प्रायोगिक सत्यापन कार्य करती हुई क्यूसीआई और ओएससीएससी की टीमें।



ओडिशा के पुरी में अपर नागरिक आपूर्ति अधिकारी और मिल प्रभारी के साथ चर्चा करती क्यूसीआई टीम, ताकि मिलों द्वारा अपनाई गई मिलिंग प्रक्रियाओं को समझा जा सके, साथ ही ओएससीएससी के लिए केएमएस 2024-25 में धान मिलों और प्रापण केन्द्रों की सत्यापन परियोजना के तहत दक्षता, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रक्रिया अनुकूलन से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

6.6 चुनिंदा खाद्य तेल उत्पादों की अखिल भारतीय निगरानी

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, एफएसएसआर विनियमों के अनुरूप, विभिन्न पैकेज्ड खाद्य तेलों के फिजियो-केमिकल मापदंडों से संबंधित गुणवत्ता, संरक्षा, और लेबलिंग मानकों का आकलन करना, और क्षेत्रीय अनुपालन स्तर का मूल्यांकन करना है।
- इस परियोजना के लिए पूरे भारत से नमूने सफलतापूर्वक एकत्र किए गए, जिनका परीक्षण एनएबीएल प्रत्यायित और एफएसएसएआई-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया गया।
- परीक्षण रिपोर्टों पर एक व्यापक सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया, जिससे मिलावट के हॉटस्पॉट की पहचान करने और जहां लागू हो, वहां भ्रामक लेबलिंग की व्यापकता का आकलन करने में मदद मिली।
- मार्च 2025 तक, प्रत्यायित निकायों का चयन किया जा चुका है, और सभी हितधारकों को शामिल करने और प्रशिक्षण देने का काम पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण के लिए एक तकनीकी प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लिया गया है और नमूना संग्रह का काम जारी है।

6.7 मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तहत, वैद्युत कार्य का अन्य-पक्ष निरीक्षण

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल)

- इस परियोजना का उद्देश्य, 2023-24 और 2024-25 में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम (एमवीवीएनएल) के अंतर्गत, डिस्कॉम गुणवत्ता निगरानी एजेंसी (डीक्यूएमए) के रूप में भिन्न-भिन्न जिलों में व्यवसाय योजना, प्रणाली विस्तार/ सुदृढ़ीकरण के संबंध में किए गए वैद्युत कार्यों का अन्य-पक्ष निरीक्षण करना है। इसमें अंतिम मापन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए डिस्कॉम अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण भी शामिल है।
- क्यूसीआई, बरेली, रायबरेली, अयोध्या, लखनऊ और उन्नाव जैसे प्रक्षेत्रों में 600 से अधिक स्थानों पर निरीक्षण का काम सफलतापूर्वक कर रही है।



मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तहत, वैद्युत कार्य के अन्य-पक्ष निरीक्षण से संबंधित परियोजना के अंतर्गत, मार्च 2025 में 33 केवी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और करंट ट्रांसफार्मर स्थापित करने के काम का अन्य-पक्ष आकलन करती हुई क्यूसीआई टीम।

6.8 पश्चिम अंसारी नगर एम्स के पुनर्विकास के लिए अन्य-पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी (टीपीक्यूएमए) के रूप में कार्य

नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) इंडिया लिमिटेड

- इस परियोजना का उद्देश्य परियोजना विनिर्देशों, मानकों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी, आकलन और

सत्यापन करना है, ताकि पुनर्विकास कार्य सफल, समय पर और उच्च-गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।

- इसके अलावा, अन्य-पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी कार्यान्वयन में किसी भी अंतराल की पहचान करेगी और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करते हुए सुधार के लिए सिफारिशें देगी तथा परियोजना की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तार की संभावना सुनिश्चित करेगी।
- पैकेज-I/भाग-I, नई दिल्ली के अंतर्गत पश्चिम अंसारी नगर एम्स में पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण प्रगति पर है।



मार्च 2024 में पश्चिम अंसारी नगर, एम्स के पुनर्विकास संबंधी परियोजना के तहत, अन्य-पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी (टीपीक्यूएमए) के रूप में साइट पर स्टील संबलीकरण के गुणवत्ता आश्वासन और निगरानी का कार्य करती हुई क्यूसीआई टीम

6.9 पीएचईडी हरियाणा द्वारा जल जीवन मिशन से इतर निष्पादित कार्यों का अन्य-पक्ष निरीक्षण

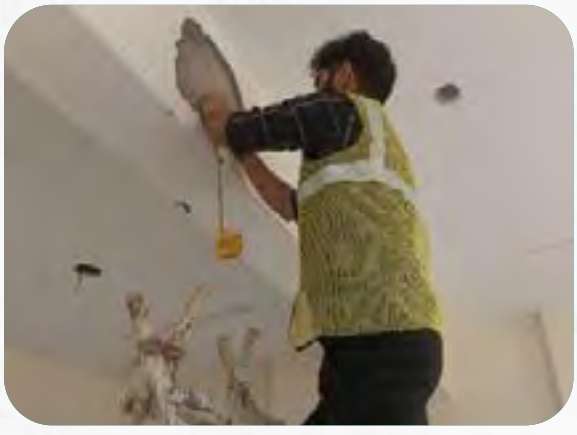
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा सरकार

- क्यूसीआई को हरियाणा राज्य में पीएचईडी (लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) द्वारा जेजेएम से इतर निष्पादित अन्य कार्यों का अन्य-पक्ष निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया था।
- मार्च 2025 तक, क्यूसीआई ने आबंटित की गई 13 स्कीमों में से 8 का स्थल निरीक्षण कर लिया है और स्थल पर प्राप्त निष्कर्षों सहित एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित ग्राहक को प्रस्तुत कर दी गई है।

6.10 यूपीपीसीएल गाजियाबाद के लिए संरचनात्मक स्थिरता विश्लेषण

उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड

- क्यूसीआई को राजकीय इंटर कॉलेज मसूरी, गाजियाबाद की विशेष तकनीकी जांच करने का कार्य सौंपा गया था, जिसमें संरचनात्मक स्थिरता विश्लेषण और कार्य स्थल पर मौजूदा संरचनाओं का गैर-विनाशक परीक्षण शामिल था।
- क्यूसीआई ने गैर-विनाशक परीक्षण किया और आगे की तकनीकी जांच के लिए संरचनात्मक विश्लेषण हेतु नमूना एकत्र किया। और कार्य स्थल पर प्राप्त निष्कर्षों सहित एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट, ग्राहक को प्रस्तुत कर दी गई है।



नवंबर 2024 में, यूपीपीसीएल गाजियाबाद के लिए संरचनात्मक स्थिरता विश्लेषण परियोजना के तहत कार्य स्थल पर एनडीटी (गैर-विनाशक) परीक्षण करती हुई क्यूसीआई टीम।

6.11 श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों का अन्य-पक्ष मूल्यांकन

श्रम और रोजगार मंत्रालय

- इस परियोजना का उद्देश्य, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई तीन योजनाओं - ई-श्रम, राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (एनसीएस), और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एनसीएससी-एससी/एसटी) और उनके लक्षित लाभार्थियों, क्षेत्रों, और अंचलों के लिए इन योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। इस मूल्यांकन में आउटपुट-आउटकम विश्लेषण और कार्यान्वयन अंतरालों की जांच करना शामिल है, जिसमें इच्छित स्कीम डिज़ाइन से उनके तालमेल की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, क्यूसीआई कार्यान्वयन दक्षता बढ़ाने, इन स्कीमों की निरंतरता सुनिश्चित करने, और अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रभावी तरीके से आच्छादित करने के लिए उनके संभावित विस्तार का पता लगाने के लिए सिफारिशें प्रदान करेगी।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित तीन केंद्रीय स्कीमों अर्थात् ई-श्रम, एनसीएस और एनसीएससी-एससी/एसटी - के प्रभाव का आकलन करने के लिए पूरे भारत से कुल 6,323 प्रतिक्रियाएं एकत्र की गईं थीं। इन प्रतिक्रियाओं का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया: ई-श्रम के लिए 3,661, एनसीएस के लिए 2,215, और एनसीएससी-एससी/एसटी के लिए 447।

- सभी तीनों स्कीमों की आकलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है, और उनकी प्रभावशीलता, लाभार्थियों पर प्रभाव, और अभीष्ट उद्देश्यों के साथ तालमेल का मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत विश्लेषण पूरा किया जा चुका है।



श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के अन्य पक्ष आकलन संबंधी परियोजना के तहत एससी/एसटी के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र के अधीन, फरवरी 2025 में कड़कड़डूमा एनआईईएलआईटी केंद्र में प्रभाव आकलन करती क्यूसीआई परियोजना टीम



परियोजना टीम ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के अन्य पक्ष आकलन संबंधी परियोजना के तहत राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र के अधीन, फरवरी 2025 में मंगलदोई, असम केंद्र का प्रभाव आकलन किया।

6.12 एनएलसी तालाबीरा खदान में कोयले का अन्य पक्ष नमूनाकरण, परीक्षण और विश्लेषण

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), तालाबीरा

- एनएलसी ने अपने खदान क्षेत्र में कोयले के गुणवत्ता विश्लेषण के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) को नामित किया है। इस परियोजना का उद्देश्य कोयला उपभोक्ताओं को उनके उतराई स्थल पर प्राप्त होने वाले कोयले का गुणवत्ता आकलन करना है।
- योजनारंभ के बाद से मार्च 2025 तक, कुल 3.83 एमएमटी कोयले का नमूनाकरण किया गया है।

6.13 जीएसईसीएल संयंत्रों में कोयले का गुणवत्ता विश्लेषण

गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड

- जीएसईसीएल ने अपने संयंत्रों में पहुंचने वाले कोयले के गुणवत्ता विश्लेषण के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) को नामित किया है। यह पहल उपभोक्ताओं को मिलने वाले कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु मूलभूत पद्धतियों को बेहतर बनाने का एक ठोस प्रयास है।
- योजनारंभ के बाद से मार्च 2025 तक, 9.54 एमएमटी से अधिक कोयले का नमूनाकरण किया गया है।



भारतीय गुणवत्ता परिषद् की टीम फरवरी 2025 में रेल मार्ग से गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (जीएसईसीएल) के संयंत्र में पहुंचने वाले कोयले का पूर्वसूचक नमूनाकरण करती हुई।

6.14 एससीसीएल के लोडिंग स्थलों पर कोयले का अन्य पक्ष नमूनाकरण, परीक्षण और विश्लेषण

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

- सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने अपने लोडिंग स्थल पर कोयले के गुणवत्ता विश्लेषण के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) को नामित किया है। इस परियोजना में प्रयास यह किया जा रहा है कि कोयला पारिस्थितिकी तंत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित प्रक्रियाओं में सुधार लाया जाए।
- मार्च 2025 तक, परियोजना की शुरुआत से अब तक 5.36 एमएमटी से अधिक की कुल मात्रा का नमूना लिया जा चुका है।



भारतीय गुणवत्ता परिषद् की टीम, मार्च 2025 में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) में कोयला का नमूना लेने की तैयारी कर रही है।

6.15 एवीबीटीपीएस संयंत्र में कोयले का द्वि-पक्षीय नमूनाकरण, परीक्षण और विश्लेषण

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड

- क्यूसीआई ने एवीबीटीपीएस की खदान में कोयले के गुणवत्ता विश्लेषण के लिए प्रतिस्पर्धी बोली में यह परियोजना जीती है।
- परियोजना की शुरुआत से लेकर अब तक यानि 25 मार्च तक कुल 2.03 एमएमटी कोयले का नमूना लिया जा चुका है।



क्यूसीआई टीम मार्च 2025 में रेल मोड से एवीबीटीपीएस के प्लांट स्थल पर कोयला नमूना का संग्रह करती हुई

6.16 गुजरात शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024

शहरी विकास एवं शहरी आवासन विभाग, गुजरात

- सौंपे गए इस कार्य का उद्देश्य एक व्यवस्थित कार्य योजना के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भाग लेने वाले शहरों की स्वच्छता और साफ-सफाई मानकों का व्यापक आकलन और निगरानी करना है। इसमें क्षेत्र दौरे, डेटा संग्रहण, और सर्विस-लेवल प्रगति संकेतकों का स्वतंत्र सत्यापन शामिल है। शहरों को विस्तृत रिपोर्टों, प्रस्तुतीकरणों और सर्वोत्तम परिपाटियों के प्रलेखन के साथ प्राप्त समेकित अंकों के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी।
- क्यूसीआई त्रैमासिक आकलन करेगी, राज्य मिशन निदेशकों के साथ रैंकिंग साझा करेगी, और निरंतर सुधार के लिए अंतराल विश्लेषण प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, क्यूसीआई उच्च-गुणवत्ता वाला प्रलेखन सुनिश्चित करेगी, जिसमें पुरस्कार विजेता शहरों के लिए प्रमाणपत्र शामिल हैं, जिससे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की पारदर्शिता और सफलता में वृद्धि होगी।
- मार्च 2025 तक, इस परियोजना ने 80,000 नागरिकों को स्वच्छता आकलन प्रक्रिया में शामिल किया है, जिसके परिणामस्वरूप जन जागरूकता और भागीदारी का स्तर बढ़ा है। डेटा संग्रह एप्लिकेशन और आकलन पोर्टल के विकास ने क्षेत्र कार्यों को सुव्यवस्थित किया है, जिससे डेटा प्रसंस्करण समय में कमी आई है और रिपोर्टिंग अधिक सटीक हुई है। एसएमडी और संभागीय पोर्टल ने समीक्षा और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाया है, जिससे स्वच्छता और साफ- सफाई संबंधी मुद्दों पर प्रतिक्रिया समय में सुधार हुआ है।



अक्टूबर 2024 में प्रथम चरण के आकलन के सफल समापन के बाद, स्वच्छ सर्वेक्षण गुजरात 2024 की टीम

6.17 स्वच्छ सर्वेक्षण गुजरात ग्रामीण 2024

ग्रामीण विकास आयुक्तालय, गुजरात

- क्यूसीआई, जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण टूलकिट के अनुरूप, गुजरात राज्य में दो चरणों में 1,000 गांवों में साफ-सफाई का आकलन कर रही है। इस मूल्यांकन में स्वच्छता से संबंधित विभिन्न पहलुओं का मौके पर सत्यापन शामिल है।
- मार्च 2025 तक, आकलन के लिए पीएमयू टीम की तैनाती, क्षमता निर्माण और प्रश्नावली विकास का कार्य पूरा हो चुका है। एसबीएम के अंतर्गत 526 गांवों और पीएमएवाई के अंतर्गत निर्मित घरों के क्षेत्र आकलन का कार्य पूरा हो चुका है। विभिन्न स्कीमों के लिए जिला समन्वयकों के माध्यम से क्षमता निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है। आईटी पोर्टल की तैनाती की जा चुकी है और विभिन्न स्कीमों के लिए जिला समन्वयकों के माध्यम से क्षमता निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है।

6.18 जल ही अमृत

अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन/आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

- क्यूसीआई 'जल ही अमृत' पहल के तहत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर देश भर में एसटीपी का आकलन कर रही है।
- मार्च 2025 तक, परियोजना के पहले और दूसरे चरण के

लिए 848 एसटीपी का क्षेत्र आकलन पूरा हो चुका है। जल ही अमृत पहल से देश की अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- एसटीपी की कार्यक्षमता और परिचालन दक्षता में वृद्धि।
- उपचारित जल की गुणवत्ता में सुधार, इसे पुन: उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त बनाना।
- स्थायित्वपूर्ण जल प्रबंधन को बढ़ावा, शहरों और राज्यों को सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

- जवाबदेही को बढ़ावा देकर और कार्य निष्पादन को प्रोत्साहित करके, 'जल ही अमृत' पहल में क्यूसीआई की भूमिका ने भारत में एक अधिक कुशल और टिकाऊ अपशिष्ट जल उपचार पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान दिया है।



जनवरी 2025 में ऋषिकेश स्थित एसटीपी से क्यूसीआई टीम द्वारा जल का नमूना एकत्रित किया जा रहा है, ताकि निर्धारित मापदंडों के अनुसार परीक्षण किया जा सके, और जल ही अमृत परियोजना के तहत गुणवत्ता आकलन एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।



अक्टूबर 2024 में क्यूसीआई द्वारा जल ही अमृत टीम के लिए प्रशिक्षकों का आंतरिक प्रशिक्षण (टीओटी) सत्र आयोजित किया गया

6.19 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा संदाय आकलन - आगे की राह (एनईएसडीए डब्ल्यू एफ) पीएमयू

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी)

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा संदाय आकलन (एनईएसडीए) द्विवार्षिक रूप से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और केंद्र सरकार के ई-गवर्नेंस सेवा संदाय की गंभीरता और प्रभावशीलता के आधार पर आकलन और बैंचमार्क तय करने का काम करता है। एनईएसडीए - वे फॉरवर्ड पीएमयू, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को, एनईएसडीए 2021 रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने में सहायता करता है, साथ ही राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार श्रृंखला, राज्यों के आरटीएस आयुक्तों के साथ बैठकें करने आदि जैसी अन्य पहलों में भी सहायता करता है।

- एनईएसडीए- वे फॉरवर्ड पीएमयू ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए:
  - ई-सेवा संदाय को मजबूत करने के लिए समर्पित मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें अनिवार्य ई-सेवाओं और एकीकृत सेवा संदाय पोर्टलों की संतृप्ति पर विशेष बल दिया गया।
  - फरवरी 2025 में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 20,250 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान की जा रही थीं, जबकि अप्रैल 2023 में 11,614 ई-सेवाएं प्रदान की जा रही थीं (74% की वृद्धि)
  - फरवरी 2025 में अभिनिर्धारित अनिवार्य ई-सेवाओं की 78% से अधिक संतृप्ति प्राप्त की गई, जबकि अप्रैल 2023 में यह 66% थी।
  - 10 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार (एनईजीडब्ल्यू) का आयोजन किया गया, जिनमें 1000 से अधिक अधिकारियों की भागीदारी हुई और पुरस्कार विजेता पहलों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया।
  - एनईएसडीए रूपरेखा में आकलन मापदंडों के अनुरूप, साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन सुगम बनाया गया, जिनमें साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और विशेष अभियान 4.0 के दौरान इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की पहल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के एआर/आईटी सचिवों, राज्यों के आरटीएस आयुक्तों के साथ बैठकें आयोजित की गईं, और इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के साथ विशेष बैठकें की गईं।

6.20 भविष्य के लिए तैयार टीसीजीएल

गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड

- टीसीजीएल ने व्यापक संगठनात्मक पुनर्गठन के लिए क्यूसीआई को काम सौंपा है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य टीसीजीएल की वर्तमान संगठनात्मक रूपरेखा का

मूल्यांकन करना, अंतरालों की पहचान करना और भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की जाने वाली संरचना का प्रस्ताव करना है। इसमें समान संगठनों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, जनशक्ति आबंटन को सुचारु बनाना और बेहतर प्रचालन दक्षता तथा हितधारक प्रबंधन के लिए रणनीतियों की सिफारिश करना शामिल है।

- इस परियोजना का उद्देश्य टीजीसीएल की संगठनात्मक संरचना का आकलन और अनुकूलन करना था, जो सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में, प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना, पारिश्रमिक रूपरेखा, ग्रेडिंग और बेंचमार्किंग विश्लेषण का विवरण देने वाली एक व्यापक रिपोर्ट और प्रस्तुतीकरण ग्राहक को प्रस्तुत किया गया।
- अंतिम अनुशंसाएं, उद्योग क्षेत्र की सर्वोत्तम परिपाटियों और सरकारी मापदंडों के साथ उसकी संरचना का तालमेल बनाकर, टीसीजीएल की दक्षता, जनशक्ति उपयोग और भविष्य की तैयारियों को बढ़ाने के लिए अभिकल्पित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, माननीय मुख्यमंत्री के लिए एक प्रस्तुति तैयार की गई है, जिसमें प्रमुख निष्कर्षों और प्रस्तावित सुधारों का सारांश दिया गया है।



भविष्य के लिए तैयार टीसीजीएल परियोजना के तहत, नवंबर 2024 में टीसीजीएल के सभी कर्मियों के साथ व्यक्तिगत तौर पर साक्षात्कार पूरा होने के बाद, पीपीआईडी टीम और टीसीजीएल टीम, जिसमें जीएम फाइनेंस भी शामिल रहे।

6.21 अटल भूजल योजना के तहत ग्राम पंचायतों का प्रभाव आकलन

जल शक्ति मंत्रालय

- क्यूसीआई ने भूजल प्रबंधन चुनौतियों से निपटने और इसके अभीष्ट परिणामों को प्राप्त करने में स्कीम की प्रभावशीलता के विस्तृत मूल्यांकन के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के साथ एक अन्य-पक्ष निरीक्षण निकाय के रूप में सहकार्य किया है। इस परियोजना का उद्देश्य, स्थानीय समुदायों में जल संबंधी कुशल परिपाटियों, सामुदायिक भागीदारी और भूजल प्रबंधन संबंधी व्यवहारिक परिवर्तनों के बारे में जागरूकता का आकलन करके अटल भूजल योजना के प्रभाव का आकलन करने के साथ ही 07 राज्यों में सतत जल परिपाटियों के अंगीकरण की जांच करना भी है।
- क्यूसीआई के आकलन के एक भाग के रूप में निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त किए जा चुके हैं
  - प्रमुख आउटपुट और आउटकम संकेतकों का आकलन किया गया, भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी सफलता को मापा गया, और जमीनी स्तर पर इसकी समग्र कार्यान्वयन प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया।
  - स्थानीय संस्थाओं की भूमिका, हितधारकों की सहभागिता, और समुदायों द्वारा भूजल के स्थायित्वपूर्ण उपयोग को अपनाने की सीमा का मूल्यांकन किया गया।
  - कार्यक्रम हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन किया गया, जैसे कि सहभागी जल बजट तैयार करना, मांग-पक्ष प्रबंधन, और दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करने में संस्थागत सुदृढ़ीकरण।
  - उच्च प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों की सर्वोत्तम परिपाटियों और सफलता की गाथाओं की पहचान की गई।



अटल भूजल योजना के तहत, ग्राम पंचायतों के प्रभाव आकलन की परियोजना के अंतर्गत दिसंबर 2024 में गुजरात में क्यूसीआई टीम के भ्रमण के दौरान, संवाद-संपर्क के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत अधिकारियों (फोकस ग्रुप डिस्कशन) के साथ सहभागिता।



फरवरी 2025 में कर्नाटक की हमारी यात्रा के दौरान, क्यूसीआई टीम का साक्षात्कार कोलार के महेर की गौतमी की प्रेरक गाथा से हुआ। उन्हें अपने पिता की ज़मीन विरासत में मिली थी, लेकिन उसकी पथरीली ज़मीन के कारण खेती करना असंभव लग रहा था। उस पर खेती करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, उन्होंने कृषि विभाग से सहायता मांगी। उनके मार्गदर्शन में, उन्होंने ज़मीन को समतल किया और एक खेत तालाब के साथ-साथ ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित की, जिससे वह भूमि उपजाऊ कृषि भूमि में बदल गई।



दिसंबर 2024 में, हरियाणा की नरनिया ग्राम पंचायत की हमारी यात्रा के दौरान, पीपीआईडी टीम ने ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों को शामिल करके और फोकस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बातचीत की, और सामुदायिक पहलों में महिलाओं की भागीदारी का भी विश्लेषण किया।

6.22 कच्चा माल आपूर्ति स्कीम का अन्य-पक्ष मूल्यांकन (आरएमएसएस)

वस्त्र मंत्रालय

- भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) ने सितंबर से दिसंबर 2024 तक अखिल भारतीय स्तर पर अन्य -पक्ष मूल्यांकन (टीपीए) आयोजित किया, जिसमें 2021-24 के लिए वस्त्र मंत्रालय की कच्चा माल आपूर्ति स्कीम (आरएमएसएस) का मूल्यांकन किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) द्वारा कार्यान्वित इस प्रमुख पहल में, हथकरघा बुनकरों को प्राकृतिक रेशे वाले धागों पर 15% मूल्य सब्सिडी और परिवहन सब्सिडी प्रदान की जाती है। 676 लाभार्थी समूहों और 65 आपूर्तिकर्ताओं (सांख्यिकीय रूप से प्रतिनिधि नमूने) को शामिल करते हुए किए गए इस मूल्यांकन में प्रलेख और लेनदेन सत्यापन, प्रमुख सूचनादाताओं के साक्षात्कार और फोकस समूह चर्चाएं की गईं जिनमें निम्नलिखित कार्य भी शामिल थे,
  - स्कीम की प्रभावशीलता और दक्षता का निर्धारण करना,
  - नीति में सुधार के लिए डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करना, और
  - भारतीय हथकरघा बुनकरों को भावी समर्थन की जानकारी देने के लिए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- इस परियोजना के निम्नलिखित निष्कर्ष थे:
  - आय में वृद्धि: 70% से अधिक लाभार्थियों ने आय में वृद्धि की सूचना दी, जो 2019 की जनगणना के स्तर से काफी अधिक है।
  - डिलीवरी/ सब्सिडी: अधिकांश संतुष्ट, लेकिन >25% को डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ा, और सब्सिडी औसतन 3 महीने की रही।
  - ऐप का कम उपयोग: ई-धागा ऐप का उपयोग कम है; एनएचडीसी पर निर्भरता अधिक है।
  - आपूर्तिकर्ता गैर-अनुपालन: अधिकांश आपूर्तिकर्ता निरीक्षण और लेबल अपेक्षाओं को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

6.23 एसआरकेवीएम–एपी के तहत उत्पादों का गुणवत्ता आश्वासन

समग्र शिक्षा, शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश

- स्कूल शिक्षा विभाग ने क्यूसीआई को गुणवत्ता आश्वासन भागीदार के रूप में शामिल किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खरीदे गए उत्पाद निर्दिष्ट भारतीय मानकों का 100% अनुपालन करते हैं। यह साझेदारी इस बात की गारंटी देने के लिए महत्वपूर्ण है कि अंतिम लाभार्थियों तक केवल गुणवत्तापूर्ण उत्पाद ही पहुंचाए जाएं, जिससे विश्वास बना रहे और स्कीम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए।
- एक व्यवस्थित गुणवत्ता आश्वासन रूपरेखा को समाहित करके, क्यूसीआई का लक्ष्य प्रापण की समग्र दक्षता को बढ़ाना है और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि केवल उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पाद ही विद्यार्थियों तक पहुंचें। इन पूर्वानुमानित परिणामों में शामिल हैं:
  - उत्पाद शुद्धता और अनुपालन - निर्धारित मानकों का 100% पालन, दोष दर में कमी और स्थायित्व में वृद्धि।
  - बेहतर विद्यार्थी अनुभव - यह सुनिश्चित करना कि 26 जिलों के 49,190 स्कूलों के 33.75 लाख विद्यार्थियों को उच्च-गुणवत्ता वाली अधिगम सामग्री प्राप्त हो, जिससे बेहतर अधिगम परिणामों में योगदान प्राप्त हो।
  - प्रचालन दक्षता - सक्रिय परीक्षण और गुणवत्ता जांच के माध्यम से प्रापण तंत्र को मजबूत करना, अस्वीकृति और विलंब को कम करना।
  - अभिशासन और विश्वास - सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, इस पहल में हितधारकों का विश्वास मजबूत करना।



क्यूसीआई की पीएमयू टीम, फरवरी 2025 में विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्या मित्र (एसआरवीएम) कार्यक्रम के लिए बोली-पूर्व उत्पादों का मूल्यांकन, कलर स्कीम का विश्लेषण करती हुई



NDIE
National Division for Industry Excellence

7 राष्ट्रीय औद्योगिक उत्कृष्टता प्रभाग

यह प्रभाग 'आत्मनिर्भर भारत' पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न परियोजनाओं का नेतृत्व करता है। यह प्रभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल है।

7.1 सरकारी परियोजनाओं/स्कीमों से संबंधित गतिविधियां

7.1.1 "एमएसएमई सस्टेनेबल (ज़ेड) प्रमाणन" योजना

एमएसएमई सस्टेनेबल (ज़ेड) प्रमाणन, ज़ीरो डिफ़ेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट (ज़ेड) परिपाटियों के बारे में एमएसएमई के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें ज़ेड प्रमाणन के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने का एक व्यापक अभियान है। ज़ेड प्रमाणन की तैयारी के माध्यम से, एमएसएमई अपशिष्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण चेतना बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर सकते हैं, अपने बाजार का विस्तार आदि कार्य कर सकते हैं। एमएसएमई को कार्य संस्कृति, उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों आदि के मानकीकरण में सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा ताकि उनकी वैश्विक स्पर्धात्मकता और स्थायित्व बढ़ाया जा सके।

एमएसएमई सस्टेनेबल (ज़ेड) प्रमाणन योजना के तहत क्यूसीआई को कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के रूप में काम जारी रखने के लिए नामित किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय की एमएसएमई सस्टेनेबल (ज़ेड) प्रमाणन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रमाण के तौर पर, भारतीय गुणवत्ता परिषद् ने इस योजना के तहत कम समय में ही 2,75,000 से अधिक ज़ेड प्रमाणन प्रदान करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उल्लेखनीय सफलता, विभिन्न क्षेत्रों में अपने संचालन में एमएसएमई की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करने की बढ़ती प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। एमएसएमई सस्टेनेबल (ज़ेड) प्रमाणन योजना के दिशानिर्देशों के आधार पर क्यूसीआई द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां पूरी की गई हैं:

क. उद्योग जागरूकता कार्यक्रम

भिन्न भिन्न राज्यों और एमएसएमई क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता योजना क्रियान्वित की गई। इन कार्यक्रमों के संचालन में राज्य सरकार के डीआईसी कार्यालयों, उद्योग संघों और अन्य आयोजन भागीदारों का व्यापक योगदान मिला। ज़ेड योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, 150 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जागरूकता कार्यक्रमों के अलावा, आयोजन भागीदारों के माध्यम से भारत भर के 500 से अधिक शहरों में 1.25 लाख से अधिक एमएसएमई को ऑन-साइट सहायता भी प्रदान की गई।





















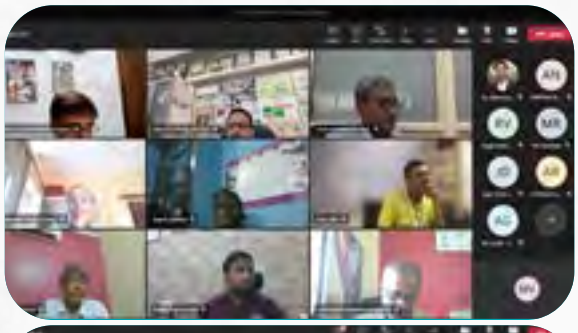
एमएसएमई के लिए ज़ेड जागरूकता कार्यक्रम और पंजीकरण शिविर आयोजित किए गए।

ख. परामर्शदाता और आकलनकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम

परामर्शदाता और आकलनकर्ता ज़ेड प्रमाणन योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आकलन और परामर्श के दौरान यथा-प्रयोज्य सार्थक इनपुट प्रदान करते हैं, तथा एमएसएमई को उच्चतर स्तर पर ले जाने में उनकी मदद करते हैं। इस प्रकार, आकलन और परामर्श की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उनका प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है।

i. 5 दिवसीय परामर्शदाता प्रशिक्षण आयोजित किए गए : 08 (प्रतिभागी: 240)

ii. 5 दिवसीय आकलनकर्ता प्रशिक्षण आयोजित किए गए : 07 (प्रतिभागी: 197)





परामर्शदाताओं और आकलनकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

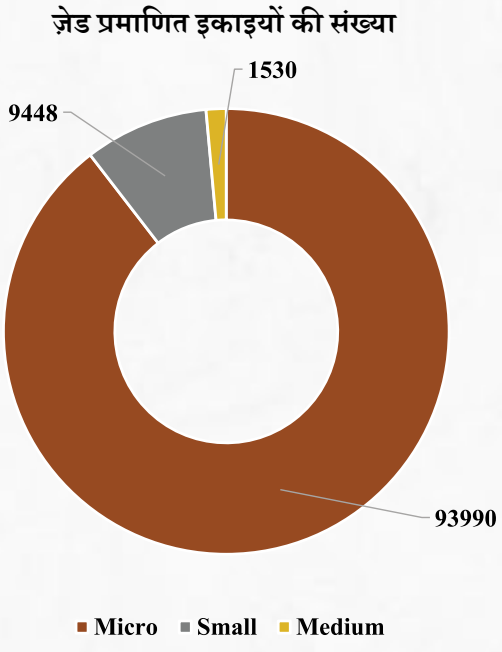
ग. आकलन, प्रमाणन और परामर्श के माध्यम से हैंडहोल्डिंग

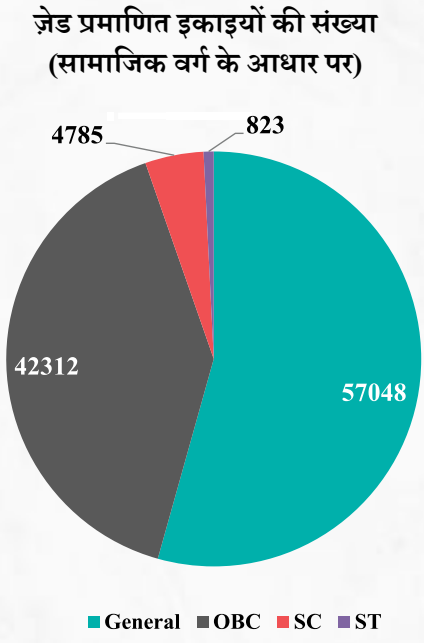
i. पंजीकृत एमएसएमई: 149836 (सूक्ष्म: 136267, लघु: 11737, मध्यम: 1825)

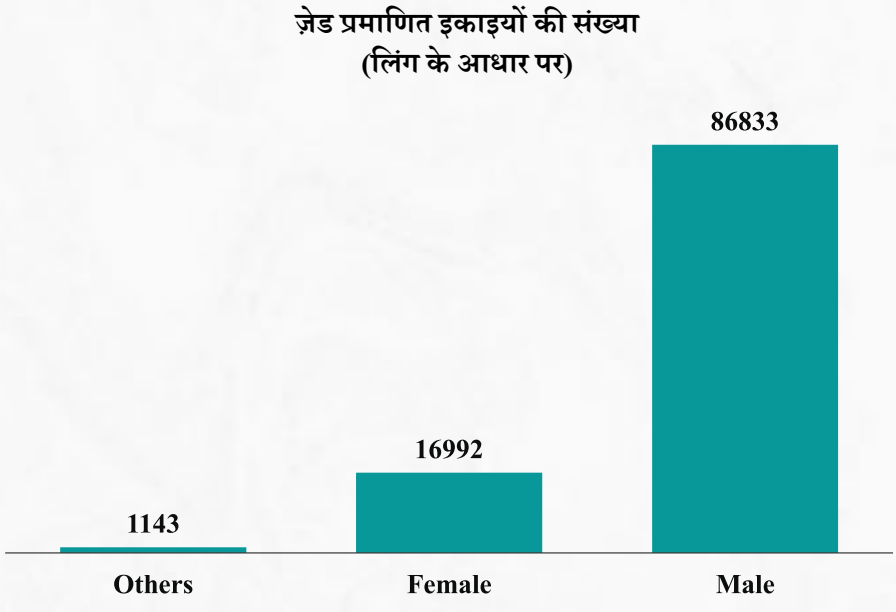
ii. प्रमाणित एमएसएमई: 104968 (कांस्य: 102958, रजत: 731 और स्वर्ण: 1279)

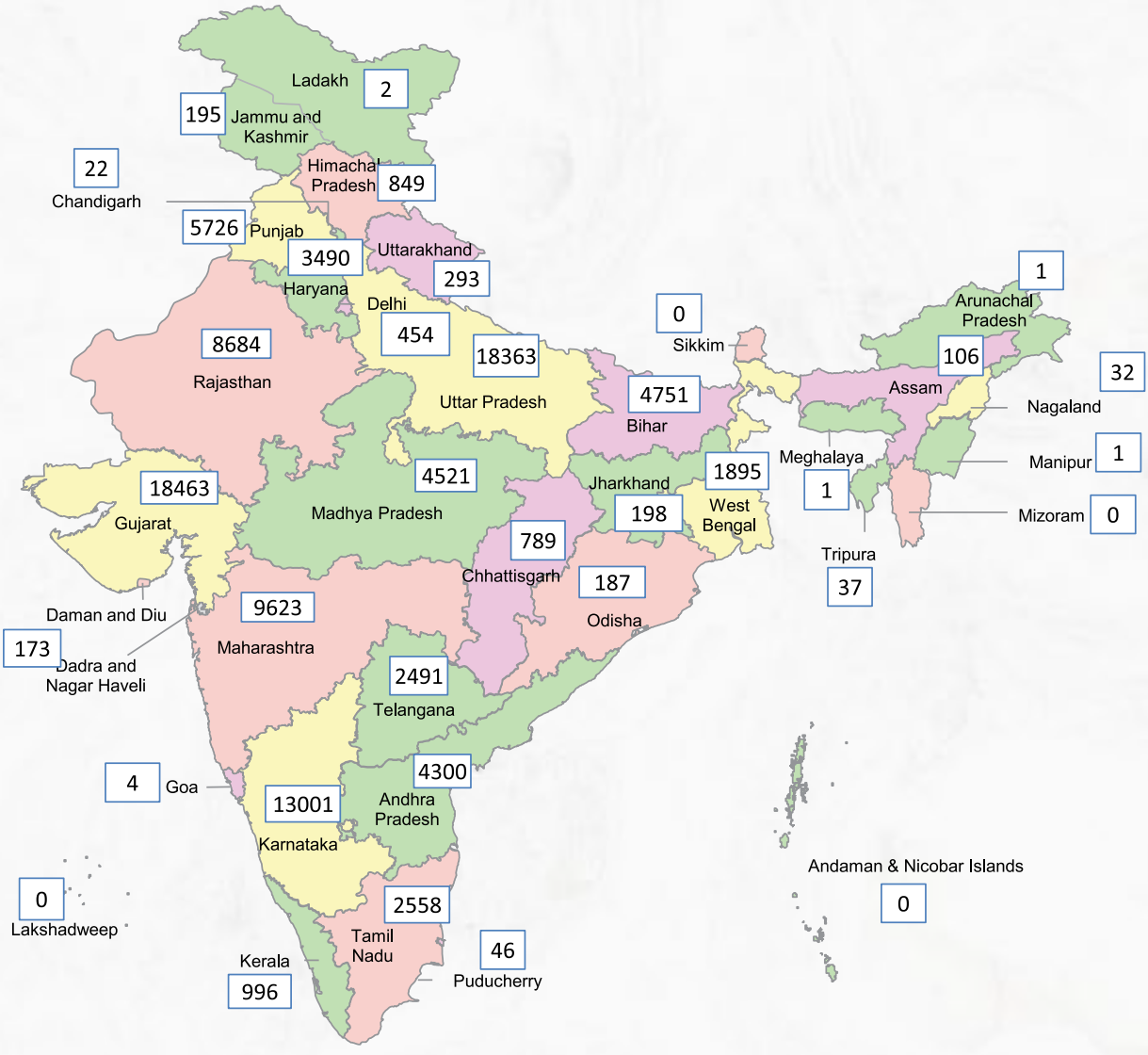
iii. हैंडहोल्डिंग /परामर्श सहायता के लिए प्राप्त आवेदन: 1959

iv. एमएसएमई की संख्या जिन्होंने सिस्टम (गुणवत्ता)/ परीक्षण/उत्पाद प्रमाणन के संबंध में वित्तीय सहायता का लाभ उठाया: 1119


ज़ेड प्रमाणित इकाइयों की संख्या
1530
9448
93990
Micro
Small
Medium


ज़ेड प्रमाणित इकाइयों की संख्या
(सामाजिक वर्ग के आधार पर)
4785
823
42312
57048
General
OBC
SC
ST


ज़ेड प्रमाणित इकाइयों की संख्या
(लिंग के आधार पर)
86833
16992
1143
Others
Female
Male



ZED Certified MSMEs – State wise

घ. प्रचार-प्रसार एवं ब्रांडिंग

- 17 मार्च, 2025 को असम लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एएसआईडीसी), असम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- 26 मार्च, 2025 को उत्तराखंड सरकार के उद्योग निदेशालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- 5 सितंबर, 2024 और 6 सितंबर, 2024 को क्रमश: मोंटे कार्लो और एवन साइकिल्स के साथ लुधियाना में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- मध्य प्रदेश में ज़ेड योजना का प्रचार-प्रसार करने के लिए, 3 अक्टूबर, 2024 को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (एमपीएलयूएन) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
- 27 दिसंबर, 2024 को बीएचईएल की आपूर्ति श्रृंखला में ज़ेड प्रमाणन को अंगीकार किए जाने पर चर्चा के लिए बीएचईएल के साथ बैठक आयोजित की गई।
- ज़ेड प्रमाणन की संख्या बढ़ाने के लिए, विभिन्न राज्य सरकारों (त्रिपुरा, चंडीगढ़, कर्नाटक, नगालैंड, हरियाणा, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात) के साथ बैठकें आयोजित की गई।
- 17 जनवरी, 2025 को आईआईएम अमृतसर में, आईसीएमएम – 2025 के दौरान ज़ेड का प्रस्तुतीकरण किया गया।

- 30-31 जनवरी, 2025 को डीआईएसएचए कार्यशाला आयोजित की गई।
- 21 अगस्त, 2024 को दिल्ली में निर्यात के लिए ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म पर ज़ेड रजत और स्वर्ण प्रमाणित एमएसएमई को सूचीबद्ध करने के लिए, सहकार्य हेतु विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के साथ बैठक आयोजित की गई।
- 19 जुलाई, 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित व्यापक स्पर्धात्मकता कार्यशाला में ज़ेड को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया।
- 2 अगस्त, 2024 को वाराणसी में बीएलडब्ल्यू विक्रेताओं के लिए एक ज़ेड जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इसमें 50 से अधिक विक्रेताओं ने प्रतिभाग किया।
- एसोचैम गुजरात परिषद् के सदस्यों के लिए 31 मई, 2024 को अहमदाबाद, गुजरात में एक ज़ेड जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इसमें 75 से अधिक एमएसएमई ने प्रतिभाग किया।
- 11 सितंबर, 2024 को रांची, झारखंड में आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव के दौरान, ज़ेड रजत और स्वर्ण प्रमाणित एमएसएमई को माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने सम्मानित किया।
- 13 फरवरी, 2025 को चेन्नै, तमिलनाडु में गुणवत्ता मंथन का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान लीन स्कीम की रूपरेखा से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की गई, और इसके संपर्क विस्तार एवं कार्यान्वयन के अवसरों की तलाश की गई।





अहमदाबाद, गुजरात में एसोचैम गुजरात परिषद् के सदस्यों के लिए ज़ेड जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।



असम लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एएसआईडीसी), असम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।



उत्तराखंड सरकार के उद्योग निदेशालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।







लुधियाना में मोंटे कार्लो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।





लुधियाना में एवन साइकिल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।





रांची, झारखंड में एमएसएमई कॉन्क्लेव के दौरान, ज़ेड रजत और स्वर्ण प्रमाणित एमएसएमई को माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने सम्मानित किया।





वर्तमान लीन स्कीम की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चेन्नै, तमिलनाडु में गुणवत्ता मंथन का आयोजन किया गया।

ड. ज़ेड मीडिया कवरेज



रैम्प स्कीम के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित

रायसेन। जिले में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम के अंतर्गत एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्री मंडीदीप के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जेड स्कीम, लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, बौद्धिक संपदा अधिकार और व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम की शुरुआत योजना के नोडल अधिकारी और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के उप महाप्रबंधक अनिल बागले एवं जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र मंडीदीप के महाप्रबंधक के संबोधन से हुई। जिसमें उन्होंने योजना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने योजना के उद्देश्यों और इसमें मध्य प्रदेश सरकार की भूमिका और योगदान पर प्रकाश डाला।



रैंप प्रोग्राम के तहत हुई कार्यशाला, दी योजनाओं की जानकारी

राष्ट्रीय हिन्दी मेल

रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस को लेकर कार्यशाला आयोजित

संवाददाता सुरभि सिंघल माहेश्वरी
मो. 9981322343

Date: 16/10/2024, Page: 4, City: Bhopal

राष्ट्रीय हिन्दी मेल

राज एक्सप्रेस

रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप स्कीम के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित

रैंप प्रोग्राम में भाग लेकर उद्योगों को लाभ लेने प्रोत्साहित करें एसोसिएशन



दैनिक उजाला

मंडीदीप में रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (रैम्प) स्कीम के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित



जिले के उद्योगों को जेड सर्टिफाइड बनाने के लिए हुई कार्यशाला



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न



एमएसएमई विभाग की कार्यशाला सम्पन्न





रैम्प योजना के तहत सागर में कार्यशाला का आयोजन

सागर। नवदुनिया

जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (रैम्प) योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होटल दीपक, सिविल लाइंस, सागर में किया गया। इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न उद्योग संघों ने सक्रिय भागीदारी की।कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) योजना, लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धात्मकता योजना (एलएमसीएस), बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), और व्यापार प्राप्त सिस्टम (टीआरईडीएस) के प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यशाला की शुरुआत जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र, सागर की महाप्रबंधक सुश्री मदकिनी फाटे के स्वागत भाषण से हुई। अपने संबोधन में उन्होंने रैम्प योजना के उद्देश्य, मध्य प्रदेश सरकार की भूमिका और इसमें स्थानीय उद्योगों के लिए संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।इसके पश्चात, जोनल के विशेषज्ञ डॉ अमन जैसवाल ने इस योजना के लाभों और क्रियान्वयन पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि जेड सर्टिफिकेशन प्राप्त करने से उद्योगों की गुणवत्ता और पर्यावरणीय प्रभाव में सुधार होगा। उन्होंने स्थानीय उद्योगों से नेट सर्टिफाइड बनने का आह्वान किया।

7.1.2 समर प्रमाणन: डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय के विक्रेताओं का आकलन और रेटिंग

उन्नत विनिर्माण आकलन और रेटिंग (समर) प्रमाणन प्रणाली, क्यूसीआई और डीआरडीओ के बीच सहकार्य का परिणाम है और रक्षा विनिर्माण उद्यमों की परिपक्वता मापने का एक बेंचमार्क है। इसका उद्देश्य देश में रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

यह प्रमाणन, भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) द्वारा विकसित परिपक्वता आकलन मॉडल पर आधारित है और यह सभी रक्षा विनिर्माण उद्यमों यानी सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों पर लागू होता है। इसकी मुख्य गतिविधियों की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- आकलन के लिए आवेदनों की संख्या: 81
- किए गए आकलनों की संख्या: 60
- रेटिंग प्राप्त संगठनों की संख्या: 47 (लेवल 1: 04, लेवल 2: 13, लेवल 3: 23, लेवल 4: 07)
- रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एयरो इंडिया शो 2025 में प्रदर्शित समर प्रमाणन का उद्देश्य, विक्रेताओं की गुणवत्ता और अनुपालन को बढ़ाना है। इसमें 120 से अधिक डीआरडीओ विक्रेता शामिल हुए।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा आयुध एवं युद्ध इंजीनियरिंग (एसीई) संकुल के माध्यम से 18 अक्टूबर, 2024 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित विक्रेता संपर्क अभियान में समर प्रमाणन का प्रदर्शन किया गया। 250 से अधिक संगठनों ने इसमें भाग लिया।
- दिल्ली में 14 नवंबर, 2024 को डीआरडीओ-आईएसएसए द्वारा उनकी गुणवत्ता माह पहल के एक भाग के रूप में समर प्रमाणन का प्रदर्शन किया गया।
- 24 अप्रैल, 2024 को हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित "बीडीएल विक्रेताओं की सामंजस्य बैठक" में समर प्रमाणन का प्रदर्शन किया गया। 75 से अधिक बीडीएल विक्रेताओं ने प्रतिभाग किया।





रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एयरो इंडिया शो 2025 में समर प्रमाणन का प्रदर्शन किया गया।



हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित "बीडीएल विक्रेताओं की सामंजस्य बैठक" में समर प्रमाणन का प्रदर्शन किया गया।


PADD
Project Analysis and
Documentation Division
8
परियोजना
विश्लेषण
और प्रलेखन
प्रभाग
(पीएडीडी)

परियोजना विश्लेषण और प्रलेखन प्रभाग: अंतिम छोर तक पहुंच, उच्च श्रेणी की गुणवत्ता

परियोजना विश्लेषण और प्रलेखन प्रभाग उन परियोजनाओं का काम संभालता है, जिनका उद्देश्य सरकारी, अंतर्सरकारी, क्षेत्रीय और वैश्विक संगठनों के लिए अनुरूपता आकलन रूपरेखाओं के अभिकल्पन, विकास और कार्यान्वयन की दिशा में बढ़ना है।

यह प्रभाग राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक प्रासंगिकता वाली अभिनव पहलों को आगे बढ़ाने में गर्व महसूस करता है। क्यूसीआई, इस प्रभाग के माध्यम से, विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों, औद्योगिक निकायों, अंतरराष्ट्रीय दान-दाता एजेंसियों, विकासात्मक संगठनों, तथा अंतर-सरकारी निकायों जैसे संयुक्त राष्ट्र का फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन (एफएओ), यूएनएफएसएस, यूएनसीटीएडी, सार्क कृषि केंद्र, आईसीआरआईएसएटी, आईटीटीओ, यूएनडीपी, ग्लोबल जीएपी, आईआरआरआई आदि को समाधान प्रदान कर रही है।

अब एफएसएसएआई, डीजीसीए, एनबीए जैसे विनियामकों और एनईजीडी, एनजीसीएमए, एनटीआरओ, एनसीआईआईपीसी, एनसीपीसीआर जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा संबंधित अनुमोदन जारी करने से पूर्व समुचित आकलन में सहायता के लिए पीपीआईडी की मांग की जाने लगी है।

हम निम्नलिखित उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करके अपने मिशन को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं:

- अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुरूप, विभिन्न क्षेत्रों में अनुरूपता आकलन रूपरेखाओं का विकास
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र और उद्योग निकायों को तकनीकी सहायता का प्रावधान
- अनुरूपता आकलन के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता
- परिणाम देने और उच्च स्तर की गुणवत्ता प्रेरित करने के लिए अभिनव कार्यनीति और विशेषज्ञता के समावेश के माध्यम से सामंजस्यपूर्वक काम करना
- अग्रणी अनुसंधान और इसके परिणाम का प्रसार प्रासंगिक प्रकाशनों, रिपोर्टों और व्यापार पत्रिकाओं में करके एकीकृत समाधान प्रदान करना
- बहु-हितधारक नीत पहल करना जो विविध व्यावसायिक मिश्रण पर केंद्रित हों जिनमें सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को बढ़ाना और बेहतर स्वीकृति के लिए अनुरूपता आकलन समाधानों पर आम सहमति बनाने हेतु सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करना शामिल है।



8.1 पारंपरिक सामुदायिक स्वास्थ्यचर्या- प्रदाताओं के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम (वीसीएस-टीसीएचपी)

8.1.1 यह स्कीम, उन पारंपरिक सामुदायिक स्वास्थ्यचर्या-प्रदाताओं के लिए एक समान और मानकीकृत आकलन फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती है जो अपने पारंपरिक ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं की विभिन्न धाराओं (पीलिया, सामान्य बीमारियों, जहरीले जंतुओं के काटने, हड्डियों की सेटिंग, जोड़ों के दर्द और पारंपरिक जन्म परिचरों) का प्रबंधन करते हैं।

8.1.2 अब तक, इस स्कीम के अंतर्गत कुल 2522 पारंपरिक सामुदायिक स्वास्थ्यचर्या-प्रदाता प्रमाणित किए गए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना की पुष्टि की है और गोवा और तमिलनाडु जैसे राज्य पहले से ही इस स्कीम को समर्थन दे रहे हैं।

8.1.3 छत्तीसगढ़ के समर्थन के बाद से राज्य में 216 पारंपरिक सामुदायिक स्वास्थ्यचर्या-प्रदाता प्रमाणित किए गए।

8.2 आयुष मार्क स्कीम

8.2.1 तत्कालीन आयुष विभाग के आदेश पर, उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने के लिए आयुष उत्पादों के लिए एक स्वैच्छिक उत्पाद प्रमाणन स्कीम भारतीय गुणवत्ता परिषद् द्वारा अभिकल्पित की गई थी। इस स्कीम में प्रमाणन के दो स्तर हैं: मानक और प्रीमियम।

8.2.2 अब तक, इस स्कीम के तहत, कुल प्रमाणित किए गए 68 विनिर्माताओं सहित कुल 5797 उत्पादों को आयुष मार्क प्रदान किए गए हैं।

8.2.3 आयुष मंत्रालय आयुष आहार (एएएचएआर) लेकर आ रहा है, जो आयुष मार्क से जुड़ी है जिसके लिए क्यूसीआई को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसमें एनएबीसीबी और पीएडीडी की भागीदारी भी होगी।

8.3 हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों (एचआरएए) की मान्यता

8.3.1 पीएडीडी ने हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों ((एचआरएए) के अनुमोदन के लिए एक स्कीम विकसित की है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उन खाद्य दुकानों के बारे में पर्याप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में मदद करना है जहां भोजन करना वे पसंद करते हैं, और इसके लिए प्रभाग ने व्यवसायों को साफ-सफाई तथा संरक्षा मानकों में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया है। मान्यता प्राप्त एजेंसी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित फूड हाइजीन और संरक्षा पद्धतियों के अनुपालन की पुष्टि करेगी।

8.3.2 क्यूसीआई के पास इस स्कीम के तहत, वर्तमान में 27 हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियां सक्रिय हैं।

8.3.3 इन हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों द्वारा अब तक कुल 62233 हाइजीन रेटिंग स्कीम (एचआरएस) की संपरीक्षा की गई है।

8.3.4 प्रभाग ने, 23 जनवरी, 2025 और 21 फरवरी, 2025 को दो हाइजीन रेटिंग संपरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (अर्हक एवं पुनश्चर्या) सफलतापूर्वक आयोजित किए, जिनमें कुल 87 प्रतिभागियों को एफएसएसएआई की हाइजीन रेटिंग स्कीम के तहत प्रशिक्षित किया गया।

8.3.5 एफएसएसएआई की 'ईट राइट इंडिया पहल' के अंतर्गत, 10 जनवरी, 2025 को उत्तम हाइजीन और उत्तम विनिर्माण परिपाटियों (जीएचपी और जीएमपी) पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न आईएचएम के 28 छात्रों ने प्रतिभाग किया।



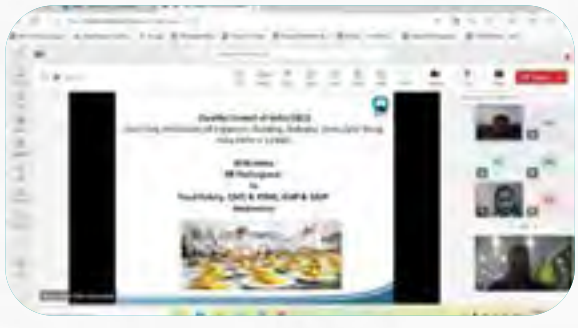


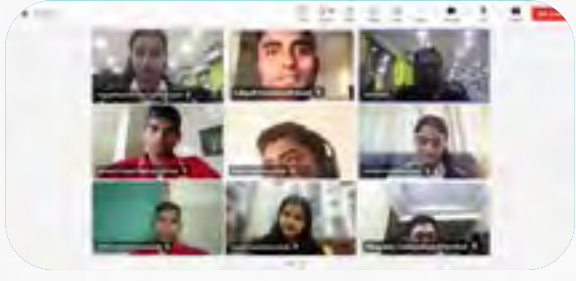
प्रभाग ने, 23 जनवरी, 2025 को हाइजीन रेटिंग ऑडिटर प्रशिक्षण आयोजित किया।





प्रभाग ने, 21 फरवरी, 2025 को हाइजीन रेटिंग ऑडिटर प्रशिक्षण आयोजित किया।





आतिथ्य क्षेत्र के भावी नेतृत्वकर्ताओं का सशक्तीकरण : एफएसएसएआई की ईट राइट इंडिया पहल के तहत, जीएचपी और जीएमपी विषय पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण में, 10 जनवरी, 2025 को 28 आईएचएम विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

8.4 मानव-रहित विमान प्रणाली के लिए प्रमाणन स्कीम (सीएसयूएएस)

8.4.1 नागर विमानन मंत्रालय के आदेश पर क्यूसीआई मानवरहित विमान प्रणालियों (यूएएस) के लिए प्रमाणन स्कीम प्रचालित कर रही है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी, 2022 को राजपत्र में इस स्कीम को अधिसूचित किया गया था।

8.4.2 आरंभ के बाद से कुल 104 टाइप प्रमाणपत्र (टीसी) जारी किए जा चुके हैं।

8.4.3 ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हुए, पीएडीडी ने सीएसयूएएस के माध्यम से ड्रोन क्षेत्र में अपने हस्तक्षेप के बारे में नागर विमानन मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को जानकारी दी और सहयोग प्रदान किया। किसान ड्रोन में मजबूत स्वदेशी सामग्री सुनिश्चित करके नमो ड्रोन दीदी स्कीम को आगे बढ़ाया, जिससे आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त हुआ।

8.4.4 पीएडीडी ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे का क्षमता निर्माण कार्य किया, जिसमें अनुरूपता आकलन रूपरेखा और परीक्षण अपेक्षाओं सहित सीएसयूएएस की तकनीकी अपेक्षाओं पर केंद्रित प्रशिक्षण को शामिल किया गया ताकि उन्हें एक प्राधिकृत परीक्षण संस्था (एटीई) बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

8.4.5 पीएडीडी, क्यूसीआई ने वीएलओएस के लिए उन्नत सीएसयूएएस स्कीम विकसित की है, किसान ड्रोन के स्वदेशीकरण के लिए रूपरेखा और बीवीएलओएस रूपरेखा विकसित की है जिसे तकनीकी समिति और प्रमाणन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

8.4.6 पीएडीडी ने कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (एफएमटीटीआई) के सहयोग से, चार अवस्थानों : एफएमटीटीआई सेंट्रल, बुदनी, एफएमटीटीआई उत्तरी क्षेत्र, हिसार, एफएमटीटीआई पूर्वोत्तर क्षेत्र, विश्वनाथ चरियाली (10-13 दिसंबर, 2024), एफएमटीटीआई दक्षिणी क्षेत्र, अनंतपुर (11-14 दिसंबर, 2024) पर सीएसयूएएस विषयक चार दिवसीय क्षमता निर्माण-सह-संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। एफएमटीटीआई, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक संस्थान है, जो मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है, किसानों को आधुनिक समाधानों से सशक्त बना रहा है ताकि वे अधिक टिकाऊ और प्रौद्योगिकी-संचालित भविष्य का निर्माण कर सकें।

8.4.7 भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) ने एपी ड्रोन कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ड्रोन प्रौद्योगिकी और प्रमाणन के क्षेत्र में सहयोग को पुष्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



पीएडीडी द्वारा सीएसयूएएस के माध्यम से नवाचार का प्रेरण : आत्मनिर्भर भारत के लिए नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत स्वदेशी कृषि-ड्रोन के साथ भारत के ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण













कृषि का सशक्तीकरण : कृषि मंत्रालय के एफएमटीटीआई के लिए चार अवस्थानों पर सीएसयूएएस क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।



क्यूसीआई ने उन्नत ड्रोन तकनीक और प्रमाणन के लिए, एपी ड्रोन कॉर्पोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

8.5 इंड गैप प्रमाणन योजना

8.5.1 यह पहल खाद्य सुरक्षा, उत्पादन की गुणवत्ता, और कृषि में संसाधन अनुकूलन को बढ़ाने, वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुपालन के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करने तथा बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने पर केंद्रित था।

8.5.2 इस प्रभाग ने, आंध्र प्रदेश सरकार के राज्य कृषि विभाग के 233 अधिकारियों के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों (क्यूएमएस), खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों (एफएसएमएस), और इंडगैप अनुपालन हेतु आईएसओ 19011 घटक विषय पर तीन दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया। यह प्रशिक्षण 28 से 30 अगस्त, 9 से 11 सितंबर, 18 से 20 सितंबर और 24 से 25 सितंबर, 2024 तक क्रमश: चार बैचों में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।

8.5.3 आंध्र प्रदेश के कृषि विभाग में कृषि आयुक्त एवं निदेशक श्री एस. दिली राव, आईएएस, के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राज्य में सभी एफपीओ के क्षमता निर्माण पर बल दिए जाने के बारे में चर्चा की गई। इस स्कीम के तहत प्रमाणन प्रक्रिया और संपरीक्षा के अभिग्रहण के लिए एक पोर्टल विकसित करने का अनुरोध किया गया था।





पीएडीडी, क्यूसीआई ने 28 से 30 अगस्त, 2024 तक इंडगैप/ वीसीएसएमपीपी अनुपालन के लिए क्यूएमएस, एफएसएमएस और आईएसओ 19011 घटक पर तीन दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।



कृषि क्षमता का सशक्तीकरण : आंध्र प्रदेश में एफपीओ के क्षमता निर्माण पर चर्चा करने के लिए श्री एस. दिली राव, आईएएस से मुलाकात करते हुए पीएडीडी की टीम।

8.6 औषधीय पादप उत्पादों के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन योजना (वीसीएसएमपीपी)

8.6.1 भारत सरकार के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के आदेश पर, क्यूसीआई ने औषधीय पादप उत्पादों के लिए एक स्वैच्छिक प्रमाणन योजना विकसित और अभिकल्पित की है ताकि औषधीय पादपों के लिए उत्तम कृषि परिपाटियां (जीएपी) और उत्तम फील्ड संग्रहण परिपाटियां (जीएफसीपी) लागू की जा सकें।

8.6.2 पूरे भारत में कुल 100 प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे, जिनमें 6000 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त, 111 प्रजातियों के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसिज (पीओपी) विकसित किए गए। कुल 30 अवस्थानों पर प्रदर्शन भूखंड अभिनिर्धारित किए गए और उन्हें स्थापित किया गया, और अब तक 30 परियोजनाओं को प्रमाणित किया जा चुका है।

8.6.3 प्रभाग ने, 21 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में, औषधीय पादप उत्पादों के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन योजना (वीसीएसएमपीपी) विषय पर एक दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया।









21 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित औषधीय पादप उत्पादों के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन योजना (वीसीएसएमपीपी) पर एक दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला।

8.7 महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) के संरक्षण हेतु अनुरूपता आकलन प्रणाली और संसाधन का विकास

8.7.1 क्यूसीआई ने महत्वपूर्ण क्षेत्र की संस्थाओं की साइबर सुरक्षा के लिए एक अनुरूपता आकलन रूपरेखा (सीएएफ) विकसित की है, जिसमें एनसीआईआईपीसी योजना स्वामी (एसओ) होगा और क्यूसीआई की भूमिका राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय एवं योजना प्रबंधक की होगी और वह एनसीआईआईपीसी की ओर से योजना का प्रबंधन करेगा।

8.7.2 पीएडीडी ने साइबर सुरक्षा में सीआईआई के संरक्षण हेतु, अनुरूपता आकलन प्रणाली और संसाधनों के लिए विकसित योजनाओं के एक समुच्चय के अंतर्गत अनुमोदित निकायों को शामिल करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

8.7.3 16 जनवरी, 2025 को तकनीकी समिति (टीसी) की एक बैठक आयोजित की गई थी, और रूपरेखा के तहत चयनित संस्थाओं को वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया।

8.7.4 फिक्की द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय दूरसंचार विभाग के सहयोग से आयोजित साइबरकॉम 2025 में, क्यूसीआई के महासचिव श्री चक्रवर्ती टी. कन्नन ने भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करने में साइबर उत्थानशीलता के महत्व पर बल दिया। पीएडीडी के प्रमुख, डॉ. मनीष पांडे ने विकसित भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनुकूलनीय नीतियों और वैश्विक सहकार्य पर बल दिया।

8.7.5 प्रभाग ने महत्वपूर्ण क्षेत्र की संस्थाओं (सीएसई) में उत्थानशीलता को सुदृढ़ करने के लिए 30 साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें पूरे भारत से 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

8.7.6 टीयूवी एसयूडी दक्षिण एशिया, आईटी/आईसीएस साइबर सुरक्षा पेशेवरों के लिए कार्मिक प्रमाणन योजना के तहत, अस्थायी रूप से अनुमोदित प्रथम पीआरसीबी बना।





क्यूसीआई महासचिव, श्री चक्रवर्ती टी. कन्नन ने, साइबरकॉम 2025 (9 जनवरी, 2025, फिक्की, नई दिल्ली) में, साइबर उत्थानशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया, और विकसित भारत एवं भारत के डिजिटल भविष्य की नींव के रूप में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने की बात कही।





पीएडीडी प्रमुख डॉ. मनीष पांडे ने, साइबरकॉम 2025 (9 जनवरी, 2025, फिक्की, नई दिल्ली) में, क्यूसीआई के सीएएफ को रेखांकित किया, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा के लिए एक प्रमुख सक्षमताकारी तत्व है तथा विकसित भारत के लिए उत्थानशीलता का प्रेरक है।















महत्वपूर्ण क्षेत्र की संस्थाओं (सीएसई) में उत्थानशीलता को सुदृढ़ करने के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

8.8 रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट प्रमाणन स्कीम (आरएमसीपीसीएस)

8.8.1 क्यूसीआई ने रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) संयंत्रों में गुणवत्ता आश्वस्ति करने के लिए "आरएमसी प्लांट प्रमाणन स्कीम" शुरू की है। यह स्कीम, उद्योग के प्रमुख हितधारकों के सहकार्य से विकसित की गई है, जिसमें रेडी मिक्स कंक्रीट विनिर्माता संघ (आरएमसीएमए), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (बीएमटीपीसी), निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सीआईडीसी), सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एमईएस), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और जल संसाधन मंत्रालय शामिल हैं।

8.8.2 यह स्कीम दो प्रमाणन विकल्प प्रदान करती है, 'आरएमसी क्षमता प्रमाणन' और 'आरएमसी 9000+ क्षमता प्रमाणन', जिनमें से दूसरा विकल्प आईएसओ 9001 के अनुरूप है।

8.8.3 इस स्कीम के तहत, अब तक कुल 518 सक्रिय ग्राहक प्रमाणित किए गए हैं जिनमें अनंतिम रूप से अनुमोदित 2 प्रमाणन निकाय और 5 प्रत्यायित प्रमाणन निकाय शामिल हैं।

8.8.4 आरएमसीपीसीएस को अनेक प्रतिष्ठित निकायों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इनमें कर्नाटक और पुदुचेरी के लोक निर्माण विभाग, बृहन्मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको), महाराष्ट्र का जलसंपदा (जल संसाधन) विभाग, और डिज़ाइनट्री सर्विस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड तथा कॉनकॉन्स कंसल्टेंट्स कंसोर्शियम जैसी उल्लेखनीय निजी एजेंसियां शामिल हैं।

8.9 भारतीय चिकित्सा उपकरण प्रमाणन (आईसीएमईडी) स्कीम

8.9.1 देश में चिकित्सा उपकरणों के गुणवत्ता प्रमाणन क्षेत्र में तत्कालीन नियामक शून्यता को भरने के लिए, भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग संघ (एआईएमईडी) ने भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) के सहकार्य से चिकित्सा उपकरणों के लिए एक स्वैच्छिक गुणवत्ता प्रमाणन स्कीम शुरू की है।

8.9.2 जबकि आईसीएमईडी, क्यूएमएस पर केंद्रित था, वहीं क्यूसीआई ने इस स्कीम को आईसीएमईडी 13485 प्लस में अपग्रेड कर दिया है जो अब प्रत्येक चिकित्सा उपकरण को उसके उत्पाद प्रदर्शन के आधार पर प्रमाणन प्रदान करता है।

8.9.3 भारतीय भेषज संहिता आयोग (आईपीसी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, को अब आईसीएमईडी स्कीम के तहत एक प्रमाणन निकाय के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है।

8.9.4 आईसीएमईडी 13485 प्लस स्कीम के तहत, अब जेनिथ क्वालिटी असेसर्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुमोदित कर दिया गया है।

8.10 भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना:

8.10.1 क्यूसीआई, भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन परिषद् के सदस्यों में से एक है।

8.10.2 क्यूसीआई, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम) के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य कर रही है। इस भूमिका में भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन स्कीम (आईएफडब्ल्यूसीएस) के संवर्धन और प्रायोगिक कार्यान्वयन, अनुरूपता आकलन रूपरेखाएं विकसित करने, और प्रमाणन निकायों का क्षमता निर्माण शामिल है।

8.10.3 क्यूसीआई ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वामित्व वाली भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन स्कीम – प्रमाण (पीआरएमएएएन), को आगे बढ़ाने के लिए 5 अगस्त, 2024 को आईआईएफएम, भोपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

8.10.4. क्यूसीआई आईएफडब्ल्यूसी परिषद् में और इसके तहत गठित की गई तकनीकी समिति में अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करती है।





क्यूसीआई ने, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वामित्व वाली भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन स्कीम – प्रमाण (पीआरएमएएएन) को आगे बढ़ाने के लिए 5 अगस्त, 2024 को आईआईएफएम, भोपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

8.11 डिजिरेडी प्रमाणन

8.11.1 डिजिरेडी प्रमाणन (डीआरसी) पहल, भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के बीच एक सहकार्यात्मक प्रयास है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई संस्थाओं की डिजिटल रेडीनेस का आकलन और प्रमाणन करना है।

8.11.2 डीआरसी पोर्टल पर 2881 से अधिक प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक शामिल किया जा चुका है, और अब तक 755 से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं।

8.11.3 दिनांक 17-18 दिसंबर, 2024 को विक्रेता विकास कार्यक्रम (विक्रेता बैठक) के दौरान, एमएसएमई-विकास कार्यालय, जयपुर, राजस्थान में, डीआरसी जागरूकता अभियान आयोजित किए गए थे। इनमें आयोजित सत्र, डिजिरेडी प्रमाणन (डीआरसी) के माध्यम से, ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल होने के लाभों के बारे में एमएसएमई को शिक्षित करने पर केंद्रित थे, ताकि डिजिटल कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भागीदारी को सुगम बनाया जा सके।

8.11.4 डिजिटल रेडीनेस प्रमाणन परियोजना के अंतर्गत जनवरी और फरवरी माह में 28 एजेंसियों को संगठन संस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया, जिससे इस पहल की पहुंच और प्रभाव का आगे विस्तार हुआ।

8.11.5 डॉ. मनीष पांडे, निदेशक एवं प्रमुख, पीएडीडी- क्यूसीआई ने, बीएए इंडिया द्वारा आयोजित इंडिया सोर्सिंग कॉन्क्लेव 2025 में "अनुरूपता आकलन रूपरेखाओं के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं का सशक्तीकरण" विषय पर क्यूसीआई द्वारा संचालित सत्र का नेतृत्व किया। यह सत्र सभी हितधारकों के लिए ईएसजी अनुपालन पर केंद्रित था, जिसमें डिजिरेडी प्रमाणन (डीआरसी) के तहत एमएसएमई क्षमता निर्माण और डिजिटल परिवर्तन पर बल दिया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के साधिकार मंत्री श्री मुस्तफा एफ. शेखों ने की।





इंडिया सोर्सिंग कॉन्क्लेव 2025 में क्यूसीआई सत्र का नेतृत्व डॉ. मनीष पांडे ने किया, उन्होंने डीआरसी के तहत ईएसजी अनुपालन, एमएसएमई क्षमता निर्माण और डिजिटल परिवर्तन को रेखांकित किया।







एमएसएमई का सशक्तीकरण : डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा देने और ओएनडीसी में शामिल करने के लिए, एमएसएमई-विकास कार्यालय, जयपुर में आयोजित डीआरसी जागरूकता अभियान।

8.12 डिजिटल सक्षमता के निर्माण हेतु अनुरूपता आकलन रूपरेखा

8.12.1 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) के सरकारी अधिकारियों की डिजिटल सक्षमता को बढ़ाने के लिए एक अनुरूपता आकलन रूपरेखा विकसित करना।

8.12.2 यह रूपरेखा निम्नलिखित पर केंद्रित होगी : डिजिटल आयोजना और अभिकल्पना, डेटा प्रयोग और अभिशासन, डिजिटल प्रबंधन तथा क्रियान्वयन।

8.12.3 दिनांक 15 मार्च, 2025 को, चौथी तकनीकी समिति (टीसी) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तकनीकी

मापदंड दस्तावेज़ पर परस्पर सहमति बनी और उसके बाद अध्यक्ष द्वारा उसे अनुमोदन प्रदान किया गया।

8.12.4 दिनांक 29 मार्च, 2025 को, प्रमाणन समिति (सीसी) की पहली बैठक आयोजित की गई। इसमें अध्यक्ष द्वारा, अंतिम दस्तावेज़, जिसमें समिति की सभी प्रतिक्रियाएं शामिल थीं, को अनुमोदन प्रदान किया गया।



15 मार्च, 2025 को आयोजित, तकनीकी समिति (टीसी) की चौथी बैठक।



29 मार्च, 2025 को आयोजित, प्रमाणन समिति (सीसी) की पहली बैठक।



Strategy & Policy Division

QCI

9 रणनीति और नीति प्रभाग (एसपीडी)

9.1 संक्षिप्त विवरण

9.1.1 वर्ष 2020 में, क्यूसीआई में नीति यूनिट की स्थापना नीति निर्माण, निगरानी में निर्णयकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने, और लोक नीति के एक विषय के रूप में गुणवत्ता को समाहित करने के लिए की गई है। इस यूनिट ने संगठन को रणनीतिक विज़न प्रदान करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में गुणवत्ता कार्यसूची को प्रेरित करने का काम किया है। दिसंबर 2024 में, यह यूनिट रणनीति और नीति प्रभाग (एसपीडी) के रूप में विकसित हुई और इसने क्यूसीआई के 'रूपांतरण' अधिदेश के तहत काम करना आरंभ किया। यह प्रभाग आंतरिक बोर्डों और प्रभागों के साथ-साथ बाहरी हितधारकों को भी सेवाएं प्रदान करता है।

9.2 एसपीडी की संरचना और प्रकार्य

एसपीडी ने निम्नलिखित स्कंध विकसित किए हैं:

9.2.1 आंतरिक रणनीति स्कंध:

9.2.1.1 ग्राहक : क्यूसीआई के बोर्ड एवं प्रभाग

9.2.1.2. कार्यक्षेत्र:

- क्यूसीआई के रणनीति चक्र में सहायता करता है, जिसमें विज़न तैयार करना, सबलता-निर्बलता, अवसर-जोखिम (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण, और रणनीतिक प्राथमिकताएं तय करना शामिल हैं।
- सर्विस-लाइन रणनीति विकास में सहायता करता है।
- रणनीतिक क्षमताओं के साथ सहायता प्रस्तावित करता है (जैसे, कॅस्टमर अंतर्दृष्टि, सुगम बाज़ार रणनीति)
- विश्लेषण टीम: क्यूसीआई और उसके प्रभागों को डेटा विश्लेषण उपलब्ध कराती है।

9.2.2 इनक्यूबेटर:

9.2.2.1 ग्राहक : बाह्य हितधारक

9.2.2.2 कार्यक्षेत्र:

- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संबंधी स्थायी टीम: उद्योग और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी से संबंधित मामले) के लिए अवधारणाओं और पहलों का विकास करती है।
- अवधारणा विकास टीम: विभिन्न क्षेत्रों में अवधारणाओं और परिवर्तनकारी पहलों का परिपाक करती है और अवधारणाओं को प्रभावोन्मुख परियोजनाओं में परिवर्तित करने की क्षमताएं विकसित करती है।
- प्रत्यायित स्वास्थ्यचर्या संगठनों (एचसीओ) का वर्गीकरण करना – स्वास्थ्यचर्या प्रकार्य के तहत अंततः विलय के लिए सर्विस लाइन को आकार देने में मदद करना।

9.2.3 एक्सीलिरेटर (त्वरक):

9.2.3.1 ग्राहक : बाह्य हितधारक

9.2.3.2 कार्यक्षेत्र: अवधारणा विकास, प्रचार से उभरने वाली परियोजनाएं डिलीवर करता है अथवा विकसित भारत के लिए रणनीति विकास, रणनीतिक रूपांतरण और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित रखते हुए क्यूसीआई के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत करता है।

9.3 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान शुरू की गई प्रमुख पहलें और परियोजनाएं

9.3.1 आंतरिक रणनीति

9.3.1.1 रणनीति चक्र: उभरती आकांक्षाओं, सबलता-निर्बलता, अवसर-जोखिम (एसडब्ल्यूओटी), सीवीपी, रणनीतिक प्राथमिकताओं और पहलों की एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से बोर्डों और प्रभागों को अपनी आंतरिक रणनीति तैयार करने में सहायता करना।

9.3.1.2 हितधारक रणनीति/नेट प्रमोटर स्कोर (एनपीएस) कार्यान्वयन:

9.3.1.2.1 क्यूसीआई ने अपने बोर्डों और प्रभागों के लिए नेट प्रमोटर स्कोर (एनपीएस) प्राप्त करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यनीति कार्यान्वित की है, जिसकी शुरुआत एनएबीएच और एनएबीएल से हुई है। इस पहल का उद्देश्य, आंतरिक सेवा संदाय का आकलन और सुधार, हितधारकों की प्रतिक्रिया के माध्यम से आंतरिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना, और शिकायत निवारण एवं सेवा संवर्धन के लिए एक मानकीकृत रूपरेखा स्थापित करना है।

9.3.1.2.2 अपेक्षित परिणामों में शामिल हैं- बेहतर सेवा गुणवत्ता, डेटा प्रेरित निर्णयन, सुपरिभाषित एनपीएस रूपरेखा, और आंतरिक शिकायत निवारण के लिए अधिक जिम्मेदारीपूर्ण कार्यनीति।

9.3.1.3 स्वास्थ्यचर्या संगठनों (एचसीओ) का वर्गीकरण:

9.3.1.3.1 अपनी उपचार आवश्यकताओं के लिए स्वास्थ्यचर्या संगठनों का चयन करने में मरीजों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में 750 से अधिक मरीजों पर रोगी-अंतर्दृष्टि अध्ययन किया गया है। यह पाया गया है कि मरीजों को सूचना के विश्वसनीय स्रोत की आवश्यकता

होती है, जिसमें स्वास्थ्यचर्या संगठनों के गुणवत्ता पहलुओं से संबंधित आवश्यक जानकारी शामिल हो।

9.3.1.3.2 गुणवत्ता और निरंतरता को प्रेरित करने के लिए स्वास्थ्यचर्या संगठनों के वर्गीकरण हेतु एक रूपरेखा विकसित की गई है। स्वास्थ्यचर्या संगठनों का मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें एक ऑडिट स्कोर और ग्रेड (प्रत्यायन+, प्रत्यायन++, प्रत्यायन+++) प्रदान किया जाएगा।

9.3.1.3.3 मूल्यांकन विभिन्न श्रेणियों जैसे संरचना, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी प्रयोग, रोगी अनुभव, और परिणाम के मामले में मापनीय तत्वों पर आधारित होगा मानक और मूल्यांकन प्रक्रियाएं विकसित की जा रही हैं, और पायलट अध्ययन आयोजित किया जा चुका है।

9.3.1.3.4 संचालन समिति के सदस्यों द्वारा वर्गीकरण मानकों को अंतिम रूप दे दिया गया है और सार्वजनिक समीक्षा एवं टिप्पणियों के लिए इन्हें क्यूसीआई की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

9.3.1.3.5 भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाली गतिविधि सूची के साथ इसके आरंभ की योजना तैयार की गई। मई के पहले सप्ताह में पोर्टल शुभारंभ की योजना थी।

9.3.1.4 सुराज्य मान्यता 2.0 का उद्भव

9.3.1.4.1 सुराज्य मान्यता को वर्तमान में चार स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ये स्तंभ हैं - शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुशासन। सुराज्य मान्यता मासिक आधार पर, प्रत्येक स्तंभ में राज्यों द्वारा सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन और गुणवत्ता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

9.3.1.4.2 ईएसजी से संबंधित मापदंड शामिल किए जा चुके हैं। सुराज्य 2.0 के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। यह एक व्यापकतर रूपरेखा है, जो न केवल प्रगति का मापन करती है, बल्कि गुणवत्ता अभिशासन को बढ़ाती है, नीतिगत बदलावों को प्रेरित करती है और सतत विकास का संवर्धन करती है, और इस प्रकार से विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा को गति प्रदान करती है।

9.3.2 इनक्यूबेटर

9.3.2.1 फार्मा क्वालिटी एक्सीलेंस

9.3.2.1.1 भारत को 'विश्व की फार्मेसी' से वैश्विक गुणवत्ता फार्मेसी हब' बनाने के लिए, क्यूसीआई ने इस नव बाजार रणनीति (ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी) का इनक्यूबेशन शुरू किया है, ताकि भारतीय फार्मा उद्योग की चुनौतियों को समझा जा सके और उसके लिए नीतिगत अनुशंसाएं तैयार करने पर विमर्श किया जा सके। इस प्रयोजन से, एक गहन मूल्य श्रृंखला विश्लेषण किया गया और एमएसएमई मैट्रिक्स विकसित किया गया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय बैंचमार्किंग के साथ-साथ सरकारी सहायता, मूल्य श्रृंखला घटकों में भारत की स्थिति, समस्या वाले क्षेत्रों, विनियामक बाधाओं, रिपोर्टों और अनुशंसाओं का मानचित्रण किया गया।

9.3.2.1.2 विशेषज्ञों के साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली तैयार की गई और साक्षात्कार आयोजित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया, जिनमें समस्या समाधान किया जाना जरूरी है।

9.3.2.1.3 मांग पक्ष विश्लेषण आरंभ किया गया ताकि महामारी विज्ञान, जनसांख्यिकी, भौगोलिक, चिकित्सा संबंधी प्रमुख क्षेत्रों/प्रवृत्तियों का पता लगाया जा सके, जो घरेलू फार्मा उद्योग को 'विज़न 2047: विकसित भारत' के लिए तैयार होने में मदद कर सके।

9.3.2.1.4 फार्मा विनिर्माण में विनियामक और गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों पर हमारे शोध को आगे बढ़ाने के लिए, टीम ने लगभग 30 एमएसएमई विनिर्माताओं के साथ साक्षात्कार आयोजित किए थे, ताकि विनियामक और गुणवत्ता संबंधी उन चुनौतियों पर एमएसएमई के दृष्टिकोण को समझा जा सके, जिनका वे सामना करते हैं।

9.3.2.1.5 टीम ने फार्मा विनिर्माण भूदृश्य के लिए संभावित परिदृश्यों का मानचित्रण किया, ताकि विनिर्माण, औषधि नवाचार, मानव संसाधन विकास, किफायती और सुलभ दवाओं तथा फार्मा डिजिटलीकरण में प्रमुख क्षेत्रों/प्रवृत्तियों का अभिनिर्धारण किया जा सके।

9.3.2.2 एमएसएमई उत्कृष्टता

9.3.2.2.1 विकसित भारत के लिए एमएसएमई में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के समग्र दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, क्यूसीआई ने निम्नानुसार चहुं-आयामी रणनीति अपनाई है:

9.3.2.2.1.1 गुणवत्ता उत्कृष्टता: ज़ेड, लीन और आगामी ज़ेड-एक्स प्रमाणन से संबंधित क्यूसीआई की वर्तमान परियोजनाएं, रणनीति के इस स्तंभ का हिस्सा हैं। ये पहलें एमएसएमई को अपनी गुणवत्ता यात्रा शुरू करने में सक्षम बनाती हैं।

9.3.2.2.1.2 गुणवत्ता त्वरक : गुणवत्ता यात्रा के अंगीकरण में तीव्रता लाना और साथ ही एक एंकर ड्रिवेन इंटरवेंशन से उनकी गुणवत्ता संबंधी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना। क्यूसीआई द्वारा, ओईएमएस, सीओई, बड़ी फर्मों, मंत्रालय और अन्य हितधारकों के बीच सर्वांगीण सहकार्य को सक्षम बनाया जाता है, ताकि एमएसएमई को उनकी गुणवत्ता यात्रा में तेजी लाने में संबल प्रदान किया जा सके।

9.3.2.2.1.3 एमएसएमई के लिए सीवीपी: क्यूसीआई नवीनतम प्रौद्योगिकीय और गुणवत्ता उन्नयन जैसे ओसीईएन, यूएलआई आदि से जुड़ना सुगम बनाने के लिए हस्तक्षेपों का सृजन करेगा।

9.3.2.2.1.4 मांग सृजन: एमएसएमई द्वारा उत्पादित गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के लिए, उद्योग और सरकार से समर्थन सहित अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से मांग सृजन को सुगम बनाना।

9.3.2.2.2 एमएसएमई को नामित करने वाले ओईएम को शामिल करते हुए एक सर्वांगीण एंकर ड्रिवेन इंटरवेंशन एमएसएमई परियोजना तैयार की गई है और क्यूसीआई इन एमएसएमई को परामर्शदाताओं की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि उन एमएसएमई को विभिन्न पहलुओं पर संबल, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जा सके जो एमएसएमई के लिए समस्या बने हुए हैं।

9.3.2.2.3 इस परियोजना की रणनीति बनाई गई है और कार्यान्वयन के लिए इसे ज़ेड प्रभाग को सौंप दिया गया है।

9.3.2.3 गुजरात के लिए साहसिक पर्यटन

9.3.2.3.1 गीयर-अप (गुजरात एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर रिट्रीट) के तहत गुजरात के पर्यटन विभाग के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की गई, ताकि गुजरात को भारत के शीर्ष साहसिक खेल गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

9.3.2.3.2 यह रणनीति गुजरात के साहसिक पर्यटन परिदृश्य को सुदृढ़ करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के साथ तालमेल पर बल देती है, अवसंरचना में सुधार और सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता देती है, अन्य-पक्ष पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण करती है, और सेवा प्रदाताओं के प्रमाणन पर बल देती है।

9.3.2.3.3 एक 'सुगम बाजार रणनीति' भी विकसित की गई है, जिसमें गंतव्य-विशिष्ट अभियानों द्वारा राज्यव्यापी प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

9.3.2.3.4 इस पहल में, क्यूसीआई गुजरात के पर्यटन विभाग के लिए, ज्ञान और रणनीति भागीदार के रूप में कार्य करेगी, और राज्य के साहसिक पर्यटन प्रोफ़ाइल को बढ़ाने के लिए लक्षित प्रयासों को आगे बढ़ाएगी।

9.3.2.4 मेडिकल वैल्यू पर्यटन

9.3.2.4.1 भारत के चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र के लिए एक मजबूत रणनीति विकसित करने और चिकित्सा उद्योग की कमजोरियों (समस्या बिंदुओं) और अवसरों की पहचान करने हेतु एक क्षेत्र अध्ययन – विस्तृत क्षेत्र विश्लेषण किया गया।

9.3.2.4.2 क्षेत्र का सबलता-निर्बलता, अवसर-जोखिम विश्लेषण, सभी 20 केपीआई में रोगी की यात्रा का मानचित्रण और विश्लेषण सहित विस्तृत कंट्री बेंचमार्किंग के साथ व्यापक स्तर पर द्वितीयक अनुसंधान आरंभ किया गया है।

9.3.2.4.3 क्षेत्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के साथ भारत के मेडिकल वैल्यू पर्यटन पर तुलनात्मक अध्ययन करना, ताकि उनकी सर्वोत्तम परिपाटियों को समझा जा सके।

9.3.2.4.4 फ्यूचर-रेडी सिनारियो प्लानिंग - वैश्विक मेडिकल वैल्यू पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत के लक्ष्य को समझने के लिए सिनारियो प्लानिंग कार्य-पद्धति विकसित की गई।

9.3.2.4.5 फिक्की जैसे उद्योग संघों और मंत्रालय जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ संभावित सहकार्य की खोज की गई।

9.3.2.5 आईएसटीएम पर प्रशिक्षण सत्र

9.3.2.5.1 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान के ग्रुप 'ई' के अधिकारियों के लिए 'नीति में गुणवत्ता उत्कृष्टता' पर एक मॉड्यूल तैयार किया गया।

9.3.2.5.2 इस मॉड्यूल में नीति निर्माण या अभिशासन में विभिन्न चरणों को कैसे अपनाया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया।

9.3.2.5.3 हितधारक नीति निर्माताओं को साक्ष्य-आधारित निर्णयन में सक्षम बनाने वाली विभिन्न रूपरेखाओं के उपयोग को व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए, हितधारक पैरवी सिमुलेशन के साथ संवादात्कम सत्रों का आयोजन।

9.3.2.6 स्टार्टअप

9.3.2.6.1 भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की गहन समीक्षा की गई, ताकि इस क्षेत्र की दक्षता और समग्र विकास की गति को तेज करने के लिए, प्रमुख बाधाओं, अंतरालों और अवसरों की पहचान की जा सके।

9.3.2.6.2 'स्तंभ' (स्टार्टअप एक्सेलेरेटर मॉडल फॉर भारत) के तहत, कई रणनीतिक पहलों को अभिकल्पित और विकसित किया गया है। इस रणनीति का एक आधार परीक्षण आधार स्तंभ पहल है, जो परिपक्व स्टार्टअप्स को वास्तविक दुनिया के वातावरण में, अपने उत्पादों और सेवाओं को परिष्कृत और विधिमान्य करने का अवसर प्रदान करता है। यह पहल यूज़-केस मच्यूरेशन समूहों के गठन के माध्यम से स्टार्टअप-उद्योग से संपर्क को सुगम बनाती है।

9.3.2.6.3 डीपीआईआईटी और स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर औपचारिक साझेदारियों की संभावना तलाशी गई, जिसमें एक संभावित समझौता ज्ञापन भी शामिल है। इस सहकार्य का लक्ष्य, उद्योग-स्टार्टअप संपर्क को मज़बूत करना, और एक विशाल नेटवर्क तथा रिपॉजिटरी का लाभ उठाते हुए संपर्क-संवाद के प्रयासों का समर्थन करना है।

9.3.2.6.4 इसके अतिरिक्त, इस पहल की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता का मापन करने के लिए, क्षेत्र-विशिष्ट संपर्क-संवाद शुरू किया गया है। स्वास्थ्यचर्या क्षेत्र में, प्रमुख हितधारकों से उनकी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को समझने के लिए परस्पर संवाद किया गया। इसी प्रकार, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की अनूठी आवश्यकताओं के अनुकूल पहल तैयार करने के लिए, नवाचार केंद्रों के साथ संवाद शुरू किया गया है। भावी रणनीति का विकास - समग्र स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। इन्क्यूबेशन और एक्सीलेरेशन से परे, हर विकास चरण में स्टार्टअप के लिए एक व्यापक समर्थन प्रणाली तैयार करने और इनक्यूबेटर/एक्सीलेरेटर के लिए एक निगरानी एवं मूल्यांकन मॉडल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

9.3.2.7 उद्योग एवं आंतरिक व्यापार पर स्थायी टीम:

9.3.2.7.1 स्वायत्त संगठनों को डीपीआईआईटी की एसओएम बैठकों के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद, रणनीति और नीति प्रभाग ने, भारत सरकार में क्यूसीआई के नोडल पॉइंट को बेहतर समन्वय, तालमेल और परामर्श प्रदान करने के लिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार पर एक स्थायी टीम का गठन किया है।

9.3.2.7.2 वर्तमान में, इस टीम ने राष्ट्रीय मिशनों और पहलों (जैसे राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, केंद्रीय बजट पहलों) पर विकसित हो रही अवधारणाओं से अपना तालमेल बैठाया है।

9.3.2.7.3 नीति और रूपरेखा विकास पर कार्य करना (जैसे राष्ट्रीय गुणवत्ता नीति और अधिनियम, डिज़ाइन नीति 2.0)।

9.3.2.8 विश्वव्यापी अभिशासन संकेतक (डब्ल्यूजीआई) कार्यविधि का आलोचनात्मक विश्लेषण:

9.3.2.8.1 क्यूसीआई ने, विश्व बैंक की विश्वव्यापी अभिशासन संकेतक (डब्ल्यूजीआई) कार्यविधि का आलोचनात्मक विश्लेषण आरंभ किया है। इस आकलन में, डेटा स्रोतों की पहचान और वर्गीकरण, तथा पारदर्शिता, पूर्वाग्रहता, कार्यविधि एवं आलोचना जैसे मापदंडों का मूल्यांकन शामिल था। इसका परिणाम वर्तमान कार्यविधि से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए प्रमुख केंद्रीय प्रश्नों और वैकल्पिक डेटा स्रोतों के समुच्चय के रूप में सामने आया है।

9.3.2.9 भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों का त्वरण

9.3.2.9.1 केंद्रीय बजट घोषणा 2025 के आधार पर, क्यूसीआई ने एक अग्रगामी कार्यनीति अपनाई है और वर्तमान जीसीसी पारिस्थितिकी तंत्र का विश्लेषण किया है। साथ ही, विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए एक विज़न का निर्धारण किया है, ताकि भारत को दुनिया में जीसीसी के लिए सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य बनाया जा सके।

9.3.2.9.2 देश में जीसीसी से संबंधित व्यापक द्वितीयक अनुसंधान किया गया, प्रमुख टियर-1/2 शहरों में उनकी उपस्थिति का अध्ययन किया गया। साथ ही, टियर-2/3 शहरों में जीसीसी की असमान उपस्थिति के कारणों की पहचान की गई। विभिन्न देशों के मापदंडों का अध्ययन किया गया और उनके जीसीसी पारिस्थितिकी तंत्र का मानचित्रण किया गया। जीसीसी स्थापित करने हेतु किसी देश का चयन करने के लिए जिम्मेदार कारकों और जीसीसी यूनिट स्थापित करने के लिए, किसी शहर के चयन के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान की गई। किसी शहर की जीसीसी से संबंधित तत्परता को मापने के लिए, एक विस्तृत कारक सूची तैयार की गई है।

9.3.2.9.3 हितधारकों का मानचित्रण किया गया है ताकि उनके दृष्टिकोण और समस्या कथनों को समझने के लिए उनसे परामर्श किया जा सके।

9.3.2.9.4 बहुराष्ट्रीय कंपनियों, रियल एस्टेट से जुड़ी संस्थाओं आदि जैसे हितधारकों के साथ चर्चा की जाएगी। इन जानकारियों के आधार पर, विनियामक का प्रस्ताव करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

9.3.2.10 राष्ट्रीय डिज़ाइन नीति 2.0

9.3.2.10.1 डीपीआईआईटी के सहयोग से क्यूसीआई, व्यापक स्तर पर हितधारकों से परामर्श का काम कर रही है,

ताकि राष्ट्रीय डिज़ाइन नीति को नया रूप दिया जा सके। इसमें अकादमिक क्षेत्र, उद्योग जगत और सरकार के दर्जन भर से अधिक डिज़ाइन विशेषज्ञों से संपर्क-संवाद किया जाना शामिल है।

9.3.2.10.2 पहली विशेषज्ञ परामर्श बैठक 18 फरवरी, 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इस दौरान विशेषज्ञों ने नई डिज़ाइन नीति में विविध पहलुओं को एकीकृत करने पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसमें डिज़ाइन के माध्यम से स्थायित्व, संस्कृति, राष्ट्रीय ब्रांडिंग से लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और डिज़ाइन पार्क आदि की स्थापना शामिल हैं।

9.3.2.10.3 बैठक के बाद, विशेषज्ञों से प्राप्त विस्तृत जानकारी का विश्लेषण किया गया, ताकि इस कार्य से संबंधित आगे की कार्रवाई के लिए विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया जा सके। इन विचारार्थ विषयों के आधार पर, कई समूह और उप-समूह बनाए जाएंगे, जिनमें विशेषज्ञों को उनकी विशेषज्ञता और अनुभव के अनुसार मानचित्रित किया जाएगा।

9.3.2.11 यूरोपीय संघ के डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट (डीपीपी) के लिए भारत की तत्परता सुनिश्चित करना

9.3.2.11.1 आयात से संबंधित यूरोपीय संघ के ईएसपीआर एवं डीपीपी अधिदेश की प्रतिक्रिया में, क्यूसीआई ने एक अग्रगामी कार्यनीति अपनाई है, जिसका आशय ऐसी विनियामक नीति तैयार करना है, जो यूरोपीय संघ के लिए भारत के निर्यात को प्रभावित करती हो।

9.3.2.11.2 भारत के निर्यात प्रदर्शन पर गैर-अनुपालन के संभावित परिणामों को समझने के लिए, परिदृश्य-आधारित जोखिम मॉडलिंग का उपयोग किया गया। यह अध्ययन करने के लिए कि अन्य देश अभिशासन, क्रियान्वयन, और निजी क्षेत्र की भागीदारी में, डीपीपी कार्यान्वयन के लिए तैयारी कैसे कर रहे हैं, वैश्विक बेंचमार्किंग की गई। परिदृश्य नियोजन के माध्यम से रणनीतिक अवसरों का मानचित्रण किया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत किस प्रकार से प्रतिक्रियात्मक अनुपालन से पुरोगामी वैश्विक नेतृत्वशीलता की ओर बढ़ सकता है।

9.3.2.11.3 एक नीतिगत अवधारणा नोट तैयार किया गया, जिसमें व्यवस्थित रूप से आगे के कदमों की अनुशंसा की गई, ताकि डीपीआईआईटी को निर्णयन के लिए जानकारी दी जा सके और राष्ट्रीय स्तर की तैयारियों को समर्थन दिया जा सके।

9.3.2.12 ज्ञान भारतम् मिशन

9.3.2.12.1 केंद्रीय बजट 2025 की घोषणा के अनुसार, और संस्कृति मंत्रालय के साथ चल रहे संपर्क-संवाद के क्रम में, क्यूसीआई ने ज्ञान भारतम् मिशन का प्रारूप तैयार किए जाने की विधि बनाने की पहल की । पिछली परियोजनाओं से बनी साख का लाभ उठाते हुए, क्यूसीआई ने इस मिशन में मंत्रालय का समर्थन करने के लिए रणनीति विकसित करने हेतु आधारभूत कार्य शुरू किए।

9.3.2.12.2 वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक व्यापक बेंचमार्किंग कार्य किया गया, ताकि एक व्यवस्थित आधार प्रदान किया जा सके जो मिशन की अभिकल्पना, कार्यान्वयन, और प्रभाव मापन में मार्गदर्शन कर सके।

9.3.2.12.3 पांडुलिपि मूल्य श्रृंखला को आठ प्रमुख चरणों में मानचित्रित किया गया है, जिसमें सर्वेक्षण और प्रलेखन से लेकर रक्षण और परिरक्षण, डिजिटलीकरण, अनुवाद और व्याख्या, अनुसंधान और क्षमता निर्माण तक की गतिविधियां शामिल हैं। प्रत्येक चरण को विरासत संरक्षण और डिजिटल अभिलेखागार के लिए जानी जाने वाली सात प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पहलों के साथ बैंचमार्क किया गया है।

9.3.2.12.4 अगले चरणों में शामिल है - ज्ञान भारतम् मिशन के लिए संभावित मॉडलों और अभिशासन पथों की रूपरेखा दर्शाने वाली एक रणनीतिक रूपरेखा का मसौदा तैयार करना।

9.3.2.13 चक्रीय अर्थव्यवस्था पहल:

9.3.2.13.1 चक्रीय अर्थव्यवस्था पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करने पर बल।

9.3.2.13.2 प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:

- प्रत्यायन मॉडल: मानकों और प्रक्रियाओं के साथ एक प्रत्यायन मॉडल तैयार करना
- रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स : उपभोक्ता सशक्तीकरण के लिए एक रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स तैयार करना
- औद्योगिक सहजीवन: संसाधन साझा करने के लिए सहकार्य को बढ़ावा देना
- क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियां: विभिन्न क्षेत्रों में चक्रीयता के लिए कार्य योजनाएं विकसित करना
- सर्कुलर एक्सीलरेटर: सर्कुलर नवाचारों को मापने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करना
- डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट: उत्पाद ट्रेसेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जानकारी के लिए डिजिटल पासपोर्ट तैयार करना।

9.3.3 त्वरक

9.3.3.1 भारतीय डाक का रूपांतरण:

9.3.3.1.1 क्यूसीआई ने, भारतीय डाक के लिए एक रूपांतरकारी परिपक्वता मॉडल विकसित किया है, जिसका प्रभाव 1.64 लाख से अधिक डाकघरों पर होगा और डाकघरों के व्यापक नेटवर्क को सशक्त बनाएगा, जिसमें 2.4 लाख डाक सेवक शामिल हैं, ताकि सेवा की उत्कृष्टता और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

9.3.3.1.2 केंद्रीय बजट 2025 के अनुरूप, यह पहल भारतीय डाक का रणनीतिक परिवर्तन एक प्रमुख सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संस्था के रूप में सुगम बनाने में सहायक है, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में उसके योगदान में तीव्रता आएगी।

9.3.3.1.3 इस पहल का उद्देश्य डाक सेवकों सहित भारतीय डाक के नेटवर्क को सशक्त बनाना है, और एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स इकाई के रूप में इसके परिवर्तन को सुगम बनाना है। इस मॉडल का अभिकल्पन केंद्रीय बजट 2025 के अनुरूप और विकसित भारत में योगदान देने के लिए किया गया है।

9.3.3.1.4 यह मॉडल, भारतीय डाक की सेवा वितरण क्षमताओं का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने में सहायक होगा। फीडबैक लूप और आकलन चक्र समय में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसमें निरीक्षण और सेवोत्तम मॉडल से संबंधित मापदंडों को समाहित कर लिया गया है।

9.3.3.1.5 इसमें व्यावसायिक परिपक्वता, सर्वक्वाल मच्योरिटी, प्रक्रिया, कर्मचारी और कस्टमर डाइमेंशन शामिल हैं।

9.3.3.2 'मेड इन इंडिया' लेबल हेतु योजना:

9.3.3.2.1 'मेड इन इंडिया' लेबल के लिए बनाई गई स्कीम को, वर्तमान सरकार की 125-दिन की कार्यसूची में शामिल किया गया है।

9.3.3.2.2 इस स्कीम की अभिशासन संरचना, वित्तीय परिव्यय और भविष्य की रूपरेखा का विवरण देने वाला ईएफसी नोट समीक्षा के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को भेज दिया गया है।

9.3.3.2.3 स्कीम पर 20 मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त मंत्रि-समूह में सफलतापूर्वक चर्चा की गई है। बैठक में सभी मंत्रियों ने इस स्कीम की सराहना की और इसे शीघ्र ही लांच किया जाएगा।

9.3.3.2.4 यह पहल आगे बढ़ी है और भारतीय इस्पात संयंत्रों द्वारा "मेड इन इंडिया" लेबल लगाने की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इस स्कीम के लिए मापदंड विकसित किए जा चुके हैं, जो विनिर्माता की पहचान, मूल उत्पादक मापदंड और गुणवत्ता मापदंडों पर केंद्रित हैं। 13 मार्च, 2025 तक, इस्पात उत्पादों के लिए 1 करोड़ लेबल जारी किए जाने के साथ ही, इस स्कीम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है।

9.3.3.2.5 अगले महीने तक, यह नोट वित्त मंत्रालय और नीति आयोग सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों और निकायों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि उनके सुझाव प्राप्त किए जा सकें, जिन्हें तदनुसार शामिल किया जाएगा।

9.3.3.2.6 इसके अतिरिक्त, केवीआईसी के उत्पादों पर 'मेड इन इंडिया' लेबल लगाने के लिए, शीघ्र ही खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। लेबलिंग का आरंभ शहद उत्पादों से किया जाएगा।

भाग
3

HR



10 मानव संसाधन एवं प्रशासनिक गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा

10.1 क्यूसीआई लीडरशिप टीम

क) क्यूसीआई में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी

- श्री जक्षय शाह, अध्यक्ष, क्यूसीआई।
- श्री चक्रवर्ती टी. कन्नन, महासचिव, क्यूसीआई।

ख) क्यूसीआई के घटक बोर्डों के अध्यक्ष (मानद पद)

एनएबीएल - पद्मश्री प्रोफेसर सुब्बन्ना अय्यप्पन, चांसलर, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल; अध्यक्ष, कर्नाटक विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी, बेंगलुरु; और अनुषंगी प्रोफेसर, एनआईएएस, बेंगलुरु। दिनांक 18. 12. 2024 तक।

एवं

डॉ. संदीप शाह, संयुक्त प्रबंध निदेशक, न्यूबर्ग सुप्राटेक लैब, दिनांक 19.12.2024 से प्रभावी

एनएबीएच - दिनांक 05.05.2024 तक, पद्मश्री प्रोफेसर (डॉ) महेश वर्मा, कुलपति, जीजीएसआईपीयू

एवं

श्री रिज़वान कोइता, निदेशक, कोइता फाउंडेशन, दिनांक 06.05.2024 से प्रभावी

एनएबीईटी - श्री प्रेमेंद्र राज मेहता, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया के पूर्व अध्यक्ष

एनएबीसीबी - डॉ. आर.पी. सिंह, प्रोवोस्ट (कुलपति), अडाणी यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद

एनबीक्यूपी - श्री विपिन सोंधी, पूर्व एमडी और सीईओ, अशोक लेलैंड और जेसीबी इंडिया। पूर्व अध्यक्ष, आईआईएसईआर, भोपाल। अध्यक्ष: सीआईआई मिशन ऑन टेक, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड फ्यूचर मोबिलिटी

ग) क्यूसीआई के घटक बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

एनएबीएच	डॉ. अतुल मोहन कोचर
एनबीक्यूपी	डॉ. ऐश्वर्य राज
एनएबीईटी	प्रोफेसर (डॉ.) वरिन्दर एस कंवर
एनएबीसीबी	श्री राजेश माहेश्वरी
एनएबीएल	श्री एन वेंकटेश्वरन

घ) बोर्डों/प्रभागों/प्रकोष्ठों के प्रमुख

पीएडीडी	डॉ. मनीष पांडे, निदेशक
पीपीआईडी	श्री सुब्रतो घोष, प्रधान सलाहकार
एनडीआईई	डॉ. रामानंद एन. शुक्ल, वरिष्ठ निदेशक
एसपीडी	श्री रुद्रनील चट्टोपाध्याय, ग्रुप लीड

10.2 वित्त समिति

वित्त समिति का संघटन निम्नानुसार है:

वर्तमान संघटन

1. श्री विनोद शर्मा, प्रबंध निदेशक, डेकी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सदस्य, कार्यकारी समिति, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग संघ - अध्यक्ष
2. श्री हेमंत नवीनचंद्र शाह, अध्यक्ष, गुजरात चैप्टर, पीएचडीसीसीआई - सदस्य
3. श्री जितेंद्र ठक्कर, अध्यक्ष, सलाहकार परिषद (संविधान) एवं सदस्य कार्यकारी समिति - सदस्य
4. डॉ. संदीप शाह, अध्यक्ष, एनएबीएल - सदस्य
5. प्रभारी, (वित्त एवं लेखा) - पदेन

10.3 स्वीकृत पदों के सापेक्ष, भारतीय गुणवत्ता परिषद् में पदस्थ अधिकारियों का विवरण (31.03.2025 तक)

पद	पदस्थ
महासचिव	1
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	5
वरिष्ठ निदेशक	1
निदेशक	10
संयुक्त निदेशक	23
उप निदेशक	49
सहायक निदेशक	74

प्रत्यायन अधिकारी	39
कार्यकारी अधिकारी	36
कार्यकारी अधिकारी प्रशिक्षु	1
प्रशासनिक अधिकारी	7
वरिष्ठ कार्यकारी सहायक	1
कार्यकारी सहायक	5
लेखा अधिकारी	3
वरिष्ठ लेखाकार	1
वरिष्ठ कार्यालय सहायक	2
कुल	**258**

इसके अतिरिक्त, क्यूसीआई ने आवश्यकतानुसार, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अल्पावधि आधार पर विशिष्ट कौशल वाले पेशेवरों को भी नियुक्त किया है।

10.4 नियमित कर्मचारियों की पदोन्नति

रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित विवरण के अनुसार भारतीय गुणवत्ता परिषद् के 12 अधिकारी पदोन्नत किए गए-

पदोन्नत (किस पद से किस पद पर)	कर्मचारियों की संख्या
संयुक्त निदेशक से निदेशक	1
उप निदेशक से संयुक्त निदेशक	2
सहायक निदेशक से उप निदेशक	3
प्रत्यायन अधिकारी से सहायक निदेशक	6

10.5 शासी निकाय/शासी परिषद् की बैठकों का विवरण

शासी परिषद्	26वीं बैठक, 25 सितम्बर, 2024
शासी निकाय	75वीं बैठक, 10 जुलाई , 2024
	76वीं बैठक, 25 सितम्बर, 2024
	77वीं बैठक, 23 दिसम्बर, 2024
	78वीं बैठक, 27 मार्च, 2025

10.6 पदत्याग

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, क्यूसीआई के संस्वीकृत पदों पर कार्यरत 20 अधिकारियों को उनके संबंधित पदों से मुक्त (त्यागपत्र/ अधिवर्षिता/कार्यकाल पूरा होने के कारण) किया गया।

10.7 आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)

पीओएसएच अधिनियम, या कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, भारत में महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया एक कानून है। यह अधिनियम संगठनों को शिकायतों के समाधान के लिए नीतियां, पद्धतियां, और एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) स्थापित करने का अधिकार देता है।

इसके अनुरूप, क्यूसीआई में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया। इस समिति के सदस्यों की मुख्य भूमिका संगठन की महिला कर्मचारियों से संवाद स्थापित करना, जागरूकता पैदा करना, और उनकी समस्याओं (यदि कोई हो) को चिह्नित करना है। इस समिति के सदस्य निर्धारित समय अंतराल पर मिलते हैं और प्राप्त मामलों की समीक्षा करते हैं। इस अवधि में, महिला कर्मचारियों से तीन शिकायतें प्राप्त हुईं और उनका निपटारा निर्धारित समय के भीतर कर दिया गया।

आईसीसी का गठन :

श्रीमती मधु अहलूवालिया, वरिष्ठ सलाहकार, एनएबीईटी	अध्यक्ष
श्रीमती पूनम बजाज, निदेशक, एनएबीएच	सदस्य
श्रीमती मल्लिका गोप, निदेशक, एनएबीएल	सदस्य
डॉ हरि प्रकाश, निदेशक पीपीआईडी	सदस्य
श्रीमती वर्षा मिश्रा, उप निदेशक, एनएबीसीबी	सदस्य
श्रीमती पूजा शुक्ला, उप निदेशक, एनबीक्यूपी	सदस्य
श्रीमती मंजू बगई, विधिक परामर्शदाता	बाहरी विशेषज्ञ
श्रीमती स्मिता भारती, सहायक सलाहकार, नैतिकता प्रकोष्ठ	संयोजक

10.8 सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग

क्यूसीआई का हिंदी प्रकोष्ठ, परिषद् के कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देता है और अधिकारियों/ कर्मचारियों को दस्तावेजों के अनुवाद में सहायता प्रदान करता है। साथ ही, राजभाषा नीति आदि विषयों पर कार्यशालाओं आदि का आयोजन करता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, हिंदी प्रकोष्ठ ने पांच हिंदी कार्यशालाएं आयोजित कीं। इन कार्यशालाओं में 31 अधिकारियों और 38 कर्मचारियों ने भाग लिया और भारत सरकार की राजभाषा नीति, अपने दैनिक कार्यों में सरल हिंदी शब्दावली के प्रयोग और तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में जानकारी प्राप्त की।

परिषद् में दिनांक 14 से 29 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसमें 05 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। यह आयोजन अत्यंत सफल रहा और

इसमें परिषद् के कुल 226 पदाधिकारियों ने भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

वर्ष के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की 4 बैठकें आयोजित की गईं और हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई।

हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्टें, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के राजभाषा प्रभाग को प्रस्तुत की गईं।

समझौतों, विज्ञापनों, रिपोर्टों, प्रचार सामग्री, फ़्लायर्स आदि का समय पर अनुवाद उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए ताकि इन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किया जा सके।







वित्तीय वर्ष के दौरान क्यूसीआई में हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित प्रमुख गतिविधियों की झलक

10.9 महत्वपूर्ण गतिविधियों की अद्यतन स्थिति:

क) हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

एनएबीएल

- दिनांक 24 अप्रैल, 2024 को अहमदाबाद में, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

- इस समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य, पीएचडीसीसीआई से जुड़े सदस्यों के बीच एनएबीएल प्रत्यायन के बारे में जागरूकता पैदा करना है ताकि उनके उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।





एनएबीएल और पीएचडीसीसीआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- 26 सितंबर, 2024 को दिल्ली में, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) और भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् (ईईपीसी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।





एनएबीएल और ईईपीसी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

- एनएबीएल और भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स संघों के परिसंघ (क्रेडाई) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

  एनएबीएल ने 26 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में क्रेडाई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर एनएबीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एन. वेंकटेश्वरन और क्रेडाई के निर्वाचित अध्यक्ष श्री शंकर जी. पटेल ने माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल और क्यूसीआई के अध्यक्ष श्री जक्षय शाह की गरिमामय उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।



एनएबीएल और भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स संघों के परिसंघ (क्रेडाई) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

एनएबीएच

एनएबीएच ने, 12,000 से अधिक सदस्यों वाले, भारत के सबसे बड़े मधुमेह संघ, **'रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया' के साथ सहकार्य किया है।** समझौता ज्ञापन पर श्री रिज़वान कोइता (अध्यक्ष, एनएबीएच) और डॉ. अतुल मोहन कोचर (एनएबीएच के मुख्य कार्यकारी अधिकारी) ने हस्ताक्षर किए।

इस साझेदारी के तहत, आरएसएसडीआई और एनएबीएच-क्यूसीआई, तीन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग करेंगे:

- आरएसएसडीआई के देखभाल दिशानिर्देशों से तालमेल बैठाते हुए, एनएबीएच द्वारा, मधुमेह-विशिष्ट मानकों का विकास।
- इलेक्ट्रानिक मेडिकल रिकार्ड (ईएमआर) और क्लीनिक प्रबंधन प्रणालियों (सीएमएस) के लिए एनएबीएच द्वारा मधुमेह-विशिष्ट मानकों का विकास।
- समूचे आरएसएसडीआई सदस्य नेटवर्क में एनएबीएच एलोपैथिक क्लीनिक मानकों का क्रियान्वयन।
- गुजरात राज्य के अस्पतालों को टियर 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश स्तरीय प्रमाणन कार्यक्रम एवं आयुष प्रवेश-स्तरीय प्रमाणन कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एनएबीएच ने **एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई)** के साथ सहकार्य किया ताकि जागरूकता कार्यक्रम और क्षमता निर्माण से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जा सकें।
- **गुजरात सरकार के साथ एनएबीएच का सहकार्य-** एनएबीएच ने गुजरात सरकार को सफलतापूर्वक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनमें राज्य भर में स्वास्थ्यचर्या सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक रूपरेखा वर्णित की गई है।
- गुजरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 03 प्रस्ताव स्वीकार किए जा चुके हैं और कार्य आदेश प्राप्त हो चुके हैं।

एनएबीईटी

1. एमएसएमई लीन प्रभाग

- 01 अप्रैल, 2024 को, क्यूसीआई ने लघु उद्योग भारती के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, एमएसएमई मंत्रालय की एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन स्कीम की पहुंच अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ाने के लिए, लघु उद्योग भारती से जुड़े एमएसएमई के व्यापक नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा (लघु उद्योग भारती के, भारत भर के 27 राज्यों के 578 जिलों में, 52,000 से अधिक सदस्य हैं)।



मैसर्स लघु उद्योग भारती के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (1 अप्रैल, 2024)

- दिनांक 13 अगस्त, 2024 को, क्यूसीआई ने **आईआईए (भारतीय उद्योग संघ)** के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत, एमएसएमई मंत्रालय की एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन स्कीम की पहुंच

बढ़ाने के लिए,आईआईए से जुड़े एमएसएमई के व्यापक नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा (आईआईए के पास 50 से अधिक चैप्टर्स और 12000 एमएसएमई का व्यापक नेटवर्क है, जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और आसपास के राज्यों के अधिकांश औद्योगिकीकृत जिलों में फैला हुआ है।)



आईआईए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (13 अगस्त, 2024)

- दिनांक 5 सितंबर, 2024 को, क्यूसीआई ने एमएसएमई मंत्रालय की एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन स्कीम के लाभों को मोंटे कार्लो की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी एमएसएमई तक पहुंचाने के लिए, **मैसर्स मोंटे कार्लो** के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (मैसर्स मोंटे कार्लो की पूरे पंजाब में 200 से अधिक विक्रेताओं की एक व्यापक आपूर्ति श्रृंखला है)।



मैसर्स मोंटे कार्लो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (5 सितंबर, 2024)

- दिनांक 6 सितंबर, 2024 को, क्यूसीआई ने एमएसएमई मंत्रालय की एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन स्कीम के लाभों को मैसर्स एवन साइकिल्स की आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंचाने के लिए, **मैसर्स एवन साइकिल्स** के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (मैसर्स एवन साइकिल्स की पंजाब और बिहार राज्य में 200 से अधिक विक्रेताओं की एक व्यापक आपूर्ति श्रृंखला है)।



मैसर्स एवन साइकिल्स के साथ समझौता ज्ञापन (6 सितंबर, 2024)

- दिनांक 17 सितंबर, 2024 को, क्यूसीआई ने एमएसएमई मंत्रालय की एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन स्कीम के लाभों को **मैसर्स जे.के.टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड** की आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंचाने के लिए, मैसर्स जे.के. टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। (मैसर्स जे.के. टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूरे भारत में 200 से अधिक विक्रेताओं की एक व्यापक आपूर्ति श्रृंखला है।)



मैसर्स जे. के. टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (17 सितंबर, 2024)

- दिनांक 7 नवंबर, 2024 को, क्यूसीआई ने **अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल उत्कृष्टता केंद्र (आईएसीई)** के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ताकि ऑटोमोटिव क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सशक्त बनाया जा सके। यह समझौता एमएसएमई मंत्रालय की एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन स्कीम (एमसीएलएस) के तहत, लीन मैन्युफैक्चरिंग यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए ऑटोमोटिव क्षेत्र की इकाइयों को प्रेरित करेगा।



आईएसीई के साथ समझौता ज्ञापन (15 नवंबर, 2024)

- दिनांक 6 दिसंबर, 2024 को क्यूसीआई ने, एमएसएमई मंत्रालय की एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन स्कीम के लाभों को **मैसर्स फोर्ब्स मार्शल** की आपूर्ति श्रृंखला जो पूरे भारत में फैली हुई है, तक पहुंचाने के लिए मैसर्स फोर्ब्स मार्शल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



मैसर्स फोर्ब्स मार्शल के साथ समझौता ज्ञापन (6 दिसंबर, 2024)

2. औपचारिक शिक्षा उत्कृष्टता प्रभाग (एफईईडी प्रभाग)

- क्यूसीआई ने नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों के निरीक्षण के लिए **18 जून, 2024** को 3 वर्ष की अवधि के लिए **उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय** के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- क्यूसीआई ने क्वालिटी सिटी नासिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता हस्तक्षेप के लिए **7 अक्टूबर, 2024 को श्री श्यामलाल गुप्ता हिंदी विद्यालय, सतपुर** के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- क्यूसीआई ने **20 मार्च, 2025** को विद्यार्थियों के आकलन हेतु **कॉन्वेजीनियस डिजिटल इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

एनएबीसीबी

- एनएबीसीबी ने 19 मार्च, 2025 को एफएसएससी 22000 और एफएसएससी 24000 स्कीम के लिए एफएसएससी फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- एनएबीसीबी ने 3 फरवरी, 2025 को आईएससीसी प्रमाणन प्रणाली के लिए इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन (आईएससीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

पीएडीडी

- क्यूसीआई ने **22 अक्टूबर, 2024** को **ड्रोन प्रौद्योगिकी और प्रमाणन को आगे बढ़ाने** के लिए **आंध्र प्रदेश ड्रोन कॉर्पोरेशन** के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय गुणवत्ता परिषद्, भिन्न-भिन्न कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करना चाहती है। परिषद् का उद्देश्य अनुरूपता आकलन रूपरेखा के विकास एवं अभिकल्पन, प्रशिक्षण, प्रत्यायन सेवाएं प्रदान करने तथा स्थानीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं के क्षमता निर्माण में और अन्य सहमत गतिविधियों में सहयोग और सहकार्य विकसित करना है जो संस्थाओं के उद्देश्यों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाएं।

- क्यूसीआई ने **भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन स्कीम – 'प्रमाण' को आगे बढ़ाने के लिए 5 अगस्त, 2024 को भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम)** के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

  भारतीय गुणवत्ता परिषद् ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वामित्व वाली भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन स्कीम – 'प्रमाण' को आगे बढ़ाने के लिए आईआईएफएम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्यूसीआई भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन स्कीम (आईएफडब्ल्यूसीएस) के संवर्धन और संचालन, अनुरूपता आकलन रूपरेखा विकसित करने और प्रमाणन निकायों की क्षमता निर्माण में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम) के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में काम कर रही है।

- क्यूसीआई ने **13 मार्च, 2025 को प्रशिक्षण संस्था प्रत्यायन, शहर-स्तरीय हस्तक्षेप, चिकित्सा पर्यटन के संबंध में सहकार्य और कुशल पेशेवरों के प्रमाणन सहित कई पहलों के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ।**

- क्यूसीआई ने मार्च 2025 में **किसान ड्रोनों की स्वदेशी सामग्री के आकलन हेतु रूपरेखा तैयार करने में सहायता के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

  भारतीय गुणवत्ता परिषद् ने क्षमता निर्माण, कौशल विकास और बेहतर प्रमाणन एवं प्रत्यायन प्रणालियों के साथ उन्नत गुणवत्ता आश्वासन रूपरेखाओं के माध्यम से टिकाऊ कृषि के सुदृढ़ीकरण के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों और मशीनीकरण को भी यह समझौता ज्ञापन प्रोत्साहन देता है। इस सहकार्य का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में दक्षता, स्थायित्व और उत्थानशीलता बढ़ाना है।

एनडीआईई

- असम लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एएसआईडीसी), असम सरकार के साथ 17 मार्च, 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड सरकार के साथ 26 मार्च, 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- लुधियाना में मोंटे कार्लो और एवन साइकिल्स के साथ क्रमशः 5 सितम्बर, 2024 और 6 सितम्बर, 2024 को समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- मध्य प्रदेश में ज़ेड स्कीम का प्रचार-प्रसार करने के लिए 3 अक्टूबर, 2024 को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (एमपीएलयूएन) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

ख) सूचना का अधिकार

तिमाही	प्राप्त/हस्तांतरित/उत्तरित/अग्रेनीत किए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या (समय सीमा के भीतर)	प्राप्त/उत्तरित प्रथम अपीलों की संख्या
पहली तिमाही (01 अप्रैल, 2024 से 30 जून, 2024) जिसमें पहले से मौजूद आरटीआई भी शामिल हैं	87 (इसमें पहले से मौजूद 27 आरटीआई शामिल हैं)	10 (इसमें पहले से मौजूद 03 आरटीआई शामिल हैं)
दूसरी तिमाही (01 जुलाई, 2024 से 30 सितंबर, 2024)	62	06
तीसरी तिमाही (01 अक्टूबर, 2024 से 31 दिसंबर, 2024)	61	06
चौथी तिमाही (01 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025)	55	05
योग	**265**	**27**

ग) लोक शिकायत

सीपीजीआरएएमएस पर प्राप्त	लोक शिकायतों की संख्या	उत्तरित	प्राप्त अपीलों की संख्या	उत्तरित
पोर्टल से प्राप्त	35 (इसमें डीपीआईआईटी से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त 03 शिकायतें शामिल हैं)	33	07	07
अन्य विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त	0	0	0	0

घ) पारदर्शिता संपरीक्षा

एनपीसी द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए क्यूसीआई की पारदर्शिता संपरीक्षा की गई और उसके आधार पर क्यूसीआई को **ग्रेड ए (100%)** प्रदान किया गया।

10.10 अपने लोगों में निवेश- कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ाने के संबंध में आयोजित गतिविधियां:

क) प्रशिक्षण/ वेबिनार

- व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण/वेबिनार (ऑनलाइन)

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण की तारीख	प्रतिभागी
खाद्य साफ-सफाई और गुणवत्ता पर जागरूकता सत्र	14 नवंबर, 2024	120
व्यापारिक संचार	11 दिसंबर, 2024	240
भावनात्मक बुद्धिमत्ता	19 दिसंबर, 2024	155
नेतृत्व कौशल	10 जनवरी, 2025	184
व्यक्तित्व विकास	17 जनवरी, 2025	142
विवाद प्रबंधन	31 जनवरी, 2025	109
स्वामित्व और परिवर्तन अनुकूलनशीलता	07 फरवरी, 2025	96
प्राथमिकता निर्धारण और समय प्रबंधन	14 फरवरी, 2025	85
नैतिकता प्रबंधन	21 फरवरी, 2025	79
पारस्परिक कौशल	28 फरवरी, 2025	98
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यस्थल पर महिला नेतृत्व की सराहना	13 मार्च, 2025	97
दिन-प्रतिदिन कार्य-जीवन में समानुभूति	21 मार्च, 2025	69
	कुल योग	**1474**

ख) कौशल विकास कार्यक्रम

- कर्मचारियों के लिए डेटा एनालिटिक्स प्रमाणन पाठ्यक्रम (ऑफ़लाइन) - पाठ्यक्रम संरचना: 3 दिनों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 5 सत्र शामिल थे। पाठ्यक्रम पूरा होने के एक सप्ताह बाद, प्रतिभागियों की समझ और सामग्री के अनुप्रयोग का मूल्यांकन करने के लिए एक आकलन आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण की तारीख	प्रतिभागी
समन्वयकों के लिए डेटा एनालिटिक्स प्रमाणन पाठ्यक्रम	14 जनवरी, 2025 15 जनवरी, 2025 17 जनवरी, 2025	39
विश्लेषकों के लिए डेटा एनालिटिक्स प्रमाणन पाठ्यक्रम	18 फरवरी, 2025 19 फरवरी, 2025 20 फरवरी, 2025	34
सहायक प्रबंधकों के लिए डेटा एनालिटिक्स प्रमाणन पाठ्यक्रम	15 मार्च, 2025 16 मार्च, 2025 17 मार्च, 2025	34
कुल योग		**107**

ग) कर्मचारी सहभागिता गतिविधियां

- **नेत्र शिविर (24 सितम्बर - 16 अक्टूबर, 2024)** – कर्मचारियों के लिए अपनी स्वास्थ्य पहल के रूप में कर्मचारी निःशुल्क नेत्र देखभाल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निरश्रुता, मोतियाबिंद, रेटिना, वर्णांधता की जांच सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- **दिवाली (30 अक्टूबर, 2024)** – विभिन्न टीम-निर्माण गतिविधियों जैसे कि रंगोली बनाना, कार्यालय सजावट प्रतियोगिताएं, मिठाई बनाने की प्रतियोगिता, सर्वश्रेष्ठ पोशाक पुरस्कार आदि का आयोजन किया गया तथा कार्निवल खेलों और स्नैक्स के साथ दिवाली मेले का आयोजन किया गया जिससे कर्मचारियों में आपसी लगाव और उत्सव भावना को बढ़ावा मिला।
- **पुरुष दिवस (19 नवंबर, 2024)** – क्यूसीआई ने 19 नवंबर को आकर्षक दाढ़ी और साजसंवार चुनौती के साथ पुरुष दिवस सफलतापूर्वक मनाया। इसमें प्रतिभागियों ने विभिन्न दाढ़ी स्टाइल और हेयरकट प्रदर्शित किए, जिससे यह कार्यक्रम प्रभावी और मनोरंजक बन गया।
- **क्रिसमस (20 दिसंबर, 2024)** –'अपना क्रिसमस ट्री बनाएं', सीक्रेट सांता एक्सचेंज, और क्यूसीआई कर्मचारियों द्वारा त्यौहारी सेल जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिससे टीम भावना को बढ़ावा मिलने के साथ छुट्टियों का आनंद भी मिला।
- **कर्मचारी बैंकिंग लाभ (28 जनवरी - 4 फरवरी, 2025) और (19 - 20 मार्च, 2025)-** अनन्य बैंकिंग उत्पादों तक कर्मचारियों की पहुंच, वित्तीय योजना संसाधन, सेवानिवृत्ति बचत के विकल्प, गृह ऋण सहायता, व्यक्तिगत निवेश सलाह और बीमा सुरक्षा सहित कर्मचारियों को बैंकिंग के व्यापक लाभ प्रदान करने पर केंद्रित ये अभियान सफलतापूर्वक पूरे किए गए।
- **होली (12 मार्च, 2025) -** क्यूसीआई ने पर्यावरण अनुकूल हर्बल रंगों, पारंपरिक भोजन और संगीत के साथ एक जीवंत और समावेशी होली कार्यक्रम का आयोजन किया। इससे कर्मचारियों के बीच एकता प्रगाढ़ हुई, खुशी बढ़ी और यह कार्यक्रम अविस्मरणीय बन गया।

घ) सुशासन के लिए पहल

- **राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर, 2024)** – इस अवसर पर, एकता और एकजुटता दर्शाते हुए छोटे-छोटे स्लोगन साझा करने के लिए कार्मिकों को आमंत्रित करके राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया गया।
- **सतर्कता सप्ताह (30 अक्टूबर - 3 नवंबर, 2024) स्लोगन** - सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें संकल्प समारोह, बैनर प्रदर्शन, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता, वाद-विवाद/समूह चर्चा और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता शामिल हैं। इस सप्ताह के आयोजन से निष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत हुई। साथ ही, क्यूसीआई के सभी सदस्यों का आह्वान भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में हाथ मिलाने के लिए किया गया।
- **विश्व गुणवत्ता दिवस, (14 नवंबर, 2024)-** क्यूसीआई ने 14 नवंबर 2024 को विश्व गुणवत्ता दिवस वेबिनार की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इसका शीर्षक था 'खाद्य साफ-सफाई और गुणवत्ता पर जागरूकता सत्र', जिसमें मूलभूत खाद्य सुरक्षा परिपाटियों, संदूषण जोखिमों तथा खाद्य सुरक्षा में प्रमाणन और प्रत्यायन के महत्व पर चर्चा की गई।
- **संविधान दिवस (26 नवंबर, 2024)-** क्यूसीआई ने प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता के साथ सफलतापूर्वक संविधान दिवस मनाया। इसमें प्रतिभागियों ने भारत के संविधान, उसके इतिहास, मौलिक अधिकारों, सरकार की संरचना और देश के कानूनों को आकार देने वाले प्रमुख प्रावधानों के बारे में अपना ज्ञान परखा।
- **महिला दिवस (8 मार्च, 2025) -** अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 'महिला मिनी ओलंपिक 2025' सहित कई गतिविधियों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिला कर्मचारियों के लिए विभिन्न खेल गतिविधियां आयोजित की गईं। इसके अलावा, डॉ. उपासना द्वारा 'कार्यस्थल पर महिला नेतृत्वशीलता का उत्सव' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया और हमें प्रेरित करने वाली महिलाओं एवं सफलता की कहानियों को एकत्र करने के लिए एक सर्वेक्षण भी किया गया।







रंगोली बनाने की प्रतियोगिता







मिठाइयां बनाने की प्रतियोगिता



सर्वोत्तम पोशाक (पुरुष एवं महिला) प्रतियोगिता



भाग
4

11 वित्तीय विवरण

टी आर चड्ढा एंड कंपनी एलएलपी
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

भारतीय गुणवत्ता परिषद् के सदस्यों की सेवा में

राय

हमने, भारतीय गुणवत्ता परिषद् (''सोसाइटी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इनमें 31 मार्च, 2025 तक का तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं। वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे इसमें आगे ''वित्तीय विवरण सोसाइटी'' कहा गया है) भी शामिल है।

हमारी राय में, संलग्न वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार सोसाइटी की वित्तीय स्थिति और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का आगे वर्णन, हमारी इस रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां' खंड में किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार तथा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत, वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम सोसाइटी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं एवं आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रबंधन की है। उक्त वित्तीय विवरण, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, सोसाइटी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय कार्य-निष्पादन की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में सोसाइटी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस जिम्मेदारी में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हों, ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हों जो एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हों, और गंभीर मिथ्याकथन से मुक्त हों, चाहे वह मिथ्याकथन धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन, 'चालू प्रतिष्ठान' बने रहने की सोसाइटी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है और ऐसा करते हुए उसे, 'चालू प्रतिष्ठान' से जुड़े यथा-प्रयोज्य मामलों का और लेखांकन के 'चालू प्रतिष्ठान' आधार का उपयोग करने का प्रकटीकरण भी करना होगा जब तक कि प्रबंधन का इरादा या तो सोसाइटी के परिसमापन का अथवा सोसाइटी का संचालन बंद करने का न हो, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

सोसाइटी का प्रबंधन, सोसाइटी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण समग्र रूप से गंभीर मिथ्याकथन से मुक्त हैं या नहीं, चाहे वह मिथ्याकथन धोखाधड़ी से हुआ हो या त्रुटि के कारण और, साथ ही, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन का आशय, उच्च स्तर के आश्वासन से है, लेकिन यह आश्वासन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा से, किसी मौजूदा गंभीर मिथ्याकथन का पता हमेशा ही लग जाएगा। मिथ्याकथन, किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकते हैं और उन्हें गंभीर मिथ्याकथन तब माना जाता है जब, अलग-अलग या कुल मिलाकर, ऐसे गंभीर मिथ्याकथनों से, तर्कसंगत तौर पर यह संभावना बनती हो कि उनसे, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर शंका का भाव बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के गंभीर मिथ्याकथन, चाहे वे धोखाधड़ी से किए गए हों या गलती से, के जोखिमों का पता लगाना और उनका आकलन करना तथा इन जोखिमों के लिए प्रतिक्रियाशील

लेखापरीक्षा पद्धति की रूप-रेखा बनाना और उसे पूरा करना; तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्य और समुचित हों। धोखाधड़ी के फलस्वरूप होने वाले गंभीर मिथ्याकथन का पता न लग पाने का जोखिम, गलती से होने वाले मिथ्याकथन के जोखिम से कहीं अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जान-बूझकर की गई चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- मौजूदा परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ बनाना, परंतु इस समझ का प्रयोजन, सोसाइटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में राय व्यक्त करना नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के 'चालू प्रतिष्ठान' आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष भी निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों से जुड़ी ऐसी कोई गंभीर अनिश्चितता मौजूद है, जिससे 'चालू प्रतिष्ठान' के रूप में बने रहने की कंपनी की सक्षमता पर कोई गहरा संदेह पैदा होता हो। यदि हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी गंभीर अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में इससे संबंधित प्रकटनों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना होता है अथवा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों, तो अपनी राय को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष, लेखापरीक्षक की हमारी रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। फिर भी, भविष्य में होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के कारण ऐसी स्थिति बन सकती है, जिसमें कंपनी चालू प्रतिष्ठान बनी न रह सके।

- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना और यह देखना कि क्या इन वित्तीय विवरणों से अप्रकट लेन-देन और घटनाओं का प्रस्तुतीकरण इस तरह हो रहा है कि इससे समुचित प्रस्तुति सामने आ गई है।

वित्तीय विवरण में मिथ्याकथनों की गंभीरता अहम होती है, जिससे अलग-अलग अथवा कुल मिलाकर यह संभावना बनती है कि वित्तीय विवरण के पर्याप्त ज्ञानी प्रयोक्ता का आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्य-क्षेत्र की योजना बनाने में और (ii) वित्तीय विवरण में अभिनिर्धारित किसी मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक गंभीरता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम, प्रशासन से जुड़े प्राधिकारियों को, अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे और समय-सारणी के बारे में तथा लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में सूचित करते हैं। इसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल होती हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं।

हम, प्रशासन से जुड़े प्राधिकारियों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने निष्पक्षता के बारे में संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और हम, अपनी निष्पक्षता को संभावित रूप से प्रभावित करने वाले अपने सभी संबंधों एवं अन्य मामलों के बारे में, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों के बारे में भी सूचित करते हैं।

उपर्युक्त पैरा में दी गई टिप्पणी के अतिरिक्त, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने वह समस्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांग लिए और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख. हमारी राय में, जैसा कि लेखाबहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, सोसाइटी द्वारा विधि की अपेक्षानुसार उचित लेखाबहियां तैयार की गई हैं।

ग. इस रिपोर्ट में समीक्षित तुलन-पत्र, आय और व्यय तथा नकदी प्रवाह विवरण, सोसाइटी की लेखाबहियों के अनुरूप हैं।

कृते टी आर चड्ढा एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या - 006711N/N500028)

राजेन्द्र प्रसाद
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: 098941
यूडीआईएन: 25098941BMLMSJ1126

स्थान: नोएडा
दिनांक: 19-09-2025

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

तुलन पत्र

(समस्त धनराशि भारतीय रुपए में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
निधि के स्रोत			
I. निधि शेष			
कॉर्पस फंड	2	1,03,00,000	1,03,00,000
आरक्षित और अधिशेष	3	8,45,33,81,417	6,86,07,82,850
उप-योग (I)		**8,46,36,81,417**	**6,87,10,82,850**
II. गैर-वर्तमान देनदारियां			
दीर्घकालिक प्रावधान	4	24,36,01,624	21,67,37,821
उप-योग (II)		**24,36,01,624**	**21,67,37,821**
III. वर्तमान देनदारियां			
विविध लेनदार			
-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया		2,17,64,009	3,69,87,976
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		12,68,51,543	18,19,58,354
अव्ययित अनुदान	5	12,33,56,708	8,12,94,628
अल्पकालिक उधारी	6	2,35,00,00,000	-
अन्य वर्तमान देनदारियां	7	1,15,24,51,206	54,81,01,367
अल्पकालिक प्रावधान	8	6,09,43,578	3,43,01,374
उप-योग (III)		**3,83,53,67,044**	**88,26,43,699**
योग (I+II+III)		**12,54,26,50,085**	**7,97,04,64,370**
निधि के अनुप्रयोग			
I. गैर वर्तमान परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	9क	11,35,08,679	10,90,49,480
अमूर्त परिसंपत्तियां	9ख	19,71,000	26,28,001
चालू पूंजीगत कार्य	9ग	4,96,35,36,595	-
दीर्घकालिक निवेश	10	42,50,99,990	42,50,99,990
उप-योग (I)		**5,50,41,16,264**	**53,67,77,471**
II. वर्तमान परिसंपत्तियां			
विविध देनदार	11	84,04,20,253	96,70,77,473
नकदी और बैंक बैलेंस	12	5,31,18,25,801	5,75,00,98,434
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	13	71,05,04,707	56,81,07,114
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	14	17,57,83,060	14,84,03,878
उप-योग (II)		**7,03,85,33,821**	**7,43,36,86,899**
योग (I+II)		**12,54,26,50,085**	**7,97,04,64,370**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते टी आर चड्ढा एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 006711N/N500028

भारतीय गुणवत्ता परिषद् के लिए और उसकी ओर से

राजेन्द्र प्रसाद
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098941

स्थान: नोएडा
तारीख: 19-09-2025

चक्रवर्ती टी कन्नन
(महासचिव)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-09-2025

जक्षय शाह
(अध्यक्ष)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-09-2025

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

आय और व्यय लेखा

(समस्त धनराशि भारतीय रुपए में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
प्रचालन से राजस्व	15	6,26,04,35,017	5,69,37,40,823
अन्य आय	16	36,22,25,616	33,29,28,761
कुल आय: (क)		**6,62,26,60,633**	**6,02,66,69,584**
व्यय			
मानदेय और आकलन प्रभार		1,21,25,40,943	1,10,53,45,628
ब्याज व्यय		5,93,98,522	-
अनुदान व्यय		1,68,62,16,860	1,73,43,67,977
कर्मचारी हितलाभ व्यय	17	68,56,28,061	57,04,35,877
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	18	2,00,49,746	1,80,42,994
सामान्य और प्रशासनिक व्यय	19	1,36,62,27,934	1,33,99,17,503
कुल व्यय: (ख)		**5,03,00,62,066**	**4,76,81,09,979**
व्यय के मुकाबले में आय की अधिकता (आय के मुकाबले में व्यय की अधिकता) जिसे आरक्षित और अधिशेष में अंतरित किया गया	(क-ख)	**1,59,25,98,567**	**1,25,85,59,605**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **टी आर चड्ढा एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 006711N/N500028

राजेन्द्र प्रसाद
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098941

स्थान: नोएडा
तारीख: 19-09-2025

भारतीय गुणवत्ता परिषद् के लिए और उसकी ओर से

चक्रवर्ती टी. कन्नन
(महासचिव)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-09-2025

जक्षय शाह
(अध्यक्ष)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-09-2025

(इस स्थान को जानबूझकर खाली छोड़ा गया है।)

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

टिप्पणी 1: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

1.1 पृष्ठभूमि: सोसाइटी संबंधी सूचना

भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) ('सोसाइटी') का निगमन, 21 जनवरी, 1997 को 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी स्वायत्त सोसाइटी के रूप में किया गया था। यह सोसाइटी शिक्षा, स्वास्थ्यचर्या, पर्यावरण संरक्षण, अभिशासन, सामाजिक क्षेत्रों, अवसंरचना क्षेत्रों और संगठित गतिविधियों के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों सहित गतिविधियों के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों के प्रचार, अंगीकरण और पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिनका भारत के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में सुधार लाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सोसाइटी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कख (पूर्ववर्ती 12कक) के तहत दिनांक 11.03.2022 की विशिष्ट पंजीकरण संख्या AAATQ0055DE20217 के तहत पंजीकृत है। इसका उद्देश्य शिक्षा, चिकित्सा राहत, पर्यावरण संरक्षण (वाटरशेड, वन और वन्यजीव सहित) और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित किन्हीं अन्य उद्देश्यों की दिशा में काम करना है। यह पंजीकरण आकलन वर्ष 2022-23 से आकलन वर्ष 2026-27 तक मान्य है और हर पांच साल में इसका नवीकरण कराना होगा।

1.2 तैयारी का आधार

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों और गैर-लाभकारी संगठनों के लिए भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ये वित्तीय विवरण, संगठन के लिए प्रासंगिक समझी जाने वाली सीमा तक, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, उपार्जन आधार पर ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए जाते हैं।

ये वित्तीय विवरण 'चालू प्रतिष्ठान' आधार पर तैयार किए गए हैं और सोसाइटी द्वारा लेखांकन नीतियां, अन्यथा उल्लेख को छोड़कर, निरंतर रूप में लागू की गई हैं।

1.3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(क) आय को मान्य किया जाना

प्रबंधन द्वारा अंतिम वसूली का अनुमान लगाए जाने पर, राजस्व को उपार्जन आधार पर मान्य किया जाता है:

- आकलन और प्रत्यायन के लिए प्राप्त आवेदन शुल्क, प्राप्ति के आधार पर आय के रूप में मान्य किया जा रहा है।
- आकलन, प्रत्यायन प्रभार और परियोजना कार्यान्वयन से आय को तब मान्य किया जाता है जब इसे संबंधित बोर्डों/प्रभागों की तकनीकी समितियों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो।
- अनुदान को शुरू में देयता के रूप में मान्य किया जाता है। अनुदान आय को उसके उपयोग की सीमा तक आय के रूप में मान्य किया जाता है। अप्रयुक्त अनुदान को वर्तमान देयताओं के रूप में दिखाया जाता है।
- वार्षिक प्रत्यायन शुल्क को संबंधित प्रभागों/बोर्डों की तकनीकी समिति के अनुमोदन के बाद अनुरूपता आकलन निकाय (सीएबी) द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने पर मान्य किया जाता है।
- आयकर रिफंड पर ब्याज से भिन्न अन्य ब्याज आय को लेनदेन में निहित दर के आधार पर समय अनुपात विधि का प्रयोग करके मान्य किया जाता है।
- आयकर रिफंड पर ब्याज, प्राप्ति के आधार पर मान्य किया जाता है।

(ख) व्यय

व्यय को संबंधित बोर्ड/डिवीजनों की तकनीकी समितियों द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार मान्य किया जाता है।

अनुग्रह राशि का हिसाब नकद आधार पर रखा जा रहा है।

(ग) कॉर्पस फंड

'कॉर्पस फंड' संस्थापक सदस्यों/दाताओं द्वारा निगमन के समय योगदान की गई निधियों से संबंधित है, जो सोसाइटी के कॉर्पस का हिस्सा होगा।

(घ) निवेश:

दीर्घकालिक निवेश लागत पर अंकित किए जाते हैं। तथापि, निवेश के मूल्य में अस्थायी से इतर गिरावट को मान्य करने के लिए प्रावधान किया जाता है।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश लागत पर अंकित किया जाता है। तथापि, निवेश के मूल्य में अस्थायी से इतर गिरावट को मान्य करने के लिए प्रावधान किया जाता है।

वर्तमान निवेश : रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान निवेश, बाजार मूल्य के अनुसार अंकित किए जाते हैं।

(ङ) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और मूल्यह्रास

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उनके अधिग्रहण की लागत पर अंकित किए जाते हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, लागत में से किसी संचित मूल्यह्रास को घटाकर अंकित किए जाते हैं। लागत में खरीद मूल्य और अभीष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति को उसकी कामकाजी स्थिति में लाने पर आने वाली प्रत्यक्ष लागत शामिल है। खरीद मूल्य की गणना में, किसी भी व्यापार छूट एवं रियायत की कटौती की जाती है। नियत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आयकर नियम, 1962 के तहत अवलिखित मूल्य पद्धति पर निर्दिष्ट दरों पर प्रदान किया जाता है। मूल्यह्रास की दरें परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल के संकेतक हैं। मूल्यह्रास की दर इस प्रकार हैं:

- वाहन - 15%
- फर्नीचर और फिक्स्चर - 10%
- कार्यालय उपकरण - 15%
- कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर - 40%
- भवन - 10%

(च) अमूर्त परिसंपत्ति और परिशोधन

अलग से अधिगृहीत अमूर्त परिसंपत्ति का मापन, लागत के आधार पर प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों का अंकन, लागत में से किसी संचित परिशोधन को घटाकर किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन, अवलिखित मूल्य पद्धति पर आयकर नियम, 1962 के तहत विनिर्दिष्ट दरों पर प्रदान किया जाता है। परिशोधन की दरें परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल की संकेतक हैं। मूल्यह्रास की दर इस प्रकार हैं:

- ट्रेड-मार्क - 25%
- बौद्धिक संपदा अधिकार - 25%

(छ) विदेशी मुद्रा लेनदेन

प्रारंभिक मान्यीकरण:

विदेशी मुद्रा लेनदेन, रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किए जाते हैं और इसके लिए विदेशी मुद्रा राशि पर लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू की जाती है।

मुद्रा परिवर्तन:

विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को समापन दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है। गैर-मौद्रिक मदों को जो विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में दर्शाई जाती हैं, लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।

विनिमय अंतर:

मौद्रिक मदों के निपटारे पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, या सोसाइटी की ऐसी मौद्रिक वस्तुओं को उन दरों से अलग दरों पर रिपोर्ट करने पर जिन पर वे वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज की गई थीं, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई थीं, को उस वर्ष में आय के रूप में या व्यय के रूप में मान्य किया जाता है जिसमें वे सृजित होती हैं।

(ज) कर्मचारी हितलाभ:

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

सेवा प्रदान करने के बारह महीने के भीतर पूरी तरह से देय सभी कर्मचारी हितलाभों को अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वेतन, मजदूरी और बोनस आदि जैसे हितलाभ को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

परिभाषित अंशदान योजना:

परिभाषित अंशदान योजना, रोजगार के बाद की हितलाभ योजना है जिसके तहत कोई संस्था अलग-अलग संस्थाओं में एक निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और जिसके लिए, आगे की राशि का भुगतान करने का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजनाओं में, अंशदान के लिए दायित्वों को उस अवधि में होने वाले लाभ या हानि में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में मान्य किया जाता है जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

कंपनी, सरकार द्वारा प्रशासित भविष्य निधि योजना के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, में निर्दिष्ट मासिक अंशदान करती है। कंपनी के अंशदान को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

परिभाषित हितलाभ योजना, एक परिभाषित अंशदान योजना से इतर रोजगार के बाद की हितलाभ योजना है।

ग्रेच्युटी एक परिभाषित हितलाभ योजना है।

ग्रेच्युटी के प्रति सोसाइटी की देयता की गणना, तुलन-पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए

बीमांकित आकलन के आधार पर की जाती है। ग्रेच्युटी देयता की गणना, अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके की जाती है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी हितलाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई के सृजन के रूप में मान्य करती है और अंतिम दायित्व की गणना करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापती है। दायित्व को, भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। दायित्व के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली छूट दरें, तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार सरकारी बांड्स पर आने वाले बाजार प्रतिफल पर आधारित होती हैं, जिसमें परिपक्वता अवधि, संबंधित दायित्वों की अवधि के लगभग समान होती है। शुद्ध परिभाषित हितलाभ देयता का पुनर्मूल्यांकन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल होते हैं, को अन्य व्यापक आय विवरण में मान्य किया जाता है। किसी परिभाषित हितलाभ योजना या दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ की कटौती या निपटारे पर लाभ या हानि को तब मान्य किया जाता है जब कटौती या निपटारा होता है।

अन्य दीर्घकालिक लाभ

क्षतिपूर्त अनुपस्थिति:

कर्मचारीगण, अप्रयुक्त उपार्जित क्षतिपूर्त अनुपस्थिति के एक हिस्से को आगे ले जा सकते हैं और भविष्य की सेवा अवधियों में इसका उपयोग कर सकते हैं या रोजगार की समाप्ति पर नकद मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि क्षतिपूर्त अनुपस्थिति, उस अवधि की समाप्ति के बाद बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय नहीं हो जाती जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं और ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद, बारह महीनों के अंदर पूरी तरह से इनके उपयोग किए जाने की उम्मीद नहीं होती है, इसलिए हितलाभ को दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सोसाइटी, उस अवधि में ऐसी क्षतिपूर्त अनुपस्थिति के लिए एक दायित्व दर्ज करती है जिसमें कर्मचारी इस पात्रता को बढ़ाने वाली सेवाएं प्रदान करता है। दायित्व को अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके, स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है।

अधिवर्षिता:

सोसाइटी हर साल वार्षिक मूल वेतन का 15%, प्रत्येक कर्मचारी के खाते में अंशदान के रूप में देती है और इस राशि को उपार्जन आधार पर मान्य किया जाता है। अधिवर्षिता आरक्षित निधि एलआईसी में रखी जाती है और भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों से शासित होती है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को किए जाने वाले अंशदान को हिसाब में लिया जाता है।

(झ) वर्तमान कर और आस्थगित कर

सोसाइटी को आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 12कक के तहत आयकर से छूट प्राप्त है और तदनुसार कराधान के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। चूंकि सोसाइटी आयकर से मुक्त है, इसलिए समय अंतर के संबंध में किसी आस्थगित कर (परिसंपत्ति या देयता) को मान्य किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ञ) प्रावधान और आकस्मिकताएं

सोसाइटी कोई प्रावधान तब करती है जब अतीत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व बनता है जहां आर्थिक संसाधनों का बहिर्गमन संभावित होता है और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब:

- संभावित दायित्व बनता हो, जिसके अस्तित्व की पुष्टि एक या एक से अधिक ऐसी अनिश्चित घटनाओं के घटने/ न घटने से की जाएगी, जो पूरी तरह से सोसाइटी के नियंत्रण में नहीं हैं;
- वर्तमान दायित्व हो, जहां यह संभावना न हो कि दायित्व के निपटारे के लिए आर्थिक हितलाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी;
- वर्तमान दायित्व बनता हो, जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ट) अनुमानों का उपयोग

आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान लगाने और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की संसूचित राशि और वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संचालन के परिणामों को प्रभावित करती हैं। यद्यपि ये अनुमान, वर्तमान घटनाओं और कार्यों के, प्रबंधन के ज्ञान पर आधारित होते हैं, तथापि वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और संशोधन, यदि कोई हों, को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में मान्य किया जाता है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(आईसीएआई लेखांकन मानक-3 के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया)

(समस्त धनराशि भारतीय रुपए में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
क	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	कर पूर्व अधिशेष और असाधारण मदें	**1,59,25,98,567**	**1,25,85,59,605**
	गैर-नकदी और गैर-प्रचालनरत मदों के लिए समायोजन		
	जोड़ें: मूल्यह्रास	2,00,49,746	1,80,42,994
	घटाएं: ब्याज से आय	(36,22,25,616)	(33,29,28,761)
	जोड़ें: ब्याज पर व्यय	(5,93,98,522)	-
	जोड़ें : ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान में वृद्धि	2,03,36,625	82,77,718
	जोड़ें: अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान में वृद्धि	2,56,30,516	1,57,76,556
	जोड़ें: अधिवर्षिता के लिए प्रावधान में वृद्धि	75,38,866	22,38,603
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन अधिशेष	1,36,33,27,226	96,99,66,715
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों के लिए समायोजन		
	विविध देनदारियों में (वृद्धि)/ गिरावट	12,66,57,220	(9,91,23,108)
	ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/ गिरावट	(14,23,97,593)	(3,42,12,658)
	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/गिरावट	(4,02,75,145)	(4,03,14,001)
	फुटकर लेनदारियों में वृद्धि/ (गिरावट)	(7,03,30,778)	14,57,30,779
	अव्ययित अनुदानों में वृद्धि/ (गिरावट)	4,20,62,080	(6,50,512)
	अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि/ (गिरावट)	60,43,49,839	32,06,36,999
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**1,88,33,92,849**	**1,26,20,34,214**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	नियत परिसंपत्तियों की खरीद	(4,98,73,88,539)	(2,70,98,393)
	जोड़ें: नियत परिसंपत्तियों की बिक्री से आय	-	-
	निवेश खरीद	-	(30,00,00,000)
	सावधि जमा से/(को) आय	2,09,96,79,051	1,22,45,97,604
	जोड़ें: प्राप्त ब्याज	37,51,21,579	34,46,26,044
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(2,51,25,87,909)**	**1,24,21,25,255**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	दीर्घकालिक उधारी से आय	2,35,00,00,000	
	घटाएं: अदा किया गया ब्याज	5,93,98,522	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**2,29,06,01,478**	-
घ	**नकदी और नकदी समवस्तुओं में निवल वृद्धि/ (गिरावट)**		
	नकदी और नकदी समवस्तुओं में वृद्धि (क+ख+ग)	**1,66,14,06,418**	**2,50,41,59,469**
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समवस्तुएं	3,14,99,07,849	64,57,48,380
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समवस्तुएं	**4,81,13,14,267**	**3,14,99,07,849**

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **टी आर चड्ढा एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 006711N/N500028

भारतीय गुणवत्ता परिषद् की ओर से और उसके लिए

राजेन्द्र प्रसाद
भागीदार
सदस्यता संख्या 098941

स्थान: नोएडा
तारीख: 19-09-2025

चक्रवर्ती टी कन्नन
(महासचिव)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-09-2025

जक्षय शाह
(अध्यक्ष)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-09-2025

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

आय और प्राप्ति लेखा

(समस्त धनराशि भारतीय रुपए में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

प्राप्ति	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक शेष			**व्यय**		
बैंकों में शेष राशि			मानदेय और आकलन प्रभार	1,21,25,40,943	49,06,45,957
- बचत खातों में	1,56,89,64,271	61,10,83,111	ब्याज पर व्यय	5,93,98,522	-
- चालू खातों में	4,85,40,808	2,94,83,974	परियोजना व्यय	-	1,02,42,99,532
- बैंक जमाओं में	4,13,25,44,006	3,82,98,34,798	कर्मचारी हितलाभ व्यय	68,56,28,061	55,08,60,826
हाथ में नकदी	49,349	1,34,686	सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय	1,36,62,27,934	61,32,18,674
			अनुदान व्यय	1,68,62,16,860	2,07,10,41,995
	5,75,00,98,434	**4,47,05,36,569**		**5,01,00,12,320**	**4,75,00,66,985**
आय					
प्रचालनों से राजस्व	6,26,04,35,017	5,69,37,40,823			
अन्य आय			नियत परिसंपत्तियों की खरीद	2,38,51,944	2,70,98,393
निम्नलिखित से ब्याज आय			निवेश खरीद	-	30,00,00,000
- बैंकों में सावधि जमा	32,47,36,432	30,21,69,810	चालू पूंजीगत कार्य	4963536595	
- आय कर रिफंड	1,46,37,040	1,04,35,809			
- अन्य	1,99,42,226	2,03,23,141			
विविध आय	29,09,918				
पुनरांकित देनदारियां	-	-			
	6,62,26,60,633	**6,02,66,69,584**		**4,98,73,88,539**	**32,70,98,393**
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री से आय	-	-	**अंत शेष**		
		-	बैंकों में शेष राशि		
परिसंपत्तियों/देनदारियों में परिवर्तन			- बचत खातों में	1,57,84,81,418	1,56,89,64,271
ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अधिवर्षिता निधि	5,35,06,007	2,62,92,877	- चालू खातों में	3,39,21,472	4,85,40,808
फुटकर लेनदारियां	(7,03,30,778)	14,57,30,779	- बैंक जमाओं में	3,69,92,65,045	4,13,25,44,005
अन्य वर्तमान देनदारियां	60,43,49,839	32,06,36,999	हाथ में नकदी	1,57,861	49,349
अग्रिम रूप से प्राप्त राजस्व	*9,58,86,661*	*13,27,45,853*		**5,31,18,25,796**	**5,75,00,98,433**
समाधान के लिए लंबित प्राप्तियां	*(42,00,375)*	*1,31,50,324*			
देय व्यय	*46,41,43,454*	*(1,22,224)*			
सांविधिक देयताएं	*4,59,88,794*	*17,56,89,064*			
कर्मचारियों से संबंधित देय राशि	*27,56,457*	*(45,60,444)*			
अन्य देय राशियां	*(2,25,151)*	*37,34,426*			
अव्ययित अनुदान	4,20,62,080	(6,50,512)			
फुटकर देनदार	12,66,57,216	(9,91,23,110)			
अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	(14,23,97,593)	(3,42,12,657)			
स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम	*50,67,845*	*(13,41,534)*			
विक्रेताओं को अग्रिम	*(52,54,089)*	*(2,52,27,722)*			
पूर्वदत्त व्यय	*(8,33,67,212)*	*1,41,68,068*			
सरकारी प्राणिकरणों के पास शेष	*1,24,08,124*	*93,97,224*			
स्रोत पर काटा गया कर	*(7,12,52,262)*	*(3,12,08,693)*			
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(2,73,79,182)	(2,86,16,718)			
प्रतिभूति जमा	*(4,02,75,145)*	*(4,03,14,001)*			
बैंकों में जमा राशि पर उपार्जित ब्याज	*1,28,95,963*	*1,16,97,283*			
अल्पकालिक उधारी	*2,35,00,00,000*	-			
चालू पूंजीगत कार्य	-	-			
नियत परिसंपत्तियों का समायोजन	-	-			
	2,93,64,67,588	**33,00,57,658**		**15,30,92,26,654**	**10,82,72,63,811**
योग	**15,30,92,26,655**	**10,82,72,63,811**	**योग**		

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते टी आर चड्ढा एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 006711N/N500028

राजेन्द्र प्रसाद
भागीदार
सदस्यता संख्या : 098941

स्थान: नोएडा
तारीख: 19-09-2025

भारतीय गुणवत्ता परिषद की ओर से और उसके लिए

चक्रवर्ती टी कन्नन
(महासचिव)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-09-2025

जक्षय शाह
(अध्यक्ष)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-09-2025

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(समस्त धनराशि भारतीय रुपए में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
टिप्पणी 2		
कॉपस निधि		
वर्ष के आरंभ में शेष	1,03,00,000	1,03,00,000
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन अथवा विलोपन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**1,03,00,000**	**1,03,00,000**
टिप्पणी 3		
आरक्षित और अधिशेष		
वर्ष के आरंभ में शेष	6,86,07,82,850	5,60,22,23,245
जोड़ :आय एव व्यय खात स अतारत व्यय क मुकाबल आधक आय	1,59,25,98,567	1,25,85,59,605
वष क अत म शष	**8,45,33,81,417**	**6,86,07,82,850**
टिप्पणी 4		
दीर्घकालिक प्रावधान		
कर्मचारियों के हितलाभ के लिए प्रावधान		
ग्रेच्युटी	9,99,11,943	8,83,16,844
अर्जित अवकाश का नकदीकरण	14,36,89,681	12,84,20,977
योग	**24,36,01,624**	**21,67,37,821**
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		
वर्तमान देयताएं (अल्पकालिक प्रावधान टिप्पणी 8 में दिखाया गया है)	1,09,87,047	22,45,521
गैर-वर्तमान देयताएं (दीर्घकालिक प्रावधान टिप्पणी 4 में दिखाया गया है)	9,99,11,943	8,83,16,844
	11,08,98,990	**9,05,62,365**
अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए प्रावधान		
वर्तमान देयताएं (अल्पकालिक प्रावधान टिप्पणी 8 में दिखाया गया है)	1,26,16,430	22,54,618
गैर-वर्तमान देयताएं (दीर्घकालिक प्रावधान टिप्पणी 4 में दिखाया गया है)	14,36,89,681	12,84,20,977
	15,63,06,111	**13,06,75,595**
टिप्पणी 5		
अव्ययित अनुदान #		
सरकारी अनुदान	12,26,33,210	8,05,71,130
अन्य अनुदान	7,23,498	7,23,498
योग	**12,33,56,708**	**8,12,94,628**
# विवरण के लिए टिप्पणी 26 देखें।		
टिप्पणी 6		
अल्पकालिक उधारी		
जमानती ऋण		
आवधिक ऋण		
आईसीआईसीआई बैंक से*	2,35,00,00,000	-
	2,35,00,00,000	

*सोसायटी ने अपनी कार्यशील पूंजी जरूरतों को पूरा करने, अल्पकालिक वित्तीय अंतर को भरने और सामान्य पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण हेतु धनराशि जुटाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण लिया है। रेपो रेट ही इस ऋण पर ब्याज दर होगी और यह सम्मत अवधि के लिए होगा। इस ऋण को व्यापार से प्राप्त होने वाली आय, बैंक में शेष राशि और सावधि जमा राशि सहित सोसायटी की समस्त वर्तमान परिसंपत्तियों पर हाइपोथिकेशन प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

टिप्पणी 7		
अन्य वर्तमान देनदारियां		
अग्रिम रूप से प्राप्त राजस्व	31,62,36,254	22,03,49,593
समाधान के लिए लंबित प्राप्तियां *	2,13,92,604	2,55,92,979
देय व्यय	46,50,77,454	9,34,000
सांविधिक देय	33,88,63,969	29,28,75,175
कर्मचारियों से संबंधित देय	41,83,325	14,26,868
अन्य देय	66,97,600	69,22,751
योग	**1,15,24,51,206**	**54,81,01,367**

टिप्पणी:

* यह कॉलम ऐसी प्राप्तियों और संबंधित आदाता को दर्शाता है, जहां प्राप्तियों के प्रयोजन की पहचान बैलेंस शीट की तारीख को नहीं हो पाई है। सोसायटी इन प्राप्तियों और इनसे संबंधित आदाता की पहचान और मिलान की प्रक्रिया में है। प्रबंधन का विचार है कि इसका मिलान उचित समय पर कर लिया जाएगा।

टिप्पणी 8		
अल्पकालिक प्रावधान		
कर्मचारियों के हितलाभ के लिए प्रावधान :		
ग्रेच्युटी	1,09,87,047	22,45,521
अर्जित अवकाश का नकदीकरण	1,26,16,430	22,54,618
अधिवर्षिता	3,73,40,101	2,98,01,235
योग	**6,09,43,578**	**3,43,01,374**

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(समस्त धनराशि भारतीय रुपए में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

टिप्पणी 9क

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

विवरण	भूमि	भवन	कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर	फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	वाहन	योग
1 अप्रेल 2023 को शेष	1,15,50,176	3,59,50,376	86,97,321	2,58,57,557	1,63,69,392	6,93,258	9,91,18,079
परिवर्धन	-	-	1,27,05,873	52,96,782	90,95,738	-	2,70,98,393
निपटानों से आय	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास प्रभार	-	35,95,038	72,37,176	28,68,076	33,62,714	1,03,988	1,71,66,992
31 मार्च 2024 को शेष	**1,15,50,176**	**3,23,55,338**	**1,41,66,018**	**2,82,86,263**	**2,21,02,416**	**5,89,270**	**10,90,49,480**
परिवर्धन	-	-	1,19,01,184	29,60,169	65,49,342	24,37,730	2,38,51,944
निपटानों से आय	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास प्रभार	-	32,35,534	1,04,22,782	30,50,438	39,82,961	2,71,221	1,93,92,745
31 मार्च 2025 को शेष	**1,15,50,176**	**2,91,19,804**	**1,56,44,420**	**2,81,95,994**	**2,46,68,797**	**27,55,779**	**11,35,08,679**

टिप्पणी 9ख

अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	ट्रेडमार्क्स	बौद्धिक संपदा अधिकार	योग
1 अप्रेल 2023 को शेष	1,12,660	33,91,343	35,04,003
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-
वर्ष के लिए परिशोधन	28,165	8,47,837	8,76,002
31 मार्च 2024 को शेष	**84,495**	**25,43,506**	**26,28,001**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-
वर्ष के लिए परिशोधन	21,124	6,35,877	6,57,001
31 मार्च 2025 को शेष	**63,371**	**19,07,629**	**19,71,000**

टिप्पणी 9ग

चालू पूंजीगत कार्य

विवरण	चालू पूंजीगत कार्य	योग
1 अप्रेल 2023 को शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के लिए परिशोधन	-	-
31 मार्च 2024 को शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,96,35,36,595	4,96,35,36,595
वर्ष के लिए परिशोधन	-	-
31 मार्च 2025 को शेष	**4,96,35,36,595**	**4,96,35,36,595**

(इस स्थान को जानबूझकर खाली छोड़ा गया है।)

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(समस्त धनराशि भारतीय रुपए में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
टिप्पणी 10		
दीर्घकालिक निवेश		
अनकोटेड इक्विटी शेयरों में निवेश (लागत पर मापा गया)		
सहायक कंपनी में निवेश (100% सहायक)*		
उन्नति रोजगार नेटवर्क के 10-10 रुपए मूल्य के पूरी तरह से चुकता 25,09,999 इक्विटी शेयर	2,50,99,990	2,50,99,990
एसोसिएट में निवेश*		
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के 100-100 रुपए के पूरी तरह से चुकता 40,00,000 इक्विटी शेयर (भारतीय गुणवत्ता परिषद् द्वारा प्रवर्तित)	40,00,00,000	40,00,00,000
योग	**42,50,99,990**	**42,50,99,990**
*टिप्पणी संख्या 27 देखें		
टिप्पणी 11		
विविध देनदार		
अरक्षित, प्राप्य माने गए	84,04,20,253	96,70,77,473
अरक्षित, संदिग्ध माने गए	41,28,66,615	38,73,71,553
	1,25,32,86,868	**1,35,44,49,026**
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	41,28,66,615	38,73,71,553
योग	**84,04,20,253**	**96,70,77,473**
टिप्पणी 12		
नकदी और बैंक बैलेंस		
क) नकदी और नकदी समतुल्य		
बैंकों में शेष राशि		
- बचत खातों में	1,57,84,81,418	1,56,89,64,271
- चालू खातों में	3,39,21,472	4,85,40,808
- रिपोर्टिंग की तारीख से 3 महीने में परिपक्व होने वाली बैंक जमाओं में	3,19,87,53,515	1,53,23,53,421
हाथ में नकदी	1,57,861	49,349
	4,81,13,14,267	**3,14,99,07,849**
ख) अन्य बैंक बैलेंस		
गिरवी रखी गई बैंक जमा	7,56,52,823	8,56,95,791
बैंक जमा जिनकी परिपक्वता की तारीख 3 माह से अधिक है	42,48,58,712	2,51,44,94,794
	50,05,11,534	**2,60,01,90,585**
योग	**5,31,18,25,801**	**5,75,00,98,434**
टिप्पणी 13		
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम		
(अरक्षित, प्राप्य माने गए)		
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	61,09,869	1,11,77,714
विक्रेताओं को अग्रिम	5,39,33,153	4,86,79,064
प्रीपेड खर्च	8,53,18,713	19,51,501
सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष #	4,83,19,126	6,07,27,250
स्रोत पर कर की कटौती^	51,68,23,847	44,55,71,585
योग	**71,05,04,707**	**56,81,07,114**

टिप्पणियां:

इसमें विभिन्न मामलों में विरोध के साथ भुगतान की गई 41,807,307 रुपए की राशि (31 मार्च 2024: 41,807,307 रुपए) शामिल है, अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 20 देखें।

^सोसाइटी का प्रबंधन आयकर विभाग के पोर्टल पर दर्शाए गए टैक्स क्रेडिट विवरण के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान मान्य की गई आय का मिलान करने की प्रक्रिया में है। प्राप्य टीडीएस में 1,87,68,453 रुपए (31 मार्च, 2024: 1,17,72,540 रुपए) का अचिह्नित टीडीएस शामिल है। सोसाइटी के प्रबंधन के विचार से, इस तरह के मिलान से कोई महत्वपूर्ण भिन्नता उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।

टिप्पणी 14		
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		
प्रतिभूति जमा	13,21,77,587	9,19,02,441
बैंक जमा पर उपार्जित ब्याज	4,36,05,474	5,65,01,437
योग	**17,57,83,060**	**14,84,03,878**

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(समस्त धनराशि भारतीय रुपए में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 15		
प्रचालनों से राजस्व		
गुणवत्ता आवेदन, आकलन और प्रत्यायन शुल्क	2,55,39,93,506	2,13,70,31,370
परियोजनाओं से आय	1,42,07,46,612	1,79,60,02,227
संगोष्ठी से आय और विविध प्राप्तियां	10,90,97,293	5,40,52,557
अनुदान आय	2,14,94,92,694	1,70,66,54,669
आय जिसका बिल जारी नहीं किया गया	2,70,94,913	-
सदस्यता शुल्क	10,000	-
योग	**6,26,04,35,017**	**5,69,37,40,823**
टिप्पणी 16		
अन्य आय		
ब्याज से आय:		
- बैंकों में सावधि जमा	32,47,36,432	30,21,69,810
- आय कर रिफंड	1,46,37,040	1,04,35,809
- अन्य	1,99,42,226	2,03,23,141
विविध आय	29,09,918	-
पुनरांकित देनदारियां	-	-
योग	**36,22,25,616**	**33,29,28,761**
टिप्पणी 17		
कर्मचारी हितलाभ व्यय		
वेतन, अनुग्रह राशि और अन्य हितलाभ	55,19,16,426	46,37,75,435
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	2,95,22,367	2,56,32,581
ग्रेच्युटी व्यय	2,63,41,208	1,41,84,224
अवकाश नकदीकरण व्यय	3,29,86,489	2,00,05,685
अधिवर्षिता व्यय	3,52,65,446	3,05,29,668
कर्मचारी कल्याण व्यय	95,96,125	1,63,08,284
योग	**68,56,28,061**	**57,04,35,877**
टिप्पणी 18		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का मूल्यह्रास	1,93,92,745	1,71,66,992
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	6,57,001	8,76,002
योग	**2,00,49,746**	**1,80,42,994**
टिप्पणी 19		
सामान्य और प्रशासनिक व्यय		
किराए पर व्यय	11,47,31,528	8,21,78,110
पौरकर और कर	66,63,015	34,29,781
परामर्श और पेशेवर शुल्क	5,07,81,314	4,58,87,729
बाह्य परामर्शदाताओं के लिए पेशेवर शुल्क	31,55,57,338	36,03,27,069
लेखापरीक्षक को भुगतान	8,52,000	7,15,000
संचार व्यय	84,22,650	78,51,451
यात्रा और परिवहन	20,50,61,593	19,69,03,105
अशोध्य ऋण	6,90,90,065	-
कार्यालय व्यय	7,56,93,802	6,14,38,816
बिजली और ईंधन	1,34,29,273	1,01,08,265
संदिग्ध ऋणों - व्यय के लिए प्रावधान	2,54,95,064	6,97,31,929
बैठक व्यय	7,26,08,477	6,74,59,315
मरम्मत और अनुरक्षण	1,68,39,223	4,26,31,588
प्रचार गतिविधियां	22,99,20,312	22,92,32,994
प्रौद्योगिकी व्यय	15,29,61,859	15,54,98,281
सदस्यता शुल्क - व्यय	15,14,613	45,95,496
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण घाटा	1,08,185	14,699
विविध व्यय	64,97,621	19,13,875
योग	**1,36,62,27,934**	**1,33,99,17,503**

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(समस्त धनराशि भारतीय रुपए में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

टिप्पणी 20

आकस्मिक देनदारियां

अ) संस्था के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
(i) सेवा कर		
(क) उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले जिनके संबंध में सोसाइटी ने अपील दायर की है	1,02,40,938	1,02,40,938
(ख) सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष लंबित मामले जिनके संबंध में सोसाइटी ने अपील दायर की है	17,54,25,373	17,54,25,373
योग	**18,56,66,311**	**18,56,66,311**
उपर्युक्त मामलों में विरोध दर्ज कराते हुए भुगतान की गई राशि	4,18,07,307	4,18,07,307

ब) सोसाइटी द्वारा ऊपर बताए गए सभी मामले प्रचालन के सामान्य क्रम में कानूनी कार्यवाही के अधीन हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित अपीलों में उसकी स्थिति को सही ठहराया जाएगा और इन कार्यवाहियों के कारण सोसाइटी पर कोई देनदारी उत्पन्न नहीं होगी।

स) आयकर के मामले:

आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत आकलन वर्ष 2016-17 के लिए 2,32,61,362 रुपए के रिफंड के बजाए 4,94,98,085 रुपए की मांग की है। सोसाइटी ने उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली के समक्ष अपील दायर की है जो अभी लंबित है।
तथापि, प्रबंधन के सर्वोत्तम आकलन के आधार पर संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम है। इसीलिए लेखा-बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

द) निम्नलिखित सावधि जमा गिरवी रखे गए हैं :

बैंकों में जमा राशि	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
एक्सिस बैंक में सावधि जमा राशि	1,14,79,098	3,05,46,404
कोटक बैंक में सावधि जमा राशि	3,22,36,644	2,97,53,027
आइसीआईसीआई में सावधि जमा राशि	2,06,99,065	-
स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक में सावधि जमा राशि	1,12,38,016	-
येस बैंक में सावधि जमा राशि	-	2,53,96,360
योग	**7,56,52,823**	**8,56,95,791**

टिप्पणी 21

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 की धारा 22 के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत कराने वाले आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त पुष्टि के आधार पर तथा सोसायटी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर विवरण निम्नलिखित है :

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
(i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा न किया गया मूलधन और उस पर देय ब्याज।	2,17,64,009	3,69,87,976
(ii) धारा 16 के संदर्भ में क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
(iii) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान तो किया गया है किंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
(iv) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित और अदा न की गई ब्याज की राशि; और	-	-
(v) परवर्ती वर्ष में भी ऐसी तारीख तक जब उपर्युक्त देय ब्याज का भुगतान, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन से लघु उद्यम को वास्तव में किया गया है, बकाया और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि	-	-
	2,17,64,009	**3,69,87,976**

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(समस्त धनराशि भारतीय रुपए में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

टिप्पणी 22

कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान:

क) परिभाषित अंशदान योजनाएं : सोसाइटी अर्हताप्राप्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान योजनाओं में भविष्य निधि और पेंशन निधि अंशदान करती है। सोसाइटी को इन योजनाओं के अंतर्गत हितलाभों के वित्तपोषण के लिए पे-रोल लागत के एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत का अंशदान करना होता है। सोसाइटी ने लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में निम्नलिखित अंशदान को मान्य किया है। कंपनी द्वारा इन योजनाओं के लिए देय अंशदान, योजनाओं के नियमों में निर्दिष्ट दरों पर किया गया है।

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
ईपीएफ- नियोक्ता के अंशदान*	3,00,42,479	2,56,32,581
योग	**3,00,42,479**	**2,56,32,581**

** उपर्युक्त राशि में भविष्य निधि प्रशासन व्यय शामिल है।*

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं : सोसायटी ने, अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं को अपने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अधिवर्षिता निधि के रूप में वर्गीकृत किया है। सोसायटी, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के प्रति अपनी देनदारी को एक्चुरियल वैल्युएशन रिपोर्ट के अनुसार मान्य करती है। अधिवर्षिता आरक्षित निधि का रख-रखाव भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है और यह निधि, ऐसी निधियों के लिए एलआईसी के नियमों द्वारा शासित होती हैं। सोसायटी प्रत्येक कर्मचारी के खाते में अंशदान के रूप में वार्षिक मूल वेतन का 15% अंशदान देती है। यह निधि एलआईसी को हस्तांतरित कर दी जाती है और एलआईसी की योजना के अनुसार कर्मचारी को उसकी अधिवर्षिता के समय संचित राशि का भुगतान किया जाता है।

ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण

निम्नलिखित तालिका में, परिभाषित हितलाभ योजनाओं की वित्तपोषित स्थिति और वित्तीय विवरणों में मान्य की गई राशि निर्धारित की गई है।

लाभ और हानि विवरण में मान्य व्यय

	अवकाश नकदीकरण		ग्रेच्युटी	
विवरण	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**
वर्तमान सेवा लागत	13,06,75,595	11,48,99,039	1,18,09,110	1,02,63,915
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
ब्याज लागत	94,34,778	84,56,569	65,38,603	60,56,150
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	-	-	-	-
कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-	-	-
निपटारा लागत / (क्रेडिट)	-	-	-	-
बीमांकिक हानि /(लाभ)	(37,01,945)	3,56,04,943	79,93,495	(21,35,841)
लाभ और हानि विवरण में मान्य कुल व्यय	**13,64,08,428**	**15,89,60,551**	**2,63,41,208**	**1,41,84,224**

तुलन पत्र में मान्य निवल परिसंपत्ति / (देयता)

	अवकाश नकदीकरण		ग्रेच्युटी	
विवरण	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,63,06,110	13,06,75,595	11,08,98,990	9,05,62,365
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
वित्तपोषित स्थिति/अंतर	(15,63,06,110)	(13,06,75,595)	(11,08,98,990)	(9,05,62,365)
अनुमानित के मुकाबले में वास्तविक की अधिकता	-	-	-	-
अमान्य बीमांकिक (लाभ) /हानि	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल पसंपत्तियां (देयताएं)	**(15,63,06,110)**	**(13,06,75,595)**	**(11,08,98,990)**	**(9,05,62,365)**

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(समस्त धनराशि भारतीय रुपए में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

	अवकाश नकदीकरण		ग्रेच्युटी	
	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,06,75,595	11,48,99,039	9,05,62,365	8,22,84,647
अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
ब्याज लागत	94,34,778	84,56,569	65,38,603	60,56,150
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	1,94,42,582	1,52,51,061	1,18,09,110	1,02,63,915
कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-	-	-
निपटारा लागत / (क्रेडिट)	-	-	-	-
भुगतान किए गए हितलाभ	(73,55,973)	(42,29,129)	(60,04,583)	(59,06,506)
बीमांकिक हानि/(लाभ)	41,09,128	(37,01,945)	79,93,495	(21,35,841)
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**15,63,06,110**	**13,06,75,595**	**11,08,98,990**	**9,05,62,365**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

	अवकाश नकदीकरण		ग्रेच्युटी	
	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अवधि के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-
भुगतान किए गए हितलाभ	-	-	-	-
बीमांकिक हानि/(लाभ)	-	-	-	-
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-

योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य

	अवकाश नकदीकरण		ग्रेच्युटी	
	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अवधि के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-
भुगतान किए गए हितलाभ	-	-	-	-
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
वित्तपोषित स्थिति	(15,63,06,110)	(13,06,75,595)	(11,08,98,990)	(9,05,62,365)
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित लाभ के मुकाबले में वास्तविक लाभ की अधिकता	-	-	-	-

बीमांकिक अनुमान: लेखांकन मानक 15 के अनुसार उपर्युक्त परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में एक बीमांकिक मूल्यांकन किया गया था। ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण हितलाभ देयता के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमान इस प्रकार हैं:

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(समस्त धनराशि भारतीय रुपए में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

	अवकाश नकदीकरण		ग्रेच्युटी	
विवरण	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2024को समाप्त वर्ष**
छूट दर	6.99%	7.22%	6.99%	7.22%
मुआवजे के स्तरों में वृद्धि की दर	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर रिटर्न की अपेक्षित दर				

छूट दर, आमतौर पर लेखांकन की तारीख को सरकारी बांड्स पर उस अवधि के लिए उपलब्ध बाजार रिटर्न पर आधारित होती है जो देनदारियों की अवधि से मेल खाती है। भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमान में, जिसे बीमांकिक मूल्यांकन में मान्य किया जाता है, दीर्घकालिक आधार पर मुद्रस्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

अधिवर्षिता

तुलन पत्र में मान्य प्रावधानों में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

विवरण	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**
वर्ष के आरंभ में शेष	2,98,01,235	2,75,62,632
मान्य व्यय	4,45,38,466	3,05,29,668
भुगतान किए गए हितलाभ	(3,69,99,600)	(2,82,91,065)
वर्ष के अंत में शेष	**3,73,40,101**	**2,98,01,235**

टिप्पणी 23

संबंधित पक्षकार संबंधी प्रकटन

लेखांकन मानक - 18 के अनुसार, सोसाइटी के संबंधित पक्षकार और लेनदेन का प्रकटीकरण नीचे किया गया है:

संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंधित पक्षकार के साथ संबंध

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री राजेश माहेश्वरी	अंतरिम महासचिव	**(14.04.2024 तक)**
श्री चक्रवर्ती टी कन्नन	महासचिव	**(15.04.2024 से)**

संबंधित पक्षकार लेनदेन		**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**
	लेनदेन का स्वरूप		
श्री राजेश माहेश्वरी	वेतन एवं भत्ते	68,03,840	61,94,485
श्री चक्रवर्ती टी कन्नन	वेतन एवं भत्ते	83,55,775	-

टिप्पणी 24

यह सोसायटी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 कख के तहत पंजीकृत है और सोसायटी के उद्देश्यों तथा उनसे प्रासंगिक उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां संचालित कर रही है। सोसाइटी के पास कोई पहचान योग्य रिपोर्टिंग खंड नहीं है, इसलिए एएस -17 का प्रकटीकरण लागू नहीं है।

टिप्पणी 25

'यह सोसायटी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 कख के तहत पंजीकृत है और सोसायटी की आय को अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत छूट प्राप्त है, इसलिए, आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(समस्त धनराशि भारतीय रुपए में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

टिप्पणी 26

1 अव्ययित अनुदानों का मिलान:

विवरण	सरकारी अनुदान						योग	अन्य अनुदान (जनजातीय शोध सूचना शिक्षा संचार)	अन्य अनुदान (डीएल शाह ट्रस्ट)
	ज़ीरो डिफ़ेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट (ज़ेड) प्रमाणन स्कीम	लीन विनिर्माण स्पर्धात्मकता स्कीम	प्रबंधन सेवा निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	राष्ट्रीय उत्तम प्रयोगशाला परिपाटी अनुपालन निगरानी प्राधिकरण (एनजीसीएमए)	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी)	जल जीवन शक्ति मिशन (जेजेएसएम)			
1 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष	7,81,59,167	-	-	1,70,129	28,92,347	-	**8,12,21,643**	-	**7,23,498**
प्राप्तियां	1,98,69,10,210	2,98,20,154	-	62,64,306	-	1,06,85,578.00	**2,03,36,80,248**	-	-
आय उपार्जन#	1,38,172	-	-	-	14,60,066	-	**15,98,238**	-	-
समायोजन/(रिफंड्स)	(1,30,35,175)	(1,27,69,357)	-	(70,78,110)	(3,94,472)	(79,65,337)	**(4,12,42,451)**	-	-
समायोजित शेष (1+2+3+4)	**2,05,21,72,374**	**1,70,50,797**	-	**(6,43,675)**	**39,57,941**	**27,20,241**	**2,07,52,57,678**	-	**7,23,498**
प्रयुक्त अनुदान^^	(1,67,65,38,120)	(1,22,08,591)	-	-	(39,57,941)	-	**(1,69,27,04,652)**	-	-
करों के लिए समायोजन	(30,17,76,862)	(2,05,034)	-	-	-	-	**(30,19,81,896)**	-	-
व्यय के लिए समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार अंतशेष	**7,38,57,392**	**46,37,172**	-	**(6,43,675)**	-	**27,20,241**	**8,05,71,130**	-	**7,23,498**
प्राप्तियां	2,42,06,64,708	12,00,08,263	48,02,319	-	-	1,61,68,604	**2,56,16,43,894**	**20,37,500**	-
आय उपार्जन#	31,01,714	-	-	-	-	-	**31,01,714**	-	-
समायोजन/(रिफंड्स)	(31,01,714)	-	-	6,43,675	-	-	**(24,58,039)**	**(20,37,500)**	-
समायोजित शेष (8+9+10+11)	**2,49,45,22,100**	**12,46,45,435**	**48,02,319**	-	-	**1,88,88,845**	**2,64,28,58,699**	-	**7,23,498**
प्रयुक्त अनुदान^^	(2,03,83,14,895)	(9,50,09,194)	-	-	-	(1,37,02,207)	**(2,14,70,26,296)**	-	-
करों के लिए समायोजन	(36,68,96,681)	-	-	-	-	(24,66,397)	**(36,93,63,078)**	-	-
व्यय के लिए समायोजन	-	(11,15,874)	-	-	-	(27,20,241)	**(38,36,115)**	-	-
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार अंतशेष	**8,93,10,524**	**2,85,20,367**	**48,02,319**	-	-	-	**12,26,33,210**	-	**7,23,498**

इसमें ब्याज से आय और अनुदान संबंधी अन्य आय के लिए उपार्जन शामिल है।

^^ प्रयुक्त अनुदान, अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए खर्च किए गए अनुदान हैं। अनुदान आय और व्यय को तदनुसार मान्य किया गया है।

(इस स्थान का जानबूझकर खाला छोड़ा गया है)

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(समस्त धनराशि भारतीय रुपए में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

टिप्पणी 27

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) को दिसंबर 2021 में सेक्शन 8 कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, जिसमें भारतीय गुणवत्ता परिषद् और प्रोटियन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड संस्थापक सदस्य थे।
भारतीय गुणवत्ता परिषद् द्वारा उन्नति एम्प्लॉयमेंट नेटवर्क को मई 2021 में सेक्शन 8 कंपनी के रूप में निगमित किया गया था और यह भारतीय गुणवत्ता परिषद् की 100% सहायक कंपनी है।
दोनों कंपनियां हाल ही में बनी हैं और पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान घाटे में रही हैं। प्रबंधन का मानना है कि यह घाटा अस्थायी है क्योंकि संस्थाओं ने अभी तक पूरी तरह से अपना प्रचालन शुरू नहीं किया है। प्रबंधन की राय है कि यह घाटा अस्थायी स्वरूप का है और इसलिए क्षतिग्रस्तता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

टिप्पणी 28

चालू वर्ष की रिपोर्टिंग से अनुरूपता बनाए रखने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े आवश्यकतानुसार पुन: समूहित/ पुन: वर्गीकृत किए गए हैं।

कृते **टी आर चड्ढ़ा एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 006711N/N500028

राजेन्द्र प्रसाद
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098941

स्थान: नोएडा
तारीख: 19-09-2025

भारतीय गुणवत्ता परिषद् के लिए और उसकी ओर से

चक्रवर्ती टी कन्नन
(महासचिव)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-09-2025

जक्षय शाह
(अध्यक्ष)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-09-2025

(इस स्थान को जानबूझकर खाली छोड़ा गया है।)

भारतीय गुणवत्ता परिषद् (बोर्डवार सहित) का वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आय एवं व्यय

(आंकड़े करोड़ में)

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक						
बोर्ड और प्रभाग	आय			व्यय		
	बजट	वास्तविक	प्राप्त %	बजट	वास्तविक	प्राप्त %
एनएबीसीबी	17.80	18.26	103%	11.19	10.95	98%
एनएबीईटी	43.47	39.28	90%	36.31	37.43	103%
एनएबीएच	95.77	100.89	105%	48.33	54.77	113%
एनएबीएल	105.00	102.51	98%	82.44	75.45	92%
एनबीक्यूपी	1.91	2.39	125%	18.30	13.41	73%
पीएडीडी	2.76	3.30	120%	4.33	4.94	114%
पीपीआईडी	138.89	144.46	104%	134.53	138.93	103%
ज़ेड	200.00	215.25	108%	156.41	123.17	79%
क्यूसीआई -मुख्यालय	-	-	-	45.00	30.48	68%
ब्याज आय और व्यय	32.00	35.93	112%	6.50	5.93	91%
क्यूजीआईडी	-	-	0%	10.00	7.53	75%
जोड़	**637.60**	**662.26**	**104%**	**553.35**	**503.00**	**91%**



भाग
5

12 संक्षिप्ताक्षर और उनका पूर्ण रूप

क्र. सं.	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
1	क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता परिषद्
2	एसजी	महासचिव
3	सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
4	एचओडी	विभाग प्रमुख
5	जीसी	शासी परिषद्
6	जीबी	शासी निकाय
7	एनएबीएल	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
8	एनएबीएच	राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्यचर्या-प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड
9	एनएबीईटी	राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड
10	एनएबीसीबी	राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड
11	एनबीक्यूपी	राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड
12	पीपीआईडी	परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन प्रभाग
13	एनडीआईई	राष्ट्रीय उद्योग उत्कृष्टता प्रभाग
14	पीएडीडी	परियोजना विश्लेषण और प्रलेखन प्रभाग
15	एसपीडी	रणनीति और नीति प्रभाग
		एनएबीएल
1	एपीएसी	एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग
2	एपीडा	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण
3	आयुष	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
4	ईआईसी	निर्यात निरीक्षण परिषद्
5	एफएसएसएआई	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
6	जी-एलएपी	राजकीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला प्रत्यायन कार्यक्रम
7	आईएलएसी	अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग
8	आईओपीईपीसी	भारतीय तिलहन एवं उपज निर्यात संवर्धन परिषद्
9	एम(ईएल)टी	मेडिकल (प्रवेश स्तर) परीक्षण
10	एमआरए	पारस्परिक मान्यता व्यवस्था
11	एनएबीसीबी	राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड
12	पीटीपी	निपुणता परीक्षण प्रदाता
13	आरएमपी	संदर्भ सामग्री उत्पादक
14	एनएबीएल	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड

15	सीएबी	अनुरूपता आकलन निकाय
16	क्यूए	गुणवत्ता आश्वासन
17	एईआरबी	परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड
18	ईईपीसी	इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद
19	एडीएपीटी एपीएसी-पीटीबी	एडीएपीटी एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग – साइकेलिश-टेक्निश बंडेसंसटाल्ट
20	एनएमएल	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला
21	पीटीबी	पावर टर्मिनल ब्लॉक
22	आईएसओ	अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
23	आईईसी	इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन
24	आईएलएसी – एआईसी	आईएलएसी प्रत्यायन समिति (एआईसी)
25	डब्ल्यूजी	कार्य समूह
26	यूएएफ	यूनाइटिड एक्रेडिटेशन फाउंडेशन
27	ए2एलए	अमेरिकन एसोसिएशन फॉर लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन
28	आईएएस	अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन सेवा
29	पीटीडब्ल्यूजी	निपुणता परीक्षण कार्य समूह
	एनएबीएच	
1	एनएबीएच	राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्यचर्या-प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड
2	एचसीओ	स्वास्थ्यचर्या संगठन
3	एसएचसीओ	लघु स्वास्थ्यचर्या संगठन
4	बीबी	ब्लड बैंक
5	एमआईएस	मेडिकल इमेजिंग सेवाएं
6	डीएचएसपी	दंत चिकित्सा स्वास्थ्यचर्या सेवा प्रदाता
7	एसी	एलोपैथिक क्लीनिक
8	एएच	आयुष अस्पताल
9	पीसी	पंचकर्म क्लीनिक
10	सीटी-ईसी	क्लिनिकल परीक्षण आचार समिति
11	ईसीओ	आई केयर ऑर्गेनाइजेशन
12	पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
13	ओएसटी	ओरल सब्स्टीट्यूशन थेरेपी
14	आईआरसीए	नशा रोगी एकीकृत पुनर्वास केन्द्र
15	एचओपीई	स्वास्थ्यचर्या प्रवेश स्तरीय प्रमाणन संगठन मंच

16	एईएलसी	आयुष प्रवेश स्तरीय प्रमाणन
17	सीजीएचएस	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना
18	ईसीएचएस	पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
19	एमवीटीएफ	मेडिकल वैल्यू ट्रैवल फैसिलिटेटर
20	पीओआई	कार्यान्वयन संबंधी कार्यक्रम
21	एनएबीएच आई	एनएबीएच इंटरनेशनल
22	डीएचएफसी	डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स
23	एनपीएससी	एनएबीएच रोगी सुरक्षा सम्मेलन
	एनएबीईटी	
1	एएए	शैक्षिक एवं प्रशासनिक एकक
2	एडीएलक्यू	एंटी-डोपिंग लैब कतर
3	एई/आईई	प्राधिकरण के इंजीनियर/ स्वतंत्र इंजीनियर
4	एम्स	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
5	एएमपीआरआई	एडवांस्ड मेटीरियल्स एंड प्रोसेसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट
6	बिपार्ड	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान
7	सीआईपीईटी	केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
8	क्रेडाई	कन्फेडरेशन ऑफ रीयल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया
9	सीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
10	डीएचएमसी	डिजिटल हेल्थ मास्टर क्लास
11	डीएचआर	स्वास्थ्य एवं अनुसंधान विभाग
12	ईएमआर	इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड
13	ईएसजी	पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन
14	एचई-आरएसीबी	उच्चतर शिक्षा-अनुसंधान विश्लेषण और क्षमता निर्माण प्रभाग
15	एचईआई	उच्चतर शिक्षा संस्थान
16	एचएमआईएस	अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली
17	आईसीएटी	इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी
18	आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
19	आईजीएसटीसी	इंडो -जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र
20	आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
21	आई-एसटीईएम	इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजिनीयरिंग फेसिलिटीज
22	एम/ओ एमएसएमई	सूक्ष्म, लधु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

23	एमओईएफ एंड सीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
24	एमओआरटीएच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
25	एमएसएमई	सूक्ष्म, लधु और मध्यम उद्यम
26	एनएएसी	राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद्
27	एनएबीईटी	राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड
28	एनसीडीसी	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र
29	एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
30	एनएचईक्यूसी	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा गुणवत्ता प्रमाणन
31	एनएचआईडीसीएल	नेशनल हाईवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवलपमेंट कॉरपोरेशन
32	एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
33	एनजेजेएम	राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
34	एनएमसीजी	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
35	क्यूएमएस	गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
36	आरएचएआई	उच्चतर शिक्षण संस्थानों की रेंकिंग
37	एसओपी	मानक प्रचालन प्रक्रिया
38	एसपीएमएनआईडब्ल्यूएएस	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सेनीटेशन
39	टीसीबी	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
40	यूकेपीसीबी	उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
41	यूनिसेफ	यूनाइटिड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड
42	यूपीपीसीबी	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
	एनएबीसीबी	
1	एबीएमएस	रिश्वत-रोधी प्रबंधन प्रणाली
2	एआईएमएस	कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रबंधन प्रणली
3	एएमएस	परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणली
4	एपीएसी	एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग
5	एक्यूएमएस	एयरोस्पेस गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
6	बीएपी	सर्वोत्तम जलकृषि पद्धतियां
7	बीसीएमएस	व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली
8	बीईई	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
9	बीएचईएल	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड
10	बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो

11	बीआरसीजीएस	ब्रांड रेपुटेशन थ्रू कम्प्लाइंस ग्लोबल स्टैन्डर्ड्स
12	बीएसआई	ब्रिटिश स्टेंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन
13	सीएबी	अनुरूपता आकलन निकाय
14	सीएएससीओ	आईएसओ अनुरूपता आकलन समिति
15	सीडीएससीओ	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
16	सीओआरएसआईए	कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन
17	डीजीसीए	नागरिक विमानन महानिदेशालय
18	डीजीक्यूए	गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय
19	डीएमआरसी	दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन
20	डीपीआईआईटी	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
21	ईएएसए	यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी
22	ईसीसीपी	यूरोपीयन सेंटर फॉर सर्टीफिकेशन एंड प्राइवेसी
23	ईएनएमएस	ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली
24	ईएसजी	पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन
25	एफएएमआई-क्यूएस	फ़ीड एडिटिव्स एंड प्री-मिक्सचर्स क्वालिटी सिस्टम
26	एफएमएस	सुविधा प्रबंधन प्रणाली
27	एफएसएमएस	खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
28	एफएसएसएआई	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
29	एफएसएससी	खाद्य सुरक्षा प्रणाली प्रमाणन
30	जीएचजी	ग्रीन हाउस गैसें
31	जीआईएफ	गेट इट फेयर
32	ग्लोबल गैप	वैश्विक उत्तम कृषि पद्धति
33	जीक्यूआईआई	वैश्विक गुणवत्ता आश्वासन सूचकांक
34	जीएसए-बीएपी	ग्लोबल सीफूड अलाइंस - सर्वोत्तम जलकृषि पद्धतियां
35	आईएएफ	अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन मंच
36	आईएक्यूजी	अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस गुणवत्ता समूह
37	आईबी	निरीक्षण निकाय
38	आईसीएओ	अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन
39	आईसीओपी	इंडस्ट्री कंट्रोल्ड अदर पार्टी
40	आईईसी	इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन
41	आईएफएस	अंतरराष्ट्रीय विशेषीकृत मानक

42	आईएलएसी	अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग
43	आईएनएक्यूजी	भारतीय एयरोस्पेस गुणवत्ता समूह
44	आईएसए	इंटरनेशनल सोसायटी ऑफ ऑटोमेशन
45	आईएसएसीए	इन्फोर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन
46	आईएससीसी	इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टीफिकेशन
47	आईएसएमएस	सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
48	आईएसओ	अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
49	आईटीएसएमएस	सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रबंधन प्रणाली
50	मॉरीटास	मॉरीशस प्रत्यायन सेवाएं
51	एमएलए	बहुपक्षीय मान्यता व्यवस्था
52	एमआरए	पारस्परिक मान्यता व्यवस्था
53	एमओपी	विद्युत मंत्रालय
54	एनपीएल	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
55	ओएचएसएमएस	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
56	पीसीबी	उत्पाद प्रमाणन निकाय
57	पीईएफसी	प्रोग्राम फॉर दि एंडोर्समेंट ऑफ फोरेस्ट सर्टिफिकेशन
58	पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
59	पीआरसीबी	कार्मिक प्रमाणन निकाय
60	क्यूएमएस	गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
61	आरटीएसएमएस	सड़क यातायात सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
62	एसएएफ	स्थायित्वपूर्ण विमानन ईंधन
63	एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
64	एसईआरआई	सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग इंटरनेशनल
65	एसएफएल	सुन्दरम फास्टनर्स लिमिटेड
66	एसपीएस	स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय
67	टीबीटी	तकनीकी व्यापारिक बाधा
68	टीडीआरएमएस	भरोसेमंद डिजिटल रिपॉजिटरी प्रबंधन प्रणाली
69	टीईसी	दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र
70	यूकेएएस	यूनाइटेड किंगडम प्रत्यायन सेवा
71	वीवीबी	विधिमान्यकरण एवं सत्यापन निकाय
72	डब्ल्यूएडी	विश्व प्रत्यायन दिवस

73	डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन
	एनबीक्यूपी	
1	5जी मॉडल	पांचवीं पीढ़ी
2	एएचपीआई	एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया
3	एएचपीआईसीओएन	एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया कॉन्फ्रेंस
4	सीएएचओसीओएन	कंसोर्टियम ऑफ एक्रेडिटेड हेल्थकेयर ऑर्गेनाईजेशन्स कॉन्फ्रेंस
5	सीएएचओएलएबीसीओएन	कंसोर्टियम ऑफ एक्रेडिटेड हेल्थकेयर ऑर्गेनाईजेशन्स लैब कॉन्फ्रेंस
6	सीबीटी	चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट
7	सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8	सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
9	डीएवी	दयानन्द एंग्लो-वैदिक
10	डीजी	महानिदेशक
11	ईईपीसी	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्
12	फिक्की	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
13	एफटीसीसीआई	द फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
14	जीबी	शासी निकाय
15	जीसी	शासी परिषद्
16	एचसीओ	स्वास्थ्यचर्या संगठन
17	एचईएएल	स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन और साक्षरता
18	एचओडी	विभाग प्रमुख
19	आईएएस	भारतीय प्रशासनिक सेवा
20	आईडीए	इंडियन डेन्टल एसोसिएशन
21	आईईएसएस	इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो
22	आईएफएससीए	इंटरनेशनल फायनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथोरिटी
23	आईएचडब्ल्यू	इंटीग्रेटिड हेल्थ एंड वैलबीइंग
24	आईएमए	इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
25	आईआरएस	भारतीय राजस्व सेवा
26	आईएसबीटीआई	इंडियन सोसायटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी
27	आईएसओ	अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
28	आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
29	जेवी	संयुक्त उद्यम

30	केसीसीआई	कनारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
31	केसीटी	कुमारगुरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी
32	एमसीएलएस	एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता लीन स्कीम
33	एमओयू	समझौता ज्ञापन
34	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
35	एनएबीसीबी	राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड
36	एनएबीएच	राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थचर्या-प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड
37	एनएबीएल	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
38	एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
39	एनडीआईई	राष्ट्रीय उद्योग उत्कृष्टता प्रभाग
40	एनडीएमसी	नई दिल्ली नगर निगम
41	एनई	उत्तर-पूर्व
42	एनआईडीएचआई	हॉस्पिटैलिटी उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस
43	एनपीएससी	राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा सम्मेलन
44	एनएससी	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
45	पीएडीडी	परियोजना विश्लेषण और प्रलेखन प्रभाग
46	पीडीसीए	योजना, क्रियान्वयन, जाँच, कार्रवाई
47	पीएचडीसीसीआई	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
48	पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
49	संजीवनी	कला को बढ़ावा देना, यात्राओं को समृद्ध करना, नवाचार करना, राष्ट्रीय पहचान को महत्व देना और उसका विस्तार करना
50	एसईएंडआई	स्कूली शिक्षा और साक्षरता
51	एसजी	महासचिव
52	एसएचसीओ	लधु स्वास्थ्यचर्या संगठन
53	एसआईईसीसी	सूरत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर
54	यूएफएसईसी	उत्तर प्रदेश फायर एंड सेफ्टी एक्सपो और कॉन्फ्रेंस
55	यूटी	संघ राज्यक्षेत्र
56	डब्ल्यूएसीआईए	व्हाइटफील्ड एरिया कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
57	ज़ेड	ज़ीरो डिफ़ेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट
	पीपीआईडी	
1	एम्स	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
2	एपीसी	कृषि प्रसंस्करण समूह

3	सीआईएल	केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला
4	डाएआरपीजी	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
5	डीक्यूएमए	डिस्कॉम गुणवत्ता निगरानी एजेंसी
6	एफसीआई	भारतीय खाद्य निगम
7	एफएसएसएआई	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
8	जीएसईसीएल	गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
9	जेजेएम	जल जीवन मिशन
10	एमएमटी	मिलियन मीट्रिक टन
11	एमओएएफडब्ल्यू	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
12	एमओएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय
13	एमओएचयूए	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
14	एमवीवीएनएल	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम
15	एनबीसीसी	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
16	एनसीएस	नेशनल करियर सर्विस
17	एनसीएस-एससी/एसटी	एससी/एसटी के लिए नेशनल करियर सर्विस सेंटर
18	एनईजीडब्ल्यू	नेशनल ई-गवर्नेंस वेबीनार
19	एनईएसडीए (डब्ल्यूएफ)	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी आकलन – आगे की राह
20	एनएचबी	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
21	एनएचडीसी	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम
22	एनएलसीआईएल	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
23	ओएससीएससी	ओडीशा स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन
24	पीसी	प्रापण केन्द्र
25	पीसीएसएपी	प्रापण केन्द्र स्व-आकलन मंच
26	पीएचईडी	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
27	पीएमएवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
28	पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
29	पीएमयू	परियोजना प्रबंधन इकाई
30	एसबीएम	स्वच्छ भारत मिशन
31	एससीसीएल	सिंगरेनी कोलीरीज कंपनी लिमिटेड
32	एसआरकेवीएम-एपी	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्या मित्र – आंध्र प्रदेश
33	एसटीपी	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

34	टीसीजीएल	गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड
35	टीपीई	अन्य पक्ष मूल्यांकन
36	टीपीआई	अन्य पक्ष निरीक्षण
37	टीपीक्यूएमए	अन्य पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी
38	यूपीपीसीएल	उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड
	एनडीआईई	
1	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
2	डीआईसी	जिला उद्योग केन्द्र
3	आईए	कार्यान्वयन एजेंसी
4	डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
5	समर	सिस्टम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रेटिंग
6	एमओयू	समझौता ज्ञापन
7	एसोचेम	एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
8	एमपीएलयूएन	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम
9	बीएचईएल	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
10	डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
11	बीएलडब्ल्यू	बनारस लोकोमोटिव वर्क्स
12	एएसआईडीसी	असम लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड
13	एसीई	आयुध और युद्धक अभियांत्रिकी
14	बीडीएल	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
	पीएडीडी	
1	एएसी	शैक्षणिक सलाहकार परिषद्
2	आधार	भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट पहचान संख्या
3	एपीडा	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
4	एएसआई	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
5	आयुष	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
6	सीबी	प्रमाणन निकाय
7	सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8	सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
9	सीएसई	क्रिटिकल सेक्टर एन्टिटी
10	सीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

11	सीएसयूएएस	मानव रहित विमान प्रणाली प्रमाणन योजना
12	डीजी	महानिदेशालय
13	डीजीसीए	नागर विमानन महानिदेशालय
14	डीआरसी	डिजिटल रेडीनेस सर्टिफिकेट
15	ईपीसीएच	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
16	ईयू	यूरोपीय संघ
17	एफएओ	खाद्य एवं कृषि संगठन
18	एफडीए	खाद्य एवं औषधि प्रशासन
19	एफजीडी	फोकस ग्रुप डिस्कसन
20	एफपीओ	किसान उत्पादक संगठन
21	एफएसएसएआई	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
22	जीएपी	उत्तम कृषि पद्धति
23	जीईएम	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
24	जीएफसीपी	उत्तम क्षेत्र संग्रहण पद्धति
25	ग्लोबल गैप	वैश्विक उत्तम क्षेत्र संग्रहण पद्धति
26	जीएलपी	उत्तम प्रयोगशाला पद्धति
27	जीआरएएसपी	सामाजिक व्यवहार जोखिम आकलन
28	जीएसटीआईएन	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या
29	एचआरएए	हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी
30	आईसीआरआईएसएटी	इंटरनेशनल क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी- एरिड ट्रापिक्स
31	आईसीएसटीएस	अंतरराष्ट्रीय स्थायित्वपूर्ण व्यापार और मानक सम्मेलन
32	आईएनपीपीएसएस	भारतीय राष्ट्रीय निजी स्थायित्व मानक मंच
33	आईआरआरआई	अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान
34	आईटीटीओ	इंटरनेशनल ट्रापिकल टिम्बर आर्गेनाइजेशन
35	एमओयू	समझौता ज्ञापन
36	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
37	एनईजीडी	नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन
38	एनसीआईआईपीसी	राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र
39	एनजीसीएमए	राष्ट्रीय उत्तम प्रयोगशाला पद्धति अनुपालन निगरानी प्राधिकरण
40	एनएमपीबी	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड
41	एनटीडब्ल्यूजी	राष्ट्रीय तकनीकी कार्य समूह

42	ओएनडीसी	ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स
43	पीएएन	स्थाई खाता संख्या
44	पीओपी	पैकेज ऑफ प्रैक्टिस
45	आरपीएएस	दूर-संचालित विमान प्रणाली
46	सार्क	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
47	एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
48	एसओसी	अनुरूपता पत्रक
49	टीडीयू	ट्रांस-डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी
50	टीआईएचएएन	टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन आटोनॉमस नेविगेशन
51	यूएएस	मानव रहित विमान प्रणाली
52	यूएनसीटीएडी	संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन
53	यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
54	यूएनएफएसएस	संयुक्त राष्ट्र स्थायित्व मानक मंच
55	यूएनआईडीओ	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
56	वीसीएसएमपीपी	औषधीय पादप उत्पाद के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम
57	वीसीएस-टीसीएचपी	पारंपरिक सामुदायिक स्वास्थ्यचर्या-प्रदाताओं के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम

भारतीय गुणवत्ता परिषद्
QUALITY COUNCIL®
OF INDIA
Creating an Ecosystem for Quality

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2024-25



CONTE

Chairperson Message.....06

Secretary General Message.....08

Chairperson- NABL, Message 10

Chairperson- NABH, Message 11

Chairperson-NABET, Message 12

Chairperson-NABCB, Message 13

Chairperson-NBQP, Message 14

QCI Credentials 16

QCI Offerings 17

PAN India Presence of QCI 18

Key Highlights for the FY 2024-25 24

PART 01

Introduction 34

Governing Council 36

Governing Body 38

Structure 39

PART 03

Annual Review of Human Resources & Admin Activities 171

PART 04

Financial Statement 183



PART 02 Annual Review of Activities for the FY 2024-25 of Boards/Divisions/Cells

1. National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL).....43
2. National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH).....57
3. National Accreditation Board for Education and Training (NABET).....74
4. National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB).....97
5. National Board for Quality Promotion (NBQP).....116
6. Project Planning and Implementation Division (PPID).....135
7. National Division for Industry Excellence (NDIE).....145
8. Project Analysis and Documentation Division (PADD).....154
9. Strategy and Policy Division (SPD).....164

PART 05

Acronyms & Abbreviations I

CHAIRPERSON Message



SHRI JAXAY SHAH
Chairperson, QCI

To my colleagues at the Quality Council of India and our valued stakeholders,

It is with immense pride and a deep sense of purpose that I present the Annual Report for 2024-25. This document chronicles a year of remarkable progress, but more than that, it reflects a journey of profound transformation. Guided by the vision of a Viksit Bharat, articulated with such clarity by our Hon'ble Prime Minister, QCI has been steadfast in its mission to build a resilient, prosperous, and globally respected nation.

Our North Star has always been an unwavering commitment to improving the Quality of Life for every citizen. We dared to dream of a future where quality was not a privilege but a right; we aspired to take this mission to every corner of India; and we committed to executing this vision with unprecedented speed, scale, and integrity.

To drive national change, we first had to transform ourselves. Our guiding principle was to focus on the three pillars of People, Processes, and Place. We embarked on a foundational reform to build an aspirational, efficient, and ethical workplace. Our vision of "One QCI" became a reality this year with the inauguration of our new headquarters at the World Trade Centre in New Delhi. After many dedicated attempts, this long-held dream was finally realised, and I extend my deepest gratitude to the team whose perseverance made it possible.

This physical unity was matched by a cultural and procedural overhaul. We focused on our most valuable asset: our People. We attracted top-tier talent from industry to serve in key leadership roles, infusing QCI with new expertise to spearhead reforms and champion Ease of Doing Business. To anchor this new culture, we modernized our governance frameworks. The core Service & Finance Manual was overhauled to create a clear and adaptable framework for all. Our Processes were re-engineered for accessibility and efficiency. Through initiatives like DISHA, Manthan, and Yatra, and the introduction of simple 'Saral' forms, we have made the path to Quality smoother and faster, especially for small and rural organizations.

A defining feature of this tenure was expanding our last-mile reach—Through Gunvatta Sankalp, our state-connect initiative, we convened sankalps in Gujarat and, notably, in Nagaland—fulfilling the very purpose of this effort: to ensure that quality truly reaches the last mile. Our Sarpanch Samvaad initiative has also grown into a pioneering platform, engaging over 30,000 Sarpanchs and empowering them as true agents of change. This democratic spirit is also reflected in the incredible outreach of our ZED scheme, which has certified over 350,000 MSMEs, 90% of which are micro-enterprises.

Perhaps our most significant philosophical shift was moving QCI from being merely a 'watchdog' to becoming a proactive Enabler for the government. We leveraged our vast data and field expertise to provide strategic support for policymaking and implementation. We executed a time-bound study to rationalize manpower across six central ministries, optimizing government resources. We

helped drive administrative reforms through the Maharashtra 100 Days program, evaluating over 370 government offices. We developed a maturity model for India Post to transform its vast network into a catalyst for the rural economy. We even extended our quality frameworks to the sacred space of the Shree Somnath Trust, training its staff and certifying its services.

A Viksit Bharat must be a leader on the world stage. We proudly hosted the APAC Annual Conclave, bringing delegates from over 35 countries to our shores and making a strong case for India's leadership in the new global quality dialogue. The recognition of NABCB by the International Aerospace Quality Group (IAQG) is a massive boost for our Atmanirbhar mission in defence and aerospace manufacturing.

This year also marked new milestones across our Boards. NABH launched the 6th Edition of its Accreditation Standards and introduced a pioneering Digital Health Certification Programme, making quality healthcare more accessible and future ready. NABL introduced vital accreditation programmes for Biobanking and Air Quality Monitoring Equipment, addressing critical health and environmental challenges. NABET advanced its work in Education and Skilling, with assessments and ratings of medical colleges in Homoeopathy, Ayurveda, Siddha & Unani, and Nursing—raising benchmarks for excellence in medical education.

It was also a year of reflection and remembrance. We mourned the passing of our former Chairperson, NABL, the late Padma Shri Prof. Subbamma Ayyappan, whose legacy continues to inspire our mission for excellence in science and innovation.

Looking ahead, our vision is to build on this momentum. Our journey is a continuous one. The road ahead is filled with limitless possibilities to innovate, collaborate, and deepen our commitment to building a nation defined by excellence. This is not just our mission; it is a solemn promise to our nation.

Sd/-

Shri Jaxay Shah
Chairperson, QCI

SECRETARY GENERAL Message



SHRI CHAKRAVARTHY T. KANNAN

Secretary General, QCI

Dear Stakeholders and QCI Family,

It is my pleasure to present the Annual Report of the Quality Council of India (QCI) for the year 2024-25. As we reflect on the progress we've made, we can confidently say that we have grown both as an organization and as a key partner in accelerating India's Viksit Bharat journey.

As I reflect on my first year in QCI, I am filled with a deep sense of pride in the work we have done, and an even stronger sense of purpose for the journey ahead. This past year has been an incredible learning experience, one that has deepened my understanding of our vibrant organization, its people, and the relentless commitment to support India's progress toward a Viksit Bharat.

Viksit Bharat is not just a goal for us; it is our north star. Achieving this vision requires us to focus on reaching every citizen, understanding their needs, and listening to their concerns. Only by doing so can we identify areas where quality can play a transformative role. The Hon'ble Prime Minister's emphasis on improving Ease of Doing Business aligns perfectly with our mission to reduce time, streamline documentation, and simplify processes.

To achieve this, we focus on programs that bring us closer to people and make quality accessible and affordable. The Gunvatta Yatra (nationwide outreach to enhance customer advocacy and last-mile connectivity so quality standards and best practices are communicated and adopted), Gunvatta Manthan (a forum that unites stakeholders to listen, learn, re-engineer, implement, and scale quality across industries), and Samriddhi (a strategic industry-connect to strengthen quality infrastructure, streamline access to certifications/accreditations, and build capacity for global market readiness) are designed to do just that. These programs help us connect directly with communities, understand their challenges, and simplify the adoption of quality standards.

In line with the Government's call for simplification and reducing business friction, QCI is actively working on technology-driven solutions to improve the ease of accreditation. Our Q-Mitra platform, for example, will make it easier for hospitals, MSMEs, and schools to understand and apply for quality certifications, cutting down on time, documentation, and effort.

This year also marked a significant growth in our accreditation systems across various sectors. Under NABH, NABL, NABCB, and NABET, our accreditation and certification processes have steadily expanded, enabling more organizations to meet high standards of quality. Here are some key highlights:

- With over 24,000 accreditations, certifications, and empanelment to date, NABH has introduced new standards for emerging healthcare technologies such as Digital Health and enhanced its focus on cybersecurity and data privacy to meet global healthcare demands.
- With 12,500+ accreditations and recognitions, NABL has introduced new Recognition Programs for Temporary Site Labs in building projects and supported the Swachh Bharat Mission through its Swasthya Dhara Toh Khet Hara (SHC) initiative, ensuring quality at the grassroots.

- This year, NABCB conducted 1,00,000+ inspections and 2,500+ management system certifications by 290+ accredited bodies. Additionally, it was recognized by the European Aerospace Quality Group (EAQG) and International Aerospace Quality Group (IAQG) for Aerospace Quality Management System (AQMS) certifications, marking a significant milestone in India's aerospace and defense sector.

- Over 8,500 schools have been assessed and accredited under NABET, with ongoing assessments for 45,000+ students and 1,300+ teachers in Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (Pune). NABET also conducted audits of academic programs, R&D, and infrastructure at eight IITs, contributing to the national vision of quality education.

- The ZED certification for MSMEs continues to grow, with over 350,000 MSMEs certified, of which 90% are micro-enterprises. The LEAN Scheme has also seen over 8,700 MSMEs registered, and 30+ defense manufacturers have been certified under SAMAR.

QCI has also played a crucial role in supporting the quality of life across various sectors. Through the Third-Party Sampling, Testing, and Analysis of Coal, over 4,500 tripartite agreements have been signed, and 600+ MMT of coal has been sampled, ensuring compliance with quality standards in the energy sector. The City Finance Rankings (CFR) initiative, a first-of-its-kind effort, evaluated and recognized 2,570 urban local bodies (ULBs) across 15+ states, focusing on their financial performance, resource mobilization, and fiscal governance systems, promoting better urban governance. In the Impact Assessment of CLSS under PMAY-U, QCI surveyed 30,000+ beneficiaries, evaluating the effectiveness of the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban), which helps address the housing needs of urban households. Additionally, QCI supported the Ministry of Culture in shaping the Vision 2047 for India's cultural economy by conducting a comprehensive review of 43 organizations and central sector schemes, contributing to the long-term growth of India's cultural heritage and sector.

At QCI, we are committed to achieving the broader goal of Viksit Bharat 2047 by ensuring that quality is not just a benchmark, but a way of life. By expanding our reach, simplifying processes, and leveraging technology, we continue to build an ecosystem of excellence that benefits every citizen, every business, and every institution in India.

I thank each one of you for your continued support and collaboration. Together, we will continue our journey to a quality-driven, prosperous future.

Sd/-

Shri Chakravarthy T. Kannan
Secretary General, QCI



DR. SANDIP SHAH

Chairperson, NABL

It is always a pleasure to be involved in the service of the country through NABL. We all are aware about the important role played by NABL in the accreditation infrastructure of our country and in ensuring safety in all sectors, be it health, environment, food, medicines or drinking water.

The health and welfare of citizens has always been a national mission and through NABL accreditation it was ensured competent laboratories are available for medical testing. NABL initiatives are helping medical testing laboratories to differentiate their services as trust-worthy through NABL Medical Entry Level Testing Labs Program – [M(EL)T] which is based on successful participation in Proficiency Testing.

There are many achievements of NABL during the period like successful APAC re-evaluation, soil testing laboratories recognition program, etc. NABL has started the accreditation program for biobanking with International Standard ISO 20387. NABL has also supported the Government in ensuring the safety of drinking water through accreditation of water testing laboratories at district level.

As we embark upon increasing our exports through the Production Linked Incentive (PLI) schemes and ensure safety of consumers through the Quality Control Orders (QCOs). It is imperative we develop a world class conformity assessment infrastructure in the nation. NABL Accreditation instills trust in the test results of its accredited laboratories, thereby enabling a boost in the exports. It is our constant endeavor to bring more and more areas under the umbrella of accreditation so that quality and safety are assured.

I commend NABL on reaching out to the laboratories operating at the grassroot levels and bringing about a much-needed change in the minds of people to demand quality products and services.

I wish success for many more milestones that are to come in NABL's journey in the Quality Infrastructure development.

Sd/-

Dr. Sandip Shah

Chairperson, NABL



SHRI RIZWAN KOITA

Chairperson, NABH

The healthcare sector continues to transform, and NABH's role in anchoring that change with a strong focus on quality and patient safety remains more vital than ever. FY 2024–2025 has been a year of learning, collaboration, and decisive steps forward, both in strengthening core accreditation systems and in exploring new ways of supporting hospitals and healthcare providers.

During the year, NABH worked on strengthening its various programs and introducing practical updates that support healthcare providers across different levels. One of the key milestones was the launch of the 6th Edition of NABH Accreditation Standards, alongside enhancements in other certification and assessment programs. These updates have been guided by feedback from stakeholders and reflect the evolving needs of our hospitals and healthcare systems.

We continued to focus on building capacity through new assessor trainings, awareness sessions, and direct engagement with healthcare providers. This was supported by initiatives like the Gunvatta Manthan, Hospital Leadership Roundtable, which brought together institutional heads to discuss challenges and collaborative solutions around quality and accreditation. Furthering our outreach, the Gunvatta Yatra helped take NABH's message of quality to hospitals and healthcare institutions across the country, creating space for on-ground interaction, awareness, and support.

In the digital domain, the NABH Digital Health Standards (DHS) for hospitals and standards for Hospital Information Systems (HIS) and Electronic Medical Records (EMR) have started seeing strong adoption. More hospitals are now applying for certification, and a significant number of software vendors have aligned their systems with the NABH framework. We also launched the Digital Health Certification Programme for NABH Entry-Level Certified Hospitals, opening new doors for smaller facilities to strengthen their digital journey. Incentives were rolled out to encourage early adoption, and revisions were made to the fee structure to make these programs more accessible.

This year also witnessed new partnerships and collaborations that align with our shared goal of raising standards in healthcare including NABH Collaborated with Association of Healthcare Providers India (AHPI) for organizing Awareness Programs and Capacity Building Activities, NATHEALTH for patient safety microsite, RSSDI for Diabetes standards, and many others. These engagements will continue to play an important role in strengthening the larger ecosystem.

NABH's work continues to be closely aligned with India's Viksit Bharat 2047 vision, where healthcare plays a foundational role. As we move forward, we are committed to contributing meaningfully to this national goal by empowering hospitals and healthcare providers through quality systems that are practical, inclusive, and future-ready.

I take this opportunity to express my sincere appreciation to the NABH team, our assessors, and all our partners whose dedication and efforts are making an impact where it matters the most at the level of patient care. Thank you for being a part of this journey. I look forward to sharing more updates and accomplishments with you in future.

Warm regards,

Sd/-

Shri Rizwan Koita

Chairperson, NABH



SHRI P. R. MEHTA

Chairperson, NABET

The year 2024-25 has been a defining period of consolidation for NABET, necessitating bold and strategic decisions, including the difficult yet imperative step of relinquishing one of its strongest verticals as part of a broader restructuring initiative. This decisive action reflects NABET's unwavering commitment to its long-term vision and institutional sustainability.

Historically, NABET has operated at the intersection of industry, education, and research, with its primary identity rooted in education and training. By streamlining its focus and divesting the MSME Lean Vertical, NABET is reaffirming its identity as a pioneering institution committed to fostering knowledge, innovation, and excellence in these domains.

NABET's Formal Education Excellence Division (FEED) has consistently demonstrated leadership in driving educational transformation. In the school education sector, FEED has played a pivotal role through accreditation, capacity building, and quality improvement initiatives. It has conducted large-scale assessments and evaluations of various government and publicly funded schools, including Ashram Schools, Eklavya Model Residential Schools under the Ministry of Tribal Affairs, Sainik Schools, schools run by PCMC, and schools in Nashik, among others. These efforts have helped in elevating teaching standards, foster accountability, and encourage continuous improvement.

This year also marked a significant milestone in healthcare education. For the first time, FEED led the assessment and rating of medical colleges in Homoeopathy, Ayurveda, Siddha & Unani, and Nursing. This initiative introduced transparency and system-specific standards, setting a new benchmark for quality in medical education.

The Environment and Exploration Division has evolved significantly since its inception, where it pioneered the Accreditation of Environmental Impact Assessment (EIA) Consultant Organizations. Today, its scope has expanded to include the accreditation of Exploration & Mine Plan Consultants, reflecting its critical role in shaping the sustainability landscape. NABET remains steadfast in its duty to safeguard environmental integrity—not just for the present but for generations to come.

Research and Development (R&D) are vital for national progress, and India is witnessing a strong push in this area through government support and industry-academia collaboration. NABET's Research, Analysis, and Capacity Building Division is conducting impact assessments of key initiatives, including IGSTC's 2+2 Bilateral Projects and the I-STEM National Portal, to evaluate and enhance R&D capabilities across sectors.

The Training and Capacity Building (TCB) and eQuest Divisions are collaborating closely with government and private entities to meet the critical need for workforce training at various levels. By addressing skill gaps and enhancing competency development, these divisions are playing a crucial role in strengthening India's human capital.

Before concluding, I extend my deepest gratitude to the NABET Board Members and Advisory Committee for their invaluable guidance and continued support. I also thank the NABET Secretariat for their dedication and tireless efforts in implementing the Board's vision.

Together, we are not just adapting to change—we are leading it. With a sharper focus and renewed purpose, NABET is poised to leave a lasting legacy in the fields of education and training, creating a profound and positive impact on society.

Sd/-

Shri P. R. MEHTA

Chairperson, NABET



DR. RAVI PRAKASH SINGH

Chairperson, NABCB

Greetings!

NABCB is one of the most crucial Boards within the Quality Ecosystem of the country, since it provides for a system of internationally recognized and acclaimed process driven assurance of quality in products, processes, services and systems.

As we conclude another year of progress and purposeful engagement in FY 2024–25, it gives me immense pride to reflect on the dynamic journey of the National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB). Over the past year, NABCB has continued to strengthen its stature as a vital institution in India's Quality Infrastructure, promoting internationally benchmarked conformity assessment services across sectors.

This year marked a significant leap forward with NABCB becoming a signatory to the IAF Multilateral Recognition Arrangement (MLA) for Validation and Verification, as well as securing APAC MRA status for newer sub-scopes such as EOMS and FAMI-QS. NABCB has also commenced the accreditation scheme for Artificial Intelligence Management Systems (AIMS) for certifications to ISO/IEC 42001:2023.

Through extensive collaboration with Regulators and Ministries, which encompasses Securities and Exchange Board of India (SEBI), Bureau of Energy Efficiency (BEE), Telecommunication Engineering Centre(TEC) and Ministry of Power, NABCB has made concerted efforts to embed accredited conformity assessment as a cornerstone for regulatory compliance. Our role in supporting the Government's climate agenda, such as through Carbon Credit Trading and Sustainable Aviation Fuel certification frameworks, reaffirms the growing relevance of accreditation in national policy initiatives.

NABCB outreach extended globally with Capacity Building projects for Mauritius Accreditation Service (MAURITAS), participation in international forums (IAF, ILAC, APAC), and technical collaborations with international scheme owners like FSSC, ISCC, Verra, IFS, SERI and BRCGS. Initiatives such as Gunvatta Manthan and Gunvatta Samridhi; Industry interactions with organizations like BHEL, DMRC, Reliance Jio, Mazagon Dock Shipbuilders Ltd., L&T Energy, Sundram Fasteners Limited, and KDDL Limited have helped us better understand and respond to the expectations of industry stakeholder.

Training and assessor development remained a cornerstone of our quality assurance strategy, with over dozen national programs conducted to enhance assessor competence across multiple standards covering sector specific schemes such as Aerospace QMS, FAMI-QS and various accreditation standards.

Looking ahead, as India strengthens its global position in trade and innovation, NABCB remains committed to expanding the reach of quality and accredited conformity assessment to all sectors-especially in supporting MSMEs, advancing ESG objectives, and integrating new-age technologies like AI and cybersecurity into our ecosystem.

Let us continue this journey together in building a credible, resilient, and globally recognized accreditation framework for India.

Wishing all stakeholders a successful and impactful year ahead.

Sd/-

Dr. Ravi Prakash Singh

Chairperson, NABCB



SHRI VIPIN SONDHI

Chairperson, NBQP

The National Board for Quality Promotion (NBQP) continues to lead with purpose, passion, and an unwavering commitment to cultivating a culture of Quality that touches every aspect of life in India. We remain steadfast in our mission to Engage, Educate, and Empower, embracing innovation and collaboration as the cornerstones of our progress. Under the visionary guidance of our Chairperson, Shri Jaxay Shah, and the dynamic leadership of our Secretary General, Shri Chakravarthy T. Kannan, we are not just advancing standards—we are building a Quality movement that resonates from grassroots communities to national institutions.

This year, NBQP has expanded its reach and impact through a diverse spectrum of initiatives aligned with the goals of Viksit Bharat @2047. Each project has been a step toward embedding Quality as a way of life, strengthening our resolve to promote excellence, safety, and awareness in every sector.

We saw the resounding success of the second edition of the Quality Summer FunCamp, engaging over 13,000 students from all 36 States and UTs, with a focus on safety under the theme "Safety Stars: Shining Bright with Quality." Through our collaboration with the National Safety Council and widespread support from educational boards and Ministries, we instilled critical life skills in our youngest citizens.

The launch of the Quality Bharat Cell (QBC) stands out as a pioneering step to nurture future ambassadors of Quality. With five pilot schools and hundreds of trained students and educators, this initiative is laying the groundwork for a generational shift in how we view excellence in education and society.

Gunvatta Pakhwada replaced Quality Month with a powerful, interactive celebration of Quality values through nationwide competitions, public engagement, and awareness drives. Likewise, Gunvatta Sankalp reached across states—from Gujarat to Nagaland—bringing together stakeholders from government, healthcare, industry, and civil society to drive sectoral improvement and innovation.

Through Gunvatta Manthan, we created a structured platform for reflection and collaboration with stakeholders across our Boards and Divisions. These dialogues are fueling strategic planning and ensuring that our efforts stay rooted in the real needs of our communities and industries.

Alongside, the Gunvatta Yatra is a strategic initiative to promote Quality standards in healthcare and manufacturing. Through capacity-building workshops, the Yatra equips stakeholders with the knowledge needed for accreditation and certification. As of March 2025, 48 Yatras have been conducted across India, reaffirming QCI's commitment to driving Quality in underserved regions. And with initiatives like MITRA, we are working to empower small healthcare organizations to achieve NABH certification and uplift Quality in underserved regions.

This year, we also launched the SANJIVANI initiative to revive India's rich tapestry of dying art forms an intersection of culture and Quality that underscores our holistic approach to development. Moreover, our partnership with Ministries on Management Systems implementation continues to enhance governance excellence. We were proud to extend our support to the EEPC India Quality & Green Awards, recognizing organizations championing sustainable and exemplary practices.

The Quality Bharat Pledge, taken by over 29,000 citizens via MyGov, captures the spirit of our movement: "**गुणवत्ता अपनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे**"—"We will adopt Quality, we will make a developed India."

As we look to the coming year, we are driven by a shared belief that Quality is not a milestone—it is a mindset. I commend Team NBQP for its exceptional work, deeply appreciate the insightful and steadfast guidance of our esteemed Board Members, and express my gratitude to the CEO, Dr. A. Raj and every team member whose dedication continues to elevate our mission.

Let us move forward together, where Quality isn't just a goal, but the very foundation of our collective journey toward a brighter, stronger, and more developed India.

Sd/-

Shri Vipin Sondhi

Chairperson, NBQP

QCI CREDENTIALS & OFFERINGS

QCI CREDENTIALS

- A National Accreditation Body for Certification/Inspection/Validation bodies, Testing/Calibration/Medical Laboratory, Hospitals & Healthcare Providers and Education & Training/Environment sector.
- Striving towards creation of an Ecosystem of Quality Infrastructure in India through competent Testing, Certification & Inspection System.
- Acceptance of Certification/Inspection as well as Testing/Calibration results of NABCB/NABL accredited organizations amongst IAF/ILAC/ APAC MRA partner countries.
- Delivering quality across sectors by design and development of conformity assessment frameworks.
- Leading various projects of national importance and supporting Government of India in driving its flagship programmes at speed and scale.
- Promoting quality at every level by offering 100+ eLearning courses through eQuest platform and offering quality instructor-led training to the professionals.
- Enhancing the level of awareness on Quality amongst the stakeholders by motivating, educating, facilitating, assessing on key aspects of quality.

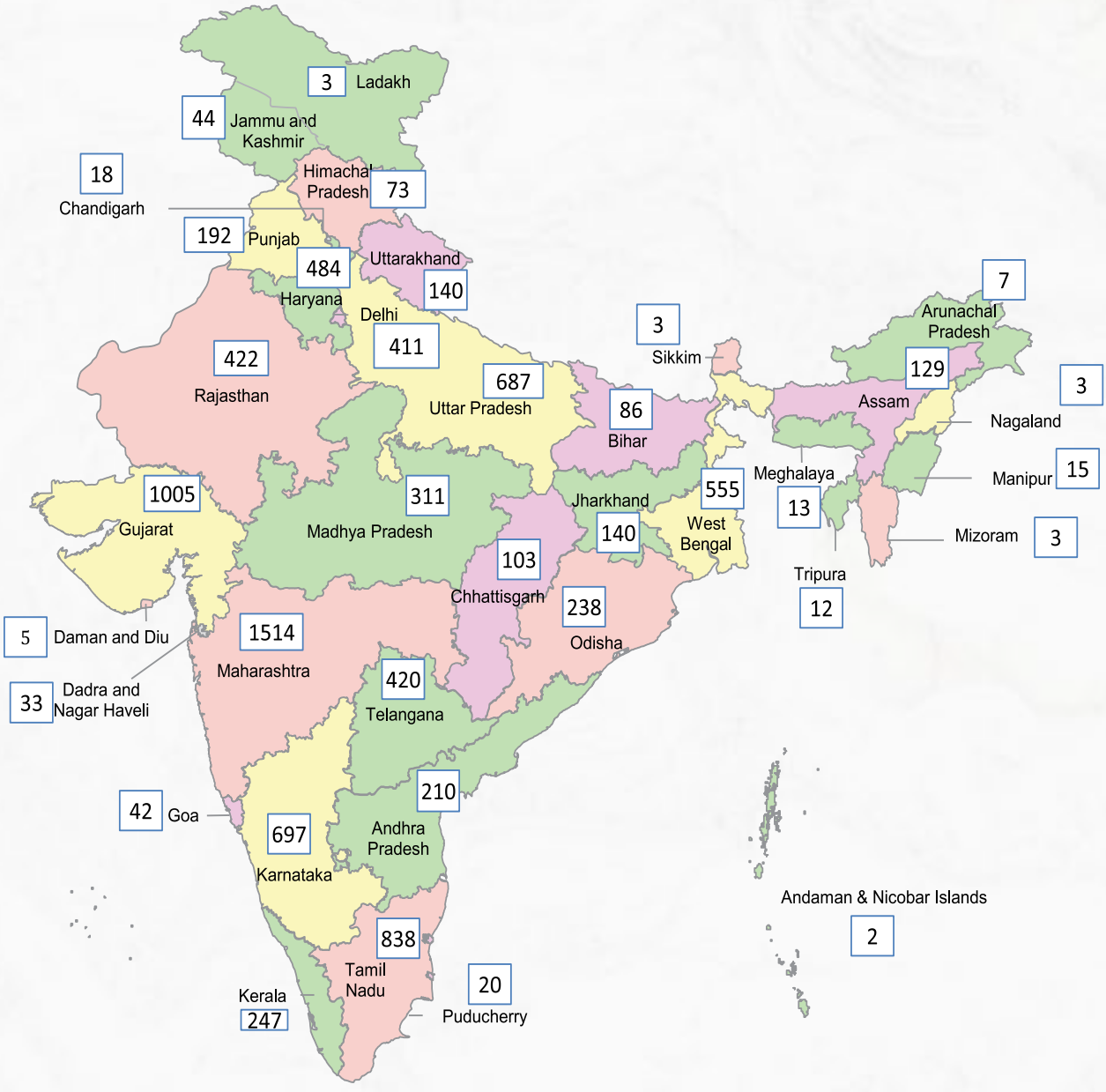
QCI OFFERINGS

to establish & operate	National Accreditation Programmes	NABCB, NABL, NABH, NABET
to conduct	Third-Party Assessment to measure Quality	PPID (through accredited CABs)
to run a	Nation-wide Quality Campaign	NBQP
to catalyze	Indian industry's Competitiveness	NDIE
to develop	Capacity for Quality in Emerging Areas	PADD
to augment	Government's capacity in Quality	SPD



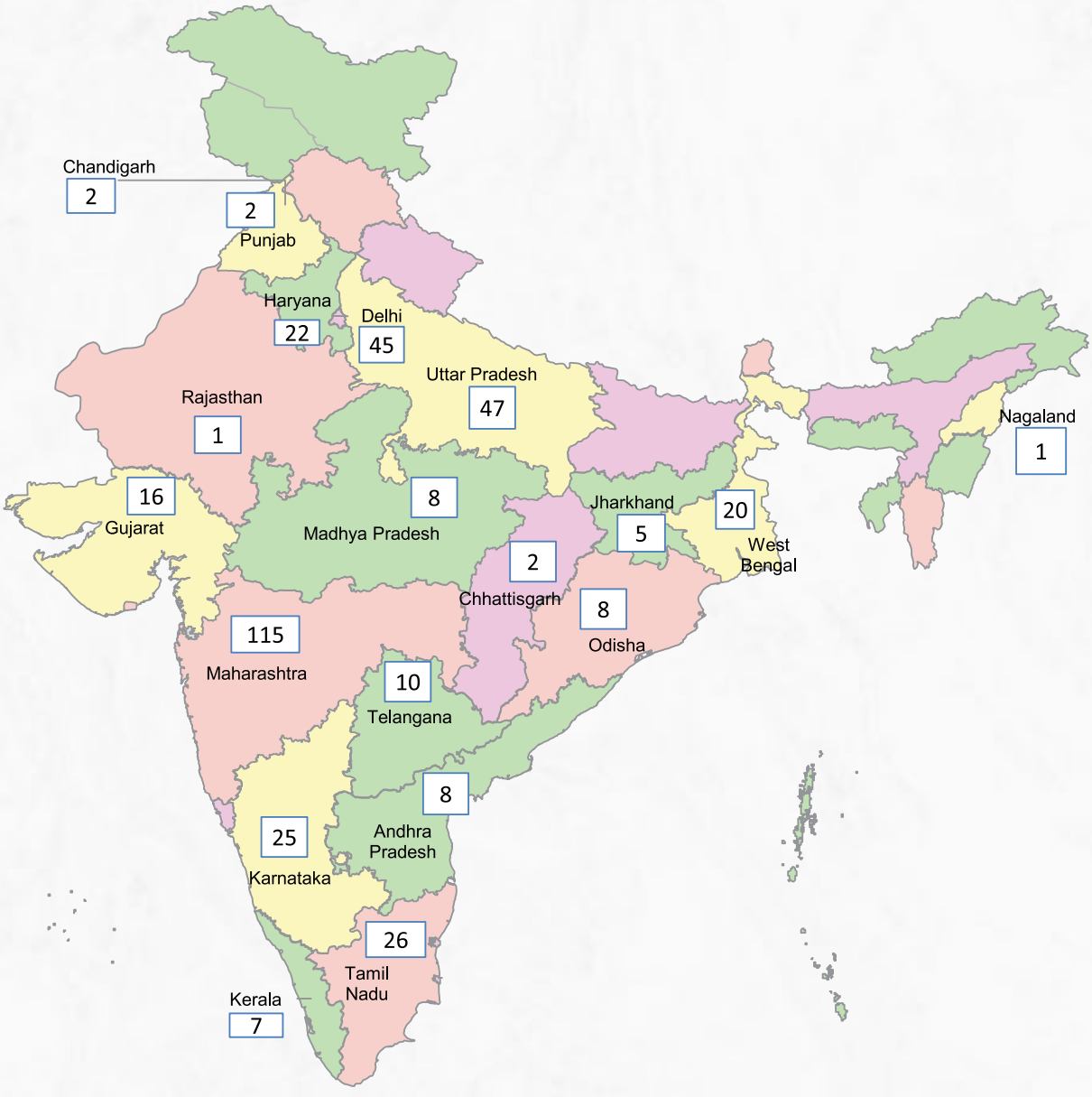
PAN INDIA PRESENCE OF QCI

NATIONAL ACCREDITATION BOARD FOR TESTING AND CALIBRATION LABORATORIES (NABL)



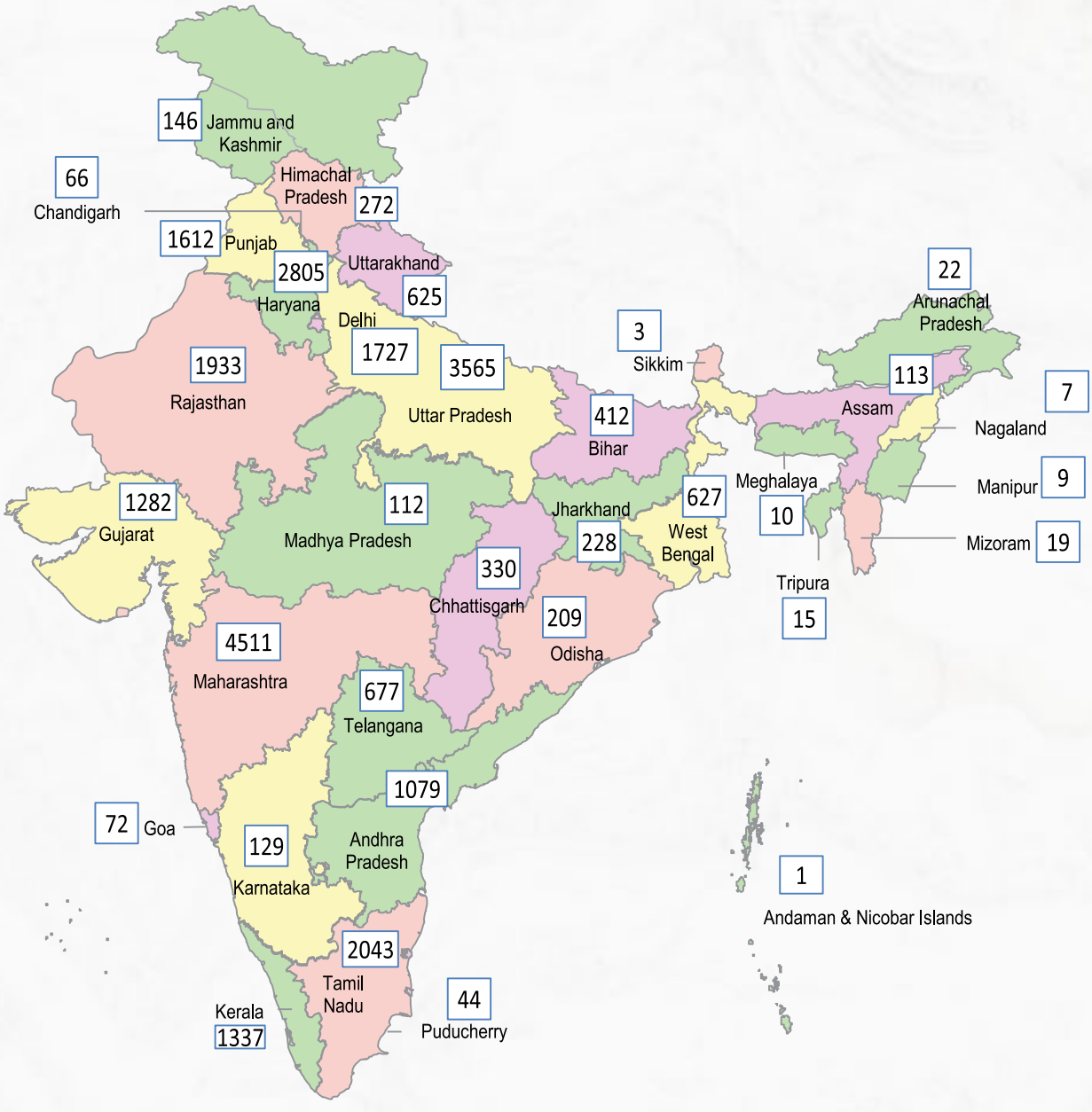
NABL ACCREDITED LABORATORIES

NATIONAL ACCREDITATION BOARD FOR CERTIFICATION BODIES (NABCB)



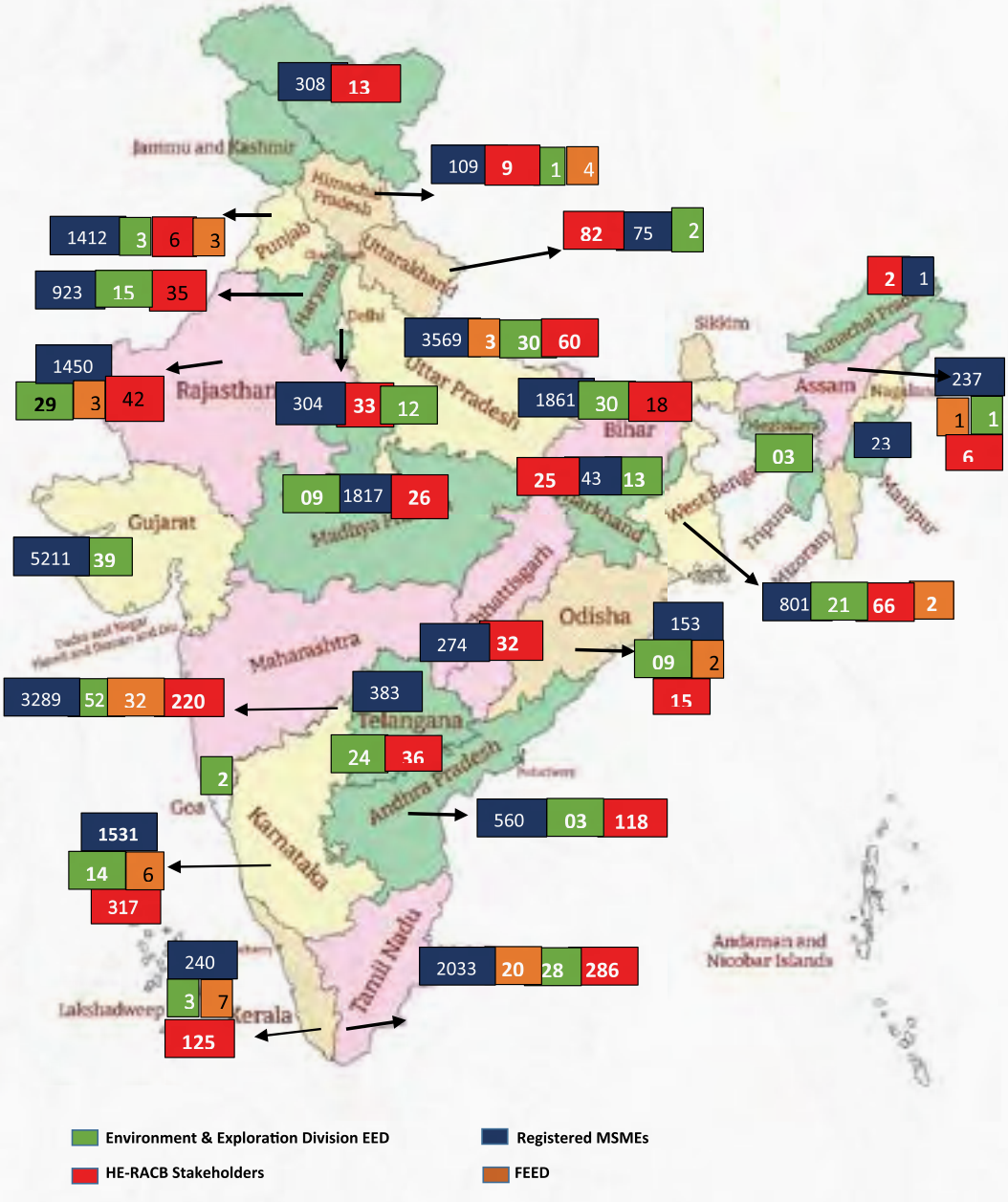
NABCB ACCREDITED CONFORMITY ASSESSMENT BODIES

NATIONAL ACCREDITATION BOARD FOR HOSPITALS & HEALTHCARE PROVIDERS (NABH)



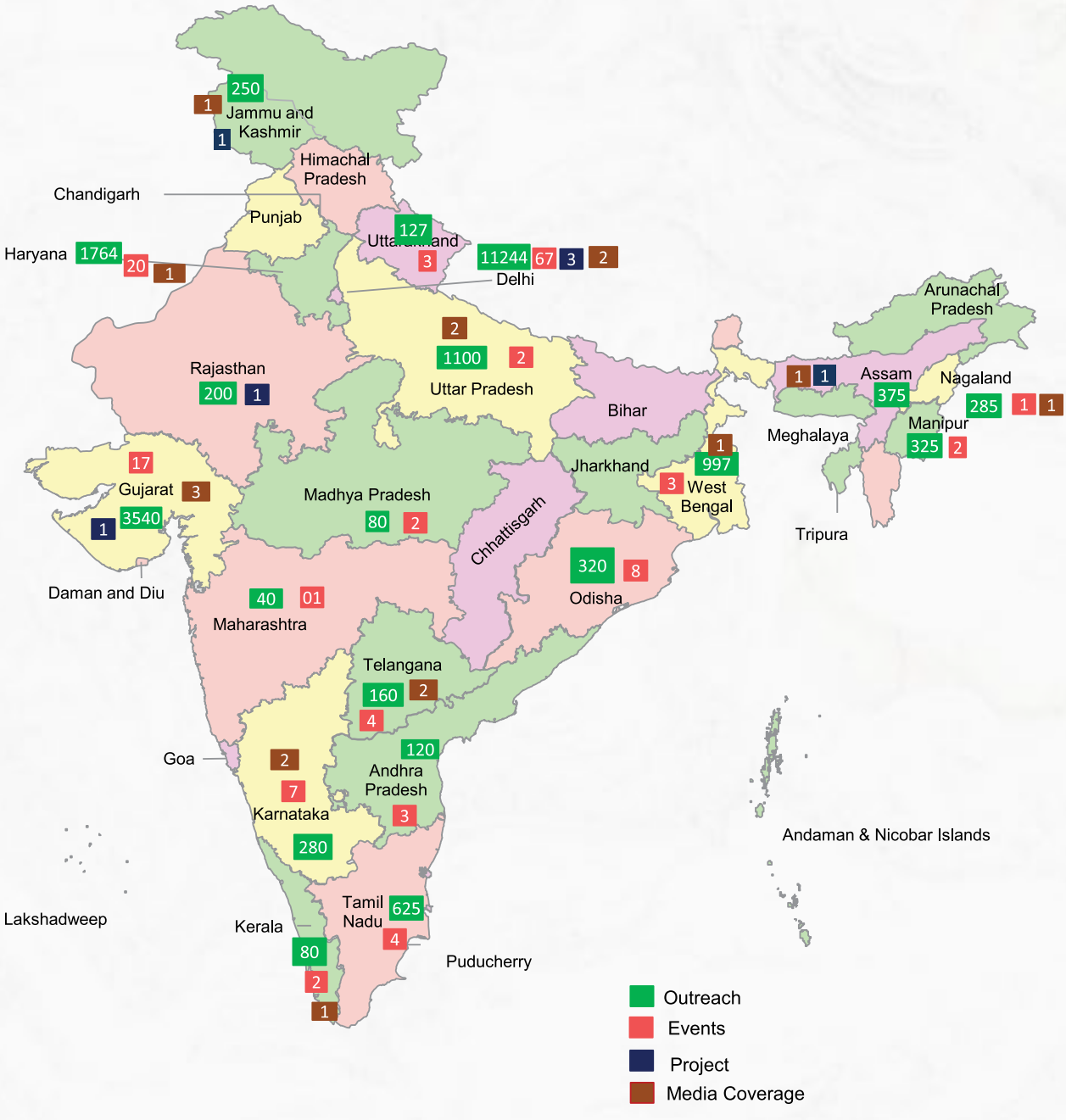
NABH ACCREDITED/ CERTIFIED/EMPANELED HOSPITALS & HEALTHCARE PROVIDERS

NATIONAL ACCREDITATION BOARD FOR EDUCATION AND TRAINING (NABET)



NABET ACCREDITED SCHOOLS & ACCREDITED CONSULTANT ORGANIZATIONS

NATIONAL BOARD FOR QUALITY PROMOTION (NBQP)



KEY HIGHLIGHTS FOR THE FY 2024–25

International Recognitions

- NABL maintain its APAC MRA signatory status for the following scopes:

  1. Testing ISO/IEC 17025;
  2. Calibration ISO/IEC 17025;
  3. Medical Testing ISO 15189;
  4. Reference Materials Producers ISO 17034;
  5. Proficiency Testing Providers ISO/IEC 17043

- NABCB has been recognized as a signatory to the IAF MLA (International Accreditation Forum Inc. Multilateral Recognition Arrangement) for Validation & Verification, reaffirming its commitment to providing accreditation services.

  The scope of recognition covers:

  - Main Scope: Validation and Verification - ISO/IEC 17029
  - Level 4 Sub-scope: ISO 14065:2020 / ISO 14066 / ISO 14064-3
  - Level 5 Sub-scope: ISO 14064-1 / ISO 14064-2

- **NABCB secures International Equivalence for EOMS & FAMI-QS**

  Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) recently confirmed its MRA signatory Status for NABCB for the following sub-scopes(s):

  - Education Organization Management Systems (EOMS);
  - Quality and Safety System for Specialty Feed Ingredients (FAMI-QS)

Accomplishment and Growth

- Granted recognition to 2964 labs under NABL Medical (Entry Level) Testing Labs Program based on successful PT participation
- Accredited 489 (with 121 fresh accreditation) District Water Testing Laboratories under Ministry of Jal Shakti, Public Health Engineering Department, Government of India. Total 855 (with 248 fresh recognition) of Water Testing Laboratories under G-LAP Accreditation program
- 433 recognition given Soil Testing Laboratory Program
- Number of Accredited CABs as on 31.03.2025: 9142 (T-5755, C-1152, M-2146, PTP-69, RMP-20)
- Accredited 119 labs in the niche area of Diagnostic Radiology X ray Equipment QA testing Agencies.
- **NABCB grants 1st Accreditation for Artificial Intelligence (AI) Management Systems**

  NABCB has now granted its 1st AIMS accreditation to TUV India for ISO/IEC 42001 certifications. ISO/IEC 42001 is the world's first AI management system standard, specifying requirements for establishing, implementing, maintaining, and continually improving AIMS within organizations, providing a structured way to manage risks & opportunities associated with AI, and balancing innovation with governance.

- NABH accredited/ certified **3672** healthcare providers, inspected **750** hospitals for ECHS and CGHS empanelment, and organised **111** training programs for healthcare professionals.
- As a step towards paperless initiative, NABH has completely switched to digital portals and on boarded all applicants and accredited HCOs & SHCOs under Ayush entry level program, CGHS/ ECHS empanelment schemes, Hospital and SHCO Accreditation Programs.
- **Inspection of National Commission of Homoeopathy (NCH):**

  NCH entrusted NABH for conducting inspections of 101 homeopathic colleges & hospitals across country, which NABH completed within the time stipulated by NCH. The inspections were conducted as per the requirements provided

by NCH, and reports have been submitted to National Commission for Homoeopathy.

- **Digital Health initiatives:** The NABH Digital Health Initiative represents a significant stride towards integrating technology into healthcare systems to enhance efficiency, accessibility, and quality of care.

  By embracing digital transformation, healthcare providers can improve patient outcomes, optimize resource utilization and bridge geographical barriers to healthcare access.

- **NABH- Digital Health Foundation course** is running on E-quest portal since 26th July 2024; till date 280 registrations and certificates have been given

- **Inspection of National Commission of Homoeopathy (NCH):** NABH conducted inspections of Homoeopathic Medical Colleges using inspectors trained by NCH, as decided by the Medical Assessment and Rating Board.

- **NABH Strtegic meet समVAYANA:** NABH Annual Strategic Meet was held at Statue of Unity, Gujarat 28 to 30 March 2024. The Annual Strategic Meet 2024- समVAYANA, was organized by the National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH), unfolded as an enriching three-day event.

- **NABH-AELC initiative:** NABH aims to strengthen the healthcare system at the grassroots level across India. This includes not only ensuring proper service delivery to the population but also adequately training the workforce to do so. This initiative seeks to upgrade existing infrastructure and foster a culture that prioritizes patient health and safety.

  1371 Ayush Health and Wellness Centres / Aarogya Mandir across India certified by NABH across India.

  More than **2005 AHWCs have been assessed** across India including states of Arunachal Pradesh, Nagaland, Kashmir, Uttarakhand, Assam and Mizoram.

- **NABH Standards for Allopathic Clinics 2nd Edition:** In response to these needs, the Allopathic Clinics 2nd Edition, released in 2023, expands the original framework to include specialized care services such as Day Care units, standalone Dermatology clinics and Dialysis centres.

- **NABH Patient Safety Conference 2024:** NABH organized the "NABH Patient Safety Conference 2024" on 17th September with the theme "**एक स्वस्थ देश, विकसित भारत के लिए.**" The event featured seven panel discussions, bringing together over 1,000 delegates nationwide.

- **Collaboration with Stakeholders:** NABH collaborated with the Research Society for the Study of Diabetes in India (RSSDI) to develop diabetes-specific standards, align EMR and CMS standards, and roll out NABH Allopathic Clinic standards across RSSDI's network of over 12,000 members nationwide.

- **Gujarat Gunvatta Sankalp**

  This is a pivotal initiative to augment and support State Government's initiatives through quality interventions across sectors to build a holistic quality ecosystem. It represents a significant effort aimed at promoting cooperative federalism. The Gujarat Gunvatta Sankalp at Ahmedabad witnessed participation of more than 600 delegates, with 43 speakers from Government of Gujarat and Industry.

- **Quality Summer FunCamp**

  The Online Quality Summer Funcamp (QSFC) is designed to engage students in Quality-related learning through a fun, interactive approach which aims to ignite curiosity and deepen understanding of Quality among young minds. Through a range of competitions and activities, children are encouraged to demonstrate their creativity, talent, and knowledge while exploring the significance of Quality in everyday life.

  More than 13,000 School students from all 36 States and UTs participated.

- NBQP actively organizes events and **QCI Powered Sessions (QPS)** to engage a broad spectrum of stakeholders, fostering deeper understanding and wider adoption of quality practices essential for thriving in a competitive global environment. **In FY 2024-25, NBQP participated in 21 such QPS with various Industry Associations.**

- **Quality Awareness Workshop,** which is designed to be both engaging and informative for school students. These workshops aim to instill a sense of responsibility and awareness in young learners on topics such as hygiene, environmental protection, problem-solving skills, tools/ techniques, the basics of quality, safety, empathy, and other essential subjects. **In FY 2024-25, 57 workshops have been conducted in NDMC schools, non-aided primary schools, and other Govt./Pvt. Schools.**

- NBQP-QCI assists the Government/Departments in their various **flagship Awards** and has established PMUs for the execution of the same. NBQP has assisted in 7 such awards.

- **Nagaland Gunvatta Sankalp:**

  This is a pivotal initiative to augment and support State Government's initiatives through quality interventions across sectors to build a holistic quality ecosystem. It represents a significant effort aimed at promoting cooperative federalism. The Nagaland Gunvatta Sankalp at Kohima witnessed **participation of more than 125 delegates, with 23 speakers from Government of Nagaland and Industry.**

- **Quality Bharat Cells (QBC):**

  This is a pioneering initiative to promote a quality culture among students and educators nationwide. This initiative aligns with the Viksit Bharat 2047 vision and aims to empower the next generation to lead with excellence. **Currently a pilot in 5 schools (J&K, Rajasthan, UP, Delhi and Haryana) is being conducted.**

- Completion of **ISO 9001 (Quality Management Systems)** at the Office of the Mission Director, Samagra Shiksha Assam, Govt. Of Assam.

- **Assessment and Rating of Medical and Allied Healthcare Institutions:**

  In a historic initiative led by NITI Aayog and commissioned by the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), NABET conducted the first-ever assessment and rating of medical and allied healthcare education institutions.

  A formal Memorandum of Understanding (MoU) was signed between NABET and six regulatory bodies:

  - National Medical Commission (NMC)
  - Dental Council of India (DCI)
  - National Commission for Indian System of Medicine (NCISM)
  - National Commission for Homoeopathy (NCH)
  - Indian Nursing Council (INC)
  - Pharmacy Council of India (PCI)

  As a part of the initiative for 2024–25, NABET conducted assessments of 240 homoeopathy colleges under NCH and 258 colleges of Ayurveda, Siddha, and Unani under NCISM. This marked the first instance of such system-specific evaluations being conducted on a national scale.

  The results have been officially published by the relevant regulators and can be found on their websites, representing a significant advancement in quality benchmarking, transparency, and accountability in healthcare education.

- **Assessment and Quality Assurance of Nursing & Paramedical Institutions:**

  In a significant stride towards enhancing nursing and paramedical education standards, thorough assessments were carried out across two states:

  - **Uttar Pradesh:** A total of 698 nursing and paramedical colleges were inspected for the issuance of the No Objection Certificate (NOC) under the Uttar Pradesh State Medical Faculty (UPSMF).
  - **Bihar:** A total of 315 nursing colleges were assessed in two phases by the Bihar Nurses Registration Council (BNRC) as a part of the state's first-ever quality rating initiative.

  These large-scale evaluations represent a crucial step toward ensuring quality assurance, regulatory compliance, and standardization across nursing and paramedical institutions in India.

- **Quality Improvement Initiatives in School Education Domain**

  - **Quality Intervention in Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC):** This project aims to improve student learning outcomes through a three-year intervention model in 128 PCMC schools. Total number of students assessed: 47,418 (baseline assessment) and 42,291 (endline assessment); total number of teachers assessed: 965.
  - **Quality City Nashik- Education Project:** Assessment of students and the teaching-learning process across 22 schools under

the Quality City Nashik Project: Number of students assessed: 5544 (baseline assessment) and 4578 (endline assessment); Number of teachers assessed: 271.

- **Assessment and Evaluation of Tribal Schools and Hostels:** Assessed and evaluated 300 Ashram schools and hostels across five states: Maharashtra, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Odisha. The objective was to conduct assessments of these schools and hostels against established parameters, identify existing gaps, highlight major areas of concern, and provide recommendations to the Ministry of Tribal Affairs for improving the quality and effectiveness of these schools and hostels.

➤ **Assessment of Central Training Institutes (CTIs) and Administrative Training Institutes (ATIs) under the Capacity Building Commission:** Between April 1, 2024, and March 31, 2025, a total of 52 institutes successfully obtained accreditation and certification. However, the overall number of accredited and certified institutes totals 146, demonstrating continuous progress in the accreditation and certification process.

➤ **Training of Professionals – National, International and Govt. officials**

- Approximately 5,913 professionals have been registered and trained.
- QCI's Margdarshan Orientation Program trains ICMR technical recruits in essential skills, enhancing public health research. With four batches completed, 160 recruits from various locations in India have been trained under this program.
- QCI and CREDAI piloted a specific training program at GIFT City, training over 1,000 workers in technical skills and welfare schemes. This program was further expanded at CREDAI Kochi. For CREDAI Pune Metro, TCB assessed labor camps for the 'Best Facility Award'.
- TCB-NABET, in association with NATHealth, conducted DHMC sessions in Varanasi, Lucknow, Patiala, and Amritsar, training 229 healthcare professionals on digital health maturity, HMIS/EMR adoption, and interoperability.
- UNICEF sponsored a four-day training in Kolkata, where TCB-NABET trained 83 participants from 18 states to improve NJJM lab performance and water quality testing.

➤ **The Environment and Exploration Division** has accredited approximately 226 Environment Impact Assessment Consultant Organizations, along with 58 Accredited Consultant Organizations focusing on Exploration (Geological Report) and Mining Plan Preparation for the Coal Sector (Ministry of Coal) and the Mineral Sector (Ministry of Mines). It has expanded NABET's footprint with the first EIA Accreditation in the State of Himachal Pradesh and organized four awareness and capacity-building workshops on the quality of EIA in Assam, Jharkhand, Gujarat, and Maharashtra.

➤ Through mining and metallurgy projects, PPID initiated engagements with the Public Sector Undertakings (PSUs) under State Government of Chhattisgarh, Telangana, Tamil Nadu, and Karnataka.

➤ PPID also ventured into social development sector and delivered projects like – Mission for Urban Poverty Alleviation (National Urban Livelihood Mission), Third-Party Evaluation of Schemes Implemented by Ministry of Labour & Employment: e-Shram, National Career Service (NCS) & National Career Service Centres for SC/ST (NCSC-SC/ST), and Impact Assessment of Village Social Transformation Foundation (VSTF).

➤ Marking its first engagement in the handloom sector with the Ministry of Textiles, PPID conducted a third-party evaluation of the Raw Material Supply Scheme (RMSS)—a flagship initiative of the National Handloom Development Corporation (NHDC).

➤ Through technological interventions, PPID engaged in the development of multiple portals assisting our clients in better decision making and enabling enhanced service delivery of the concerned projects/schemes. Some of the platforms include Procurement Centre Self-Assessment Platform (PCSAP) for Grading of Government Grain Procurement Centers and Data Collection Application and Assessment Portals, State Monitoring Dashboards (SMD) and Zonal Portals for the Swachh Survekshan Gujarat Urban 2024 project.

➤ **"MSME Sustainable (ZED) Certification" Scheme of Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME): Ongoing**

- MoU signed with Assam Small Industries Development Corporation Ltd. (ASIDC), Government of Assam on March 17, 2025

- MoU signed with Directorate of Industries, Government of Uttarakhand on March 26, 2025
- MoUs signed with Monte Carlo and Avon Cycles at Ludhiana on September 05, 2024 and September 06, 2024, respectively.
- MoU signed with Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam (MPLUN) on October 03, 2024 to propagate ZED Scheme in Madhya Pradesh
- Registered MSMEs: 149836 (Micro: 136267, Small: 11737, Medium: 1825)
- Certified MSMEs: 104968 (Bronze: 102958, Silver: 731 and Gold: 1279)
- Handholding/Consultancy support applications received: 1959
- MSMEs availed Financial Assistance on System (Quality)/Testing/Product Certification: 1119

➤ **SAMAR Certification: Assessment and Rating of Vendors of DRDO, Ministry of Defence: Ongoing**

- The SAMAR Certification showcased at AERO India Show 2025, organized by the Ministry of Defence aimed at enhancing vendor quality and compliance.120+ DRDO vendors engaged.
- The SAMAR Certification showcased at vendor interaction campaign, organised by the Defence Research and Development Organisation (DRDO) through Armaments and Combat Engineering (ACE) cluster on October 18, 2024, at Pune, Maharashtra. 250+ organisations participated
- Number of organizations rated: 47 (Level 1: 04, Level 2: 13, Level 3: 23, Level 4: 07)

➤ **Development of Conformity Assessment System and Resource for Protection of Critical Information Infrastructure (CII)**- As cyberspace continues to revolutionize industries, it also presents significant threats to national security, the economy, and public safety. Safeguarding Critical Information Infrastructure (CII) is essential to preventing systemic harm. The Project Analysis and Documentation Division has conducted 30 Cybersecurity Awareness Programs across India to enhance the resilience of Critical Sector Entities (CSEs). The National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) has played a vital role in this effort through its Conformity Assessment Framework (CAF), ensuring robust security measures for critical sectors.

➤ **Voluntary Certification Scheme for Traditional Community Healthcare Providers (VCS-TCHP) -** The **VCS-TCHP Scheme** has achieved a significant milestone by certifying **2,522 Traditional Community Healthcare Providers (TCHPs) by FY 2024-25**, reinforcing the recognition and validation of traditional healthcare practices. Building on the earlier endorsements from **Goa and Tamil Nadu, the Government of Chhattisgarh** has now joined in recognizing the scheme's impact. Following Chhattisgarh's endorsement, **216 TCHPs were certified in the state,** further strengthening the initiative's reach and credibility. This growing support highlights the scheme's success in standardizing and validating traditional healthcare practices across India.

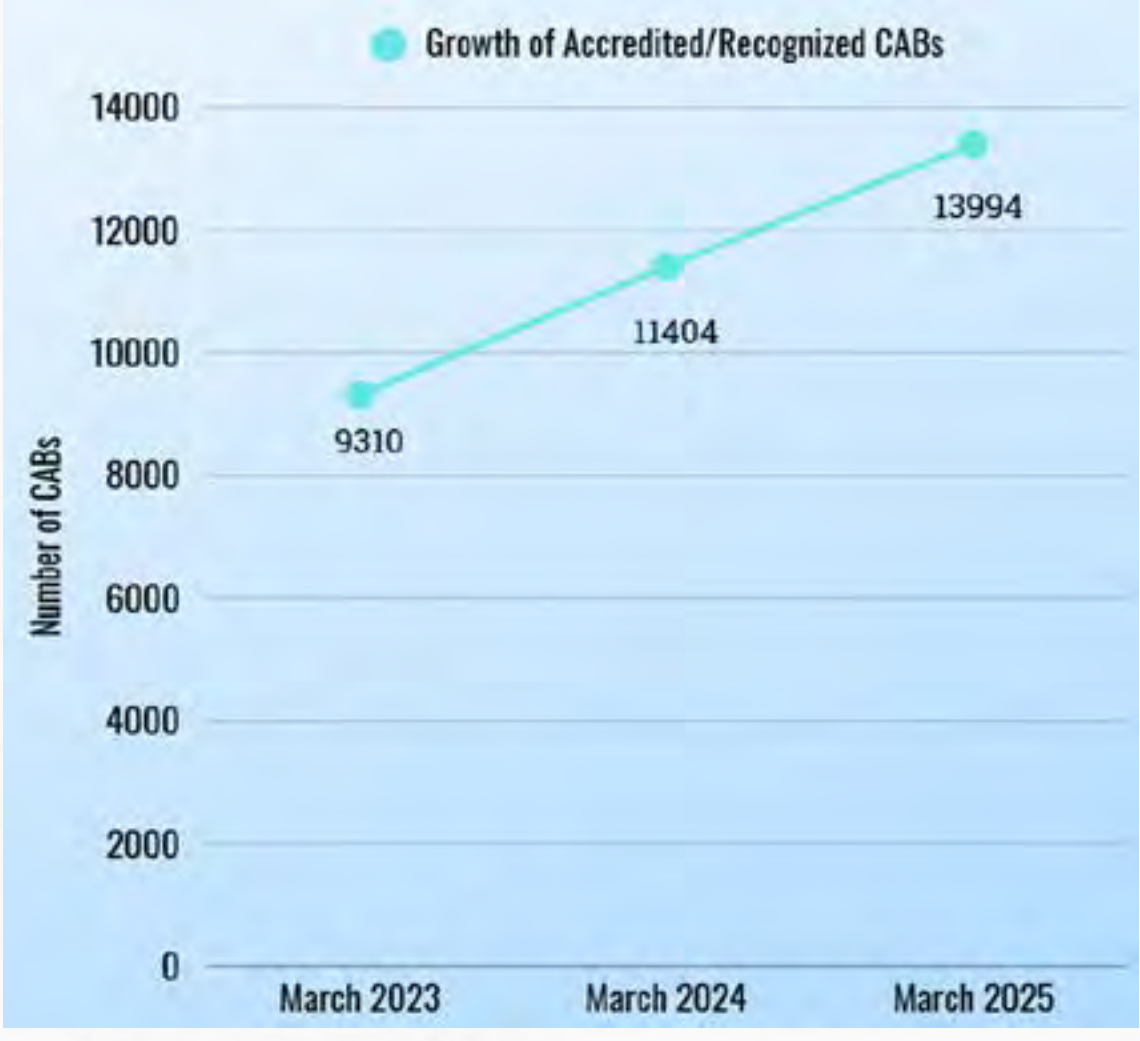
➤ **Voluntary Certification Scheme for Medicinal Plant Produce (VCSMPP)-** In a remarkable effort to promote best practices in medicinal plant cultivation, **100 training programs were conducted Pan India**, engaging **more than 6000 participants**. As a part of this initiative, **Package of Practices (PoPs) were developed for 111 species**, ensuring standardized guidelines for sustainable cultivation. To further strengthen this effort, **30 demonstration plots were established and certified**, marking a significant step toward improving quality standards in the sector.

➤ **Certification Scheme for UAS (CSUAS)** - In a significant push to **strengthen India's drone ecosystem, 104 Type Certificates (TCs)** have been issued since the scheme's launch, supporting the growth of indigenous drone technology. **PADD, QCI** has played a crucial role in this transformation, collaborating with the **Ministry of Civil Aviation** and the **Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare** through **CSUAS**, enhancing the **Namo Drone Didi** scheme by ensuring robust indigenous content in **Kisan Drones**, fostering **Aatmanirbhar Bharat.** To ensure seamless implementation, **five capacity-building programs** were conducted for **Authorized Testing Entities (ATEs),** aligning their understanding with **DGCA** regulations.

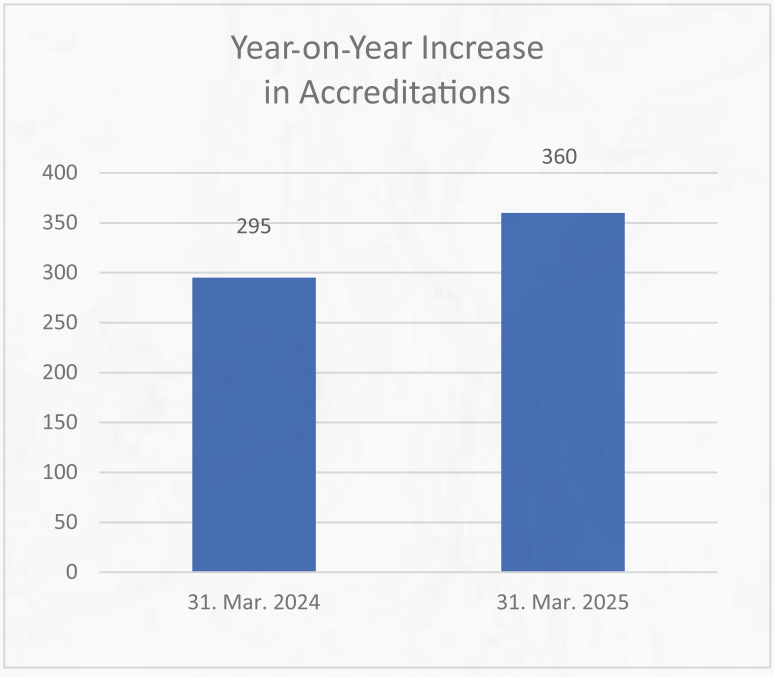
➤ In collaboration with the **Farm Machinery Training and Testing Institute (FMTTI),** a **four-day Capacity Building-cum-Sensitization Program** was hosted across **four key locations—Budni, Hisar, Biswanath Chariali, and Ananthapur**—to empower farmers with cutting-edge **Unmanned Aircraft Systems (UAS) technology.** This initiative is driving **sustainable, technology-driven solutions** in Indian agriculture, ensuring a future-ready farming ecosystem.

➤ **AYUSH Mark Scheme**

➤ The **AYUSH Mark** certification scheme continues to grow, with **5,797 products and 68 manufacturers** certified under the Scheme. In a significant development, the **Ministry of Ayush** is set to launch **Ayush Aahar,** an initiative integrated with the **Ayush Mark**, where **QCI has been included as a key member,** reinforcing its role in ensuring quality and standards in the sector. Further strengthening stakeholder engagement, Gunvatta Manthan was successfully conducted on March 21, 2025 provided a platform for stakeholders to address implementation challenges, propose solutions, and contribute to the scheme's continuous improvement.

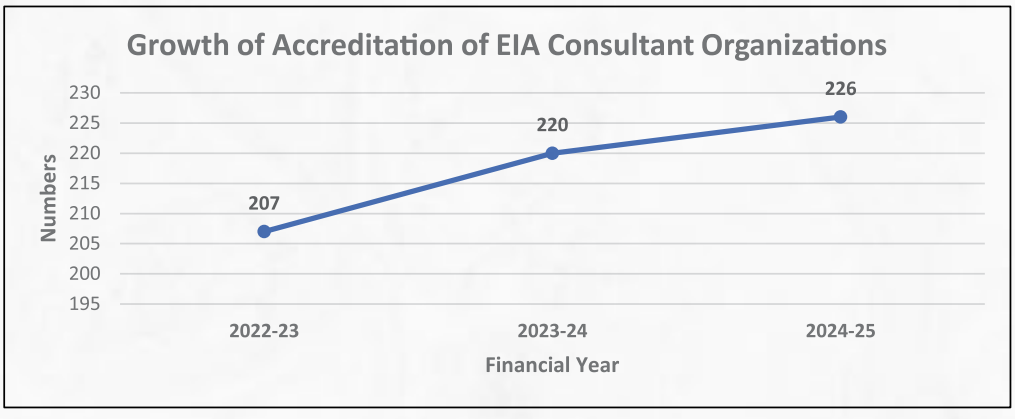


Accreditation Update

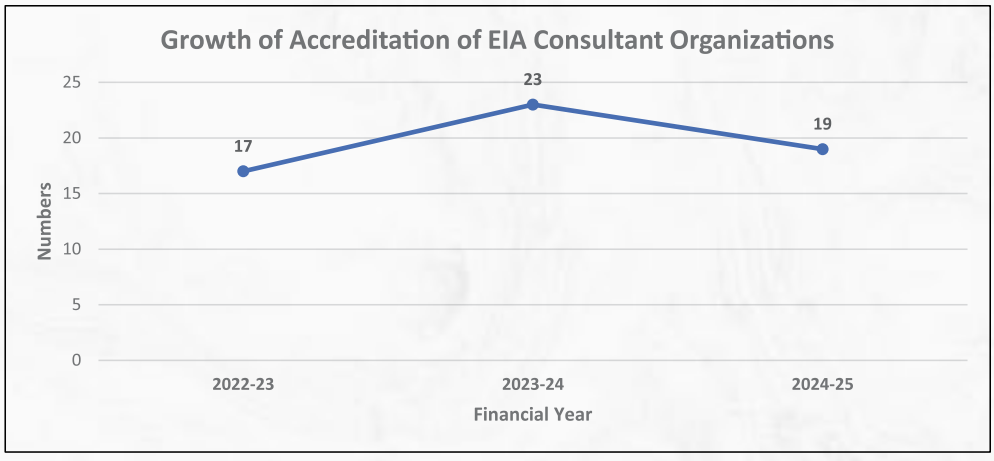




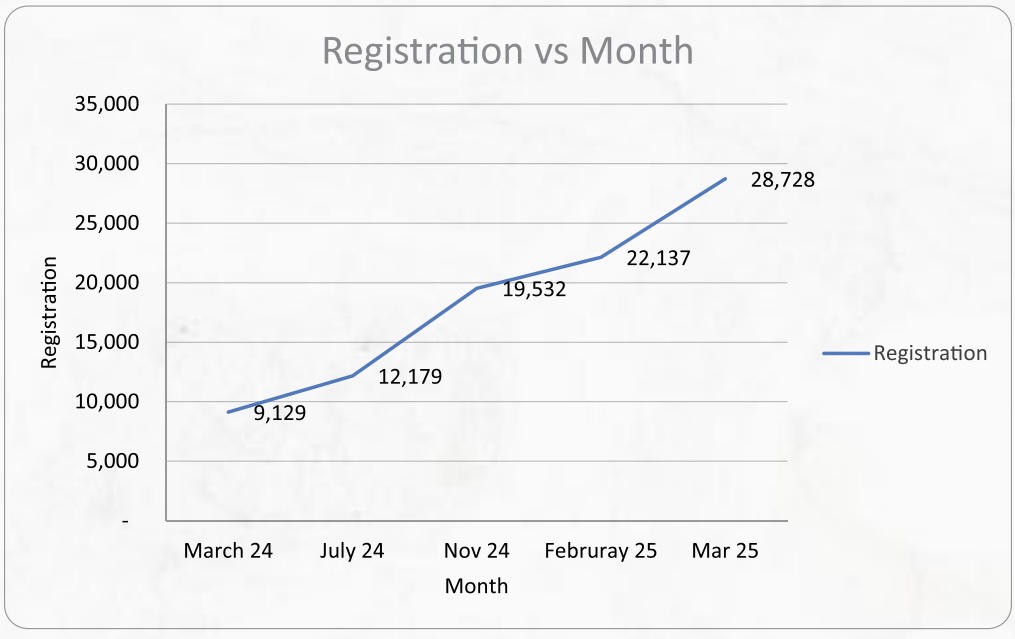
Environment and Exploration Division

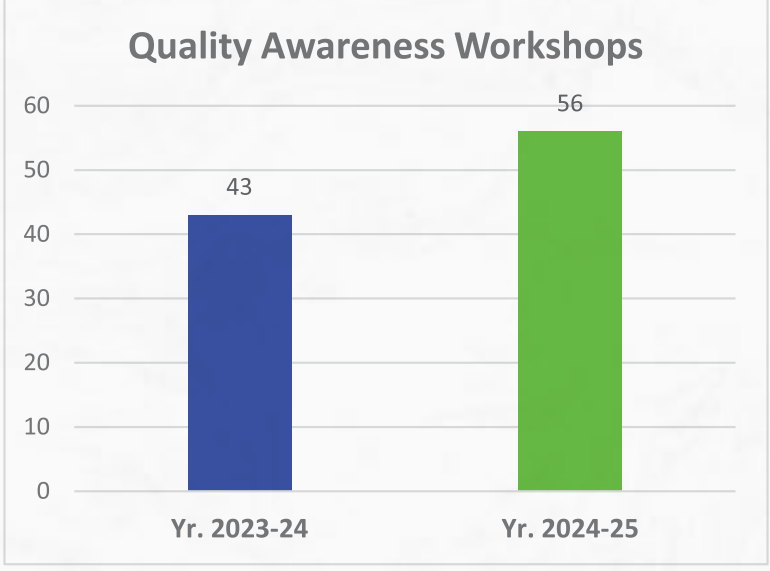


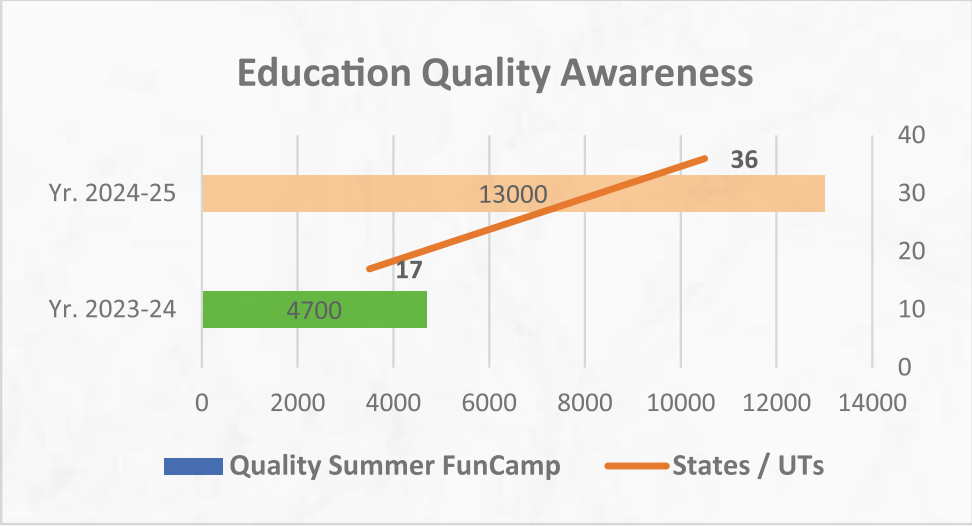
New Accredited EIA Consultant Organizations



Growth of MSME Registration (Lean)







Launching of New Schemes

- Launch of Accreditation program for Biobanking (ISO 20387)
- Launch of accreditation program for Calibration of Air Quality Monitoring Equipment under Chemical Metrology Discipline
- NABCB was one of the first among very few accreditation bodies in the world to have launched an accreditation scheme in Artificial Intelligence Management System (AIMS) last year in Oct 2024
- **Customer Relationship Management:** With an objective to streamline stakeholder engagement and enhance service delivery, NABH has initiated a Customer Relationship Management (CRM) tool which will be designed to manage interactions and improve relationships with stakeholders.
- **Website Revamp:** NABH website revamp has been initiated to enhance user experience and accessibility. The UI/UX phase is nearing completion, with stakeholder feedback being incorporated before transitioning to the development phase.
- **E-Mitra:** A chatbot integrated with a digital library is being developed to provide seamless assistance by fetching videos and templated forms tailored to user queries.
- **Hospital in a Box:** This initiative is being designed to support hospitals in their quality journey with NABH, and will focus on creating a repository of process-oriented documents in phase-wise manner. Phase 1 will target entry-level hospitals, during the next phase NABH will plan to expand this initiative to other NABH programs to establish robust quality systems.
- **Gunvatta Yatra:** NABH-QCI is driving the Gunvatta Yatra, a nationwide initiative aimed at engaging directly with hospitals and healthcare providers. Till date NABH has covered cities like Rewari, Ahmedabad, Rajkot, Kochi, Kolkata, Imphal, Hyderabad, Bengaluru, Mysuru, Bhavnagar.
- **Gunvatta Manthan:** The first NABH Gunvatta Manthan, was organized on February 18, 2025 at New Delhi for the accredited Hospitals. The objective of Manthan is to recognize and celebrate the contribution of Quality Ambassadors in the healthcare sector, to engage and empower CEOs in promoting healthcare quality.
- **Brand Building & Communication Strategy:** NABH is working for brand building and to craft a cohesive brand identity and communication strategy to enhance visibility and stakeholder engagement.
- **Release of new and Revised Standards of NABH Program**
  - NABH Accreditation Standards for Hospitals 6th Edition (In 12 Indian languages)
  - NABH Guidebook for Climate Action & Sustainability in Healthcare

- NABH Checklist for Dementia Friendly Hospitals
- NABH Accreditation Standards for Ayush Hospitals - 1st Edition
- NABH Accreditation Standards for Ayush Treatment & Wellness Centers (ATWC)
- NABH Empanelment standards for Medical Value Travel Facilitators - 2nd Edition
- NABH Newsletter
- NABH Digital Health Standards for HIS/EMR Systems- 1st Edition

➤ In FY 2024–25, PPID led a portfolio of 124 projects out of which 50 projects were newly initiated. These newly initiated projects exhibited the diverse nature of projects that PPID delivers – Third-Party Inspection/ Evaluation/Assessment/Quality Assurance (34), Capacity Building & Impact Assessments (10) etc.

➤ Initiated **Gunvatta Yatra**, an initiative that began with a focus on improving healthcare Quality and is now expanding to enhance manufacturing Quality. It promotes NABH, NABCB, and NDIE standards among Small & Large Healthcare Organizations (HCOs), manufacturing associations, and units, particularly in Tier-2, and Tier-3 cities. **48 Yatras were conducted in this duration.**

➤ Initiated **Gunvatta Manthan**, a strategic initiative by QCI aimed at gathering feedback from stakeholders and fostering a culture of Quality through collaboration and actionable solutions. It provides a dedicated platform for stakeholders to share insights and adopt best practices, QCI uses this collective knowledge to enhance strategic planning, advance Quality initiatives, and promote excellence. **Manthans have been conducted for NABCB, NABH, NDIE & PADD.**

PART 1

Introduction

Quality Council of India (QCI) has been set up as a non-profit autonomous society registered under Societies Registration Act XXI of 1860 to establish an accreditation structure in the country and to spread quality movement in India by undertaking a National Quality Campaign. QCI works as the National Accreditation body, supported by the Government but independent in its functioning.

A. VISION:

Creating an eco-system for Quality.

B. MISSION STATEMENT:

The Mission of QCI is to lead nationwide quality movement in India by involving all stakeholders for emphasis on adherence to quality standards in all spheres of activities primarily for promoting and protecting interests of the nation and its citizens.

C. MAIN OBJECTIVES:

To achieve the Mission of QCI by playing a pivotal role in propagating, adoption and adherence to quality standards in all important spheres of activities including education, healthcare, environment protection, governance, social sectors, infrastructure sector and such other areas of organized activities that have significant bearing in improving the quality of life and well being of the citizens of India and without restricting its generality shall inter-alia include:

(a) To lead nationwide quality movement in the country through National Quality Campaign aimed at creating awareness amongst citizens, empowering them to demand quality in all spheres of activities, and promoting and protecting their well being by encouraging manufacturers and suppliers of goods and service providers for adoption of and adherence to quality standards and tools.

(b) To develop apropos capacities at the level of Governments, Institutions and enterprises for implementing & institutionalizing continuous quality improvement.

(c) To develop, establish & operate National Accreditation programmes in accordance with the relevant international standards & guides for the conformity assessment bodies certifying products, personnel, management systems, carrying out inspection testing, calibration & medical laboratories, proficiency testing providers, reference material producers & test facilities adhering to OECD Principles of Good Laboratory Practices and such other areas of organized activities that have significant bearing in improving the quality of life and well being of the citizens of India.

(d) To develop, establish and operate National Accreditation Programmes for various service sectors such as education, healthcare, environment protection, governance, social sectors, infrastructure sector, vocational training etc., to site a few, as may be required, based on national/ international standards and guidelines and where such standards are not available, to develop accreditation standards to support accreditation programmes.

(e) To build capacities in the areas of regulation, conformity assessment and accreditation to overcome TBT/SPS constraints;

To establish and maintain strong linkages with international and regional fora such as International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), International Accreditation Forum (IAF), Asia Pacific Laboratory Accreditation (APLAC), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), International Society for Quality in Healthcare (ISQua), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) etc. and to participate in Plenary Sessions, Committee Meeting etc. in order to keep pace with the latest development and for promoting Multi-lateral Recognition Arrangements/Mutual acceptance of Data and

To undertake all the activities which promote Bi-lateral/ Multi-lateral Recognition Arrangements between QCI/ Constituent Boards and Accreditation Bodies in other countries.

(f) To encourage development & application of third party assessment model for use in government, regulators, organizations and society.

(g) To promote quality competitiveness of India's enterprises especially MSMEs through adoption of and adherence to quality management standards and quality tools.

(h) Promoting the establishment of quality improvement and benchmarking centre, as a repository of best international / national practices and their dissemination among the industry in all the sectors.

(i) To encourage industrial / applied research and development in the field of quality and dissemination of its result in relevant publication and trade journals;

To Publish books, literature & periodicals and disseminate information related to the objectives of QCI and

To organize / participate in trade fairs, exhibitions, seminars etc. at National & International fora.

(j) To build capacities including development of appropriate quality accreditation mechanism for other emerging areas that have significant bearing in improving the quality of life and well being of the citizens of India such as food sector, oil & gas, forestry, agriculture /animal husbandry, warehouse, pharmacy etc. or as the need may arise from time to time.

(k) To facilitate effective functioning of a National Information & Enquiry Services on standards & quality including an appeal mechanism to deal with unresolved complaints.

(l) To develop and operate an appeal mechanism to deal with unresolved complaints.

GOVERNING COUNCIL

As provided for in the rules and regulations of the Council, the members on the Council are as under:

The Chairperson	Quality Council of India, Institution of Engineers Building, 2nd Floor, 2 - Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Secretary	Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry, Udyog Bhawan, New Delhi-110011
Secretary	Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Udyog Bhawan, New Delhi-110011
Secretary	Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016.
Secretary	Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Chairman DCC & Secretary(T)	Department of Telecommunication, Ministry of Communications, Sanchar Bhawan, 20 Ashoka Road New Delhi- 110001
Secretary	Department of Health & Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi - 110011
Chairman & CEO	Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001
Director General	Directorate General of Quality Assurance (DGQA), D-1 Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011
Director General	Bureau of Indian Standards (BIS), 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002, India
Director General	Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi -110 001
Director General	Standardisation Testing and Quality Certification (STQC), Ministry of Electronics & Information Technology, Electronics Niketan, III Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi - 110 003
Director	National Physical Laboratory (NPL), Dr. K.S. Krishnan Marg, New Delhi – 110012
President	Confederation of Indian Industry (CII), 23, Lodhi Institutional Area, New Delhi -110 003
President	The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM), 5, Sardar Patel Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110 021
President	Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), Federation House, Tansen Marg, New Delhi-110 001
President	Federation of Indian Export Organization (FIEO), Niryat Bhawan, Rao Tularam Marg, Opp. Army Hospital, New Delhi, Delhi-110057
President	Indian Industries Association (IIA), IIA Bhawan,Vibhuti Khand, Phase II, Gomtinagar, Lucknow - 226010
President	Indian Merchant Chambers (IMC), IMC Bldg, IMC Marg, Station, opp. Churchgate, Churchgate, Mumbai, Maharashtra-400020
Secretary General	Quality Council of India, Institution of Engineers Building, 2nd Floor, 2 - Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002

Chairperson, NABCB	Institution of Engineers Building, 1st Floor, 2 - Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Chairperson, NBQP	ASHI Building, 19, Rouse Avenue Institutional Area, New Delhi-110002
Chairperson, NABH	ITPI Building, 4-A, Ring Road, IP Estate, New Delhi-110002
Chairperson, NABET	ITPI Building, 4-A, Ring Road, IP Estate, New Delhi-110002
Chairperson, NABL	NABL House Plot No. 45, Sector 44, Gurugram-122003, Haryana
Chairperson	Finance Committee, B-Block, Sec-58, Noida -201307
Representative	PHD Chamber of Commerce & Industry (PHDCCI), "Navin House, Near Sadar Patel, Sewa Samaj Hall, Navrangpura, Ahmedabad-380006 (Gujarat)"
Secretary General	Consumer Electronics & Appliances Manufacturers Association (CEAMA), F-4 / 23, 4th Floor, Wave 1st Silver Tower, Sector 18, Noida, Uttar Pradesh-201301
Chairman	Engineering Export Promotion Council (EEPC), "'Vandhna', 4th Floor, 11, Tolstoy Marg, New Delhi 110001"
MD, Deki Electronics Ltd.	Nominee, Electronic Industries Association of India (ELCINA), Elcina House, 422, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-10020
DDG (Agri. Education)	Indian Council for Agricultural Research (ICAR), Krishi Bhavan, New Delhi-110 001
Member	Managing Committee, Sportscom Industry Confederation, 24-25 Institutional Area Lodhi Road, New Delhi - 110003
Chief Executive Officer	National Skill Development Corporation (NSDC), 301, 3rd Floor, West Wing, World Mark 1, Asset 11, Aerocity, New Delhi-110037
National President	Indian Drug Manufacturers' Association (IDMA), 102, Poonam Chambers, 'A' Wing, 1st Floor, Dr. A. B. Road, Worli, Mumbai-400 018
Representative	Confederation of Real Estate Developers' Associations of India (CREDAI), PHD House, 5th Floor, 4/2 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110 016
Chief Executive	National Cooperative Union of India (NCUI), 3, Siri Institutional Area August Kranti Marg, New Delhi-110016 (India)
Drugs Controller General (India)	Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), DGHS, MoH&FW, FDA Bhavan, ITO, Kotla Road, New Delhi-110002
General Secretary	Consumer Guidance Society of India (CGSI), Block J, Azad Maidan, Opposite Cama Hospital, Mahapalika Marg, Fort, Mumbai-400001, Maharashtra

GOVERNING BODY

Governing Body has following members:

The Chairperson	Quality Council of India, Institution of Engineers Building, 2nd Floor, 2 - Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Secretary	Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry, Udyog Bhawan, New Delhi-110011
Commerce Secretary	Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Udyog Bhawan, New Delhi-110011
Secretary	Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016.
Chairman & CEO	Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001
Director General	Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Anusandhan Bhawan, 2 Rafi Marg, New Delhi-110 001
President	Confederation of Indian Industry (CII), 23, Lodhi Institutional Area, New Delhi -110 003
President	Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), Federation House, Tansen Marg New Delhi-110 001
President	The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM), 5, Sardar Patel Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110 021
Director General	Standardisation Testing and Quality Certification (STQC), Ministry of Electronics & Information Technology, Electronics Niketan, III Floor, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
President	Indian Industries Association (IIA), IIA Bhawan, Vibhuti Khand, Phase II, Gomtinagar, Lucknow-226010
Member	Managing Committee, Sportscom Industry Confederation, 24-25 Institutional Area Lodhi Road, New Delhi - 110003
Chairperson, NABCB	Institution of Engineers Building, 1st Floor, 2 - Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Chairperson, NBQP	ASHI Building, 19, Rouse Avenue Institutional Area, New Delhi-110002
Chairperson, NABH	ITPI Building, 4-A, Ring Road, IP Estate, New Delhi-110002
Chairperson, NABET	ITPI Building, 4-A, Ring Road, IP Estate, New Delhi-110002
Chairperson, NABL	NABL House Plot No. 45, Sector 44, Gurugram-122003, Haryana
Chairperson	Finance Committee, B-Block, Sec-58, Noida -201307
Representative	Confederation of Real Estate Developers' Associations of India (CREDAI), PHD House, 5th Floor, 4/2 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110 016
Representative	PHD Chamber of Commerce & Industry (PHDCCI), Navin House, near Sardar Patel Sewa Samaj Hall, Navrangpura, Ahmedabad - 380006
Secretary General	Quality Council of India, Institution of Engineers Building, 2nd Floor, 2 - Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

STRUCTURE

QCI functions through the Governing Body and other executive bodies (Boards/ Committees) for implementing the strategy, policy and operational guidelines set out by the Governing Council with a view of achieving international acceptance and recognition.

The various bodies of QCI are as under (as mentioned in Governance Structure):

(i) The Governing Council (GC)

(ii) The Governing Body (GB)

(iii) Finance Committee (FC)

(iv) Accreditation Boards (ABs) and Quality Promotion Board

In addition, the organisation has a full-fledged Secretariat which manages the administrative, financial as well as the technical functions as authorized by the Governing Body from time to time..

The Governance Structure and Administrative Structure of QCI are as per Figure-1 and Figure-2.

GOVERNANCE STRUCTURE

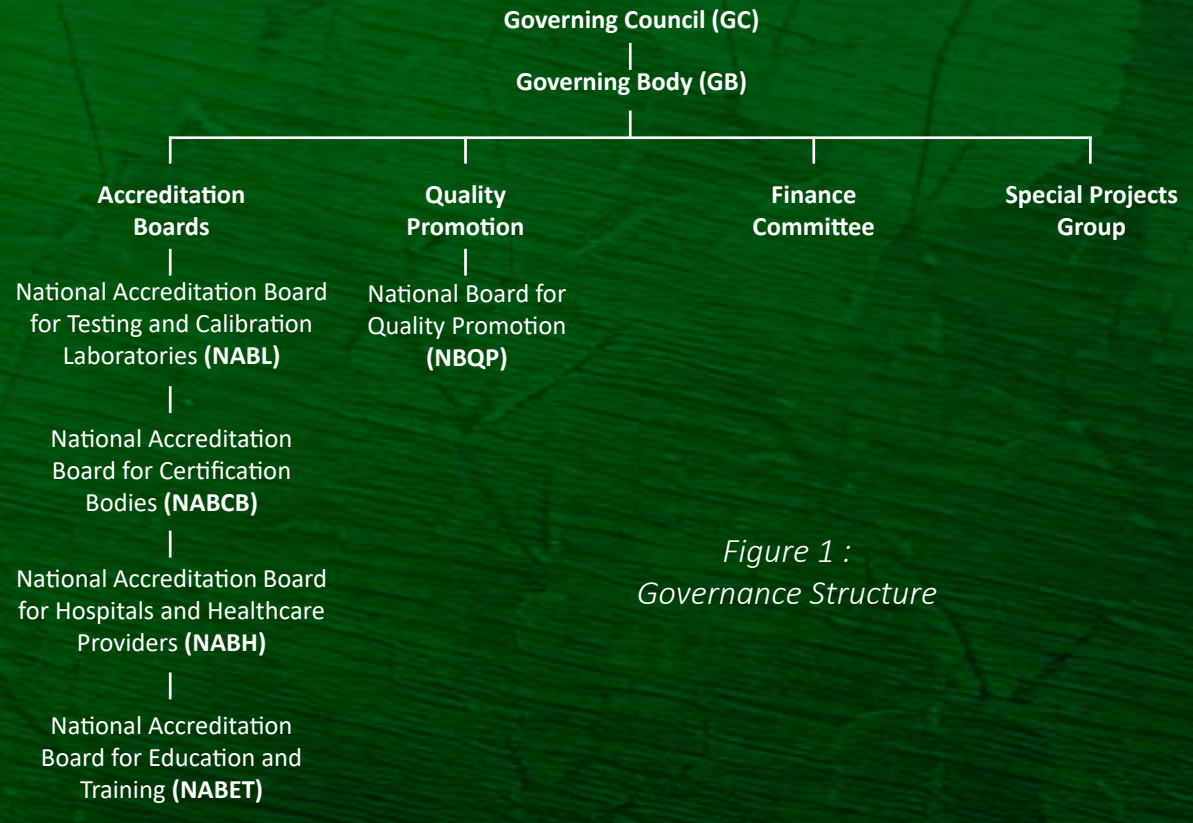


Figure 1 : Governance Structure

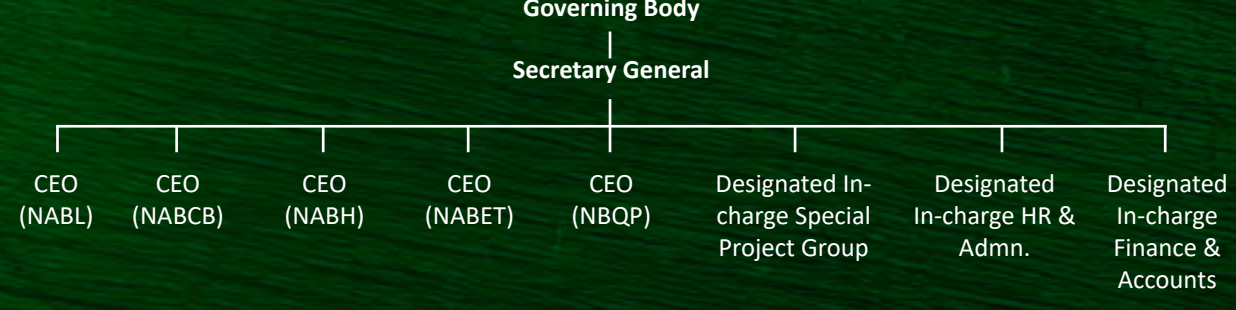


Figure 2 : Administrative Structure

OUR SOCIAL MEDIA PRESENCE



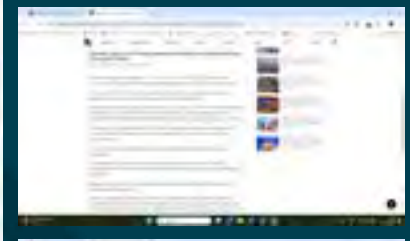


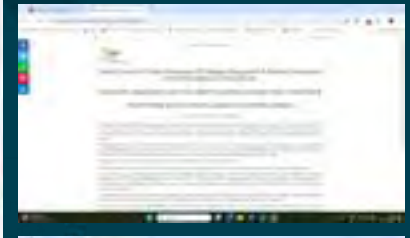






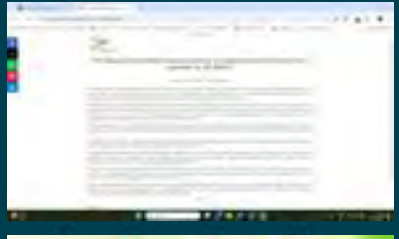






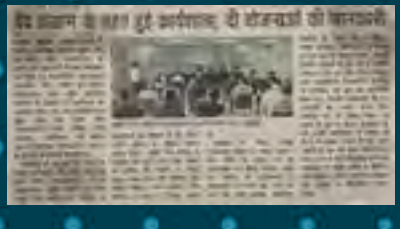


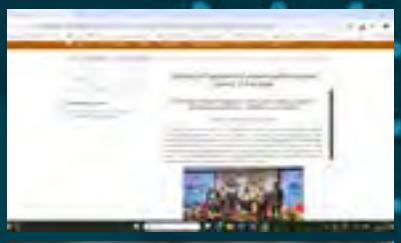




















राज एक्सप्रेस

रैंप प्रोग्राम में भाग लेकर उद्योगों को लाभ लेने प्रोत्साहित करें एसोसिएशन







जिले के उद्योगों को जेड सर्टिफाइड बनाने के लिए हुई कार्यशाला





एमएसएमई विभाग की कार्यशाला सम्पन्न



राष्ट्रीय हिन्दी मेल

रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस को लेकर कार्यशाला आयोजित



रैम्प योजना के तहत सागर में कार्यशाला का आयोजन



PART
2

ANNUAL REVIEW OF ACTIVITIES OF BOARDS/ DIVISIONS/ CELLS FOR THE FY 2024-25



NABL

1 NATIONAL ACCREDITATION BOARD FOR TESTING AND CALIBRATION LABORATORIES (NABL)

National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) has been working towards its vision of becoming the world's leading accreditation body and to enhance stakeholders' confidence in its services. The quality of services offered by NABL has never been compromised in the journey of scaling up the number of accredited CABs. In line with the mission of NABL, the activities to strengthen the accreditation system like empaneling competent assessors, creating awareness among the stakeholders, initiating new programs supporting accreditation activities and pursuing organizational excellence have been undertaken.

NABL provides voluntary accreditation services to:

- Testing laboratories as per ISO/IEC 17025:2017
- Calibration laboratories as per ISO/IEC 17025:2017
- Medical laboratories as per ISO 15189:2012/2022
- Proficiency testing providers as per ISO/IEC 17043:2010/2023
- Reference material producers as per ISO 17034:2016

NABL is complying to ISO/IEC 17011: 2017 "conformity assessment – requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies".

INTERNATIONAL RECOGNITIONS

NABL is a full member and a signatory (since 2000) to International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) as well as Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Mutual Recognition Arrangements (MRA), which is based on peer evaluation. Such international arrangements facilitate acceptance of test / calibration results between countries which MRA partners represent.

OBJECTIVES

a) To promote, implement and maintain an accreditation system for laboratories, PTP & RMP in accordance with the relevant national and international standards, suitable for the country and responsive to changing needs.

b) To provide timely accreditation services to accredited and applicant conformity assessment bodies.

c) To organize awareness programs on all aspects of conformity assessment body's accreditation by various means including seminars, workshops, conformity assessment body-industry-accreditation body meets.

d) To prepare and maintain database of assessors and experts in different disciplines of testing, calibration, medical testing, PTP, RMP and undertake regular monitoring of assessors.

e) To undertake appropriate training programs in support of laboratory / RMP / PTP accreditation and related activities and for their improvement, like training of assessors, accreditation officers.

f) To develop and operate mechanisms to deal with complaints as well as appeals against NABL decisions on accreditation.

g) To establish and maintain linkages with international and regional bodies such as International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) through active participation in various meetings and activities of such bodies.

h) To undertake all the activities that shall promote bilateral / multilateral (mutual) Recognition Arrangements between NABL and accreditation bodies in other countries for wider acceptance of test results of NABL accredited conformity assessment bodies.

1.1 TESTING

- 1079 Testing Labs were granted accreditation as per ISO/IEC 17025: 2017 (Total of 5755 Testing Laboratories accredited by NABL).
- 314 Accreditation committees were conducted for recommending decisions on accreditation.
- 40 Accreditation committees for integrated assessments involving Regulators like FSSAI, EIC, APEDA, etc were conducted.
- 207 Laboratories got benefit from the integrated assessment scheme (EIC, IOPEPC and APEDA) for export market; FSSAI and Commodity Boards for domestic market.
- Accredited 489 (with 121 fresh accreditation) District Water Testing Laboratories of Ministry of Jal Shakti, Public Health Engineering Department, Government of India. A total

of 855 (with 248 fresh recognition) Water Testing Laboratories recognised under G-LAP Accreditation program.

- Granted fresh accreditation to 18 labs with total 119 accreditation in QA testing for diagnostic radiology under recognition scheme of AERB.
- 433 recognition given to Soil Testing Laboratory Program

1.2 CALIBRATION

- 171 Calibration Labs were accredited as per ISO/IEC 17025:2017 (A total of about 1152 Calibration Laboratories accredited by NABL).
- 5 laboratories were granted accreditation under Medical Device Calibration. Total number of accredited lab is 69 in Medical Device Calibration.
- 98 Accreditation committees were conducted for recommending decisions on accreditation.

1.3 MEDICAL

- 440 Medical Labs accredited as per ISO 15189 (A total of 2146 Medical laboratories accredited by NABL)
- 147 Accreditation committees were conducted for recommending decisions on accreditation.

1.4 PROFICIENCY TESTING PROVIDER (PTP)

- NABL has 69 Proficiency Testing Providers (PTPs) accredited in various areas of Testing, Calibration and Medical disciplines. 10 new PTPs were granted accreditation in the current year.
- 10 Accreditation committees were conducted for recommending decisions on accreditation of PTPs.

1.5 REFERENCE MATERIAL PRODUCER (RMP)

- NABL has 20 Reference Material Producers (RMPs) accredited, out of these 5 have been granted accreditation in current year. For the first time, RMP producing Certified Reference Materials (CRMs) for Pesticides is added under NABL Accreditation. This is a remarkable initiative by RMP under 'Make in India' as it will significantly reduce the money spent by laboratories in procuring CRMs from outside India.
- 8 Accreditation committees were conducted for recommending decisions on accreditation of RMPs.

CONCLAVE: 8th RMP/PTP Conclave held during August 30-31, 2024 at Mysuru

The 8th Proficiency Testing Provider / Reference Material Producer (PTP / RMP) conclave was successfully conducted on August 30 and 31, 2024 at Mysuru. Around 140 participants attended including representatives from Proficiency Testing Providers (PTPs), Reference Material Producers (RMPs), Testing Laboratories, Calibration Laboratories, Medical Testing Laboratories and Government and Regulatory bodies participated in the conclave. The conclave provided an opportunity for participants to discuss and share ideas about the technical challenges and opportunities in their fields. The conclave had presentations from accredited PTPs and RMPs on their PT schemes and RM production plan. First prize was won by a PT Provider (PTP) Green Economy Initiatives Private Limited, Zirakpur. Second prize also went to another PT Provider Landmark Material Testing & Research Laboratory Pvt. Ltd., Jaipur. Third prize was won by a Reference Material Producer (RMP) HPCL RMP, Visakhapatnam. A Poster competition was also held wherein the PT Schemes conducted by PTPs were displayed. The winners of the Poster competition were BPCL Proficiency Testing Mumbai, NML Jamshedpur and Export Inspection Agency - Kochi. The conclave was a valuable event for networking, collaboration and exploring new opportunities to conduct proficiency testing and to produce reference materials.

1.6 NABL M(EL)T LABS PROGRAM

- NABL voluntary program namely "NABL Medical (Entry Level) Testing M(EL)T Laboratory program" for sensitizing medical testing laboratories performing basic testing to improve the quality practices and provide access to quality health care for majority of citizens, especially those residing in villages, small towns. This scheme is an independent

quality assurance scheme, which is not covered under APAC & ILAC MRA. 377 Labs got benefit from the M(EL)T Labs Program in FY 2024-25.

1.7 QUALITY

- NABL maintains its APAC MRA signatory status in accordance with ISO/IEC 17011: 2017.
- NABL conducted its internal audit from June 19 to 25, 2024 by 08-member team including 06 external trained auditors.
- NABL has conducted three Risk committee and Impartiality committee meetings.
- NABL has amended/released 10 documents.

1.8 NABL AWARENESS/TRAINING PROGRAMS

GUNVATTA PATHSHALA - NABL ASSESSORS' TRAINING PROGRAMS AS PER ISO/IEC 17025:2017			
SI.	**VENUE**	**DATE**	**NO. OF ASSESSORS TRAINED**
1	Chennai	April 27 – May 1, 2024	24
2	Bengaluru	May 13 – 17, 2024	24
3	Kolkata	May 14 – 18, 2024	21
4	Mumbai	May 26 – 30, 2024	19
5	Delhi	May 27 – 31, 2024	21
6	Hyderabad	May 27 – 31, 2024	22
7	Chennai	May 27 – 31, 2024	21
8	Pune	May 28 – June 1, 2024	22
9	Kolkata	June 11 – 15, 2024	22
10	Bengaluru	June 11 – 15, 2024	22
11	Mumbai	June 11 – 15, 2024	22
12	Chennai	June 11 – 15, 2024	19
13	Delhi	June 12 – 16, 2024	21
14	Delhi	June 19 – 23, 2024	15
15	Delhi	June 24 – 28, 2024	20
16	Pune	June 24 – 28, 2024	16
17	Hyderabad	June 24 – 28, 2024	19
18	Ahmedabad	June 25 – 29, 2024	21
19	Delhi	August 5 – 9, 2024	19
20	Hyderabad	September 9 – 13, 2024	19
21	Bengaluru	August 25 – 29, 2024	18

22	Gurugram	October 14 – 18, 2024	20
23	Bengaluru	November 18 – 22, 2024	21
24	Mumbai	December 9 – 13, 2024	23
25	Madurai	January 20 – 24, 2025	14
26	Gurugram	February 17 – 21, 2025	21
Gunvatta Pathshala - NABL Assessors' Training Programs as per ISO 15189:2022			
27	Delhi	November 18 – 22, 2024	28
28	Chennai	November 27 – December 1, 2024	22
29	Pune	February 4 – 8, 2025	23
30	Kolkata	February 11 – 15, 2025	25
Gunvatta Yatra - NABL Awareness program on accreditation/recognition programs			
Sl. No.	**State**	**City**	**Number of programs**
1	Rajasthan	Jaipur, Udaipur, Bikaner, Jodhpur, Pali, Kota	10
2	Uttar Pradesh	Varanasi, Noida, Meerut	3
3	West Bengal	Kolkata, Jalpaiguri, Durgapur, Malda, Siliguri, Bardhaman, Purba Midnapur, Hoogly, Barrackpore, Purba Bardhaman, Coochbehar, Tamluk, Paschim Medinipur, Baharampur, Bankura, North 24 Paraganas, Birbhum, Uttarpara, Purulia, South 24 Parganas, Malda, Howrah	36
4	Delhi	New Delhi	3
5	Gujarat	Vadodara, Ahmedabad, Rajkot, Veraval, Surat, Gandhinagar, Navsari, Junagadh, Mehsana, Vapi, Dahej, Sardarkrushinagar, Porbandar, Morbi, Karamsad, Anjar, Bhuj, Jamnagar, Amreli, Ankleshwar, Bharuch, Bhavnagar, Vadnagar	46
6	Madhya Pradesh	Indore, Bhopal, Dr. Ambedkar Nagar (Mhow), Gwalior, Datia, Satna, Jabalpur	13
7	Karnataka	Mysuru, Mangaluru, Hubballi, Bengaluru, Chikkamagaluru+1, Raichur, Moodbidri, Belagavi, Chickballapur	21

8	Telangana	Hyderabad	7
9	Tamil Nadu	Madurai, Thoothukudi, Chennai, Pudukkottai, Thanjavur, Tiruchirappalli, Hosur, Gummidipoondi, Vellore, Kancheepuram, Chengalpattu, Dindigul, Tirupur, Virudhunagar, Coimbatore, Tirunelveli, Krishnagiri, Madurai, Salem	26
10	Kerala	Calicut, Thiruvananthapuram, Kochi	4
11	Assam	Guwahati, Dibrugarh, Sonitpur	5
12	Puducherry	Puducherry	2
13	Punjab	Bhatinda, Ludhiana, Jalandhar	3
14	Maharashtra	Nagpur, Mumbai, Aurangabad, Kopargaon, Nashik, Pune, Kolahpur, Amravati	22
15	Manipur	Imphal	2
16	Chhattisgarh	Raipur	1
17	Odisha	Mayurbhanj, Cuttack, Bhubaneswar, Keonjhar, Rourkela, Puri, Angul, Behrampur, Paradeep, Rourkela	15
18	Himachal Pradesh	Shimla	1
19	Andhra Pradesh	Visakhapatnam, Sri City, Kakinada	3
20	Meghalaya	Shillong	1
21	Bihar	Patna, Mahua	2
22	Lakshadweep	Kavaratti Island	1
23	Goa	Panaji	1
24	Jharkhand	Jamshedpur, Ranchi, Dhanbad, Bokaro	6
25	Haryana	Bahadurgarh	1

Other Programs (National)

- NABL, jointly with NABCB, celebrated World Accreditation Day 2024 on June 10, 2024 at New Delhi. It was conducted by NABL in 20 other cities pan India in 10 Regional Languages on the theme "Accreditation: Empowering Tomorrow and Shaping the Future", which focused on how accreditation can help shape various aspects of life in our changing world.
- Launch of accreditation program for Calibration of Air Quality Monitoring Equipment under Chemical Metrology Discipline.
- Launch of Accreditation program for Biobanking (ISO 20387).

INTERNATIONAL PARTICIPATION BY NABL

Sl.	Name of the Activity	Date
Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)		
1	APAC evaluation of KAN-Indonesia as Provisional Evaluator	May 25 – June 1, 2024
2	APAC Executive Committee & MRAMC Meeting and 2024 APAC Annual Meetings at Dubai	July 14 - 18, 2024
3	ADAPT Digitalization WG Online Meetings:	May 22, 2024, July 26, 2024, September 18, 2024, October 24, 2024, November 25, 2024, January 30, 2025, March 25 2025
4	IAAC APAC Joint Online Webinar on Digitalization Transformation in Accreditation	July 31, 2024
5	Online ADAPT Workshop on Digital Assessment Tool & Techniques: Experience Sharing (Post Assessment)	August 7, 2024
6	APAC Evaluation of United Accreditation Foundation (UAF), USA as APAC Team Leader	August 5 – 10, 2024
7	ADAPT Digitalization Network meeting	April 17, 2024, May 21, 2024, August 28, 2024, November 16, 2024, February 5, 2025, March 19, 2025
8	Online ADAPT Project Steering Committee Meeting	May 22, 2024, July 13, 2024, September 12, 2024, February 5, 2025
9	Attended APAC ISO 20387 Biobanking Training at A2LA, USA	September 10 – 12, 2024
10	Online Workshop - Production of Qualitative Reference Materials organized by EURACHEM	September 19, 2024
11	APAC MRAMC Meeting at Berlin, Germany	September 29, 2024
12	APAC Executive Committee Meeting at Berlin, Germany	September 30, 2024
13	APAC Evaluation of AAC “Analytica”, Federation of Russia as APAC Team Leader & Evaluator	October 19 – 26, 2024

14	**Conducted the following event of APAC** 1. Online ADAPT Experience Sharing Workshop on Assessment activities 2. Hosted APAC Training program related to Accreditation of Medical Testing (ISO 15189) labs and APAC Evaluators Workshop (Medical testing evaluators) at New Delhi 3. Online ADAPT Experience Sharing Workshop on Post Assessment activities 4. Online ADAPT workshop on Digitalization of Online Training 5. Online Workshop on Change Management to Support CABs	1. May 10, 2024 2. June 24 – 28, 2024 3. August 7, 2024 4. September 10, 2024 5. October 16, 2024
15	APAC Evaluator Training Working Group meetings to prepare Shanghai Evaluator Training Material	November 8, 2024, December 13, 2024, January 9, 2025, January 31, 2025
16	APMP - APAC PTWG Meeting as APAC EC delegates at NPL, India	November 24, 2024
17	APAC - Accreditation of RMP (ISO 17034) and relevant ISO 3340x series at Muscat, Oman	December 2 – 6, 2024
18	Online-Euro Lab - 23IND13 Screen Food project - (Stakeholders workshop) - Safety of Sustainable Food Packaging State-of-the-art and needs for contaminant assessment	February 12, 2025
19	APAC Peer Evaluation of IAS, USA (Extension of Scope) as APAC Evaluator team at Bahrain	January 29 – 30, 2025
20	Online ADAPT PSC Sub-WG on Trainer Organizations' Specifications Drafting	February 18, 2025
21	APAC Nominated Peer Evaluator Training Program at Shanghai, China	February 24 – 25, 2025
22	APAC Lead Evaluator Workshop at Shanghai, China	February 26 – 27, 2025
23	APAC MRAMC and APAC Executive Committee Meetings at Shanghai, China	February 28 – March 1, 2025
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)		
24	30 Officers participated in online IAF/ILAC Mid Term (ILAC Accreditation Committee-AIC) Meeting	April 10, 2024
25	27 Officers participated in online IAF/ILAC Mid Term (ILAC Joint Development Support Committee-JDSC) Meeting	April 16, 2024
26	28 Officers participated in online IAF/ILAC Mid Term (ILAC Arrangement Committee-ARC) Meeting	April 18, 2024
27	21 Officers participated in online IAF/ILAC Mid Term (ILAC Inspection Committee-IC) Meeting	April 19, 2024
28	ILAC Annual Meetings 2024, Berlin, Germany	October 1 – 10, 2024

29	ILAC AIC WG Metrology (Newsletter #3)	November 26, 2024
30	ILAC Liaison meeting with ITU	December 20, 2024, January 9, 2025
International Organization for Standardization (ISO)		
31	ISO/TC 334 Reference Material Plenary Meeting	April 19, 2024
32	Participated in the Meeting of ISO TC 212 WG 1 "Quality and Competence in the Medical Laboratory" at Berlin, Germany	May 6 – 8, 2024
33	ISO TC 212 WG 2 "Reference Systems"	May 14 – 15, 2024
34	ISO/TC 334 Reference Material	June 4 – 5, 2024 & June 7, 2024
35	Participation in 46th plenary meetings of the ISO/TC 69, its Subcommittees and Working Groups at Amarante, Portugal	June 17 – 21, 2024
36	ISO/TC 334/WG 10 "RM Terms and Definitions"	August 12 – 14, 2024
37	ISO/TC 212/WG 1 "Quality and Competence in Medical Laboratory"	October 7 – 9, 2024
38	ISO/TC 334/WG 13 "Qualitative Reference Materials"	October 11, 2024
39	ISO/TC 212/WG 2 "Reference Systems"	October 18, 2024
40	ISO/TC 212 "Medical laboratories and Invitro Diagnostic System"	October 25, 2024
41	ISO/TC69/SC6/WG 1 "Accuracy of Measurement Methods and Results"	November 5 – 8, 2024
42	ISO/TC 334/WG 19 "Purity RMs for Metals"	December 19, 2024
43	ISO/TC 69 SC6 WG7 - Statistical methods to support measurement uncertainty evaluation	March 6, 2025



Memorandum of Understanding (MoU) signed between (NABL) and (PHDCCI)



Memorandum of Understanding (MoU) signed between (NABL) and (PHDCCI)





Memorandum of Understanding (MoU) signed between (NABL) and (EEPC)



MoU signed between NABL & Confederation of Real Estate Developers' Associations of India (CREDAI)

8th Conclave for Proficiency Testing Providers (PTPs) and Reference Material Producers (RMPs)

NABL 8th Conclave for Proficiency Testing Providers (PTPs) and Reference Material Producers (RMPs)

The program was successfully conducted on 30th and August 31, 2024 at Mysuru. Around 140 participants attended, including representatives from Proficiency Testing Providers (PTPs), Reference

Material Producers (RMPs), Testing Laboratories, Calibration Laboratories, Medical Testing Laboratories, and Government and Regulatory bodies.

The session was inaugurated by Padma Shri Prof. Subbanna Ayyappan, Chairman of NABL, who lit the lamp together with Prof. Venugopal Achanta, the Director of the National Physical Laboratory (NPL), and Mr. N. Venkateswaran, the CEO, NABL.

Key highlights were:

- Accredited PTPs and RMPs displayed their proficiency testing schemes and reference material productions.
- The conclave provided an opportunity for participants to discuss and share ideas about the technical challenges and opportunities in their fields.
- A poster competition was held, wherein the PT scheme conducted by PTPs were displayed through posters.
- The conclave was a valuable event for networking, collaboration, and exploring new opportunities to conduct proficiency testing and to produce reference materials.



World Accreditation Day 2024

NABL, jointly with NABCB, celebrated World Accreditation Day 2024 on June 10, 2024 at 20 cities in India in 10 Regional Languages on the theme "Accreditation: Empowering Tomorrow and Shaping the Future", which focuses on how accreditation can help shape various aspects of life in our changing world.







World Accreditation Day 2024



Gunvatta Manthan - One-Day Discussion Involving Stakeholders from Accredited Laboratories

NABL has conducted Gunvatta Manthan - One-Day Discussion Involving Stakeholders from Accredited Testing, Calibration and Medical Laboratories to gather feedback on their accreditation journey at

a) New Delhi, Delhi, on February 4, 2025

b) Nagpur, Maharashtra, on February 16, 2025

c) Ahmedabad, Gujarat, on March 6 – 7, 2025

d) Chennai, Tamil Nadu, on March 20, 2025

e) Kolkata, West Bengal, on 28.03.2025







Events - Felicitation Ceremony of Newly Accredited Laboratories

Felicitation Ceremony of Newly Accredited Laboratories Conducted by NABL at New Delhi.

a) 1st Felicitation Ceremony of Newly Accredited Laboratories on May 30, 2024

b) 2nd Felicitation Ceremony of Newly Accredited Laboratories on July 1, 2024.

c) 3rd Felicitation Ceremony of Newly Accredited Laboratories on August 1, 2024.

d) 4th and 5th Felicitation Ceremony of Newly Accredited Laboratories on September 4, 2024 and September 26, 2024.

e) 6th Felicitation Ceremony of Newly Accredited Laboratories on November 4, 2024.

f) 7th Felicitation Ceremony of Newly Accredited Laboratories on December 9, 2024.

g) 8th Felicitation Ceremony of Newly Accredited Laboratories on January 7, 2025.

h) 9th Felicitation Ceremony of Newly Accredited Laboratories on February 4, 2025.

i) 10th Felicitation Ceremony of Newly Accredited Laboratories on March 19, 2025







APAC Training Hosted by NABL at New Delhi

APAC Training on Medical Testing (ISO 15189) organised by APAC and hosted by NABL, India during June 24 to 26, 2024.

The in-person, interactive, knowledge-sharing training program for accreditation managers and assessment personnel of APAC Members and APAC Evaluators conducted successfully on June 24 — 26, 2024 on behalf of APAC and hosted by NABL at Hotel Le-Meridien, New Delhi.

The participants were from the 16 Accreditation Bodies, i.e. all economies across the world.

It covers the use of the new edition of ISO 15189 Medical laboratories — Requirements for quality and competence to accredit medical testing facilities and included reference to Point-of-Care testing (POCT) along with the changes in every clause of ISO 15189.



Gunvatta Pathshala – Training Program conducted by NABL

Proficiency Testing Providers (PTPs) and Reference Materials Producers (RMPs) Training Program:

a) Training program on ISO 17034: 2016 “General Requirements for Competence of Reference Material Producers” Date: May 14 - 15, 2024 Venue: Delhi

b) Awareness Program on Proficiency Testing Provider Date – May 22, 2024 Venue – Bharuch

c) Training program on ISO Guide 35 - Characterization and assessment of homogeneity and Stability of Reference Material Date-May 16 -17, 2024 Venue – Delhi

d) Proficiency Testing Providers (PTPs) Training Program on ISO/IEC 17043:2023 & ISO 13528:2022 held at Bengaluru from December 3 – 6, 2024.

e) Training Program on Reference Material Producer as per ISO 17034:2016 on November 26 – 27, 2024 and on ISO Guide 35:2017 on November 28 – 29, 2024 at Pune.

f) ISO 17034 and ISO Guide 35 at Chennai, Tamil Nadu during February 4 – 7, 2025

g) ISO/IEC 17043:2023 and ISO 13528:2022 at New Delhi during March 4 – 7, 2025











NABL Assessors' Training Program as per ISO/IEC 17025:2017 conducted during February 17 - 21, 2025 at Gurugram, Haryana



Gunvatta Yatra – Awareness Program conducted by NABL

NABL has conducted one-day awareness program on NABL accreditation and its benefits. It was an informative session on NABL ISO 15189:2022 standard. The program was conducted at

a) AIIMS Bhatinda, Punjab on July 26, 2024

b) AIIMS, Guwahati, Assam on August 10, 2024

c) AIIMS, Raipur, Chhattisgarh on August 27, 2024

d) Indira Gandhi Medical College and Research Institute, Puducherry on December 6, 2024.

e) AllIMS, Rajkot, Gujarat on December 18, 2024.

f) ESIC Medical College & Hospital, Patna, Bihar on January 24, 2025

g) ESIC Hospital, Bapunagar, Ahmedabad, Gujarat on February 21, 2025













NABL has conducted awareness program on importance of NABL Accreditation and its benefits at

a) ICAR CIFT, Veraval Somnath, Gujarat on July 19, 2024

b) Vapi Industries Association, Vapi, Gujarat on August 12, 2024

c) Virudhunagar, Tamil Nadu on January 30, 2025

d) KLE Technological University, Belagavi (Kunda nagara), Karnataka on February 13, 2025

e) Hyderabad, Telangana, on February 21, 2025

NABL has conducted awareness program on importance of NABL Accreditation and its benefits, M(EL)T recognition scheme and Soil Testing Recognition Scheme at

f) Rathindra Krishi Vigyan Kendra (KVK), Visva-Bharati, Birbhum, Kolkata on 20.12.2024

g) IMS and SUM Hospital, Bhubaneshwar, Odisha on 20.12.2024





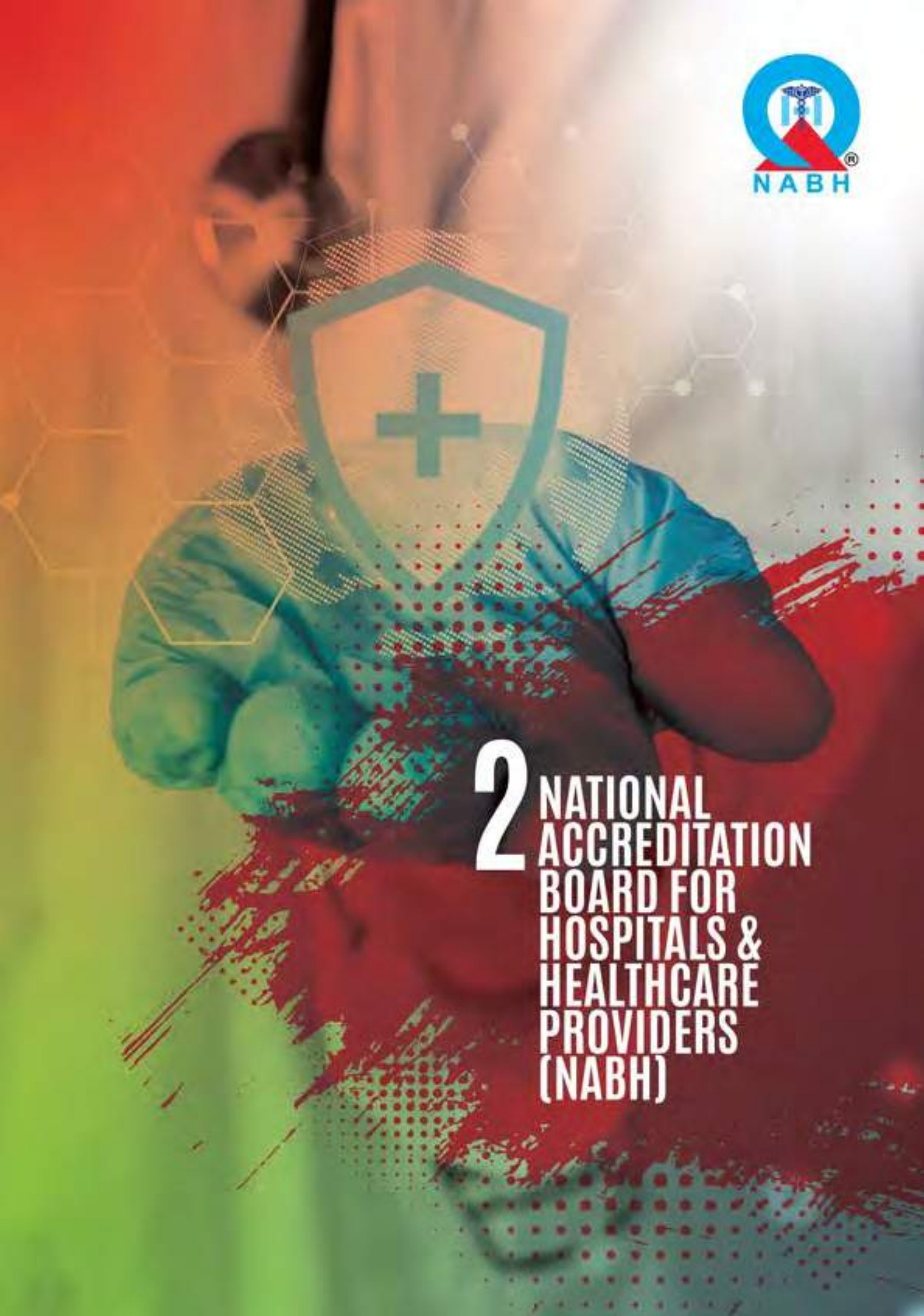












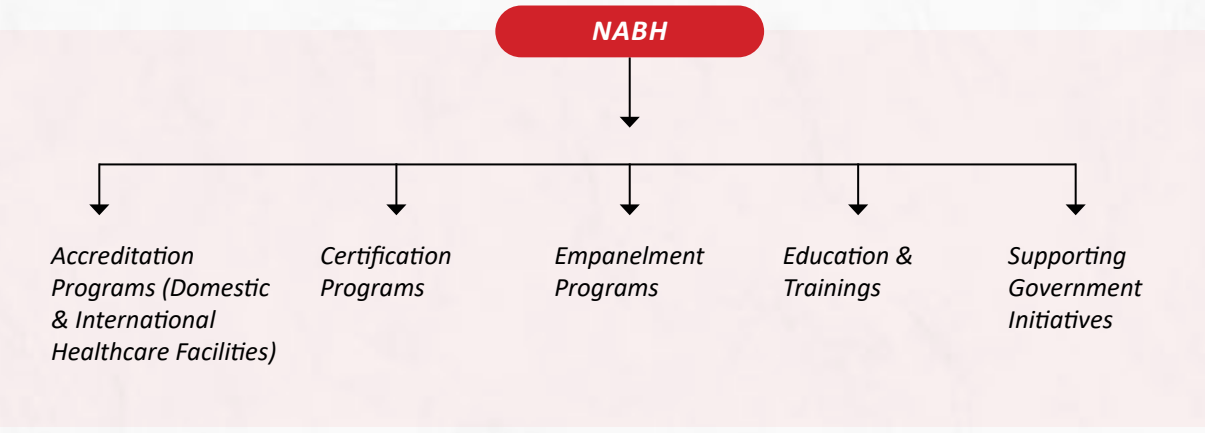
2 NATIONAL ACCREDITATION BOARD FOR HOSPITALS & HEALTHCARE PROVIDERS (NABH)

National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers (NABH), since its inception in 2006, has played a pivotal role in bringing about remarkable & significant positive change in the approach taken by the healthcare providers towards the management & delivery of the healthcare services to the patients. It is one of the constituent boards of Quality Council of India (QCI) and is taking care of the functioning of accreditation, certification & empanelment programs for healthcare organizations. NABH has been established with the objective of enhancing health systems & promoting continuous quality improvement and patient safety. The board while being supported by all stakeholders, including industry, consumers, government, enjoys absolute functional autonomy in its operation. NABH standards focus on patient safety and quality of the delivery of services by the healthcare facilities in the changing healthcare environment. Through its various programs, it focuses on providing the best of healthcare across the masses.

NABH provides accreditation/certification to hospitals in an objective, non-discriminatory manner regardless of their ownership, size and degree of independence.

NABH standards for Hospital Accreditation Program have been accredited by ISQua. NABH as an organization has also been accredited by ISQua. These accreditations authenticates that NABH standards for Hospital accreditation program as well as NABH itself as an organization is in consonance with the global benchmarks set by ISQua.

2.1 NABH Activities



NABH Accreditation Programs: NABH offers accreditation to Hospitals, Blood Banks and Transfusion Services, Small Healthcare Organisations, Dental Care Facilities, Ayush Hospitals, Medical Imaging Services (MIS), Primary Health Centres (PHCs), Allopathic Clinics, Oral Substitution Therapy (OST) Centres, Clinical Trial (Ethics Committees), Eye Care Organisations (ECO) and Panchkarma Clinics, Integrated Rehabilitation Centres For Addicts (IRCAs), Digital Health and Care homes

NABH Certification Programs: NABH offers certification to Medical Laboratories, Nursing Excellence, Entry-Level Certification for Hospitals, Entry-Level Certification for Small Healthcare Organizations, Emergency Department in hospital, Entry-Level Certification for Ayush Centres, Entry-Level Certification for Ayush Hospitals, Entry-Level Certification for Dental Clinics, Certification program for HIS/EMR systems, Stroke Certification.

NABH Empanelment Programs: NABH carries out empanelment programmes for the following a) Central Government Health Scheme (CGHS), b) Ex-Serviceman Contributory Health Scheme (ECHS) and c) Medical Value Travel Facilitator (MVTF).

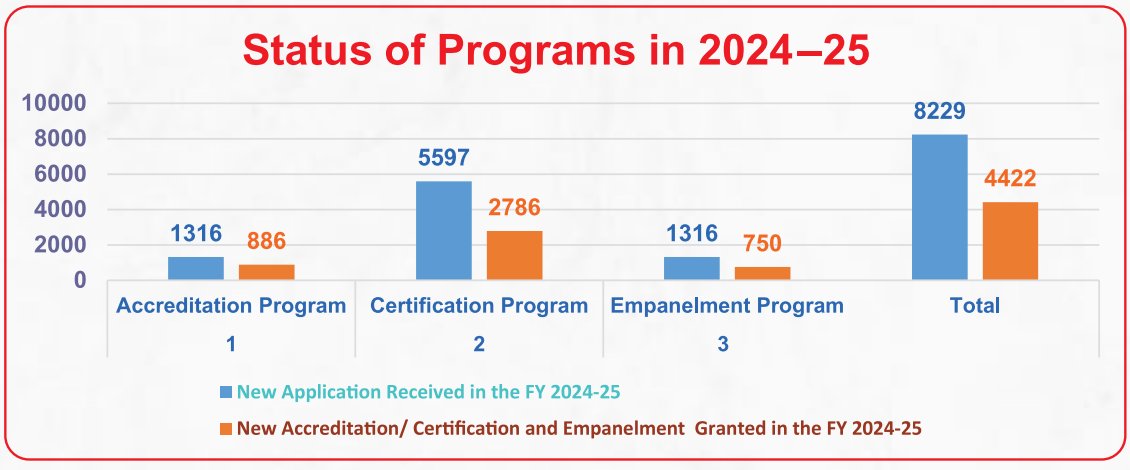
NABH International: NABH offers accreditation services for overseas facilities under Hospital Accreditation Program, Small Healthcare Organisation (SHCO) Accreditation Program, Eye Care Organisation (ECO) Accreditation program & Ayush Accreditation Program.

Trainings & Education: NABH conducts Assessor Training Courses, Programme on Implementation (POIs), Education Interactive Workshops and Awareness Programmes.

2.1.1 During the period of April 2024 to March 2025 following is the status of new application received and new accreditation/certification granted

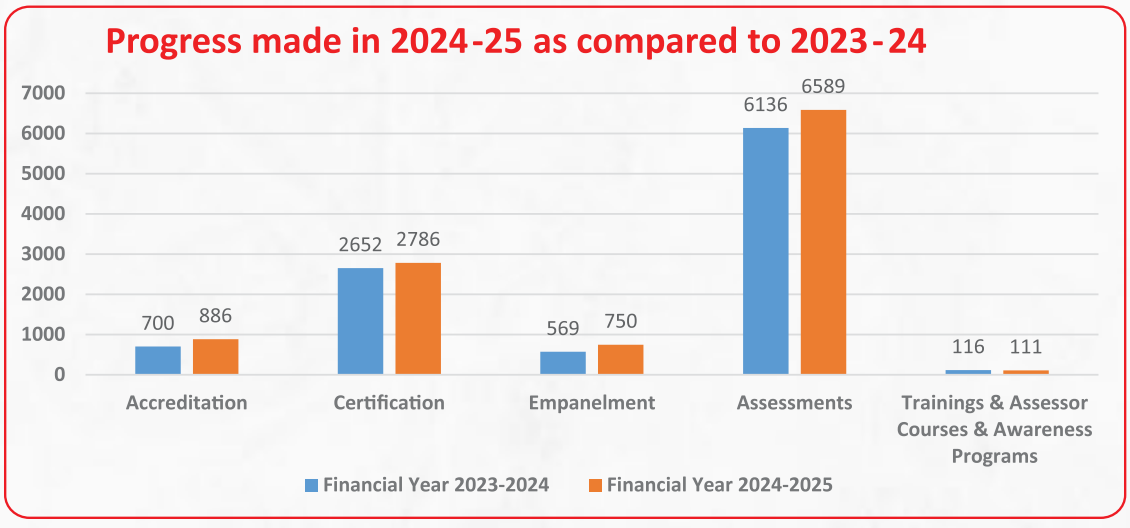
S. NO.	NAME OF THE PROGRAM	NEW APPLICATIONS	NEW ACCREDITATION/ CERTIFICATION
ACCREDITATION PROGRAM			
1	Hospital Accreditation Program	280	181
2	Small Healthcare Organisation (SHCO) Accreditation Program	295	223
3	Blood Bank Accreditation Program	18	8
4	Medical Imaging Services Accreditation Program	133	68
5	Allopathic Clinic Accreditation Program	59	38
6	Dental Accreditation Program	160	90
7	AYUSH Accreditation Program	106	97
8	Panchakarma Clinics Accreditation Program	24	27
9	Clinical Trial (Ethics Committee) Accreditation Program	3	3
10	Eye Care Organization	106	49
11	Digital Health Accreditation Program	127	100
12	Care Homes Accreditation Program	5	2
	Total	**1316**	**886**
CERTIFICATION PROGRAM			
1	Entry-Level Hospital	869	357
2	Entry-Level Small Healthcare Organisation	3093	1364
3	Nursing Excellence Program	59	40
4	Medical Laboratory Program	10	10
5	Emergency Department in the Hospital	22	21
6	Entry-Level Ayush Hospitals	60	60
7	Entry-Level Ayush Centres	14	24
8	Ayush Health & Wellness Centres under NAM	1446	900
9	Stroke Centre Certification Program	17	10
10	HIS/EMR System	7	0
	Total	**5597**	**2786**
EMPANELMENT			
1	Ex Serviceman Contributory Health Scheme (ECHS) Empanelment Program	652	359

2	Central Government Health Scheme (CGHS) Empanelment Program	660	389
3	Medical Value Travel Facility (MVTF) Empanelment Program	4	2
	Total	**1316**	**750**



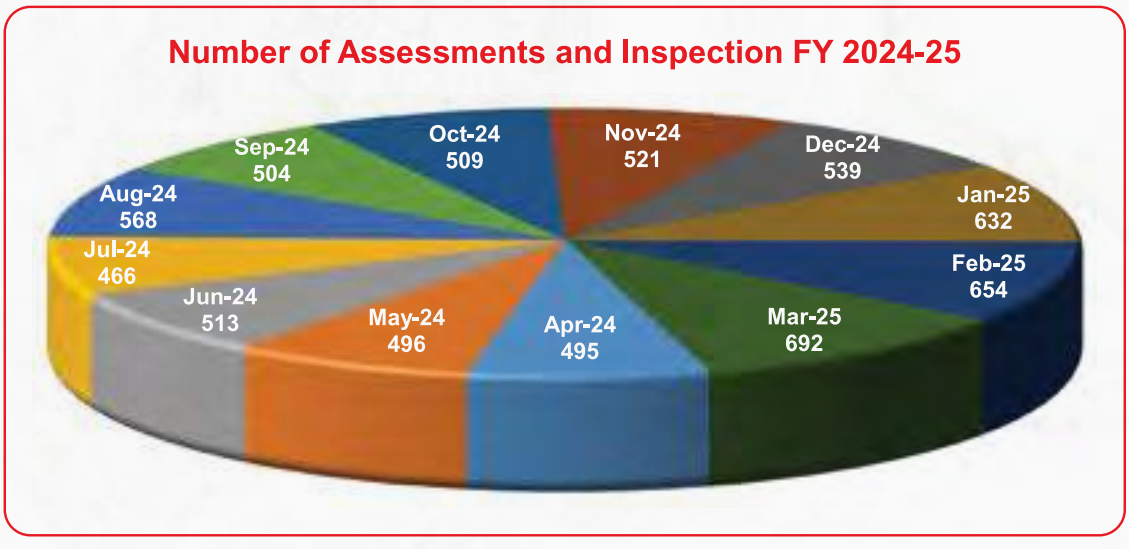
2.1.2 Progress in 2024-25 as compared to 2023-24

ACTIVITIES	FINANCIAL YEAR 2023-2024	FINANCIAL YEAR 202-2025
Accreditation	700	886
Certification	2652	2786
Empanelment	569	750
Assessments	6136	6589
Trainings & Assessor Course	116	111



2.1.3 Number of Assessments and Inspection in the FY 2024-25

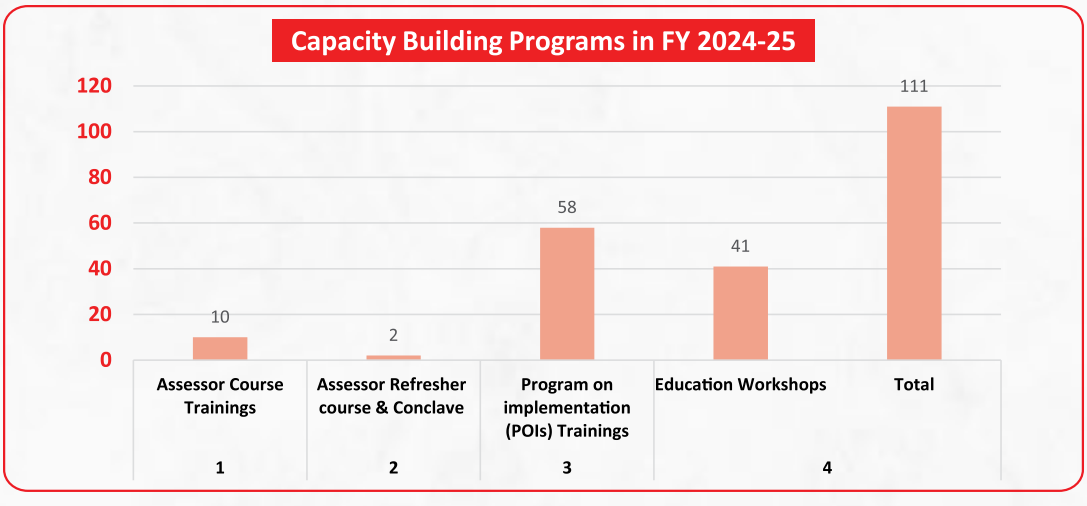
MONTH & YEAR	NUMBER OF ASSESSMENTS
April 2024	495
May 2024	496
June 2024	513
July 2024	466
August 2024	568
September 2024	504
October 2024	509
November 2024	521
December 2024	539
January 2025	632
February 2025	654
March 2025	692
TOTAL	**6589**



2.1.4 Status of NABH Assessor Training Courses, Education Trainigs & Workshops under Quality Connect Learning with NABH

S.NO.	NAME OF TRAINING PROGRAMS	TOTAL NOS.
	ASSESSOR TRAINING COURSE	
1.	Hospital Accreditation Assessor Course	2
2.	Medical Imaging Center Assessor Course	1

3.	Ayush Assessor Course	1
4.	IRCA Assessor Course	1
5.	Entry-Level Hospital & SHCO Certification Assessor Course	4
6.	Digital Health Standard Assessor Course	1
	Total Assessor Courses	**10**
PRINCIPAL ASSESSOR REGIONAL CONCLAVE		
1.	Assessor Refresher Course & Conclave	2
PROGRAMS ON IMPLEMENTATION (POI)		
1.	Hospital Accreditation 6th Edition Standards	22
2.	Hospital Accreditation 5th Edition Standards	14
3.	Ayush Accreditation 2nd Edition Standards	2
4.	Dental Accreditation 3rd Edition Standards	2
5.	HIS/EMR Certification 1st Edition Standard	3
6.	Medical Value Travel Facilitator (MVTF)	2
7.	Digital Health Accreditation 1st Edition Standard	13
	Total POI courses	**58**
EDUCATION AND TRAINING WORKSHOPS		
1	Clinical Audit	13
2.	Continual Quality Improvement	8
3.	Documentation Requirement for Patient Safety	10
4.	Good Clinical Trial Practices (GCP)	10
	Total Education and Training Workshops	**41**



Glimpse of NABH Trainings



NABH Assessors Training Program on Entry-level Hospital Assessor Training Program conducted on April 24 – 26, 2024 in New Delhi



NABH 48th Hospital Assessor training Program conducted on April 29 to May 3, 2024 in New Delhi.



NABH Assessors Training Program on 8th NABH Assessor Course for Ayush Accreditation Program conducted on July 15 to 19, 2024 in New Delhi.



Pivotal three-day Assessor Training Program was successfully held, inclusive of India's top healthcare CIOs and CTOs, represented by CHIME members, along with Hospital Accreditation Program Assessors. This was 3rd Assessor Training on 1st Edition of NABH's Digital Health Standards for Hospitals, a transformative initiative aligning healthcare institutions with cutting-edge digital practices.

2.2 New NABH Participation in Various Forums:

2.2.1 NABH Participation: NABH team participated in 10th NATHEALTH Annual Arogya Bharat Summit held at New Delhi.



2.2.2 NABH team coordinated a powered session at CAHOCON on the impact of accreditation on healthcare quality on April 5 to 7, 2024.



2.2.3 NABH team participated in World Homeopathy Day 2024 hosted by Ministry of Ayush, Government of India in New Delhi on April 10 & 11, 2024.



2.2.4 NABH team Participated in NRCeS Users' Summer Meet held at Pune on May 3, 2024. It was an opportunity to share about adoption of EHR standards, practical challenges, solutions, best practices and future approaches.

Dr. Kumudita Talwar and Dr Priyanka Chauhan presented on NABH initiative in Digital Health Standards, fostering collaboration towards establishment of Interoperable healthcare system across the nation





2.2.5 NABH-Smile Train India Project meeting was held on April 29, 2024, in New Delhi. Dr. Elizabeth Igaga, Smile Train Director, addressed the members regarding the Smile Train Project and Patient Safety aspects. CEO, NABH, provided insights into NABH activities and initiatives, followed by the NABH team presenting the Smile Train Project status report.



2.2.6 NABH has successfully trained over 85 District Ayush Officers (DAOs) from Uttar Pradesh under the NABH Ayush Entry-Level Certification program, as a part of the National Ayush Mission (NAM) for Ayushman Arogya Mandir (AAM).



2.2.7 Ayush MVT Summit was held on September 30, 2024 at Hotel Sofitel, BKC, Mumbai.

The event was organized by Ministry of Ayush, Government of India, in collaboration with the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI).



2.2.8 NABH actively participated in the System Integrators in Digital Health (SIDH) workshops held in Jaipur, Cochin, Bhubaneswar and Bhopal.



2.2.9 NABH team participated in 49th Annual TRANSCON Conference, hosted by Indian Society of Blood Transfusion and Immunohematology (ISBTI) in Gandhinagar, Gujarat





2.2.10 NABH participation - 15th meeting of National Council for Clinical Establishments held on October 30, 2024 at Nirman Bhawan, New Delhi



2.2.11 NABH participated in FICCI HEAL 2024 Conference; a key session was held, focusing on expanding hospital and laboratory accreditation in India, with a special emphasis on NABH's pivotal role.





2.2.12 NABH was honored to participate in the landmark celebrations of Dhanvantari Jayanti and the 9th Ayurveda Day, where Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated transformative projects aimed at advancing healthcare in India.



2.2.13 NABH attended the Stakeholders' Meet-cum-Valedictory Ceremony of the 4th National Pharmacovigilance Week, organized by the National Coordination Centre (NCC) for Pharmacovigilance Programme of India (PvPI) on September 23, 2024 at Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad.



2.2.14 NABH Participated in G-SPARC 2024 (Global South Conference on Infection Prevention and Control and Antimicrobial Stewardship), held at the Shilpakala Vedika, Hitech City, Hyderabad, from October 3 to 5, 2024.



2.2.15 NABH-QCI conducted field visit for Gunvatta Gurukul trainees (Batch 7) at Yashoda Super Specialty Hospitals, Kaushambi, on February 1, 2025. The aim is to provide these students with a unique chance to explore how NABH plays a crucial role in elevating healthcare standards, ensuring Quality Care and Patient Safety across all aspects of hospital operations.



2.2.16 NABH recently participated in a Workshop-cum-training programme on Pharmacovigilance at Fortis Mohali on January 31, 2025, aimed at NABH-accredited hospitals. During the session, Ms. Varsha Srivastava, Deputy Director - NABH, addressed the audience on the significance of ADR (Adverse Drug Reaction) reporting for NABH accredited hospitals in India.



2.2.17 NABH participated in Unani Day 2025 and the International Conference on Innovation in Unani Medicine for Integrative Health Solutions – A Way Forward, organized by the Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM) and Ministry of Ayush, Government of India on February 11 to 12, 2025



2.2.18 NABH participated in Unani Day Celebrations 2025 & International Conference at Jamia Hamdard on February 13, 2025. CEO-NABH highlighted the significance of Unani medicine in holistic healthcare and felicitated Majeedia Hospital for achieving NABH Entry-Level Certification, acknowledging their commitment to quality and patient safety.



2.2.19 NABH participated in the 12th International Patient Safety Conference (IPSC) 2025, organized by Apollo Hospitals at Bharat Mandapam on February 21 to 22, 2025. The event brought together global healthcare leaders to discuss patient safety, quality improvement, and the future of healthcare.



2.2.20 NABH actively participated in the NHA System Integrators in Digital Health (SIDH) workshop held in Kochi on January 31, 2025 and Bhubaneswar on March 7, 2025.







2.2.21 NABH Patient Safety Conference 2024 (NPSC 2024):

Adopting the message and this year's theme, NABH organized a one-day conference "NABH Patient Safety Conference 2024" on September 17, 2024 keeping the theme "**एक स्वस्थ देश, विकसित भारत के लिए**" which was a well-knit structural program to learn and deep dive into all the aspects of patient safety. This event also marked the congregation of the global thought leaders, industry experts and healthcare practitioners sharing their experiences and new innovative approaches to patient safety. This was an ingenious and invigorating conference reflecting the direction of healthcare into a new era of patient safety as NABH had involved experts, representatives and stakeholders from all aspects of healthcare like Hospitals, national organizations, AYUSH, Digital Health, Medical education. The fundamental aim of the conference was to discuss how proactive practices for patient care, streamlined systems for understanding and involving patients in the healthcare systems and decision making can improve patient safety. The conference was well-knit with 7 interactive panel discussions. More than 1000 delegates from all over the country actively participated in this conference which marked this event to be one of the biggest conferences in India.















Quality Pledge

Quality Bharat pledge was taken by more than 1000 Patient Safety Champions. The Quality Bharat Pledge, initiated by the Quality Council of India, is a commitment to fostering a culture of quality across various sectors in India. By encouraging individuals and organizations to embrace quality practices, the pledge aims to enhance productivity, promote sustainable development and improve overall standards of living. Participants in the pledge commit to continuous improvement, innovation, and collaboration, recognizing that quality is a collective responsibility that transcends industries. This initiative not only seeks to elevate the performance of Indian enterprises but also positions India as a global leader in quality excellence, contributing to national growth and global competitiveness.





Shri J P Nadda (Union Health Minister) virtually addressed the participants in NABH patient safety conference on World Patient Safety Day.

The Health Minister urged the hospitals to adopt Digital Technology to manage healthcare data which will help ensure the security and accessibility of patient data.

The Health Minister emphasized the utilization of telemedicine e-health services in remote areas where access to specialized medical experts is limited. He mentioned that when patient data is transferred from one hospital to another, several challenges occur which include data security, interoperability and accuracy of information. He added that government is continuously making efforts to promote innovations and expand digital healthcare. He informed that QCI-NABH's accreditation system has played a vital role in raising the standards of healthcare services in the country. We must also ensure that NABH standards reach even smallest hospitals in the country so that every citizen has access to high quality healthcare services.

Shri J P Nadda Ji-

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7241758170128285696





NABH Quality Connect Grants 2024: NABH Quality Connect Grants 2024 program is for the healthcare quality professionals who are keen to establish new initiatives with innovative thinking and changemaking in the field of healthcare quality and patient safety. This program is designed and created to support these professionals to take their strategic, operational, thought leadership and innovative skills to the next level. It was proposed to award grants ranging from Rs. 25,000/- to Rs. 50,000/- which are selected for the program. Based on this, an advertisement was placed through NABH social media platforms and NABH website calling for submissions from July 15, 2024 to August 15, 2024. NABH received overwhelming responses of submissions from various healthcare professionals all over India. While making recommendations of the proposals, feasibility, the quality of writeup, potential ability of publication and reliance to quality/patient safety was considered. Five innovative proposals were selected by NABH to grant a committee of 3 renowned experts and leaders in the field of healthcare quality and patient safety was formed to judge these proposals and give their verdict for recommendation and the amount of grants to be provided. The winners were awarded trophies, certificates and cheques on September 17, 2024 during the Inaugural session of NABH Patient Safety Conference 2024. NABH, the national accreditation body of India established for focused approach of quality assurance in healthcare and patient safety shall support the researches through this program for up to 5 candidates and these selected proposals will be awarded on September 17 every year (World Patient Safety Day) through the same process.











2.2.22 Release of new and revised NABH standards:



NABH Accreditation Standards for Hospitals – 6th Edition (Including Vernacular Languages)



NABH Accreditation Standards for Ayush Treatment & Wellness Centers - 1st Edition



NABH Guidebook for Climate Action and Sustainability in Healthcare – 1st Edition



NABH Empanelment Standards for Medical Value Travel Facilitator – 2nd Edition



NABH Checklist for Dementia Friendly Hospitals – 1st Edition



NABH Newsletter



NABH Accreditation Standards for Ayush Hospitals – 1st Edition



Strengthening Maternal & Child Health Service through NABH FOGSI Collaboration



NABH Digital Health Standards for HIS/EMR Systems- 1st Edition

2.3 Glimpse of MoU Signing: NABH partnerships with various organizations for advancement of healthcare

2.3.1 NABH Collaborated with Research Society for the Study of Diabetes in India, India's largest Diabetes Association, comprising over 12,000 members. The MoU was signed by Shri Rizwan Koita (Chairperson, NABH) and Dr Atul Mohan Kochhar (CEO, NABH).

Under this partnership, RSSDI and NABH-QCI, will collaborate on three key areas:

- Development of diabetes-specific standards by NABH, aligned with RSSDI care guidelines
- Development of diabetes-specific standards by NABH for Electronic Medical Records (EMR) and Clinic Management Systems (CMS)
- Roll-out of NABH Allopathic Clinic standards across the RSSDI member network.





2.3.2 NABH Collaborated with Association of Healthcare Providers India (AHPI) for organizing Awareness Training Program and Capacity Building Activities for promoting hospitals in the State of Gujarat for Entry-Level Certification Program and Ayush Entry-Level Certification Programme in tier III cities and rural areas.

2.3.3 NABH Collaboration with Government of Gujarat- NABH has successfully submitted the proposals to the Government of Gujarat, outlining a comprehensive framework aimed at enhancing the quality of healthcare services across the state.

03 proposals have been accepted by the Ministry of Health, Government of Gujarat and the work order for the same has been received.

2.4 NABH International Presence:

2.4.1 ISQua Conference 2023: NABH team actively participated in crucial discussions on sustainable care, digital health innovations and patient safety at the ISQua 2024 conference, held from September 23 to 27, 2024 in Istanbul, Turkey.















At the 12th International Patient Safety Conference IPSC 2025, Dr. Kumudita Talwar, Deputy Director, NABH, highlighted the organization's commitment to evolving healthcare standards. She emphasized the Continuum of Care, the Green Checklist for sustainability, and the updated Medical Value Travel MVT Standards, ensuring alignment with global benchmarks. Only few countries have their own accreditation standards; India remains at the forefront, strengthening its position in global healthcare quality and accreditation.



2.4.2 NABH participated in the 12th International Patient Safety Conference (IPSC) 2025, organized by Apollo Hospitals at Bharat Mandapam on February 21 to 22, 2025. The event brought together global healthcare leaders to discuss patient safety, quality improvement, and the future of healthcare.

Mr. Avinash Pandey, Group Leader – Digital Health, NABH, introduced NABH NextGen: Pioneering Digital Health Standards, marking a new era in healthcare accreditation. Recognizing that integration of digital interventions with Hospital workflows is now essential, and NABH has mapped its quality standards to digital health benchmarks, creating a seamless and efficient accreditation framework.

With this initiative, India probably becomes the first country globally to adopt an integrated approach, aligning hospital quality standards with Digital Health Standards, HIS and EMR standards to enhance quality of healthcare delivery.



Transforming Quality and Patient Safety: A Qualitative Exploration of Digital Healthcare through NABH's Perspective by Mr. Uzair Rehmani and Mr. Prateek Gautam, co-authored by Dr. Priyanka Chauhan and Dr Atul Mohan Kochhar, this research paper has been selected for presentation at the 12th International Patient Safety Conference (IPSC).



2.4.3 NABH Participated in 25th HA Forum an International Hybrid Conference held on March 19, 2025, in Thailand. Dr. Punam Bajaj, Director NABH took a session on Potential of NABH Standards towards building climate resilient and adaptive healthcare Ecosystem in India.





3 NATIONAL ACCREDITATION BOARD FOR EDUCATION AND TRAINING (NABET)

The National Accreditation Board for Education and Training (NABET), a key board of the Quality Council of India (QCI), is dedicated to promoting excellence in education, training, and skill development. It consistently aims to create a dynamic ecosystem in line with its mandate by establishing strong accreditation and assessment frameworks that improve institutional quality, encourage competency-based learning, and enhance the national skill landscape.

3.1 Formal Education Excellence Division (FEED)

3.1.1 Projects:

3.1.1.1 Assessment and accreditation of civil services training institutes under capacity building commission: Between April 1, 2024, and March 31, 2025, a total of 52 institutes successfully achieved accreditation and certification. However, the overall number of accredited and certified institutes totals 146, indicating continuous progress in the accreditation and certification process.



Onsite Assessment of Himachal Pradesh Institute of Public Administration (HPIPA) held on September 11-12, 2024

3.1.1.2 Quality City Nashik (Education Project): NABET has signed an MoU with three Education Societies in 2023 and 2024. This initiative involves assessment of over 5,000 students from 3rd, 5th, and 8th grades across 22 schools in Nashik. Assessments for 4408 students and 250 classroom observations of teachers have been completed, and the results compilation is underway.





Assessment of Students in the month of August 2024

3.1.1.3 Assessment & Rating of 250+ Ayurveda, Siddha & Unani Colleges: The assessment and rating of 258 Ayurveda, Siddha, and Unani colleges were successfully conducted from July 2024 to October 2024.



Assessor training for Ayurveda, Siddha and Unani Assessors in May 2024



Assessment in Simulation lab of D.Y. Patil Ayurveda College in August 2024



Assessment of Skill lab at SDM Ayurveda College in August 2024

3.1.1.4 Assessment and Rating of 240 Homeopathy Colleges: The assessment and rating of 240 Homoeopathy medical colleges were successfully conducted from April 2024 to July 2024.



Student assessment in Bakson Homoeopathic Medical College in May 2024



Faculty interaction in Bakson Homoeopathic Medical College in May 2024



Student interaction in Nehru Homeopathic Medical College in July 2024

3.1.1.5 Transforming School Education: Collaboration between PCMC & QCI: Shri Chakravarthy T. Kannan, Secretary General of QCI, visited schools under the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) to assess the implementation of a transformative education initiative impacting over 45,000 students from Classes 1 to 10. During his visit, the Secretary-General connected with principals, teachers, and assessors to gain first hand insights into the program's progress and challenges. These discussions strengthened QCI's commitment to refining intervention strategies and optimizing the teaching-learning process. His visit represented a milestone in QCI's mission to elevate educational standards and promote impactful models nationwide.

The project seeks to improve student learning outcomes through a three-year intervention model in 128 PCMC schools. To date, assessments of over 42,000 students and observations of 950 teachers have been completed, with the compilation of results currently in progress.



School welcomes SG-QCI on his visit to PCMC Schools in July 2024



SG-QCI's Interaction with QCI assessors in July 2024



Interaction between SG-QCI and the Principal of the School in July 2024

3.1.1.6 Assessment and Evaluation of 300 Tribal Ashram Schools and Hostels under the Ministry of Tribal Affairs: As a part of the project, 300 Tribal Schools and Hostels were assessed across five states based on six key parameters. Gaps were identified, and strategies were recommended to improve the quality of each School and Hostel.



Assessment of Ashram Schools & Hostels in the month of May 2024



Assessment of Ashram Schools & Hostels in the month of May 2024

3.1.1.7 Assessment of Nursing & Paramedical Colleges for grant of affiliation NOC under the Uttar Pradesh State Medical Faculty (UPSMF): NABET, QCI was entrusted with the inspection of Nursing and Paramedical Institutes. The project scope included the inspection of 698 institutes, covering the teaching block, hostel block, and hospital, in accordance with the norms established by the Indian Nursing Council and the Uttar Pradesh State Medical Faculty.

The detailed inspection reports for the year 2024–25 have been submitted to the department for consideration regarding granting NOC to the respective institutes.



Inspection of nursing and paramedical colleges under UPSMF in August 2024



Inspection of nursing and paramedical colleges under UPSMF in the month of September 2024

3.1.1.8 Bihar Nurses Registration Council (BNRC): Following the successful completion of Phase 1 of the project, during which 231 nursing institutes were assessed, NABET-QCI was awarded an additional work order to assess 84 more nursing institutes under Phase 2.

A draft assessment report based on ground findings has been submitted to the department. The final report is currently being prepared and is scheduled for submission in April 2025.



Bihar assessment in the month of December 2024

3.1.2 Other Activities:

3.1.2.1 Assessors' Meet: NABET organized an Assessors' Meet on January 31, 2025, in Delhi to standardize the accreditation process. The focus was on simplifying standards and procedures.



Assessors Meet organized on January 31, 2025, New Delhi



Assessors Meet organized on January 31, 2025, New Delhi



Assessors Meet organized on January 31, 2025, New Delhi

3.1.2.2 Outreach activities: Ms. Madhu Ahluwalia, Senior Advisor at QCI, shared insights on equitable, inclusive, and quality education under NEP 2020, highlighting NABET-QCI initiatives. The Hon'ble Minister of State for Education, Dr. Sukanta Majumdar, graced the event and addressed over 60 school stakeholders regarding transformative education and the vision for Viksit Bharat.



Glimpse of program held in the month of February 2025



Glimpse of program held in the month of February 2025

3.2 Environment and Exploration Division (EED)

3.2.1 One-day National Workshop on "Preparation of FC, EC, and EIA-EMP proposals, including eco-friendly mitigation measures and challenges" regarding statutory clearances organised by **NHAI - Ministry of Road Transport & Highways on April 15, 2024.** The total number of participants was around 800 (300 in physical mode and 500 in online mode), primarily from MoRTH, NHAI, NHIDCL, MoEF&CC, QCI-NABET, DPR consultants, concessionaires, AE, and IE organisations. It was attended by **Sh. A. K. Jha,** Sr. Director, QCI-NABET.



Workshop on Preparation of FC, EC and EIA-EMP proposals including Eco-friendly Mitigation Measures & Challenges

3.2.2 The Department of Zoology, Carmel College of Arts, Science and Commerce for Women, Nuvem-Goa, organized an online guest lecture on the role of QCI-NABET in enhancing the quality of EIA on April 6, 2024. Dr. Yati Kachhawa (Dy. Director) delivered the lecture, which was attended by approximately 40 students/participants.



Online guest lecture on the role of QCI-NABET in enhancing the quality of EIA

3.2.3 A one-day awareness workshop on the 'Scheme for Accreditation of EIA Consultant Organizations' was organized on May 28, 2024, in Guwahati, Assam, for experts and consultants working in the field of Environmental Impact Assessment. A total of over 25 participants attended this workshop.



Awareness Workshop on the 'Scheme for Accreditation of EIA Consultants organizations'

3.2.4 A capacity-building workshop was organized at CMPDIL, Ranchi (Jharkhand), from June 19-21, 2024, covering different technical/ EIA-related sessions. The total number of participants was around 50.



Capacity building workshop was organized at CMPDIL, Ranchi

3.2.5 A webinar themed "Land Restoration, Desertification, and Drought Resilience" was organized by the division for World Environment Day on June 5, 2024. Over 130 participants attended the workshop.

3.2.6 National Geoscience Awards: On August 20, 2024, President Droupadi Murmu presented the National Geoscience Awards (NGA) for 2023 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi. A total of 21 geoscientists were honoured during the ceremony, which was attended by the Minister of Mines, Shri G. Kishan Reddy, along with distinguished geoscientists, scholars, policymakers, and industry leaders. From QCI-NABET, Senior Director Mr. A.K. Jha and Joint Director Mr. Jagminder Kataria were also present.

3.2.7 The 4th International Climate Summit 2024 was held on July 19, 2024, organized by the PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI). Under the theme 'Dented Corn Ethanol: Energy Security, Food Security, and Decarbonization,' which had around 500 participants, it highlighted the interconnected challenges and opportunities as the world advances towards sustainable development.





4th International Climate Summit 2024, Taj Palace, New Delhi

3.2.8 The event for World Ozone Day 2024 was organized by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) on September 13, 2024, at Bharat Mandapam, New Delhi. The Government of India has celebrated World Ozone Day each year at the national and regional levels since becoming a Party to the Montreal Protocol in 1992. Approximately 350 participants attended this year. The theme for this year is "Montreal Protocol: Advancing Climate Action."



Event of World Ozone Day 2024 at Bharat Mandapam

3.2.9 The Accredited Consultant Organization (ACO) meeting was held on September 11, 2024 (Wednesday) at the Hotel Radisson Blu Plaza in New Delhi. The agenda for the ACO meeting included discussions on new amendments to the Comprehensive EIA Scheme guidelines, evaluations of the Environmental Clearance (EC) process, and the expectations of the MoEF&CC from accredited consultants. It also provided a platform for consultants to share their perspectives on accreditation and explore new opportunities for growth. NABET was represented by CEO Dr. Varinder Singh Kanwar, who delivered the welcome address and provided concluding remarks during the valedictory session. Mr. Chakravarthy T. Kannan, Secretary General of QCI, delivered an address during the inaugural session. Mr. A. K. Jha, Senior Director of NABET, QCI, discussed amendments to the guidelines of the Comprehensive EIA Scheme. Dr. Shruti Rai, Director of MoEF&CC, led the session on the evaluation of the EC process and compliance monitoring. A total of over 230 participants attended the event.



Accredited Consultant Organization (ACO) Meet

3.2.10 QCI-NABET, Environment Division organized a three-day "Capacity Building Workshop" for Accredited Consultant Organizations in Pune from September 25-27, 2024, at Hotel Pride, Pune, Maharashtra. The Chief Guest was Shri Deepak Govindrao Mhaisekar (Rtd. IAS), Chairman SEIAA, and the Guest of Honour was Dr. Deepali Nimbalkar, VSI, Pune. The workshop began with the Lighting of the Lamp and the National Anthem, accompanied by a welcome address from Shri A.K. Jha, Sr. Director NABET, highlighting the objectives of the workshop. This was followed by addresses from the Guest of Honour and the Chief Guest. More than 70 experts from accredited consultant organizations attended the workshop. Along with Shri A.K. Jha, NABET was represented by Dr. Yati Kachhawa, Deputy Director, and Ms. Kritika Sharma, Accreditation Officer.



Capacity Building Workshop for Accredited Consultants Organizations at Pune



Capacity Building Workshop for Accredited Consultants Organizations at Pune

3.2.11 QCI-NABET successfully organised a 3-day workshop from December 17-19, 2024, at Park Inn by Radisson, Surat, Gujarat, aimed at enhancing the capacity of EIA consultants to develop high-quality Environmental Impact Assessment (EIA) reports. This workshop covered critical topics, including Environmental Damage Assessment & Restoration Cost/Compensation Calculation; Extended Producer Responsibility (EPR) and ESG Practices; the Use of GIS in EIA report preparation; Socio-Economic and Baseline Studies; Ecology; Biodiversity Risk & Hazards Assessment; Quantification and Interpretation of Data for impact identification; Hands-on Group Activities and Case Studies; and Insights into PARIVESH 2.0. With the participation of over 45 professionals, including EIA coordinators, functional area experts, and associates, the workshop featured 8-10 experienced faculty members who shared their expertise and practical insights into EIA preparation. The event fostered rich discussions, hands-on activities, and learning opportunities to ensure continuous improvement in the field of environmental assessments. QCI-NABET was represented by Dr. A. K. Jha (Sr. Director), Dr. Yati Kachhawa (Dy. Director), and Mr. Vipin Pant (Accreditation Officer).





Capacity Building Workshop for EIA consultants to develop high-quality Environmental Impact Assessment (EIA) reports at Surat

3.2.12 The Bengal Chamber of Commerce & Industry (BCC&I) organized its annual "Minerals Mining & Metals Conclave" on February 10, 2025, at Silver Oak Hall, India Habitat Centre, New Delhi, with approximately 70 participants. The event was honoured by esteemed dignitaries including Mr. Sandeep Poundrik, IAS, Secretary, Ministry of Steel, Government of India; Mr. Nagendra Sinha, Chairperson of the Metals National Committee and Former Secretary of the Ministry of Steel, Government of India; Mr. Rana Som, Mentor of the Minerals & Mining National Committee, BCC&I, and Former CMD of NMDC and Hindustan Copper Limited; and from QCI-NABET, Sh. Jagminder Kataria, Joint Director, and Dr. Yati Kachhawa, Deputy Director. They engaged in discussions on quality standards, sustainability, and advancements in the minerals, mining, and metals sector.



Annual Minerals Mining & Metals Conclave at IHC, New Delhi

3.2.13 The National Highways Authority of India (NHAI) organised a day-long workshop at its headquarters in New Delhi on January 15, 2025, titled "GIS-Based LAP Creation, GIS Mapping for GHD & Forest and Environment Clearance related Issues." Approximately 75 participants attended the workshop, which aimed to enhance the efficiency of Land Acquisition Planning (LAP) for NHAI projects while emphasizing the preparation of high-quality Detailed Project Reports (DPRs). Prof. (Dr.) Varinder S. Kanwar, CEO of QCI-NABET, shared valuable insights on selecting quality consultants for the road infrastructure sector and highlighted the key attributes of an effective DPR consultant during the technical session.



Workshop on "GIS-Based LAP Creation, GIS Mapping for GHD & Forest and Environment Clearance related Issues"

3.2.14 India Climate Week 2025: Uniting the World for Climate Action took place from February 3 to 7, 2025, bringing together global stakeholders to promote climate action. A key highlight of the event was the launch of the India EPR Alliance, which aims to champion net-zero solutions and foster engagement for decarbonization and resilience. The event featured Shri Jitin Prasada, Hon'ble Minister of State, Ministry of Commerce and Industry, as the Chief Guest. It included participation from government officials, industry leaders, policymakers, international organizations, and climate change experts. Representing QCI-NABET, Dr. Yati Kachhawa, Deputy Director, was present at the discussions. A significant session of the conference took place on February 6, 2025, at Le Meridien, New Delhi. The event witnessed an impressive turnout of over 500 participants from more than 30 nations, highlighting the global commitment to sustainable solutions and climate resilience.



India Climate Week 2025 at Le - Meridian, New Delhi

3.2.15 The World Sustainable Development Summit 2025 was held from March 5 to 7, 2025, at the India Habitat Centre in New Delhi. Organized by The Energy and Resources Institute (TERI), the summit focused on the theme "Partnerships for Accelerating Sustainable Development and Climate Solutions." The event was inaugurated by His Excellency Brigadier Mark Phillip, Prime Minister of Guyana, and Her Excellency Ms. Marina Silva, Minister of Environment and Climate Change in Brazil. Also in attendance was the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav, along with other dignitaries and subject experts. The summit brought together over 100 participants, with QCI-NABET represented by Mr. Vipin Chander Pant, Assistant Director, fostering collaboration and discussions on sustainable development and climate action.



The World Sustainable Development Summit 2025 at IHC, New Delhi

3.2.16 The Environment Division is operating four accreditation schemes.

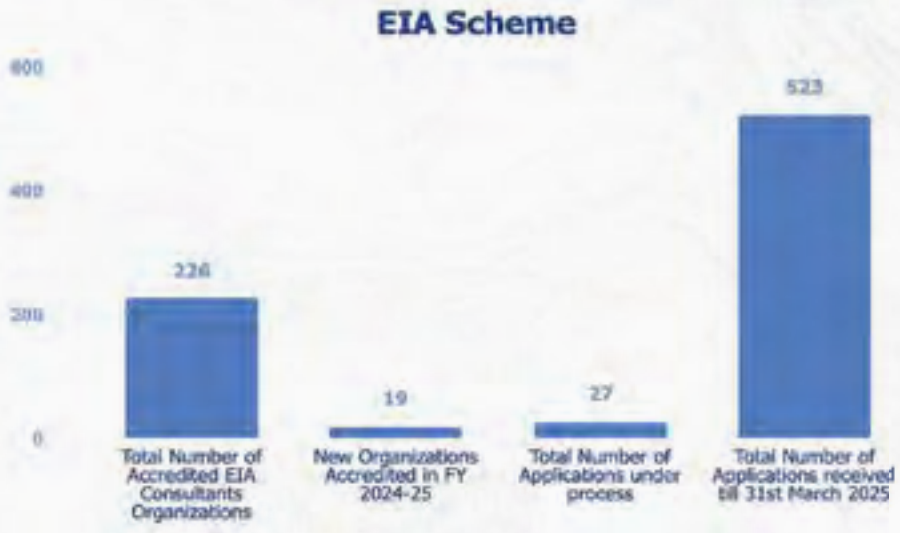
a. Environment Impact Assessment (EIA) consultant organization under the Ministry of Environment Forest and Climate Change (MoEFCC)

b. Ground Water Consultant Organization under Jal Shakti Mission;

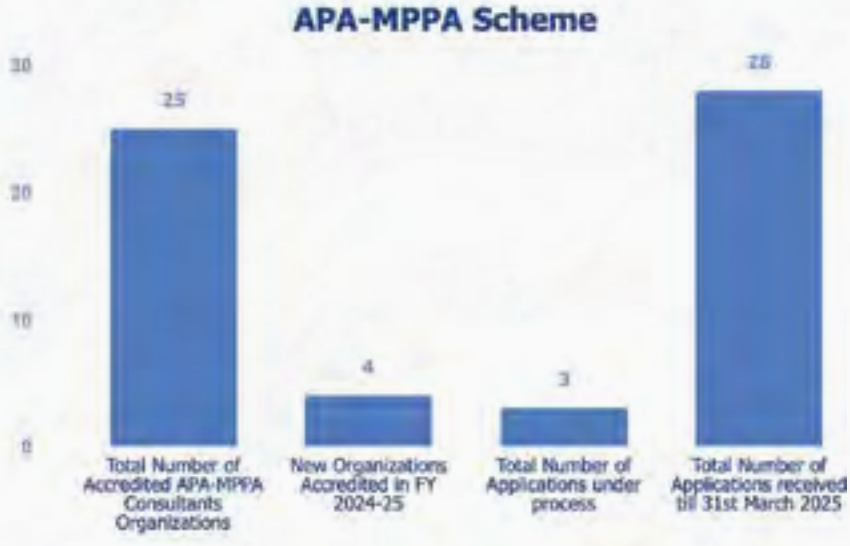
c. Prospecting / Mine Plan preparing Agencies (APA/MPPA) under the Ministry of Coal.

d. Accreditation Scheme for Exploration Agencies in Mineral Sector (AEA) under the Ministry of Mines.

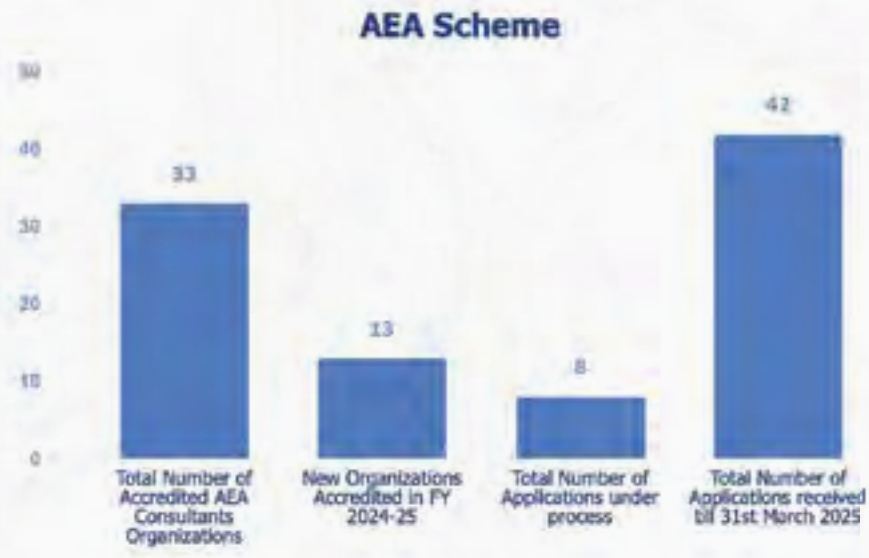
Scheme for the Accreditation of EIA Consultant Organizations



Scheme for the Accreditation of Agencies Preparing Exploration and Mining Plans in the Coal Sector



Scheme for the Accreditation of Exploration Agencies (AEA) in the Mineral Sector



Scheme for Accreditation of Groundwater Consulting Organizations



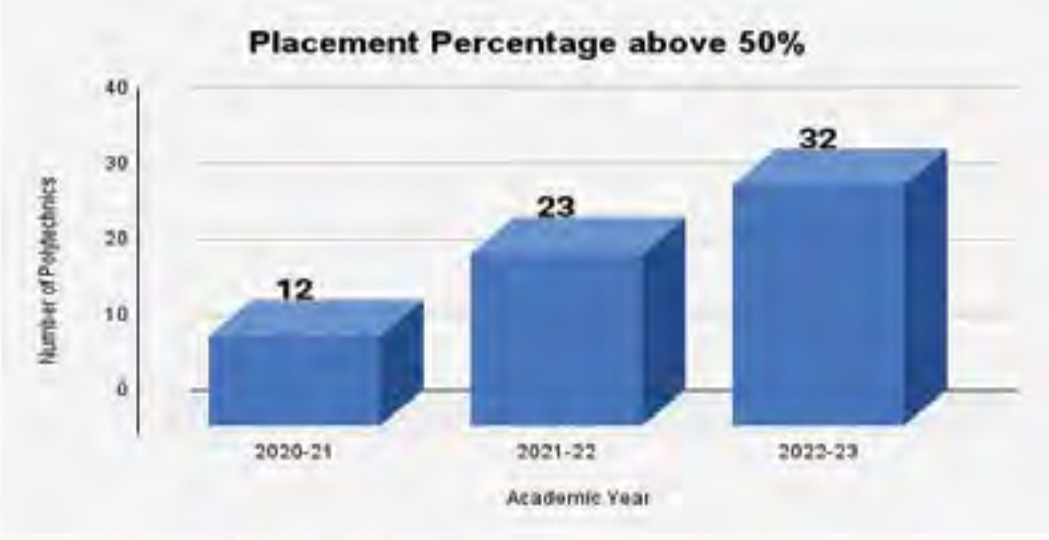
3.3 MSME LEAN and Skill Training and Service (STS) Division

3.3.1 Skill Training and Service Division

NABET-QCI completed the third cycle of the Ranking of Polytechnics in June 2024. A total of 132 Government and Private Polytechnics participated in the 3rd cycle of the ranking process. The report for this cycle was launched on July 30, 2024, by Shri Sampad Chandra Swain, Hon'ble Minister of State for the Skill Development and Technical Education Department, Government of Odisha. This unique project by the Government of Odisha aimed to improve the academic performance of polytechnics and enhance the teaching and learning outcomes for students. Quality interventions by QCI in this area resulted in notable improvements, demonstrating an

incremental increase in the performance of nearly all participating polytechnics based on the evaluation parameters (seven broad and eighty-four sub-parameters) over three cycles. This progress has led to an increase in NBA accreditation and ARIIA rankings for the polytechnics. Furthermore, it has boosted students' employability by approximately 30% (details presented in the charts below).

Increase in placement percentage of all polytechnics above 50% compared to AY 2022-23, AY 2021-22, and AY 2020-21.





The report for the third cycle was launched by Shri Sampad Chandra Swain, the Hon'ble Minister of State SCTE&VT Department, Government of Odisha.

3.3.2 MSME LEAN Division

The Quality Council of India (QCI) – National Accreditation Board for Education and Training (NABET) has been designated as one of the Implementing Agencies under the MSME Competitive Lean Scheme of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MoMSME).

The financial year 2024–25 has been a landmark year for the MSME Lean Vertical at QCI-NABET, marked by significant quantitative and qualitative advancements in implementation.

Key Achievements

a) **Expansion and Industry Collaboration:** In FY 2024–25, QCI-NABET significantly enhanced its outreach by:

- o On-boarding 26,613 MSMEs onto the Lean platform.
- o Collaborating with prominent industry associations such as Laghu Udyog Bharati and the Indian Industries Association.
- o Engaging with reputed Original Equipment Manufacturers (OEMs) such as M/s Forbes Marshall, M/s Avon Cycles, M/s Monte Carlo, and M/s J.K. Tyres Industries Ltd.

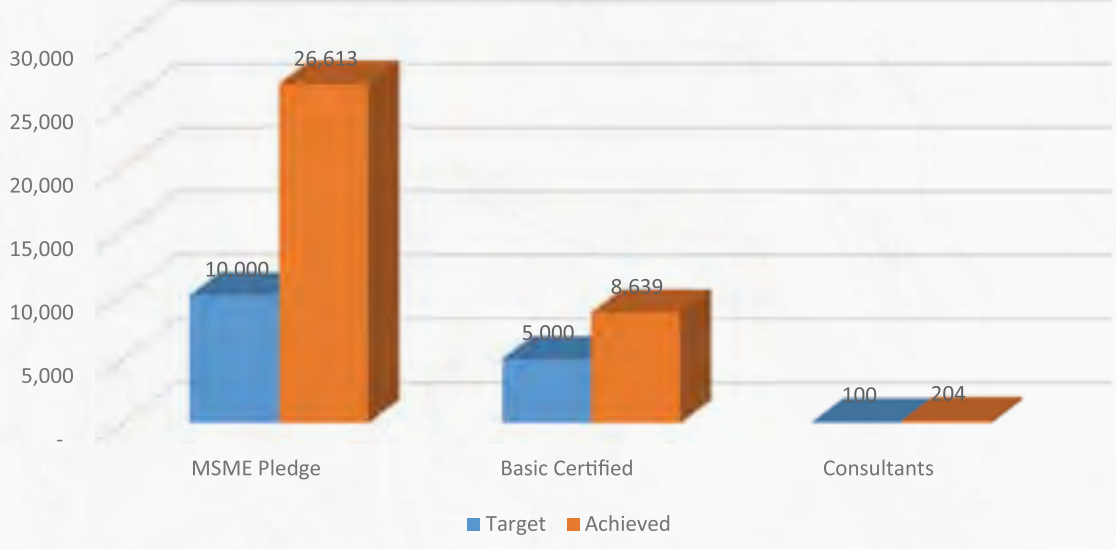
b) MSME Progression under the Scheme

On-boarding and progression of MSMEs across different stages are summarized below:

STAGE	Count
MSME Registration	26,613
Basic Certification	8,639
Intermediate Registered MSMEs	526
Group of Enterprises (GoEs) Formed	59

c) Support and Outreach Activities: In order to build capacity and generate awareness around the Lean scheme, the following initiatives were undertaken:

ACTIVITY	Count
Awareness Programmes Conducted	300
Lean Manufacturing Consultant (LMC) – 5-Day Training	10
Assessor Programme Conducted	1
LMC Organizations Empanelled	22
Consultants Empanelled	204



3.4 Higher Education – Research Analysis and Capacity Building Division (HE- RACB)

The HE-RACB division is exploring new opportunities for quality intervention in academics and research, and it is committed to promoting quality indexes in higher education and research, which are of immense interest in the current global transformational era.

3.4.1 Audit of Higher Educational Institutions (HEIs)

The HE-RACB division received a work order to conduct academic, financial, and administrative audits of 24 private universities in Haryana. The audit of Starex University in Gurugram has been completed and report has been submitted to the Directorate of Higher Education, Government of Haryana.

The division, in consultation with the experts, has developed concept notes, frameworks, and standard operating procedures (SoPs) for conducting the Academic and Administrative Audit (AAA) in higher educational institutions (HEIs); a certification program (National Quality Education Quality Certificate); and the Ranking of Higher Academic Institutions (RHAI). In the last meeting with the expert committee, held on February 24, 2025, the framework and SoPs for AAA of HEIs; the framework for the certification program (NHEQC); and the concept note, framework, and SoPs for ranking HEIs were finalized. The committee also discussed the binary accreditation framework being developed in accordance with the proposed NAAC updates. Based on the developed framework, AAA has been conducted for Adani University, Ahmedabad, from March 10 to 11, 2025.



Sub Advisory Committee Meetings held at NABET-QCI Office to discuss and finalize frameworks, SOPs and concept note for AAA of HEIs, NHEQC and RHAI

3.4.2 Applied & Industrial Research:

3.4.2.1 Collaboration with Indo-German Science & Technology Centre (IGSTC)

The HE-RACB division at NABET conducted an evaluation of the R&D capabilities of industries for IGSTC's 2+2 bilateral projects, involving 16 Indian industry partners. These partners are part of a consortium formed by an academic institute and an industry from both India and Germany, participating in IGSTC's 2+2 bilateral program according to the established framework. IGSTC invited proposals for joint R&D&I projects with industrial relevance in the 2+2 mode of partnership, specifically in the thematic area of "AI for Sustainability." The shortlisted industries were then forwarded to the division for an assessment of their roles in the consortium, focusing on R&D capabilities, technical know-how, and financial stability necessary for the successful completion of the proposed project.



Expert interaction at Suhora Technologies Pvt. Ltd., Noida on November 25, 2024 for IGSTC's 2+2 bilateral Proposals



Expert interaction at Growloc Pvt. Ltd., Pune on November 28, 2024 for IGSTC's 2+2 bilateral Proposals

3.4.3 Scientific Projects:

3.4.3.1 Impact Assessment of I-STEM National Portal

The office of Principal Scientific Advisor to the Govt of India has assigned the division to conduct Impact Assessment Study of I-STEM National Portal. List of participating institutions and the beneficiary users of I-STEM portal has been obtained from the I-STEM office at Bengaluru. The data which was very large was thoroughly analyzed and based on time restriction and financial constraints a 10% sample size has been finalized for interaction to carry out the impact assessment. This includes 315 institutes and 939 users that have been shortlisted upon discussion with the I-STEM officials and office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India. Further, considering the large size of the shortlisted sample and time limitations, 10% of the interaction are being carried out in the physical mode while remaining 90% are being done through the virtual mode. So far around 40% of the physical assessments and 10% of the virtual assessment have been carried out.



Expert interaction at IIT Mandi on March 8, 2025 for impact assessment study of I-STEM national portal



Expert interaction at Jamia Milia Islamia, New Delhi on March 3, 2025 for impact assessment study of I-STEM national portal



Expert interaction at NIT Calicut on March 4, 2025 for impact assessment study of I-STEM national portal

3.5 Training and Capacity Building Division (TCB Division)

3.5.1 Brief of Activities

TCB synergizes training, awareness workshops, and capacity-building activities at national and international levels. It conducts instructor-led, virtual, onsite trainings, and e-learning sessions covering various domains, such as conformity assessment, food, general management systems, medical and healthcare, manufacturing, environment, and social aspects.

3.5.2 Annual Review of Activities

3.5.2.1 Instructor-led-Trainings (Virtual & Onsite)

a) In the financial year 2024-25, a total of 148 training sessions were conducted by TCB, with approximately 5913 professionals in attendance. Virtual training programs were offered on various accreditation and certification standards, including ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17025, ISO 13485, ISO 15189, and ISO/IEC 17065. A series of virtual programs were also held in the field of General Management, such as Six Sigma Yellow Belt Certification, Lean Six Sigma Green Belt, and Fundamentals of Digital Marketing. New training programs were introduced this year, including Environmental, Social, and Governance (ESG) in the Indian Regulatory Framework, Method Validation and Verification for Chemical Analysis (covering pesticide residue,

contaminants, and nutritional analysis), and Implementation of Integrated Management Systems (ISO 9001, ISO 45001, and 14001).

b) TCB has conducted several exclusive training sessions for officials affiliated with both government and private organizations, including AIIMS (PAN India), ICMR, UNICEF, ADLQ, BIPARD, BKT Tires, Bhuj, ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd., Surat, Axis Electrical Component, I-CAT, NATHealth, NCDC, CIPET, Maulana Azad Medical College, Govind Ballabh Pant Hospital, Department of Health Research, ADI Consultant, Department of Industries and Commerce, UT Ladakh, and Indian Navy Training Ship Building Center, Visakhapatnam.













3.5.3 Capacity Building Interventions (National)

(a) Under the MoU between QCI and CREDAI Women's Wing, a pilot training session was conducted at GIFT City, Gandhinagar, for construction workers from Savvy and Shivalik Groups. Over three days, more than 1,000 workers received training on social welfare schemes and technical skills, with 350 attending sessions on masonry, bar bending, and shuttering carpentry, while 750 participated in welfare sessions on social welfare schemes, digital skills, and financial literacy. Special sessions focused on

women's health and environmental awareness, with 225 workers registering for government schemes. Additionally, CREDAI Kochi completed similar training for over 300 workers from six developers. Meanwhile, as an associate partner, CREDAI Pune Metro participated in on-site assessments of labour camps for the 'Best Facility Award' and attended the award ceremony in Pune on August 31, 2024.











(b) Conducted PTB Germany-sponsored training for officials from the State and Regional Offices of the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) in Lucknow, and the Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) in Dehradun. The training focused on Water Quality Testing Infrastructure and Laboratory Accreditation to support the 'National Mission for Clean Ganga (NMCG)'. Participants, including officials from UKPCB's Regional Offices in Roorkee, Haldwani, Kashipur, and Dehradun, as well as the Head Office, were introduced to international standards encompassing key metrology and quality requirements. The program enhanced their skills in laboratory operations, measurement accuracy, and accreditation processes.







(c) UNICEF sponsored a comprehensive four-day residential 'Workshop-cum-Training' at SPM Niwas, Kolkata, aimed at assessing and enhancing laboratory performance under the National Jal Jeevan Mission (NJJM) Framework. The program sought to identify existing gaps in laboratory operations and provided targeted training to address these deficiencies. TCB designed and administered the training, engaging participants in hands-on sessions, discussions, and practical exercises to improve laboratory practices, ensuring better water quality testing and compliance with NJJM standards. The workshop-cum-training saw participation from 83 individuals across 18 states of India.











(d) The Margdarshan Orientation Program, hosted by the QCI, is a flagship initiative aimed at equipping recruits of the Indian Council of Medical Research (ICMR) with essential knowledge and skills. It is a month-long program designed to provide a strong foundation in key areas such as administration, finance, scientific leadership, quality, and project management. This initiative plays a crucial role in shaping the future of public health research in India by empowering participants with the tools and insights needed to excel in their roles, foster innovation, and contribute to ICMR's transformative initiatives while upholding the highest standards of excellence and integrity. To date, Four batches have completed the program, with training sessions conducted at multiple locations, including Manav Rachna University, Faridabad (2 batches), NPC, Chennai (1 batch), and IIT Hyderabad (1 batch), training approximately 160 recruits. The Margdarshan Orientation Program continues to serve as a vital step in strengthening India's public health research ecosystem.
















(e) TCB-NABET, QCI, in collaboration with NATHealth, successfully conducted Digital Health Master Class (DHMC) training sessions aimed at equipping healthcare professionals with essential insights into digital health maturity, HMIS/EMR adoption, and interoperability. These sessions reaffirm our commitment to accelerating India's digital health transformation by fostering innovation, compliance, and seamless technology integration within the healthcare ecosystem. So far, we have conducted DHMC training in four cities, namely Varanasi, Lucknow, Patiala, and Amritsar, with a total of 229 participants attending the program at these locations.

(f) A Gap Analysis Report and a detailed Action Plan were shared with BIPARD Patna and Gaya to support the implementation of a Quality Management System (QMS) at their institutes. The Gap Analysis pinpointed key areas needing improvement by evaluating current processes against QMS standards. Based on the findings, an Action Plan was created, outlining step-by-step measures for implementation, including training, documentation, process optimization, and adherence to best practices.







(g) A Gap Analysis according to ISO 15189:2022 requirements was conducted by TCB/QCI officials and experts at AIIMS Bathinda across four departments: Biochemistry, Microbiology, Pathology, and Radiodiagnosis laboratories. The assessment report was shared with the relevant departments, and a follow-up visit was conducted to assess the implementation of the recommended actions. The final visit consisted of laboratory inspections, discussions with personnel, operations reviews, documentation verification (SOPs, records, reporting), and compliance checks. Observations from this visit will bring further improvements.













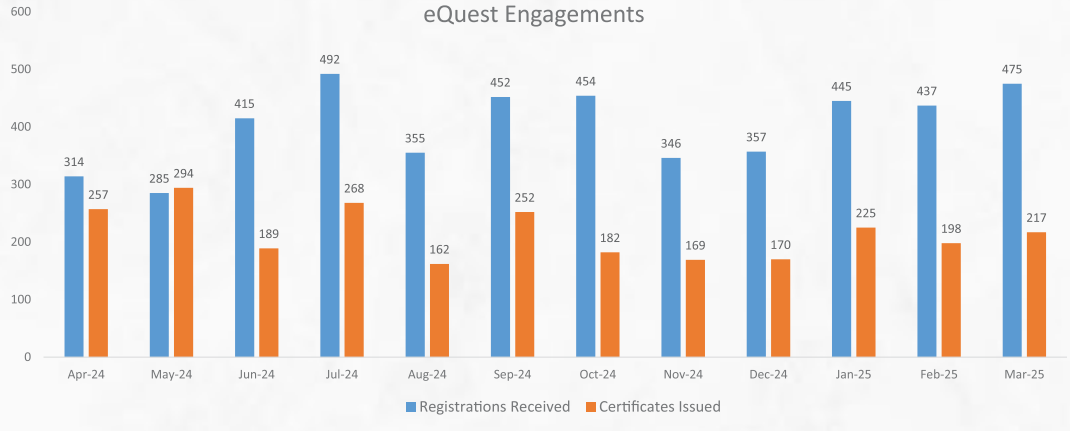
3.5.4 International Activities by TCB

(a) Conducted specialized training for the Anti-Doping Lab Qatar (ADLQ) to enhance quality management and compliance. Sessions held in September focused on Quality, Testing, and Risk Management, while December training covered Risk Management under ISO/IEC 17025:2017 and Uncertainty of Measurement. These programs strengthened ADLQ's capabilities in maintaining international laboratory standards.

3.5.5 Theme: E-Learning/Online Learning:

a) eQuest: Outcomes in FY 2024-25:

eQuest is the e-learning portal of NABET, the Education Board of the Quality Council of India. It hosts 100 e-learning courses across various domains, including Quality, Healthcare, Education, Environment, and MSME. It is designed to promote employability through skills and training. Registrations received and certificates issued for 2024-25:



b) Future Projections:

Develop e-learning courses across multiple domains to expand the catalogue of available courses.

Enter into MoU with educational institutions, govt and international organizations, MSMEs to facilitate training and capacity building initiatives

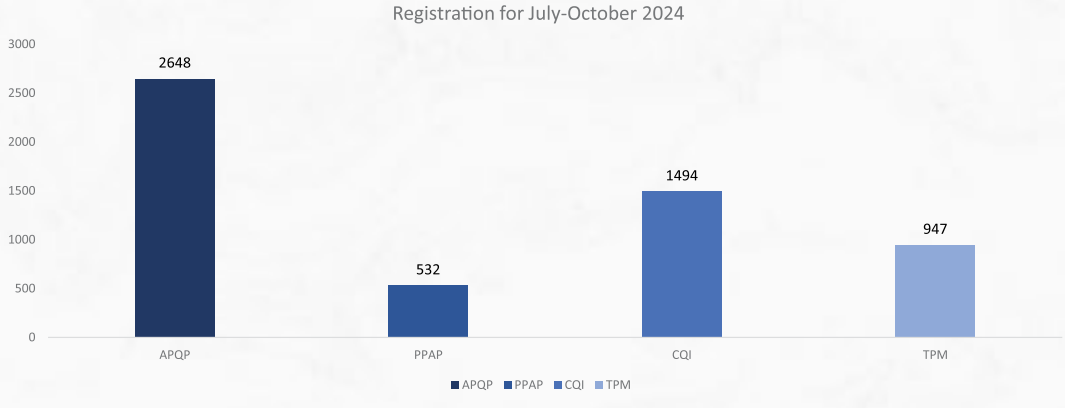
3.5.6 QCI Courses hosted on SWAYAM Portal: -

SWAYAM is a programme initiated by the Government of India to achieve the three cardinal principles of the Education Policy: access, equity, and quality. The primary goal of eQuest-QCI's partnership with SWAYAM is to develop and promote e-learning courses in the field of Quality, in collaboration with and vetted by the Indian Institute of Management Bangalore (IIMB).

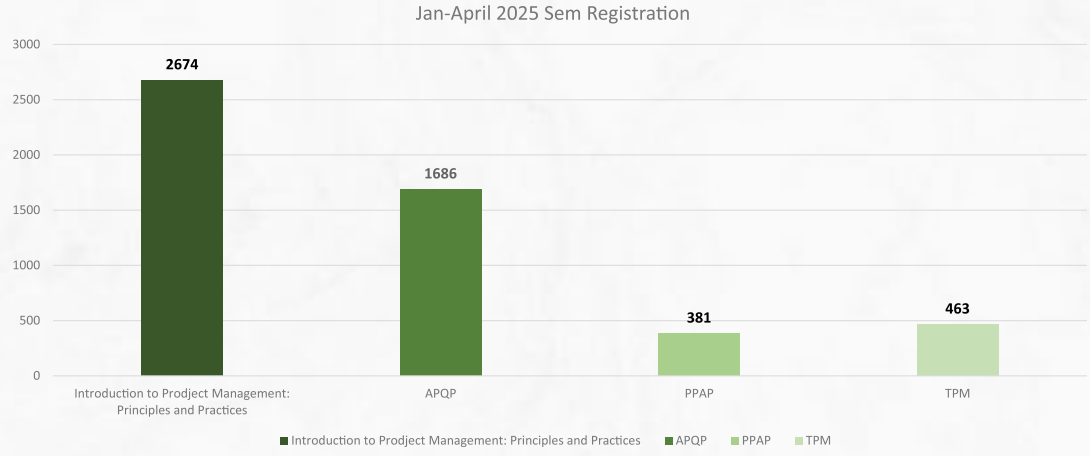
a) Course-wise Registrations Received for the January-April Semester 2024:



b) Course-wise Registrations Received for the July-October Semester 2024:



c) Course-wise Registrations Received for January-March Semester 2025:



Future Projection- Continued promotion of aforementioned courses in order to received outreach

---

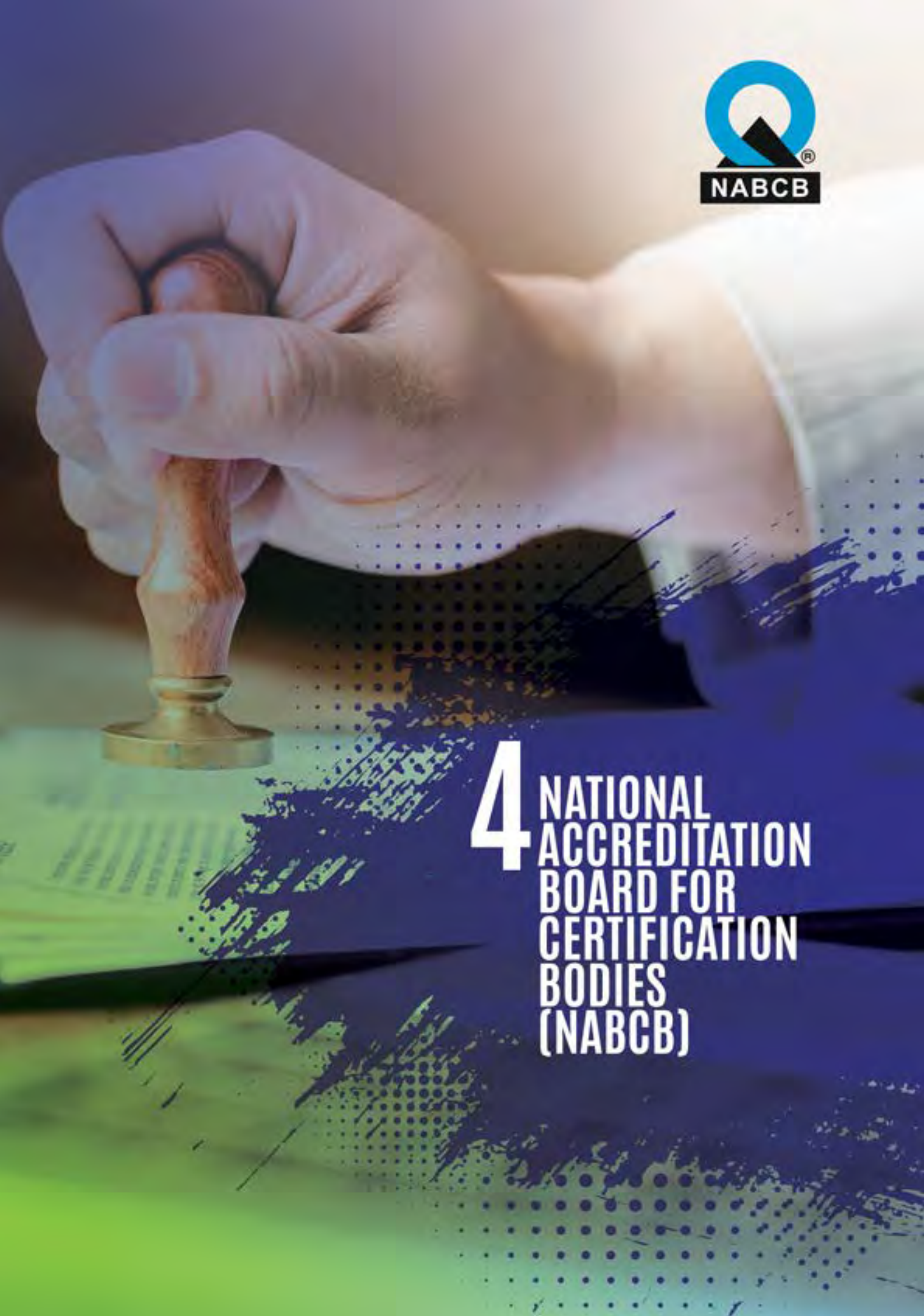
3.5.7 iGOT:

Karmayogi Bharat is an integral part of the National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB), also known as Mission Karmayogi. This initiative is designed to transform the landscape of civil services capacity building in India. It aims to create a competent civil service that is rooted in Indian ethos and has a shared understanding of the country's priorities. iGOT Karmayogi is a large-scale, comprehensive learning and career management platform that caters to the distinctive knowledge requirements of government officials.

Course-wise Registrations Received April 2024 - March 2025:



Future Projection- Continued promotion of the aforementioned courses in order to receive outreach

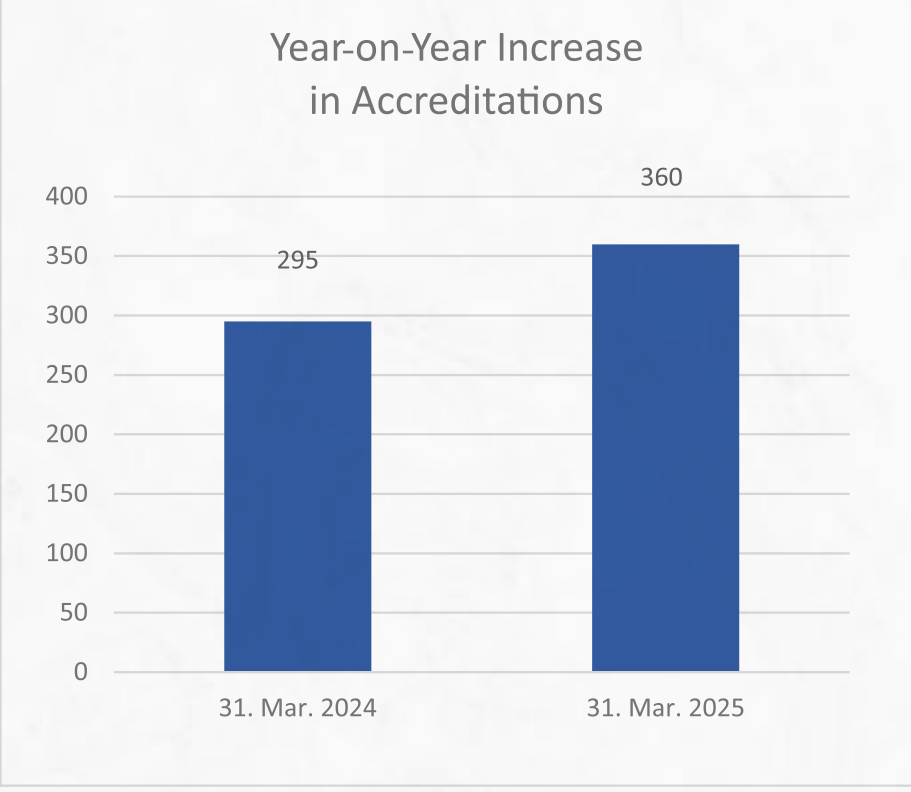


4 NATIONAL ACCREDITATION BOARD FOR CERTIFICATION BODIES (NABCB)

The National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), a constituent Board of the QCI, was established in year 2000 and provides accreditation to Certification, Inspection, and Validation & Verification Bodies as per International Standards (ISO/IEC).

NABCB is a member of international bodies– the International Accreditation Forum (IAF), the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and the Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)– and is a signatory to their Multilateral Mutual Recognition Arrangements (MLAs / MRAs) for Management Systems (ISO/IEC 17021-1), Product (ISO/IEC 17065), & Persons (ISO/IEC 17024) certifications; Inspection (ISO/IEC 17020) and Validation & Verification (ISO/IEC 17029) which provide international equivalence & acceptance to accredited certificates & reports. NABCB is also recognized by many international sector specific certification Scheme Owners e.g. Global G.A.P, International Featured Standards (IFS), Global Seafood Alliance-Best Aquaculture Practices (GSA-BAP), British Retail Consortium (BRCGS), Programme for Endorsement of Forest Certifications (PEFC), FSSC 22000 Foundation, FAMI-QS, International Civil Aviation Organization-Carbon Offsetting & Reduction Scheme for International Aviation (ICAO-CORSIA), VERRA, Sustainable Electronics Recycling International (SERI), and International Society of Automation (ISA) Secure for Cybersecurity of Industrial automation.

Conformity Assessment has assumed a vital role in international trade in view of provision for relying on accreditation under both TBT and SPS Agreements of WTO. Increasingly, the Regulatory Bodies world over are relying on national accreditation in recognizing Conformity Assessment Bodies for the purpose of verifying compliance to regulations. Accreditation helps bring down technical barriers to trade both in regulatory as well as voluntary sectors, apart from G2G bilateral / multilateral trade agreements.



Accreditation Status as on March 31, 2025

ACCREDITATION PROGRAMMES	ACCREDITATIONS	APPLICATIONS
Quality Management Systems (QMS)	56	8
Environmental Management Systems (EMS)	29	4
Inspection Bodies (IB)	134	27
Food Safety Management Systems (FSMS)	29	6
Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS)	24	5
Product Certification (PCB)	41	8
Information Security Management Systems (ISMS)	11	5
Energy Management Systems (EnMS)	9	2
Information Technology Service Management Systems (ITSMS)	4	0
Personnel Certification (PrCB)	9	2
Road Traffic Safety Management Systems (RTSMS)	0	0
Trustworthy Digital Repositories Management Systems (TDRMS)	1	0
Greenhouse as Validation and Verification Bodies (GHG)	7	10
Business Continuity Management Systems (BCMS)	3	0
Anti-Bribery Management Systems (ABMS)	0	1
Asset Management Systems (AMS)	0	1
Facility Management Systems (FMS)	0	0
Aerospace Quality Management Systems (AQMS)	2	3
Artificial Intelligence Management System (AIMS)	1	2

4.1 INTERNATIONAL EQUIVALENCES

4.1.1 NABCB becomes signatory to IAF MLA for Validation and Verification

NABCB has been recognized as a signatory to the IAF MLA (International Accreditation Forum Inc. Multilateral Recognition Arrangement) for Validation & Verification, reaffirming its commitment to providing accreditation services which is internationally recognized.

The scope of recognition covers:

- Main Scope: Validation and Verification - ISO/IEC 17029
- Level 4 Sub-scope: ISO 14065:2020 / ISO 14066 / ISO 14064-3
- Level 5 Sub-scope: ISO 14064-1 / ISO 14064-2

This recognition underscores NABCB's proficiency and credibility in providing accreditation to validation and verification conformity assessment activities in accordance with international standards. It reflects NABCB dedication to upholding the highest quality standards and contributing to environmental sustainability efforts globally.

4.1.2 APAC reconfirms MRA status for NABCB

Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) recently reconfirmed its MRA signatory Status for NABCB for the following scope(s) and sub-scopes(s):

- Certification - Managements System (ISO/IEC 17021-1) – BCMS, EMS, EnMS, FSMS, FSSC 22000, ISMS, ITSMS, MDQMS, OHSMS and QMS;
- Certification - Persons (ISO/IEC 17024);
- Certification – Product, Process and Services (ISO/IEC 17065) including Global G.A.P.;
- Inspection (ISO/IEC 17020);
- Validation & Verification Greenhouse Gases (ISO 14065:2013), including ICAO-CORSIA;
- Validation & Verification (ISO/IEC 17029), including Environmental Information (ISO 14065:2020);

The reconfirmation of the MRA signatory status was granted after a rigorous Peer Re-evaluation process by a 9 Member APAC Peer Evaluation Team having evaluators from 9 different accreditation bodies / countries during March/April 2024.

4.1.3 Evaluation of NABCB for Aerospace Quality Management Systems Scheme

The annual oversight visit of NABCB by United Kingdom Regional Management Structure (UK-RMS) for Aerospace Quality Management Systems scheme was successfully conducted during July 3 to 4, 2024. The evaluation was conducted by Mr. Marco Pellegrini, Regional Manager for Northern Europe, and Mr. Mike Oldham, Supplier Quality Specialist from Boeing Commercial Airplanes. This visit was also observed by 2 officials from the Indian Aerospace Quality Group (InAQG). There were 3 Strengths, 4 OFIs and 1 Minor NC reported out of this oversight evaluation, which were suitably addressed by NABCB and accepted by UK-RMS team on August 7 of 2024.

NABCB already accredited two Certification Bodies in AQMS Scheme for providing certifications to AS 9100 series of standards and two more applications are under process.





4.1.4 NABCB secures International Equivalence for EOMS & FAMI-QS

Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) recently confirmed its MRA signatory Status for NABCB for the following sub-scopes(s):

- Education Organization Management Systems (EOMS);
- Quality and Safety System for Specialty Feed Ingredients (FAMI-QS)

The recognition by APAC is based on demonstration by NABCB that it complies with the requirements of international standard, ISO/IEC 17011 applicable to it and has the competence to accredit the certification bodies for EOMS standard & FAMI-QS scheme.

This reaffirms NABCB commitment to providing accreditation services as per the needs of the industry / market.

4.2 UPDATE ON ASSESSORS' CONCLAVE & TRAININGS

4.2.1 NABCB Assessors' Conclave 2024

NABCB organized an annual Assessors' conclave, in hybrid mode during December 16 to 17, 2024 in Manesar, Gurugram. On the first day, which was specific to assessors for certification bodies schemes, deliberations

were held on new accreditation schemes launched by NABCB such as Artificial Intelligence Management Systems, Updates on Scheme Requirements such as FSSC 22000, BRCGS, GlobalG.A.P., IFS, FAMI-QS, Transition Policy on ISO/IEC 27001-1:2024, Latest Development in Aerospace Quality Management Systems, Updates on Schemes under development, Ongoing revisions of ISO CASCO Standards including newly published ISO Standards, IAF mandatory documents and many other relevant topics/ issues.

Mr. Rajesh Maheshwari, CEO, NABCB inaugurated the conclave with a welcome address and provided updates on NABCB, APAC, ISO, IAF & ILAC. He appreciated all assessors for providing their strong support & services to NABCB.

Other deliberations included discussion on document review, key non-conformities, Assessment techniques and risk-based Assessment methodologies, assessment reports, code of ethics, and assessment experience sharing for harmonization of assessors.

The second day of the Conclave was held to harmonize NABCB Assessors for Inspection and Validation/Verification Bodies. Updates on Govt., Regulators, Industry & other bodies prescribing NABCB accredited Inspection bodies were provided to assessors.

The deliberations included Key requirements for IB Accreditation, Issues related to assessments of IB.

A session was also held on Overview of ICAO CORSIA Scheme, Discussion on New Schemes – ISCC, BRSR Code Assurance, Transition Policy for ISO 14066:2023.

The conclave was attended by more than 100 assessors who joined physically and virtually both.





4.2.2 NABCB Assessors Training on ISO/IEC 17065:2012

To enhance the NABCB Assessors pool and to train the existing assessors on different standards, NABCB conducted a 3-day Assessors' Training on ISO/IEC 17065:2012 from December 19 to 21, 2024 in New Delhi. The training was attended by 25 potential assessors. The training was delivered by very experienced and seasoned NABCB faculty, Ms. Rajalakshmi Subrahmanyam and Mr. Anupam Gupta. This was followed by an examination/ evaluation of the participants

4.2.3 NABCB Training Programme on ISO/IEC 17020:2012

To enhance the NABCB Assessors database and to train the existing assessors and new potential assessors on different standards, NABCB conducted a 3-day Assessors' Training on ISO/IEC 17020:2012 from January 6-8, 2025 in New Delhi. The training was attended by 26 potential assessors. The training was delivered by very experienced and seasoned NABCB Trainer, Ms. Rajalakshmi Subrahmanyam and Mr. R.D. Khatri. The training was followed by an examination process of all the participants.



4.2.4 NABCB partnership with BSI and UKAS

NABCB, in partnership with BSI and UKAS, successfully organized a training on Quality Management Systems (AQMS) on March 4–5, 2025. The program focused on AS 9104-001:2013 and best practices in aerospace quality management system certification, encouraging active participation. It was designed for professionals familiar with QMS requirements and those seeking a better understanding of aerospace and defense sector standards.

The training aimed to support NABCB, QCI, Indian industries, training institutions, and key stakeholders in developing and implementing QMS standards in the aviation sector by sharing UK/EU best practices. Key topics covered included an overview of standards, best practices in assessment planning, common assessment challenges, and key updates on AS 9104-1:2022 and IA 9104/1.



4.2.5 NABCB organized Assessors Training on ISO/IEC 17024:2012

To enhance the NABCB Assessors database and to train the existing assessors and new potential assessors on different standards, NABCB conducted a 3-day Assessors' Training on ISO/IEC 17024:2012 from February 20-22, 2025 in New Delhi. The training was attended by 21 potential assessors. The training was delivered by very experienced and seasoned NABCB Trainer, Mr. S Krishnamurthy and Mr. A Sudhindra. The training was followed by an examination process of all the participants.



4.2.6 Training Programme on Sustainable Aviation Fuel

NABCB participated in a workshop organized by Directorate General of Civil Aviation (DGCA) International Civil Aviation Organization (ICAO) and the European Aviation Safety Agency (EASA) on Sustainable Aviation Fuel during January 23-24, 2025.

The 2-day interaction had invaluable learning experience for all the participants. Many aspects of SAF, including feedstocks technology pathways, potential SAF production capacity creations, infrastructure creation for feedstock aggregation, SAF production and SAF blending and its supply to airport facilities, including SAF Sustainability Certification, eligibility of ensuing CORSIA credits on production and sale of SAF as well as their trading mechanism.



4.2.7 NABCB organized Assessors Training Programme on ISO/IEC 17021-1:2015

To enhance the NABCB Assessors database and to train the existing assessors and new potential assessors on different standards, NABCB conducted a 3-day Assessors' Training on ISO/IEC 17021-1:2015 from March 24-26, 2025 in New Delhi. The training was attended by 29 potential assessors. The training was delivered by very experienced and seasoned NABCB Trainer, Ms. Rajalakshmi Subrahmanyam

and Mr. Anupam Gupta. The training was followed by an examination process of all the participants.



INTERNATIONAL CAPACITY BUILDING ACTIVITIES

4.3 INTERNATIONAL ACTIVITIES

4.3.1 NABCB supported APAC in organizing Training on BRCGS

NABCB supported Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) in organising a Training Programme for Accreditation Bodies on BRCGS Food Standard in relation to ISO/ IEC 17065 during September 3 – 5, 2024 in New Delhi. The training was attended by 19 Participants from Asia Pacific Region. Ms. Ritu Bajaj and Mr. Ashish Gaur from BRCGS were Faculty for this training. 06 NABCB officials also attended this training.



4.3.2 Capacity Building Activities for Mauritius Accreditation Body (MAURITAS)

NABCB was assigned projects by The Ministry of Industrial Development, SMEs and Cooperatives, Govt. of Mauritius for Capacity Building Activities of Mauritius Accreditation Body (MAURITAS) for Information Security Management Systems, Product Certification & Food Safety Management Systems.

As a part of this project, NABCB organized training programmes on Information Security Management Systems (ISMS), Product Certification (PCB) and Food Safety Management Systems (FSMS) during July 29 – August 2, 2024, August 5 – 9, 2024 and November 18-20, 2024 respectively which was attended by approx. 20 participants in each programme. The trainings were highly appreciated by the participants.

NABCB also conducted the Gap Analysis of the existing system of MAURITAS for Product Certification accreditation scheme and presented a report to MAURITAS.





4.4 INTERNATIONAL EVENTS PARTICIPATION

4.4.1 Participation in IAF/ILAC/PAC/APLAC meetings

i. APAC Peer Evaluator Workshop on ISO 15189 in New Delhi during June 27-28, 2024

ii. Meeting of Small Group TFG Document to Address AB Cooperation virtually on July 5, 2024

iii. APAC Annual Meetings in Dubai during July 14-18, 2024

iv. Joint IAF / ILAC Mid Term Meeting virtually during March– April 2024

v. 4th meeting of ISO/CASCO WG 30 in Geneva during May 28-30, 2024

vi. BRCGS Annual Meeting on September 30, 2024 in Berlin

vii. IFS Annual Meeting on October 1, 2024 in Berlin

viii. GlobalG.A.P. Annual Meeting on October 2, 2024 in Berlin

ix. IAF & ILAC Joint Annual Meeting during October 1-10, 2024 in Berlin

x. Peer Evaluation of RusAccreditation during September 23 – 28, 2024 in Moscow

xi. Bilateral Meeting with Ministry of Industry & Advanced Technology (MoIAT), Govt. of UAE to discuss MRA for Halal Certification on February 18, 2025

xii. APAC Lead Evaluator Workshop, Meeting with CNAS regarding IAF CertSearch and APAC Executive Committee Meeting during February 26 – March 1, 2025.

4.4.2 Other meetings/trainings

NABCB officials participated / attended in the following:

i. United Kingdom Regional Management Structure Board Meeting virtually on May 14, 2024, in which NABCB presented the current status of AQMS accreditation programme.

ii. Indian Regional Management Structure Board Meeting virtually on May 17, 2024. NABCB presented the current status update for AQMS accreditation to InAQG.

iii. Meeting TFG Document to Address AB Cooperation virtually on August 1, 2024.

iv. ADAPT Workshop on Digital Assessment Tools & Techniques: Experience Sharing–Post assessment virtually on August 7, 2024.

v. IAF Digital Transformation Meeting virtually.

vi. PEFC CoC EUDR Training for Accreditation Bodies on August 26, 2024.

vii. APAQG & IAQG Annual Meeting during October 20-24, 2024

viii. ISO CASCO WG 65 Meeting during October 29-31, 2024

ix. ISO CASCO WG 65 Meeting during November 20-22, 2024

x. 47th session of Codex Alimentarius Commission during November 25-30, 2024 in Geneva

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL MEETINGS

4.5 INTERNATIONAL MEETINGS

4.5.1 NABCB meeting with Mesopartner

NABCB had a meeting with Dr. Ulrich Harmes-Liedtke, a partner at Mesopartner on July 12, 2024, to discuss strategies for improving India's ranking in the Global Quality Infrastructure Index (GQII). Mesopartner is a knowledge firm that specializes in economic development, competitiveness and innovation.

The GQII measures the quality and performance of a country's quality infrastructure, including standards, metrology, accreditation, and conformity assessment. India's current ranking in the index was a focal point of the discussion, with the goal of identifying actionable steps to enhance its position. Currently, Indian Accreditation system is ranked 5th in the world.

During the meeting, Dr. Harmes-Liedtke informed about some parameters on which the GQII ranking is based. The collaboration between NABCB and Mesopartner is expected to contribute to India's strategic efforts to enhance its global competitiveness by aligning its quality infrastructure with international benchmarks.

4.5.2 NABCB meeting with DGCA and ISCC Gmbh

DGCA along with NABCB initiated discussions with ISCC Gmbh, which ICAO officially recognizes as one of the certification schemes, to demonstrate compliance with

the sustainability criteria for CORSIA-eligible fuels, with an intent to initiate certification of SAFs in India. This meeting was held on July 5, 2024.

The International Civil Aviation Organization's (ICAO) Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) will require airlines to blend sustainable aviation fuel (SAF) with jet fuel for international flights starting in 2027. This is a key part of CORSIA's mandatory phase, which will apply to all international operators, with some exceptions. The goal is to reduce carbon dioxide emissions beyond 2020 levels. The Government of India has also set an indicative target of blending 1% SAF with conventional jet fuel by 2027. The National Biofuels Coordination Committee (NBCC) of India has set a target to blend 1% sustainable aviation fuel (SAF) with jet fuel for international flights starting in 2027. This target is in line with the International Civil Aviation Organization's (ICAO) Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).

4.5.3 NABCB meeting with Global Seafood Alliance (GSA)

An Annual Meeting was held virtually between NABCB and Global Seafood Alliance (GSA) on July 25, 2024.

GSA engages worldwide stakeholders committed to advancing environmentally and socially responsible aquaculture practices. Through the development of the Best Aquaculture Practices (BAP) certification standards, GSA has become the leading standards-setting organization for aquaculture seafood.

The meeting covered technical updates about GSA programs as well as potential areas for collaboration and technical advancement between NABCB and GSA. NABCB has already singed an MoU with the GSA.

4.5.4 Meeting with FSSC Foundation Team

NABCB had a virtual meeting on May 3, 2024 with the FSSC Foundation team which comprises Mr. Aldin Hilbrands- CEO, Mr. Colin Morgan – Market Development Director; Mr. Ante Batinic- Technical Manager Social Sustainability and Ms. Smita Murthy-India Representative for FSSC Foundation. The meeting was aimed to discuss the FSSC 24000 scheme and the way forward. Interaction was also focused on organizing a training program for NABCB assessors & officers for FSSC 24000 scheme and a detailed awareness session for NABCB accredited / applicant CABs on FSSC 24000. The meeting was attended by CEO, NABCB along with senior officials.

4.5.5 Webinar on ISACA's Credentialing Programme and CMMI Assessment Frameworks

NABCB, in collaboration with ISACA, conducted a highly informative webinar on ISACA's Credentialing Programme and CMMI Assessment Frameworks on July 8, 2024.

ISACA, a global leader in IT certifications with a membership of over 170,000 professionals worldwide, shares its commitment to support India's cyber security goals. Their extensive expertise in IT certifications, including CISA, CISM, and the Certified in Emerging Technology (CET) certification, align perfectly with our mission to promote excellence in various fields.

The webinar included detailed presentation on ISACA's Credentialing Programme (CISA, CISM, CGEIT, CDPSE, CRISC) and the CMMI Assessment Frameworks. The webinar was attended by more than 100 participants.

4.5.6 Webinar on ECCP & Europrivacy / Interprivacy Certification Schemes

NABCB in association with Europrivacy conducted a Webinar on ECCP & Europrivacy / Interprivacy Certification Schemes, which drew an impressive participation of over 140 participants worldwide.

The session kicked off with current insights from Mr. Rajesh Maheshwari, CEO, NABCB on the regulatory landscape and the need for accredited certification on data privacy / protection. Dr. Sébastien Z., Chairman of the Europrivacy International Board of Experts

at ECCP provided an overview on the ECCP, Europrivacy, and Interprivacy frameworks essential tools for safeguarding data privacy in today's interconnected world. He also outlined how certification bodies can certify under these schemes to lead in privacy compliance and data protection. This turnout reinforces the urgency and commitment to advancing privacy certification standards on a global scale.

The webinar was attended by around 200 participants.

4.5.7 Webinar on Get It Fair (GIF) ESG Rating and Sustainability Reporting Scheme

NABCB in collaboration with Get It Fair conducted a highly informative webinar on Get It Fair (GIF) - ESG Rating and Sustainability Reporting Scheme on November 22, 2024.

The GIF ESG Rating scheme is designed to meet the organization (and its Stakeholders) needs for credible and verified information regarding social responsibility and the ESG risks within its operations and supply chain.

The webinar provided insights about the Get It Fair (GIF) ESG Rating and Sustainability Reporting Scheme, Trends and demand for Accurate, Reliable and Credible Sustainability Information, ESG Rating and Sustainability Reporting, the role of accreditation and Onboarding Process for VVBs.

The webinar was attended by more than 200 participants.

4.5.8 Meeting with Siemens, Germany

NABCB had a meeting with senior officials from Siemens, Germany, the industry giant from Germany, which operates in multiple industry sectors and has a significant presence in India.

The meeting was held on December 4, 2024 to have information exchange and hold discussions on emerging areas & practices in conformity assessment such as Artificial Intelligence (AI), Digital Product Passport and other related areas. The Siemens team also briefed NABCB on the implementation of the forthcoming EC Regulation on AI and offered to facilitate mutual areas of interest from the industry's perspective. NABCB also briefed the Siemens team about the Quality Infrastructure in India, especially the accreditation ecosystem which is ranked 5th globally as per the last two GQII global rankings.

4.5.9 Meeting with Global Quality Infrastructure Index (GQII)

NABCB organized a meeting with Global Quality Infrastructure Index (GQII) on February 14, 2025. The meeting was attended by representatives of Bureau of Indian Standards (BIS), National Physical Laboratory (NPLI), National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL). The meeting was organized to discuss the methodology for GQII 2025 Rankings and to present inputs/preparation for this year's ranking.

4.5.10 UK RMS Board Meeting

NABCB attended the quarterly meeting of UK-RMS (United Kingdom Regional Management Structure for Aerospace QMS scheme) in virtual mode, which was held on February 25, 2025. This meeting was attended by CEO along with senior officials from NABCB. The meeting had deliberations from various stakeholders i.e. certification bodies, accreditation bodies such as UKAS & NABCB, Regulatory body from Defense sector of UK.

4.6 SUPPORT TO GOVT / REGULATORS/ INDUSTRY / CONSUMERS

4.6.1 TEC decides to rely on NABCB accreditation

QCI/NABCB and Telecom Engineering Centre (TEC), the Regulator in India for approval of Telecom Products and their manufacturers, agreed to collaborate for developing the "India Conformity Assessment Scheme (i-CAS) –Telecom Products" for accrediting Product Certification Bodies (PCBs) in accordance with ISO/IEC 17065 and to rely on NABCB accredited certification of the manufacturers of telecom products and related ICT equipment, and their type approvals.

A kick-off meeting was held between QCI/ NABCB and TEC, which marks a landmark moment as another Regulator decides to rely on NABCB accreditation. CEO NABCB Mr. Rajesh Maheshwari and DDG TEC Mr. Prashant Kumar together with their respective teams and experts deliberated on various aspects in developing this scheme and its specific requirements.

This collaboration signifies a concerted effort by QCI/NABCB towards ensuring a robust, accredited conformity assessment ecosystem for telecom & related ICT products in India, promising a future where certified products from India shall meet international benchmarks, fostering trade and competitiveness in the global markets.

4.6.2 Meeting with Securities Exchange Board of India (SEBI)

SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD-2/P/CIR/2021/562 dated May 10, 2021 in conjunction with Master Circular No. SEBI/ HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 had decided to introduce Verification of Assurance of ESG Disclosure by the listed entities. In this context, NABCB initiated discussion with SEBI on prescribing NABCB accreditation for Assurance Providers who shall be carrying out verification of Business Responsibility (BR) and Sustainability Reporting (SR) Core Assurance. SEBI has agreed to consider National Accreditation in their industry standards on BRSR Core Assurance.

4.6.3 Meeting with Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)

A meeting was held with CMD, BHEL on December 24, 2024 to prescribe NABCB accreditation for its various manufacturing facilities, vendors in the whole supply value chain. Subsequently, discussion was also held with senior officials of Quality Assurance department, BHEL to prescribe NABCB accreditation specially for Inspections and Management systems for its needs as well in its supply chains. NABCB and BHEL agreed to work together to further leverage other areas of NABCB accreditation to enhance the quality of products and services in its supply chain.

NABCB officials Mr. Ajay Sharma and Mr. Anand Deep Gupta, Joint Directors also had the follow up meeting with BHEL on February 13, 2025 for further deliberations with Senior officials from Corporate QA and Corporate HSE departments of BHEL.

4.6.4 Meeting with Ministry of Power (MoP) and Director General, BEE

Shri Rajesh Maheshwari, CEO, NABCB met with Mr. Shri Srikant Nagulapalli, Additional Secretary, Ministry of Power (MoP) and Director General, BEE on January 20, 2025 regarding prescribing National Accreditation for Carbon Credit Trading Scheme (CCTS). Extensive discussions were also held on utilization of NABCB accredited Conformity Assessment Bodies (CABs) for carrying out inspections, certifications and Validation & Verification for various regulatory bodies, PSUs and JVs under the MoP.

4.6.5 Meeting with Mazagon Dock Shipbuilders

NABCB, as part of its “Industry Connect” initiative, met senior officials at Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. in Mumbai on February 18, 2025 to promote NABCB accreditation and accredited conformity assessment. Mazagaon Dock Shipbuilders, a 250 years old organization, is one of India’s premier shipbuilding companies, producing modern warships for the Navy and Coast Guard, Offshore structures for Bombay High, as well as various commercial and utility marine vessels. Over the years MDL has earned a reputation for quality work and excellent service in the shipping industry.

Mr. Rajesh Maheshwari, CEO NABCB and Mr. C M Latkar, HOD/GM led the discussions along with other senior officials of MDL and Mr. Ajay Sharma, Joint Director, NABCB. It was emphasized to MDL to use or prescribe NABCB accreditation for its diverse conformity assessment needs of MDL, including third-party inspections and product certification in its supply chain, certification of persons, verification activities etc and the benefits it will gain from international recognition of NABCB. It was hearty to know that MDL was already holding NABCB-accredited management systems certifications and was prescribing

NABCB accreditation for third-party inspections.

The meeting was facilitated by Mumbai-based International Certification Services Pvt. Ltd., a NABCB accredited body. Its Country Manager Mr. Sumeet Kataria and other officials attended the meeting.



4.6.6 Meeting with Reliance Jio

NABCB, as a part of its "Industry Connect" initiative met senior officials at Reliance Jio Infocomm Limited on February 21, 2025 to promote NABCB accreditation and accredited conformity assessment. Reliance Jio is the largest telecom operator in India and the 2nd largest single-country operator in the world. Jio has ushered in a digital revolution across India, and after launch of its services in 2016 has catapulted India in an year to 1st rank globally in mobile broadband data consumption.

Mr. Rajesh Maheshwari, CEO and Mr. Ajay Sharma, Joint Director from NABCB met Mr. Dhruv Kumar Tayal, President, Network Infra; Mr. Sudhir. Aggarwal, Sr. VP; Mr. Ashok Kumar Shrivastava & Sustainability and other senior officials of RJIL at Reliance Corporate Park in Navi Mumbai. An overview on NABCB accreditation and its global reach across industry sectors was presented to RJIL and it was emphasized to use or prescribe NABCB accreditation for its diverse conformity assessment needs, including its supply chain. RJIL officials showed very keen interest in NABCB accreditation, especially in accredited third-party inspections, product certifications in its supply chain, certification of persons for various skills it needs in the field to establish & maintain its infrastructure, accredited verification activities etc. and the benefits it will gain from international recognition of NABCB. It was hearty to know that RJIL was already holding NABCB accredited certification in one management system, and intends to have more under NABCB accreditation. It has also shown interest to prescribe NABCB accreditation for various third-party conformity assessments.

The meeting was facilitated by Mumbai based Bureau Veritas Group India Pvt. Ltd., a NABCB accredited body and was also attended by its General Manager Mr. Shyam Deshmukh and other officials.



4.6.7 Meeting with Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC)

Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC) senior officials recently visited NABCB to understand more about NABCB accreditation and accredited conformity assessment, especially product certification. Delhi Metro, a public sector company jointly established by the Government of India & the Government of Delhi in 1995, is the largest and busiest rapid transport system in India, connecting the country's capital region with satellite cities. The Delhi Metro has been instrumental in ushering in a new era in the sphere of mass urban transportation in India. The Delhi Metro has also contributed tremendously on the environment front by becoming the first ever railway project in the world to claim carbon credits for regenerative braking. DMRC has also been certified by the United Nations (UN) as the first Metro Rail and rail-based system in the world to get carbon Credits for reducing greenhouse gas emissions, as it has helped reduce pollution levels in the city by 6.3 lakh tons every year, thus helping in reducing global warming.

DMRC officials Mr. Arun Kumar, Advisor (S&T), Mr. Shobhan Chaudhuri, Advisor

(R&D); Mr. Navin Talwar, Executive Director (R&D); & others met Mr. Rajesh Maheshwari, CEO, Mr. Ajay Sharma and Mr. Anand Deep Gupta, Joint Directors at NABCB. An overview of NABCB accreditation and, more specifically, related to accredited conformity assessment in the metro/railway sector was presented to DMRC officials. It was emphasized to DMRC to use or prescribe NABCB accreditation for its diverse conformity assessment needs, including in its supply chain. DMRC officials expressed keen interest in NABCB accreditation, especially in accredited product certification for Independent Safety Assessment (ISA) for railway safety standards & regulations. Product certifications in the supply chain and certification of persons for various specialized skills were also emphasized to DMRC. DMRC has shown interest in prescribing NABCB accreditation for its various third-party conformity assessment needs, and DMRC shall have further follow-up meetings with NABCB.



4.6.8 Meeting with L&T Energy – Hydrocarbon (AdVENT)

NABCB, as part of its "Industry Connect" initiative, recently met senior officials at L&T Energy – Hydrocarbon (AdVENT) to promote NABCB accreditation and accredited conformity assessment. The Hydrocarbon business of L&T executes projects encompassing all functions, such as engineering, procurement, fabrication, construction, installation, project management, and asset life management services. AdVENT (Advanced Value Engineering & Technology) is one of the business verticals in L&T that offers Integrated Modular Solutions, EPC Project Solutions & Cutting-Edge Hydrocarbon Technologies to the Hydrocarbon and Specialty Chemical Industry.

Mr. Rajesh Maheshwari, CEO, and Mr. Ajay Sharma, Joint Director from NABCB, met Mr. Alok Khare, Head QA/QC; Mr. Gurudas Madye, Head Quality, Offshore Wind Business; Mr. Pramod Patil L&T, DGM QA/QC, and other senior officials of L&T AdVENT in Mumbai. An overview of NABCB accreditation and its global reach across industry sectors was presented to L&T, and it was emphasized to use or prescribe NABCB accreditation for its diverse conformity assessment needs, including its supply chain. L&T officials expressed keen interest in NABCB accreditation, especially in accredited third-party inspections, product certifications in its supply chain, certification of persons for various specialized skills it needs, etc. L&T has also shown interest in prescribing NABCB accreditation for its various third-party conformity assessment needs.

SGS India Pvt. Ltd., a NABCB-accredited body, facilitated the meeting. Mr. Vishwas Nakhwa, Head, EXIM and HS&Q, Industries & Environment from SGS, also attended.

4.6.9 Meeting with Sundram Fasteners Limited (SFL)

NABCB, as part of its "Industry Connect" initiative, recently met senior officials at Sundram Fasteners Limited (SFL) to promote NABCB accreditation and accredited conformity assessment. Sundram Fasteners Limited is an Indian manufacturer of high-precision components for the automotive, infrastructure, wind energy and aviation sectors. SFL was established in 1962 as a subsidiary of the TVS Group under the name Kasjax Engineering Ancillaries. The company manufactures a wide range of products including fasteners, drivetrain parts, molded metal goods, radiator tops and water pumps. Headquartered in Chennai, Tamil Nadu, SFL operates several plants across Puducherry, Andhra Pradesh, Uttarakhand and Tamil Nadu. The company has also built a global footprint with subsidiaries such as Sundram Fasteners (Zhejiang) Limited in China and Cramlington Precision Forge Limited in the United Kingdom.

Mr. Rajesh Maheshwari, CEO, and Mr. Ajay Sharma, Joint Director from NABCB, met with Mr. S.V. Mahesh, Executive director from SFL. An overview of NABCB accreditation and its global reach across industry sectors was presented to Sundram Fasteners Limited (SFL), and it was emphasized to use or prescribe NABCB accreditation for its diverse conformity assessment needs, including its supply chain. Sundram Fasteners Limited (SFL) officials expressed keen interest in NABCB accreditation, especially in accredited third-party inspections, product certifications in its supply chain, certification of persons for various specialized skills it needs, etc. SFL has also shown interest in prescribing NABCB accreditation for its various third-party conformity assessment needs.

4.6.10 Meeting with KDDL Limited, A Unit of Eigen Group

NABCB, as part of its "Industry Connect" initiative, recently met senior officials at KDDL limited (Unit Eigen) on March 24, 2025 to promote NABCB accreditation and accredited conformity assessment.

Mr. Rajesh Maheshwari, CEO, and Mr. Ajay Sharma, Joint Director from NABCB, met with Mr. MS Ramanandan (Plant head); Mr. Krishnamurthy Bhat (Management Representative) and Mr. Bhoopathi (Marketing Head) from KDDL Limited. An overview of NABCB accreditation and its global reach across industry sectors was presented to KDDL limited (Eigen group). KDDL Limited officials expressed keen interest in NABCB accreditation, especially in accredited third-party inspections, product certifications in its supply chain, certification of persons for various specialized skills it needs, etc. KDDL Limited has also shown interest in prescribing NABCB accreditation for its various third-party conformity assessment needs.

4.6.11 Industrial Decarbonization Summit 2025 (IDS)

NABCB CEO Mr. Rajesh Maheshwari was invited as a "Speaker" in 2nd edition of the "Industrial Decarbonization Summit – Road to Net Zero 2025 (IDS)" on January 15, 2025. He delivered a technical presentation about "Accreditation facilitating Carbon Capture & Storage technologies", where he described about the role of NABCB accreditation and how the industry benefits from using accredited services.

This event was inaugurated by Hon'ble Minister Shri Nitin Gadkari, Union Minister, Road Transport and Highways. It was attended by various stakeholders including government, industry, consultants and service providers. Panel Discussion and Presentations covered divergent topics including government policies and regulations in promoting the adoption of Decarbonization, International Climate, E-Mobility, ESG, Low Carbon Production, Battery Charging & Energy Storage System and Carbon Capture Utilization and Storage technologies.

This event was jointly organized by Indian Association for Air Pollution Control (IAAPC), Delhi and PHDCC.

The summit will focus on several topics related to decarbonization leading to climate change & mitigation, sustainability management, policy issues, sustainability trajectory to net zero and promising technologies for innovative climate solutions.

This event was attended by a community of public and private sector leaders who were at the forefront of climate action in India, aiming to build strategic business connections, gain new insights, and collaborate with global leaders on climate through networking events and strategy exchange sessions.



4.6.12 International Material Recycling Conference by MRAI

Mr. Rajesh Maheshwari, CEO NABCB, was invited as a speaker at the 2025 International Material Recycling Conference by MRAI on January 28, 2025, joining the session "Unlocking Carbon Markets and the Role of Recycling in the Circular Economy." He spoke about the role of Carbon Capture and Storage (CCS) in reducing GHG emissions, the importance of accreditation in ensuring credible emission reduction, and the role of accredited Validation and Verification Bodies (VVBs) in Carbon Capture and Utilization (CCU).

This conference brought together various ministries, stakeholders, and recyclers under one roof for networking and showcasing their business interests, products, technologies, services, new innovations, and perspectives.



4.7 PROMOTIONAL ACTIVITIES

4.7.1 NABCB celebrates World Accreditation Day 2024

World Accreditation Day (WAD) is a global initiative established by the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and International Accreditation Forum (IAF). It is celebrated on June 9 every year to raise awareness on the importance of accreditation among relevant stakeholders. To commemorate the World Accreditation Day (WAD) 2024, National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) and National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), the two constituent boards of the Quality Council of India (QCI), organized events at different parts of countries with main event being held at New Delhi and 19 parallel events in other cities namely Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, Ahmedabad and Lucknow etc. on the theme "Accreditation: Empowering Tomorrow and Shaping the future".

The Inaugural session had the presence of eminent dignitaries including Mr. Rajesh Kumar Singh, Secretary, DPIIT; Mr. M. Srinivas, Director, AIIMS, New Delhi; Mr. Jaxay Shah, Chairman, QCI & Mr. Chakravarthy T. Kannan, Secretary General, QCI.

Mr. Rajesh Maheshwari, CEO, NABCB in his welcome address stressed that a robust accreditation system ensures that an organization reaches a high-level of quality and standards and the boards of QCI – NABCB & NABL – have a significant role to play in enlightening about accreditation.

The WAD 2024 joint message by the IAF-ILAC chair message was read by Mr. Pankaj Johri, Director, NABL. The message delivered that by providing a framework of trust and reliability, accreditation enables organizations to confidently embrace new technologies and drive innovation. Whether in manufacturing, healthcare or agriculture, accredited conformity assessment conferms that new products and processes meet rigorous requirements, facilitating their adoption and integration into existing systems. Testing and inspection provide confidence in product safety and regulatory compliance. Data protection and cyber security schemes help businesses to implement comprehensive data protection processes, guard against increasingly sophisticated cyber attacks, and safeguard customer privacy.

Chief Guest, Mr. Rajesh Kumar Singh, Secretary, DPIIT, emphasized on the need to go beyond the standard practices and develop processes that make us stand out from the crowd. He mentioned that strengthening the accreditation body and the entire quality system is not just a necessity but a strategic move towards excellence.

Mr. Chakravarthy T. Kannan, Secretary General, QCI in his speech at the event, talked about the futuristic vision of QCI, emphasizing India's significant achievements

under QCI's guidance and outlining ambitious goals for the coming years. He highlighted that quality is a continuous journey and underscored the pivotal role of artificial intelligence in shaping the future, suggesting that AI would be instrumental in advancing the quality standards and accreditation processes.

In his keynote speech, Dr. M. Srinivas, Director, AIIMS, New Delhi, stressed upon the importance of maintaining high standards across all domains, including IT, cyber security, and AI. Dr. Srinivas pointed out that many laboratory tasks are now performed by AI, which enhances checks, balances, and security processes.

In the technical session, panellist from BIS, ICMR, Carbon Check. IARI, TUV SUD South Asia, Drone Federation of India & IRCLASS highlighted the critical role of standards as the threads that weave excellence into every aspect of industrial practices. They emphasized that adherence to these standards ensures consistency, quality, and reliability. Additionally, they underscored the importance of accreditation, portraying it as a seal of trust that validates an organization's commitment to maintain these high standards, thereby fostering confidence among stakeholders and consumers.





4.8 NABCB Interaction with Conformity Assessment Bodies (CABs)

4.8.1 Annual Meeting 2024 with Inspection Bodies

NABCB Annual Inspection & Validation/ Verification Bodies (IBs & VVBs) interaction meeting was organized on May 13, 2024. This meeting was organized in Hybrid mode. The meeting was also graced by Dr. R.P. Singh, Chairman-NABCB, who also addressed the participants with his insights. The meeting was attended by 82 participants in-person and approx. 40 participants virtually. The meeting also had presence of regulators & Scheme Owners organizations like PNGRB, BIS, FSSAI, BEE, DGQA, DGCA & VERRA who shared about their requirements / experience w.r.t use of accredited Inspection Bodies. Various issues and concerns raised by IBs & VVBs were discussed. Discussions were focused on accredited third-party inspections, experiences from accredited bodies and the status of Sustainable Aviation Fuel programme. The NABCB Secretariat shared updates on ILAC, APAC, and IAF resolutions, transition policies, and revised accreditation criteria.



4.8.2 Annual Meeting 2024 with Certification Bodies

NABCB Annual Certification Bodies (CBs) interaction meeting was organized on May 14, 2024. This meeting was organized in Hybrid mode. Meeting was attended by 58 participants in-person and approx. 35 participants virtually. As per the agenda, presentations on various topics like update

on IAF/APAC, New ISO CASCO standards & revision status, New Schemes included under IAF MLA, various IAF Mandatory Documents, Transition Policy, were made and clarifications provided on queries of CBs. Certification Bodies also shared their experience with NABCB. The meeting also had presence of Regulators & Scheme Owners organizations like CEA, CDSCO, FSSC Foundation and BRCGS who also attended this meeting and interacted with the Certification Bodies.



4.8.3 NABCB Gunvatta Manthan

The Gunvatta Manthan of the National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) was successfully conducted on February 17, 2025, bringing together 35+ industry leaders from Conformity Assessment Bodies (CABs) for a deep dive into the future needs for NABCB accreditation and accredited conformity assessment as required from the national as well as the stakeholder's perspective. The event was organized by NABCB and NBQP.

The deliberations were led by Shri Chakravarthy T. Kannan, Secretary General, QCI; Dr. Ravi P. Singh, Chairperson, NABCB; Smt. Hemgauri Bhandari, Chief Advisor, QCI; and Shri Rajesh Maheshwari, CEO, NABCB. They actively led the brainstorming session, addressed queries, gathered stakeholders feedback, and provided valuable insights to strengthen the accreditation ecosystem.

With valuable insights and a shared commitment to quality, this Manthan paves the way for a stronger ecosystem for assuring quality through accredited third-party conformity assessment across industry sectors in India.



4.8.4 Annual Meeting 2025 with Certification Bodies

NABCB Annual Certification Bodies (CBs) interaction meeting was organized on February 24, 2025. This meeting was organized in Hybrid mode. Meeting was attended by 51 participants in-person and approx. 35 participants virtually. As per the agenda, presentations on various topics like update on IAF/APAC, ICOP Scheme of Aviation, Space & Defense Sector, i-CAS Halal Scheme, Transition Policy, Certification Scheme on Sustainable Aviation Fuel, International Featured Standards (IFS) Scheme, QCI-PADD: Conformity Assessment Schemes, ISA Secure Scheme for Cybersecurity in Industrial Automation, Independent Safety Assessment (ISA) for Railways etc., were made and clarifications provided on queries of CBs. Certification Bodies also shared their experience with NABCB. The meeting also had presence of Regulator such as CDSCO & Scheme Owner organizations like ISCC, IFS and InAQG who also attended this meeting and interacted with the Certification Bodies.



4.8.5 Annual Meeting 2025 with Inspection Bodies

NABCB Annual Inspection & Validation/ Verification Bodies (IBs & VVBs) interaction meeting was organized on February 25, 2025. This meeting was organized in Hybrid mode. Dr. R.P. Singh, Chairman-NABCB joined the meeting virtually and addressed the participants with his insights. The Meeting was attended by 86 participants in-person and approx. 30 participants virtually. The meeting also had presence of Regulators & Scheme Owners organizations like PNGRB, Gold Standard & VERRA who shared about their requirements / experience w.r.t use of accredited Inspection Bodies. Various issues and concerns raised by IBs & VVBs were discussed. Discussions were focused on accredited third-party inspections, Gold Standard, VERRA Certification Scheme Sustainable Aviation Fuel programme etc. The NABCB Secretariat shared updates on ILAC, APAC, and IAF resolutions, transition policies, and updates on the change in ISO ISO/IEC 17020.



4.9 CONSUMER / INDUSTRY AWARENESS PROGRAMMES

4.9.1 Awareness Session on AQMS Accreditation

The Indian Aerospace Quality Group (InAQG), the country quality group of APAQG/IAQG along with NABCB, hosted Awareness Webinar session on “InAQG and its role in the Indian Aerospace supply chain improvement initiatives” on April 25, 2024. This awareness session covered the topics such as establishment of InAQG and its role and India-ICOP Scheme developed by NABCB. The session was attended by approx. 40 participants.

4.9.2 Webinar on NABCB accreditation for Inspection Bodies and its benefits to Industry & Government Bodies

NABCB organized a webinar on Inspection Bodies Accreditation Scheme on June 18, August 28, 2024; November 13, 2024, January 15, 2025; February 19, 2025 & March 19, 2025 with an objective to increase the awareness about the benefits of using NABCB accredited inspection body amongst the Government organizations, Regulators, Industry and to promote the Inspection Bodies accreditation scheme. NABCB received an overwhelming response and approx. 740 participants attended, including from countries like Afghanistan, Bangladesh, Ghana, Morocco, Hong Kong, Bhutan, Kazakhstan, Mongolia, Nepal, Kenya, Russia, Philippines, Jordan, Taiwan, Iran & UAE etc. The webinar covered details of NABCB accreditation and its benefits, NABCB accreditation process and key requirements of ISO/IEC 17020:2012 standard. The speakers for the webinar were Mr. Ajay Sharma, Mr. Anand Deep Gupta, Joint Directors and Ms. Varsha Misra, Deputy Director from NABCB.

4.9.3 Webinar on NABCB Accreditation for Validation and Verification Bodies, with an overview of ISO/IEC 17029:2019

NABCB organized webinars on August 23, 2024 and December 30, 2024 with an objective to increase the awareness about the benefits of using NABCB accredited Validation and Verification Bodies amongst the Government organizations, Regulators, Industry and to promote the Validation and Verification Bodies accreditation scheme. NABCB received an overwhelming response and approx. 300 participants attended, including from countries like Bhutan, Ghana, Kazakhstan, Mongolia, Peru, Sri Lanka Tunisia, Myanmar, Mongolia, Kenya, UAE & Jordan etc. The webinar covered details of NABCB accreditation and its benefits, NABCB accreditation process and key requirements of ISO/IEC 17029 standard. The speakers for the webinar were Mr Ajay Sharma and Mr. Anand Deep Gupta, Joint Directors from NABCB.

4.9.4 Webinar on Accreditation of Product Certification Bodies with an overview on ISO/IEC 17065:2012

NABCB conducted a webinar on November 19, 2024 & February 26, 2025 on Accreditation of Product Certification Bodies with an overview on ISO/IEC 17065:2012 standard. Knowledge on Various National / International Product Certification Schemes was provided during this webinar. The webinar provided insight on the requirements of ISO 17065 :2012 Standard and the various existing product certification schemes. Around 220 participants attended this webinar including countries from Bhutan, Ghana, Pakistan, Oman, Kenya, Philippines, South Africa, Nepal, Tunisia, Jordan, Australia, Bangladesh etc. The speakers for the webinar were Mr. Anand Deep Gupta, Joint Director, and Ms. Varsha Misra, Deputy Director from NABCB.

4.9.5 Webinar on Food Safety Management Systems

NABCB conducted a webinar on March 28, 2025 on the Accreditation of Management Systems Certification Bodies, focusing on Food Safety Management Systems (FSMS). The session covered key insights into ISO/IEC 17021-1:2015 and ISO 22003-1:2022, highlighting the NABCB accreditation process, its criteria, and its significance in ensuring food safety and regulatory compliance. With 120+ participants including participants from Bangladesh, Bhutan, Ghana, Sri Lanka, UAE etc., attended the webinar. The session fostered meaningful discussions on certification processes and industry best practices. The speakers for the webinar were Mr. Anand Deep Gupta, Joint Director, and Ms. Varsha Misra, Deputy Director from NABCB.

4.9.6 Webinar on Regulations, Accreditation and Certifications in IT Sector

NABCB conducted a webinar on December 23, 2024 on Regulations, Accreditation and Certifications in IT Sector. The webinar provided brief overview about Best practices & compliances in Global IT scenario, Overview on the requirements of NABCB Accreditation Criteria, Procedure for Information Security and Information Technology Services Management Systems schemes and its Benefits and IT/Cyber Laws Ecosystem in India and Way Forward. The speakers for the webinars were Mr. Srinivas Kaza, NABCB Expert and Mr. Ajay Sharma, Joint Director (NABCB). The webinar was attended by around 50 participants.

4.9.7 Webinar on NABCB Accreditation for Personnel Certification Bodies, with an overview of ISO/IEC 17024:2012

NABCB organized a webinar on January 31, 2025 with an objective to increase the awareness programs on accreditation standards, NABCB recently organized an insightful webinar on "NABCB Accreditation for Personnel Certification Bodies: An Overview of ISO/IEC 17024 and its Significance Across Various Sectors." The session provided a comprehensive understanding of the ISO/IEC 17024 standard, covering the accreditation process, key clauses, certification schemes, essential requirements, and the benefits it offers to certification bodies, industries, and regulatory authorities. NABCB received an overwhelming response and approx. 150 participants attended, including from countries like Oman, UAE, Bhutan, Kenya, Sri Lanka, Afghanistan, Japan, Iran etc. The speakers for the webinar were Mr Ajay Sharma, Joint Director and Ms. Varsha Misra, Deputy Director from NABCB.



5 NATIONAL BOARD FOR QUALITY PROMOTION (NBQP)

The National Board for Quality Promotion (NBQP) is a constituent Board of the Quality Council of India (QCI), entrusted with the mission of embedding Quality as a core value across sectors and society. Guided by the overarching vision of "Quality for National Wellbeing," NBQP plays a catalytic role in advancing the adoption of Quality management systems, tools, and frameworks across high-impact sectors such as Education, Healthcare, and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) - widely recognized as the pillars of India's inclusive growth and development.

At its core, NBQP aims to foster a culture of continuous improvement, enhance productivity and competitiveness, and strengthen governance systems through the lens of Quality. Its interventions not only help institutions streamline internal processes but also cultivate a mindset of excellence and responsibility among citizens and service providers alike.

A distinctive element of NBQP's approach is its emphasis on citizen empowerment. Through a series of targeted awareness programs, campaigns, and capacity-building initiatives, the board encourages individuals to become informed and quality-conscious consumers. This demand-driven strategy creates a ripple effect - where consumer expectations push producers, service providers, and institutions to elevate their standards - making Quality a shared national aspiration rather than a regulatory obligation.

To fulfil this mission, NBQP drives a wide array of outreach, engagement, and educational initiatives across the country. Flagship programs like Gunvatta Sankalp, Gunvatta Yatra, Gunvatta Manthan, and Gunvatta Samruddhi serve as dynamic platforms that bring together policymakers, industry experts, youth, and civil society to discuss and co-create pathways for Quality transformation. Youth-centric campaigns such as the Quality Summer Funcamp and Gunvatta Pakhwada are designed to instil Quality values early, ensuring that the next generation is equipped to uphold and demand high standards. Apart from these initiatives, NBQP also assists QCI's Boards and Divisions in organising their flagship events, offering strategic and operational support to amplify the reach and impact of Quality across diverse domains.

NBQP also plays a strategic advisory role in collaborating with central ministries, state governments, and public sector undertakings (PSUs) for the implementation of ISO standards, performance excellence frameworks, and customized Quality interventions. From process improvement and capacity assessment to handholding, NBQP contributes significantly to enhancing institutional efficiency and service delivery mechanisms. Further, the board actively supports award mechanisms and recognition frameworks that honour exemplary efforts in Quality implementation. These awards motivate organizations to adopt best practices, benchmark globally, and create a culture of aspiration and excellence.

In essence, NBQP is not just a facilitator but a force multiplier for India's Quality movement - building awareness, driving adoption, enabling innovation, and ultimately contributing to the nation's journey towards Viksit Bharat @2047. Through its integrated efforts, NBQP continues to redefine what Quality means for governance, industry, and society - making it a cornerstone of national wellbeing.

5.1 ONLINE QUALITY SUMMER FUNCAMP

The Quality Council of India (QCI) successfully concluded the second edition of its annual Online Quality Summer Funcamp—an initiative aimed at fostering the principles of quality among the next generation of decision-makers. The core mission of this event is to introduce and instill the value of quality in children from a young age, covering crucial aspects such as food, healthcare, education, habitat, environmental care, toys, and sustainability. By emphasising these concepts early, QCI aims to enhance the standard of living and develop a quality-oriented mindset among India's youth.

Competitions were open to students from Kindergarten to Grade 12, demonstrating that the pursuit of quality knows no age. This year's theme "Safety Stars: Shining Bright with Quality," encouraged participants to reflect on the importance of safety and quality across various sectors.

The Online Quality Summer Funcamp, held online, featured a variety of competitions designed to engage students in a fun and educational way. These included:

– Essay/Article Writing
– Drawing Competition
– Quality Quiz Competition
– Short Video-Making Competition

The grand finale of this exciting journey was marked by the Award Ceremony held virtually on September 6, 2024. The event, attended by students, parents, and esteemed guests, celebrated the young winners. The winners were announced through a special video presentation in the presence of Shri Sanjay Kumar, IAS, Secretary at the Department of School Education & Literacy (SE&L), Ministry of Education, Government of India and Dr. Lalit Gabhane (DG, NSC); Shri Chakravarthy T. Kannan (SG, QCI); Shri Vipin Sondhi (Chairperson, NBQP); Smt. Hemgauri Bhandari (Chief Advisor, QCI), and Dr. A. Raj (CEO, NBQP). The ceremony also saw the participation of key speakers - Dr. Om Prakash. Mission Director, Samagra Shiksha, Assam; Mr. Rupesh Mathur, Joint Secretary, Vivekananda Kendra Vidyalaya, AP; Dr. Arun Kumar, In Charge, District Education, Quality Cell, DoE, Govt. of Rajasthan; Mrs Meena Manhas, Hindi Mistress (School Incharge), Government Middle School, Hoshiarpur, Punjab. Their collective presence highlighted the importance of the event and QCI's dedication to nurturing a quality-conscious future generation.

The Online Quality Summer Funcamp 2024 proved to be a remarkable platform for children to showcase their talents, creativity, and understanding of quality in a fun and engaging manner. It served as a reminder that the seeds of quality, when planted early, can grow into lifelong values that contribute meaningfully to society.

States:

13000+ Entries

Top 3 entries state-wise: Haryana (2915), Delhi (1750) and Punjab (1166) - Special mentions: Andaman and Nicobar Islands (3)

Top 3 winners state-wise: West Bengal (27), Haryana (25), Chandigarh (16), Delhi (14) and Arunachal Pradesh (12)

Total 153 winners: Girls (98) and Boys (55) [Winner comprises 64% girls and 36% boys]

In this edition, the Ministry of Education supported us by issuing a circular to its respective departments to promote the 2nd Online Quality Summer Funcamp. Additionally, several states, including Assam, Punjab, Haryana, Odisha, Goa, Rajasthan, Madhya Pradesh, Nagaland, and Mizoram, extended their support by issuing circulars within their jurisdictions.



NBQP organised Online Award Ceremony for the 2nd Edition of Quality Summer FunCamp. The virtual award ceremony was graced by Shri Sanjay Kumar, Secretary, Dept. SE&L, Ministry of Education, GoI, with a keynote by Dr. Lalit R. Gabhane, DG, National Safety Council on September 6, 2024.

5.2 QUALITY AWARENESS WORKSHOP

The Quality Awareness Workshop which is designed to be both engaging and informative for students. The workshop aims to instill a sense of responsibility and awareness in young learners on topics such as hygiene, environmental protection, problem-solving skills, tools/techniques, the basics of quality, safety, empathy, and other essential subjects. So far, 57 workshops have been conducted in NDMC schools, non-aided primary schools, and other govt. /pvt. Schools.



NBQP organized Quality Awareness Workshops in collaboration with the Children's Book Trust (CBT). These workshops were held every Saturday in June at New Delhi.



NBQP conducted various workshops in NDMC schools, non-aided primary schools, and other government schools in Delhi-NCR during April-May, 2024.



5.3 QUALITY SETU

Quality Setu, a flagship initiative by NBQP, aims to become a comprehensive and up-to-date platform for all queries related to Quality in India.

To ensure seamless interaction between QCI's Boards & Divisions and their users, NBQP has introduced Quality Setu—a centralized information and enquiry system. It enhances user experience by serving as a one-stop platform for accessing and tracking information across all QCI initiatives.

According to Office Order QCI/Order/2024/476 dated August 16, 2024, the Quality Setu app and website have been transferred to the IT Cell, and the knowledge transfer process has been completed.

5.4 GUJARAT GUNVATTA SANKALP

The Gujarat Gunvatta Sankalp was a remarkable success, showcasing a stellar lineup of 43 speakers and moderators from the Government of Gujarat and various Boards & Divisions of Quality Council of India (QCI).

Hon'ble Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, inaugurated the Gujarat Gunvatta Sankalp, reaffirming the state's commitment to embedding Quality as a cornerstone of development. Highlighting Prime Minister Narendra Modi's vision, he emphasized that Gujarat is accelerating its progress under the 5G model and proposed adding 'Gunvatta' (Quality) as a new dimension. He expressed confidence in achieving 100% success in making Quality a key driver of Viksit Gujarat and Viksit Bharat.

Covering diverse sectors such as Education and Skilling, Healthcare, MSME and e-commerce, Tourism and Culture, and overall Quality of Life, the event addressed critical themes including citizen empowerment, healthcare advancements, economic growth, and e-commerce transformation. With participation from over 600 distinguished representatives from prominent organizations, the event received widespread acclaim for its well-organized structure, relevant content, and efficient scheduling.











Gujarat Gunvatta Sankalp

July 11, 2024 | Ahmedabad

Inaugurated by Shri Bhupendra Patel, Hon'ble Chief Minister of Gujarat, with Shri S. J. Haider (IAS), Additional Chief Secretary; Shri S. S. Rathore, Advisor to the Hon'ble CM Gujarat; Shri Jaxay Shah, Chairperson, QCI; Shri Chakravarthy T. Kannan, Secretary General, QCI; and Smt. Hemgauri Bhandari, Chief Advisor, QCI

5.5 NAGALAND GUNVATTA SANKALP

The Nagaland Gunvatta Sankalp was a resounding success, showcasing an impressive lineup of 23 speakers and moderators from Govt. of Nagaland and QCI Boards & Divisions.

Gunvatta Sankalp Nagaland witnessed the esteemed presence of Shri Temjen Imna Along, Minister of Tourism and Higher Education; Dr. J. Alam (IAS), Chief Secretary; Shri Kesonyu Yhome (IAS), Secretary to the Chief Minister; and Shri Jaxay Shah, Chairperson, QCI. In his keynote address, the Hon'ble Minister emphasized, "The people of Nagaland can serve as a beacon of Quality for the nation. The pursuit of Excellence and Quality is at the heart of our progress." The event provided a vital platform for discussions with AHODs/HoDs on enhancing Quality in key sectors such as Healthcare, Education & Skilling, MSMEs, Tourism & Culture, Transport, and Public Health & Engineering, reinforcing Nagaland's commitment to the vision of Viksit Bharat 2047 through Quality-led development.

The event attracted over 125+ participants from esteemed organizations including various departments of Govt. of Nagaland, who engaged in insightful discussions and shared valuable perspectives. The initial feedback from attendees was positive, with high praise for the event carried out by Quality Council of India.

The diverse array of speakers and moderators brought a wealth of knowledge and experience to the table, fostering a collaborative environment where innovative ideas and best practices were exchanged. This collaborative spirit was instrumental in addressing the unique challenges and opportunities faced by Nagaland, ultimately contributing to the region's development and growth.

Overall, the Nagaland Gunvatta Sankalp not only highlighted the importance of Quality in various sectors but also reinforced the commitment of stakeholders to drive excellence and continuous improvement in the region.



Nagaland Gunvatta Sankalp, February 27, 2025 Kohima, Nagaland



Event inaugurated by Shri Temjen Imna Along, Minister of Tourism and Higher Education, Govt. of Nagaland



Shri Jaxay Shah, Chairperson, QCI



Shri Kesonyu Yhome (IAS), Commissioner & Secretary to the Hon'ble Chief Minister



Dr. J. Alam (IAS), Chief Secretary, Govt. of Nagaland



Shri Chakravarthy T. Kannan, Secretary General, QCI



Smt. Hemgauri Bhandari, Chief Advisor, QCI



5.6 FOLLOW-UP FROM PREVIOUS GUNVATTA SANKALP

In continuation of our efforts to engage with States/UTs following the Gunvatta Sankalp initiative, the National Board for Quality Promotion (NBQP) engaged with the Government of Assam regarding the recommendations submitted to the Chief Secretary of Assam after the Assam Gunvatta Sankalp. NBQP team conducted in-person meetings in Assam and subsequently facilitated multiple online meetings between relevant officials of the Government of Assam and senior management team members from the concerned Boards/ Divisions of QCI. These discussions focused on the following areas:

1. Manufacturing & Services
2. Education & Skilling, and 3. Tourism

5.7 QUALITY BHARAT PLEDGE

The Quality Bharat pledge aims to adopt quality practices and contribute to building a developed India. This commitment is encapsulated in the Hindi phrase "गुणवत्ता अपनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे," which translates to "We will adopt quality, we will make a developed India." The pledge emphasizes the following key intentions:

- Dedication to Quality
- Driving National Development
- Raising Awareness and Taking Action
- Collective Responsibility

The Quality Bharat Pledge was officially launched on August 29, 2024, on QCI's website. To expand its reach, a successful collaboration with "MyGov" was established. So far, over 29,000+ individuals have taken the Quality Bharat Pledge on MyGov page.



5.8 STATE LIAISON

NBQP has been actively fostering partnerships and exploring opportunities across India by engaging with State Governments through their nodal offices in Delhi, including Resident Commissioners and Additional Resident Commissioners.

NBQP has established meaningful connections with the Resident Commissioners of Mizoram, Sikkim, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, and Nagaland, laying the foundation for strategic collaboration and growth with these States/UTs. Additionally, the Board has initiated communication with various ministries and State Governments to explore avenues for mutual support and to advance Quality initiatives across the country.



Meeting with Shri Anurag Jain, Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh







5.9 SANJIVANI

The SANJIVANI initiative is poised to revitalize dying art forms. With a well-developed concept and pitch deck, a dedicated internal committee has been assembled, including members from esteemed organizations such as the Indira Gandhi National Centre for Arts, National Museum, All India Association for Craftsmen and Artisans, Textile Sector Skill Council, Weavers Service Centre, and others. Initial meetings with committee members and the CEO of NBQP have been productive, paving the way for drafting terms of reference and officially onboarding committee members.

SANJIVANI is making significant strides. The committee has successfully onboarded members from esteemed organizations and conducted its inaugural meeting along with several rounds of discussions. These meetings have generated valuable suggestions for both tangible and intangible art forms. “Nautanki” has been chosen for pilot studies, and field research and visits are actively underway to evaluate this art form. These efforts reflect steady progress towards SANJIVANI’s goal of revitalizing India’s dying art forms through collaboration and innovation.

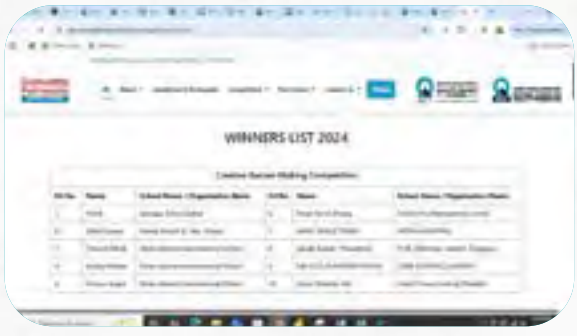




SANJIVANI – an initiative under the Quality Bharat Mission:

1st Empowered Committee meeting with Members





5.10 GUNVATTA PAKHWADA

With the theme 'Gunvatta se Sashakt Bharat, Viksit Bharat' (गुणवत्ता से सशक्त भारत, विकसित भारत) the National Board of Quality Promotion (NBQP) is proud to announce Gunvatta Pakhwada from November 14 to 28 every year. This two-week initiative is designed to promote a deeper understanding of the significance of quality in various aspects of life, from personal practices to organizational standards. By encouraging a culture of quality, we aim to build a stronger and more efficient nation that upholds the highest benchmarks of excellence across industries and sectors.

As a part of this initiative, we are hosting a series of exciting competitions to engage individuals and organisations. Below are the competitions:

- Creative Banner Making Competition
- Showcasing Quality Improvement Initiatives
- Quality Quiz Competition
- Celebrating Quality Culture within Organisations

The Board launched a web portal for online competitions during the 15-day event in November 2024. We received 1,201 entries, which was higher than the previous year. The winners of Gunvatta Pakhwada have been announced.

5.11 QUALITY TIMES

Quality Times is a quarterly video capsule, between 5-7 minutes, aimed to reach out to the masses and relevant stakeholders, with the message of Quality. The segments broadly cover trivia on Quality, a Quality Newsmaker and Spotlight. So far 5 editions have been released and the 5th edition covered Smt. Pabiben Rabari, Founder, Pabi Designs Pvt. Ltd., which was launched on July 11, during the Gujarat Gunvatta Sankalp held in Ahmedabad, Gujarat.

The team also worked on design tasks for various boards and divisions, ensuring all visual contents align with our Quality standards.

The team also managed the social media presence of QCI, its boards, and divisions, effectively engaging with a diverse audience and promoting the message of Quality.



Newsmaker Shoot: Featuring Manu Bhaker (Olympic Medalist) and Mr. Kalikesh Narayan Singh Deo (President, National Rifle Association of India) for Quality Times Episode 6

5.12 QUALITY BHARAT CELL

The National Board for Quality Promotion (NBQP) has launched the Quality Bharat Cell (QBC), a pioneering initiative designed to cultivate a culture of Quality among students and educators and empower them with quality tools/techniques, foster community engagement, and nurture empathy. The QBC seeks to build capacity and enhance understanding of key quality principles through trainings, systematic pre and post-assessments across the nation. This initiative supports the vision of Viksit Bharat 2047, empowering the next generation to lead with excellence.

An implementing agency was onboarded to aid in the conceptualization of modules and program implementation.

In its pilot phase, QBC is being implemented in five schools within the North and West region: DAV Public School (Sahibabad, UP), Hindu Kanya Vidyalaya (Sonipat, Haryana), Adinath Public School (Alwar, Rajasthan), The Mann School (West Delhi), and Air Force School (Jammu).

A total of 480 students and educators are being trained as future Quality Ambassadors who will actively promote and disseminate Quality principles and Quality tools and techniques among their peers to foster continuous improvement.

The Quality Bharat Cell (QBC) Phase 1 at Air Force School, Jammu, concluded with a powerful closing ceremony on April 2, 2025- marking a key milestone in the students' journey toward a quality-driven mindset.

The ceremony was graced by esteemed leaders including Mr. Vipin Sondhi (Chairperson, NBQP-QCI), Dr. A. Raj (CEO, NBQP-QCI), Air Commodore Sagar Singh Rawat VM (Chairman), Mrs. Shuchi Gupta (Principal), and Mr. Raman Arora (Headmaster).

Mr. Sondhi shared a compelling story on how quality isn't just a concept—it's a way of life. Students echoed this spirit, sharing how QBC shifted their view of quality from "just products" to "everyday actions." From applying 5S at home to using PDCA to manage exam stress—their stories were inspiring and real. Dr. Raj elucidated the importance of systems and processes even in our daily lives.



Launch of First 'Quality Bharat Cell' at DAV Public School, Sahibabad

January 22, 2025, Sahibabad, Uttar Pradesh



Launch of 'Quality Bharat Cell' at The Mann School, Delhi

February 3, 2025, New Delhi



Launch of Third 'Quality Bharat Cell' at Adinath Public School

February 10, 2025, Alwar, Rajasthan



Launch of Fourth 'Quality Bharat Cell' at Hindu Kanya Sr. Sec. School

February 19, 2025, Sonipat, Haryana



Launch of Fifth 'Quality Bharat Cell' at Air Force School

March 17, 2025, Jammu, J&K

5.13 GUNVATTA MANTHAN

Gunvatta Manthan is a strategic initiative by QCI aimed at gathering feedback from stakeholders and fostering a culture of Quality through collaboration and actionable solutions. By leveraging stakeholder expertise and customer advocacy, the initiative seeks to drive continuous improvement across various sectors.

Providing a dedicated platform for stakeholders to share insights and adopt best practices, QCI uses this collective knowledge to enhance strategic planning, advance Quality initiatives, and promote excellence. Through these concerted efforts, Gunvatta Manthan aims to raise industry standards, strengthen Quality practices, and improve overall outcomes.

The first Manthan for NDIE was held on February 13, 2025. As of March 31, 2025, we have completed four Gunvatta Manthans for PAD Division (New Delhi), NABCB (New Delhi), NABH (New Delhi), and NDIE (Chennai). We plan to engage more stakeholders and foster deeper collaboration in the upcoming financial year as well.







5.14 GUNVATTA SAMRIDDHI

Gunvatta Samriddhi is an industry connect initiative designed to enhance business excellence and global competitiveness by leveraging QCI's expertise and resources. The primary aim of Samriddhi is to strengthen Indian quality standards, reduce certification burdens, and create export opportunities, thereby fostering a robust and globally competitive ecosystem. Through targeted interventions such as certification support, quality enhancement programs, and industry collaborations, Samriddhi seeks to bridge the gap between MSMEs and larger enterprises while promoting adherence to internationally recognized quality standards

Sectors Selected

- Electronics
- White Goods
- Pharmaceuticals

Contact Established with 4 Industries

1. **Haier:** Meeting with Haier and QCI leadership was held on February 20, 2025.

a) Initial Meeting Discussion Include:

- **NABL:** The discussion focused on the international acceptance of NABL's services, the importance of awareness programs for Haier's supply chain

vendors, and strategies to encourage vendor participation in Quality initiatives.

- **NDIE:** The discussion focused on introducing the ZED (Zero Defect Zero Effect) and MCLS (MSME Competitiveness Lean Scheme) Certifications, exploring potential synergies between Haier and its supply chain, and identifying ways to enhance Quality standards in Haier's vendor ecosystem.
- **NABCB:** The discussion focused on Haier's requirements for certification, industry challenges in standard adherence, and the need for a streamlined and cost-effective standardization process. NABCB proposed a pilot project to map Haier's ecosystem and guide vendors toward relevant certifications.

b) Follow-up meeting and workshop will be conducted on April 16, 2025, at Haier Plant, Noida.

c) Further collaboration and engagement with Haier to be structured based on discussions.

5.15 GUNVATTA YATRA

The Gunvatta Yatra is an initiative that began with a focus on improving healthcare Quality and is now expanding to enhance manufacturing Quality. It promotes NABH, NABCB, and NDIE standards among Small & Large Healthcare Organizations (HCOs), manufacturing associations, and units, particularly in Tier-2, and Tier-3 cities. Through targeted capacity-building workshops and robust support systems, the Yatra aims to equip professionals with the knowledge and tools needed to achieve these critical standards. By elevating healthcare and manufacturing practices and fostering accessibility, the Yatra reaffirms QCI's commitment to driving excellence in underserved regions.

As of March 31, 2025, we have completed 48 Gunvatta Yatras across India to promote and raise awareness among relevant stakeholders about NABH, NABL, and NDIE accreditation and certification process and benefits.

Zone-wise and Board Overview – Gunvatta Yatra Completed

- North: Completed 10
- East: Completed 06
- South: Completed 18
- West: Completed 14

Number of Associations onboarded for Yatra: 30+

- IMA – Gujarat (Ahmedabad & Bhavnagar), Kerala (Kochi), Haryana (Rewari), Telangana (Hyderabad), and Tamil Nadu (Coimbatore)
- AHPI
- IDA – Tamil Nadu, Karnataka, & Kerala
- FTCCI
- WACIA
- NI – MSME
- IamSMEofIndia
- Others



GUNVATTA YATRA – KOCHI, SOUTH EDITION



Bhavnagar, West Edition



Rewari, North Edition



Imphal, East Edition





5.16 EEPC INDIA QUALITY AWARD – 4TH EDITION

The EEPC India Quality Award, continued its journey of recognizing and celebrating excellence in Quality practices within the engineering industry, for which NBQP/ QCI provided the technical support. The award process comprised of four key stages: Document Assessment, Presentation Assessment, Onsite Assessment, and Jury presentation to the EEPC India senior leadership.

This rigorous evaluation ensured a comprehensive appraisal of contenders across various categories such as:

The cycle came to an end with the announcement of the awardees, who were honored during the 54th Export Awards National and Quality Awards Ceremony held in New Delhi on February 15, 2025

1. EEPC India Quality Award for Central JVs/ Govt./PSUs enterprise
2. EEPC India Quality Award for Large Enterprise
3. EEPC India Quality Award for Medium enterprise
4. EEPC India Quality Award for SME units

The awards were presented by Shri Jitin Prasada, Hon'ble Minister of State, Ministry of Commerce and Industry, Government of India; Shri Vimal Anand, Joint Secretary, Department of Commerce, Government of India; Shri Adhip Mitra, Executive Director & Secretary EEPC India; Shri Pankaj Chadha, Chairman, EEPC India; Shri Pradeep Kumar Aggarwal, Regional Chairman (North Region)

5.17 EEPC INDIA GREEN AWARD – 1ST EDITION

The EEPC India Green Award is a flagship initiative to recognizing and celebrating the sustainable practices within the engineering industry, for which NBQP/ QCI provided the technical support. The award process comprised of three key stages: Document Assessment, Onsite Assessment, and Jury presentation to EEPC India senior leadership.

This rigorous evaluation ensured a comprehensive appraisal of contenders across various categories such as:

1. EEPC India Green Award for Central JVs/ Govt./PSUs enterprise
2. EEPC India Green Award for Large Enterprise
3. EEPC India Green Award for Medium Enterprise
4. EEPC India Green Award for SME units

The cycle came to an end with the announcement of the awardees, who were honored during the XII IESS Inauguration and Green Award Ceremony held in Chennai on November 27, 2024.

The award was presented by Dr. Atul Anand (IAS), Principal Secretary, Dept. of MSME, Government of Tamil Nadu; Mr. Vimal Anand, (IRS), Joint Secretary, Department of Commerce, Government of India; Mr. Aakash

Shah, Vice Chairman (EEPC India); Mr. Pankaj Chadha, Chairman (EEPC India); Mr. Adhip Mitra, Executive Director (EEPC India).



5.18 NIDHI - NATIONAL INTEGRATED DATABASE OF HOSPITALITY INDUSTRY

QCI had developed NIDHI portal for the Ministry of Tourism which is an initiative towards Aatmanirbhar Bharat to use technology to empower Tourism businesses in India. It's a database that aspires to become a gateway to opportunities for the Tourism Industry. Registration with NIDHI ensures electronic delivery of various services and benefits to the tourism unit. It also serves as a platform for all the organizations of industry to ideate, share best practices and connect with the Government for ease of doing business.

QCI/ NBQP is assisting the Ministry in managing the portal, helping in IT Operations and providing helpdesk support for the queries of the stakeholders. This comprehensive system digitizes all processes, from registration to showcasing to onsite/remote assessments, utilizing mobile applications, and offering API integration with stakeholders. It is fully operational, with all Quality Certifications issued through this digital platform (https://nidhi.tourism.gov.in/)

5.19 ISO STANDARD IMPLEMENTATION IN GOVERNMENT DEPARTMENTS

QCI/ NBQP has been playing a pivotal role in supporting Ministries and Government Departments (both at the Central and State Level) across the country in the adoption and certification of ISO standards, ensuring the enhancement of quality management systems in various sectors. NBQP's efforts have been instrumental in improving governance, accountability, and operational efficiency within public institutions.

The implementation activities were carried out in phases through our empaneled Technical Expert. The various stages include:

Stage 1: Awareness Training

Stage 2: Gap Analysis

Stage 3: Documentation

Stage 4: Internal Auditor Training

Stage 5: Internal Audit and Management Review

a) ISO 9001:2015 Implementation Activities were completed in the Office of Mission Director, Samagra Shiksha Assam, Government of Assam

NBQP extended its support to the Office of the Mission Director, Samagra Shiksha Assam, in the implementation of the requirements of the ISO 9001:2015 Quality Management Systems standard and providing assistance in onboarding NABCB accredited Certification Body for conducting the Certification Audit. The Office of Mission Director, Samagra Shiksha Assam, was successful in achieving the Certification. This achievement reflects the state's dedication to fostering excellence in education management. The prestigious certification ceremony was attended by the Hon'ble Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, who received the certificate on behalf of the institution. This recognition not only highlights Assam's commitment to quality education but also serves as an inspiring example for other states in India to follow in strengthening their educational frameworks.







b) ISO 9001:2015 Implementation Activities are in progress at the National Institute of Design, Ahmedabad

NBQP has extended its support to the National Institute of Design, Ahmedabad, in the implementation of the requirements of the ISO 9001:2015 Quality Management Systems. The implementation related activities are in progress.







5.20 MITRA INITIATIVE

With an objective to build capacity within the healthcare system by promoting the adoption of NABH standards and facilitating the attainment of NABH Entry Level Certification (or accreditation) by Small Health Care Organizations (SHCOs), particularly in Tier-2 and Tier-3 cities as well as rural areas, NBQP has initiated a pilot project with Association of Healthcare Providers India (AHPI) in the State of Gujarat as part of the "MITRA" initiative (physical mode) that was announced at the National Patient Safety Conference by Chairperson, QCI. Two workshops have been conducted in Vadodara & Surat for uncertified/ unaccredited SHCOs of the nearby regions.



Gunvatta Yatra under the MITRA initiative:

Meeting with Ahmedabad Medical Association for discussing the collaboration for Gunvatta Yatra

Ahmedabad, Gujarat, October 24, 2024



Gunvatta Yatra under the MITRA initiative:

Meeting with Dr. Neeraj Lal, President, AHPI Gujarat and his Team

Ahmedabad, Gujarat, October 24, 2024





Gunvatta Yatra under the MITRA initiative:

Meeting with IMA - Gujarat State Branch Officials for discussing the collaboration for Gunvatta Yatra

Ahmedabad, Gujarat, November 20, 2024

5.21 EVENTS

QCI actively organizes events and QCI-Powered Sessions (QPS) to engage a broad spectrum of stakeholders, fostering deeper understanding and wider adoption of quality practices essential for thriving in a competitive global environment. In FY 2024-25, NBQP successfully conducted 28 notable events, including Gunvatta Sankalp, Gunvatta Gurukul Convocation & Anniversary, and NABH Patient Safety 2025. Additionally, NBQP coordinated 21 QCI-Powered Sessions in collaboration with various industry associations and bodies across India. These sessions significantly promoted schemes and activities of QCI's Boards and Divisions in diverse sectors such as Health, MSME, Food, Agriculture, Drones, and Textiles.



NBQP Assisted in organizing the 74th QCI GB Meeting, held on March 21, 2024 at Ambedkar Bhawan International Centre



Shri Jaxay Shah, Chairperson of QCI, addressing the students during IInd batch Convocation at Hindi Bhavan, New Delhi



IIIrd batch of Gunvatta Gurukul begins April 12, 2024



NABL's collaboration with PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI), aimed at enhancing quality standards in lab operations across industries



The students of III batch with Chief Guest, Shri Anurag Jain, Secretary, MoRTH and MoHUA, during their Convocation



IVth batch of Gunvatta Gurukul, joined from different corners of our nation



Chief Guest Shri Hemang Priyavadan Jani, Senior Advisor, World Bank while addressing the students at the convocation of the 4th batch of Gunvatta Gurukul



NBQP assisted Gunvatta Gurukul in organizing its VI Batch Orientation



Vth and the largest batch of Gunvatta Gurukul during their Orientation



Speaking at the anniversary celebration, QCI's Chairman, Shri Jaxay Shah, extended his heartfelt congratulations to the Gunvatta Gurukul team for their remarkable achievements over the past year



NABH's Patient Safety Day, supported by NBQP, emphasizes secure health infrastructure and introduces twelve new standards, honoring healthcare professionals



NBQP assisted NABH in organizing the Assessor's Training Program in Delhi-NCR on November 30, 2024



Felicitation of Chief Guest, Shri K. Srinivas, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, during the Convocation ceremony



Shri Jaxay Shah, Chairperson of QCI, and Shri Chakravarthy T Kannan, Secretary General of QCI performing Pooja for new Office—1QCI, Located at the iconic World Trade Centre, New Delhi



NBQP assisted NDIE in organizing the two-day workshop under DISHA, an initiative aimed at simplifying and strengthening ZED assessment models



Ms. Arpita Sen, Head HR, and Head Operations of Gunvatta Gurukul, led a captivating QCI-Powered Session, shedding light on the journey, process, and advantages of Gunvatta Gurukul



VI and VII Batchs during their convocation



Felicitation of Mr. C S Sharma, PADD-QCI during 4th Good Air Summit 2024.



NBQP Assisted in organizing 78th Governing Body Meeting of QCI in New Delhi



Mr. Rajesh Maheshwari, CEO-NABCB, delivered a keynote address during QCI Powered Session focusing on "Driving Growth through Digital Transformation"



Dr. Atul Mohan Kochhar, CEO, NABH-QCI, addressing on "Making Healthcare Efficient, Effective, Economical, and Equitable"



Dr. Aradhana Chopra, Director & Head of the MSME Lean Division at NABET, QCI, led a QCI-Powered Session on the transformative impact of the MCLS (Lean) Scheme



Mr Ajay Sharma, Joint Director NABCB, shared valuable insights on QCI's significant role in the fire and life safety domain at the QCI-powered session



QCI signed a Memorandum of Understanding to collaborate on skill development initiatives that support GIFT IFSC's talent ecosystem



Mr. Subroto Ghosh, PPID Head, took centerstage during the QCI-powered session "Empowering Talent and Embracing Global Excellence: Transforming Skills for Global Success"



NBQP assisted NABH for 'ISBTI's 49th National Conference.



Dr. Atul Mohan Kochhar, CEO NABH-QCI, and Mr. Pankaj Johri, Director NABL-QCI emphasized the importance of fostering a quality ecosystem in India



Shri C. Venugopal, Advisor, NBQP-QCI, delivered a Special Address as Guest of Honour at the QCI-powered Session on Natural Dyeing and Handloom Products



Representing NABH, Deputy Director Dr. Kumudita Talwar, introduced the Entry-Level Certification Program for Dental Clinics during the QCI-Powered Session



Dr Bhumi Rajyaguru speaking during the QCI-powered Session on NABL's contribution to the sector through accreditation and certification.



Dr. Bhumi, NABL-QCI, and Mr. Sameep, ZED Assessor, during the QCI-powered Session encouraged the MSMEs to embrace quality excellence through the NABL, ZED and Lean programmes



Dr. Mamoni Maity, Accreditation Officer, NABH-QCI, highlighted the NABH's pivotal role in driving healthcare quality and patient safety across India



Felicitation of Dr. Mamoni Maity, Accreditation Officer, NABH-QCI by the organisers of 1st AHPICON NE II



Dr. Manish Pande, Director & Head PADD-QCI, led QCI-powered Session on "Empowering Supply Chains via Conformity Assessment Frameworks" at India Sourcing Conclave 2025 by BAA India, focussing ESG compliance for all actors



PHDCCI felicitated QCI for being a valued partner in advancing innovation and strengthening India's quality ecosystem





Mr. Pankaj Johri, Director, NABL and Dr. Manish Pande, Director & Head PADD-QCI addressing during QCI-powered Session at Medical Fair India 2025



PPID
Project Planning &
Implementation Division

6 PROJECT PLANNING & IMPLEMENTATION DIVISION (PPID)

6.1 CIL, Faridabad

Central Insecticides Laboratory (CIL), Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage

- QCI was entrusted with the responsibility of conducting Third-Party Assessment of all four divisions (Chemistry, Bioassay, Medical Toxicology, & Processing & Packaging) of Central Insecticides Laboratory (CIL), Faridabad, with respect to available Infrastructure, Infrastructure required, Work discharged by CIL, and give suggestions to establish CIL as one of the best in present global scenario, and ways to prevent/control adulteration in Insecticides/Pesticides, etc.
- The evaluation done by QCI highlights the urgent need for significant enhancements in infrastructure, technological capabilities, and human resource capacity to enable CIL to operate at par with global standards. To transform CIL into a world-class centre for pesticide testing and research, a phased development strategy was recommended by QCI:
  - Phase I (0–2 Years): Immediate expansion of infrastructure and workforce
  - Phase II (3–5 Years): Integration of advanced technologies and capacity-building initiatives
  - Phase III (Beyond 5 Years): Implementation of strategic policies to achieve international accreditation and recognition



QCI team in discussion with CIL team to understand the status in terms of infrastructure, technological capabilities and human resources at CIL Faridabad in August 2024 under the project Central Insecticides Laboratory, Faridabad

6.2 Third-Party Evaluation of Scheme - I & II of National Horticulture Board

National Horticulture Board (NHB), Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare (MoAFW)

- QCI was entrusted to do Third-Party Evaluation of the NHB Scheme - I & II for the FY 2019-20 to 2022-23 for Phase-I and concurrent for FY 2023-24 as Phase-II for:
  - Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management of Horticulture Crops
  - Capital Investment Subsidy Scheme for Construction / Expansion / Modernization of Cold Storages and Storages for Horticulture Products.
- The Quality Council of India (QCI) conducted assessments of approximately 432 units in Phase I and 108 units in Phase II under the NHB scheme. Based on QCI's observations, the National Horticulture Board has undertaken several key initiatives to enhance the scheme's impact and accessibility:
  - Comprehensive Information Dissemination
  - Model DPRs and Training Resources
  - Strengthened Institutional Collaborations
  - Clean Planting Program
  - Promotion of Certifications



QCI team during evaluation of Grapes Farm in Osmanabad, Maharashtra, in September 2024 under the project Third-Party Evaluation of Scheme - I & II of National Horticulture Board

6.3 Impact Evaluation Study of Scheme for Creation of Infrastructure for Agro Processing Clusters (APC Scheme) under PMKSY of MoFPI

Ministry of Food Processing & Industries (MoFPI)

- APC Scheme of MoFPI aims to encourage entrepreneurs to set up food processing units based on cluster approach with modern infrastructure. Evaluation of APC Scheme has been done as per following output/ outcome indicators.
  - Physical and financial targets of the scheme
  - Reduction of wastage in terms of quantity and values
  - Gap Assessment & Capacity utilization of infrastructure being created
  - Impact on farmers (small, marginal & large) in terms of service & income
  - Employment Generation, etc.
- The evaluation has been completed, and the report has been submitted to MoFPIs APC



QCI team during evaluation of Shree Shyam Snacks APC, Hisar in Haryana, in August 2024 under the project Impact Evaluation Study of Scheme for Creation of Infrastructure for Agro Processing Clusters (APC Scheme)

6.4 Grading Government Grain Procurement Centers: Platform Development

FCI and Department of Food and Public Distribution

- In line with the resolution taken during the National Food Ministers and UTs Conference on July 5, 2023, a grading mechanism for over 44,000 grain procurement centers (PCs) was introduced. Developed by the Quality Council of India (QCI), this maturity model aims to improve transparency, efficiency, and overall quality management at the grassroots level of grain procurement operations.
- To drive this reform, QCI designed and implemented an innovative ICT-based initiative named Procurement Centre Self-Assessment Platform (PCSAP), that enables procurement centers to conduct self-assessments and determine their maturity levels. QCI also undertook extensive capacity-building efforts to ensure successful implementation across states.
- As of the Kharif Marketing Season 2024–25, over 42,217 procurement centers (94%) have registered on the PCSAP with more than 37,455 centers (89%) completing their self-assessments. This wide-scale adoption has significantly enhanced transparency and accountability in grain procurement operations, directly benefiting over 15 million farmers across the country.
- Real-time, data-driven dashboards at both state and national levels now empower policymakers with actionable insights, enabling more informed fiscal and policy decisions.

6.5 Verification of Paddy Mills & PCs in KMS 2024-25 for OSCSC

Odisha State Civil Suppies Corporation (OSCSC)

- The project aims to ensure compliance with OSCSC and KMS operational standards across 1,337 empaneled mills and procurement centers in Odisha by conducting a verification of mills and spot checks at procurement centers.
- As of March 2025, QCI has successfully assessed over 1,400 grain procurement centres, fostering greater confidence among farmers in the transparency and efficiency of procurement operations.
- In the upcoming month, QCI will commence stock verification and grading of the mills, ensuring accountability and compliance with procurement and storage standards.
- This initiative aims to strengthen Odisha's grain procurement and storage ecosystem, reinforcing trust in the public food distribution system while enhancing

efficiency across procurement centres and mills.



QCI & OSCSC teams conducting a pilot verification exercise at Payal Rice Mill in Puri, Odisha, in December 2024 under the project Verification of Paddy Mills & PCs in KMS 2024-25 for OSCSC



QCI team engaging in discussions with the Additional Civil Supply Officer and Mills In-charge in Puri, Odisha, to understand the milling processes adopted by the mills, while addressing key challenges related to efficiency, quality control, and process optimization under the project Verification of Paddy Mills & PCs in KMS 2024-25 for OSCSC

6.6 Pan-India Surveillance of Selected Edible Oil Products

Food Safety and Standards Authority of India

- The key objectives of the project are to assess the quality, safety, and labelling standards for the physio-chemical parameters of different packaged edible oils, in line with FSSR regulations, and evaluate regional compliance levels.
- The project successfully collected samples from across India, which were then tested in NABL-accredited and FSSAI-recognized laboratories.
- A comprehensive statistical analysis was conducted on the test reports, enabling the identification of adulteration hotspots and assessing the prevalence of mislabeling where applicable.
- As of March 2025, accredited bodies have been selected, and onboarding and training of all stakeholders has been conducted. A technology platform for survey has also been prepared and sample collection is underway.

6.7 Third-Party Inspection work of Electrical work under Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd

Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam (MVVNL)

- The objective of the project is to conduct a third-party inspection of electrical works carried out in 2023-24 and 2024-25 under Business Plan, System Augmentation/ Strengthening work in different districts, under Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam (MVVNL) as Discom Quality Monitoring Agency (DQMA). It also includes conducting joint inspection with the Discom officials for final measurement and quality control.
- QCI is successfully undertaking inspections at more than 600 locations in zones like Bareilly, Raebareilley, Ayodhya, Lucknow and Unnao etc.



QCI team conducting third-party assessment of 33kV Vacuum Circuit Breaker & Current Transformer installation in March 2025 under the project Third-Party Inspection work of Electrical work under Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd

6.8 Third-Party Quality Monitoring Agency (TPQMA) for redevelopment of West Ansari Nagar AIIMS

National Building Construction Corporation (NBCC) India Limited

- The objective of this project is to monitor, assess, and verify compliance with project specifications, standards, and regulations to

ensure successful, timely, and high-quality completion of the redevelopment.

- Additionally, the TPQMA will identify any implementation gaps and provide recommendations for improvements, ensuring continuous monitoring and the potential for expansion to meet evolving project needs.
- Inspection of redevelopment work at West Ansari Nagar AIIMS under Package-I/Part-I, New Delhi is in progress.



QCI team conducting the quality assurance and monitoring of steel reinforcement at site in March 2024 under the project Third-Party Quality Monitoring Agency (TPQMA) for redevelopment of West Ansari Nagar AIIMS

6.9 Third-Party Inspection of works other than Jal Jeevan Mission executed by PHED Haryana

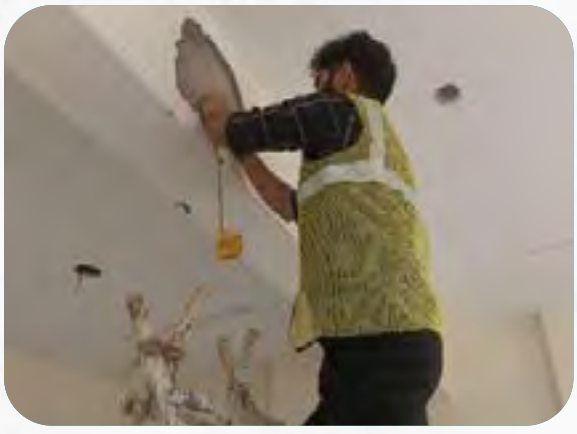
Public Health Engineering Department, Government of Haryana

- QCI was entrusted to conduct Third-Party Inspection of works other than JJM executed by PHED (Public Health Engineering Department) in the state of Haryana.
- As of March 2025, QCI has conducted site inspections of 8 out of 13 schemes alloted. And a detailed inspection report including the findings at site has been submitted to the client.

6.10 Structural Stability Analysis for UPPCL Ghaziabad

U.P. Projects Corporation Limited

- QCI was entrusted to conduct a special technical investigation of the Government Inter College Mussoorie, Ghaziabad, which included structural stability analysis and perform non-destructive test of the existing structures at site.
- QCI conducted non-destructive test and collected sample for structural analysis for further technical investigation. And a detailed inspection report, including the findings at site, has been submitted to the client.



QCI team conducting NDT (non-destructive) tests at the site in November 2024 under the project Structural Stability Analysis for UPPCL Ghaziabad

6.11 Third-Party Evaluation of Schemes Implemented by Ministry of Labour & Employment

Ministry of Labor and Employment

- The objective of this project is to evaluate the impact of three schemes implemented by the Ministry of Labour and Employment—e-Shram, National Career Service (NCS), and National Career Service Centres for SC/ST (NCSC-SC/ST)—on their targeted beneficiaries, sectors, and regions. The assessment includes an output-outcome analysis and an examination of implementation gaps by reviewing their alignment with the intended scheme design. Additionally, QCI will provide recommendations to enhance implementation efficiency, ensure the continuation of these schemes, and explore their potential expansion to effectively cover additional sectors.
- A total of 6,323 responses were collected across India to assess the impact of three central schemes implemented by the Ministry of Labour and Employment-e-Shram, NCS, and NCSC-SC/ST. The responses were distributed as follows:

3,661 for e-Shram, 2,215 for NCS, and 447 for NCSC-SC/ST.

- The assessment process for all three schemes has been successfully completed, and a detailed analysis has been done to evaluate their effectiveness, impact on beneficiaries, and alignment with the intended objectives.



The QCI project team conducting the impact assessment of the Karkardooma NIELIT Centre in February 2025 under the National Career Service Centre (NCSC) for SC/ ST under the project Third Party Evaluation of Schemes Implemented by Ministry of Labour & Employment



The project team conducted the impact assessment of Mangaldoi, Assam Centre in February 2025 under the National Career Service Centre under the project Third Party Evaluation of Schemes Implemented by Ministry of Labour & Employment

6.12 Third Party Sampling, Testing & Analysis of Coal at mine end of NLC Talabira

NLC India Limited (NLCIL), Talabira

- NLC has nominated Quality Council of India (QCI) for quality analysis of coal at their mine end. The objective of this project is to provide coal consumers with quality assessment of the coal received at their unloading– end.
- As of March 2025, a total of 3.83 MMT of coal has been sampled since the inception.

6.13 Quality Analysis of coal at plants ends of GSECL

Gujarat State Electricity Corporation Limited

- GSECL has nominated Quality Council of India (QCI) for quality analysis of coal at their plants end. This initiative makes a concerted effort to enhance the fundamental procedures for ensuring the quality of the coal received by the consumer.
- As of March 2025, a total volume of over 9.54 MMT of Coal has been sampled since the inception.



Quality Council of India team conducting auger sampling of coal at the plant end of Gujarat State Electricity Corporation Limited (GSECL) in February 2025 via rail mode

6.14 Third Party Sampling, Testing & Analysis of Coal at the loading ends of SCCL

Singareni Collieries Company Limited (SCCL)

- Singareni Collieries Company Limited (SCCL) has nominated Quality Council of India (QCI) for quality analysis of coal at their loading end. This project strives hard towards improving underlying processes for ensuring quality in the coal ecosystem.
- As of March 2025, a total volume of over 5.36 MMT has been sampled since inception of the project.



Quality Council of India team carrying out coal sample preparation at Singareni Collieries Company Limited (SCCL) in March 2025

6.15 Bi-Party Sampling, Testing & Analysis of Coal at plant-end of AVBTPS

Chhattisgarh State Power Generation Company Limited

- QCI has won this project in the competitive bidding for quality analysis of coal at the mine-end of ABVTPS.
- As of March 25, a total volume of 2.03 MMT of coal has been sampled since the incpetion of the project.



QCI team conducting coal sample collection at the plant-end of AVBTPS via rail mode in March 2025

6.16 Swachh Survekshan Gujarat Urban 2024

Urban Development and Urban Housing Department, Gujarat

- The assignment aims to comprehensively assess and monitor the cleanliness and sanitation standards of cities participating in Swachh Survekshan 2024 through a structured work plan. This includes field visits, data collection, and independent verification of Service-Level Progress indicators. Cities will be ranked based on aggregated scores, with detailed reports, presentations, and documentation of best practices.
- QCI will conduct quarterly assessments, share rankings with State Mission Directors, and provide gap analyses to drive continuous improvement. Additionally, QCI will ensure high-quality documentation, including certificates for awardee cities, enhancing the transparency and success of Swachh Survekshan 2024.
- As of March 2025, the project has engaged 80,000 citizens in cleanliness assessment process, resulting in higher level of public awareness and participation. The development of Data Collection Application and Assessment Portals has streamlined field operations, leading to reduction in data processing time and more accurate reporting. The SMD and Zonal Portals have facilitated more effective review and decision-making processes, improving response times on cleanliness and sanitation issues.



Swachh Survekshan Gujarat 2024 team after successful completion of first-phase assessment in October 2024

6.17 Swachh Survekshan Gujarat Rural 2024

Commissionerate of Rural Development, Gujarat

- QCI is conducting sanitation assessments of 1,000 villages in two phases in the state of Gujarat in accordance with the Jal Shakti Ministry Swachh Survekshan toolkit. The evaluation consists of on-site verification of various sanitation-related aspects.
- As of March 2025, deployment of PMU Team, Capacity Building and Questionnaire development for the assessment has been completed. Field Assessment of 526 villages under SBM and houses built under PMAY has been concluded. Capacity building via District coordinators for various schemes has also been undertaken. IT Portal has been deployed and capacity building via District coordinators for various schemes is being conducted.

6.18 Jal Hi Amrit

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation/ Ministry of Housing and Urban Affairs

- QCI is conducting assessments of STP across the country on the parameters defined by MoHUA under 'Jal hi Amrit' Initiative.
- Till March 2025, field assessment of 848

STPs for the 1st and 2nd phase of the project has been completed. The Jal Hi Amrit initiative led to significant improvements in the country's wastewater management system, including:

- Enhanced functionality and operational efficiency of STPs.
- Improved quality of treated water, making it more suitable for reuse.
- A boost in sustainable water management, encouraging cities and states to adopt best practices.

- By fostering accountability and incentivizing performance, QCI's role in the Jal Hi Amrit initiative has contributed to a more efficient and sustainable wastewater treatment ecosystem in India.



Water sample is being collected by QCI team from STP in Rishikesh in January 2025 for testing against stipulated parameters, ensuring quality assessment and compliance under the project Jal Hi Amrit



In-house Training of Trainers (ToT) session for the Jal Hi Amrit team conducted by QCI in October 2024

6.19 National e-Governance Service Delivery Assessment - Way Forward (NeSDA WF) PMU

Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG)

- National e-Governance Service Delivery Assessment (NeSDA) biennially assesses and benchmarks State/UTs and Central Government on the depth and effectiveness of e-governance service delivery. The NeSDA Way Forward PMU assists DARPG to monitor and evaluate the implementation of recommendations given in the NeSDA 2021 report, along with assisting in other initiatives like National e-Governance Webinar Series, meetings with RTS Commissioners of States etc.

- The NeSDA Way Forward PMU undertook following key tasks during the year:
  - Published monthly reports dedicated to strengthening e-service delivery with special emphasis on saturation of mandatory e-services and unified service delivery portals
  - Over 20,250 e-services were being provided across states/UTs in February 2025 as compared to 11,614 e-services in April 2023 (a 74% rise)
  - Over 78% saturation of identified mandatory e-Services was achieved in February 2025 as compared to 66% in April 2023
  - Facilitated 10 National e-Governance Webinars (NeGW), showcasing award-winning initiatives, with participation from over 1000 officials
  - In alignment with assessment parameters in NeSDA framework, facilitated key events like Workshop on Cyber Security, that focused on enhancing cyber security awareness and promoting MeitY's initiative during the Special Campaign 4.0
  - Facilitated meetings with AR/IT Secretaries of States/UTs, RTS Commissioners of States, and focus Meetings with Northeastern States

6.20 Future Ready TCGL

Tourism Corporation of Gujarat Limited

- TCGL has engaged QCI to undertake a comprehensive organizational restructuring. The primary objectives are to evaluate TCGL's current organizational framework, identify gaps, and propose a future-ready structure. This includes benchmarking against similar

organizations, streamlining manpower allocation, and recommending strategies for improved operational efficiency and stakeholder management.

- The project aimed at assessing and optimizing the organizational structure of TCGL, which has been successfully completed. As a part of the engagement, a comprehensive report and presentation detailing the proposed organizational structure, remuneration framework, grading and benchmarking analysis were submitted to the client.
- The final recommendations were designed to enhance efficiency, manpower utilization, and future readiness of TCGL by aligning its structure with industry best practices and government benchmarks. Additionally, a presentation has been prepared for the Hon'ble Chief Minister, summarizing the key findings and proposed reforms.



PPID team with TCGL team, including GM Finance, following the completion of one-on-one interviews with the entire TCGL staff in November 2024 under the project Future Ready TCGL

6.21 Impact Assessment of Gram Panchayats under Atal Bhujal Yojana

Ministry of Jal Shakti

- QCI collaborated as a third-party inspection body with the National Program Management Unit under the Ministry of Jal Shakti for a detailed evaluation of the scheme's effectiveness in addressing groundwater management challenges and achieving its intended outcomes. The project aims to evaluate the impact of the Atal Bhujal Yojana by assessing the awareness among local communities regarding water-efficient practices, community participation, and behavioral changes in groundwater management, as well as examining the adoption of sustainable water practices across seven states.
- The following objectives have been achieved as a part of QCI's assessment
  - Assessed key output and outcome indicators, measuring its success in achieving physical and financial targets, and analysed its overall implementation effectiveness at the grassroots level.
  - Evaluated the role of local institutions, stakeholder engagement, and the extent to which communities have embraced sustainable groundwater usage.
  - Measured the Effectiveness of Program Interventions such as participatory water budgeting, demand-side management, and institutional strengthening in ensuring long-term sustainability.
  - Identified best practices and success stories from high-performing Gram Panchayats



Engagement with Panchayat Officials (focused group discussions) at the Gram Panchayat level through interactions during QCI team visit to Gujarat in December 2024 under the project Impact Assessment of GPs under Atal Bhujal Yojana



During our visit to Karnataka in February 2025, QCI team came across the inspiring story of Gowthami from Madder, Kolar. She inherited her father's land, but its rocky terrain made farming seem impossible. Determined to cultivate it, she sought support from the Agriculture Department. With their guidance, she levelled the land and implemented a drip irrigation system along with a farm pond, transforming it into fertile farmland.



During our visit to Haryana in Gram Panchayat Narnia in December 2024, the PPID team engaged with citizens at the Gram Panchayat level through interactions and focused group discussions, also analyzing women's participation in community initiatives.

6.22 Third-Party Evaluation of Raw Material Supply Scheme (RMSS)

Ministry of Textiles

- The Quality Council of India (QCI) conducted a pan-India third-party evaluation (TPE) from September to December 2024, assessing the Ministry of Textiles' Raw Material Supply Scheme (RMSS) for 2021-24. This flagship initiative, implemented by the National Handlooms Development Corporation (NHDC), provides 15% price subsidies on natural fiber yarns and transport subsidies to handloom weavers. The evaluation, covering 676 beneficiary groups and 65 suppliers (statistically representative samples), employed document and transaction verifications, key informant interviews, and focus group discussions to:
  - Determine the scheme's effectiveness and efficiency,
  - Provide data-driven insights for policy refinement, and
  - Deliver a comprehensive report to inform future support for Indian handloom weavers.
- Following were the findings of the project:
  - Income Boost: Over 70% of beneficiaries reported increased income, significantly above 2019 census levels.
  - Delivery/Subsidy: Most satisfied, but >25% faced delivery delays, and subsidy averaged 3 months.
  - App Underuse: E-Dhaga app adoption is low; reliance on NHDC is high.
  - Supplier Non-Compliance: Majority of suppliers skip inspections and label requirements.

6.23 Quality Assurance of Products under SRKVM-AP

Samagra Shiksha, Department of Education, Andhra Pradesh

- The Department of School Education on-boarded QCI as a quality assurance partner to ensure that the procured products meet 100% compliance with the specified Indian Standards. This partnership is critical to guarantee that only quality products are delivered to the end beneficiaries, thereby maintaining trust and achieving the scheme's objectives.
- By embedding a structured quality assurance framework, QCI aims to enhance the overall efficiency of procurement while ensuring that only high-quality products reach students. The anticipated outcomes include:
  - Product Integrity & Compliance – 100% adherence to prescribed standards, reducing defect rates and enhancing durability.
  - Improved Student Experience – Ensuring that 33.75 lakh students across 49,190 schools in 26 districts receive high-quality learning materials, contributing to better learning outcomes.
  - Operational Efficiency – Strengthening procurement mechanisms through proactive testing and quality checks, reducing rejections and delays.
  - Governance & Trust – Enhancing transparency and accountability in public procurement, reinforcing stakeholder confidence in the initiative.



The PMU team of QCI evaluating pre-bid products, analyzing the color scheme in February 2025 in Vijayawada, Andhra Pradesh, for Sarvepalli Radhakrishnan Vidya Mitra (SRVM) Program.


NDIE
National Division for
Industry Excellence
7
NATIONAL
DIVISION FOR
INDUSTRY
EXCELLENCE

This Division leads various projects of national importance with a focus on 'Atmanirbhar Bharat'. The division is involved in flagship programmes of Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Ministry of Defence and others.

7.1 GOVERNMENT PROJECTS/SCHEMES-RELATED ACTIVITIES

7.1.1 "MSME Sustainable (ZED) Certification" Scheme

MSME Sustainable (ZED) Certification is an extensive drive to create awareness amongst MSMEs about Zero Defect Zero Effect (ZED) practices and motivate and incentivise them for ZED Certification. Through the journey of ZED Certification, MSMEs can reduce wastages substantially, increase productivity, enhance environmental consciousness, save energy, optimally use natural resources, expand their markets, etc. MSMEs will also be motivated to adopt best practices in work culture, standardization of products, processes, and systems etc. to enhance their global competitiveness and sustainability.

QCI has been nominated to continue as an Implementing Agency (IA) under the MSME Sustainable (ZED) Certification Scheme. In a testament to an effective implementation of the MSME Sustainable (ZED) Certification Scheme of Ministry of MSME, by the Quality Council of India, the Scheme has achieved a significant milestone by granting 2,75,000+ ZED Certifications in a short span of time. This remarkable success underscores the growing commitment of MSMEs across various sectors to ensure quality and sustainability in their operations. Based on the MSME Sustainable (ZED) Scheme Guidelines, the following activities have been completed by QCI during financial year 2024-25:

a. Industry Awareness Programs

A nationwide plan for awareness was executed covering different states and sectors of the MSMEs. Extensive contributions came from State Government DIC offices, Industry Associations & other Organizing Partners in conducting these programs. To build the awareness on the ZED Scheme, 150+ awareness programs were conducted. In addition to awareness programs, on-site assistance through organizing partners were also provided covering more than 1.25 lakh MSMEs in 500+ cities across India.













ZED Awareness Programs and Registration Camps conducted for MSMEs

b. Consultants and Assessors Training Programs

Consultants and Assessors play a critical role in ZED Certification Scheme. They provide meaningful inputs during the assessment and consultancy, as applicable, helping the MSMEs in their upgradation to higher levels. Thus, their training is crucial to maintain quality and reliability of the assessment and consultancy.

i. 5-day Consultant Trainings conducted: 08 (Participants: 240)

ii. 5-day Assessor Trainings conducted: 07 (Participants: 197)



5-day Training Programs conducted for Consultants and Assessors

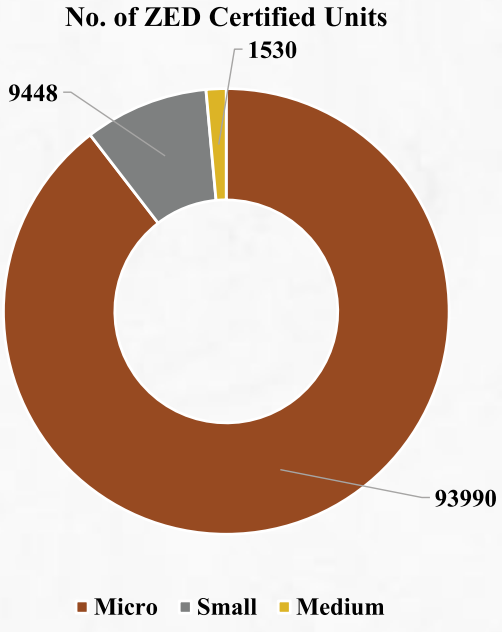
c. Assessment, Certification and Handholding through Consultancy

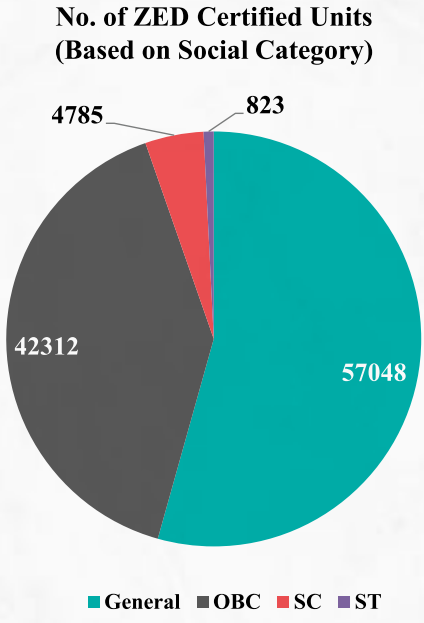
i. Registered MSMEs: 149836 (Micro: 136267, Small: 11737, Medium: 1825)

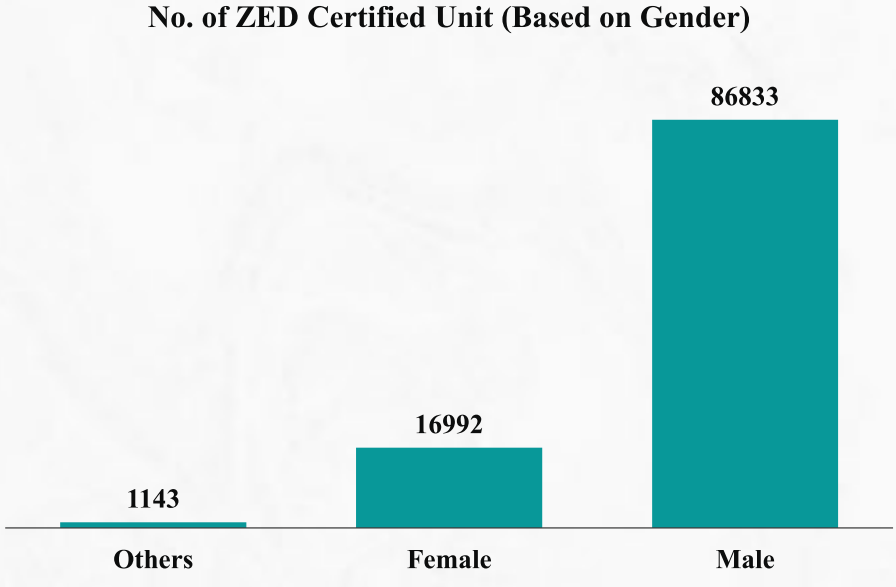
ii. Certified MSMEs: 104968 (Bronze: 102958, Silver: 731 and Gold: 1279)

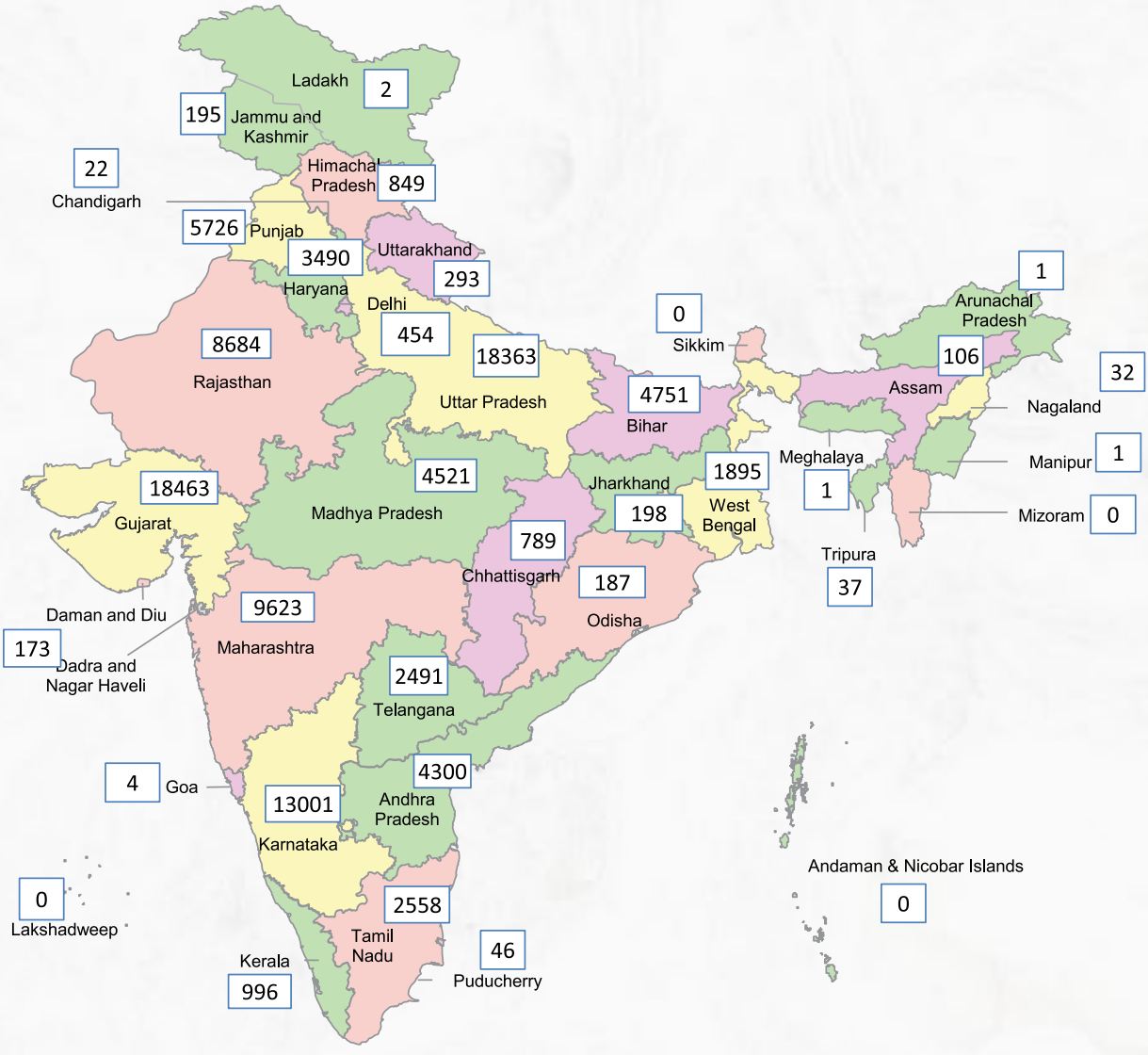
iii. Handholding/Consultancy support applications received: 1959

iv. MSMEs availed Financial Assistance on System (Quality)/Testing/Product Certification: 1119


No. of ZED Certified Units
1530
9448
93990
Micro
Small
Medium


No. of ZED Certified Units
(Based on Social Category)
4785
823
42312
57048
General
OBC
SC
ST


No. of ZED Certified Unit (Based on Gender)
86833
16992
1143
Others
Female
Male



ZED Certified MSMEs – State wise

d. Promotion & Branding

- MoU signed with Assam Small Industries Development Corporation Ltd. (ASIDC), Government of Assam on March 17, 2025
- MoU signed with Directorate of Industries, Government of Uttarakhand on March 26, 2025
- MoUs signed with Monte Carlo and Avon Cycles at Ludhiana on September 5, 2024 and September 06, 2024, respectively.
- MoU signed with Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam (MPLUN) on October 3, 2024 to propagate ZED Scheme in Madhya Pradesh
- Meeting conducted with BHEL to discuss adoption of ZED Certification in their supply chain on December 27, 2024.
- Meetings conducted with various state governments (Tripura, Chandigarh, Karnataka, Nagaland, Haryana, Tamil Nadu, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat) to scale-up the ZED Certifications

- ZED Presented at ICMM – 2025, IIM Amritsar on January 17, 2025
- A DISHA workshop conducted on January 30-31, 2025
- Meeting conducted with Directorate General of Foreign Trade (DGFT) for collaboration to enlist ZED Silver and Gold Certified MSMEs on Trade Connect e-Platform for exports at Delhi on August 21, 2024
- ZED showcased at Comprehensive Competitiveness Workshop at Pune, Maharashtra on July 19, 2024
- A ZED awareness session conducted for BLW vendors at Varanasi on August 2, 2024. 50+ vendors participated
- A ZED awareness session conducted for the ASSOCHAM Gujarat Council members on May 31, 2024, at Ahmedabad, Gujarat. 75+ MSMEs participated
- ZED Silver & Gold Certified MSMEs Felicitated by Hon'ble Union Minister of MoMSME at MSME Conclave held on September 11, 2024, in Ranchi, Jharkhand
- A Gunvatta Manthan organised at Chennai, Tamil Nadu to discuss the challenges in the current Lean Scheme framework and explore opportunities for enhanced outreach and implementation on February 13, 2025





ZED awareness session conducted for the ASSOCHAM Gujarat Council members at Ahmedabad, Gujarat



MoU signed with Assam Small Industries Development Corporation Ltd. (ASIDC), Government of Assam



MoU signed with Directorate of Industries, Government of Uttarakhand







MoU signed with Monte Carlo at Ludhiana





MoU signed with Avon Cycles at Ludhiana





ZED Silver & Gold Certified MSMEs Felicitated by Hon'ble Union Minister of MoMSME at MSME Conclave at Ranchi, Jharkhand





A Gunvatta Manthan organised at Chennai, Tamil Nadu to discuss the challenges in the current Lean Scheme

e. ZED Media Coverage



रैम्प स्कीम के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित

रायसेन। जिले में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम के अंतर्गत एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री मंडीदीप के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जेड स्कीम, लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, बौद्धिक संपदा अधिकार और व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम की शुरुआत योजना के फील्ड अधिकारी और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के उप महाप्रबंधक अनिल धागले एवं जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र मंडीदीप के महाप्रबंधक के संबोधन से हुई। जिसमें उन्होंने योजना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने योजना के उद्देश्यों और इसमें मध्य प्रदेश सरकार की भूमिका और योगदान पर प्रकाश डाला।



रैंप प्रोग्राम के तहत हुई कार्यशाला, दी योजनाओं की जानकारी

राष्ट्रीय हिन्दी मेल

रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस को लेकर कार्यशाला आयोजित

संवाददाता सुरभि सिंघल माहेश्वरी
मो. 9981322343

Date: 16/10/2024, Page: 4, City: Bhopal

राष्ट्रीय हिन्दी मेल

राज एक्सप्रेस

रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप स्कीम के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित

रैंप प्रोग्राम में भाग लेकर उद्योगों को लाभ लेने प्रोत्साहित करें एसोसिएशन



दैनिक उजाला

मंडीदीप में रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (रैम्प) स्कीम के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित



जिले के उद्योगों को जेड सर्टिफाइड बनाने के लिए हुई कार्यशाला



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न



एमएसएमई विभाग की कार्यशाला सम्पन्न





रैम्प योजना के तहत सागर में कार्यशाला का आयोजन

सागर। नवदुनिया

जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (रैम्प) योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होटल दीपक, सिविल लाइंस, सागर में किया गया। इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न उद्योग संघों ने सक्रिय भागीदारी की।कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) योजना, लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धात्मकता योजना (एलएमसीएस), बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), और व्यापार प्राप्त सिस्टम (टीआरईडीएस) के प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यशाला की शुरुआत जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र, सागर की महाप्रबंधक सुश्री मदकिनी फाटे के स्वागत भाषण से हुई। अपने संबोधन में उन्होंने रैम्प योजना के उद्देश्य, मध्य प्रदेश सरकार की भूमिका और इसमें स्थानीय उद्योगों के लिए संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।इसके पश्चात, जोनल के विशेषज्ञ डॉ अमन जैसवाल ने इस योजना के लाभों और क्रियान्वयन पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि जेड सर्टिफिकेशन प्राप्त करने से उद्योगों की गुणवत्ता और पर्यावरणीय प्रभाव में सुधार होगा। उन्होंने स्थानीय उद्योगों से नेट सर्टिफाइड बनने का आह्वान किया।

7.1.2 SAMAR Certification: Assessment and Rating of Vendors of DRDO, Ministry of Defence

System for Advance Manufacturing Assessment and Rating (SAMAR) Certification is an outcome of the collaboration between QCI & DRDO and is a benchmark to measure the maturity of defence manufacturing enterprises. It aims to strengthen the defence manufacturing ecosystem in the country.

The certification is based on a maturity assessment model developed by Quality Council of India (QCI) and is applicable to all defence manufacturing enterprises i.e., micro, small, medium and large enterprises. Key highlights of the activities are as under:

- Number of applications for assessment: 81
- Number of Assessment conducted: 60
- Number of organizations rated: 47 (Level 1: 04, Level 2: 13, Level 3: 23, Level 4: 07)
- The SAMAR Certification showcased at AERO India Show 2025, organized by the Ministry of Defence aimed at enhancing vendor quality and compliance.120+ DRDO vendors engaged.
- The SAMAR Certification showcased at vendor interaction campaign, organised by the Defence Research and Development (DRDO) through Armaments and Combat Engineering (ACE) cluster on October 18, 2024, at Pune, Maharashtra. 250+ organisations participated
- The SAMAR Certification showcased at DRDO-ISSA as a part of their quality month initiatives on November 14, 2024, at Delhi
- The SAMAR Certification showcased at the “Synergy Meet of BDL Vendors” on April 24, 2024, at Hyderabad, Telangana. 75+ BDL vendors participated





The SAMAR Certification showcased at AERO India Show 2025, organized by the Ministry of Defence



SAMAR Certification showcased at the “Synergy Meet of BDL Vendors” at Hyderabad, Telangana


PADD
Project Analysis and
Documentation Division
8
PROJECT
ANALYSIS AND
DOCUMENTATION
DIVISION
(PADD)

Project Analysis and Documentation Division: Last-mile access, First class Quality

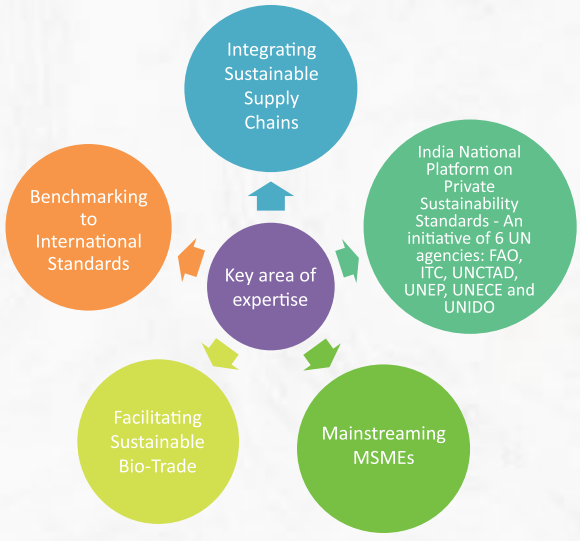
Project Analysis and Documentation Division handles projects which aim towards the design, development, and implementation of conformity assessment frameworks for governmental, inter-governmental, regional, and global organizations.

The Division prides itself in driving noble initiatives that have national, regional, and global relevance. QCI through this division continues to offer solutions to various Government ministries/departments/ organizations, industrial bodies, international donor agencies, developmental organizations, and inter-governmental bodies such as the FAO of the UN, UNFSS, UNCTAD, SAARC Agriculture Centre, ICRISAT, ITTO, UNDP, GLOBALG.A.P., IRRI etc.

PADD has now been sought by regulators such as the FSSAI, DGCA, NBA and national agencies such as NeGD, NGCMA, NTRO, NCIIPC, NCPCR for assisting in due diligence as a precursor to issuing of respective approvals.

We strive to achieve our mission by focusing on the following objectives:

- Development of conformity assessment frameworks across sectors, in line with international standards and best practices
- Provision of technical support to regulatory ecosystem and industry bodies for effective implementation of national and international initiatives
- Awareness amongst users through large-scale training and capacity building programmes to build capacities in the areas of conformity assessment
- Work cohesively through assimilating innovative approaches and expertise to deliver outcomes and drive quality at the cutting-edge
- Delivering integrated solutions through leading-edge research and dissemination of its result in relevant publication, reports and trade journals
- Multi-stakeholder led initiatives focused on diversified business mix that includes enhancing achievement of sustainable development goals and creating positive societal impact to achieve consensus on conformity assessment solutions for better acceptance



8.1 Voluntary Certification Scheme for Traditional Community Healthcare Providers (VCS-TCHP)

8.1.1 The Scheme offers a uniform and standardized assessment framework for TCHPs who manage various streams of health services (jaundice, common ailments, poisonous bites, bone setting, joint pains, and traditional birth attendants) based on their traditional knowledge, experience, and expertise.

8.1.2 A total of 2522 TCHPs certified under the Scheme till date with the Government of Chhattisgarh adding to endorsing of the scheme in addition to the earlier states – Goa and Tamil Nadu.

8.1.3 Following Chhattisgarh's endorsement, 216 TCHPs were certified in the state.

8.2 AYUSH Mark Scheme

8.2.1 At the behest of the then Department of AYUSH, a voluntary product certification scheme for AYUSH products to enhance consumer confidence was designed by the Quality Council of India. The Scheme has two levels of certification: Standard and Premium.

8.2.2 Till date a total of 5797 products are under the AYUSH Mark with a total of 68 manufacturers certified under the scheme.

8.2.3 Ministry of AYUSH is coming out with AYUSH AAHAR that is integrated to AYUSH Mark for which QCI is included as member this will see the involvement of NABCB and PADD.

8.3 Recognition of Hygiene Rating Audit Agencies (HRAA)

8.3.1 PADD developed a scheme for approval of Hygiene Rating Audit Agencies (HRAAs) with an aim to help consumers make informed decisions regarding food outlets where they prefer to eat by encouraging businesses to improve hygiene and safety standards. The recognised agency will verify compliance with food hygiene and safety procedures laid down by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI).

8.3.2 QCI have 27 HRAAs currently active under the Scheme.

8.3.3 A total of 62233 Hygiene Rating Scheme (HRS) audits conducted till date by these HRAAs.

8.3.4 Division successfully conducted 2 Hygiene Rating (HR) Auditor Training Program (Qualifying & Refresher) on January 23, 2025 and February 21, 2025, trained total 87 participants under FSSAI's Hygiene Rating Scheme.

8.3.5 A one-day online training program on Good Hygiene and Good Manufacturing Practices (GHP & GMP) was conducted on January 10, 2025, under FSSAI's Eat Right India Initiative, with 28 students from various IHMs participating.



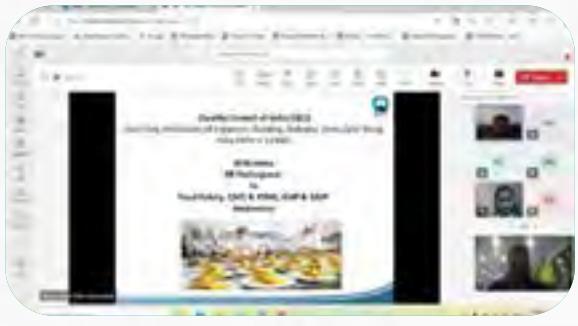


Division conducted Hygiene Rating Auditor Training on January 23, 2025





Division conducted Hygiene Rating Auditor Training on February 21, 2025





Empowering Future Hospitality Leaders: A one-day online training on GHP & GMP under FSSAI's Eat Right India Initiative trained 28 IHM students on January 10, 2025

8.4 Certification Scheme for UAS (CSUAS)

8.4.1 QCI at the behest of Ministry of Civil Aviation is operationalising the Certification Scheme for Unmanned Aircraft Systems (UAS). The Scheme was notified by Ministry of Civil Aviation in Gazette on January 26, 2022.

8.4.2 A total of 104 Type Certificates (TC) has been issued since the launch.

8.4.3 Strengthening the drone ecosystem, PADD briefed on its intervention in drone sector, supporting Ministry of Civil Aviation and Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare through CSUAS. Enhancing the Namo Drone Didi scheme by ensuring robust indigenous content in kisan drones, paving the way for Aatmanirbhar Bharat.

8.4.4 PADD built the capacity of the Automotive Research Association of India (ARAI), Pune in a combination of training focused on Conformity Assessment Framework and technical requirements of CSUAS including the testing requirements to encourage them to become an Authorised Testing Entities (ATEs).

8.4.5 PADD, QCI has developed the upgraded CSUAS Scheme for VLoS, has developed indigenisation framework for Kisan Drones and has developed BVLoS framework which is placed to the technical committee and the certification committee.

8.4.6 PADD, in collaboration with Farm Machinery Training and Testing Institute (FMTTI), hosted a 4-day Capacity Building-cum-Sensitization Program on CSUAS across four locations: Central FMTTI, Budni, Northern Region FMTTI, Hisar, Northeast Region FMTTI, Biswanath Chariali (December 10-13, 2024), Southern Region FMTTI, Ananthapur (December 11-14, 2024). The FMTTI, a public institute under the Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, is actively driving capacity building in Unmanned Aircraft Systems (UAS) technology, empowering farmers with modern solutions for a more sustainable and technology-driven future.

8.4.7 Quality Council of India (QCI) has signed an MoU with AP Drone Corporation, marking a significant step toward fostering collaboration in the field of drone technology and certification.



PADD Driving Innovation through CSUAS: Strengthening India's drone ecosystem with indigenous agri-drones under the Namo Drone Didi scheme for Aatmanirbhar Bharat













Empowering Agriculture: CSUAS Capacity Building Programs conducted across four locations for FMTTI, Ministry of Agriculture



QCI signs MoU with AP Drone Corporation to advance drone technology and certification

8.5 IndG.A.P. Certification Scheme

8.5.1 An initiative focused on enhancing food safety, produce quality, and resource optimization in agriculture, ensuring better market access and improved livelihoods for small and marginal farmers through adherence to globally recognized standards.

8.5.2 The Division also conducted a 3-day virtual training program for 233 officers from the State Agriculture Department, Government of Andhra Pradesh, on Quality Management Systems (QMS), Food Safety Management Systems (FSMS), and ISO 19011 elements for IndG.A.P. compliance. The Training was successfully completed in four batches: from August 28-30, September 9-11, September 18-20 and September 25-24, 2024.

8.5.3 A meeting was held with Sri S. Dilli Rao, IAS, Commissioner and Director of Agriculture, Department of Agriculture, Andhra Pradesh, to discuss the emphasis on building capacity across FPOs in the state. A request was made for the development of a portal to capture the certification process and audit under the Scheme.



PADD, QCI conducted a 3-day virtual training program on QMS, FSMS, & ISO 19011 elements for IndG.A.P./VCSMPP compliance from 28th to 30th August 2024



Empowering Agricultural Capacity: Team PADD meets with Sri S. Dilli Rao, IAS, to discuss capacity building for FPOs in Andhra Pradesh

8.6 Voluntary Certification Scheme for Medicinal Plant Produce (VCSMPP)

8.6.1 QCI, at the behest of National Medicinal Plant Board (NMPB), Government of India, has developed and designed a voluntary certification scheme for medicinal plant produce to introduce Good Agricultural Practices (GAP) and Good Field Collection Practices (GFCP) for medicinal plants.

8.6.2 A total of 100 trainings were conducted Pan-India, engaging more than 6000 attendees. Additionally, Package of Practices (PoPs) were developed for 111 species. Demonstration plots were identified and established in 30 locations, and 30 projects have been certified to date.

8.6.3 Division organised one-day technical training workshop on voluntary certification scheme for medicinal plant produce (VCSMPP) on March 21, 2025, New Delhi.









One-day technical training workshop on voluntary certification scheme for medicinal plant produce (VCSMPP) on March 21, 2025, New Delhi

8.7 Development of Conformity Assessment System and Resource for Protection of Critical Information Infrastructure (CII)

8.7.1 QCI has developed a Conformity Assessment Framework (CAF) for the Cyber Security of Critical Sector Entities, with NCIIPC as the Scheme Owner (SO) and QCI as the National Accreditation Body & Scheme Manager to manage the scheme on behalf of NCIIPC.

8.7.2 PADD invited applications for onboarding approved bodies under a set of schemes developed for the Conformity Assessment System and resources for the protection of CII in cybersecurity.

8.7.3 A Technical Committee (TC) meeting was conducted on January 16th 2025, and the selected entities under the framework are notified on the website.

8.7.4 At CyberComm 2025, organized by FICCI India in collaboration with the Ministry of Electronics and Information Technology and the Department of Telecommunications India, Shri Kannan Chakravarthy, SG, QCI, stressed the importance of cyber resilience in securing India's digital future. Dr. Manish Pande, HoD, PADD, emphasized adaptive policies and global collaboration to strengthen cybersecurity in Viksit Bharat.

8.7.5 Division conducted 30 Cybersecurity Awareness Programs, engaging more than 1000 participants pan India to strengthen resilience in Critical Sector Entities (CSEs).

8.7.6 TÜV SÜD South Asia become first provisionally approved PrCB under the Personnel Certification Scheme for IT/ ICS Cyber Security Professionals.





Shri Kannan Chakravarthy, SG, QCI, emphasizes the critical role of cyber resilience at #CyberComm2025 (January 9, 2025, FICCI, New Delhi), reinforcing cybersecurity as a foundation for India's digital future and Viksit Bharat





Dr. Manish Pande, HoD PADD, highlights QCI's CAF at #CyberComm2025 (January 9, 2025, FICCI, New Delhi) as a key enabler for cybersecurity in critical sectors, driving resilience for Viksit Bharat















Cybersecurity Awareness Programs Pan India to strengthen resilience in Critical Sector Entities (CSEs)

8.8 Ready Mix Concrete Plant Certification Scheme (RMCPCS)

8.8.1 QCI has launched "RMC Plant Certification Scheme" to assure quality in Ready Mix Concrete (RMC) plants, developed in collaboration with key industry stakeholders, including the Ready Mixed Concrete Manufacturers' Association (RMCMA), the Building Materials & Technology Promotion Council (BMTPC) under the Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, the Construction Industry Development Council (CIDC), Military Engineering Services (MES), the Airport Authority of India, and the Ministry of Water Resources.

8.8.2 The scheme offers two certification options, 'RMC Capability Certification' and 'RMC 9000+ Capability Certification', the latter aligning with ISO 9001.

8.8.3 A total of 518 active clients are certified under the Scheme till now with 2 Provisional Approved CBs and 5 Accredited CBs.

8.8.4 RMCPCS has been recognized by several esteemed bodies such as the Public Works Departments of Karnataka and Puducherry, Brihanmumbai Municipal Corporation, City and Industrial Development Corporation of Maharashtra (CIDCO), Jalsampada (Water Resources) Department of Maharashtra, as well as notable private agencies including DesignTree Service Consultants Pvt. Ltd. and Concons Consultants Consortium.

8.9 Indian Certification of Medical Devices (ICMED) Scheme

8.9.1 To fill the then regulatory vacuum in quality certification space for medical devices in the country, the Association of Indian Medical Device Industry (AIMED) in collaboration with the Quality Council of India (QCI) has rolled out a voluntary quality certification scheme for medical devices.

8.9.2 While the ICMED was focused on QMS, QCI has upgraded the scheme to ICMED 13485 Plus that now offers certification to the individual medical devices based on their product performance.

8.9.3 The Indian Pharmacopoeia Commission (IPC), an autonomous Institution of the Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India is now approved as a Certification Body under the ICMED Scheme.

8.9.4 ICMED 13485 Plus scheme now has approved Zenith Quality Assessors Pvt. Ltd.

8.10 Indian Forest and Wood Certification Scheme:

8.10.1 QCI is one of the members of Indian Forest and Wood Certification Council.

8.10.2 QCI serving as the knowledge partner for the Indian Institute of Forest Management (IIFM) in promoting and piloting the Indian Forest and Wood Certification Scheme (IFWCS), developing conformity assessment frameworks, and building the capacity of certification bodies.

8.10.3 QCI has inked MoU with IIFM, Bhopal on August 5, 2024 to advance Indian Forest & Wood Certification Scheme – PRAMAAN, owned by Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

8.10.4. QCI represents itself in the IFWC Council and the technical committee constituted under it.



QCI inked MoU with IIFM, Bhopal on August 5, 2024 to advance Indian Forest & Wood Certification Scheme – PRAMAAN, owned by MoEF&CC

8.11 DigiReady Certification

8.11.1 The DigiReady Certification (DRC) initiative is a collaborative effort between Quality Council of India (QCI) and Open Network for Digital Network (ONDC), aimed at assessing and certifying the digital readiness of MSME entities.

8.11.2 Over 2881 participants have been successfully onboarded on the DRC portal, with more than 755 certificates issued till date.

8.11.3 DRC awareness campaigns were conducted at the MSME-Development Office, Jaipur, Rajasthan, during the Vendor Development Program (Vendor Meet) on December 17-18, 2024. The sessions focused on educating MSMEs about the benefits of onboarding to the ONDC network through DigiReady Certification (DRC), facilitating their participation in the digital commerce ecosystem.

8.11.4 28 agencies were empanelled as Organising Entities in the month of January and February under the Digital Readiness Certification project, further expanding the initiative's reach and impact.

8.11.5 Dr. Manish Pande, Director & Head, PADD-QCI, led the QCI-powered session on "Empowering Supply Chains via Conformity Assessment Frameworks" at India Sourcing Conclave 2025 by BAA India. The session focused on ESG compliance for all actors, emphasizing MSME capacity building and digital transformation under DigiReady Certification (DRC). The conference was presided over by Mr. Moustafa F. Shaikhon, Minister Plenipotentiary, Egypt.





Dr. Manish Pande leads QCI session at India Sourcing Conclave 2025, highlighting ESG compliance, MSME capacity building, and digital transformation under DRC







Empowering MSMEs: DRC awareness campaigns at MSME-DO Jaipur drive ONDC onboarding for digital commerce growth

8.12 Conformity Assessment Framework to build Digital Competencies

8.12.1 Developing a Conformity Assessment Framework to build Digital Competencies of government officials for National e-Governance Division (NeGD).

8.12.2 The framework will focus on: Digital Planning and Design, Data Use and Governance, Digital Management and Execution.

8.12.3 The 4th Technical Committee (TC) meeting held on March 15, 2025, where mutual

consensus was received on the technical criteria document followed by its approval by the Chair.

8.12.4 The 1st Certification Committee (CC) meeting held on March 29, 2025. The final document, incorporating all committee feedback, was approved by the Chair.



4th Technical Committee (TC) meeting conducted on March 15, 2025



1st Certification Committee (CC) meeting conducted on March 29, 2025



9 STRATEGY AND POLICY DIVISION (SPD)

9.1 Overview

9.1.1 The Policy Unit in QCI has been established in 2020 to complement the capacity of decision-makers in policy making, monitoring, and to ingrain quality as a subject of public policy. The Unit has worked towards providing strategic vision to the organisation, driving the quality agenda towards Viksit Bharat 2047. In December 2024, the unit has evolved into Strategy and Policy Division (SPD) and operated under the 'Transform' mandate of QCI. The division serves both Internal boards and divisions along with external stakeholders.

9.2 Structure and Functions of SPD

The SPD has evolved the following wings:

9.2.1 Internal Strategy Wing:

9.2.1.1 Clients: QCI Boards & Divisions

9.2.1.2. Scope:

- Assists with QCI's strategy cycle, including vision setting, SWOT analysis, and strategic priorities
- Supports service-line strategy development
- Offers support with strategic capabilities (e.g., customer insight, Go-To-Market strategy)
- Analytics Team: Provides data analytics to the Division and QCI

9.2.2 Incubator:

9.2.2.1 Clients: External stakeholders

9.2.2.2 Scope:

- Standing Team on Industry & Internal Trade: Incubates concepts and initiatives for industry and internal trade (DPIIT matters)
- Concept Development Team: Incubates concepts and transformation initiatives across sectors and develops capabilities for converting concepts into impact-oriented projects
- Grading of Accredited HCOs – helping shape the service line for eventual merger under healthcare function

9.2.3 Accelerator:

9.2.3.1 Clients: External stakeholders

9.2.3.2 Scope: Delivers projects emerging from concept development, evangelizing, or requests to QCI, focused on strategy development, strategic transformation, and capabilities for Viksit Bharat.

9.3 Key Initiatives and Projects started during the financial year 2024-25

9.3.1 Internal Strategy

9.3.1.1 Strategy Cycle: Helping Boards & Divisions formulate their internal strategy through a structured process of evolving aspiration, SWOT, CVP, strategic priorities and initiatives.

9.3.1.2 Stakeholder Strategy / Net Promoter Score (NPS) Implementation:

9.3.1.2.1 QCI implemented a phased approach to derive the Net Promoter Score (NPS) for its boards and divisions, starting with NABH and NABL. This initiative aims to assess and improve internal service delivery, strengthen internal processes through stakeholder feedback, and establish a standardized framework for grievance resolution and service enhancement.

9.3.1.2.2 The expected outcomes include improved service quality, data-driven decision-making, a well-defined NPS framework, and a more responsive approach to internal grievance resolution.

9.3.1.3 Grading of Healthcare Organisations (HCOs):

9.3.1.3.1 To understand the challenges faced by the patients in choosing HCOs for their treatment needs, a patient in-sighting study has been carried out at Delhi, Bengaluru, Hyderabad and Pune with more than 750 patients. It has been learnt that patients need a credible source of information that encompasses necessary

information on quality aspects of the HCOs.

9.3.1.3.2 Developed a framework for grading healthcare organizations to drive quality and consistency. Healthcare organizations will be evaluated and given an audit score and grade (Accreditation+, Accreditation++, Accreditation+++).

9.3.1.3.3 The evaluation will be based on measurable elements across categories like Structure, Process, Technology Use, Patient Experience, and Outcome. Standards and assessment processes are being developed, and pilot has been carried out.

9.3.1.3.4 Grading standards finalised by the Steering Committee members and was uploaded on QCI's website for public review & comments.

9.3.1.3.5 A launch plan was created with activity list assigning roles & responsibilities, with a plan to launch the portal during May 1st week.

9.3.1.4 Evolving Surajya Recognition 2.0

9.3.1.4.1 Surajya Recognition is currently categorized under four pillars: Shiksha (Education), Swasthya (Health), Samriddhi (Prosperity) and Sushasan (Governance). The Surajya Recognition highlights the outstanding performance and commitment to quality by states across each pillar on a monthly basis.

9.3.1.4.2 ESG related parameters have been included. Work is in progress to build Surajya 2.0, a more comprehensive framework that not only measures progress but also enhances quality governance, drives policy changes and promotes sustainable development, accelerating India's journey towards Viksit Bharat.

9.3.2 Incubator

9.3.2.1 Pharma Quality Excellence

9.3.2.1.1 To move India from being the 'Pharmacy of the world to global Quality Pharmacy hub', QCI has undertaken incubation of this blue-ocean strategy area to understand the challenges of the Indian Pharma Industry and ideate policy recommendations for the same. For this purpose, an in-depth value chain analysis was conducted and MSME matrix was developed, mapping areas like government support, India's standing across value chain components, problems areas, regulatory bottlenecks, reports and recommendations, along with international benchmarking.

9.3.2.1.2 Expert Interview Questions were designed, and interviews were conducted, which resulted in adding more focus areas that need problem-solving to be done.

9.3.2.1.3 Demand side analysis was undertaken to arrive at key areas/trends in epidemiological, demographic, geographic, therapeutic, segments that could help the domestic pharma industry to prepare for the 'Vision 2047: Viksit Bharat'.

9.3.2.1.4 The team conducted interviews with around 30 MSME manufacturers to understand their viewpoints on regulatory and quality challenges that they tackle to further our research on Regulatory and Quality challenges in Pharma manufacturing.

9.3.2.1.5 The team mapped potential scenarios for the pharma manufacturing landscape to identify focal areas/trends in manufacturing, drug innovation, Human Resource development, affordable & accessible medicines, and pharma digitization.

9.3.2.2 MSME Excellence

9.3.2.2.1 As part of the overall vision of driving quality in MSMEs for Viksit Bharat, QCI has adopted a 4-pronged strategy as below

9.3.2.2.1.1 Quality Excellence: The existing QCI projects of ZED, LEAN and the upcoming ZEDx certifications are part of this pillar of the strategy. These initiatives enable MSMEs to start their quality journey.

9.3.2.2.1.2 Quality Accelerator: To increase the adoption of quality journey and also to level up their quality processes, with an anchor driven intervention. QCI enables a holistic collaboration among OEMs, COE, large firms, Ministry and other stakeholders to handhold MSMEs in accelerating their quality journey.

9.3.2.2.1.3 CVP for MSMEs: QCI would create interventions to enable linkages to latest technological and quality upgradations like OCEN, ULI etc.

9.3.2.2.1.4 Demand Generation: Enabling generation of demand for MSME produced quality products through advocacy and other interventions with industry and government.

9.3.2.2.2 A holistic Anchor driven MSME project has been designed involving OEMs who nominate MSMEs and QCI would facilitate consultants for these MSMEs to handhold, guide and train them on various aspects that are pain points for MSMEs.

9.3.2.2.3 The project has been strategized and handed over to ZED Division for implementation.

9.3.2.3 Adventure Tourism for Gujarat

9.3.2.3.1 A comprehensive strategy was devised for Gujarat's Department of Tourism under the GEAR UP (Gujarat Exploration and Adventure Retreat) for positioning Gujarat as India's top Adventure sports destination.

9.3.2.3.2 This strategy emphasizes alignment with international safety standards, prioritizing infrastructure enhancements, community involvement, a third-party ecosystem analysis, and the accreditation of service providers to strengthen Gujarat's adventure tourism landscape.

9.3.2.3.3 A go-to-market strategy has also been developed, focusing on state-wide promotions complemented by destination-specific campaigns.

9.3.2.3.4 In this initiative, QCI will act as the knowledge and strategy partner for the Department of Tourism, Gujarat, driving targeted efforts to enhance the state's adventure tourism profile.

9.3.2.4 Medical Value Tourism

9.3.2.4.1 Conducted a sector study - granular sector analysis to identify industry's vulnerabilities (pain points) and opportunities and develop a robust strategy for India's medical tourism sector.

9.3.2.4.2 Comprehensive secondary research has been undertaken with detailed country benchmarking, SWOT analysis of the sector, mapping and analysing patient journey across 20 KPIs.

9.3.2.4.3 Comparative study on India's Medical Value tourism with Regional and Global competitors to understand their best practices.

9.3.2.4.4 Future-Ready Scenario Planning- Developed scenario planning methodology for understanding India's goal as Global MVT destination.

9.3.2.4.5 Explored potential collaboration with various stakeholders like Ministry and Industry association like FICCI.

9.3.2.5 Training Sessions on ISTM

9.3.2.5.1 Designed a module on 'Quality Excellence in Policy' for Group E Officers at Institute of Secretariat Training and Management.

9.3.2.5.2 The module focused on how to approach various steps in policy formulation or governance.

9.3.2.5.3 Interactive sessions with stakeholder advocacy simulations to practically demonstrate the usage of various frameworks enabling policymakers with evidence-based decisions.

9.3.2.6 STARTUPS

9.3.2.6.1 Conducted an in-depth review of the startup ecosystem in India to identify key constraints, gaps, and opportunities for enhancing the sector's efficiency and overall development.

9.3.2.6.2 Several strategic initiatives are designed and developed under the umbrella of STAMBH (Startup Accelerator Model for Bharat). A cornerstone of this strategy is the Testbed STAMBH Initiative, which provides mature startups with opportunities to refine and validate their products and services in real-world environments. This initiative facilitates Startup-Industry Connect through the formation of Use-Case Maturation Cohorts.

9.3.2.6.3 Engaged with DPIIT and Startup India to explore formal partnerships, including a potential MoU. This collaboration aims to strengthen the industry-startup connect and support outreach efforts, leveraging a vast network and repository.

9.3.2.6.4 Additionally, sector-specific outreach has been initiated to gauge the initiative's relevance and effectiveness. In the healthcare sector, engaged with key stakeholders to understand their expectations and requirements. Similarly, dialogues have begun with innovation hubs to tailor the initiative to the unique needs of different sectors. Future Strategy Development - working on additional strategies to enhance the overall startup ecosystem. Beyond incubation and acceleration, the focus is on creating a comprehensive support system for startups at every growth stage and develop a monitoring and evaluation model for incubators/ accelerators.

9.3.2.7 Standing Team on Industry & Internal Trade:

9.3.2.7.1 Following the invitation to autonomous organisations for the SOM meetings of DPIIT, the SPD has set up a Standing Team on Industry & Internal Trade for better coordination, alignment and advisory to QCI's Nodal Point in GoI.

9.3.2.7.2 Currently the team has aligned itself with developing concepts on national missions and initiatives (e.g., National Manufacturing Mission, Union Budget initiatives).

9.3.2.7.3 Working on policy and framework development (e.g., National Quality Policy & Act, Design Policy 2.0).

9.3.2.8 Critical Analysis of WGI Methodology:

9.3.2.8.1 QCI has undertaken a critical analysis of the World Bank's Worldwide Governance Indicators (WGI) methodology. This assessment involved identifying and categorizing data sources, and evaluating parameters such as transparency, biasness, methodology, and criticism. The outcome is a set of key focal questions and alternate data sources to address the issues with the current methodology.

9.3.2.9 Accelerating Global Capability Centers in India

9.3.2.9.1 Based on the Union budget announcement 2025, QCI has taken a proactive approach and analysed the GCC ecosystem at present and set a vision in line with Viksit Bharat 2047 to make India the most preferred destination for GCCs in the World.

9.3.2.9.2 Extensive secondary research on GCCs in the country, studied their presence across major tier-1/2 cities. Identified the reasons for unequal presence of GCC in tier- 2/3 cities. Benchmarked various countries and mapped their GCC ecosystem, Identified the factors responsible for choosing a country to set the GCC and factors responsible for selection of a city to set a GCC unit. An extensive factor list has been created to gauge the GCC readiness of a city is prepared.

9.3.2.9.3 Stakeholder mapping has been done to consult them in understanding their perspectives and problem statements.

9.3.2.9.4 Discussions will be held with MNCs, real estate players, etc. stakeholders with these insights, a report would be prepared to propose the regulator.

9.3.2.10 National Design Policy 2.0

9.3.2.10.1 QCI, in collaboration with DPIIT, is conducting a comprehensive

stakeholder consultation exercise to revamp the National Design Policy. This involves engaging with over a dozen design experts from academia, industry, and government.

9.3.2.10.2 The first expert consultation meeting was held on February 18, 2025, and received an enthusiastic participation. Experts provided valuable insights on integrating diverse aspects in the new design policy ranging from sustainability, culture, national branding through design to quality education and design parks, among others.

9.3.2.10.3 Following the meeting, detailed inputs from the experts have been analyzed to finalize the Terms of Reference (ToRs) for the exercise. Based on these ToRs, several groups and sub-groups will be formed, with experts mapped according to their expertise and experience.

9.3.2.11 Ensuring India's Readiness for EU's Digital Product Passport (DPP)

9.3.2.11.1 In response to EU's ESPR and DPP mandate for its imports, QCI has undertaken a proactive approach with an intent to frame the regulatory policy that impacts India's exports to the EU.

9.3.2.11.2 Conducted scenario-based risk modelling to understand potential consequences of non-compliance on India's export performance. Undertook global benchmarking to study how other countries are preparing for DPP implementation across governance, execution, and private-sector engagement. Mapped strategic opportunities through scenario planning to explore how India could move from reactive compliance to proactive global leadership.

9.3.2.11.3 Prepared a policy concept note recommending structured next steps, to inform decision-making at DPIIT and support national-level preparedness.

9.3.2.12 Gyan Bharatam Mission

9.3.2.12.1 As per the Union Budget 2025 announcement, and in continuation of the ongoing engagements with the Ministry of Culture, QCI took an initiative to explore how the Gyan Bharatam Mission can be drafted. Drawing on the goodwill built through previous projects, QCI began groundwork to develop a strategy to support the Ministry in the mission.

9.3.2.12.2 A comprehensive benchmarking exercise to draw insights from global best practices was carried out to provide a structured foundation that can guide the Mission's design, implementation, and impact measurement.

9.3.2.12.3 The manuscript value chain is mapped into eight key stages, encompassing activities from survey and documentation to conservation and preservation, digitization, translation and interpretation, research and capacity building. Each stage is benchmarked against seven prominent international initiatives known for heritage preservation and digital archiving.

9.3.2.12.4 Next steps include, drafting a strategic framework outlining potential models, and governance pathways for the Gyan Bharatam Mission.

9.3.2.13 Circular Economy Initiatives:

9.3.2.13.1 Focus on establishing a circular economy ecosystem.

9.3.2.13.2 Key areas include:

- Accreditation Model: Devising an accreditation model with standards and processes
- Repairability Index: Creating a Repairability Index for consumer empowerment
- Industrial Symbiosis: Fostering collaboration for resource sharing
- Sector-Specific Strategies: Developing action plans for circularity in various sectors
- Circular Accelerator: Launching a program to scale circular innovations

- Digital Product Passports: Creating digital passports for product traceability and sustainability information.

9.3.3 Accelerator

9.3.3.1 India Post Transformation:

9.3.3.1.1 QCI has developed a transformative maturity model for India Post, impacting over 1.64 lakh post offices and empowering its extensive network, including 2.4 lakh Dak Sevaks, to drive service excellence and inclusive growth.

9.3.3.1.2 Aligned with the Union Budget 2025, this initiative facilitates India Post's strategic transition into a premier public logistics entity, accelerating its contribution toward the realization of Viksit Bharat.

9.3.3.1.3 The initiative aims to empower India Post's network, including Dak Sevaks, and facilitate its transition into a premier public logistics entity. The model is designed to align with the Union Budget 2025 and contribute to Viksit Bharat.

9.3.3.1.4 The model will assist India Post in assessing service delivery capabilities and identifying improvement areas. It subsumes inspection and Sevottam model parameters, focusing on accelerating feedback loops and assessment cycle times.

9.3.3.1.5 Encompasses Business Maturity, SERVQUAL Maturity, Process, Employee, and Customer dimensions.

9.3.3.2 Scheme for "Made in India" Label:

9.3.3.2.1 Scheme for Made in India Label has been included in the 125-days agenda of the government.

9.3.3.2.2 The EFC note detailing the scheme's governance structure, financial outlay, and future roadmap has been forwarded to the appropriate authority for review.

9.3.3.2.3 Scheme has been discussed at I-GOM successfully, with 20 ministers. The scheme is appreciated by all the ministers in the meeting and will be launched soon.

9.3.3.2.4 The initiative has progressed with Indian Steel Plants increasingly affixing the "Made in India" labels. Criteria for the scheme have been developed, focusing on Manufacturer Identity, Origin Criteria, and Quality Criteria. As of March 13, 2025, the scheme has reached a significant milestone, with 1 crore labels issued for steel products.

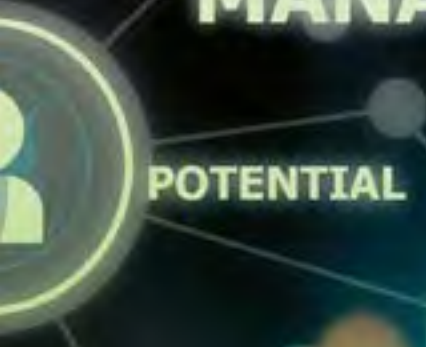
9.3.3.2.5 By next month, the note will be shared with other relevant ministries and bodies, including the Ministry of Finance and NITI Aayog, for their inputs, which will be incorporated accordingly.

9.3.3.2.6 Additionally, the MoU with the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) for granting MII label to KVIC products is set to be executed soon, starting with honey products.

PART
3

HR

HR MANAGEMENT



10 ANNUAL REVIEW OF HUMAN RESOURCES & ADMIN. ACTIVITIES

10.1 QCI Leadership Team

a) QCI Senior officials in position

- Shri Jaxay Shah, Chairperson, QCI.
- Shri Chakravarthy T. Kannan, Secretary General, QCI.

b) Chairpersons of QCI's constituent Boards (honorary position)

NABL - Padma Shri Prof. Subbanna Ayyappan, Chancellor, Central Agricultural University, Imphal; Chairman, Karnataka Science & Technology Academy, Bengaluru; and Adjunct Professor, NIAS, Bengaluru., upto 18.12.2024

&

Dr. Sandip, Shah, Joint Managing Director, Neuberg Supratech Lab, w.e.f. 19.12.2024

NABH - Padma Shri Prof. (Dr.) Mahesh Verma, Vice Chancellor, GGSIPU, upto 05.05.2024

&

Shri Rizwan Koita, Director, Koita Foundation, w.e.f. 06.05.2024

NABET - Shri Premendra Raj Mehta, former President of Council of Architecture India

NABCB - Dr. R.P. Singh, Provost (Vice Chancellor), Adani University, Ahmedabad

NBQP - Shri Vipin Sondhi, Former MD & CEO Ashok Leyland and JCB India. Former Chairman IISER, Bhopal. Chairman CII Mission on Tech, Innovation & Research and Future Mobility

c) Chief Executive Officers (CEOs) of QCI's constituent Boards

NABH	Dr. Atul Mohan Kochhar
NBQP	Dr. Aishvarya Raj
NABET	Prof (Dr.) Varinder S Kanwar
NABCB	Shri Rajesh Maheshwari
NABL	Shri N. Venkateswaran

d) HoDs of Boards / Divisions/Cells

PADD	Dr. Manish Pande, Director
PPID	Shri Subroto Ghosh, Principal Advisor
NDIE	Dr. Ramanand N Shukla, Sr. Director
SPD	Shri Rudraneel Chattopadhyay, Group Leader

10.2. Finance Committee

The constitution of Finance Committee is as under:

Current constitution

1. Shri Vinod Sharma, MD, Deki Electronic Ltd. Member Executive Comm. Electronic Industries Association of India - Chairperson
2. Shri Hemant Navinchandra Shah, Chair, Gujarat Chapter, PHDCCI - Member
3. Shri Jitendra Thakker, Chairman, Advisory Council (Constitution) & Member-Executive Committee - Member
4. Dr. Sandip Shah, Chairperson, NABL - Member
5. Incharge , (F&A) - Ex-officio

10.3 Details of QCI officials in position against sanctioned posts (as on 31.03.2025)

Post	In position
Secretary General	1
Chief Executive Officer	5
Sr. Director	1
Director	10
Joint Director	23
Deputy Director	49

Assistant Director	74
Accreditation Officer	39
Executive Officer	36
Executive Officer Trainee	1
Administrative Officer	7
Sr. Executive Assistant	1
Executive Assistant	5
Accounts Officer	3
Sr. Accountant	1
Sr. Office Assistant	2
Total	**258**

In addition to the above hirings, QCI has engaged professionals on short-term which are project specific and need-base.

10.4 Promotions of the regular employees

During the period of the report, 12 QCI officials, as per the details below, were promoted:

Promoted (from to)	No. of Employees
Joint Director to Director	1
Deputy Director to Joint Director	2
Assistant Director to Deputy Director	3
Accreditation Officer to Assistant Director	6

10.5 Details of GB/GC meetings

Governing Council	26th Meeting, September 25, 2024
Governing Body	75th Meeting, July 10, 2024
	76th Meeting, September 25, 2024
	77th Meeting, December 23, 2024
	78th Meeting, March 27, 2025

10.6 Attrition

During the period of report, 20 QCI officials working against the sanctioned posts were relieved from their respective posts (on account of resignation / superannuation / completion of term).

10.7 Internal Complaint Committee (ICC)

The POSH Act, or the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, is a law in India designed to protect women from sexual harassment at the workplace. It mandates organizations to establish policies, procedures, and an internal committee (ICC) to handle complaints.

In alignment with this, an Internal Complaint Committee was constituted in QCI. The primary role of members of this committee is to interact with female employees of the organization, create awareness, and flag the issues being faced by them (if any). Members of this committee meet at specified time intervals and review the cases received. In this period, three complaints were received from female employees and the same was dealt and closed within the stipulated time.

Constitution of ICC:

Smt. Madhu Ahluwalia, Sr. Advisor, NABET	Chairperson
Smt. Punam Bajaj, Director NABH	Member
Smt. Mallika Gope, Director, NABL	Member
Dr. Hari Prakash, Director, PPID	Member
Smt. Varsha Misra, Deputy Director, NABCB	Member
Smt. Pooja Shukla, Deputy Director, NBQP	Member
Smt. Manju Bagai, Legal Consultant	Outside Expert
Smt. Smita Bharti, Assistant Advisor, Ethics Cell	Convenor

10.8 Use of Hindi in Official work

Hindi Cell of the QCI promotes use of Official Language Hindi in the working of Council and facilitates officers/employees with translation of documents and workshops on Official Language policy etc. During the year under report, Hindi cell conducted five Hindi workshops. 31 officers and 38 employees participated in these workshops and learnt about the official language policy of Government of India, use of easy Hindi vocabulary in their day-to-day work and submitting Quarterly Progress Reports.

A Hindi fortnight was organised from September 14 to 29, 2024 wherein 05 competitions were organised. The event was a grand success, with participation of 226 officials of the Council, in all. Winners were awarded with cash prizes.

During the year, 4 meetings of Official Language Implementation Committee (OLIC) were held and progress made in the use of Hindi was reviewed.

Quarterly & Annual Reports pertaining to progressive use of Hindi were submitted to the OL Division of DPIIT, Ministry of Commerce and Industry.

Efforts have been made to provide timely translation of agreements, advertisements, reports, promotional material, flyers etc. so that these are published, both in Hindi and English.







Glimpses of the major activities organized by Hindi Cell for promotion of Hindi in QCI during the financial year

10.9 Update on Significant activities:

a) MoUs Signed

NABL

- Memorandum of Understanding (MoU) signed between National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) and PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI) at Ahmedabad on April 24, 2024.
- The primary objective of this MoU is to create awareness among the PHDCCI about NABL Accreditation so as to improve the quality products and services of the members.





Memorandum of Understanding (MoU) signed between NABL and PHDCCI

- Memorandum of Understanding (MoU) signed between National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) with the Engineering Export Promotion Council of India (EEPC) at Delhi on September 26, 2024.





Memorandum of Understanding (MoU) signed between NABL and EEPC

- MoU signed between NABL and Confederation of Real Estate Developers' Associations of India (CREDAI)

  NABL signed an MoU with CREDAI at New Delhi on November 26, 2024. The MoU was signed by NABL CEO Mr. N. Venkateswaran, CREDAI's President-elect Mr. Shankar G. Patel in the esteemed presence of Hon'ble Minister Shri Piyush Goyal and Chairman QCI Mr. Jaxay Shah.



MoU signed between NABL & Confederation of Real Estate Developers' Associations of India (CREDAI)

NABH

NABH Collaborated with Research Society for the Study of Diabetes in India, India's largest Diabetes Association, comprising over 12,000 members. The MoU was signed by Shri Rizwan Koita (Chairperson, NABH) and Dr Atul Mohan Kochhar (CEO, NABH).

Under this partnership, RSSDI and NABH-QCI, will collaborate on three key areas:

- Development of diabetes-specific standards by NABH, aligned with RSSDI care guidelines
- Development of diabetes-specific standards by NABH for Electronic Medical Records (EMR) and Clinic Management Systems (CMS)
- Roll-out of NABH Allopathic Clinic standards across the RSSDI member network.
- **NABH Collaborated with Association of Healthcare Providers India (AHPI)** for organizing Awareness Programs and Capacity Building Activities for promoting hospitals in the State of Gujarat for Entry-Level Certification Program and Ayush Entry-Level Certification Programme in tier III cities and rural areas.
- **NABH Collaboration with Government of Gujarat-** NABH has successfully submitted the proposals to the Government of Gujarat, outlining a comprehensive framework aimed at enhancing the quality of healthcare services across the state.
- 03 proposals have been accepted by the Ministry of health, Government of Gujarat and work order has been received.

NABET

1. MSME LEAN Division

- On April 1, 2024, QCI signed an MoU with **Laghu Udyog Bharti** on having its extensive network of MSMEs to increase the reach of MSME Competitive Lean Scheme of M/o MSME on PAN India basis (Laghu Udyog Bharti has more than 52,000 members across 578 Districts in 27 states across India)



MoU Signing with M/s Laghu Udyog Bharti (April 1, 2024)

- On August 13, 2024, QCI signed an MoU with **IIA (Indian Industry Association)**, on having its extensive network of MSMEs to increase the reach of MSME

Competitive Lean Scheme of M/o MSME (IIA have extensive network of more than 50 chapters & 12000 MSMEs spread in most of the industrialized districts of U.P, Delhi, Uttarakhand, and surrounding states.)



MoU Signing with IIA (August 13, 2024)

- On September 5, 2024, QCI signed an MoU with **M/s Monte Carlo** for spreading the benefits of MSME Competitive Lean Scheme of M/o MSME to the supply chain of M/s Monte Carlo (M/s Monte Carlo has an extensive supply chain of more than 200+ vendors spread across Punjab)



MoU Signing with M/s Monte Carlo (September 5, 2024)

- On September 6, 2024, QCI signed an MoU with **M/s Avon Cycles** for spreading the benefits of MSME Competitive Lean Scheme of M/o MSME to the supply chain of M/s Avon Cycles (M/s Avon Cylces has an extensive supply chain of more than 200+ vendors spread across in the State of Punjab & Bihar)



MoU with M/s Avon Cycles (September 6, 2024)

- On September 17, 2024 QCI signed an MoU with **M/s J.K. Tyre & Industries Ltd.** for spreading the benefits of MSME Competitive Lean Scheme of M/o MSME to the supply chain of M/s J.K.Tyre & Industries Ltd. (M/s J K Tyre & Industries Ltd. has an extensive supply chain of more than 200+ vendors spread across in St India)



MoU with M/s J K Tyre & Industries Ltd. (September 17, 2024)

- On November 7, 2024, QCI signed an MoU with **International Automobile Centre of Excellence (iACE)** to empower the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) of the Automotive sector, by way of driving the units through the Lean Manufacturing Journey under MSME Competitive Lean Scheme (MCLS) of M/o MSME.



MoU with IACE (November 15, 2024)

- On December 6, 2024, QCI signed an MoU with **M/s Forbes Marshall** for spreading the benefits of MSME Competitive Lean Scheme of M/o MSME to the supply chain of M/s Forbes Marshall which are spread across India.



MoU with M/s Forbes Marshall (December 6, 2024)

2. Formal Education Excellence Division (FEED Division)

- QCI signed an MoU with the **Uttar Pradesh State Medical Faculty on June 18, 2024** for a period of 3 years to conduct inspections of Nursing and Paramedical
- QCI signed an MoU with **Shri Shyamlal Gupta Hindi Vidyalaya, Satpur on October 7, 2024** for Quality Interventions in teaching learning process under Quality City Nashik Education Project.
- QCI signed an MoU with **ConveGenius Digital India Services Private Limited** for the Assessment of students on **March 20, 2025.**

NABCB

- NABCB signed an MoU with FSSC Foundation for FSSC 22000 & FSSC 24000 Scheme on March 19, 2025.
- NABCB signed an MoU with International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) for ISCC Certification System on February 3, 2025.

PADD

- QCI signed an MoU with **Andhra Pradesh Drone Corporation** to **advance drone technology and certification** on **October 22, 2024.**

  The Quality Council of India desires to extend technical support to A.P. Govt. in different agriculture and allied sector and intend to develop cooperation and collaboration in developing and designing conformity assessment framework, training, rendering accreditation services, capacity building of local and state-level institutions and other agreed activities that further the aims and objectives of the Institutions.

- QCI signed an MoU with **Indian Institute of Forest Management (IIFM)** for **advance Indian Forest & Wood Certification Scheme – PRAMAAN on August 5, 2024.**

  The Quality Council of India signed an MoU with IIFM for advance Indian Forest & Wood Certification Scheme – PRAMAAN, owned by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. QCI is serving as the knowledge partner for the Indian Institute of Forest Management (IIFM) in promoting and piloting the Indian Forest and Wood Certification Scheme (IFWCS), developing conformity assessment frameworks, and building the capacity of certification bodies.

- QCI signed an MoU with **National Skill Development Corporation (NSDC)** for **initiatives including training institution accreditation, city-level interventions, collaboration** on **medical tourism, and certification of skilled professionals on March 13, 2025.**

- QCI signed an MoU with **Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (MoA&FW)** to **assist them in designing framework for assessing indigenous content of Kisan drones** on March 2025.

  The Quality Council of India signed an MoU with MoA&FW for strengthening sustainable agriculture through capacity building, skill development, and enhanced quality assurance frameworks with improved certification and accreditation systems. It also promotes digital technologies and mechanization, such as drones, to boost productivity and farmer welfare. This collaboration aims to enhance efficiency, sustainability, and resilience in the agricultural sector.

NDIE

- MoU signed with Assam Small Industries Development Corporation Ltd. (ASIDC), Government of Assam on March 17, 2025
- MoU signed with Directorate of Industries, Government of Uttarakhand on March 26, 2025
- MoUs signed with Monte Carlo and Avon Cycles at Ludhiana on September 5, 2024 and September 6, 2024, respectively.
- MoU signed with Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam (MPLUN) on October 3, 2024 to propagate ZED Scheme in Madhya Pradesh

b) Right to Information

Quarter	No. of RTI Applications received / transferred / responded/ carry forwarded (within time limits)	No. of First Appeals Received/ responded
1st Quarter (April 1, 2024 to June 30, 2024) including opening Balance	87 (includes 27 as opening balance)	10 (includes 03 as opening balance)
2nd Quarter (July 1, 2024 to September 30, 2024)	62	06
3rd Quarter (October 1, 2024 to December 31, 2024)	61	06
4th Quarter (January 1, 2025 to March 31, 2025)	55	05
Total	**265**	**27**

c) Public Grievances

Received on CPGRAMS	No. of PGs	Replied	No. of Appeals received	Replied
Received from portal	35 (includes 03 received from DPIIT through e-mail)	33	07	07
Received from other dept./ministries	0	0	0	0

d) Transparency Audit

Transparency Audit of QCI for the FY 2023-24 was done by NPC and based on the same QCI was awarded **Grade A (100%).**

10.10 Investing in our People - Employee engagement Activities:

a) Trainings/ Webinars

- Behavioral Skills training/Webinar (Online)

Training name	Training date	Participants
Awareness session on Food Hygiene and Quality	November 14, 2024	120
Business Communication	December 11, 2024	240
Emotional Intelligence	December 19, 2024	155
Leadership Skills	January 10, 2025	184
Personality Development	January 17, 2025	142
Conflict Management	January 31, 2025	109
Ownership and Change Adaptability	February 7, 2025	96
Prioritization and Time Management	February 14, 2025	85
Ethics Management	February 21, 2025	79
Interpersonal Skills	February 28, 2025	98
Celebrating Women Leadership at the Workplace on International Women's Day	March 13, 2025	97
Empathy in Day-to-Day Work life	March 21, 2025	69
Grand Total		**1474**

b) Skill development programs

- Data Analytics Certification Course for Employees (Offline) - Course Structure: A training program was held for 3 days, consisting of a total of 5 sessions. An assessment was conducted one week after the completion of the course to evaluate participants' understanding and application of the material.

Training name	Training date	Participants
Data Analytics Certification Course for Coordinators	January 14, 2025, January 15, 2025, January 17, 2025	39
Data Analytics Certification Course for Analysts	February 18, 2025, February 19, 2025, February 20, 2025	34
Data Analytics Certification Course for Assistant Managers	March 15, 2025, March 16, 2025, March 17, 2025	34
Grand total		**107**

c) Employee engaging activities

- **EYE Camp (September 24 - October 16, 2024)** – Free Eye Care Camp for employees was organized, providing check-ups for dry eye, cataract, retina, colour blindness, as a part of its employee wellness initiative.
- **Diwali (October 30, 2024)** – Various team-building activities were organized like Rangoli Making, Office Decoration Competitions, Sweet-Making Contest, Best Dressed Awards, and Diwali Mela with carnival games and snacks, promoting employee engagement and festive spirit.
- **Men's Day (November 19, 2024)** – QCI successfully celebrated Men's Day on November 19th with an engaging Shave & Grooming Challenge, where participants showcased various beard styles and haircuts, making the event interactive and fun.
- **Christmas (December 20, 2024)** – competitions like 'Create Your Christmas Tree', Secret Santa Exchange, and festive sales by QCI employees were organized, promoting team spirit and holiday cheer.
- **Employee Banking Benefits (January 28 - February 4, 2025) & (March 19 - March 20, 2025)** – Successfully completed campaigns focused on providing employees with comprehensive banking benefits, including access to exclusive banking products, financial planning resources, retirement savings options, home loan assistance, personalized investment advice, and insurance coverage.
- **Holi (March 12, 2025)** – QCI organized a vibrant and inclusive Holi event with eco-friendly herbal colours, traditional food, and music to enhance the event, fostering unity and joy among employees while creating lasting memories.

d) Initiatives for good governance

- **National Unity Day (October 31, 2024)** – On this occasion, were engaged in the spirit by inviting to share short slogans reflecting unity and togetherness.
- **Vigilance Week Slogan (October 30 - November 3, 2024)** – During the Vigilance Awareness Week various activities were organized, including a pledge-taking ceremony, banner display, poster-making competition, debate/ group discussion, and slogan-writing competition. The week reinforced our commitment to integrity, transparency, and accountability, inviting all from QCI to join hands in the fight against corruption.
- **World Quality Day, (November 14, 2024)** - QCI successfully hosted a World Quality Day webinar on 14th November 2024, titled as 'Awareness Session on Food Hygiene and Quality,' covering essential food safety practices, contamination risks, and the importance of certification and accreditation in food safety.
- **Constitution Day (November 26, 2024)** – QCI successfully marked Constitution Day with a Quiz Competition, where participants tested their knowledge on the Constitution of India, its history, fundamental rights, government structure, and key provisions that shape the country's laws.
- **Women's Day (March 8, 2025)** – International Women's Day was celebrated with activities including the 'Women's Mini Olympics 2025' where various sports activities were organized for the female staff. Also, a webinar was organized on 'Celebrating Women Leadership at the Workplace' by Dr. Upasana, and a survey to gather success stories and women who inspire us.



Rangoli Making Competition



Sweet Making Competition






Best Dressed (Male & Female) Competition

PART
4

11 FINANCIAL STATEMENT



T R CHADHA & CO LLP

Independent Auditor's Report

To the members of Quality Council of India

Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of Quality Council of India ("the Society"), which comprise Balance Sheet as at 31st March 2025, Income & Expenditure Account and cash flow statements for the year ended 31st March 2025 including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "Financial Statements").

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Society as at March 31, 2025, and of its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with accounting principles generally accepted in India.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountant of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Society in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

The Society's Management is responsible for the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Society in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Society and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, management is responsible for assessing the Society's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Society or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The management of the society is also responsible for overseeing the Society's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements,

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the society's internal financial control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of Management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Society's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Society to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statement that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decision of a reasonably knowledgeable user of the financial statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factor in (i) Planning the scope of our audit work and evaluating of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified of any misstatements in the financials statement.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Further to the comment in para above, we report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b. In our opinion, proper books of account as required by the Law have been kept by the Society so far as it appears from our examination of those books.

c. The Balance Sheet, the Income and Expenditure and cash flow statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

For T R Chadha & Co LLP
Chartered Accountants
(Firm Registration No – 006711N/N500028)

Rajendra Prasad
(Partner)
Membership No. 098941
UDIN: 25098941BMLMSJ1126

Place: Noida
Date: 19-09-2025

QUALITY COUNCIL OF INDIA

BALANCE SHEET

(All amounts in INR, unless otherwise stated)

Particulars	Note	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Sources of funds			
I. Fund balances			
Corpus fund	2	1,03,00,000	1,03,00,000
Reserves and surplus	3	8,45,33,81,417	6,86,07,82,850
Sub-total (I)		**8,46,36,81,417**	**6,87,10,82,850**
II. Non-current liabilities			
Long-term Provisions	4	24,36,01,624	21,67,37,821
Sub-total (II)		**24,36,01,624**	**21,67,37,821**
III. Current liabilities			
Sundry creditors			
- Total outstanding dues of micro, small and medium enterprises		2,17,64,009	3,69,87,976
- Total outstanding dues of creditors other than micro, small and medium enterprises		12,68,51,543	18,19,58,354
Unspent grants	5	12,33,56,708	8,12,94,628
Short-term borrowing	6	2,35,00,00,000	-
Other current liabilities	7	1,15,24,51,206	54,81,01,367
Short-term Provisions	8	6,09,43,578	3,43,01,374
Sub-total (III)		**3,83,53,67,044**	**88,26,43,699**
Total (I+II+III)		**12,54,26,50,085**	**7,97,04,64,370**
Applications of funds			
I. Non-current assets			
Property, plant and equipment	9A	11,35,08,679	10,90,49,480
Intangible assets	9B	19,71,000	26,28,001
Capital work-in-progress	9C	4,96,35,36,595	-
Long term Investment	10	42,50,99,990	42,50,99,990
Sub-total (I)		**5,50,41,16,264**	**53,67,77,471**
II. Current assets			
Sundry debtors	11	84,04,20,253	96,70,77,473
Cash and bank balances	12	5,31,18,25,801	5,75,00,98,434
Short-term loans and advances	13	71,05,04,707	56,81,07,114
Other current assets	14	17,57,83,060	14,84,03,878
Sub-total (II)		**7,03,85,33,821**	**7,43,36,86,899**
Total (I+II)		**12,54,26,50,085**	**7,97,04,64,370**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

As per our report of even date attached

For **T R Chadha & Co LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 006711N/N500028

For and on behalf of **Quality Council of India**

Rajendra Prasad
Partner
Membership No. 098941

Place: Noida
Date: 19-09-2025

Chakravarthy T Kannan
(Secretary General)

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

Jaxay Shah
(Chairman)

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

QUALITY COUNCIL OF INDIA

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

(All amounts in INR, unless otherwise stated)

Particulars	Note	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
Income			
Revenue from operations	15	6,26,04,35,017	5,69,37,40,823
Other income	16	36,22,25,616	33,29,28,761
Total income:	**(A)**	**6,62,26,60,633**	**6,02,66,69,584**
Expenditure			
Honorarium and assessment charges		1,21,25,40,943	1,10,53,45,628
Interest expenses		5,93,98,522	-
Grant expenses		1,68,62,16,860	1,73,43,67,977
Employee benefit expenses	17	68,56,28,061	57,04,35,877
Depreciation and amortization expense	18	2,00,49,746	1,80,42,994
General and administrative expenses	19	1,36,62,27,934	1,33,99,17,503
Total expenditure:	**(B)**	**5,03,00,62,066**	**4,76,81,09,979**
Excess of Income over expenditure (excess of expenditure over income) transferred to Reserve and Surplus	(A-B)	**1,59,25,98,567**	**1,25,85,59,605**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

As per our report of even date attached

For **T R Chadha & Co LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 006711N/N500028

Rajendra Prasad
Partner
Membership No. 098941

Place: Noida
Date: 19-09-2025

For and on behalf of **Quality Council of India**

Chakravarthy T Kannan
(Secretary General)

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

Jaxay Shah
(Chairman)

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

(This space has been intentionally left blank)

QUALITY COUNCIL OF INDIA

NOTE 1: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1.1 Background: Society information

Quality Council of India (QCI) (the "Society") was incorporated in 21 January 1997 as a non-profit autonomous Society registered under Societies Registration Act XXI of 1860. The Society plays a pivotal role in propagating, adoption and adherence to quality standards in all important spheres of activities including education, healthcare, environment protection, governance, social sectors, infrastructure sector and such other areas of organized activities that have significant bearing in improving the quality of life and well-being of the citizens of India. Society is registered u/s 12AB (erstwhile 12AA) of the Income Tax Act, 1961 vide unique registration number AAATQ0055DE20217 dated 11-03-2022, with the object clauses "Education, Medical Relief, Preservation of Environment (including watersheds, forests and wildlife) and advancement of any other objects of general public utility, which is valid from Assessment Year 2022-23 to AY 2026-27 and is renewable every five years.

1.2 Basis of preparation

The financial statements are prepared under historical cost convention on an accrual basis except as stated otherwise, in accordance with the accounting principles generally accepted in India for not for profit organizations including the accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India to the extent considered relevant for the organization.

These financial statements have been prepared on a going concern basis and the accounting policies have been consistently applied by the Society, except as stated otherwise.

1.3 Summary of significant accounting policies

(a) Income recognition

Revenue is recognized on an accrual basis when the ultimate collection is estimated by the management:

- Application fees for the assessment and accreditation is being recognized as income on receipt basis.
- Income from assessment, accreditation charges and project implementation is recognized when it is approved by the technical committees of the respective boards/ divisions.
- Grant is initially recognized as liability. Grant income is recognized as income to the extent of its utilization. Unspent grant is shown as current liabilities.
- Annual accreditation fee is recognized upon issuance of certificate by Conformity Assessment Body (CAB) after approval by the technical committee of the respective divisions/ boards.
- Interest income other than interest on income tax refund is recognized using time proportion method, based on the rate implicit in the transaction.
- Interest on income tax refund is recognized on receipt basis.

(b) Expenses

Expenses are recognized in accordance when it is approved by the technical committees of the respective board/ divisions.

Ex-gratia is being accounted on cash basis.

(c) Corpus fund

"Corpus fund" relates to funds contributed by the founder members/donors at incorporation shall form part of the corpus of the Society.

(d) Investments:

Long term Investments are stated at cost. However, provision is made to recognize a decline, other than temporary, in the value of investments.

Investments in Subsidiaries, Joint ventures and Associates are carried at cost. However, provision is made to recognize a decline, other than temporary, in the value of investments.

Current investments: Current investments are carried at market value as at the end of the reporting period.

(e) Property, plant and equipment and depreciation

Property, plant and equipment are stated at their cost of acquisition. Following initial recognition, property, plant and equipment are carried at cost less any accumulated depreciation. The cost comprises purchase price and directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for the intended use. Any trade discount and rebates are deducted in arriving at the purchase price. Depreciation on fixed assets is provided at the rates specified under the Income Tax Rules, 1962 on written down value method. The rates of depreciation are indications of the useful lives of the assets. Rate of depreciation are as follows:

- Vehicle - 15%
- Furniture & Fixtures - 10%
- Office Equipment - 15%
- Computer & Software - 40%
- Building – 10%

(f) Intangible assets and amortization

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization. Amortizations on intangible assets is provided at the rates specified under the Income Tax Rules, 1962 on written down value method. The rates of amortizations are indications of the useful lives of the assets. Rate of depreciation are as follows:

- Trade-marks - 25%
- Intellectual property rights - 25%

(g) Foreign currency transactions

Initial Recognition:

Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of the transaction.

Conversion:

Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

Exchange Differences:

Exchange differences arising on the settlement of monetary items, or on reporting such monetary items of the Society at rates different from those at which they were initially recorded during the year, or reported in previous financial statements, are recognized as income or as expenses in the year in which they arise.

(h) Employee benefits:

Short term employees' benefits

All employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service are classified as short term employee benefits. Benefits such as salaries, wages and bonus etc. are recognized in the statement of profit and loss in the period in which the employee renders the related service.

A defined contribution plan:

Defined contribution plan is a post-employment benefit plan under which an entity pays fixed contributions into separate entities and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for contributions to defined contribution plans are recognized as an employee benefits expense in profit or loss in the period during which services are rendered by employees.

The Company makes specified monthly contributions towards employee provident fund to Government administered provident fund scheme which is a defined contribution plan. The Company's contribution is recognized as an expense in the statement of profit and loss during the period in which the employee renders the related service.

Defined Benefit Plans:

A defined benefit plan is a post-employment benefit plan other than a defined contribution plan.

Gratuity is defined benefit plan.

Society's liability towards gratuity is calculated on the basis of actuarial valuation carried out by an independent actuary on the balance sheet date. The gratuity liability is calculated using the Projected Unit Credit Method, which recognizes each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measure each unit separately to build up the final obligation. The obligation is measured at the present value of estimated future cash flows. The discount rates used for determining the present value of obligation, is based on the market yields on government bonds as at the balance sheet date, having maturity periods approximating to the terms of related obligations. Remeasurements of the net defined benefit liability, which comprise actuarial gains and losses are recognized in the statement of other comprehensive income. Gains or losses on the curtailment or settlement of any defined benefit plan or long term employee benefit are recognized when the curtailment or settlement occurs.

Other long-term benefits

Compensated Absences:

The employees can carry-forward a portion of the unutilized accrued compensated absences and utilize it in future service periods or receive cash compensation on termination of employment. Since the compensated absences do not fall due wholly within twelve months after the end of the period in which the employees render the related service and are also not expected to be utilised wholly within twelve months after the end of such period, the benefit is classified as a long-term employee benefit. The Society records an obligation for such compensated absences in the period in which the employee renders the services that increase this entitlement. The obligation is measured on the basis of independent actuarial valuation using the projected unit credit method.

Superannuation:

The Society contributes 15% of annual basic salary every year as the contribution towards the account of every employee and recognized on accrual basis. Superannuation Reserve fund is maintained with LIC and governed by rules of LIC and contribution to LIC is accounted.

(i) Current tax and Deferred Tax

The Society is exempt from income tax under Section 12AA of the Income-tax Act, 1961 ("Act") and accordingly no provision for taxation is required. Since the Society is exempt from Income tax, no deferred tax (asset or liability) is required to be recognized in respect of timing differences.

(j) Provisions and contingencies

The Society makes a provision when there is a present obligation as a result of a past event where the outflow of economic resources is probable and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

A disclosure is made for a contingent liability when there is a:

- possible obligation, the existence of which will be confirmed by the occurrence/non-occurrence of one or more uncertain events, not fully within the control of the society;
- present obligation, where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation;
- present obligation, where a reliable estimate cannot be made.

(k) Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities on the date of the financial statements and the results of operations during the reporting periods. Although these estimates are based upon management's knowledge of current events and actions, actual results could differ from those estimates and revisions, if any, are recognized in the current and future periods.

QUALITY COUNCIL OF INDIA

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(Prepared as per indirect method, in accordance with accounting standard - 3 of ICAI)

(All amounts in INR, unless otherwise stated)

Sl. No.	Particulars	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
A	**Cash flow from operating activities**		
	Surplus before tax and extraordinary items	**1,59,25,98,567**	**1,25,85,59,605**
	Adjustments for non-cash and non-operating Items		
	Add: Depreciation	2,00,49,746	1,80,42,994
	Less: Interest income	(36,22,25,616)	(33,29,28,761)
	Add: Interest expense	5,93,98,522	-
	Add: Increase in provision for gratuity	2,03,36,625	82,77,718
	Add: Increase in provision for leave encashment	2,56,30,516	1,57,76,556
	Add: Increase in provision for superannuation	75,38,866	22,38,603
	Operating surplus before working capital changes	1,36,33,27,226	96,99,66,715
	Adjustments for changes in working capital		
	(Increase)/ decrease in sundry debtors	12,66,57,220	(9,91,23,108)
	(Increase)/ decrease in loans and advances	(14,23,97,593)	(3,42,12,658)
	(Increase)/ decrease in other current assets	(4,02,75,145)	(4,03,14,001)
	Increase/ (decrease) in sundry creditors	(7,03,30,778)	14,57,30,779
	Increase/ (decrease) in unspent grants	4,20,62,080	(6,50,512)
	Increase/ (decrease) in other current liabilities	60,43,49,839	32,06,36,999
	Net cash flow from operating activities	**1,88,33,92,849**	**1,26,20,34,214**
B	**Cash flow from investing activities**		
	Purchase of fixed assets	(4,98,73,88,539)	(2,70,98,393)
	Add: Sale proceeds from disposal of fixed assets	-	-
	Purchase of investments	-	(30,00,00,000)
	Proceeds from/(to) term deposit	2,09,96,79,051	1,22,45,97,604
	Add: Interest received	37,51,21,579	34,46,26,044
	Net cash flow from investing activities	**(2,51,25,87,909)**	**1,24,21,25,255**
C	**Cash flow from financing activities**		
	Proceeds from long term borrowings	2,35,00,00,000	-
	Less: Interest paid	(5,93,98,522)	-
	Net cash flow from financing activities	**2,29,06,01,478**	**-**
D	**Net increase/ (decrease) in cash and cash equivalents**		
	Increase in cash and cash equivalents (A+B+C)	**1,66,14,06,418**	**2,50,41,59,469**
	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	3,14,99,07,849	64,57,48,380
	Cash and cash equivalents at the end of the year	**4,81,13,14,267**	**3,14,99,07,849**

As per our report of even date attached

For **T R Chadha & Co LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 006711N/N500028

Rajendra Prasad
Partner
Membership No. 098941

Place: Noida
Date: 19-09-2025

For and on behalf of **Quality Council of India**

Chakravarthy T Kannan
(Secretary General)

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

Jaxay Shah
(Chairman)

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

QUALITY COUNCIL OF INDIA

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT

(All amounts in INR, unless otherwise stated)

Receipts	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024	Payments	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
Opening Balance			**Expenses**		
Balance with banks			Honorarium and assessment charges	1,21,25,40,943	49,06,45,957
- in savings accounts	1,56,89,64,271	61,10,83,111	Interest expenses	5,93,98,522	-
- in current accounts	4,85,40,808	2,94,83,974	Project expenses	-	1,02,42,99,532
- in bank deposits	4,13,25,44,006	3,82,98,34,798	Employee benefit expenses	68,56,28,061	55,08,60,826
Cash in Hand	49,349	1,34,686	General and administrative expenses	1,36,62,27,934	61,32,18,674
			Grant expenses	1,68,62,16,860	2,07,10,41,995
	5,75,00,98,434	**4,47,05,36,569**		**5,01,00,12,320**	**4,75,00,66,985**
Incomes					
Revenue from operations	6,26,04,35,017	5,69,37,40,823			
Other income			Purchases of Fixed Assets	2,38,51,944	2,70,98,393
Interest income from:			Purchase of Investments	-	30,00,00,000
- fixed deposits with banks	32,47,36,432	30,21,69,810	Capital Work in progress	4,96,35,36,595	-
- Income tax refund	1,46,37,040	1,04,35,809		**4,98,73,88,539**	**32,70,98,393**
- others	1,99,42,226	2,03,23,141			
Miscellaneous income	29,09,918	-	**Closing Balance**		
Liabilities written back	-	-	Balance with banks		
	6,62,26,60,633	**6,02,66,69,584**	- in savings accounts	1,57,84,81,418	1,56,89,64,271
			- in current accounts	3,39,21,472	4,85,40,808
Sales Proceeds from Fixed Assets	-	-	- in bank deposits	3,69,92,65,045	4,13,25,44,005
			Cash in Hand	1,57,861	49,349
Change in Assets/ Liabilities				**5,31,18,25,796**	**5,75,00,98,433**
Provision for Gratuity, Leave Encashment & Superannuation Fund	5,35,06,007	2,62,92,877			
Sundry Creditors	(7,03,30,778)	14,57,30,779			
Other Current Liabilities	60,43,49,839	32,06,36,999			
Revenue received in advance	*9,58,86,661*	*13,27,45,853*			
Receipts pending reconciliation	*(42,00,375)*	*1,31,50,324*			
Expenses payable	*46,41,43,454*	*(1,22,224)*			
Statutory dues	*4,59,88,794*	*17,56,89,064*			
Employee related payables	*27,56,457*	*(45,60,444)*			
Other payables	*(2,25,151)*	*37,34,426*			
Unpent grants	4,20,62,080	(6,50,512)			
Sundry Debtors	12,66,57,216	(9,91,23,110)			
Short term Loans & Advances	(14,23,97,593)	(3,42,12,657)			
Loans and advances to staff	*50,67,845*	*(13,41,534)*			
Advance to vendors	*(52,54,089)*	*(2,52,27,722)*			
Prepaid expenses	*(8,33,67,212)*	*1,41,68,068*			
Balance with government authorities	*1,24,08,124*	*93,97,224*			
Tax deducted at source	*(7,12,52,262)*	*(3,12,08,693)*			
Other Current Assets	(2,73,79,182)	(2,86,16,718)			
Security deposits	*(4,02,75,145)*	*(4,03,14,001)*			
Interest accrued on bank deposits	*1,28,95,963*	*1,16,97,283*			
Short-term Borrowing	*2,35,00,00,000*	-			
Capital Work-in-progress	-	-			
Adjustment to Fixed Assets	-	-			
	2,93,64,67,588	**33,00,57,658**			
Total	**15,30,92,26,655**	**10,82,72,63,811**	**Total**	**15,30,92,26,655**	**10,82,72,63,811**

As per our report of even date attached

For **T R Chadha & Co LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 006711N/N500028

Rajendra Prasad
Partner
Membership No. 098941

Place: Noida
Date: 19-09-2025

For and on behalf of **Quality Council of India**

Chakravarthy T Kannan
(Secretary General)

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

Jaxay Shah
(Chairman)

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

QUALITY COUNCIL OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 MARCH 2025

(All amounts in INR, unless otherwise stated)

Particulars	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Note 2		
Corpus fund		
Balance at the beginning of the year	1,03,00,000	1,03,00,000
Add: Addition or Deletion during the year	-	-
Balance at the end of the year	**1,03,00,000**	**1,03,00,000**
Note 3		
Reserves and surplus		
Balance at the beginning of the year	6,86,07,82,850	5,60,22,23,245
Add: Excess of income over expenditure transferred from income and expenditure account	1,59,25,98,567	1,25,85,59,605
Balance at the end of the year	**8,45,33,81,417**	**6,86,07,82,850**
Note 4		
Long term provisions		
Provisions for employee benefits:		
Gratuity	9,99,11,943	8,83,16,844
Earned leave encashment	14,36,89,681	12,84,20,977
Total	**24,36,01,624**	**21,67,37,821**
Provisions for Gratuity		
Current Liability (Shown in Short-term Provision Note 8)	1,09,87,047	22,45,521
Non-Current Liability (Shown in Long-term Provision Note 4)	9,99,11,943	8,83,16,844
	11,08,98,990	**9,05,62,365**
Provisions for Earned Leave Encashment		
Current Liability (Shown in Short-term Provision Note 8)	1,26,16,430	22,54,618
Non-Current Liability (Shown in Long-term Provision Note 4)	14,36,89,681	12,84,20,977
	15,63,06,111	**13,06,75,595**
Note 5		
Unspent grants #		
Government grants	12,26,33,210	8,05,71,130
Other grants	7,23,498	7,23,498
Total	**12,33,56,708**	**8,12,94,628**
Note 6		
Short-term Borrowing		
Secured Loan		
Term Loan		
From ICICI bank*	2,35,00,00,000	-
	2,35,00,00,000	**-**
Note 7		
Other current liabilities		
Revenue received in advance	31,62,36,254	22,03,49,593
Receipts pending reconciliation*	2,13,92,604	2,55,92,979
Expenses payable	46,50,77,454	9,34,000
Statutory dues	33,88,63,969	29,28,75,175
Employee related payables	41,83,325	14,26,868
Other payables	66,97,600	69,22,751
Total	**1,15,24,51,206**	**54,81,01,367**
Note 8		
Short term provisions		
Provisions for employee benefits:		
Gratuity	1,09,87,047	22,45,521
Earned leave encashment	1,26,16,430	22,54,618
Superannuation	3,73,40,101	2,98,01,235
Total	**6,09,43,578**	**3,43,01,374**

Refer note 26 for details.

*The Society has availed working capital loans from ICICI Bank to meet its working capital requirements, cover short-term mismatches, and fund normal capital expenditure. The loan carry interest at the Repo Rate plus an agreed spread and are secured by a hypothecation charge over the Society's entire current assets, including trade receivables, bank balances, and fixed deposits.

Notes:

* It represents such receipts and related payees where the purpose of receipts is not identified as at balance sheet date. The Society is in the process of identifying & reconciliation of these receipts and related payees thereto. In the management's view the same will be reconciled in due course.

QUALITY COUNCIL OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 MARCH 2025

(All amounts in INR, unless otherwise stated)

Note 9A

Property, plant and equipment

Particulars	Land	Buildings	Computer and softwares	Furniture and fixtures	Office equipments	Vehicles	Total
Balance as at 1 April 2023	1,15,50,176	3,59,50,376	86,97,321	2,58,57,557	1,63,69,392	6,93,258	9,91,18,079
Additions	-	-	1,27,05,873	52,96,782	90,95,738	-	2,70,98,393
Proceeds from disposals	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation charge	-	35,95,038	72,37,176	28,68,076	33,62,714	1,03,988	1,71,66,992
Balance as at 31 March 2024	**1,15,50,176**	**3,23,55,338**	**1,41,66,018**	**2,82,86,263**	**2,21,02,416**	**5,89,270**	**10,90,49,480**
Additions	-	-	1,19,01,184	29,60,169	65,49,342	24,37,730	2,38,51,944
Proceeds from disposals	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation charge	-	32,35,534	1,04,22,782	30,50,438	39,82,961	2,71,221	1,93,92,745
Balance as at 31 March 2025	**1,15,50,176**	**2,91,19,804**	**1,56,44,420**	**2,81,95,994**	**2,46,68,797**	**27,55,779**	**11,35,08,679**

Note 9B

Intangible assets

Particulars	Trademarks	Intellectual property rights	Total
Balance as at 1 April 2023	1,12,660	33,91,343	35,04,003
Additions during the year	-	-	-
Amortisation for the year	28,165	8,47,837	8,76,002
Balance as at 31 March 2024	**84,495**	**25,43,506**	**26,28,001**
Additions during the year	-	-	-
Amortisation for the year	21,124	6,35,877	6,57,001
Balance as at 31 March 2025	**63,371**	**19,07,629**	**19,71,000**

Note 9C

Capital work in progress

Particulars	Capital work in progress	Total
Balance as at 1 April 2023	-	-
Additions during the year	-	-
Amortisation for the year	-	-
Balance as at 31 March 2024	-	-
Additions during the year	4,96,35,36,595	4,96,35,36,595
Amortisation for the year	-	-
Balance as at 31 March 2025	**4,96,35,36,595**	**4,96,35,36,595**

(This space has been intentionally left blank)

QUALITY COUNCIL OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 MARCH 2025

(All amounts in INR, unless otherwise stated)

Particulars	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Note 10		
Long term Investment		
Investment in unquoted equity shares (measured at cost)		
Investment in Subsidiary (100% Subsidiary)*		
25,09,999 equity shares of Rs. 10 each fully paid up of Unnati Employment Network	2,50,99,990	2,50,99,990
Investment in Associate*		
40,00,000 equity shares of Rs. 100 each fully paid up of Open Network Digital Commerce (Promoted by Quality Council of India)	40,00,00,000	40,00,00,000
Total	**42,50,99,990**	**42,50,99,990**
*Refer note No. 27		
Note 11		
Sundry debtors		
Unsecured, considered good	84,04,20,253	96,70,77,473
Unsecured, considered doubtful	41,28,66,615	38,73,71,553
	1,25,32,86,868	**1,35,44,49,026**
Less: Provision for doubtful debs	41,28,66,615	38,73,71,553
Total	**84,04,20,253**	**96,70,77,473**
Note 12		
Cash and bank balances		
a) Cash & Cash Equivalents		
Balance with banks		
- in savings accounts	1,57,84,81,418	1,56,89,64,271
- in current accounts	3,39,21,472	4,85,40,808
- in Bank deposits maturing within 3 months from the reporting date	3,19,87,53,515	1,53,23,53,421
Cash on hand	1,57,861	49,349
	4,81,13,14,267	**3,14,99,07,849**
b) Other Bank Balances		
Bank Deposits pledged	7,56,52,823	8,56,95,791
Bank Deposits having maturity date more than 3 months	42,48,58,712	2,51,44,94,794
	50,05,11,534	**2,60,01,90,585**
Total	**5,31,18,25,801**	**5,75,00,98,434**
Note 13		
Short-term loans and advances		
(Unsecured, considered good)		
Loans and advances to staff	61,09,869	1,11,77,714
Advance to vendors	5,39,33,153	4,86,79,064
Prepaid expenses	8,53,18,713	19,51,501
Balance with government authorities[#]	4,83,19,126	6,07,27,250
Tax deducted at source[^]	51,68,23,847	44,55,71,585
Total	**71,05,04,707**	**56,81,07,114**

Notes:

#Includes amount paid under protest for various cases for INR 4,18,07,307 (31 March 2024: INR 4,18,07,307), for further details refer note 20.

^The management of the society is in process of reconciling the income recognized during the year ended 31 March 2024 as per the statement of tax credit as reflected on income-tax department portal. Tds receivable includes unmapped tds of INR 1,87,68,453 (31 March 2024: 1,17,72,540). As per view of the management of the society, no significant variations are likely to arise on account of such reconciliations.

Note 14		
Other current assets		
Security deposits	13,21,77,587	9,19,02,441
Interest accrued on bank deposits	4,36,05,474	5,65,01,437
Total	**17,57,83,060**	**14,84,03,878**

QUALITY COUNCIL OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 MARCH 2025

(All amounts in INR, unless otherwise stated)

Particulars	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
Note 15		
Revenue from operations		
Quality application, assessment and accreditation fees	2,55,39,93,506	2,13,70,31,370
Projects income	1,42,07,46,612	1,79,60,02,227
Seminar receipts and miscellaneous receipts	10,90,97,293	5,40,52,557
Grant income	2,14,94,92,694	1,70,66,54,669
Unbilled income	2,70,94,913	-
Membership fees	10,000	-
Total	**6,26,04,35,017**	**5,69,37,40,823**
Note 16		
Other income		
Interest income from:		
- fixed deposits with banks	32,47,36,432	30,21,69,810
- income tax refund	1,46,37,040	1,04,35,809
- others	1,99,42,226	2,03,23,141
Miscellaneous income	29,09,918	-
Liabilities written back	-	-
Total	**36,22,25,616**	**33,29,28,761**
Note 17		
Employee benefit expenses		
Salaries, ex-gratia and other benefits	55,19,16,426	46,37,75,435
Contribution to provident and other funds	2,95,22,367	2,56,32,581
Gratuity expense	2,63,41,208	1,41,84,224
Leave encashment expense	3,29,86,489	2,00,05,685
Superannuation expense	3,52,65,446	3,05,29,668
Staff welfare expenses	95,96,125	1,63,08,284
Total	**68,56,28,061**	**57,04,35,877**
Note 18		
Depreciation and amortisation expense		
Depreciation on property, plant and equipment	1,93,92,745	1,71,66,992
Amortisation of intangible assets	6,57,001	8,76,002
Total	**2,00,49,746**	**1,80,42,994**
Note 19		
General and administrative expenses		
Rent expenses	11,47,31,528	8,21,78,110
Rates and taxes	66,63,015	34,29,781
Consultancy and professional fees	5,07,81,314	4,58,87,729
Professional fees for external consultants	31,55,57,338	36,03,27,069
Payment to auditor	8,52,000	7,15,000
Communication expenses	84,22,650	78,51,451
Travelling and conveyance	20,50,61,593	19,69,03,105
Bad debts	6,90,90,065	-
Office expenses	7,56,93,802	6,14,38,816
Power and fuel	1,34,29,273	1,01,08,265
Provision for doubtful debts - expense	2,54,95,064	6,97,31,929
Meeting expenses	7,26,08,477	6,74,59,315
Repair and maintenance	1,68,39,223	4,26,31,588
Promotional activities	22,99,20,312	22,92,32,994
Technology expenses	15,29,61,859	15,54,98,281
Membership fees - expense	15,14,613	45,95,496
Foreign exchange fluctuation loss	1,08,185	14,699
Miscellaneous expenses	64,97,621	19,13,875
Total	**1,36,62,27,934**	**1,33,99,17,503**

QUALITY COUNCIL OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 MARCH 2025

(All amounts in INR, unless otherwise stated)

Note 20

Contingent liabilities

A) Claims against the entity not acknowledged as debts:

Particulars	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
(i) Service tax		
(a) Cases pending at Supreme court in respect of which the Society has filed appeals	1,02,40,938	1,02,40,938
(b) Cases pending before Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal ("CESTAT") in respect of which the Society has filed appeals	17,54,25,373	17,54,25,373
Total	**18,56,66,311**	**18,56,66,311**
Amounts paid under protest against cases stated above	4,18,07,307	4,18,07,307

B) All the matters above stated by the Society are subject to legal proceedings in the ordinary course of operations. The management is confident that its position to be upheld in the appeals pending before various appellate authorities and no liability could arise on the Society on account of these proceedings.

C) Income tax cases:

The Income tax department has raised a demand of INR 4,94,98,085 for A.Y. 2016-17 u/s 143(3) of the Income-tax Act, 1961 against a refund of Rs. 2,32,61,362. An appeal has been filed by the Society against the said order before Commissioner of Income Tax (Appeals), Delhi, which is still pending. However, based on management's best assessment, the possibility of outflow of resources is remote. Therefore, no provision has been made in the books of accounts

D) The Following fixed deposits are under pledged:

Deposits with Bank	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Fixed Deposits with Axis Bank	1,14,79,098	3,05,46,404
Fixed Deposits with Kotak Bank	3,22,36,644	2,97,53,027
Fixed Deposits with ICICI Bank	2,06,99,065	-
Fixed Deposits with Standard Chartered Bank	1,12,38,016	-
Fixed Deposits with Yes Bank	-	2,53,96,360
Total	**7,56,52,823**	**8,56,95,791**

Note 21

Dues to micro and small enterprises pursuant to section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act (MSMED), 2006

On the basis of confirmation obtained from suppliers who have registered themselves under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006) and based on the information available with the Society, the following are the details:

Particulars	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
(i) the principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year.	2,17,64,009	3,69,87,976
(ii) the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16, along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year.	-	-
(iii) the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act, 2006.	-	-
(iv) the amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year; and	-	-
(v) the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding year, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act, 2006.	-	-
	2,17,64,009	**3,69,87,976**

QUALITY COUNCIL OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 MARCH 2025

(All amounts in INR, unless otherwise stated)

Note 22

Provision for employee benefits:

a) **Defined Contribution Plans:** The Society makes Provident Fund and Pension Fund contributions to defined contribution plans for qualifying employees. Under the Schemes, the Society is required to contribute a specified percentage of the payroll costs to fund the benefits. The Society has recognized following contribution as expense in the Statement of Profit and Loss. The contributions payable to these plans by the Company are at rates specified in the rules of the schemes.

Particulars	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
EPF- Employer's Contributions*	3,00,42,479	2,56,32,581
Total	**3,00,42,479**	**2,56,32,581**

** Amount shown above is inclusive of PF admin expense.*

b) **Defined Benefit Plans** : The Society has categorised its defined benefit plans as Gratuity, Leave Encashment, & Super Annuation Funds for its employees. The society recognises its liability towards Gratuity and Leave Encashment as per the Actuarial Valuation Report. The superannuation reserve fund is maintained with LIC and governed by rules of LIC for such funds. Society contributes 15% of annual basic salary as the contribution towards the account of every employee. The fund is transferred to LIC and paid accumulated amount to the employee at the time of his/her superannuation as per scheme of LIC.

Gratuity & Leave Encashment

The following table sets out the funded status of the defined benefit schemes and the amount recognized in the financial statements:

Expense recognized in the statement of profit and loss

	Leave Encashment		Gratuity	
Particulars	**Year ended 31.03.2025**	**Year ended 31.03.2024**	**Year ended 31.03.2025**	**Year ended 31.03.2024**
Current service cost	13,06,75,595	11,48,99,039	1,18,09,110	1,02,63,915
Past service cost	-	-	-	-
Interest cost	94,34,778	84,56,569	65,38,603	60,56,150
Expected Return on Plan Assets	-	-	-	-
Curtailment cost / (credit)	-	-	-	-
Settlement cost / (credit)	-	-	-	-
Actuarial losses/(gains)	(37,01,945)	3,56,04,943	79,93,495	(21,35,841)
Total expense recognized in the Statement of Profit and Loss	**13,64,08,428**	**15,89,60,551**	**2,63,41,208**	**1,41,84,224**

Net asset / (liability) recognized in the Balance Sheet

	Leave Encashment		Gratuity	
Particulars	**Year ended 31.03.2025**	**Year ended 31.03.2024**	**Year ended 31.03.2025**	**Year ended 31.03.2024**
Present Value of Obligation as at end of period	15,63,06,110	13,06,75,595	11,08,98,990	9,05,62,365
Fair Value of Plan Assets as at end of period on	-	-	-	-
Funded Status/ Difference	(15,63,06,110)	(13,06,75,595)	(11,08,98,990)	(9,05,62,365)
Excess of Actual over estimated	-	-	-	-
Unrecognized Actuarial (gains) / losses	-	-	-	-
Net Assets/(Liability) Recognized in Balance Sheet	**(15,63,06,110)**	**(13,06,75,595)**	**(11,08,98,990)**	**(9,05,62,365)**

(This space has been intentionally left blank)

QUALITY COUNCIL OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 MARCH 2025

(All amounts in INR, unless otherwise stated)

Change in present value of defined benefit obligation

	Leave Encashment		Gratuity	
	Year ended 31.03.2025	**Year ended 31.03.2024**	**Year ended 31.03.2025**	**Year ended 31.03.2024**
Present Value of Obligation at beginning of period	13,06,75,595	11,48,99,039	9,05,62,365	8,22,84,647
Acquisitions Adjustment	-	-	-	-
Interest cost	94,34,778	84,56,569	65,38,603	60,56,150
Past service cost	-	-	-	-
Current service cost	1,94,42,582	1,52,51,061	1,18,09,110	1,02,63,915
Curtailment cost / (credit)	-	-	-	-
Settlement cost / (credit)	-	-	-	-
Benefits Paid	(73,55,973)	(42,29,129)	(60,04,583)	(59,06,506)
Actuarial losses/(gains)	41,09,128	(37,01,945)	79,93,495	(21,35,841)
Present Value of Obligation at the end of period	**15,63,06,110**	**13,06,75,595**	**11,08,98,990**	**9,05,62,365**

Change in Fair Value of Plan Assets

	Leave Encashment		Gratuity	
	Year ended 31.03.2025	**Year ended 31.03.2024**	**Year ended 31.03.2025**	**Year ended 31.03.2024**
Fair Value of Plan Assets at beginning of period	-	-	-	-
Acquisitions Adjustment	-	-	-	-
Expected return on Plan Assets	-	-	-	-
Contribution	-	-	-	-
Benefits Paid	-	-	-	-
Actuarial losses/(gains)	-	-	-	-
Fair Value of Plan Assets at end of period	-	-	-	-

Fair Value of Plan Assets

	Leave Encashment		Gratuity	
	Year ended 31.03.2025	**Year ended 31.03.2024**	**Year ended 31.03.2025**	**Year ended 31.03.2024**
Fair value of plan asset at the beginning of period	-	-	-	-
Acquisitions Adjustment	-	-	-	-
Actual return on plan assets	-	-	-	-
Contributions	-	-	-	-
Benefits Paid	-	-	-	-
Fair value of plan assets at the end of period	-	-	-	-
Funded Status	(15,63,06,110)	(13,06,75,595)	(11,08,98,990)	(9,05,62,365)
Excess of actual over expected return on plan assets	-	-	-	-

Actuarial assumptions : In accordance with Accounting Standard 15 an actuarial valuation was carried out in respect of the aforesaid defined benefit plans. The principal assumptions used in determining gratuity and leave encashment benefit obligation are as follows:

(This space has been intentionally left blank)

QUALITY COUNCIL OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 MARCH 2025

(All amounts in INR, unless otherwise stated)

Particulars	Leave Encashment		Gratuity	
	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
Discounting Rate	6.99%	7.22%	6.99%	7.22%
Rate of increase in Compensation levels	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
Expected Rate of Return on Plan Assets				

The discount rate is generally based upon the market yields available on Government Bonds at the accounting date with a term that matches that of liabilities. The estimates of future salary increases, considered in Actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factor, such as supply and demand in the employment market, on long term basis.

Superannuation

Movement in the provisions recognised in the **Balance Sheet** is determined as under:

Particulars	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
Balance at the beginning of the Year	2,98,01,235	2,75,62,632
Expense recognised	4,45,38,466	3,05,29,668
Benefits paid	(3,69,99,600)	(2,82,91,065)
Balance at the end of the Year	**3,73,40,101**	**2,98,01,235**

Note 23

Related Party Disclosure

As per Accounting Standard-18, the Society's related parties and transactions are disclosed below:

Names of Related Parties and Related Party Relationship

Key Managerial Personnel

Mr. Rajesh Maheshwari	Interim Secretary General	**(up to 14.04.2024)**
Mr. Chakravarthy T. Kannan	Secretary General	**(from 15.04.2024)**

Related Party Transactions

	Nature of Transaction	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
Mr. Rajesh Maheshwari	Salary & Allowances	68,03,840	61,94,485
Mr. Chakravarthy T. Kannan	Salary & Allowances	83,55,775	-

Note 24

Society is registered under section 12AB of the Income tax act, 1961 and carrying out the activities as per the objective of the society and incidental thereto. The Society does not have any identifiable reporting segment therefore, the disclosure of AS-17 is not applicable.

Note 25

Society is registered under section 12AB of the Income Tax Act, 1961 and the income of the society is exempt under section 11 of the Act, therefore, no provision for income tax has been made.

(This space has been intentionally left blank)

Quality Council of India
Significant accounting policies and notes to the financial statements as at 31 March 2025

(All amounts in INR, unless otherwise stated)

Note 26

1 Reconciliation of unspent grants:

Particulars	Government grants						Total	Other grants (Tribal Research Information Education Communication)	Other grants (DL Shah trust)
	Zero Defect Zero Effect ('ZED') Certification scheme	Lean manufacturing competitiveness scheme	Director of management services, Defence Research and Development Organisation	National Good Laboratory Practice Compliance Monitoring Authority (NGCMA)	National Medicinal Plants Board (NMPB)	Jal Jeevan Shakti Mission (JJSM)			
Opening balance as at 1 April 2023	7,81,59,167	-	-	1,70,129	28,92,347	-	**8,12,21,643**	-	**7,23,498**
Receipts	1,98,69,10,210	2,98,20,154	-	62,64,306	-	1,06,85,578.00	**2,03,36,80,248**	-	-
Income accrual#	1,38,172	-	-	-	14,60,066	-	**15,98,238**	-	-
Adjustments/(refunds)	(1,30,35,175)	(1,27,69,357)	-	(70,78,110)	(3,94,472)	(79,65,337)	**(4,12,42,451)**	-	-
Adjusted balances (1+2+3+4)	**2,05,21,72,374**	**1,70,50,797**	-	**(6,43,675)**	**39,57,941**	**27,20,241**	**2,07,52,57,678**	-	**7,23,498**
Grant utilised^^	(1,67,65,38,120)	(1,22,08,591)	-	-	(39,57,941)	-	**(1,69,27,04,652)**	-	-
Adjustments for taxes	(30,17,76,862)	(2,05,034)	-	-	-	-	**(30,19,81,896)**	-	-
Adjustments for expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing balance as at 31 March 2024	**7,38,57,392**	**46,37,172**	-	**(6,43,675)**	-	**27,20,241**	**8,05,71,130**	-	**7,23,498**
Receipts	2,42,06,64,708	12,00,08,263	48,02,319	-	-	1,61,68,604	**2,56,16,43,894**	**20,37,500**	-
Income accrual#	31,01,714	-	-	-	-	-	**31,01,714**	-	-
Adjustments/(refunds)	(31,01,714)	-	-	6,43,675	-	-	**(24,58,039)**	**(20,37,500)**	-
Adjusted balances (8+9+10+11)	**2,49,45,22,100**	**12,46,45,435**	**48,02,319**	-	-	**1,88,88,845**	**2,64,28,58,699**	-	**7,23,498**
Grant utilised^^	(2,03,83,14,895)	(9,50,09,194)	-	-	-	(1,37,02,207)	**(2,14,70,26,296)**	-	-
Adjustments for taxes	(36,68,96,681)	-	-	-	-	(24,66,397)	**(36,93,63,078)**	-	-
Adjustments for expenses	-	(11,15,874)	-	-	-	(27,20,241)	**(38,36,115)**	-	-
Closing balance as at 31 March 2025	**8,93,10,524**	**2,85,20,367**	**48,02,319**	-	-	-	**12,26,33,210**	-	**7,23,498**

Includes interest income and accrual for other grant related incomes.
^^ Grants utilised represents grant spent for intended purposes. Grant income and expenses have been recognised accordingly.

(This space has been intentionally left blank)

QUALITY COUNCIL OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 MARCH 2025

(All amounts in INR, unless otherwise stated)

Note 27

Open Network Digital Centre (ONDC) was incorporated as a section 8 company in December 2021, with the Quality Council of India and Protean eGov Technologies Limited as Founding Members.
Unnati Employment Network was incorporated as a section 8 company in May 2021 by Quality Council of India and it is 100 % subsidiary company of Quality Council of India.
Both the companies are recently formed and have incurred losses in during previous year and the current year. Management is of the view that these are temporary losses as the entities have not yet started its operations to the full extent. Management is of the opinion that the losses are temprorary in nature hence no provision for impairment is made.

Note 28

Previous year figures have been regrouped/reclassified wherever necessary, to confirm to current year's reporting.

For **T R Chadha & Co LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 006711N/N500028

For and on behalf of **Quality Council of India**

Rajendra Prasad
Partner
Membership No. 098941

Place: Noida
Date: 19-09-2025

Chakravarthy T Kannan
(Secretary General)

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

Jaxay Shah
(Chairman)

Place: New Delhi
Date: 19-09-2025

(This space has been intentionally left blank)

QCI (Including Boardwise) Income & Expenditure for FY 2024-25

(Figure in Crore)

1ST APRIL 2024 TO 31ST MARCH 2025						
Boards & Divisions	Income			Expense		
	Budget	Actual	%age Achieved	Budget	Actual	%age Achieved
NABCB	17.80	18.26	103%	11.19	10.95	98%
NABET	43.47	39.28	90%	36.31	37.43	103%
NABH	95.77	100.89	105%	48.33	54.77	113%
NABL	105.00	102.51	98%	82.44	75.45	92%
NBQP	1.91	2.39	125%	18.30	13.41	73%
PADD	2.76	3.30	120%	4.33	4.94	114%
PPID	138.89	144.46	104%	134.53	138.93	103%
ZED	200.00	215.25	108%	156.41	123.17	79%
QCI-HO	-	-	-	45.00	30.48	68%
Interest Income & Expense	32.00	35.93	112%	6.50	5.93	91%
QGID	-	-	0%	10.00	7.53	75%
Total	**637.60**	**662.26**	**104%**	**553.35**	**503.00**	**91%**



PART 5

12 ACRONYMS & ABBREVIATIONS

SL. NO	TERM	FULL FORM
1	QCI	Quality Council of India
2	SG	Secretary General
3	CEO	Chief Executive Officer
4	HoD	Head of the Department
5	GC	Governing Council
6	GB	Governing Body
7	NABL	National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
8	NABH	NABH Accreditation Board for Hospitals
9	NABET	National Accreditation Board for Education & Training
10	NABCB	National Accreditation Board for Certification Bodies
11	NBQP	National Board for Quality Promotion
12	PPID	Project Planning and Implementation Division
13	NDIE	National Division for Industry Excellence
14	PADD	Project Analysis and Documentation Division
15	SPD	Strategy and Policy Division
	NABL	
1	APAC	Asia Pacific Accreditation Cooperation
2	APEDA	Agricultural and Processed Food Products Development Authority
3	AYUSH	Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy
4	EIC	Export Inspection Council
5	FSSAI	Food Safety and Standards Authority of India
6	G-LAP	Government Drinking Water Testing Laboratory Accreditation Program
7	ILAC	International Laboratory Accreditation Cooperation
8	IOPEPC	Indian Oilseed and Produce Export Promotion Council
9	M(EL)T	Medical (Entry Level) Testing
10	MRA	Mutual Recognition Arrangements
11	NABCB	National Accreditation Board for Certification Bodies
12	PTPs	Proficiency Testing Providers
13	RMP	Reference Material Producers
14	NABL	National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories

15	CAB	Conformity Assessment Body
16	QA	Quality Assurance
17	AERB	Atomic Energy Regulatory Board
18	EEPC	Engineering Export Promotion Council
19	ADAPT APAC-PTB	Digital Transformation of Accreditation in Asia Pacific Asia Pacific Accreditation Cooperation – Physikalisch -Technische Bundesanstalt
20	NML	National Metallurgical Laboratory
21	PTB	Power Terminal Block
22	ISO	International Organization for Standardization
23	IEC	International Electrotechnical Commission
24	ILAC -AIC	ILAC Accreditation committee (AIC)
25	WG	Working Group
26	UAF	United Accreditation Foundation
27	A2LA	American Association for Laboratory Accreditation
28	IAS	International Accreditation Service
29	PTWG	Proficiency Testing Working Group
	NABH	
1	NABH	National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers
2	HCO	Healthcare Organisation
3	SHCO	Small Healthcare Organisation
4	BB	Blood Bank
5	MIS	Medical Imaging Services
6	DHSP	Dental Healthcare Service Providers
7	AC	Allopathic Clinics
8	AH	AYUSH Hospitals
9	PC	Panchkarma Clinics
10	CT-EC	Clinical Trials Ethics Committee
11	ECO	Eye Care Organisation
12	PHC	Primary Health Centre
13	OST	Oral Substitution Therapy
14	IRCA	Integrated Rehabilitation Centres for Addicts
15	HOPE	Healthcare Organizations Platform for Entry Level Certification

16	AELC	AYUSH Entry Level Certification
17	CGHS	Central Government Health Scheme
18	ECHS	Ex-Serviceman Contributory Health Scheme
19	MVTF	Medical Value Travel Facilitator
20	POI	Program on Implementation
21	NABH I	NABH International
22	DHFC	Digital Health Foundation Course
23	NPSC	NABHT Patient Safety Conference
	NABET	
1	AAA	Academic and Administrative Unit
2	ADLQ	Anti-Doping Lab Qatar
3	AE/IE	Authority's Engineer/Independent Engineer
4	AIIMS	All India Institute of Medical Sciences
5	AMPRI	Advanced Materials and Processes Research Institute
6	BIPARD	Bihar Institute of Public Administration & Rural Development
7	CIPET	Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology
8	CREDAI	Confederation of Real Estate Developers' Associations of India
9	CSIR	Council of Scientific and Industrial Research
10	DHMC	Digital Health Master Class
11	DHR	Department of Health & Research
12	EMR	Electronic Medical Record
13	ESG	Environmental, Social & Governance
14	HE- RACB	Higher Education – Research Analysis and Capacity Building Division
15	HEI	Higher Educational Institutions
16	HMIS	Hospital management information system
17	ICAT	International Centre for Automotive Technology
18	ICMR	Indian Council of Medical Research
19	IGSTC	Indo – German Science & Technology Centre
20	IIT	Indian Institute of Technology
21	I-STEM	Indian Science Technology and Engineering Facilities
22	M/o MSME	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

23	MoEF&CC	Ministry of Environment, Forest and Climate Change
24	MoRTH	Ministry of Road Transport and Highways
25	MSME	Micro, Small and Medium Enterprises
26	NAAC	National Assessment and Accreditation Council
27	NABET	National Accreditation Board for Education and Training
28	NCDC	National Centre for Disease Control
29	NHAI	National Highway Authority of India
30	NHEQC	National Higher Education Quality Certification
31	NHIDCL	National Highways and Infrastructure Development Corporation
32	NIT	National Institute of Technology
33	NJJM	National Jal Jeevan Mission
34	NMCG	National Mission for Clean Ganga
35	QMS	Quality Management System
36	RHAI	Ranking of Higher Academic Institutions
37	SOP	Standard operating procedure
38	SPMNIWAS	Dr. Syama Prasad Mookerjee National Institute of Water and Sanitation
39	TCB	Training and Capacity Building
40	UKPCB	Uttarakhand Pollution Control Board
41	UNICEF	United Nations Children's Fund
42	UPPCB	Uttar Pradesh Pollution Control Board
NABCB		
1	ABMS	Anti-Bribery Management Systems
2	AIMS	Artificial Intelligence Management Systems
3	AMS	Asset Management Systems
4	APAC	Asia Pacific Accreditation Cooperation
5	AQMS	Aerospace Quality Management System
6	BAP	Best Aquaculture Practices
7	BCMS	Business Continuity Management Systems
8	BEE	Bureau of Energy Efficiency
9	BHEL	Bharat Heavy Electricals Limited
10	BIS	Bureau of Indian Standards

11	BRCGS	Brand Reputation through Compliance Global Standards
12	BSI	British Standards Institution
13	CABs	Conformity assessment bodies
14	CASCO	ISO committee for conformity assessment
15	CDSCO	Central Drugs Standard Control Organisation
16	CORSIA	Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation
17	DGCA	Directorate General of Civil Aviation
18	DGQA	Directorate General of Quality Assurance
19	DMRC	Delhi Metro Rail Corporation
20	DPIIT	Deptt. for Promotion of Industry and Internal Trade
21	EASA	European Aviation Safety Agency
22	ECCP	European Centre for Certification and Privacy
23	EnMs	Energy Management Systems
24	ESG	Environmental, Social, and Governance
25	FAMI-QS	Feed Additives and Pre-mixture Quality System
26	FMS	Facility Management Systems
27	FSMS	Food Safety Management Systems
28	FSSAI	Food Safety and Standards Authority of India
29	FSSC	Food Safety System Certification
30	GHG	Green House Gases
31	GIF	Get It Fair
32	GlobalG.A.P	Global Good Agricultural Practices
33	GQII	Global Quality Infrastructure Index
34	GSA-BAP	Global Seafood Alliance – Best Aquaculture Practices
35	IAF	International Accreditation Forum
36	IAQG	International Aerospace Quality Group
37	IB	Inspection Body
38	ICAO	International Civil Aviation Organization
39	ICOP	Industry Controlled Other Party
40	IEC	International Electrotechnical Commission
41	IFS	International Featured Standards

42	ILAC	International Laboratory Accreditation Cooperation
43	InAQG	Indian Aerospace Quality Group
44	ISA	International Society of Automation
45	ISACA	Information Systems Audit and Control Association
46	ISCC	International Sustainability and Carbon Certification
47	ISMS	Information Security Management Systems
48	ISO	International Organization for Standardization
49	ITSMS	Information Technology Service Management Systems
50	MAURITAS	Mauritius Accreditation Services
51	MLA	Multilateral Recognition Arrangement
52	MRA	Mutual Recognition Arrangement
53	MoP	Ministry of Power
54	NPL	National Physical Laboratory
55	OHSMS	Occupational Health and Safety Management Systems
56	PCB	Product Certification Body
57	PEFC	Programme for the Endorsement of Forest Certification
58	PNGRB	Petroleum and Natural Gas Regulatory Board
59	PrCB	Personnel Certification Bodies
60	QMS	Quality Management Systems
61	RTSMS	Road Traffic Safety Management Systems
62	SAF	Sustainable Aviation Fuel
63	SEBI	Securities and Exchange Board of India
64	SERI	Sustainable Electronics Recycling International
65	SFL	Sundram Fasteners Limited
66	SPS	Sanitary and Phytosanitary Measures
67	TBT	Technical Barriers to Trade
68	TDRMS	Trustworthy Digital Repositories Management Systems
69	TEC	Telecommunication Engineering Center
70	UKAS	United Kingdom Accreditation Services
71	VVBs	Validation & Verification Bodies
72	WAD	World Accreditation Day

73	WTO	World Trade Organization
NBQP		
1	5G Model	Fifth Generation
2	AHPI	Association of Healthcare Providers of India
3	AHPICON	Association of Healthcare Providers India Conference
4	CAHOCON	Consortium of Accredited Healthcare Organizations Conference
5	CAHOLABCON	Consortium of Accredited Healthcare Organizations Lab Conference
6	CBT	Children's Book Trust
7	CEO	Chief Executive Officer
8	CII	Confederation of Indian Industry
9	DAV	Dayanand Anglo-Vedic
10	DG	Director General
11	EEPC	Engineering Export Promotion Council
12	FICCI	Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry
13	FTCCI	The Federation of Telangana Chambers of Commerce and Industry
14	GB	Governing Board
15	GC	Governing Council
16	HCOs	Health Care Organisations
17	HEAL	Health, Education, Administration, and Literacy
18	HOD	Head of Department
19	IAS	Indian Administrative Service
20	IDA	Indian Dental Association
21	IESS	International Engineering Sourcing Show
22	IFSCA	International Financial Services Centres Authority
23	IHW	Integrated Health and Wellbeing
24	IMA	Indian Medical Association
25	IRS	Indian Revenue Services
26	ISBTI	Indian Society of Blood Transfusion & Immunohaematology
27	ISO	International Organization for Standardization
28	IT	Information technology
29	JVs	Joint ventures

30	KCCI	Kanara Chamber of Commerce & Industry
31	KCT	Kumaraguru College of Technology
32	MCLS	MSME Competitiveness Lean Scheme
33	MoU	Memorandum of Understanding
34	MSME	Micro, Small & Medium Enterprises
35	NABCB	National Accreditation Board for Certification Bodies
36	NABH	National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers
37	NABL	National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
38	NCR	National Capital Region
39	NDIE	National Division for Industry Excellence
40	NDMC	New Delhi Municipal Corporation
41	NE	North-East
42	NIDHI	National Integrated Database of the Hospitality Industry
43	NPSC	National Patient Safety Conference
44	NSC	National Safety Council
45	PADD	Project Analysis and Documentation Division
46	PDCA	Plan, Do, Check, Act
47	PHDCCI	PHD Chamber of Commerce and Industry
48	PSU	Public Sector Undertaking
49	SANJIVANI	Sustaining Arts, Nurturing Journeys, Innovating, Valuing, and Amplifying National Identities
50	SE&I	School Education and literacy
51	SG	Secretary General
52	SHCOs	Small Health Care Organisations
53	SIECC	Surat International Exhibition and Convention Centre
54	UFSEC	Uttar Pradesh Fire & Safety Expo and Conference
55	UTs	Union Territories
56	WACIA	Whitefield Area Commerce and Industries Association
57	ZED	Zero Defect, Zero Effect
	PPID	
1	AIIMS	All India Institute of Medical Sciences
2	APC	Agro Processing Clusters

3	CIL	Central Insecticides Laboratory
4	DARPG	Department of Administrative Reforms & Public Grievances
5	DQMA	Discom Quality Monitoring Agency
6	FCI	Food Corporation of India
7	FSSAI	Food Safety and Standards Authority of India
8	GSECL	Gujarat State Electricity Corporation Limited
9	JJM	Jal Jeevan Mission
10	MMT	Million Metric Tonne
11	MoAFW	Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare
12	MoFPI	Ministry of Food Processing & Industries
13	MoHUA	Ministry of Housing and Urban Affairs
14	MVVNL	Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam
15	NBCC	National Buildings Construction Corporation Limited
16	NCS	National Career Service
17	NCSC-SC/ST	National Career Service Centres for SC/ST
18	NeGW	National e-Governance Webinars
19	NeSDA (WF)	National e-Governance Service Delivery Assessment - Way Forward
20	NHB	National Horticulture Board
21	NHDC	National Handlooms Development Corporation
22	NLCIL	NLC India Limited
23	OSCSC	Odisha State Civil Supplies Corporation
24	PC	Procurement Centres
25	PCSAP	Procurement Centre Self-Assessment Platform
26	PHED	Public Health Engineering Department
27	PMAY	Pradhan Mantri Awas Yojana
28	PMKSY	Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana
29	PMU	Project Management Unit
30	SBM	Swachh Bharat Mission
31	SCCL	Singareni Collieries Company Limited
32	SRKVM-AP	Sarvepalli Radhakrishnan Vidya Mitra - Andhra Pradesh
33	STP	Sewage Treatment Plant

34	TCGL	Tourism Corporation of Gujarat Limited
35	TPE	Third Party Evaluation
36	TPI	Third Party Inspection
37	TPQMA	Third Party Quality Monitoring Agency
38	UPPCL	Uttar Pradesh Projects Corporation Limited.
NDIE		
1	MSME	Micro Small and Medium Enterprise
2	DIC	District Industrial Centre
3	IA	Implementing Agency
4	DRDO	Defence Research and Development Organization
5	SAMAR	System for Advanced Manufacturing Assessment and Rating
6	MoU	Memorandum of Understanding
7	ASSOCHAM	Associated Chambers of Commerce & Industry of India
8	MPLUN	Madhya Pradesh Laghu Udg Nigam
9	BHEL	Bharat Heavy Electricals Limited
10	DGFT	Directorate General of Foreign Trade
11	BLW	Banaras Locomotive Works
12	ASIDC	Assam Small Industries Development Corporation Ltd.
13	ACE	Armament and Combat Engineering
14	BDL	Bharat Dynamics Limited
PADD		
1	AAC	Academic Advisory Council
2	Aadhaar	Unique Identification Number issued by the Indian government
3	APEDA	Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
4	ASI	Archaeological Survey of India
5	AYUSH	Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa
6	CB	Certification Body
7	CEO	Chief Executive Officer
8	CII	Confederation of Indian Industry
9	CSE	Critical Sector Entity
10	CSIR	Council of Scientific and Industrial Research

11	CSUAS	Certification Scheme for Unmanned Aircraft Systems
12	DG	Directorate General
13	DGCA	Directorate General of Civil Aviation
14	DRC	Digital Readiness Certificate
15	EPCH	Export Promotion Council for Handicrafts
16	EU	European Union
17	FAO	Food and Agriculture Organization
18	FDA	Food and Drug Administration
19	FGDSs	Focus Group Discussions
20	FPOs	Farmer Producer Organizations
21	FSSAI	Food Safety and Standards Authority of India
22	GAP	Good Agricultural Practices
23	GeM	Government e Marketplace
24	GFCP	Good Field Collection Practices
25	GLOBALG.A.P.	Global Good Agricultural Practice
26	GLP	Good Laboratory Practices
27	GRASP	Risk Assessment on Social Practice
28	GSTIN	Goods and Services Tax Identification Number
29	HRAA	Hygiene Rating Audit Agency
30	ICRISAT	International Crops Research Institute for the Semi-Arid Topics
31	ICSTS	International Convention on Sustainable Trade and Standards
32	INPPSS	India National Platform on Private Sustainability Standards
33	IRRI	International Rice Research Institute
34	ITTO	International Tropical Timber Organization
35	MoU	Memorandum of Understanding
36	MSME	Micro, Small, and Medium Enterprises
37	NeGD	National eGovernance Division
38	NCIIPC	National Critical Information Infrastructure Protection Centre
39	NGCMA	National Good Laboratory Practices Compliance Monitoring Authority
40	NMPB	National Medicinal Plant Board
41	NTWG	National Technical Working Group

42	ONDC	Open Network for Digital Commerce
43	PAN	Permanent Account Number
44	PoPs	Package of Practices
45	RPAS	Remotely Piloted Aircraft Systems
46	SAARC	South Asian Association for Regional Cooperation
47	SDG	Sustainable Development Goal
48	SoC	Statement of Conformity
49	TDU	The University of Trans-Disciplinary Health Science and Technology
50	TiHAN	Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation
51	UAS	Unmanned Aircraft Systems
52	UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
53	UNDP	United Nations Development Programme
54	UNFSS	United Nations Forum on Sustainability Standards
55	UNIDO	United Nations Industrial Development Organization
56	VCSMPP	Voluntary Certification Scheme for Medicinal Plant Produce
57	VCSTCHP	Voluntary Certification Scheme for Traditional Community Healthcare Providers

भारतीय गुणवत्ता परिषद्

QUALITY COUNCIL OF INDIA

जे-200, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली 110029

दूरभाष +91-11-2618-6680, 2618-6681, 2618-6682, 2618-6683

वेबसाइट www.qcin.org